

सुलभ साहित्य-माला

सरल नागरिक शास्त्र

लेखक

भगवानदास केला

भारतीय शासन, भारतीय अर्थशास्त्र, अपराघ-चिकित्सा श्रीर नागरिक शिक्षा श्रादि के रचयिता

सम्पादक

दयाशंकर दुवे एम० ए०, एल-एल० बी० श्चर्यशास्त्र श्रध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय

प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन •प्रयाग



मुद्रक— नारायण प्रसाद नारायण प्रेस, नारायण विल्डिंग्स, प्रयाग

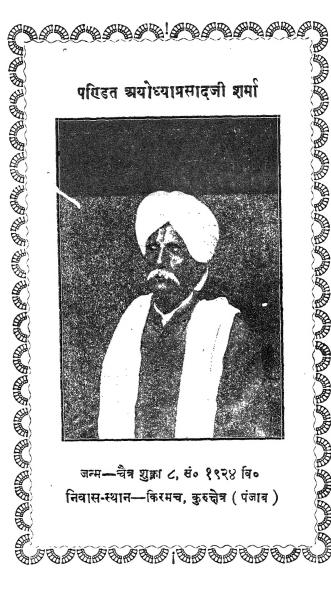
कृतज्ञता-प्रकाश

स्वर्गीय श्रीमान् बड़ौदा-नरेश महराज स्याजीराव गायकवाड़ महोद्य ने बम्बई के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच सहस्र रुपये की सहायता सम्मेलन को प्रदान की थीं उसी सहायता से सम्मेलन इस 'सुलभ-साहित्य-माला' के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। इस 'माला' में जिन सुन्दर और मनोरम प्रनथ-पुष्पों का प्रथन किया जा रहा है उनकी सुरिभ में समस्त हिन्दी-संसार सुवासित हो रहा है। इस 'माला' के द्वारा हिन्दी साहित्य की जो श्री वृद्धि हो रही है उसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय श्रीमान् बड़ौदा-नरेश महोद्य को है। उनका यह हिन्दी-प्रेम भारत के अन्य हिन्दी-प्रेमी श्रीमानों के लिए अनुकरणीय है।

निवेदक-मन्त्री

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

प्रयाग



समर्पग्र

श्रीमान् परिहत अयोध्याप्रसादनी शर्मा

रूज्य गुरुवर!

नागरिकता की पहली पाठशाला घर है; नागरिक शिक्षा के प्रथम आचार्य माता-पिता होते हैं। पीछे इस शिक्षा में सहयोग देने का कार्य उन शिक्षकों का है जो वर्णमाला के अच्चर सिखाते हैं। मैंने जब होश सँभाला तो मेरे पिता जी का देहान्त हो गया था, अतः मैं उनकी शिचा से वंचित ही रहा। माता जी ने जो कुछ वन आया, करने में कसर न उठा रखी। पर आपका प्रेम-पूर्ण आश्य न मिलता तो कौन जाने क्या होता। आपने मुक्ते अक्षर-जान ही नहीं कराया, वरन् आपने मुक्ते शिष्टाचार, सद्व्यवहार, गुरुजन-सम्मान, दूसरों से सहानुभूति और सद्भाव आदि सद्गुर्गों की भी आधार-भूत शिचा दी है। इसके लिए में आजन्म आपका ऋगी रहूँगा।

परमात्मा करे मैं गुरु-दक्षिणा-स्वरूप नागरिक-शास्त्र-साहित्य की रचना और वृद्धि में यथा-शक्ति योग देता रहूँ।

विनीत

भगवान राक नेता

निवेदन

🖓 । गरिकता नवयुग का नया छन्देश है। यह एक प्रकार से उन सब रोगों की रामवाण श्रीषधि है, जिनसे श्राधुनिक संसार कष्ट पीड़ित है। समाज-रूपी वाटिका में समय-समय पर कुछ घास-फूस उग आता है. उसके सुगन्धित पौदों को कुछ रोगों के कीटाग़ा लग जाते हैं। देश-काल के अनुसार स्थारक रोग का निदान करके समाज-बाटिका को रोग-मुक्त करते तथा उसे नवर्जावन प्रदान करते हैं। आज दिन फिर सधार और निर्माण की आवश्यकता है। पर पहले बस्तु-स्थिति को समभत्तेना ज़रूरी है। भारतवर्ष की बात लें। यहाँ हिन्दू मुसलमानों का भगड़ा क्यों है ?--ज़मींदार श्रीर किसानों का तथा पूँजीपतियों श्रीर मज़द्रों का संघर्ष क्यों है ? अनेक आदमी मुफ़्ज़ोरी या परावलम्बन का जीवन क्यों वितारहे हैं ? सासक श्रीर शासितों में विरोध का क्या कारण है १ मुख्य बात यह है कि व्यक्ति या समूह अपने-अपने नागरिक कर्तव्यों का ठीक रीति से पालन नहीं करते, अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। सब नागरिकता की समुचित शिचा प्रहण करलें तो देश के इन आन्तरिक विवादों का अन्त हो जाय। यही नहीं. नागरिकता की व्यापक शिचा तो अन्तर्राष्ट्रीय कलह को भी मिटा सकती है। जर्मनी ओर इंगलैंड का श्रथवा चीन श्रीर जापान का युद्ध क्यों उन रहा है ? कारण यही है कि इनके सामने विश्व-नागरिकता का आदर्श नहीं है। सब अपने-अपने स्वार्थ-साधन में लगे हुए हैं। नागरिक शास्त्र के सम्यक् विवेचन से संसार में शान्ति का साम्राज्य हो सकता है।

बड़े हर्ष का विषय है कि अब हिन्दी भाषा में नागरिक शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों की माँग क्रमशः बढ़ती जा रही है और उसके फल-स्वरूप उसकी पूर्ति भी होती जा रही है। नागरिकशास्त्र की साहित्य-बृद्धि का अध्येयह है कि देश में नागरिकता के भावों की बृद्धि हो, श्रीर भावी सन्तान सुयोग्य नागरिक बनें। अतः प्रत्येक देश-प्रेमी सजन का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह ऐसे साहित्य की रचना श्रीर प्रचार में भरसक सहयोग प्रदान करें।

यपना लेखन-कार्य आरम्भ करने के समय से ही—सन् १९१५ ई० से—हन पंक्तियों के लेखक ने अपने सामने विशेषतया राजनीति और अर्थशास्त्र-साहित्य की रचना में भाग लेने का कार्य-कम रखा है, और नागरिकशास्त्र सम्बन्धी जो कुछ कार्य गत २५ वर्ष में बन आया है, किया है। इसलिए जब युक्तपान्त के इंटर के विद्यार्थियों को इस विषय के प्रम पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने की अनुमित हुई, तो कई सजनों ने सुक्त कि मेरी कौन कौनसी पुस्तक उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। पाठ्य-कम को देखने से मुक्ते ज्ञात हुआ कि यद्यि मेरी भारतीय शासन, भारतीय जागृति, हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ, निर्वाचन-पद्धति, नागरिक ज्ञान, नागरिक शास्त्र और भारतीय अर्थशास्त्र आदि पुस्तकों में पाठ्य-कम की कितनी-ही बातों का समावेश है, तथापि उसकी कुछ बातें—विशेषतया विद्यान्त-सम्बन्धी— ऐसी ॰ हैं, जिन पर बहुत कम लिखा गया है, अथवा नहीं लिखा गया। यह होते हुए भी मुक्ते उस समय पाठ्य-पुस्तक लिखने का उत्साह या रुचि नहीं हुई। पीछे कभी-कभी मन में आया कि पुस्तक लिख सक्ँ तो अच्छा है। परन्तु प्रकाशन की कठिनाहयों को सोचकर रह गया। दुविधा में ही था कि श्री प्रोफेसर दयाशंकरजी दुवे (परीचा-मन्त्री, हिन्दी;साहित्य समेलन, प्रयाग) ने मुक्ते लिखा कि सम्मेलन कुछ विषयों की पाठ्य पुस्तके छुपाने का आयोजन कर रहा है, आप इन्टर के लिए 'सीविक्स' की पुस्तक लिखए।

मैंने पुस्तक लिखना स्वीकार कर लिया। गत वर्ष कार्य भी धारम्भ कर दिया था। परन्तु बृत्दावन में रहते हुए प्रथम तो बहुत-सा समय अन्य-अन्य पुस्तकों के काम में लगता रहा, फिर इस पुस्तक के लिए जो साहित्य देखना आवश्यक था, उसको प्राप्त करने की भी मुक्ते वहाँ सुविधा न थी। इस प्रकार कार्य में कुछु विशेष प्रगति न हो पायी। श्री दुवेजी का तकाज़ा होने लगा, मैं भी वचन-वद्ध था। परन्तु इच्छा होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा था। अन्ततः यह निश्चय किया कि कुछ समय प्रयाग रहकर ही इस कार्य को पूरा करूं। निदान, इस वर्ष प्रयाग में श्री दुवे जी के ही पास रह कर यह कार्य किया गया। समय-समय पर आप से इस विषय-सम्बन्धी विचार-विनिमय करते रहने की सुविधा हुई। इसके अतिरिक्त आप ने इस्तिलिखत प्रति को आद्योपान्त देखने तथा आवश्यक परामर्श देने की कुपा की।

पुस्तक के विषय का चेत्र बहुत ज्यापक है। जिज्ञामु को तो इस तरह की कई-कई पुस्तकों का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए। हीं, में ने इस बात का प्रयत्न किया है कि विद्याधियों के उपयोगी कोई आवश्यक बात छूटने न पाये, उनकी साधारण आवश्यकता की पूर्ति इस एक ही पुस्तक से हो जाय। स्थान-स्थान पर पाठकों को इसमें कुछ विचार-सामग्री भी मिलेगी। मैंने विषय-विवेचन में यथा-सम्भव उदार राष्ट्रीय हिंदर रखी है, जिससे पाठकों को अपनी मातृ-भूमि का ध्यान हो और उनके सामने नागरिकता सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्य-क्रम भी रहे। जिन पुस्तकों से मैंने इस रचना में लाभ उठाया है, उनके नाम अन्यत्र दिये गये हैं। उनके लेखकों का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। श्री प्रोफेसर दयाशंकर जी दुवे ने इस पुस्तक का सम्पादन करने का कष्ट उठाया है, और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इसे प्रकाशित करने की कृपा की है। इनका भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ।

विनीत भगवान रिक व्येटा

सहायक पुस्तकें

- 1. S. Leacock-Elements of Political Science
- Dr. Ram and Sharma—Indian Civics and Administration
- 3. R. M. Sanyal—A First Course of Civics
- 4. S. V. Puntambekar—An Introduction to Civics and Politics.
- 5. डाक्टर वेणीप्रसाद--भारतीय नागरिकता
- 6. गोरखनाथ चौबे-- नागरिकशास्त्र की विवेचना
- 7. प्राणनाथ विद्यालंकार-राजनीति शास्त्र
- 8, मुख संपत्तिराय भंडारी-राजनीति विज्ञान
- 9. भगवानदास केला—भारतीय शासन (श्राठवाँ संस्करण)
 भारतीय जायित (तीसरा संस्करण)
 नागरिक शास्त्र
 हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ (तीसरा संस्करण)
 भारतीय श्रर्यशास्त्र (दूसरा संस्करण)
 भारतीय राजस्व (दूसरा संस्करण)
- दयाशंकर दुवे
 श्रीर
 भगवानदास केला

निर्वाचन-पद्धति (तीसरा संकरणा) ब्रिटिश साम्राज्य-शासन

विषय-सूची

प्रथम भाग

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

पहला परिच्छेद: नाँगरिक शास्त्र का विषय

द्सरा परिच्छेद : नागरिक शास्त्र श्रौर श्रन्य सामाजिक शास्त्र

राजनीति से सम्बन्ध-ग्रर्थशास्त्र से सम्बन्ध-नीतिशास्त्र से सम्बन्ध-इतिहास से सम्बन्ध-नागरिक शास्त्र श्रीर क़ानून। ए० ९-१७

तीसरा परिच्छेद: सामाजिक जीवन

स्वस्था—कारीगर-ग्रवस्था; नगर-निर्माण—सामाजिक जीवन पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव—सामाजिक जीवन का श्राधार; सहकारिता—समाज श्रीर व्यक्ति। पृ०१८-३०

चौथा परिच्छेद : व्यक्ति श्रौर समृह

समूहों की आवश्यकता और निर्माण—समूहों का पारस्परिक सम्पर्क – समूहों के मेद – समूहों का चेत्र—समूह का उद्देश्य—व्यक्ति का विकास—समूह की सफलता। पृ० ३१-४२

पाँचवाँ परिच्छेद: परिवार श्रीर जाति

परिवार और उसका स्वरूप-परिवार में स्त्री और पुरूष का कर्तव्य - परिवार और व्यक्ति - संयुक्त परिवार - कुल या गोत्र - जाति - जाति, व्यक्ति और समाज। पृ० ४३-५५

छठा परिच्छेद: धार्मिक समृह

धार्मिक भावना का सूत्रपात—ईश्वर की कल्पना—धार्मिक एकता—सिंहण्युता श्रीर समभाव की आवश्यकता—धर्म श्रीर व्यक्ति—धर्म का चेत्र। पृ०५६-६७

सातवाँ परिच्छेद: व्यावसायिक समूह

श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति — श्रम विभाग और जाति-प्रथा — समता श्रोर सहकारिता की श्रावश्यकता — व्यावसायिक समूहों का श्रादर्श — ब्यावसायिक समूह और व्यक्ति । पृ० ६९—८०

श्राठवाँ परिच्छेद : राजनैतिक समृह

राजनैतिक समूह, पराधीन देशों में स्वाधीन देशों में अन्त-र्शब्दीय समूह - राज्य तथा राष्ट्र - व्यक्ति, राष्ट्रीयता और मानवता ।

नवाँ परिच्छेद: राज्य श्रौर उसके तत्व

राज्य श्रौर अन्य समूहों में मेद—राज्य के तत्व—जनता—
भूमि—राजनैतिक संगठन—प्रभुत्व शक्ति। ए० ९३-१०३

दसवाँ परिच्छेद: राज्य की उत्पत्ति

मुख्य-मुख्य विद्धान्त — देवी विद्धान्त — श्राधिक विद्धान्त — शक्ति-विद्धान्त – वामाजिक इकरार विद्धान्त – विकास विद्धान्त । पृ० १०४ – ११९

ग्यारहवाँ परिच्छेद : राज्य की प्रभुत्व-शक्ति

प्रभुत्व-शक्ति के लक्ष्य-प्रभुत्व-शक्ति श्रवाध होती है-प्रभुत्व-शक्ति के विद्धान्त की श्रालोचना-राज्य की प्रभुत्व-शक्ति कही होती है श-राजनैतिक प्रभुत्व-शक्ति श्रीर जनता-विशेष वक्तव्य। पृ० १२०-१३१

बारहवाँ परिच्छेद : राज्य और व्यक्ति

क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र था ?—सामाजिक जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता—वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा—राज्य का सावयव सिद्धान्त — स्वतंत्रता का विशेष ऋषी। पृ०१३२-१४३

तेरहवाँ परिच्छोद: राज्यों के भेद

नेगर-राज्य श्रीर देश-राज्य—राष्ट्र-राज्य—पुरोहित राज्य श्रीर लीकिक राज्य—प्रभुत्व-शक्ति के विचार से राज्यों के भेद—श्ररस्तू का मत—राजतंत्र—श्रवेष तंत्र—वैष्व राजतंत्र—पुरुतेनी या पैत्रिक राजा—निर्वाचित राजा—राजतंत्र के गुग्य-दोष—उच्च जनतंत्र—प्रजातंत्र ।

20 १४४-१६ ६

चौदहवाँ परिच्छ द : शासन-पद्धति

संधारमक श्रीर एकात्मक शासन-पद्धति — लिखित श्रीर श्रिलिखत शासन-पद्धति—परिवर्तनशील श्रीर श्रपरिवर्तनशील शासन-पद्धति— समात्मक श्रीर श्रध्यक्षात्मक शासन-पद्धति—एक-सभात्मक श्रीर द्विस्थात्मक शासन-पद्धति—भिन्न-भिन्न शासन-पद्धतियों की तुलना। पृ० १६२-१ ८८

पद्रहवां परिच्छेद : राज्य का कार्य-क्षेत्र

व्यक्तिदाद—समाजवाद—समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूरा—समाज-बाद के गुग्ग-दोष — उचित मार्ग —राज्य और व्यक्ति के उद्देश्य की समानता—भारतवर्ष और समाजवाद। पृ०१७९-१९९

सोलहवां परिच्छेद : राज्य के कार्य

शान्ति-स्थापक कार्य — रक्षा — शान्ति और सुब्यवस्था—न्याय— लोकहितकर कार्य — शिद्धा — स्वास्थ्य — यातायात के साधन — समाज-सुधार — श्रार्थिक हितसाधन। • पृ० २००-२१३

सत्रहवां परिच्छेद : सरकार के अंग

सरकार के कार्यों के मेर-सरकार के प्रत्येक कार्य का महत्व-सरकार के द्या-प्रत्येक द्यांग के द्यावश्यक गुण-व्यवस्थापक मंडल-शासक वर्ग-त्यायाधीश वर्ग। पृ० २१४-२२७

त्र्रारहवाँ परिच्छोद : शक्ति-पार्थक्य त्र्रोर त्र्राधिकार विभाजन

शक्ति - पार्थन्य-- अधिकार - त्रिमाजन -- अधिकार - विभाजन को पद्धति--स्थानीय संस्थात्रों की विशेषता। पृ० २२८--२३९

उन्नीसवाँ परिच्छेद : प्रतिनिधि-निर्वाचन

प्रतिनिध-प्रणाली - प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष निर्वाचन—निर्वाचक रुंघ — मताधिकार — मत देना – मत देने की विधि — मत-गण्ना प्रणाली — एकाकी मत-प्रणाली — श्रनेक-मत-प्रणाली — एक उम्मेद-वार, एक-मत-पद्धति — एकत्रित मत-पद्धति — एकाकी इस्तान्तरित मत-प्रणाली — उम्मेदनार — प्रतिनिधि श्रौर निर्वाचक। पृ० २४० – २६०

बोसवां परिच्छ द : नागरिकता

श्च-नागरिक—नागरिकता की प्राप्ति—नागरिकता का विस्तार— नागरिक श्रादर्श। पृ० २६१-२७१

इकीसवां परिच्छेद : नागरिकों के अधिकार

श्रिवकारों के लक्षण—श्रिवकारों का श्राधार—योग्यता—जान-माल की रक्षा—सम्पत्ति की रक्षा—श्रार्थिक स्वतंत्रता—विचार, भाषण श्रीर लेखन की स्वतंत्रता—सामाजिक स्वतंत्रता—धार्मिक स्वतंत्रता—शिक्षा-प्राप्ति का श्रीवकार—राजनैतिक श्रीवकार—विशेष वक्तव्य।

बाईसवां परिच्छेद: नागरिकों क कर्तव्य

श्रिषकार श्रीर कर्तव्यों का सम्बन्ध—कर्तव्य-पालन—कर्तव्य का चेत्र—श्रपने प्रति कर्तव्य—परिवार के प्रति कर्तव्य—समाज के प्रति कर्तव्य—धर्म-सम्बन्धों कर्तव्य—ग्राम श्रीर नगर के प्रति कर्तव्य—राज्य के प्रति कर्तव्य—देश-भक्ति—कर्तव्यों का संघर्ष—कर्तव्य-सम्बन्धी श्रादर्श।

पृ० २९९-३१९

तेईसवाँ परिच्छेद : लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ

लोकमत का प्रभाव—राज्य और लोकमत—लोकमत श्रीर उसका निर्माण—लोकमत को दूषित करनेवाली बातें श्रीर उन्हें दूर करने के उपाय-पत्र-पत्रिकाएँ—समाचार-पत्र—श्रन्य सामियक साहित्य।

पृ० ३२०-३३८

चौबीसवाँ परिच्छेद : राजनैतिक दल

दलबन्दी से लाभ-हानि — दलों का उपयोग — भारतवर्ष में राजनै-तिक दल। पृ० ३३९-३५२

पचीसवाँ परिच्छोदः नैतिक स्रोर धार्मिक प्रभाव

नागरिक जीवन श्रीर वातावरण — नैतिक वातावरण का प्रभाव — / धार्मिक वातावरण का प्रभाव। _ पृ० ३५३--३६६,

दूसरा भाग भारतीय नागरिकता

छब्बीसवाँ परिच्छेद : हमारा देश

भौगोलिक स्थिति—प्राकृतिक भाग—जल-वायु—वर्षा—निद्यां— जंगल—कृषि-योग्य भृमि—खानें—प्राकृतिक शक्ति—भारतीय जनता— भाषा—श्रन्य भेद-भाव—भारतवर्ष की एकता। पृ० ३६९-३८५ सत्ताईसवाँ परिच्छेद : धर्म श्रोर धार्मिक सुधार

धार्मिक साहित्य—वैदिक धर्म—वौद्ध धर्म और जैन धर्म— पौराणिक धर्म—इस्ताम धर्म—सिक्ल धर्म —पार्सी—ईसाई—आधु-निक धार्मिक सुधार—राजा राममोइनराय और ब्रह्मसमाज—स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज—कर्नल आल्काट और थियोसकी— स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन—इन आन्दोलनों का प्रभाव —अद्धा का सदुग्योग—दान धर्म—इरिजन मन्दिर-प्रवेश—मुस्तमानों में धार्मिक सुधार—अन्य धर्मावलिन्वियों में सुवार की मावना—विशेष वक्तव्य। ३८६-४१२

अठाईसवाँ परिच्छेद : सामाजिक जीवन

श्राश्रम व्यवस्था— वर्ण व्यवस्था—जाति-भेद के गुण-दोष—नीच जातियों से सद्व्यवहार—हरिजन श्रान्दोलन—संयुक्त-कुटुम्ब प्रणाली —महिलाश्रों की स्थिति में सुवार—मुसलमानों में समाज-सुधार— श्रान्य जातियों में प्रकाश —जन-संख्या का प्रश्न—भारतीय समाज की कमज़ोर कड़ी—सरकारी सहयोग—सेवा भाव। पृ० ४१३-४२९

उन्तीसवीं परिच्छेद : आर्थिक स्थिति

भारतीय जनता के पेशे—कृषि-सम्बन्धी सुधार—किसान-सम्बन्धी समस्याएँ—उद्योग-धन्धे—दस्तकारियों का पुनरुद्धार—उद्योग धन्धे श्रीर सरकार—व्यागर—विनिमय श्रीर वैंक—भारतवासियों की निर्धनता श्रीर उसे दूर करने के उपाय। पृ० ४३०-४४९

तीसवाँ परिच्छेद : शिक्षा श्रोर साहित्य प्राचीन शिक्षा व्यवस्था—सुसलमानों के शासन-काल में शिक्षा की व्यवस्था—श्राँगरेज़ी शिक्ता का प्रारम्भ—सरकार का नीति-परिवर्तन— शिक्ता की प्रगति—गैर-सरकारी श्रीर राष्ट्रीय संस्थाएँ - नवीन शिक्षा थोजना—साहित्य-प्रचार।

🏒 इकतीसवां परिछेदः राष्ट्रीय आन्दोत्तन

राष्ट्रीयता का विकास —राष्ट्रीयता वृद्धि के कारण —शिक्षा श्रीर विज्ञान — श्रन्य देशों की जार्यत का प्रभाव — प्रवासी भारतीयों की दुरवस्था —राष्ट्रीयता की परी चा — कांग्रेस या राष्ट्र-सभा —राष्ट्रीयता में वाचाएँ; (१) प्रान्तीयता — (२) सम्प्रदायिक संस्थाएँ — (३) राज-नैतिक श्रनेकता —राष्ट्रीय श्रान्दोलन का फल। पृ० ४६३-४७७

बत्तोसवाँ परिच्छेद : राजनैतिक विकास

भारतवर्ष में ऋँगरेज़ —कांग्रेस श्रीर शासन-सुंघार श्रान्दोलन — सत्याग्रह श्रीर श्रसहयोग — मांट-फोर्ड सुघार — साइमन कमीशन श्रीर दमन — नागरिकों के मूल श्रधिकार — देशी राज्यों की जागृति — वर्तमान शासन-निधान — विधान का प्रयोग — विधान-निर्मातृ-समा — विशेष सक्तव्य।

तेतीसवां परिच्छेद : ब्रिटिश सरकार और भारतवर्ष

बादशाह—पालिमेंट—मंत्री-मंडल—पालिमेंट श्रोर भारतवर्ष— भारत-मंत्री श्रीर उसके कार्य — इंडिया कौंसिल— हाई-किमश्नर । पृ० ४९६-५०२

चौतीसवां परिच्छेद: भारत-सरकार गवर्नर-जनरल या वायवराय—गवर्नर-जनरल के अधिकार— उसकी प्रबन्धकारिणी सभा (कौंसिल)—सेकेटरी तैथा अन्य पदाधिकारी—प्रबन्धकारिणी सभा के अधिवेशन—काम का ढंग—गवर्नर-जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपिस्थित —भारत-सरकार का कार्य—मारत-सरकार के अधिकार—सन् १९३५ का विधान और भारत-सरकार।

पैंतीसवां परिच्छेद : भारतीय व्यवस्थापक मंडल

निर्वाचक संघ—कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो एकते ?—
राज्य-परिषद — निर्वाचक की योग्यता — सदस्य कौन हो सकता है ?—
भारतीय व्यवस्थापक सभा—निर्वाचक की योग्यता — सदस्य और
सभारति — व्यवस्थापक मंडल का कार्य चेत्र—कार्य-पद्धति — प्रश्न—
प्रस्ताव — कानूक किस प्रकार बनते हैं ?— राज्य परिषद से हानि—
गवर्नर-जनरल के व्यवस्था-सम्बन्धी अधिकार — भारतीय आय-व्यय
का विचार — सन् १९३५ का विधान और भारतीय व्यवस्थापक मंडल।
पृ० ५ १३-५३३

छत्तीसवां परिच्छेद : मान्तीय सरकार

वर्तमान शासन-विधान से पहले —वर्तमान शासन-विधान; प्रांतों का वर्गों करण — नये प्रान्तों का निर्माण — गवनंर; उनकी नियुक्ति, वेतन और पद — आदेश-पत्र — गवर्नर के अधिकार — प्रान्तीय विषयों का प्रवन्ध — गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व — पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था — आतंकवाद का दमन — कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम- निर्माण — गवर्नर के अधिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य — संत्री-मंडल का निर्माण — मंत्रियों की नियुक्ति — मंत्रियों का वेतन — मंत्री-मंडल का

सभापतित्व मंत्री-मंडल से किसी मंत्री का पृथक्करण मंत्रियों के पालिमेंटरी सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल शासन विधान की निस्सारता चिफ-किमश्नरों के प्रान्तों का शासन प्रान्तों के भाग; किमश्नरियां ज़िले का शासन। पृ० ५३४-५५४

सैंतीसवाँ परिच्छेद : प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडन

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की समाएँ श्रीर उनकी श्रवधि-कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?--सदस्यों की योग्यता श्चादि—सदस्यों के रियायती श्राधकार, वेतनादि—पान्तीय व्यवस्थापक सभा का संगठन-निर्वाचक कौन हो सकते हैं ?-प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्-निर्वाचकों की योग्यता -साधारण योग्यता-स्त्रियों सम्बन्धी योग्यता-दिलत जातियों-सम्बन्धी योग्यता-दुसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्त व्य-व्यवस्थापक मंडल के ऋधिकार—व्यवस्थापक मंडल का अधिवेशन-सभापति और उपसभापति-सभात्रों में मत-प्रदान-सदस्यों-सम्बन्धी नियम-श्राँगरेजी भाषा का प्रयोग-व्यवस्था-पक मंडल की कार्य-पद्धति -- कार्य-पद्धति के नियमों का निर्माण --प्रश्न और प्रस्ताव-प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के क्रानूनों का चेत्र-कानून कैसे बनते हैं ?--प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के ऋधिकारों की सीमा-गवर्नर के श्रविकार, भाषण श्रीर संदेश-गवर्नर के श्रार्डि-नेन्त-गवर्नर के क़ानून-पृथक् या श्रंशतः पृथक् चेत्रों की व्यवस्था-श्चाय-व्यय-सम्बन्धी कार्य-पद्धति - बजट श्रधिवेशन - विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवाले नियम; गवर्नर की घोषणा--विशेष वक्तव्य। पृ० ५५५ -- ५८५,

अड़तीसवाँ परिच्छेद : स्थानीय स्वराज्यं

प्राचीन व्यवस्था— श्राधुनिक म्थिति—स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ — पंचायतें — बोर्ड ने बोर्ड का कार्य श्रीर व्यय — बोर्ड की श्राय के साधन — इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड की श्राय — इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड का व्यय — म्युनिसपैलटियां श्रीर कारपोरेशन — उनके कार्य — श्रामदनी के साधन — इलाहाबाद म्युनिसपैलटी की श्राय — इलाहाबाद म्युनिसपैलटी की श्राय — इलाहाबाद म्युनिसपैलटी का व्यय — नोटिफाइड एरिया — इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट — पोर्ट ट्रस्ट विशेष वक्तव्य ।

उनतालीसवाँ परिच्छेद : सरकारी नौकरियाँ

सैनिक नौकरियाँ—मुल्की नौकरियाँ— इंडियन-सिविल सर्विस की प्रभुता— कुछ ज्ञात्वय वार्ते—नवीन शासन-विधान ग्रौर सरकारी नौकरियाँ—पब्लिक सर्विम कमीशन—विशेष वक्तव्य । ए० ६०१-६०९

चालीसवाँ परिच्छेद : न्यायालय

संघ-न्यायालय— इसका अधिकार-चेत्र— हाईकोर्ट – जजों की संख्या— जजों की नियुक्ति— जजों का वेतनादि – हाईकोर्ट का अधि-कार-चेत्र—रेवन्यू-कोर्ट—दीवानी अदालत— फौज़दारी अदालतें - अपील-पद्धति— पंचायतें। पृ० ६१० — ६२०

इकतालीसवाँ परिच्छेद : सरकारी आय-व्यय

ब्रिटिश भारत का हिसाब—केन्द्रीय सरकार का व्यय—(सन् १९४०-४१ के व्यय का अनुमान)—कर प्राप्ति का व्यय—रेल, आवपाशी, डाक और तार—सुद्र—सिविल शासन—सुद्रा, टकसाल

श्रीर विकित्तमय—सिविल निर्माण कार्य—सेना —विविध व्यय—
केन्द्रीय सरकार की श्राय—(सन् १९४०-४१ की श्राय का
श्रानुमान)—श्रायात-निर्यात कर —उत्पादन कर—श्राय कर—
नमक-कर—श्रक्षीय-कर—श्रन्य कर—रेल —डाक श्रीर तार—
सद—सिविल निर्माण कार्य—सुद्रा, टकसाल श्रीर विकित्त्य—सेना—
विविध श्राय - प्रान्तीय श्राय-व्यय—संयुक्तप्रान्त के व्यय का श्रनुमान—कर-प्राप्ति का व्यय—श्रावपाशी—शासन—न्याय—जेल—
पुलिस—स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा—शिक्षा—कृषि—उद्योग धर्ये—सिविल
निर्माण कार्य—संयुक्तप्रान्त की श्राय का श्रनुमान—मालगुजारी—
श्रावकारी—स्टाम्य—जंगल—रिजिस्ट्री—श्राय कर—श्रावपाशी—स्र र
—न्याय—जेल—पुलिस—शिक्षा—स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा—विविध
श्राय—विशेष वक्तव्य।

• ए० ६२२-६४३

बयालीसवाँ परिच्छेद : देशी राज्य

देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध—देशी राज्यों का आय-व्यय— भारत-सरकार का नियंत्रण—नरेशों का सम्मान—देशी राज्यों के अधिकार—भारत सरकार की नीति—जाँच कमीशन—नरेन्द्र मंडल— बटलर कमेटी और उसके बाद—देशी राज्यों का सुधार—संघ-शासन और देशी राज्य।

तेतालीसवाँ परिच्छेद: भारतवर्ष और राष्ट्र-संग प्राचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध—योरपीय महा-युद्ध और साम्राज्य-परिषद् में भारत—राष्ट्रसंघ, उसका संगठन और कार्य—राष्ट्रसंघ और भारतवर्ष—राष्ट्रसंघ के उद्देश्य की पूर्ति।

पृ० ३५६--६६४

प्रथम भाग

नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

पहला परिच्छेद

नागरिक शास्त्र का विषय

ह्याम प्राय: सुनते हैं कि यहाँ नागरिकता के भातों की बहुत कमी है, हमें श्राने नागरिक कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना चाहिए, एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। क्या हमने कभी यह विचार किया है कि नागरिकता का क्या अर्थ है, नागरिकों के कर्तव्य क्या-क्या है, नागरिक श्रिधकारों में किन-किन बातों का समावेश होता है ? श्रीर, हाँ, नागरिक किसे कहते हैं, उसका राज्य से क्या सम्बन्ध होता है ? हमें नागरिकता-सम्बन्धी विविध बातों का भली-भाँति अध्ययन श्रीर मनन करना चाहिए। हम श्राने नागरिक जीवन की सम्यक् उन्नति तभी कर सकेंगे, जब इम नागरिक शास्त्र के पठन-पाठन में दत्त-चित्त होंगे और इस शास्त्र की शिक्षाओं को कार्य रूप में परिण्त करेंगे।

अब इमारे लिए विचारगीय विषय यह है कि नागरिक-शास्त्र किसे कहते हैं। यह समभाने के लिए हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि नागरिक किसे कहते हैं। साधारण बोल-चाल में नागरिक का अर्थ नगर में रहनेवाला समभा जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो गांववाला न हो, नगर-निवासी हो। किन्तु राजनैतिक भाषा में ग्राम-वांसी या नगर-निवासी में कोई मेद नहीं माना जाता। राज्य के सब व्यक्ति उसके नागरिक माने जाते हैं, चाहे वे गाँव में रहते हों. श्रथवा कस्बे या शहर में; सबके श्रिधकार समान होते हैं, श्रीर सबको समान रूप से श्रपने कर्तव्य पालन करने होते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि बहुधा बड़े-बड़े कर्मचारी नगरों में रहते हैं. सरकारी दफ़र आदि नगरों में ही होते हैं, वहाँ शिक्षा, सभ्यता आदि का प्रचार गाँवों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए नगर-निवासी ग्राम-वासियों से प्राय: श्रधिक चतुर, शिच्ति श्रीर सभय होते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर विशेष अधिकार या सविधा का अधिकारी नहीं माना जा सकता कि वह नगर में रहता है। जाति, धर्म, या पेशे की विभिन्नता से भी नागरिकों में कोई मेद नहीं माना जाता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गाँव का हो या नगर का, पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति का हो, किसी भी घर्म या सम्प्रदाय का श्रनुयायी हो, श्रीर चाहे वह कोई भी पेशा या घंधा करता हो, अपने राज्य का नागरिक होता है। जो आदमी बाहर से आकर किसी राज्य में रहने लग जाते हैं, वे भी कुछ नियम-पालन करने पर वहाँ के नागरिकों में गिने जाने लगते हैं।

प्रत्येक नागरिक को राज्य में कुछ अधिकार होते हैं। नाग-रिक होने की हैिस्यत से लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें 'नागरिक अधिकार' कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को राज्य में ये अधिकार नहीं होते, उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं कहा जा सकता। अधिकारों के साथ प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। नागरिक बना रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन कर्तव्यों का पालन करते रहना आवश्यक है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति को उस राज्य का नागरिक कहा जाता है, जिसमें उसे निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं, और जहाँ उसे विविध कर्तव्य पालन करने होते हैं।

यह स्पष्ट है कि बिना राज्य के कोई नागरिक नहीं होता, नागरिक के लिए राज्य का होना श्रानिवार्य है; उसका अधिकारों और कर्तन्यों से श्रद्ध सम्बन्ध है।

राज्य — राज्य के विषय में विशेष विचार आगे किया जायगा।
यहाँ इतना जान लोना आवश्यक है कि देश और राज्य एक ही चीज़
नहीं है; सभी देशों को राज्य नहीं कह सकते। राज्य केवल उसी देश
को कहा जा सकता है, जहाँ मनुष्यों पर शासन करनेवाली संस्था
(सरकार) हो, जहाँ शान्ति और सुन्यवस्था हो, कोई आदमी उद्दरहतापूर्वक मनमानी न कर सके, जिसकी लाठी उसकी भेंस न हो।
प्रस्थेक राज्य की एक सुनिश्चित सीमा होती है, उसमें कुछ आदमी
रहते हैं और वहां शासन-प्रवन्ध होता है। प्रत्थेक राज्य की सरकार को अपनी सीमा के अन्दर शासन-व्यवस्था करने का पूर्ण
अधिकार होता है, प्रत्थेक नागरिक को राज्य-नियमों का पालन करना

होता है, कोई नागरिक राज्य के किसी आदेश या आजा को टाल नहीं सकता। राज्य अपनी आजाओं को बत-पूर्वक चता सकता है। वह किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होता।

अधिकार और कर्त्वय — जगर यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार और कर्त्वय होते हैं। अधिकारों और कर्त्वयों के विषय में विस्तार-पूर्वक विचार आगे करना है, यहाँ उनके उदाहरण-स्वरूप यह कहा जा सकता है कि नागरिकों को, निर्धारित आयु और योग्यता के होने पर, अपने राज्य के शासन-प्रवन्ध में मत देने तथा विविध राजनैतिक पद प्राप्त करने का अधिकार होता है। वह, जब तक दूसरों को हानि न पहुँचाए, अपने राज्य में स्वतंत्रता-पूर्वक रह सकता है, और अपना सब कार्य निर्विध कर मकता है। उसे अपनी जान-माल की रखा और उन्नति के साधन प्राप्त होते हैं। विदेशों में उसकी जान-माल की रक्षा का दायित्व उसके राज्य की सरकार पर रहता है। ये अधिकार ऐसे होते हैं कि राज्य के नागरिक न होनेवाले व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से, अनेक प्रयत्नों के बाद ही, मिलते हैं, अथवा मिल ही नहीं सकते।

इन अधिकारों के प्रतिफल-स्वरूप प्रत्येक नागरिक का अपने राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी रहता है, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। उदाहरखवत् उसे राज्य के नियमों या क़ानूनों का पालन करना चाहिए, उसे अन्य नागरिकों के साथ सहानुभूति और सहयोग का भाव रखना चाहिए, सरकारी कर या टैक्स देना चाहिए, जिससे सरकार का ख़र्च चले, और वह अपने आवश्यक कार्य कर सके। ज़रूरत होने पर नागरिक को सैनिक सेवा आदि का भी कर्तब्य पालन करना होता है। जब कोई नागरिक अपने कर्तब्य-पालन में जुटि करता है तो उसे राज्य के प्रचलित नियमों के अनुसार दंड दिया जाता है, उसे कुछ समय के लिए अपने थोड़े-बहुत अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है।

नागरिक शास्त्र— नागरिकों के, राज्य में क्या श्रिधकार होने चाहिए तथा उनके राज्य के प्रति श्रथवा एक दूधरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इस विषय का विवेचन करनेवाला शास्त्र 'नागरिक शास्त्र' कहलाता हैं। यह शास्त्र बतलाता है कि नागरिक जीवन का उद्देश्य या श्रादर्श क्या है, सामाजिक जीवन के विकास या उन्नति के लिए क्या-क्या बातें श्रावश्यक हैं। नागरिकों के परस्पर, एक दूधरे से, विविध प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, श्रार्थिक श्राह्म से यह ज्ञात होता है कि नागरिकों को इन चेत्रों में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके व्यवहारों पर कहाँ तक नियंत्रण रहना श्रावश्यक है, जिससे कोई दूधरे के उचित स्वार्थ-साधन में बाधक न हो, श्रीर सब को श्रिधक-से-श्रिधक सुख, श्रान्ति श्रीर स्मृद्धि प्राप्त हो। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य मनुष्यों को श्रव्हा नागरिक, श्रीर समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है।

नागरिक शास्त्र शब्द कॅगरेज़ी के 'सीविक्स' शब्द के लिए व्यव-हृत होता है। 'सीविक्स' का अर्थ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन है। वास्तव में नागरिक शास्त्र के ऋध्ययन का प्रधान विषय अर्थात् केन्द्र-बिन्दु नागरिक है। नागरिक शास्त्र में यह विचार किया जाता है कि नागरिक कौन है और उसका समाज में क्या स्थान है।

यह स्तप्ट ही है कि नागरिक शास्त्र का आवार मनुष्य का सामा-जिक जीवन है। मनुष्य अपिस में मिल-जुत कर रहते हैं, वे एकान्त-वासी जीवन व्यतीत नहीं करते: श्रकेले-श्रकेले रहने से मनुष्य का निर्वाह भी नहीं हो सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन वस्त्रादि को नाना प्रकार की वस्त्रश्रों की ज़रूरत होती है। इन सब पदार्थों को मन्द्य अकेले अपने ही प्रयत्न से तैयार नहीं कर सकता उसे दूसरों की सहायता और सहयोग की ऋावश्यकता होती है। एक श्रादमी को दूसरे की सहायता तभी मिलतो है, जब वह भी दूसरे को, उसकी श्रावश्यकता की पूर्ति में मदद देता है। इस प्रकार हम दूसरों की सहायता लेते हैं और उन्हें सहायता देते हैं। इसके बिना हमारी गुज़र नहीं हो सकती. फिर विकास और उन्नति की तो बात ही क्या। निदान, मन्द्यों को आपने निर्वाह एवं उन्नति और विकास के लिए मिल-जुलकर रहना होता है। यही नहीं, उन्हें शान्ति श्रीर सुन्यवस्था के लिए राज्य का निर्माण करना पड़ता है। जब तक राज्य का निर्माण नहीं हो जाता. समाज के व्यक्ति 'नागरिक' नहीं कहला सकते । समाज में रहने से मनुष्यों के परहार अनेक प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। नागरिक शास्त्र मनुष्यों को राज्य का श्रंग मानता हुआ उनके इन विविध पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करता है। 🗸

श्रध्ययन की श्रावश्यकता — राज्य के सम्बन्ध में, ऊपर जो लिखा गया है, उससे सम्बट है कि भारतवर्ष को वास्तव में राज्य नहीं कह सकते। कारण, इसमें राज्य के एक प्रधान लक्षण स्वाधीनता की अभी कमी है। तथापि साधारण व्यवहार में इसे राज्य मौना जाता है, और यहाँ के निवासी—पुरुष और स्त्रियाँ—'भारतीय नागरिक' कहे जाते हैं। नागरिकता के विचार से ऊँच-नीच, जाति-पाँति, या छूत-श्रळूत का कोई विचार नहीं होता; ब्राह्मण, च्त्री, वैश्य या श्रूद्ध का, शिया-सुन्नी मुसलमान तथा ईसाई पासों श्रादि का कोई भेद-भाव नहीं माना जाता। यही नहीं, योरपियन या श्रमरीकन श्रादि भी श्रपनी जन्मभूमि छोड़कर इस देश में बस जाने पर, भारतीय नागरिक बन जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के श्रविशासियों को तो श्रानी जन्मभूमि का त्याग न करने पर भी यहाँ नागरिक श्रविकार प्राप्त हो जाते हैं। कारण. श्रभी भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का श्रंग है।

अस्तु, जब हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें चाहिए कि हम (भारतवर्ष के) सुयोग्य नागरिक बनें, ठीकवैसे, जैसे कि एक विद्यार्थीं को सुयोग्य विद्यार्थीं, एक अध्यापक को सुयोग्य अध्यापक, और लेखक को सुयोग्य लेखक बनना चाहिए। सुयोग्य नागरिक बनने के लिए हमें नागरिक शास्त्र का भली भांति अध्ययन और मनन करना चाहिए तथा अपने व्यवहार में इस शास्त्र से मिलनेवाली शिचा पर अमल करना चाहिए। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का जान होता है। इस जान को प्राप्त कर जहाँ हम अपने कर्तव्य अब्द्री तरह पालन कर सकते हैं, वहाँ हम अपने अधिकारों का दूसरों के द्वारा अपहरण किया जाना रोककर उनकी सम्यक् रक्षा करने में भी अधिक समर्थ हो सकते हैं। जब तक यह नहीं होता, हमारी सब शिचा अधूरी या अपूर्ण है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र

शिक्षा का एक अत्यावश्यक अंग है। भारतवर्ष में जहाँ शिचा-सम्बन्धी अन्य कई-एक सुधारों की आवश्यकता है, नागरिक शास्त्र के पठन-पाटन की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

नागरिक शास्त्र का क्षेत्र-पहले वहा गया है कि नागरिक! के विविध अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये सामाजिक, धार्मिक, श्रीर राजनैतिक श्रादि कई प्रकार के होते हैं। नागरिक शास्त्र में इन सब का विचार होता है। यह शास्त्र बतलाता है कि नागरिक जीवन किस प्रकार उन्नत होता है, उसके लिए नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक चेत्रों में क्या वया कार्य करना चाहिए, जिससे एक नागरिक दूसरे नागरिक के उचित स्वार्थों में बाधक न हो, नागरिक जीवन में संघर्ष न हो. सब के विकास में समुचित सहयोग श्रौर सुविधा मिले । यद्यपि नागरिक शास्त्र में विशेषतया राजनैतिक दृष्टि से विचार किया जाता है, इसमें विचारणीय विषय नागरिक का समस्त जीवन है, वह जीवन सामाजिक भी है, श्रार्थिक भी है, धार्मिक भी है, श्रीर राजनैतिक भी । इसलिए नागरिक शास्त्र का चेत्र बहुत व्यापक है. उसमें नागरिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन और अनुशीलन किया जाता है। इसीलिए इस शास्त्र का अन्य अनेक शास्त्रों—विशेषतया सामाजिक विद्यात्रों— से घनिष्ट सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में, त्रागे दूसरे परिच्छेद में लिखा जायगा।



दूसरा परिच्छेद

नागरिक शास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्र

इससे मनुष्यों में राजनैतिक आर्थिक, नैतिक आदि विविध प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। उन सम्बन्धों के विषय में समय-समय पर अनेक तर्क-वितर्क तथा अनुभव हुए हैं और होते रहते हैं। उनके विवेचन से प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय का पृथक् शास्त्र बन गया है, और बनता जा रहा है, यथा— राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति-शास्त्र। ये कब सामाजिक शास्त्र हैं। नागरिक शास्त्र का आधार भी मनुष्यों का सामाजिक जीवन है, और इस प्रकार यह भी एक सामाजिक शास्त्र है। विविध सामाजिक शास्त्रों का एक दूसरे से धनिष्ट सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही है। आगे हम इस बात का कुछ विशेष विचार बरेंगे कि नागरिक शास्त्र का आद्य सामाजिक शास्त्रों से क्या सम्बन्ध है। राजनीति से सम्बन्ध— सामाजिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्यों का ट्हेर्य यह होता है कि सब सुख शान्ति से रहें, एक दूसरे

का सहयोग श्रीर सहायता प्राप्त कर सकें। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दुसरे के हित का भी ध्यान रखे, अपनी सुविधा के लिए या स्वार्थवश किसी को कष्ट या हानि न पहुँचाए। श्रतः समाज में ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि मनुष्यों के उन कार्यों तथा व्यवहारों पर प्रतिबन्ध रहे, जो सामाजिक जीवन के लिए श्रहित-कर होते हैं। इसके वास्ते शासन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है. श्रीर राज्य की स्थापना की जाती है। (इस विषय में विस्तार पूर्वक विचार श्रागे किया जायगा)। नागरिकों को राज्य के नियमों श्रीर कानूनों का पालन करना होता है। राज्य सब नागरिकों के सामू हिक हित और सविधा का ध्यान रखकर नागरिक अधिकार निर्धारित करता है। जो नागरिक दूसरों के अधिकारों पर आधात करता है, उनके श्रावश्यक श्रीर उचित कार्यों में विन्न उपस्थित करता है, उसे राज्य दंडित करता है, श्रथवा उसे सुधारने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र का, राजनीति-शास्त्र से बहुत सम्बन्ध है। राजनीति-शास्त्र राज्य के मूल, उसकी उत्पत्ति, उसके स्वह्तप तथा विकास श्रौर शासन सम्बन्धी सिद्धांतों का विवेचन करता है। नागरिक शास्त्र यह मान-कर चलता है कि राज्य की उत्पत्ति श्रीर विकास हो चुका है, उसका राजनीति से उस सीमा तक सम्बन्ध है, जहाँ तक उसमें नागरिकों ंके जीवन, उनके व्यवहार, श्रिधिकार श्रौर कर्तव्यों का विचार होता है। स्मरण रहे कि नागरिक शास्त्र में केवल सिद्धांतों का ही समावेश नहीं रहता, उसमें व्यावहारिक विषयों का भी विचार होता है।

अर्थशास्त्र से सम्बन्ध-अर्थशास्त्र वह विद्या है, जो मनुष्यों के घन उत्पन्न करने तथा उनका उपभोग करने श्रादि के प्रयत्नों पर विचार करता है। वह बालाता है कि मन्ष्य आनी विविध भौतिक त्रावश्यकता श्रों की पूर्ति किस प्रकार करता है, पदार्थों की उत्पत्ति, क्रय-विकय, उरमोग श्रादि के क्या नियम है। इस प्रकार यह शास्त्र एक प्रकार से मनुष्यों के जीवन-निर्वाह श्रीर भौतिक सख-समृद्धि को विद्या है। जब तक मन्द्यों की ऋार्थिक उन्नति न हो, नागरिक जीवन असम्भव है। फिर, नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध तथाव्यवहार को तो बात ही क्या । श्रतः श्रर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र से घनिष्ट सम्बन्ध होना स्गष्ट है। वास्तव में नागरिक शास का अध्ययन सम्य जीवन के लिए वैशा ही आवश्यक है, जैशा अर्थशास्त्र का। पुनः युद्यपि नागरिकों के लिए धनोटात्ति आदि आर्थिक कियाएँ अत्यावश्यक हैं. किसी भी आर्थिक कार्य में नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों की उपेचा नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्र में स्थान-स्थान पर यह विचार रखा जाना त्रावश्यक होता है कि कोई त्रार्थिक कार्य ऐसा तो नहीं है. जिससे नागरिक जीवन भली भाँति व्यतीत करने में बाधा उपस्थित हो। उदाइरणवत् , मिलों श्रीर कारख़ानों में पहले प्रतिदिन बारह-तेरह श्रीर इससे भी श्रधिक घएटे काम होता था, पर इससे श्रनेक नागरिकों श्चर्यात् मज़द्रों का स्वास्थ्य बिगड़ता था, श्वत: मज़द्रों के काम करने के घएटों पर नियंत्रण किया गया. श्रीर यह नियम किया गया कि उनसे सप्ताह में ६ घएटे और एक दिन में ११ घएटे से अधिक काम न लिया जाय, चाहे इससे घनोत्पत्ति कम ही हो।

पुनः श्राथिक परिस्थितियों का नागरिक श्राधिकारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, नागरिक शास्त्र का आदेश है कि न्याय सब के लिए निस्पक्ष होना चाहिए, और न्यायालय सब के लिए समान रूप से खुले रहने चाहिए। परन्तु करूपना करों कि एक श्रमीर और एक ग्ररीब श्रादमी का भगड़ा है; श्रमीर श्रादमी श्रपने पैसे के बल से श्रच्छे बढ़िया वकील कर सकता है, और खूब खुर्च करके श्रपने पक्ष का, कानून की हिट से, समर्थन कर सकता है, जब कि गरीब श्रादमी ऐसा करने में श्रसमर्थ रहता है। परिणाम-स्वरूप जब किसी गरीब नागरिक का श्रमीर से भगड़ा होता है तो गरीब को न्यायालय जाने का साहस ही नहीं होता; और, यदि वह साहस भी करता है तो उसे यथेष्ट सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार श्रथंशास्त्र के द्वारा जनता की श्रार्थिक परिस्थित के ठीक होने की दशा में ही नागरिक श्रास्त्र श्रीक करों का ठीक उपयोग हो सकता है। इससे नागरिक शास्त्र और श्रथंशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध स्वतः सिद्ध है।

नीति-शास्त्र से सम्बन्ध नीति-शास्त्र मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों को इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि उसका कौनसा कार्य उचित है, और कौनसा अनुचित। यह मनुष्य के स्दृष्यवहार या सदाचार का विचार करता है, और आदर्श या सिद्धान्त स्थिर करता है। इस प्रकार इस शास्त्र का कार्य नागरिक शास्त्र के कार्य की ही तरह का है। हाँ, नागरिक शास्त्र मनुष्य के उन्हीं कर्तव्यों का विवेचन करता है जो नागरिक की हैस्यित से, उसके लिए आवश्यक हैं। इमारे बहुत से कर्तव्य ऐसे हैं जो इमें सामाजिक प्राणी होने के नाले

भी पालन करने चाहिए और नागरिक होने के कारण भी। उदाद्रिरणवत् हमें अपने पड़ोिंछयों तथा नगर या आमशिंखों के प्रति
प्रेम, सहानुभृति और उदारता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कोई
कष्ट हो तो उसे दूर करने में सहायक होना चाहिए तथा उनकी
उन्नति और सुख की वृद्धि में सहयोग प्रदान करना चाहिए।
इस प्रकार के कर्तव्यों का विचार नीति-शास्त्र में भी होगा और
नागरिक शास्त्र में भी। दोनों ही शास्त्र हमें इन कर्तव्यों के पालन
करने का आदेश करेंगे।

नीति शास्त्र का च्रेत्र अधिक व्यापक है, उससे नागरिक शास्त्र को अपना च्रेत्र अधिक विस्तृत करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरणवत् पहले पाश्चात्य देशों में प्रायः नागरिक के कर्तव्य-कार्य उसके राज्य तक ही परिमित माने जाते थे; बहुत से लेखक नागरिक शास्त्र में इतना ही विचार करते थे कि नागरिक के अपने राज्य में कर्तव्य तथा अधिकार क्या हैं। परन्तु अब नीति शास्त्र की भौति, नागरिक शास्त्र में नागरिक के कर्तव्यों का च्रेत्र उसके राज्य के बाहर भी दर्शाया जाता है। जिस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के कर्तव्याकर्तव्यों का विचार राज्य की सीमा के अन्तर्गत ही नहीं करता, वरन् बतलाता है कि मनुष्य को, वह चाहे जहां भी हो, अप्रुक्त कार्य करने चाहिए और अप्रुक्त नहीं करने चाहिए, उसी प्रकार नागरिक शास्त्र मी अब नागरिक के सामने अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य और अधिकारों की बात रखता है। वह बतलाता है कि उन व्यक्तियों के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जो इसारे राज्य के नागरिक न होकर किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, अथवा

जो किसी भी राज्य के नागरिक नहीं है। एक राज्य के नागरिक की, दूसरे राज्य के नागरिक के प्रति कोई दुर्भावना न होनी चाहिए, वरन् यथा सम्भव उसके साथ भी सहानुभृति और प्रेम का व्यवहार किया जानाचाहिए। इस प्रकार नागरिक शास्त्र भी विश्व-वंधुत्व का आदर्श सामने रखते हुए, नागरिकों को विश्व-नागरिक बनने का आदेश करता है। निदान, नागरिक शास्त्र और नीति शास्त्र का घनिष्ट सम्बन्ध सप्ट है।

इतिहास से सम्बन्ध-प्रचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य श्रनेक परिस्थितियों में रहा है । देश-काल के अनुसार उसकी सामाजिक अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न रही है। किसी सामाजिक संगठन में उसे अधिक सफलता मिली, और किसी संगठन की दशा में उसे विफलता ही अधिक प्राप्त हुई है। इतिहास से हुमें मनुष्य समाज के भृतकालीन विविध संगठन, कार्यों तथा श्रनुभवों का ज्ञान होता है। इस समग्री के आधार पर नागरिक शास्त्र के नियमों का विचार किया जाता है, श्रीर इससे नागरिकता सम्बन्धी बातों पर श्र-छा प्रकाश पडता है। इतिहास हमें बताता है कि जब अमुक प्रकार का नागरिक नियम प्रचलित किया गया था तो उसमें क्या कठिनाइयाँ या बाधाएँ उपस्थित हुई थीं, श्रीर उनमें किस प्रकार के परिवर्तन करने की श्रावरयकता प्रतीत हुई थी। उदाइरणवत्, इमें इतिहास से पता लगता है कि प्राचीन यूनान श्रीर रोम श्रादि में बहुत समय तक राज्य की एक बड़ी जन-संख्या नागरिक अधिकारों से वंचित रही। इन राज्यों में जनता का एक बड़ा भाग दासों या गुलामों का होता था.

इन्हें साधारण्तया नागरिक नहीं माना जाता था, केवल विशेष दशाओं में ही किसी दास को रियायत या कृषा के रूप में नागरिकता प्रदान की जाती थी। इस प्रकार राज्य के बहुत से आदिमियों को विकास का अवसर ही न मिलता था। इस से होने वाली हानि बहुत समय के बाद लोगों के ध्यान में आयी। क्रमशः दास-प्रथा का लोप हुआ, और बहुत से आदिमियों को नागरिक अधिकार मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हाँ, अब भी अनेक स्थानों में प्रतिज्ञा-वद्ध कुली-प्रथा से अनेक आदमी दासों का-सा ही जीवन विता रहे हैं। कहीं-कहीं मज़द्रों का जीवन भी कुछ अञ्छा नहीं है। आशा है, हतिहास से शिद्या लेकर, इसमें सम्यक् सुधार किया जायगा।

दासों के ऋति रिक्त अनेक स्थानों में िहत्रयों को भी पहले नागरिकता से वंचित रखा जाता था। धीरे-धीरे, चिरकालीन संघर्ष के बाद ही िक्रयों ने अपना नागरिक पद प्राप्त किया है, और अनेक राज्यों में तो अभी तक इस कार्य में यथेष्ट सफलता नहीं मिल पायी है। भारतवर्ष में, इतना उद्योग होने पर भी कितने ही आदमी हरिजनों आदि को नागरिक अधिकार देने में अत्यन्त अनुदार हैं। यहाँ हिन्दू मुसलिम प्रश्न भी नागरिकता की दृष्टि से बहुत विचारणीय है। हमारे सामने जो नागरिक समस्याएँ विद्यमान हैं, उनका जन्म भूतकाल में हुआ है, और अब उन पर विचार करने और उन्हें भली भौति हल करने के लिए, नागरिक नियम बनाने या संशोधन करने के वास्ते इतिहास वर्णित अनुभवों से बहुत सहायता मिल सकती है। इस प्रकार इतिहास और नागरिक शास्त्र में कितना

सम्बन्ध है, यह विदित हो जाता है।

नागरिक शास्त्र श्रोर कानून — नागरिक शास्त्र बतलाता है कि नागरिकों के अमुक-श्रमुक श्रिष्ठकार हैं। परन्तु उन श्रिष्ठकारों की रज्ञा सम्यक् कानून बिना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए नागरिकों को श्रीषकार है कि सार्वजनिक सड़कों, कुश्रों एवं स्कूलों श्रादि का उपयोग करें। पर इस श्रिष्ठकार की समुचित रज्ञा तभी हो सकती है, जब कोई ऐसा क़ानून विद्यमान हो कि जो न्यकि (गुंडा या बदमाश) किसी नागरिक के उपर्युक्त कार्य में विझ बाधा उपस्थित करेगा, उसे श्रमुक दंड दिया जायगा। ऐसे क़ानून के श्रमाव में, उस श्रिष्ठकार का उपयोग न हो सकेगा; फिर उस श्रिष्ठकार का महत्व ही क्या रह जायगा।

कानून द्वारा श्रिधिकारों की मर्यादा भी निश्चित की जाती है। उदाहरणवत् यदि नागरिकों को सड़कों के उपयोग का श्रिधिकार है, तो इसका यह श्राशय नहीं कि इम सड़कों पर इस प्रकार चलें श्रिथवा गाड़ी श्रादि ले जायँ या ऐसा सामान पटक दें, जिससे दूसरे नागरिकों को सड़क का उपयोग करने में बाधा उपस्थित हो। ऐसी बातों को ध्यान में रखकर श्रावश्यक क़ानून बनाये जाते हैं।

क्रानून लोगों के नागरिक जीवन तथा व्यवहार में सुविधाएँ उत्पन्न करता है। साथ ही नागरिक परिस्थितियाँ भी क्रानून पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें लक्ष्य में रखकर नये क्रानून बनाये जाते हैं तथा पुराने कानूनों का संशोधन होता है। उदाहरणवत् दास-प्रथा हटाने, मज़दूरों की दशा में सुधार करने, स्त्रियों को नागरिकता प्रदान करने, हरिजनों को नागरिक अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक क़ानून बने तथा बदले हैं। इस प्रकार नागरिक शास्त्र और क़ानून का सम्बन्ध स्पष्ट है। यहाँ उदाहरण-स्वरूप थोड़ी-सी बातों का उल्लेख किया गया है, अन्य वार्ते पाठक स्वयं विचार सकते हैं।

तीसरा परिच्छेद सामाजिक जीवन

त्तुहले इस बात का उल्लेख हो चुका है कि नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विद्या है। इस शास्त्र की रचना इसीलिए हो सकी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। इस परिच्छेद में मनुष्यों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ, विशेष विचार किया जाता है।

सामाजिक जीवन की आवश्यकता—मनुष्य स्वभाव से हो मिलनसार है, विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर, उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। उसे आतम-रक्षा तथा जीवन-निर्वाह के लिए भी समाज में रहना ज़रूरी है। फिर मनुष्य विकास-शील है। उसमें अनेक कार्य करने तथा सीखने की चमता है। उसका दिमाग सदैव कुछ-नकुछ करने की बात सोचता रहता है, यथा खेलना कूदना, किसी से प्यार या सहानुभूति करना, कुछ खोज या आविष्कार करना आदि। ये बातें सामाजिक जीवन में ही सम्भव हैं।

यदि कोई मनुष्य किसी स्थान पर अवेला रहे, जहाँ दूसरे आदमी न हों, तो उसे अपना वह स्थान बड़ा सुनसान प्रतीत होगा। कोई उससे बात-चीत करने वाला न होगा, उसे अपना जी बहलाने का कोई साधन न मिलेगा। इस दशा में उसे अपना समय व्यतीत करना बहुत कठिन हो जायगा। जब वह देखेगा कि अनेक पत्ती इकट्ठे रहते और एक-दूसरे के साथ हर्ष और प्रसन्नता-पूर्वक चहचहाते हैं तथा कितने ही पशु भुगड़ बना कर रहते हैं, इकट्ठे घूमते-फिरते और दौड़ते-भागते हैं तो उसका मन अपने एकान्तवास से व्याकुल होने लगेगा। वह चाहता है कि मेरे भी कुछ संगी-साथी हों, मैं भी अपनी मंडली में रहकर खुशी-खुशी खेलूँ-कूदूँ। इस प्रकार वह स्वभाव से सामाजिक जीवन का अभिलाषी है।

श्रव्छा, यदि जी लगने की बात छोड़ भी दी जाय, तो श्रपनी श्रा-वश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए भी मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है। छोटी उम्रवाले (बच्चे) तो श्रसहाय होते ही हैं, बड़ी उम्र के ब्यक्ति को भी श्रकेले दुवेले रहने की दशा में जङ्गली जानवरों का बड़ा भय रहता हैं, उनसे श्रपनी रक्षा करने के लिए उसे दूसरों की सहायता और सह-योग की श्रावश्यकता होती है। इस प्रकार श्रात्म-रक्षा का भाव उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है।

इसी प्रकार भरण-पोषण का विषय है। प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, उसका रहन सहत सहुत सादा और सरल था। उसकी आवश्यकताएँ कम थीं;तथापि उसे भूख-प्यास सदीं, गर्मी तो लगती ही थी। उसे भोजन बस्त्रादि की आवश्यकता होती थी। पानी बहुर्त से स्थानों में, निद्यों या फरनों में अनायास मिल भी जाता था; तो भी भोजन का हर जगह मिलना तो किंदन ही था। प्रारिम्भक अवस्था में आदमी कन्द-मूल फलादि खाता था, या पशु-पित्वयों को मार कर उनके मांस से अपना निर्वाह करता था। वृद्धों की छाल, पत्ते या पशुआों का चर्म ओड़कर मनुष्य सर्दी से बचने का प्रयत्न करता था। जब एक जगह ये पदार्थ समाप्त हो जाते तो दूसरे ऐसे स्थान की खोज की जाती, जहाँ ये चीज़ें सुगमता से मिल सकतीं। सुनसान भयानक जंगलों में ऐसे स्थान की खोज करना और वहाँ उहरना तथा शिकार करना अकेले-दुकेले आदमी के बश की बात नहीं थी। इसलिए भी उसे एक-दूसरे के साथ मिल कर रहना पड़ता था।

कमशः श्रादिमियों को यह जात हुआ कि कुछ पशु ऐसे हैं, जिन्हें मारकर खाने की अपेक्षा, पाल कर रखना अधिक लामदायक है। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी श्रादि को पाल लेने से उनसे बहुत समय तक दूध मिल सकता है, घोड़ा, गधा, बैल, भैंसा आदि से सवारी का तथा माल ढोने का काम लिया जा सकता है। इस विचार से मनुष्यों ने इन जानवरों को पालना आरम्भ किया। परन्तु अब आदिमियों को, अपने भोजन के अतिरक्त, इन पशुओं के चारे के लिए भी, उपयुक्त भूमि की खोज करने की आवश्यकता होने लगी। कुछ मनुष्यों की एक-एक टोली रहती, जो अपने पशुओं सहित घूमवी रहती। जहाँ-कहीं उसकी आवश्यकता के पदार्थ मिल जाते, वहाँ वह टोली कुछ दिन उहर जाती, पीछे फिर नये स्थान के लिए प्रस्थान कर देती।

कृषि अवस्था-धारे-धारे मनुष्यों ने बीज बोने श्रीर खेती करने की विधि जान ली। इससे उन्हें अपने लिए, तथा अपने पशुओं के लिए भोजन-सामग्री श्रव्छे बड़े परिमाण में मिलने की श्राशा हुई। अब वे अधिकाधिक कृषि करने लगे। कृषि-कार्य ने मनुष्यों की श्रावारागर्दी कम कर दी। श्रव उन्हें खेती के लिए जमीन तैयार करने, जोतने, बोने, निराई, सिंचाई श्रादि का कार्यथा। इसके बाद फसल पकने तक, उसकी जंगली जानवरों से रदा करना, श्रौर अपन्त में फसल काट कर घर लाना था। इन कामों को छोड़कर श्रादमी बहुत समय के लिए दुसरे स्थानों में नहीं जा सकते थे। कृषि ने उन्हें एक स्थान पर रहने को वाध्य किया। जब कुछ श्रादमी खेती करनेवाले द्वो गये तो उनके समृह का एक स्थायी निवास-स्थान होता गया; (इस समय भी कहीं-कहीं कछ श्रादमी खेतों ही में रहते हैं)। खेती करनेवालों को दूसरे मनुष्यों की सहायता की आवश्यक-ता बहुत होती ही है। खेती में काम आनेवाले पशुश्रों को चराने तथा उनकी देख-भाल के लिए किसान को ऋपना कोई सहायक चाहिए: फ़रल की चौकसी करने तथा फ़रल पकने पर उसे काटने छादि के लिए भी दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। फिर, खेती के विविध श्रौज़ारों को बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए कछ कारीगरों का भी पास रहना उपयोगी होता है। इस प्रकार अधिका-धिक श्रादमी इकट्रे तथा स्थायी रूप से एक ही जगह रहने लगे।

क्रमशः ऐसा हुत्रा कि जिस व्यक्ति ने जिस भूमि को जोता-बोया, उसी व्यक्ति ने उस पर श्रपना विशेष श्रिधकार जमाना शुरू किया। भूमि लोगों की व्यक्तिगत सम्मित होने लगी। पर पहले, उसके काफ़ी परिमाण में होने तथा जन-संख्या कम होने से उसके सम्बन्ध में विशेष भगड़ा होने की नौबत न आती थी। यही बात अनादि अन्य पदार्थों के विषय में थी।

याम-अवस्था — बहुत से आदिमियों का इकट्ठे एक ही स्थान में रहने से गाँव या खेड़ों का निर्माण हुआ। आरम्भ में प्रत्येक गाँव प्रायः स्वावलम्बी होता है, उसके निवासी अपनी आवश्यकताओं के पदार्थ मिल-जुल कर स्वयं बनाते हैं, वे बाहर के आदिमियों के आश्रित नहीं रहते। अधिकतर आदमी खेती करनेवाले होते हैं, कुळ मज़दूर उन्हें सहायता करते हैं। (ये मज़दूर सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से कृषकों की बरावरी के होते हैं; ऐसी हीन दशा के नहीं होते, जैसे आधुनिक पूँजीवाद के युग के समभे जाते हैं)। कारीगर खेती आदि के लिए उपयोगी वस्तुएँ बनाते तथा सुधारते हैं। इस अवस्था में प्रायः पदार्थों का अदल-बदल होता है, सद्रा द्वारा कय-विकय नहीं। मज़-दूरी भी जिन्स या पदार्थों में दी जाती है, नक़द वेतन नहीं दिया जाता।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारतवर्ष की प्राचीन ग्राम-संस्थाएँ हैं, जो समय के अनेक उलट-फेर होते हुए भी, आने यहाँ आंगरेज़ों के आने के समय तक, अपनी स्वतंत्रता तथा स्वावलम्बन बहुत कुछ बनाये हुए थीं, और, अब भी किसी-न-किसो रूप में अपनी पूर्व महत्ता की सूचना दे रही हैं। पहले, जो वस्तुएँ गाँव में नहीं बनती थीं, उन्हें गाँववाले तीर्थ-यात्रा के स्थानों या राजधानी आदि के नगरों में जाने के समय ले

आते थे, और नगर-निवासी आपनी कारोगरी के लिए कचा माल देहातों से ले लेते थे। आज कल तो गाँव-गाँव में, दूर-दूर के नगरों के ही नहीं, आन्य देशों के बने हुए पदार्थों ने प्रवेश कर लिया है।

कारीगरी अवस्थाः; नगर-निर्माण - कृषि-अवस्था में मतुष्य की मुख्य आवश्यकताएँ भोजन-वस्त्र की होतो है। ये आवश्यक-ताएँ सदैव बनो ही रहती है। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता है. समाज का विकास होता जाता है, भोजन-बस्त्र के लिए नये-नये पदार्थें। की ज़रूरत होतो जाती है: स्राज दिन हमारे खाद्य पदार्थी तथा पहनने के कपड़ों के कितने भेर हो गये हैं! पुनः अन्य आवश्यकताएँ भी बढ़ती ही रहती हैं। क्रमशः मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समस्त वस्तुत्रों की तुलना में भोजन-वस्त्र का परिमाण नगएय-सा हो जाता है। ये वस्तुएँ जिन कच्चे पदार्थों से बनती हैं, वे तो कृषि दारा ही उत्तन होते हैं, परन्तु उनकी तैयारी में पीछे और भी विशेष अम करना होता है। इन वस्त्र में को शिल्मी या कारीगर बनाते हैं। फिर, इन बहाुओं के अहल-बहल तथा क्रय-विकय का काम भो बढ़ जाता है। इस प्रकार शिलिनयों, कारीगरों और दुकानदारों आदि की संख्या बढ़तो जातो है, यहां तक कि कुछ बस्तियाँ ऐसी भी हो जाती हैं, जिनकी त्रधिकतर जन-संख्या इन लोगों तथा इनके त्राश्रितों श्रादि की होती है। ये बस्तियाँ कस्वा, नगर या शहर कहलाती हैं। इनके निवा-िषयों की श्रत्र, कशास, गता श्रादि कच्चे पदार्थों की श्रावश्यकताएँ गाँव वाले पूरी करते हैं, श्रीर ये श्रपने तथा गांव वालों के लिए कपड़ा, खांड़, नमक तथा श्रीज़ार श्रादि बनाते हैं। श्रस्तु, नगरों या शहरों में सामार्जिक जीवन की स्नावश्यकता पहले से अधिक हो जाती हैं।

श्रव तो कल-कारख़ानों का जमाना है। हमारी श्रावश्यकता की श्रनेक वस्ट एँ कारख़ानों में तैयार होती हैं। एक-एक कारख़ाने में हज़ारों श्रादमी काम करते हैं। बड़े-बड़े श्रौद्योगिक नगरों की जन-संख्या लाखों की होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के श्रकेले दुकेले रहने की बात ही क्या, श्रव तो उनका श्रौर भी श्रिधक संख्या में, इकट्ठा मिलकर एक जगह रहना श्रीनवार्य हो गया है।

सामाजिक जीवन पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव—
सामाजिक जीवन के प्रारम्भ श्रीर विकास के सम्बन्ध में उपर्यु क वातें
जान लेने के साथ, यह भी विचार कर लेना चाहिए कि भौगोलिक
स्थित का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले कहा जा चुका है कि
मनुष्य की प्रारम्भक श्रावश्यकताएँ जीवन-निर्वाह सम्बन्धी होती हैं।
जहाँ इन श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति सुगमता से हो जाती है, वहाँ ही
वह स्वभावत: रहना चाहता है। शिकारी जीवन व्यतीत करते हुए
श्रादमी उन स्थानों में श्राधक रहता है, जहाँ उसे शिकार के लिए
पश्रु-पक्षी श्राधक मिलें। कृषक जीवन में उसे ऐसी मूमि चाहिए, जो
खूव उपजाक हो, जो कॅकरीली-पथरीली, या वंजर न हो। कलकारखानों के युग में ऐसी मूमि की माँग होती है, जो उनके कारोबार
के लिए श्रच्छे मौके की हो, जहाँ लोहा, कोयला श्रीर पेट्रोल श्रादि
मिलता हो श्रीर जहाँ बड़े-बड़े श्रीद्योगिक नगरों के निर्माण की

प्राचीन काल में अनेक नगर निदयों के किनारे बसाये गर्थे। इसका कारण यह है कि पहले निदयों से सिंचाई तो होती ही थी, इसके अति-रिक्त ब्यापार के लिए माल लाने-लेजाने का बहुत काम लिया जाता था। अब यह काम बहुत-कुछ रेल-मोटर आदि द्वारा होता है; यद्यपि कृषि-कार्य के लिए अब भी निदयों की उपयोगिता बनी हुई है। किर निदयों से नगरों को एक विशेष प्रकार का सौन्दर्य या शोभा मिल जाती है। प्राकृतिक हर्यों के प्रेमी तथा मिक-भाव वाले अनेक आदमी नदी के किनारे बसना पसन्द करते हैं। प्राचीन काल में, जब आकाश-मार्ग से युद्ध नहीं होते थे, शत्रु को बड़ी-बड़ी निदयों के किनारे बसे हुए नगरों पर आक्रमण करना किंदन होता था। इसलिए राजा महाराजा अपनी राजधानी यथा-सम्भव निदयों के पास बनाते रहे हैं। इस प्रकार आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कारणों से निदयों के किनारे के नगरों का महत्व बहुत रहा है।

वर्षा का भी मनुष्यों की आवादी पर वड़ा असर पड़ता है। जहाँ वर्षा उचित मात्रा में तथा आवश्यकता के समय होती है, वहाँ पैदा-वार खूब होती है, और फल-स्वरूप आवादी घनी रहती है। इसी प्रकार जिन स्थानों का जल-वायु अच्छा होता है, वहाँ भी आवादी घनी होने की प्रवृत्ति होती है। गर्भी-सदीं का भी लोगों के निवास पर बड़ा प्रभाव पड़ता है; कारण, प्रायः गर्म देशों में पैदावार अच्छी होती है, और लोगों को भोजन-वस्त्र आदि की आवश्यकता कम होती है। ये स्थान प्रायः कृषि-प्रधान होते हैं, इनमें ग्राम या देहात अधिक होते हैं। इसके विपरीत, ठंडे देशों में पैदावार कम होती है, अधिकतर

अवदमी शिल्य या कारीगरी आदि से अपना निर्वाह करते हैं। इन भू-भागों में प्रायः नगरों या शहरों की अधिकता होती है।

इस प्रकार भूमि के भेद, निदयों, वर्षा, जल-नायु तथा सर्दी-गर्मी आधादि के रूप में भौगोलिक स्थिति का लोगों के सामाजिक जीवन पर विविध प्रकार से प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक जीवन का आधार; सहकारिता— उग्युंक्त कथन से स्वष्ट है कि मनुष्यों के निर्वाह करने अथवा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की पद्धति समय-समय पर बदलती रही है। परन्तु प्रत्येक अवस्था में मनुष्य को दूसरों के साथ मिलकर रहने की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है। अकेले-दुकेले रहना उसकी प्रकृति के विरुद्ध तो था ही, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से भी उसके लिए सामाजिक जीवन व्यतीत करना अनिवार्य है।

सामाजिक जीवन का आश्यय ही यह है कि मनुष्य एक दूसरे से मित्तकर रहें, एक दूसरे की सहायना करें और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करें। कोई मनुष्य केवत आनी बनायी वस्तुओं से ही आमा निर्वाह नहीं कर सकता, उसे दूसरों की बनायी हुई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और वे उसे तभी मिलती हैं, जब वह दूसरों को अननी बनायी वस्तुएँ भी बदले में दे। मनुष्यों ने बहुत अनुभव के बाद अमिनिमाग के सिद्धान्त का आविष्कार तथा विकास किया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ ख़ास-ख़ास वस्तुएँ या उनके आंग बनाते हैं। बहुत से व्यक्तियों के ऐसे सहयोग से अनेक वस्तुएँ सुगमता-

पूर्वक बनती हैं, और इस प्रकार समाज की आवश्यकताएँ पूरी करती हैं।

यह तो अार्थिक जीवन की बात हुई। इसी प्रकार अन्य चेत्रों का विचार किया जा सकता है। बहुवा हम भूल जाते हैं कि हमारे सामा-जिक जीवन का श्राधार हो सहयोग श्रथना सहकारिता है। जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे समानता श्रौर सहानुभृति का व्यवहार होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह अन्याय है, और इसका परिणाम स्वयं इमारे जिए भी बहुत ऋहितकर हो सकता है। कल्पना कीजिए कि जिन व्यक्तियों को समाज में नीच या निम्न जाति का समका जाता है, उनका सहयोग न रहे तो बड़े या प्रतिष्ठित कहे जानेवाले आदिमियों का जीवन कितना कष्टमय हो जाय। भारतवर्ष में घोबी, नाई, मेहतर, चमार त्रादि की गणुना निम्न जातियों में की जाती है, पर इनके बिना कितने आदिमियों का काम चलता है! अस्त, यह स्वष्ट है कि हमें एक-दूसरे के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। पारस्वरिक सहयोग के बिना मनुष्यों का जीवन घारण करना किंदन क्या, असम्भव है। जितना सहकारिता के विद्धान्तों का अधिक उपयोग होगा. उतना ही सामाजिक जीवन अधिक उन्नत तथा विकसित होने में सहायता मिलेगी।

समाज और व्यक्ति—समाज व्यक्तियों का ही बनता है; विना व्यक्तियों के समाज अधितत्व में नहीं आता। और, व्यक्ति की आवश्यकताएँ समाज में ही पूरी होती हैं। समाज के विना व्यक्ति का जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता, उसके विकास की तो बात ही अलग रही। इस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के आश्रित हैं।

एक की उन्नित में दूसरे की उन्नित या उत्थान है। समाज जितना उन्नत होगा, उतना ही वह व्यक्ति की उन्नति श्रीर विकास के लिए र्क्राधक सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा: श्रौर व्यक्ति जितना श्रधिक योग्यः श्रीर समर्थ होगा. उतना ही वह श्रन्य व्यक्तियों की, श्रीर इसलिए समाज की, उन्नति में अधिक सहायक हो सकेगा। यों तो जब व्यक्ति समाज का श्रंग है, किसी व्यक्ति के उन्नति करने से समाज के उस एक अंग की उन्नति हो ही जाती है, परन्तु किसी व्यक्ति को इसी से संतृष्ट न हो जाना चाहिए। उसे अपने सामर्थ्यानुसार समाजः की सेवा और उन्नित में भरएक योग देना चाहिए। अपने माता-पिता से. अपने ग्राम और नगर-निवासियों से, अपने देश-बन्धुओं से और अनेकः दशाओं में अन्य देशवालों से भी, इस प्रकार, सनाज से हमें विविध सुविधाएँ मिलती हैं। उनका हम पर बहुत ऋण है। अतः हमें उस ऋण को चुकाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ! समाज के भिन्न-भिन्न समृहों के प्रति हमारे क्या-क्या कर्तव्य है, यह ब्यौरेवार आगे प्रसंगा-नुसार बताया जायगा। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए ही न होना चाहिए, हमारा दूसरों के प्रति बहुत उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करना चाहिए। हम अपनी उन्नति अवश्य करें. पर उसमें समाज के हित का उद्देश्य भी रखें। हम ऐसा कार्य कदापि न करें, जिससे दूसरों की हानि हो, चाहे उससे हमारा कुछ लाभ ही क्यों न होता हो।

इसी प्रकार समाज का भी कर्तब्य है कि वह व्यक्ति के विकास के

लिए श्रिषक से श्रिषक साधन जुटावे। व्यक्ति जितना उत्तत होगा उतना ही वह समाज की उन्नित में सहायक होगा, वह समाज की प्रतिष्ठा श्रीर उसका गौरव बढ़ायेगा। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक श्रादि महानुभावों ने भारतीय समाज को श्रन्य देशों की दृष्टि में कितना ऊँचा उठाया है, श्रीर महात्मा गांधी, पं० मदनगोहन मालवीय तथा पं० जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों से समाज का दूर-दूर कितना श्रादर हो रहा है, यह सर्व-विदित है। इसी प्रकार रूस के टाल्स्टाय, इटली के मेजिनी, जर्मनी के कार्लमार्क्स, श्रमरीका के वाशिंगटन, इंगलैंड के सर जान ब्राइट, ग्लेडस्टन, डिसरेली श्रीर विलियम डिग्वी, मिश्र के जगलुल पाशा, श्रक्तग्रानिस्तान के श्रमानुल्ला, तथा टर्की के मुस्तफा कमालपाशा श्रादि महानुभावों ने श्राने-श्रपने समाज का संसार में सिर ऊँचा किया है। यही नहीं; उन्होंने श्रनेक कठिनाइयौं सहन करके जो श्रपना महान् कर्तव्य पालन किया है, उससे मानव समाज के लिए उच्च श्रादर्श उपस्थित हुआ है।

हाँ, यह अवश्य चिंतनीय है कि प्रायः तत्कालीन समाज अपने महान् व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करता, चाहे पीछे उनको कितनी ही अद्धाञ्जलियाँ अपिंत की जायँ। महात्मा ईंसा का स्ली पर चढ़ाया जाना, सुकरात को ज़हर पिलाया जाना, अमानुल्ला का देश बहिष्कृत होना समाज की कैसी टीका है! इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पढ़ा है। आवश्यकता है कि समाज अपने पथ-प्रदर्शक व्यक्तियों का उचित सम्मान करे; सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सदाचार त्यादि की परिस्थितियों तथा सुविधाओं की व्यवस्था हो, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा न हो, और प्रत्येक देशा में गांधी, टालस्टाय और वाशिगटन जैसी आत्माएँ अधिक-से-अधिक संख्या में आकर मानव-हित-साधन में योग दें।



चोथा परिच्छेद व्यक्ति श्रोर समूह

क्ष्महों की आवश्यकता और निर्माण — मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। समाज के बहुत से अंग हैं, प्रत्येक अंग को समृह कह सकते हैं। ज्यों ज्यों सामाजिक जीवन का विकास होता है, मन्ष्य सामाजिक जीवन में प्रगति करता है, त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, यह पहले बताया जा जुका है। और, जैसे-जैसे आवश्यकताएँ बढ़ती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न समृहों की संख्या मी बढ़ती जाती है। आरम्भ में आवश्यकताएँ बढ़त परिमित होती थीं, तो ये समृह भी इने-गिने ही होते थे। अब मनुष्य की मौतिक तथा अभौतिक, शारीरिक और मानसिक आदि आवश्यकताएँ असंख्य हैं, तो इन समृहों की संख्या भी अनन्त है।

पहले बच्चे का पालन-पोषण किये जाने की श्रावश्यकता होती हैं। इस कार्य को करने के लिए एक समूह का निर्माण होता है,

जो परिवार या कुटुम्ब कहलाता है। परिवार का स्वरूप देश काल के अनुसार चाहे जितना भिन्न-भिन्न प्रकार का रहा हो, पर यह समूह सदैव रहा है। बालकों को शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए दूसरा समूह बनता है, जिसे पाठशाला, स्कूल, या विद्यालय आदि नाम दिया जाता है। मनुष्यों को अन्न की आवश्यकता होती है, अन्न पैदा करने का कार्य जो समूह करता है उसे किसान कहा जाता है। जब समाज में पदार्थों का कय-विक्रय होने लगता है और मनुष्यों को पदार्थ मोल लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समूह की सृष्टि हो जाती है, जिसे दुकानदार या सौदागर वर्ग कहते हैं। मनुष्यों को मनोरंजन करने या खेल-कूद की आवश्यकता होती है तो क्लब या 'टीम' आदि का निर्माण हो जाता है। धार्मिक चर्चा तथा विचार-विनिमय के लिए साम्प्रदायिक या धार्मिक समूह बनाया जाता है।

क्रमशः एक-एक समृह के अन्तर्गत कई-कई समृह बनने लगते हैं। बात यह है कि "मुंडे-मुंडे मितिर्भिन्ना"; प्रत्येक विषय में लोगों के विचार या मत कुछ भिन्न-भिन्न होते हैं। धर्म की ही बात लीजिए। कुछ आदमी हिन्दू-धर्म को अञ्छा मानते हैं, कुछ इसलाम धर्म को, तथा कुछ ईसाई या पासीं धर्म को। फिर, इन मुख्य धर्मों में से प्रत्येक की भी कई-कई शाखाएँ होती है, कुछ आदमी एक शाखा के अनुयायी होते हैं, कुछ दूसरी के। इसी प्रकार आर्थिक जगत का विचार किया जा सकता है। कुछ आदमी एक प्रकार की आर्थिक नीति या कार्य-क्रम देश के लिए, (या अपने लिए) अञ्छा समकते हैं, कुछ आदमी दूसरी श्रीर कुछ, तीसरी ही नीति या कार्य-क्रम को। यही वात राजनैतिक च्रेत्र के संम्बन्ध में कही जा सकती है। किसी एक समूह के श्रन्तर्गत श्रिषक से श्रिषक कितने समूह हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। कमी-कमी श्रादमी एक समूह की श्रिषकाँश बातें मानते हुए, केवल दो-एक वातों में साधारण-सा मतमेद होने पर, उस समूह से पृथक हो जाते हैं, श्रीर श्रपना नया समूह बना लेते हैं। एक-एक धर्म के श्रन्तर्गत दर्जनों समूहों का होना सर्व-विदित है। कमी-कभी एक राजनैतिक दल के श्रन्तर्गत दलों को संख्या श्राठ-दस तक पहुँचने के उदाहरण मिलते हैं। मारतवर्ष में हो कांग्रेस-दल के श्रन्तर्गत कांग्रेस-किसान-दल, कांग्रेस-मज़दूर-दल, कांग्रेस-समाजवादी-दल श्रादि कई दल हैं।

अस्तु, किसी समूह का स्वरूग या सिद्धान्त सदैव एक-सा नहीं रहता। समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे-जैसे परिस्थितियों में अन्तर आता है, लोगों के विवार बदलते हैं; कोई समूह बहुत लोक-प्रिय बन जाता है, और किसी से लोगों की अद्धा हट जाती है। जिस समूह के सदस्य पहले थोड़े से होते हैं, पीछे उसके बहुत अधिक हो जाते हैं, और जिस समूह के सदस्य पहले बहुत अधिक होते हैं उसके कम रह जाते हैं। कभी-कभी कोई विशेष प्रतिभावान महानुभाव कार्य-चेत्र में आता है, उसका लोगों पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है, उसके अनुयायियों का नया समूह बन जाता है और दिन-दिन उन्नति करता जाता है। इस प्रकार नये दल बनते, और पुराने चीण होते रहते हैं।

समूहों को पारस्परिक सम्पर्क — निदान, समूह कई प्रकार के होते हैं। ये भिन्न-भिन्न आधार पर, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथक्-पृथक् उद्देश्य से बनते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक समृह के व्यक्ति दूसरे समृह के व्यक्तियों से सर्वथा जुदा हों। प्राय: एक-एक मनुष्य की कई-कई प्रकार की श्रावश्यकताएँ होती हैं, इस-लिए उसका कई-कई समूहों से सम्बन्ध होता है। उदाहरणार्थ एक नव-युवक किसान है, उसका अपने परिवार-रूपी समूह से तो सम्बन्ध है ही, वह भगवद्र्शन के वास्ते मन्दिर में जाता या कथा सुनता है, तीर्थ-यात्रा करता है. इस दृष्टि से उसका अपने सम्प्रदायवालों से सम्बन्ध रहता है। वह खेती करता है, श्रीर खेती में दूसरे किसानों से सहायता लेता तथा उन्हें सहायता देता है। इस प्रकार इस किसान-समूह से भी उसका सम्बन्ध रहता है। वह मनोरंजनार्थ, सायंकाल के समय थोड़ी देर कबड्डी खेलता है, तो कबड्डी खेलने वालों की टोली से सम्बन्धित हो जाता है। वह पढ़ने के लिए रात्रि-पाठशाला में जाता है, इसलिए उसका उससे भी सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण लिये जा सकते हैं। इससे विदित होता है कि बहुधा एक-एक व्यक्ति कई-कई समूहों का सदस्य होता है।

पुनः एक समूह में कई-कई समूहों से सम्बन्धित व्यक्ति भाग लेते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि आर्थिक या व्यावसायिक समूह में भिन्न-भिन्न जातियों या घमों के व्यक्ति होते हैं। और, राजनैतिक समूहों में कई-कई धार्मिक तथा आर्थिक समूहों के सदस्यों का मिश्रग्र होता है। जब एक समूह में विभिन्न समूहों के व्यक्ति मिलते हैं तो

यह सर्वथा सम्भव है कि ये भिन्न-भिन्न समृह परस्पर श्रपना हित एक-दूसरे के कुछ विरुद्ध मानते हों। उदाहरणवत् हिन्दुश्रों के सनातन-धर्मी समूह की बात लीजिए। इसमें अनेक किसान हैं, तो कुछ ज़मीदार भी हैं, कुछ पूँजीपित हैं तो अनेक मज़दूर भी हैं। इसके श्रतिरिक्त इसमें श्रनेक काँग्रेसवादी हैं तो कुछ लिबरल दल वाले भी हैं। बहुत से दुकानदार, अध्यापक, लेखक आदि भी इस समृह में सम्मिलित हैं। जब एक समूह में कई-कई समूहों के व्यक्तियों का समा-वेश होता है, तो भिन्न-भिन्न समूहों को एक श्रंश तक एक-दूसरे के सम्पर्क में आना पड़ता है। फल-स्वरूप एक समूह का दूसरे समूह पर कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कोई समृह दूसरे से नितान्त पृथक् नहीं रहता। वह अपनी कुछ बातें दूसरों को देता है, श्रीर कुछ बातें स्वयं दूसरों से लेता है। फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न समूहों में विचारों का समन्वय होता रहता है और उनकी उग्रता क्रमश: घटती जाती है। किसी व्यक्ति के, भिन्न-भिन्न समृहों में भाग लेने से उसे उन समूहों के उन सदस्यों के दृष्टिकोण को समझने और विचारने का अवसर मिलता है, जो कुछ बातों में उसके प्रतिकूल मत रखते हैं । यह बहुत उपयोगी है। अतः मनुष्यों को यथा-सम्भव विविध समृहों में भाग लेना चाहिए। हाँ, उन समृहों का उद्देश्य श्रच्छा श्रीर ऊँचा होना श्रावश्यक है। इस विषय पर श्रागे प्रकाश डाला जायगा।

समूहों के भेद — जब कुछ ब्रादमी अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक समूह का निर्माण करते हैं, श्रौर कुछ समय बाद उनकी वह आवश्यकता नहीं रहती, तो उनके उस समूह का अन्त हो

ì

जाता है। इसी प्रकार जब कुछ मनुष्यों की कोई नयी श्रावश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो वे उसकी पूर्ति के लिए एक नया समूह बना लेते हैं। कभी-कभी एक समूह की कई-कई शाखाएँ भी हो जाती हैं, श्राथवा एक समूह के श्रान्तर्गत नये-नये समूह बन जाते हैं। कुछ समूह बहुत महत्व के होते हैं, कुछ साधारण महत्व के ही। समूह मुख्य-तया दो प्रकार के होते हैं:—

- (१) वंशानुसार, या नातेदारी श्रथवा रिश्तेदारी के श्राघार पर बने हुए समूह — कुटुम्ब या परिवार, कबीला, जाति श्रादि । इस समूह को स्वाभाविक या जन्म-सिद्ध कहते हैं । इस समूह का सदस्य, मनुष्य अपने जन्म से ही हो जाता है ।
- (२) मनुष्य के बनाये हुए समूह। इन समूहों को मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार बनाता है। इनके अनेक भेद हैं, यथा
 - (क) धर्मानुसार, श्रर्थात् सम्प्रदाय, मत या मज़हब के श्राधार पर बने हुए समूह; यथा—हिन्दू मुसलमान, ईसाई श्रादि । फिर हिन्दुश्रों में सनातनधर्मी, श्रार्थ समाजी; मुसलमानों में शिया सुन्नी, श्रोर ईसाइयों में प्रोटेस्टैंट श्रोर रोमन कैथलिक श्रादि ।
 - (ख) व्यवसायानुसार श्रर्थात् पेशे या धन्धे के श्राधार पर बने हुए समूह; यथा—िकसान, मज़दूर, व्यापारी, श्रध्यापक, लेखक, डाक्टर श्रादि।
 - राजनैतिक मतानुसार, श्रर्थात् शासन-व्यवस्था सम्बन्धी
 विचार या श्रादर्श के श्राधार बने हुए समूह; यथा—भारत वर्ष में कांग्रेस, कांग्रेस-समाजवादी-दल, लिवरल या उदार

दल श्रादि; इंगलैंड में उदार दल, श्रनुदार दल, मज़दूर दल श्रादि ।

कुछ समूहों का उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, व्यायाम या शरीर-सुधार होता है। यथा – स्कूल, क्लब, आश्रम, क्रिकेट-टोम तथा फुटबाल-टीम आदि। ऐसे ही कुछ समूह लोक-सेवा या परोपकार के भाव से बनाये जाते हैं, जैसे स्वयं सेवक-दल, सेवा समितियाँ आदि। कुछ समूहों में स्थान या प्रदेश की भावना प्रधान रहती है। यथा—ग्राम-सुधार-समा, नगरोन्नितकारिणी सभा आदि।

पहले कहा गया है कि कुछ समूहों में, एक एक समूह के अन्तर्गत, कई-कई समूह बन जाते हैं। प्रगति या सुधार की भावना न्यूनाधिक होने से भी एक एक समूह के कई-कई भेद हो जाते हैं। इस दृष्टि से साधारणतया एक समूह के तीन भेद होना स्वाभाविक है:—

- (१) उम्र या विशेष प्रगतिशाल। इस समूह के व्यक्ति बहुत साहसी या स्वतन्त्र प्रकृति के होते हैं। चरम सीमा के सुधार या परिवर्तन-सम्बन्धी नये-नये प्रयोग करने का इन्हें बड़ा उत्साह होता है। छोटे-मोटे सुधारों से इन्हें सन्तोष नहीं होता।
- (२) पुरातन-प्रेमी, स्थिति-रक्षक, रूढ़िवादी या कट्टर । ऐसे समृह के व्यक्ति परिवर्तनों या सुधारों को आशंका की दृष्टि से देखते हैं । ये सोचते हैं कि यदि कुछ परिवर्तन हो गया तो न-जाने क्या संकट उपस्थित हो जाय । ये यथा-सम्भव किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देना चाहते । ये प्रत्येक सुधार का खूब विरोध करते हैं । ये चाहते हैं कि स्थिति जैसी है, वैसी ही बनी रहे ।

(३) उपर्यु कत दोनों समूहों के बीच में रहनेवाला। इस समूह के व्यक्ति न तो पुरानी बातों को ज्यों-का-त्यों रखने के पक्ष में होते हैं, श्रौर न ये एक-दम क्रान्तिकारी परिवर्त न करना ही उचित समभते हैं। ये सुधार तो पसन्द करते हैं, पर उसके मार्ग में क़दम फूँक-फूँक कर ही रखते हैं। समय-समय पर इनके विचार उक्त दलों में से जिसके साथ श्रिषक मिलते हैं, उसका ही ये साथ देते हैं। कुछ दशाओं में ये उक्त दोनों दलों से ही पृथक रहते हैं।

समूहों का क्षेत्र—विविध समूहों में से कोई बहुत छोटा होता है, और कोई बहुत बड़ा। उदाहरण्वत् परिवार में बहुधा तीन से पांच छः व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत कोई समूह इतना बड़ा होता है कि देश-भर के व्यक्तियों का उसमें समावेश हो जाय; उदाहरण्वत् राज्य ऐसा ही समूह है। यही नहीं, किसी समूह का चेत्र इससे भी बड़ा हो सकता है, यहीं तक कि उसका सम्बन्ध मानव समाज भर से होना सम्भव है। राष्ट्र-संघ ('लीग-आफ-नेशन्स') का उद्देश्य विश्व-व्यापी था। मज़दूरों तथा धर्म-प्रचारकों एवं व्यवसायियों के भी कुछ संघ विश्व-व्यापी उद्देश्यवाले होते हैं। वैज्ञानिक उन्नति के कारण अब यातायात के साधनों में उन्नति होती जा रही है, संसार के भिन्न-भिन्न भागों के निवासी परस्पर एक दूसरे के सम्पर्क में अधिक आते हैं, संसार एक सूत्र में बँधता जा रहा है, इसलिए बड़े-बड़े चेत्र वाले समूहों के निर्माण की सुविधा अधिक होती जा रही है।

समूहों के मेद और उपभेद अनन्त है। सब के विषय में पृथक-पृथक विचार करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इस पुस्तक में कुछ ही समूहों के विषय में विस्तार-पूर्वक विचार किया •जायगा। किन्तु पहले एक और बात को ओर ध्यान दिलाया जाना आ- वश्यक है।

समृह का उद्देश्य; व्यक्ति का विकास-यह स्तष्ट ही है कि उन्यु क समूहों में से प्रत्येक का उद्देश्य मनुष्य की किसा विशेष त्र्यावश्यकता की पूर्ति करना है। प्रत्येक समृह मनुष्य को ऋपने निर्धारित चेत्र में विकास करने की सुविधाएँ प्रदान करता है। कोई एक ही समृह उसकी सब शक्तियों का विकास नहीं कर सकता। जो समृह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार सहायक नहीं होता, श्रथवा उसमें वाषक होता है, वह समृह श्रनावश्यक श्रौर श्रनिष्ट-कर है; जैसे - जुत्रा खेलनेवालों या नशेबाजों का समृह। त्रतः किसी समूह से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए कि उनका समूह उनके विकास में सहायक रहे। जिस समय जो समूह अपने इस आदर्श से विहीन हो जाय. उस समय उस समृह के संगठन में श्रावश्यक परिवर्तन श्रौर संशोधन करके उसे उपयोगी बनाया जाना चाहिए; और यदि ऐसा न हो सके. तो उस समूह से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। नागरिक शास्त्र का लक्ष्य यह है कि इन भिन्न-भिन्न समूहों में ऐक्य स्थापित हो, सब का हित समान हो, एक दूसरे का विरोधी न हो, श्रीर सब मिल कर व्यक्ति के व्यक्तित का विकास करने वाले हैं। व्यक्ति का, भिन्न-भिन्न समृहों के प्रति जो कर्तव्य है, उसमें इस बात का बराबर ध्यान रहना चाहिए कि उसकी सेवा का चेत्र अधिकाधिक विस्तृत हो, उसकी आत्मा

को विकिस का अधिक-से-अधिक अवसर मिले, मनुष्य स्वार्थ-बुद्धि से केवल अपने परिवार या मित्र-मंडली के ही हित-चिन्तन में न रहे, वह कमशः ग्राम, नगर और देश तक का विचार करे और यहाँ भी अपने विचार-चेत्र को सीमित न करे; अपने द्वारा मानव समाज का हित-साधन होने दे, अपनी आतमा को विश्वास्मा के साथ एक-रस होने दे।

समृह की सफलता - इमने पहले कहा है कि समृह के सदस्यों की संख्या समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। प्रायः श्रादमी किसी समृह के सम्बन्ध में विचार करते हुए, उसके सदस्यों की संख्या पर ही विशेष ध्यान दिया करते हैं। श्रीर, जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो वे इसे उसकी सफलता का चिन्ह या प्रमाण समभते हैं। परन्तु, यद्यपि संख्या का कुछ महत्व अवश्य है, समृह की वास्तविक एफलता इस बात में है कि उसका उद्देश्य महान् हो, उसका त्रादर्श ऊँचा हो, त्रीर उसके सदस्य शुद्ध, त्रीर निष्काम भाव से उस उद्देश्य की पूर्ति में तन मन से जुटे हों । उचा गुणों श्रीर योग्यतावाले श्रपेक्षाकृत कम संख्यावाले सदस्यों का समृह, श्रयोग्य या गुण-हीन बहु-संख्यक समृह से, कहीं श्रच्छा है। प्रायः देखा जाता है कि आरम्भ में एक व्यक्ति विशेष प्रतिभा या विभूति वाला होता है, उसके सामने एक निश्चित श्रीर महान् उद्देशक होता है. उसकी पूर्ति के लिए वह जी-जान से जुट जाता है. श्रीर श्रपने जैसे कुछ इने-गिने व्यक्तियों का सहयोग श्रीर सहानुभृति प्राप्त कर उनका एक संगठित समृह बनाता है। इन व्यक्तियों के हृदय में

उत्साह ऐसा प्रवल होता है कि ये सब प्रकार कठिनाइयों, वाघाओं श्रौर संकटों का हर्ष-पूर्वक सामना करते हैं, श्रौर उत्तरोत्तर श्रपनी सुनिश्चित दिशा में श्रागे बढ़ते जाते हैं। कालान्तर में जब इस समूह को कुछ एफलता तथा यश मिलने लगता है तो अन्य व्यक्ति भी उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक होते जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढती जाती है। इन सदस्यों में ऊंच-नीच श्रौर मध्यम सभी प्रकार की प्रकृति श्रौर गुणवाले व्यक्ति होते हैं। सदस्यों की दिन-दुनी रात-चौगुनी वृद्धि को देखकर समृद के साधारण कार्यकर्ता फूले नहीं समाते। दूसरे समृहों की तुलना में, अपने समृह को बड़ा या विशाल देखकर वे, अपनी सफलता का अनुमान किया करते हैं। परन्तु वास्तव में समृह के इतिहास में यह समय बड़ा नाजुक होता है। संख्या-बल के प्रलोभन में अनेक समूह सदस्यता के नियमों में कुछ शिथिलता कर देते हैं, वे प्रत्येक सदस्य की वास्तविक योग्यता की परीक्षा नहीं करते।

यदि समृद्द के सूत्र-संचालक अनुभवी होते हैं तो वे समृद्द को इस रोग से यथा-सम्भव मुक्त रखते हैं। वे समय-समय पर नियमों में आवश्यक संशोधन करते रहते हैं, और यथेष्ट अनुशासन-नीति का उपयोग करते हैं। वे समृद्द-रूपी शरीर में बादी नहीं बढ़ने देते, उसे निर्विकार रखने के लिए कोई उपाय उठा नहीं रखते। अस्तु, समृद्द की सफलता के लिए संख्या-बल का एक परिमित सीमा तक ही महत्व है। यही बात धन-बल के सम्बन्ध में है। बहुत से समृद्द धन

के लोभ में पड़कर अपने उद्देश्य और आदर्श को भुला देते हैं, वे धनी ज्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के हेतु अपने सिद्धांतों की अवहेलना कर बैठते हैं, और इस प्रकार अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। प्रत्येक समूह के नेता को चाहिए कि इन विकारों से समूह की रक्षा करते हुए, उसका धैर्य, गम्भीरता और कष्ट-सहन-पूर्वक संचालन करता रहे। तभी समूह को वास्तविक सफलता प्राप्त होगी।



पाँचवाँ परिच्छेद परिवार श्रोर जाति

िम्हिल-भिन्न समूहों के सम्बन्ध में आवश्यक बातों का विचार, विचार, विक्रित परिच्छेद में किया जा चुका। अब यहाँ मुख्य-मुख्य समूहों में से एक एक के सम्बन्ध में कुछ ज्यौरेवार विचार किया जाता है। पहले ऐसे समूहों को लं, जो वंशानुसार बनते हैं, जिन्हें स्वाभाविक या जन्म सिद्ध कहते हैं।

परिवार और उसका स्वरूप—प्रारम्भिक समाज का छोटा सा चित्र हमें मां और उसके बचों के समूह में दिखायी देता है। मनुष्यों का सर्व-प्रथम स्वामाविक समूह उसका परिवार ही है। हां, परिवार का स्वरूप जैसा इस समय है, ऐसा आरम्भ में नहीं था। आज-कल परिवार से हम प्रायः विवाहित स्त्री और पुरुष तथा उनकी संतान की कल्पना करते हैं। परन्तु अति प्राचीन काल में स्त्री-पुरुषों में विवाह-शादी करके स्थायी सम्बन्ध रखने की रीति नहीं थी; विवाह-प्रणाली तथा स्त्री-पुरुष का स्थायी सम्बन्ध बहुत समय बाद आरम्भ हुआ है। प्राचीन काल में बच्चे माता के ही पास रहते थे; मां-बच्चों का ही

साथ था। स्त्री ही घर वाली, या घर की मालिकन होती थी। अस्तु, प्राचीन काल में परिवार का अर्थ मां और उसके बच्चों से होता था; यह परिवार ही उस समय का स्वाभाविक समूह था। पीछे जाकर पिता भी परिवार का स्थायी सदस्य होने लगा।

जन्म लेने के समय से ही प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माता से, श्रीर पीछे धीरे-धीरे पिता से सम्बन्ध हो जाता है। श्रव्छी तरह चलने-फिरने योग्य होने में उसे कई वर्ष लग जाते हैं। अपने जीवन-निर्वाह की योग्यता तो मनुष्य में, अपनी आयु के कितने ही वर्ष व्यतीत कर चुकने पर आती हैं। इतने समय तक वह माता-पिता के आश्रित रहता है। बच्चे बड़े होने पर स्त्री और पुरुष बनते हैं, उनका बिवाह-सम्बन्ध होता है, फिर उनकी संतान होती है। इस प्रकार नये-नये परिवार बनते रहते हैं। कभी-कभी पुरुष अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर अपने माता-पिता तथा भाइयों से अलग रहने लग जाता है, और कुछ दशाओं में उनके साथ ही रहता है। दूसरी अवस्थावाले परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं।

बच्चे अपने माता-पिता (अथवा ताऊ-ताई या चाचा-चाची आदि) की आज्ञा में रहते हैं; और, परिवार में जो बड़ा-बूढ़ा रहता है, सब उसकी सलाह मशिवरे से काम करते हैं। लड़के-लड़िक्याँ तथा पुरुष-ित्रयाँ सब उसका आदर करते हैं। कोई कार्य उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं किया जाता। यह भाव प्राचीन काल में बहुत या। आज-कल भी न्यूनाधिक पाया जाता है।

परिवार दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर स्थानों में वे पितृ-प्रधान

द्धोते हैं। बालक श्रपने पिता, पितामह, (बाबा), प्रितामह (परबाबा) श्रादि के वंश के होते हैं, श्रीर पुरुष की जायदाद जागीर का श्रिष्ठिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। किन्तु कुछ देशों में परिवार मातृ-प्रधान भी होते हैं, श्रर्थात् वंश माता, नानी, परनानी श्रादि के नाम से चलता है जागीर की श्रिषकारिणी स्त्री होती है, उसकी उत्तराधिकारिणी उसकी ज्येष्ठ पुत्री।

परिवार में स्त्री श्रोर पुरुष का कर्तव्य — परिवार किसी भी प्रकार का हो, वह समाज का एक छोटा-सा स्वरूप है। उसी से समाज का व्यापक रूप बनता और विकसित होता है। परिवार में स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर अपनी तथा अपने बचों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रायः श्रिषकतर दशाओं में स्त्रियां घर की सार-संभार करती है, श्रोर बाल-बच्चों का भरण-पोषण करती है; श्रोर पुरुष बाहर श्रजीविका-प्राप्ति का कार्य करते हैं। यह एक प्रकार से स्थूल अम-विभाग है, जो चिरकाल से चला आ रहा है। परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। स्त्रियों को चाहिए कि घर के काम से अवकाश पाकर यथा-सम्भव घनोत्पादन के कार्य में भी योग दें। लड़कियों को ऐसे काम सीखने चाहिए कि यदि किसी कारणवश पीछे बड़े होने पर उन्हें ही घर का ख़र्च चलाना पड़े तो वे उसमें नितांत असमर्थ न हों और स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें। उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना (पड़े।

परिवार जितना उन्नत होगा, बालक को श्रपनी उन्नति श्रौर विकास का उतना ही श्रिधिक श्रवसर मिलेगा। माता-पिता के संस्कार बालकों में आते हैं; वे जितने शिक्षित, योग्य, सहनशील, और समभदार होंगे, उतना ही बालक अधिक योग्य बनेंगे। अतः स्त्री-पुरुषों को चाहिए कि वे माता-पिता बनने से पूर्व अपने उत्तर-दायित्व को भली-भांति समभ लें। ऐसा न हो कि वे अयोग्य नाग-रिकों को जन्म देकर राज्य का भार बढ़ावें। उन्हें अपनी शारीरिक और मानिसक उन्नित की यथेष्ट व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें इतना धन उपार्जन करने योग्य होना चाहिए, जिससे वे बालकों के भरण-पोषण तथा शिक्षा के आवश्यक साधन जुटा सकें। उन्हें अपने रोज़मर्रा के व्यवहार से बालकों के सामने अव्छा आदर्श उपस्थित करते रहना चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक घर से बाहर जिस वातावरण में रहता है, वह अच्छे संस्कारों के उपयुक्त है। तभी उन्हें संतान के अव्छे गुणवान होने की आशा करनी चाहिए।

परिवार और व्यक्ति—परिवार-रूपी समृह का उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति करना है। व्यक्ति ही परिवार को बनाते हैं। दोनों का हित एक ही है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी अवस्था सोचने-समभने की है, यह विचार रखना चाहिए कि वह एक-दूसरे के हित का विचार रखे। प्रायः ऐसे प्रसंग आते हैं जब कि दो व्यक्तियों के विचारों में मत-मेद या भिन्नता होती है। ऐसे अवसर पर प्रत्येक को दूसरे का दृष्टि-कोण समभने, और यथा-सम्भव समभौता करने का विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति दूसरों पर अपने विचार लादने की चेष्टा न करे, परन्तु साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण रखना

चाहिए कि हमें ग्राम, नगर श्रीर राज्य के हित में योग देना है, हमारा कोई कार्य उसके प्रतिकृल न हो।

श्राज-कल प्राय: लोगों में सहनशीलता या गम्भीरता कम पायी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात पर ज़ोर देता है, वह दूसरे पक्ष की बात शान्ति-पूर्वक न सुनता श्रीर न विचारता है। लड़के बड़ों की परवा नहीं करते, कुछ तो उन्हें मूर्ख सममते हैं। उधर बड़े-बढ़े. बालकों के दृष्टिकोण का विचार नहीं करते: उन्हें उस अवस्था का ध्यान नहीं रहता, जब वे बालक थे। वे बालकों को बात-बात में डाँटते डपटते हैं, श्रौर उनकी खुले-श्राम निन्दा करते हैं। इससे बालक बिगड़ जाते हैं। श्रावश्यकता है कि बालक श्रपने बड़े-बढ़ों की बात को श्रादर पूर्वक सोचें श्रीर समर्भे, श्रीर जब तक कि उन्हें उस बात के सदीप होने का पूर्ण निश्चय न हो जाय, वे उसका पालन करें। श्रीर, जब कभी श्रपनी श्रात्मा के श्रादेशानुसार उन्हें उनकी बात न मानने का प्रसंग श्राप तो उस बात को छोड़कर श्रन्य बातों में उनके प्रति श्रादर-बुद्धि बनाये रखें. यह नहीं कि विचार-भिन्नता के कारण वे उनकी सेवा-सुशुषा में ही कमी करने लगें। साथ ही बड़े-बूढ़ों को भी चाहिए कि वे बालकों के व्यक्ति-स्वातंत्र्य का ध्यान रखे। जब तक कि कुछ श्रनिवार्य कारण उपस्थित न हो, वे बालकों की बात-व्यवहार में बृथा इस्तच्चेप न करें। बालकों पर श्रनुचित नियंत्रण रहने से उनके स्वाभाविक विकास में वाघा उपस्थित होती है। इस प्रकार बालक श्रीर बूढ़े एक दूसरे के यथा-सम्भव निकट रहें। उन के बीच में मत-मेद की चौड़ी दीवार खड़ी न होनी चाहिए। इसी प्रकार का विचार स्त्री-

पुरुषों को अपने न्यवहार से रखना चाहिए।

संयुक्त परिवार -- जब परिवार संयुक्त हो, अर्थात् दो भाई अपने-श्रपने स्त्री बच्चों सहित साथ-साथ रहते हों, वहाँ सहनशीलता, विवेक श्रीर गम्भीरता आदि गुणों की और भी अधिक आवश्यकताहोंती है। यह तो श्रावश्यक ही है कि प्रत्येक ब्यक्ति यथा-शक्ति धनोपार्जन करे, कोई खाली बैठे दूसरे की कमाई न खाए। ऐसा करने से उसके स्वाभिमान की हानि होगी और घरमें नित्य कलह रहेगा । हाँ, इस बात का भी विचार रहना चाहिए कि यदि घर में एक आदमी दूसरे से अधिक कमाता है तो उसे उसका श्रमिमान करके दूसरे श्रादमी का निरादर न करना चाहिए। उसे दूसरे के लिए वैसे ही भोजन-वस्त्र त्यादि की ब्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि वह स्वयं अपने लिए करता है। अर्थात् घर के आदिमियों के रहन-सहन श्रीर खान-पान श्रादि में भिन्नता न होनी चाहिए। यह लिखते हए हम यह भूलते नहीं है कि यह एक आदर्श मात्र है, और आज कल की आर्थिक किउनाइयों के समय में यह अनेक दशाओं में चिर-काल तक निभता नहीं। संयुक्त परिवारों में बात-बात पर आये-दिन भगड़ा होता है। पुरुषों में कुछ सहनशीलता का परिचय भी मिलता है तो स्त्रियाँ शान्ति नहीं रखतीं। अन्ततः गृह-कलह चरम सीमा पर पहुँचजाता है श्रीर परिवार श्रलग-श्रलग हो जाते हैं। प्राय: संयुक्त परिवार में व्यक्तियों का विकास रका रहता है, श्रीर जैसी स्वतंत्रता की लहर चल रही है उसमें संयुक्त-परिवार-रूपी संस्था पर प्रहार हों तो त्राश्चर्य ही क्या ! जहाँ संयुक्त परिवार में व्यक्ति श्रानन्द-पूर्वक रहते हो, समभाना चाहिए कि उनमें अपने कर्तब्य-पालन की भावना बहुत ऊंचे

दर्जे की है। अस्तु, यथा-सम्भव प्रत्येक ब्यक्ति का कर्तव्य है कि परिवार में दूसरों की सुख-शान्ति और उन्नति का यथेष्ट ब्यान रखे। इम परि-वार की उन्नति करें, और परिवार हमारे विकास में सहायक हो।

कुल या गोत्र ---परिवार के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं श्रीर उनका विवाह हो जाता है, तो कभी-कभी विवाहित पुरुष (अपनी स्त्री सहित) अपने माता-पिता से ऋलग रहने लगता है। अथवा, जब किसी परिवार में दो या अधिक भाई होते हैं तो वे विवाहित होने पर श्रलग-ग्रलग रहने लग जाते है। इस प्रकार नये-नये परिवार बनते जाते हैं। ये परिवार एक इी पूर्वज की सन्तान के होते हैं। प्राचीन काल में ये प्राय: पास ही रहा करते थे, श्रव भी बहुधा एक गाँव में कई कई निकट-सम्बन्धी परिवार रहते है। एक ही पूर्वज की सन्तानवाले परिवारों को कुल, कबीला, या गोत्र कहते हैं। एक कुल के व्यक्तियों में रहन-सहन, खान-पान तथा रीति-रिवाज की बहत समानता होती है। ये एक दूसरे के मुख-दुख और हर्ष-शोक में भाग लेते हैं। एक कुल के समस्त व्यक्ति आपस में अपनत्व का अनु-भव करते श्रीर खान-पान तथा विवाह-शादी या रोटी-बेटी का चनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। उनमें जो बड़ा-बूढ़ा होता है, वह सब का मुलिया या चौधरी माना जाता है। कुल के सब व्यक्ति उसके अधीन होते हैं। जब कोई महत्व-पूर्ण कार्य, या रीति-रस्म का संशोधन करना होता है तो उसकी सम्मति या परामर्श से किया जाता है। इस प्रकार एक-एक मुखिया की अधीनता में एक-एक कुल के आदिमियों का संगठन होता है। अगर किसी कुल के व्यक्तियों का आपस में मत-मेद या भगड़ा होता है तो इसका निपटारा मुखिया ही करता है। अन्य कुलों के आदिमियों से लड़ाई या मेल-जोल करने में उसी की सम्मित मुख्य मानी जाती है। कमशः प्रत्येक कुल के मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाती है। जब दो या अधिक कुलों के आदमी मिलकर किसी ग्राम या नगर में रहने लगते हैं तो उनके शासन-प्रबन्ध का कार्य उनके मुखि-याओं की कमेटी या पंचायत करती हैं। जिन कुलों में व्यवसाय, व्यवस्थाओं की कमेटी या पंचायत करती हैं। जिन कुलों में व्यवसाय, व्यवसायों की कमेटी या पंचायत करती हैं, या पास रहने के कारण समान हो जाते हैं, उनमें खान-पान और विवाह-शादी का सम्बन्ध होने लगता है। इस प्रकार बहुत से कुलों के व्यक्ति आपस में इतने हिल-मिल जाते हैं, उनकी माषा, रहन-सहन, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा, आदि में इतनी समानता हो जाती है कि उन सब को एक ही समूह का समभा जाता है। ऐसे समूह को जाति कहते हैं, जिसके सम्बन्ध में आगे कहा जायगा।

निदान, कुल का आधार वंश, नातेदारी या रिश्तेदारी है, एक कुल के व्यक्ति किसी विशेष पूर्वज का अभिमान करते हैं श्रीर बहुषा उस पूर्वज के ही नाम से उस कुल का नामकरण होता है। यद्यपि कालान्तर में एक कुल के व्यक्तियों का विवाह-शादी दूसरे कुल में होता रहता है; श्रीर इस प्रकार कोई भी कुल पूर्णतया विशुद्ध नहीं रहता, श्रनेक कुलों के व्यक्ति अपनी रक्त-शुद्धि का श्रीममान किया करते हैं। श्रस्तु, प्रत्येक कुल श्रपने चेत्र के व्यक्ति की उन्नति में योग देता है, श्रीर व्यक्ति अपने कुल की उन्नति का प्रयत्न करता रहता है। दोनों एक-दूसरे के सहायक श्रीर उन्नायक होते हैं।

जाति--मनुष्यों के कुल या गोत्र से बड़ा संगठन जाति हैं। अपने व्यापक अर्थ में, जाति वह समृह है जिसका मूल निवास कोई विशेष भू-भाग हो तथा जिसकी एक विशेष, संस्कृति हो। प्रत्येक जाति का रहन-सहन, खान-पान, उत्सव, त्यौहार, रीति-रिवाज़, श्रादि दसरी जाति के रहन-सहन आदि से भिन्न होता है। बात यह है कि जब किसी समृह के व्यक्ति पीढ़ियों तथा सदियों तक इकट्ठे एक ही स्थान में रह चुकते हैं श्रीर उनका खान-पान विवाह-सम्बन्ध उसी समृह के व्यक्तियों से होता रहता है तो उनका, रहन-सहन आदि एक विशेष प्रकार का हो जाता है। उनके साहित्य, सम्यता, धर्म विचार-परम्परा, रस्म, रिवाज श्रादि में ऐसी विशेषताएँ श्रा जाती हैं. जो दूसरे समृहों में नहीं पायी जातीं। ऐसे समृह को जाति कहा जाता है। एक जाति के श्रादमी समान हित श्रौर एक श्रादर्श की श्रङ्कला में बँवे होते हैं। वे कुछ ख़ास-ख़ास महापुरुषों का अभि-मान करते हैं, श्रीर उनके जीवनचरित्र श्रादि के श्राघार पर विविध कथाएँ तथा साहित्य और इतिहास का निर्माण करते हैं। उनकी एक भाषा होती है तथा उनके धर्म में भी समानता होती है।

उपर्युक्त व्यापक अर्थ के अनुसार जातियों की सख्या ससार भर में इनी-गिनी हैं। इनमें से मुख्य हैं —आर्थ जाति, सेमेटिक जाति तथा मंगोल जाति। भारतवर्ष में हिन्दू आर्य जाति के हैं और मुसलमान अपना सम्बन्ध सेमेटिक जातियों से जोड़ते हैं, यद्यपि वर्तमान अवस्था में अधिकांश मुसलमान हिन्दुओं के ही वंशज हैं। यहाँ आर्य जाति के पहले, कर्मानुसार चार मेद ये—आहारा, च्त्री, वैरय

श्रीर श्रूद । कालान्तर में इन मेदों में से प्रत्येक के अन्तर्गत अनेक छोटी छोटी शाखाएँ बन गयीं । इन उपजातियों के लिए अब 'जाति' शब्द का प्रयोग किया जाता है । उदाहर एवत् गौड़ ब्राह्मण, सार-स्वत ब्राह्मण, माहेश्वरी वैश्य, अग्रवाल वैश्य, बढ़ई, लुहार आदि अब पृथक-पृथक जातियों बनी हुई हैं । इन जातियों के आदिमयों का विवाह-सम्बन्ध उसी जाति के चेत्र में होता है । प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी पंचायत है, जो अपनी जाति के आदिमयों के जन्म-मरण, विवाह-शादी आदि से सम्बन्धित सामाजिक कायों के विषय में नियम बनाती है। जो आदमी इन नियमों का पालन नहीं करता, उन्हें पंचायत की ओर से दंड दिया जाता है । ये जातीय पंचायतें विशेष ध्यान इस बात पर देती हैं कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति में विवाह-सम्बन्ध न करे, तािक जाित की शुद्धता तथा मर्यादा बनी रहें।

इस समय इन जातियों की संख्या अनन्त है, और किसी-किसी जाति के अन्दर तो कई-कई मेद है। प्रान्तीयता के विचार से भी बहुत मेद माना जाता है। उदाहरणवत् अनेक काश्मीरी ब्राह्मण और मारवाड़ी ब्राह्मण अपने को अलग-अलग जाति का मानते हैं। इस प्रकार इनमें भी परस्पर में विवाह-सम्बन्ध विशेष प्रचलित नहीं है। कुछ जातियों के अन्दर आदिमयों की संख्या बहुत कम है। और, अधिकाँश जाति उप-जातियों का दिन्ट-कोण बहुत संकुचित है। इसलिए जाति-प्रथा को निन्दनीय समभा जाने लगा है, और जाति-पाँति-तोडक मंडल जैसी संस्थाओं की स्थापना

हो गई है, जिनके सदस्यों का उद्देश्य यह है कि जाति मेद उठ जाय श्रीर भिन्न-भिन्न जातियों का एकीकरण हो जाय।

जाति, व्यक्ति और समाज—जाति का उद्देश्य है कि वह व्यक्तियों की उन्नति श्रीर उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। वर्तमान जातियाँ कुछ श्रंश तक यह कार्य करती भी हैं। प्रत्येक जाति की पंचायत या अन्य संस्था उस जाति के अनाथों तथा विधवाओं की सहायता करती है, अपनी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देती है, या उनके लिए 'बोर्डिङ्ग हाउस' (छात्रावास) स्थापित करती है, इत्यादि । यह बात ऋच्छी है । परन्त जाति-प्रथा में यह दोष है कि इनसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति को ऊँची सममता है, श्रीर दूसरों को नीची। विशेषतया द्विज या सवर्ण (ब्राह्मण, चत्री श्रीर वैश्य) जातियों के व्यक्ति शुद्धों को बहुत निम्न-कोटि का समभते हैं, अनेक आदमी शारीरिक श्रम का यथेष्ट सम्मान नहीं करते। जब कोई व्यक्ति समता श्रौर एकता का श्रादर्श रखकर श्रन्य जातिवालों से सम्पर्क बढ़ाता है, शूद्र या हरिजन कहे जानेवालों के पास बैठता-उठता है, या उनकी पंक्ति में भोजन करता है, तो प्रायः उसकी जातिवाले उसे जाति-वृद्धिकृत कर देते हैं। इससे विचार स्वातंत्र्य का दमन होता है. व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता।

किसी जाति का श्रपनी उन्नित की श्रोर ध्यान देना उसी सीमा तक ठीक है, जब तक उससे श्रन्य जातियों का श्रहित न हो। जिस प्रकार परिवार जाति का श्रंग हैं, उसी प्रकार जाति भी समाज या राज्य का श्रंग है। ब्यक्ति को अपनी जाति की उन्नित का ध्यान रखना उस दशा में सर्वथा अनुचित है, जब उससे अन्य जातियों समाज अथवा राज्य का कल्याण न होता हो। जातियों को अपना कार्यचेत्र जाति-गत विषयों तक ही परिमित रखना चाहिए। राजनैतिक आदि विषयों में उनका क़दम बढ़ाना नितान्त हानिकर है। उदाहर-णार्थ कोई जाति यह सोचे कि ब्यवस्थापक समा में हमारे इतने सदस्य हो, सरकारो पदों में से इतने पद हमारी जातिवालों को मिले, राज्य की आय का इतना भाग हमारी जाति के कार्यों में ब्यय हो, तो यह अनुचित और अक्षम्य है। प्रत्येक जाति को दूसरी जातियों के हित में योग देना चाहिए।

श्रव हम यह विचार करें कि वंश के श्राधार पर बने हुए समूह नागरिकता में कहाँ तक सहायक होते हैं। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। वह पहले अपने मुख और मुविधा की चिन्ता करता है, और दूसरों के हित का विचार पीछे करता है। पारिवारिक जीवन से स्वार्थ-त्याग की प्रेरणा मिलती है। माँ अपने श्राराम को तिलाँजिल देकर अपनी सन्तान के लिए क्या-क्या कष्ट नहीं उठाती, श्रनेक बार अपने बच्चे के लिए उसे रात-रात भर जागना पड़ता है। वह बहुधा स्वयं भूखी-प्यासी रहकर पहले अपने बच्चे के भरण-पोषण का प्रयत्न करती है। पिता भी श्रयनी सन्तान की शिक्षा-दीक्षा श्रादि के लिए भरसक उद्योग करता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं, जब पिता ने अपने पुत्र या पुत्री की चिकित्सा या शिद्धा के लिए इतना ख़र्च किया कि उसे अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो

नया। इसी प्रकार भाई-बहिनों की एक दूसरे के लिए कष्ट सहने श्रीर स्वार्थ-त्याग करने की श्रनेक बातें प्रत्येक व्यक्ति जानता है। श्रस्तु, परिवार या कुटुम्ब सामाजिक या नागरिक भावों की शिक्षा देने वाली प्रारम्भिक संस्था हैं।

श्रवश्य हो हमें इस पाठशाला की शिक्षा से ही सन्तोष न कर लेना चाहिए। हमें परिवार की भावना को परिवार तक ही परिमित न रखना चाहिए। जैसा कि श्रागे बताया जायगा, हमें अपने ग्राम या नगर के निवासियों से बन्धु-भाव रखना चाहिए तथा अपने जिले, प्रान्त और देशवालों से भी प्रेम और सहानुभृति रखनी चाहिए यही नहीं, मनुष्य-मात्र से अपने भाई-विहन की मौति वर्ताव करना चाहिए। श्रायवा, यों भी कह सकते हैं, हमें अपनी परिवार की कल्पना को कमशः ज्यापक बनाना चाहिए। श्रानेपन का भाव अपनी स्त्री बच्चों तक ही सीमित न रख कर, उसका चेत्र अधिकाधिक विस्तृत करना चाहिए; यहाँ तक कि वह जाति या देश की सीमाश्रों को पारकर विश्व-बन्धुत्व के महान् भारतीय आदर्श को जीवन में चिरतार्थ कर सके।



ञ्चठा परिच्छेद धार्मिक समृह

- STEP

स्वृह्मिक भावना का सूत्रपात; ईश्वर की कल्पना— मनुष्य इस सृष्टि में नाना प्रकार के दृश्य और घटनाएँ देखता है। कहीं ऊँचे गगन-चुम्बी पर्वत हैं, कहीं अथाह समुद्र है। कहीं भया-नक जंगल हैं, और कहीं मनोहर तथा सुगन्धित पुष्पोंवाले बृक्ष तथा पौदे हैं। कहीं डरावनी श्राकृतिवाले पशु हैं, तो कहीं मीठी बोली से अपनी ओर श्राकर्षित करने वाले पश्ची। ये सब किसने बनाये हैं मनुष्य देखता है कि सुदूर पृथ्वी-तल से, एक रक्त-वर्ण का पिंड (सूर्य) उदय होता है, वह कमशः श्राकाश में ऊपर श्राता है, शिखर पर पहुँचकर कमशः नीचे उतरता हुआ, जिधर से उदय हुआ था, उसके ठीक विपरीत दिशा में अस्त हो जाता है। जब तक वह हमें दिखायी देता रहा, सर्वत्र प्रकाश था, उष्णता थी, हमारे लिए दिन था, उसके श्रस्त होने पर उष्णता जाती रही, ठंडक हो गयी, अन्धकार श्रागया, रात्रि हो गयी। हों, श्राकाश में श्रसंख्य तारे टिमटिमाने लगे; कभी-कभी चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी मिल जाता है। यह जल-थल, यह पर्वत और जंगल, यह पशु-पक्षी, यह सूर्य, चंद्रमा, और तारे किसने बनाये ?

श्रभी तेज़ धूप पड़ रही थी, एक-दम श्राकाश मेघाच्छन्न हो गया, सूर्य छिप गया, बादलों में बिजली कड़कने लगी। यह लो, ज़ोर से हवा भी चलने लगी; श्रांधी हो नहीं, तूफान श्रा गया। वृद्ध उखड़ने लगे, मकानों की छुतों पर से छुपार श्रौर टीन उड़-उड़ कर दूर-दूर गिरने लगे। वर्षा होने लगी, हलकी-हलकी बूँदों से श्रारम्भ होकर वर्षा मूखलाधार हो गयी। तिनक देर पहले जहां स्थल था, श्रव जल ही जल है। श्रोलों ने तो सब फसल ही नष्ट कर डाली, कई महीनों का परिश्रम नष्ट हो गया। यह महान् परिवर्तन किसने कर दिया १ मनुष्य इतना ही जानता है कि इसके करनेवाला न तो वह स्वयं ही है, श्रौर न कोई ऐसा व्यक्ति या शक्ति है, जिसे वह देख सकता हो। यह तो श्रहष्ट की महिमा है।

श्रव्छा, एक श्रन्य प्रकार का श्रनुभव होता है। एक श्रादमी है, भला चंगा श्रपना काम कर रहा है, कोई उसे भाई के रूप में प्यार करता है, कोई मित्र के रूप में, पिता-माता श्रलग ही उसे देख-देखकर मन में हर्षित होते हैं, कोई उससे श्रप्रसन्न नहीं, कोई उसका शत्रु नहीं। फिर भी यह श्रादमी एकाएक बीमार हो जाता है, श्रीर वात-की बात में इसके प्राण्-पखेरू उड़ जाते हैं। सब सम्बन्धित व्यक्ति शोक में श्रपना-श्रपना सिर धुनने लगते हैं। क्या था, क्या हो गया १ इस श्रादमी के प्राण् किसने हर लिए, इसे किसने मार डाला १ मारने

नाला दिंखायी नहीं देता। मनुष्य सोचता है कि कोई श्रहष्ट शक्ति ऐसी श्रवश्य है जो प्राणियों पर शासन करती है, श्रीर उनके जीवन-मरण का कारण है।

मनुष्य इस श्रद्धष्ट शक्ति को जान नहीं पाता, पर वह इसके श्रस्ति-त्व से सर्वथा इनकार भी नहीं कर सकता। वह सोचता है यह कैसी श्रद्भत शक्ति है. जो इस विशाल जगत् की रचना करती है, भरण-योषण करती है, और हाँ, संहार भी करती है। इस शक्ति के सामने मनुष्य का श्रहंकार नष्ट हो जाता है. उसे श्रपनी लघुता का ज्ञान होता है। इस महान सर्वोपरि सर्वनियंता. शक्ति के सन्मुख वह नत-मस्तक हो जाता है, वह इसकी पूजा या श्राराधना करता है। श्रपनी कल्पना श्रीर बुद्धि के अनुसार वह उसे निराकार या साकार मानने लगता है। साकार मानने चाले ब्यक्ति अपनी-अपनी रुचि श्रीर विचार के अनुसार इस सर्वोपरि शक्ति के स्वरूप की भिन्न-भिन्न कल्पना करते हैं। भिन्न-भिन्न मनुष्य इसे पृथक्-पृथक् नामों से संबोधित करता है, कोई ईश्वर, परमात्मा श्रादि कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई 'गाड' (God)। फिर, संसार में ब्रादमी इस शक्ति को नाना प्रकार के देवी-देवता श्रों के रूप में भी मानते हैं, तरह-तरह की पूजा-विधि प्रचलित हैं, भांति-भांति के मंदिर या पूजा-स्थान हैं । मनुष्य विश्वास करता है कि ईश्वर या देवी-देवतात्रों की त्राराधना से वह प्रसन्न रहेगा, मेरे जीवन में सुख-शांति बढेगी श्रौर श्रनिष्ट का निवारण होगा। यही नहीं, इस जीवन के बाद, मरने पर परलोक में भी मेरा हित या कल्याण होगा। उपर्युक्त भावनाएँ ही संसार में विविध धर्मी को जन्म देनेवाली हैं।

स्मरण रहे कि वास्तव में धर्म का अर्थ ब्यापक है। उसमें हमारे सब कर्तव्यों का समावेश होता है। यहाँ हम उसका साधारण, बोल-चाल में समभा जानेवाला भाव ग्रह्ण कर रहे हैं, जैसा सम्प्रदाय या मज़हब आदि से स्चित होता है।

धार्मिक एकता— जित की एकता के विषय में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। जाति की तरह धर्म की एकता भी मनुष्यों के मिल-जुल कर रहने में सहायक होती है। जो आदमी एक धर्म के अनुयायी होते हैं, एक ही समान रूप में परमात्मा को या देवी-देवताओं के। मानते हैं, एक ही तरह से पूजा-पाठ तथा दान-पुर्य आदि करते हैं, उनमें स्वभावतः पारस्परिक एकता का अनुभव होता है। वे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा आपस में अधिक सहानुमूित और प्रेम रखते हैं। उनके आचार-विचार में समानता होने से उनकी इच्छा होती है कि वे जहाँ तक हो सके, पास-पास रहें और एक-दूसरे के दुस-सुख में काम आवें।

श्राजकल विशेषतया नगरों में भिन्न-भिन्न धर्मों के माननेवाले रहते हैं, तथापि अनेक गाँवों में किसी एक धर्मवालों की अधिकता होती है। कहीं हिन्दू अधिक हैं, कहीं अधिकतर मुसलमानों का ही निवास है। मुसिलिम-प्रधान गाँव में एक मस्र है, तो हिन्दू-अधान गाँव में किसी ख़ास देवी-देवता का मंदिर है। यही नहीं, अनेक मुसलिम बस्तियों में जहाँ शिया मुसलमान हैं तो उनकी ही अधिकता है, इसके विपरीत अन्य मुसलिम बस्तियों में सुनियों को ही प्रधानता है। इसी प्रकार हिन्दू बस्तियों में कहीं राम के

मानने वालों की प्रबलता है, तो कहीं कृष्ण आदि के पुजारी ही बहु-संख्यक हैं।

इस समय पहले जैसे विस्तृत जंगल नहीं हैं, जहाँ-तहाँ सड़कें बन गयी हैं। रेल, मोटर तथा अन्य स्वारियों से जाने-आने की सुवि-घाएँ पहले से बहुत बढ़ जाने पर भी यह दशा है तो प्राचीन काल की स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है, जब कि आमदरफ़ के इतने साधन न थे। उस समय अनेक गाँव ऐसे रहे होंगे कि उनके समस्त व्यक्ति किसी धर्मविशेष के अनुयायी हों। अस्तु, धर्म की एकता या समानता लोगों के मिल-जुलकर रहने में बहुत सहायक होती है। स्थान-स्थान पर लोगों के ऐसे समूह बने हुए हैं, जिनका आधार यह है कि उन लोगों का धर्म एक ही है।

श्राधुनिक परिस्थित में यह तो सम्भव नहीं है कि एक धर्म के माननेवाले सब व्यक्ति किसी एक विशेष नगर या प्रान्त में ही रहे। मुख्य-मुख्य धर्मों के श्रनुयायी भिन्न-भिन्न स्थानों में फैले हुए हैं, यहाँ तक कि एक धर्म के माननेवाले व्यक्ति भिन्न-भिन्न राज्यों में पाये जाते हैं। समय-समय पर इन धर्मानुयायियों के सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों में भिन्न-भिन्न देशों के इस धर्म के माननेवालों के प्रतिनिधि श्राकर भाग तेते हैं। इस प्रकार धर्म का चेत्र राष्ट्र तक ही परिमित न रहकर श्रम्तर्राष्ट्रीय बन गया है।

सहिष्णुता और समभाव की आवश्यकता—-कपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि आजकल विशेषतया नगरों में भिन्न-भिन्न धर्मवाले व्यक्ति रहते हैं। बात केवल नगरों की ही नहीं है। गावों में भी बहुधा विभिन्न धमों के ब्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। इससे नागरिक जीवन में एक समस्या उपस्थित हो जाती है। यदि प्रत्येक धर्म के माननेवाले इस तरह अपने अलग-अलग समूह बनाकर रहें कि एक समूह के आदिमियों की केवल आपस में ही सहानुभूति और सहयोग रहे, किन्तु दूसरे धर्मवालों को वे गैर या पराया सममें, उनसे सहानुभूति और उदारता का व्यवहार न करें, अथवा उनके प्रति कुछ द्वेष-भाव रखें, तो रोज-मर्रा के कामों में बड़ी वाधा उपस्थित हो जाय, नागरिक जीवन में बहुत कदुता आजाय। अतः इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि किसी गाँव या नगर में चाहे जितने धर्मों के अनुयायी रहते हों, उन सब को आपस में प्रेम और सहयोग का भाव रखना चाहिए।

इस विचार की पृष्टि धार्मिक दृष्टि से भी होती है। सब धर्मों का मूल एक ही है। सब धर्म एक परम पिता परमात्मा को मानते हैं, और विविध देवी-देवताओं को उसी का स्वरूप बताते हैं। विविध धर्मों के अनुसार की जानेवाली पूजा-पाठ या दान-पुर्य आदि की विधि में चाहे जितना अन्तर हो, सब धर्म प्रेम, दया, परोपकार और लोक-सेवा आदि की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक धर्म मनुष्य को उच्च गुर्णों की वृद्धि के लिए आदेश करता है।

दुख का विषय है कि आदमी रोज़मरों के व्यवहार में इस बात को भूल जाते हैं। हिन्दू मुसलमान को गैर समफता है, और मुसलमान हिन्दू के प्रति दुर्भाव रखता है; इसलिए हमें हिन्दू-मुसलमानों के फगड़ों का अनुभव करना पड़ता है। यहीं नहीं, अनेक बार हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही विविध धर्मों के अनुयायियों का आपस में फगड़ा हो जाता है, मुसलमान मुसलमानों से लड़ बैठते हैं। इसलाम धर्म ने विशाल भ्रातृत्व (विरादरी) का श्रादर्श रखा श्रौर जीवन में परिग्रुत किया। ऐसी दशा में शिया सुन्नियों के परस्पर में लड़ने की बात क्यों होती है ! ईसाई धर्म ने शत्रुओं से भी प्रेमकरने की बात कही, परन्तु इतिहास के कितने ही पृष्ट प्रोटेस्टैंटो और रोमन कैथलिकों के एक-दूसरे के प्रति किये हुए भयंकर अत्याचारों की रोमांचकारी कथाश्रों से भरे पड़े हैं। श्रीर श्राज. हजरत ईसा की बीसवीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं ? एक प्रोटेस्टैंट राज्य दूतरे प्रोटेस्टेंट राज्य से ही घातक युद्ध ढान रहा है। एकः दूसरे को नष्ट करने पर तुला हुआ है। अपने स्वार्थ-वश आदमी दूसरे धर्मवालों से भी मित्रता करते है, और फिर स्वार्थ वश अपने धर्म के अनुयायियों की हत्या तक करने से संकोच नहीं करते । मालूम होता है, स्वार्थ ही सर्वोपिर है, धर्म का स्थान मानव जीवन में गौए कर दिया गया है। धर्म मंदिर में, पूजा-पाठ आदि के लिए एकत्रित होते समय ही आदमी अपने धर्म की याद करते हैं, फिर दिन के शेष घंटों में स्वार्थ-साधना में लगे रहते हैं, और आवश्यकता होने पर छल, कपट. हिंसा आदि से परहेज़ नहीं करते। अन्यथा जो आदमी अपने को किसी धर्म का अनुयायी कहता और मानता है-वह धर्म हिन्दू हो या इसलाम या ईसाई-वह कैसे दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट या हानि पहुँचाने का विचार कर सकता है !

धर्म श्रीर व्यक्ति—हमें समक्तना चाहिए कि धर्म हमारे उत्थान का साधन है, उसके द्वारा हम में उच्च मानवी गुणों का विकास होना चाहिए। ईश्वर या धर्म के माननेवालों (श्रास्तिकों) का सामाजिक श्रीर नागरिक जीवन कटता-रहित, श्रीर प्रेम-पूर्ण होना चाहिए । यदि किसी धर्मवाले श्रापस में, श्रथवा श्रन्य धर्म-वालों से लडते-भगडते हैं तो कहना होगा कि धर्म ने उनके हृदय पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डाला है, श्रौर वे सच्चे श्रर्थ में धर्मात्मा (धर्म वाले) नहीं हैं। जो व्यक्ति वास्तव में किसी धर्म को मानता है. उसका कभी किसी से लड़ाई-फगड़ा नहीं हो सकता, वह सब श्रादमियों को एक परमात्मा की सन्तान समभता है, श्रीर इसलिए सब को अपने भाई के समान मानता है। यही नहीं. क्योंकि वह एक परमात्मा को समस्त सुष्टि का जनक था उत्पादक मानता है, वह प्राणी-मात्र को अपने प्रेम और दया का श्रिधिकारी समभता है, श्रीर सब से व्यवहार करते समय त्याग, श्रीर सेवा-भाव का परिचय देता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति पर कैसा हितकर प्रभाव डालता है, वह व्यक्ति का समाज से कितना सुलकर सम्बन्ध स्थापित करता है. वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन के कितना श्रनुकुल बनाता है, यह स्पष्ट है। धार्मिक भगड़ों को देख-सुनकर हमें यह बात न भूलनी चाहिए: वास्तव में धार्मिक भगड़े लोगों की भ्रम-मूलक घारणा से. या संकीर्ण श्रीर श्रनुदार दृष्टि-कोण के कारण होते हैं; श्रन्यथा, धर्म तो व्यक्ति के विचारों को उच बनाने, उसमें प्रेम, दया श्रादि उन गुणों का विकास करने में प्रबल सहायक है, जो समाज को उन्नति श्रीर विकास करने वाले होते हैं।

कभी-कभी धर्म के नाम पर व्यक्तियों को अन्ध-विश्वासी बनाया जाता है, उन्हें स्वतन्त्र चिन्तन नहीं करने दिया जाता, श्रीर यदि वे

अपने विचार-स्वातंत्र्य का परिचय देते हैं तो उनका दमन किया जाता है। यह सर्वथा अनुचित है। प्रत्येक धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ खास खास प्रत्य है। सर्व-साधारण जनता उनका बहुत मान करती है। इन प्रत्यों में अनेक ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, परन्तु कोई प्रत्य समस्त ज्ञान का भंडार होने का दावा नहीं कर सकता। अब, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है जो किसी धर्म के प्रत्य में नहीं है या किसी धर्म प्रत्य में प्रतिपादित सिद्धांत के विरुद्ध है तो उस व्यक्ति पर धर्मानुयायी कहे जानेवाले सजनों की वक्र-दृष्टि स्यों होनी चाहिए!

प्राचीन काल में कितने ही धर्माधिकारियों ने इस बान का संगठित प्रयत्न किया कि सर्व-साधारण धर्म-अंथों को न पढ़ सकें, धार्मिक पुस्तकों का प्रचलित भाषात्रों में अनुवाद न होने दिया, श्रीर जबिकसी ने साहस करके अनुवाद करनाचाहा तो उसे भांति-भांति के कष्ट दिये गये। इससे व्यक्तियों की मानसिक उन्नति बहुत रुकी रही। श्रव यह बात नहीं रही है, सब मुख्य-मुख्य अंथों का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, श्रीर होता जाता है। इससे साधारण शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति न केवल अपने धर्म की पुस्तकों का अवलोकन कर सकता है, वरन् अन्य धर्मों से सम्बन्धित साहित्य को पढ़कर उसके सिद्धान्तों या विचारों से भी परिचित हो सकता है। इससे तुलनात्मक अध्ययन की सुविधाएँ बढ़ गयी है; आदमी धार्मिक विषयों में अधिकाधिक प्रगति कर सकते हैं। परन्तु दुर्माग्य से अब भी कुळ धर्माधिकारी 'मजहब में अक्ल का दखल नहीं' सिद्धान्त को 'मानते हैं। धर्म बुद्धि को कुंठित करने वाला हो, उसके विकास में बाधक हो, लोगों में अन्य विश्वास बढ़ाने वाला और

उन्हें रूढ़ियों का भक्त बनानेवाला हो, यह अत्यन्त चिन्तनीय है। हम तो किसी विद्वान के इस कथन का प्रचार और व्यवहार चाहते हैं कि 'जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं।' अस्तु, धर्म का कार्य है कि व्यक्ति को स्वतन्त्र-चिन्तन का यथेट अवसर दे और जनता में विचार-विनिमय तथा तर्क-वितर्क को प्रोत्साहन दे।

व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का गौरव बढाने वाला हो। ब्यक्ति अपने धर्म का गौरव किस प्रकार वढा सकता है ! वह अपने रोज़मर्रा के कार्य-व्यवहार में उच मानवा गुणों का परिचय दे, प्रेम, दया, सहानुभृति, सेवा, सत्य और परोपकार उसका लक्ष्य रहे। यदि मैं हिन्दू हूँ तो मुक्ते चाहिए कि हिन्दू धर्मावलम्बी होने के कारण मैं कोई ऐसा कार्यन करूँ, जिससे श्रीरों की दृष्टि में हिन्द धर्म का स्थान कुछ नीचा हो। जहाँ-कहीं सेवा श्रीर लोक-हित का श्रवसर त्राये, मुक्ते त्रागे बढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रत्येक बस्ती में भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं, मेरा यह प्रयक्त होना चाहिए कि नागरिक जीवन में हिन्दुओं का स्थान अग्रगएय रहे। यदि नगर में श्रकाल या दुर्भिक्ष है तो हिन्दू उसमें जी खोलकर सहायता दें, श्रीर सहायता देते समय स्मरण रखें कि सब व्यक्ति एक परमपिता परत्मात्मा की सन्तान हैं, अत: बिना मेद-भाव के सभी हमारी सहायता के समान श्रिवकारी हैं। इसी प्रकार यदि नगर में किसी महामारी का प्रकोप है तो हमें अपनी जान संकट में डालकर भी दूसरों की सेवा-सुश्रुषा करनी चाहिए। यदि दो व्यक्तियों का भगड़ा है, तो हमें सत्य का पक्ष लेना चाहिए। इन और ऐसी ही बातों से दूसरे आदमी समभेंगे कि हिन्दू धर्म बहुत उदार है, और परोपकारी है। उनकी हिन्दू धर्म का आदर-मान बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहते हुए असत्य का आचरण करे, दूसरों सि लड़ाई भगड़ा करे, नागरिक जीवन को कलुषित करे तो वह हिन्दू धर्म का अपकार करता है, उसे दूसरों की हिन्दू से गिराता है। इसी प्रकार प्रत्येक मुसलमान, ईसाई, पार्सी आदि को चाहिए कि वह अपने कार्य-व्यवहार से अपने धर्म को कलंकित न करे, वरन उसे अधिकाधिक आदरास्यद बनाये।

धर्म का क्षेत्र — प्रत्येक धर्म के अधिकारियों को अपने कार्यचेत्र का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। वे उस धर्म के अनुयायियों को
यह तो बतलावें कि ईश्वर की पूजा-उपासनादि किस प्रकार करें, परन्तु
उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उस धर्म के माननेवालों का कोई
कार्य ऐसा न हो जिससे अन्य धर्मवालों को असुविधा या कष्ट
पहुँचे। धर्म तो दूसरों की सेवा के लिए है, न कि दुख देने के लिए।
कुछ धर्माधिकारी धर्म की आड़ में सामाजिक कुरीतियों और अन्धविश्वासों का समर्थन करते हैं, जनता की गाड़ी-कमाई को अपने व्यक्ति
गत सुख और भोग-विलास में व्यय करते हैं, स्वयं आरामतलबी या
विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने धर्मवालों के वास्ते विशेष राजनैतिक या
आर्थिक अधिकार माँगते रहते हैं, नागरिक विषयों में साम्प्रदायिक
मावना बढ़ाते हैं। ये बातें अनिष्टकारी हैं, धर्म के नाम पर इनका
किया जाना कदापि उचित नहीं है।

हम चाहते हैं कि हमें अपने विश्वास के अनुसार पूजा-पाउँ आदि कृत्य करने की स्वतन्त्रता रहे तो हमें चाहिए कि हम अन्य मताव-लिम्बयों को भी वैसी स्वतन्त्रता देने के लिए तैयार रहें, और यदि सब को वैसा अधिकार नहीं दिया जा सकता तो हमें भी वैसे अधिकार की माँग नहीं करनी चाहिए। इसो प्रकार हमें दान-पुग्य आदि करने का अधिकार है, ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, परन्तु उसकी सीमा या मर्थादा को भुलाना उचित नहीं है। यदि हमारे दान-धर्म से लोगों में मुफ्तखोरी, विलासिता या भिद्या-वृत्ति आदि बढ़ती है, तो हमारा वह कृत्य अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, अतः वह त्याज्य है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में धर्म के वास्तविक खेत्र का ध्यान रखा जाना चाहिए।



सातवाँ परिच्छेद

व्यवसायिक समृह



जा चुका। एक समृद ऐसा होता है जिसका आधार मनुष्यों का व्यवसाय-पेशा था घन्धा होता है। एक-एक पेशे के आदमी मिल कर रहना बहुत पसन्द करते हैं, उन्हें एक दूसरे की सहायता या सलाह-मशिवरे की आवश्यकता होती है, और यह उन्हें तब ही अच्छी तरह मिल सकता है, जब वे पास-पास रहते हों।

आवश्यकताओं की पूर्ति—प्रारम्मिक अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती हैं। उस समय वे मिलकर रहते हैं तो उनके समूह का आधार वंश या जाति होती है। इस समूह के आदमी मिलकर एक दूसरे की सहायता से अपनी सब आन्वश्यकताओं की पूर्ति इकट्ठे ही कर लेते हैं। धीरे-धीरे, जब आवश्यकताओं की पूर्ति इकट्ठे ही कर लेते हैं। धीरे-धीरे, जब आवश्यकताएँ बढ़ीं, तो यह अच्छा समभा गया कि मनुष्य अपना समय और शक्ति विविध प्रकार की अनेक वस्तुओं के बनाने में न लगा

कर' किसी एक ही प्रकार के काम में लगाये, और कोई विशेष पदार्थ तैयार करके उसे उसमें से अपनी ज़रूरत के अनुसार रख कर, शेष दूसरे आदिमयों को दिया करें। हाँ, यह ध्यान रखे कि वह अपनी वस्तु ऐसे आदिमयों को दे जिन्हें उस पदार्थ की आवश्यकता हो, और जो उसके बदले में उसे उसकी आवश्यकता की वस्तु दे सकें। इसीका यह परिणाम है कि गाँव में एक आदिमी अन्नकपास आदि पैदा करता है, दूसरा कपड़ा बनाता है। अन्न या कपास वाला अपनी वस्तु दूसरे को देकर उससे कपड़ा ले लेता है। इससे उसकी कपड़े की माँग पूरी हो जाती है, और दूसरे को अपने भोजन के लिए अन्न मिल जाता है, या कपड़ा बनाने के लिए कपास प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक आदमी औज़ार बनाता है, जिसको किसान और जुलाहे को ज़रूरत होती है, वह उन्हें औज़ार देकर अन्न-वस्त्र ले लेता है।

इस प्रकार श्रम-विभाग से कुछ आदमी केवल श्रन्न या कपास आदि पैदा करते हैं, कुछ आदमी केवल कपड़ा तैयार करते हैं, श्रीर कुछ केवल श्रीज़ार बनात हैं। खेती करनेवाले व्यक्ति को दूसरे खेती करनेवाले व्यक्ति के संग-साथ की श्रावश्यकता रहती है। कल्पना कीजिये उसका एक श्रीज़ार टूट गया। श्रव जब तक वह नया श्रीज़ार बनवाये तब तक उसका काम कैसे चले? यदि पास में दूसरा खेती करने वाला है तो उससे वह श्रीज़ार मांग कर काम निकाला जा सकता है। श्रथवा, यदि दो किसानों के पास एक-एक ही बैल हैं तो पास रहने की दशा में प्रत्येक किसान दूसरे मे वैल माँगकर खेती कर सकता है। इस प्रकार दोनों किसानों का एक-एक वैल से ही काम चल सकता है। अगर प्रत्येक किसान अकेला रहे तो उसे यह सुविधा न मिले। इसी प्रकार यदि एक किसान को अपने कार्य में कुळ सलाह-मश्चिरे की ज़रूरत हो तो उसे यह आसानी से तभी मिल सकता है, जब उस कार्य का अनुभव रखनेवाला दूसरा किसान उसके निकट रहता हो। इससे प्रतीत हुआ कि खेती करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग एक दूसरे से दूर रहने में बड़ी असुविधा का समना करना पड़ता है; अतः उन्हें पास-पास रहने में ही लाभ है। यही बात अन्य कार्य करनेवालों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अब समाज में तीन समूह बन गये।
एक समूह खेती करनेवालों का है, दूसरा कताई-बुनाई करनेवालों
का, तीसरा समूह लकड़ी लोहे का काम करनेवालों का है। प्रत्येक
समूह के आदमी अपना पृथक-पृथक काम करते हैं। प्रत्येक समूह का
ब्यवसाय या पेशा अलग-अलग होता है, उसे कई-कई कार्य नहीं करने
पड़ते। व्यवसायानुसार समूह बनने की यही विशेषता है, और यह बात
कमश: बढती जाती है।

श्रम-विभाग श्रोर जाति-प्रया— ज्यों-ज्यों लोगों की श्रा-वश्यकताश्रों की वृद्धि होती है, नये-नये व्यवसाय निकलते जाते हैं, श्रीर एक व्यवसाय के भी कई-कई मेद हो जाते हैं, तथा पीछे इन मेदों के श्रनुसार नये व्यवसायिक समूह बनते जाते हैं। उदाहरणार्थ कपड़ा तैयार करने के काम की बात लें। श्रारम्भ में एक ही समूह के श्रादमी मिल कर इस कार्य को कर लेते हैं, पीछे कुछ श्रादमी केवल कपाष श्रोटने श्रर्थात् चर्ली द्वारा रूई को विनौलों से पृथक करने का काम करने लगते हैं। कुछ ब्राइमी केवल सूत कातते हैं. श्रीर कुछ केवल उस सूत का कवड़ा बुनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कार्य का एक भाग करता है। अम-विभाग से, पृथक् पृथक् कार्य या उनका भाग करनेवाले व्यक्तियों के भिन्न भिन्न समृह बन जाते हैं। प्रत्येक समृह का एक पृथक कार्य या कार्य भाग होता है। क्रमशः श्रम-विभाग का स्वरूप श्रीर श्रागे बढ़ता है। ऊपर बताये हुए एक-एक कार्य के विविध भागों में से एक-एक के कई सूक्ष्म उन-विभाग हो जाते हैं, श्रीर जब सब उप-विभागों का कार्य पूरा हो जाता है तब श्रभीष्ट वस्तु तैयार होती है। श्राधुनिक कल-कारखानों में कपड़ा खुनने की किया कई दर्जन उन-विभागों में विमक है। प्रधेक उप विभाग के काम को पृथक पेशा कहा जा सकता है। इन पेशों में से प्रत्येक पेशे के श्रादिमयों का प्रथक् समूह होजाता है, ये लोग कल-कारख़ाने में एक जगह इकट्टे काम करते हैं, श्रौर प्रायः साथ-साथ रहते हैं, अनेक वार आपस में मिलते-जुलते हैं, इनका आपस में सम्बन्ध बढ़ जाता है, इनमें मेल-जोल हो जाता है।

यह स्पष्ट ही है कि ज्यों ज्यों सम्यता की वृद्धि होती आती है, अम-विभाग सक्ष्म होता जाता है। परन्तु स्थून रूप में तो यह चिर-काल से हैं। हिन्दुओं के चार वर्णों में विभक्त होने का अध्यार भी अम-विभाग ही है। एक वर्ण शिल्ला का प्रचार और पूजा-पाठ करे; दूसरा, लोगों की जान-माल को रक्षा का भार ले; तीसरा कृषि, गो-रक्षा और वाणिज्य द्वारा समाज की आर्थिक उन्नति में योग दे; श्रीर चौथा वर्ण श्रन्य तीन वर्णों के श्रादिमयों की सेवा करे । ये वर्ण क्रमश: ब्राह्मण, च्रजी, वैश्य श्रीर श्रुद्ध कहलाते हैं । समाज में मनुष्यों के ऐसे भेद थोड़े-बहुत रूप में सभी देशों में हैं । भारतवर्ष में उपर्युक्त चार वर्णों को जातियाँ कहा जाने लगा श्रीर कालान्तर में इन जातियों की श्रनेक शाखाएँ तथा उप-शाखाएँ हो गयी । सर्व साधारण व्यवहार में यह बात भूल गये कि वास्तव में इनका श्राधार व्यवसाय या पेशा था । जातियों का श्राधार जन्म, श्रर्थात् वंश माना जाने लगा । जुहार का लड़का जुहार, सुनार का लड़का सुनार, श्रीर बढ़ई का लड़का बढ़ई, कहा जाने लगा, चाहे वह श्रपने पिता का काम न करके, कोई श्रन्य कार्य ही क्यों न करता हो । इसी प्रकार श्राज दिन श्रुद्ध कही जानेवाली जाति के श्रनेक श्रादमी ब्राह्मण, च्रत्री या वैश्य वर्ण के काम करते हैं, श्रीर ब्राह्मण, च्रत्री तथा वैश्य वर्ण के श्रादमी श्रद्धों का काम करते हैं । फिर भी ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही कहा जाता है, श्रीर श्रद्ध का लड़का श्रद्ध ही ।

यह बात विशेषतया इसलिए अखरने वाली है कि यहाँ कुछ जातियों को उच्च और दूसरों को नीच माना जाने लगा है। आरम्भ में भिन्न-भिन्न व्यवसाय या कार्य करनेवालों में ऊंच-नीच का मेद-भाव नहीं था। पीछे जाकर लोगों में यह धारणा हो गयी कि अमुक कार्य करनेवाला उच्च वर्ण या जाति का है, और अमुक कार्य करने वाला नीची जाति का है। वास्तव में जातियों का आधार अम-विभाग है, और इसमें मुख्य विचार यह रहता है कि समाज का जो अंग अथवा जो व्यक्ति जिस कार्य को अच्छी तरह

कर सके, वह उस कार्य को करे, जिससे उसके समय और शैक्ति का अधिक से अधिक उपयोग हो, उसका अप-व्यय न हो। अत: समाज के लिए किये जानेवाले प्रत्येक प्रकार के अम का सम्मान होना चाहिए। किसी भी प्रकार के उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह या जाति को निम्न श्रेणी का समभा जाना अनुचित है, सामाजिक अन्याय है, इसका निवारण होना चाहिए।

यह ठीक है कि सन्तान में माता-पिता के कुछ गुण स्वभावतः होते हैं, श्रीर वालक पैत्रिक व्यवसाय को सुगमता-पूर्वक सीख सकते हैं। परन्तु जब लड़का पिता के काम को छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करने लगता है, श्रीर यह किया कई पीढ़ियों तक चलती रहती है तो मनुष्यों में उनके पैत्रिक व्यवसाय की योग्यता मिलने की सम्भावना क्षीण हो जाती है। इस प्रकार श्राज-दिन मनुष्यों की जाति उनके जन्म श्रायति वंश के श्रनुसार मानना निरर्थक है। उदाहरण्यत् एक श्रादमी को बाह्यण्या वैश्य केवल इसलिए मानना कि पांच-सात अथवा दस-बीस पीढ़ी पहले उसके पूर्वज ब्राह्मण्या या वैश्य का कार्य करते थे, कुछ श्रार्थ नहीं रखता। देश में यह श्रान्दोलन हो रहा है कि वर्णों (जातियों) का श्राधार जन्म न माना जाकर, व्यवसाय या पेशा माना जाय। इस प्रकार के विचार शिक्षित श्रीर विवेक-शील व्यक्तियों के मन में श्रिधकाधिक स्थान पाते जा रहे हैं, परन्तु चिरकाल के जमे हुए संस्कार मन से सहज ही नहीं हटते। ऐसे कार्य में धीरे-धीरे ही सफलता मिलती है।

समता और सहकारिता की आवश्यकता-नागरिकता

की हिन्दें से यह अत्यन्त आवश्यक हैं, समाज के विविध समूहों में कंच-नीच का भेद-भाव न हों: ऐसा भाव समाज के लिए बहुत हानिकार है, इससे सामाजिक जीवन में बड़ी विषमता श्रीर कट्टता उत्पन्न होती है। समाज का कार्य सुचार रूप से चलने के लिए परस्पर साम्य श्रीर सहकारिता के भाव की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। कल्पता कीजिए, जिन्हें समाज में नीच समभा या कहा जाता है, उनका सहयोग न रहे तो उच जातियों के श्रादिमयों का जीवन कितना कष्टमय हो। उदाहरण के लिए, धोबी कपड़े न धोये तो उन्हें पहनने को उजले कपड़े कहाँ से मिलें, नाई हजामत न करे तो सब को जटाघारी ही बनना पड़े. यदि मेहतर टट्टी साफ़ न करे तो सब को जंगल की हवा खानी पड़े ! इससे स्पष्ट है कि घोबी. नाई तथा मेहतर आदि का काम समाज के लिए कितने महत्व का है। किर, इन्हें नीच वर्ण का क्यों समभा जाय। इनके कार्य की उत्योगिता है, तो इन्हें समाज में उचित सम्मान भी मिलना चाहिए; यह कोई रियायत या मेहरबानी नहीं, साधारण अधिकार और न्याय की बात है।

सामाजिक सुविधा के लिए एक और विषय भी विवारणीय है व्यक्तियों की भाँति समूहों का भी अपने हित और स्वार्थ की बात सोचना स्वाभाविक है। परन्तु इसके साथ ही इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि कोई समूह केवल अपने ही स्वार्थ की बातें न सोचा करे, प्रत्येक समूह को दूसरों के हित का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए। इड़ समूह ऐसे हैं, जिनका परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है, उनका तो एक-दूसरे से सहयोग हुए बिना ठीक तरह से काम ही नहीं चल

सकता । उदाहरखवत् किसानों श्रीर ज़मीदारों में, मज़दूरों श्रीर (मिलों श्रीर कारखानों के) मालिकों में, लेखकों कौर प्रकाशकों में श्रच्छा सहानुभूति पूर्ण ब्यवहार होना समाज हित के लिए श्रनिवार्य है। बहुधा श्रनुदार या संकीर्ण दृष्टि के कारण धनी वर्ग इस सिद्धान्त को भूल जाता है. श्रीर श्रपने श्राप को श्रधिक धनवान बनाने में उचित -श्रवचित का विचार नहीं करता। फल-स्वरूप समाज में विकट संघर्ष उपस्थित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों उपर्युक्त समृहों का परस्पर वर्ग-बैर है। सामाजिकता श्रीर नागरिकता चाइती है कि इस में सम्यक् सुधार हो, कोई ब्यक्ति, श्रथवा व्यक्ति समूह श्रपने स्वार्थ में ऐसा लवलीन न हो कि दूसरों के उचित हितों की अवहेलना करें। सब व्यक्ति, चाहे वे किसी भी व्यवसाय या पेशेवाले हों, परस्पर सहयोग श्रीर सहानुभृति का भाव रखें। सब के हित में हमारा भी हित है। केवल अपने-अपने हित का साधन करने से समाज का वास्तविक हित न होगा: फल स्वरूप हमारा भी यथेष्ट कल्याण न होगा। ऋतः प्रत्येक समूह उदार दृष्टि-कोण रखे, श्रीर दूसरों के भी हित की बात सोचा करे।

व्यवसायिक समूहों का आदर्श — अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में, वैज्ञानिक उन्नांत के कारण श्रीचोगिक कान्ति हुई। तब से श्रार्थिक जीवन का विस्तार हो गया है, सर्व साधारण के लिए जीवन-संघर्ष बढ़ गया है। अब आदमी अधिकाधिक श्रार्थिक विषयों में लीन रहते हैं। व्यवसायिक समूहों की उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है। अत्येक व्यवसाय वाले अपना अलग संगठन करके कोई संघ श्रादि

वनाते रहते हैं। किसान, मजदूर, जमींदार, व्यापारी, मिल-मालिकों के आतिरिक्त पोस्टमैन, रेलवे-कर्मचारी, अध्यापक, लेखक, सम्पादक, वकील, डाक्टर, मुन्शी-मुहरिंर, धोबी, दर्जी, लुहार, बढ़ई, मेहतर आदि भी अपना-अपना संगठन कर रहे हैं। सब 'किलियुग में संघ ही' शिक्त है' का मूल मंत्र प्रहण कर रहे हैं। संगठन करना और शिक्त बढ़ाना बुरा नहीं। पर उसका दुरुपयोग न होना चाहिए, उसके सदुपयोग की आर सम्यक् ध्यान रहना आवश्यक है।

वर्तमान श्रवस्था में प्रत्येक समृह श्रपनी उन्नति श्रीर स्वार्थ-सिद्धि में यह बात भूल जाता है कि वह एक वृहत् समाज का अंग है, श्रीर उस बृहत समाज के हित का विचार उसे हर घड़ी, अपने प्रत्येक कार्य में, रखना चाहिए। प्रायः होता यह है कि हमारा हिष्ट-कोण एकांगी रहता है, व्यापक नहीं होता, व्यवसायिक समूह केवल अपने हित की ही बात सोचता है, श्रौर समाज के उन श्रंगों के हित की भी श्रवहेलना करता है, जिनसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ अनेकः श्रध्यापक-संघ यह तो सोचते हैं कि हमारे सदस्यों को श्रधिक वेतन मिले, वेतन वृद्धि जल्दी-जल्दी हो, स्कूल में छुट्टियाँ श्रासानी से तथा सवेतन मिल सकें, इत्यादि । परन्तु वे इस बात का विचार बहुत कम करते हैं कि जो बालक उनके पास शिक्षा पाते हैं उन्हें अधिक-से-अधिक योग्य और सदाचारी कैसे बनाया जाय, स्कूल के समय के अतिरिक्तः अन्य समय भी उनकी देख-भाल करें, तथा उन्हें एवं उनके सरक्षकों को उचित परामर्श दिया करें। अध्यापकों का काम यही नहीं है कि अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को स्कूल की परी चाओं में पास करा दें,

उनका कर्तव्य भावी नागरिकों को उनके जीवन की परीचाओं में अधिक-से-अधिक सफल बनाने में सहायक होना है। अतः उनके संघ को इस श्रोर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार लेखकों के संघ का कार्य यही नहीं है कि उनके सदस्यों को ऋधिक-से-ऋधिक पारिश्रमिक मिले, उन्हें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि लेखकों द्वारा जो चाहित्य प्रस्तुत किया जाता है, वह जनता के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला न होकर उसे सुधारनेवाला हो। किसी लेखक-संघ को, अपने आपको प्रकाशकों का प्रतिद्वन्दी न समभ कर, उन का सहयोगी समस्ता चाहिए। प्रकाशकों का भी काम है कि लेखकों के परिश्रम से ऋत्यधिक लाभ उठाने की बात न सोचें, वरन् वे श्रव्छा उच कोटि का साहित्य प्रस्तत करने के लिए लेखकों को विविध सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयत्न किया करें। इसी प्रकार ज़मीदारों को किसानों के हित का, श्रौर मिलों तथा कारख़ाने के मालिकों को मज़द्रों के हित का तो ध्यान रखना ही चाहिए; उसके साथ यह भी त्र्यावश्यक है कि जो वस्तु उत्पन्न की जाती है, या तैयार की जाती है, उसको श्रधिक-से-श्रधिक श्रच्छे श्रीर उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाय।

इस सिद्धान्त की श्रोर समुचित ध्यान न दिये जाने का फल यह है कि प्रत्येक श्रार्थिक च्लेत्र में विकट संघर्ष विद्यमान है। ज़मीदार किसानों पर श्रत्याचार करते हैं, श्रोर किसान ज़मींदारों के विरुद्ध खड़े होते हैं। मज़दूर हड़ताल करते हैं श्रोर मिल-मालिक उनका काम पर श्राना बन्द करते हैं। यह सब केवल सम्बन्धित समृहों के लिए ही हानिकर नंहों है, वरन समाज की दृष्टि से भी अहितकर है। बहुत से व्यवसायिक समूहों का आधार जाति-गत या साम्प्रदायिक होता है। ऐसे समूहों से जाति-गत ईर्षा द्वेष बढ़ता है; यह निन्दनीय है। समाज में प्रत्येक समूह का स्वार्थ दूसरे समूह के स्वार्थ से मिला हुआ । रहता है, और एक समूह को हानि पहुँचाने का अर्थ अन्य समूहों को भी आगे-पीछे हानि पहुँचना होता है। प्रत्येक समूह को यह बात हृद्यंगम करनी चाहिए, उसे अपने स्वार्थ की पृथक रूप से चिन्ता न कर, उसे दूसरे समूहों के स्वार्थ के साथ सामंजस्य करना चहिए। जब ऐसा न हो तो राज्य को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वह सब समूहों के हित का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसे विभिन्न समूहों के पारस्परिक संघर्ष को मिटाने का प्रबन्ध करना चाहिए। अस्तु, प्रत्येक व्यवस्थािक समूह का आदर्श यह होना चाहिए कि वह सार्वजनिक हित की कामना करे, और उसकी पूर्ति में पूर्णतया योग दे।

व्यवसायिक समूह श्रोर व्यक्ति—प्रत्येक व्यवसायिक समूह श्रोर उसके सदस्यों का घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों को एक दूसरे के उत्थान श्रोर विकास का प्रयत्न करना चाहिए। समूह का कर्तक्य है कि वह व्यक्ति की कठिनाइयाँ दूर करे, श्रोर उसे श्रावश्यक सुविधाएँ प्रदान करे। व्यक्ति की उन्नित से उसकी भी उन्नित होगी, क्योंकि वह व्यक्तियों का ही तो बना है। इसी प्रकार व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह श्रपने कार्य-व्यवहार से श्रपने समूह का गौरव बढ़ावे। श्राज-कल लोगों की श्रादर्श-होनता श्रौर सिद्धान्त-श्रवहेलना से जन साधारण की यह घारण हो चली है कि व्यवसाय का उद्देश्य स्वार्थ-

साधन है। व्यवसाय में लगा हुआ कोई व्यक्ति सचाई ईमानदारी आदि का आदर्श नहीं रख सकता। व्यक्तियों का कर्तव्य है कि अपने अपने व्यवसाय में इन सद्गुणों का परिचय देकर लोगों की उक्त धारणा को निर्मूल करें। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने व्यवसाय को केवल धनोपार्जन का साधन न समक्त कर उसे अपने विकास का साधन बनावे। हम अपने व्यवसाय को खूब मन लगा कर करें, और विविध किंवनाइयाँ उपस्थित होने पर भी अपने सुनिर्धारित सिद्धान्तों से विचलित न हों तो हमारा व्यवसाय निरसन्देह हमारा उत्थान करने वाला होगा।

कुछ श्रादमी समभते हैं कि व्यवसाय में लग जाने से श्रादमी देश-भिक्त, नागरिकता, या समाज-सेवा नहीं कर सकता। यह समभ उीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह श्रपना व्यवसाय करते हुए ही देश-भिक्त श्रादि का सम्यक् परिचय दे सकता है। यह श्रावश्यक नहीं है कि देश-भिक्त के लिए कोई खास प्रकार का ही व्यवसाय किया जाय। चाहे जो भी कार्य हो, उसी में देश-भिक्त की भावना का समावेश किया जा सकता है। लेखक, श्रध्यापक श्रादि श्रपना कर्तव्य-पालन करते हुए देश-भिक्त कर सकते हैं, श्रीर दूसरों को देश-भक्त बना सकते हैं, यह तो सहज ही ध्यान में श्रा सकता है। परन्तु हमारा वक्तव्य यह है कि कार्य कोई भी हो, यह तो उसके करनेवाले व्यक्ति पर निर्भर है कि वह उसमें सेवा या परोपकार श्रादि का भाव रखे। उदाहरणार्थ दुकानदार की ही बात लीजिए, वह श्रच्छा माल रखता है, साधारणतया सुनिर्धारित मुनाफा लेते हुए,

उसे उचित मूल्य पर बेचता है, ढीक तोलता है, कोई बालक या अनजान आदमी भी उसके यहाँ माल लेने आवे तो उसे ठमने की कोशिश नहीं करता, अपने माल के दोष को छिपाकर या उसमें कुछ मिलावट करके आहकों की आँखों में धूल फोंकने का तथा उनके धन और स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करता, अकाल या मँहगी के समय अपने स्वार्थ के लिए उसके मूल्य में अपिरिमित बृद्धि नहीं करता, वरन् त्याग-भाव से उसे सस्ता ही बेचता है, तो कौन उस दुकानदार के नागरिक भावों की प्रशंसा न करेगा! इस व्यक्ति के देश-भक्त होने में क्या संदेह है ? ऐसे व्यक्ति दुकानदारों में, यथेष्ट संख्या में हो तो दुकानदारी का गौरव बढ़ने में क्या सन्देह है ? अस्तु, अपने व्यवसाय का मान बढ़ाना, यह प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। व्यवसायिक समूह को चाहिए कि वह अपने सदस्यों के सामने सफलता का ऐसा आदर्श उपस्थित करे, और उन्हें ऐसा आदर्श रखने के लिए प्रोत्साहित करे।



ञ्जाठवाँ परिच्छेद राजनैतिक समृह

श्रीर व्यवसायानुसार समूह के विषय में विचार किया गया है। इनके श्रातिरक्त मनुष्यों के समूहों का एक और प्रमुख भेद वह होता है, जो मनुष्यों के राजनैतिक मतानुसार होता है। जिस प्रकार लोगों के व्यवसाय मिन्न-भिन्न होते हैं। उनके धार्मिक विचार पृथक्-पृथक् होते है, उसी प्रकार उनके राजनैतिक विचार मी मिन्न-भिन्न होते हैं। जिन लोगों के राजनैतिक विचार एक प्रकार के होते हैं, उनका समूह दूसरे प्रकार के राजनैतिक विचार एक प्रकार के होते हैं, उनका समूह दूसरे प्रकार के राजनैतिक विचारवालों के समूह से भिन्न होता है। इस प्रकार एक देश में राजनैतिक मतानुसार कई समूह हो सकते हैं, श्रीर समय-समय पर नये समूहों के बनने तथा प्रराने समूहों के विज्ञत होते रहने से सब समूहों की संख्या में श्रन्तर होता रहता है।

राजनैतिक मतानुसार बने हुए समृहों का स्थूल वर्गीकरण इस ६ प्रकार किया जा सकता है—(१) पराधीन देश के अन्तर्गत (२) स्वा-धीन देश के अन्तर्गत, (३) राज्य से बाहर के चेत्र से भी सम्बन्धित । इनका क्रमशः विचार किया जायगा।

पहले उस समूह का उल्लेख कर देना आवश्यक है जो राज्य को अनावश्यक, तथा समाज के लिए अहितकर समभता है। इस समूह के व्यक्तियों का मत है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अभी समाज अपूर्ण या अविकसित अवस्था में है, इसलिए उसे राज्य जैसी नियंत्रण करनेवालो सत्ता की आवश्यकता है; जब समाज उन्नत और विकसित हो जायगा, उसे राज्य की आवश्यकता न रहेगी। हमें चाहिए कि समाज की उस परिस्थित को लाने का प्रयत्न करें, जिसमें राज्य की आवश्यकता ही न रहे। इस समूह के, देश काल के अनुसार कई मेद हैं।

राजनैतिक समृह, पराधीन देशों में — अब हम राजनैतिक मतानुसार बने हुए उन समृहों पर विचार करते हैं, जो पराधीन देशों में होते हैं। कुछ आदमी क्रांतिवादी होते हैं। ये सत्ताधारियों को हटाकर स्वराज्य स्थापित करने के पक्ष में होते हैं। इनके भी दो मेद मुख्य होते हैं, (१) सशस्त्र-क्रान्तिवादी; ये शस्त्रास्त्रों के बल से, हिंसा के प्रयोग से, सत्ताधारियों को भगा देने या उनको नष्ट करने के पत्त में होते हैं, जिससे उनका इतना आतंक जम जाय कि कोई दूसरी शांक उनके देश को पराधीन करने का साहस न करे, उनके देश को स्वराज्य मिल जाय। इस विचार-पद्धतिवालों का जब तक काफी प्रवल संगठन न हो जाय, ये खुक-छिप कर रहते हैं, इन्हें अपनी सब कार्रवाई

तथा श्रस्त-शस्त्र गुप्त रखने पड़ते हैं। इन्हें श्रपने कुछ गुप्तचर भी रखने पड़ते हैं, जो इस बात का पता लगाते रहें कि कौन मुख्य श्रिषकारी किस समय कहाँ होगा, कैसे उस पर श्राक्रमण करने में श्रिषक सफलता मिल सकेगी। प्रायः ऐसा होता है कि उनकी कार्रवाइयों का रहस्योद्धाटन हो जाता है, उनमें से कुछ व्यक्ति गिरफ़ार कर लिये जाते हैं, श्रीर उनके द्वारा दूसरों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंड दिया जाता है, श्रीर उनके समूह को छिन्न-भिन्न कर दिया जाता है। कालान्तर में ऐसा नया समूह बन सकता है, श्रीर फिर यह प्रयत्न होने लगता है। ऐसे समूह श्रनेक बार श्रसफल होते हैं, तो कभी-कभी श्रपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। श्रसफल होने की दशा में ये विद्रोही, क्रांतिकारी श्रादि कहे जाते हैं, श्रीर इनके कुछ श्रमणी मौत के घाट उतारे जाते हैं, दूसरे प्रायः श्राजन्म कारावास सुगतते हैं। हाँ, जब-कभी ये श्रपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं तो देश का शासन-सूत्र इनके ही हाथ में श्राजाता है।

कान्तिवादियों का दूसरा समूह श्रहिंसा-त्रती होता है । इस समूह के व्यक्ति सत्ताधारियों को जान-माल की हानि पहुँचाये बिना ही श्रपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। ये श्रपने विपक्षियों के प्रति भी प्रेम-भाव रखते हैं, श्रीर श्रपने सात्विक प्रयत्नों द्वारा उनके हृदय-परिवर्तन करने के पक्ष में होते हैं। इस मत का विशेष संगठन श्रीर प्रचार श्राधुनिक काल में ही हुआ है। इसके प्रधान प्रवर्तक टालस्टाय श्रीर महात्मा गांधी हैं। श्रहिंसक क्रान्तिवादियों के मुख्य साधन सत्याग्रह श्रीर श्रसहयोग हैं। उनके मतानुसार देश में रचनात्मक कार्य करके क्रमशः जनता का संगठन करना श्रोर उसका नैतिक तथा श्रार्थिक बल बढ़ाना श्रावश्यक है। उनका यह श्रादेश होता है कि श्रनुचित कान्नों को भंग करो श्रोर उसके लिए श्रावश्यक दंड सहर्ष सहन करो, साथ ही शासकों से ऐसा श्रसहयोग करो कि उन्हें शासन-यंत्र चलाना ही दूमर हो जाय; वे शासन-कार्थ को छोड़ने को बाध्य हो जायँ श्रोर देश में स्वराज्य की स्थापना हो, जिसे संमा-लने के लिए जनता पहले से ही, रचनात्मक कार्य-क्रम द्वारा, तैयार रहे। भारतवर्ष में उपर्युक्त प्रकार का समृह कांग्रेस है, श्रोर उसके सामने यह कार्य-क्रम सन् १९१९ ई० से ही है।

पराधीन देशों में एक समूह सुधारवादियों का होता है। वे काँति करना पसन्द नहीं करते। वे शासन-यंत्र में क्रमशः सुधार कराते रहना चाहते हैं, जिससे अन्त में शासन-कार्य शासितों के लिए बहुत कष्टप्रद या हानिकर न रहे। उनके प्रयत्न से जो कार्य होता है, वह जल्दी पूरा होने, में नहीं आता; शासक थोड़ी-थोड़ी रियायतें करके इस समूह को प्रसन्न करते रहते हैं। उनके कुछ आदिमियों को उच्च पद मिल जाते हैं, जनता की कुछ असुविधाएँ दूर कर दी जाती हैं। परन्तु यह सब-कुछ होता है, अधिकारियों की छत्र-छाया में ही, और उनकी ही कृपा-हिष्ट के फल-स्वरूत। आर्थिक और राजनैतिक सत्ता वास्तव में अधिकारियों के ही हाथ में रहती है, जनता को यथार्थ स्वराज्य प्राप्त नहीं होता; हाँ, स्वराज्य के नाम पर, कृत्रिम या दिखावटी स्वराज्य अवश्य प्रदान कर दिया जाता है।

भारतवर्ष में उपर्यु क प्रकार का समूह 'लिबरल' दल है। इसके

वार्षिक अधिवेशन हो जाते हैं, उसमें अनेक प्रस्ताव स्वीकाँर किये जाते हैं, समय-समय पर कुछ नेताओं के वक्तव्य निकल जाते हैं, इसे छोड़कर, इस समूह का क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य प्राय: नगएय है। देश की विशाल जन-संख्या में इसके नियमानुसार सदस्य केवल कुछ, हजार ही हैं, जबिक कांग्रेस का संगठन नगर-नगर और गाँव-गाँव में है, और इसके नियमानुसार शुल्क देकर बने हुए सदस्यों की संख्या खालों पर है। हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग भी अंशत: ऐसे समूहों में शामिल की जा सकती है। पर इनमें साम्प्रदायिकता की भावना है। मुसलिम लीग तो केवल कुछ कट्टर मुसलमानों के ही मत की स्वक है। *

पराधीन देशों में एक समूह ऐसे लोगों का भी होता है, जो देश की स्वाधीनता की बिल्कुल चिन्ता नहीं करते, उसे अपने स्वार्थ-साधन का हो ध्यान रहता है। इसलिए वह सदैव शासकों की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता है। वह शासकों के प्रत्येक कार्य का समर्थन ही नहीं करता, उसके साथ तन, मन और धन से सहयोग करता है। यही नहीं, इस समूह के आदमी अनेक बार शासकों का भाव देखकर दमन या शोषण-कार्य उस सीमा तक भी करने लगते हैं, जहाँ तक कदाचित शासक भी न करें। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने देश-बन्धुओं के हितों की अवहेलना तक करते हैं, और इस प्रकार अपने नागरिक कर्तव्य पालन न करने के

^{*}भारतवर्ष के इन राजनैतिक समूहों के सम्बन्ध में श्रागे 'राजनैतिक दलवंदी' शीर्षक परिच्छेद में लिखा जायगा।

दोषी हीते हैं। इन लोगों के समूह को 'जी-हजूर' समूह कहा जा सकता है।

भारतवर्ष में श्रिधिकतर राजा महाराजा, नवाब, तालुकेदार, जमींदार, पूंजीपित, महन्त, सरकारी नौकर तथा सरकारी पेंशन पाने-वाले इस श्रेणी में है। यद्यपि इनमें कुछ सुन्दर श्रपवाद भी है, श्रिधिकतर व्यक्तियों की भावना राष्ट्र-विरोधी ही है। पिछले राष्ट्रीय श्रान्दोलन के समय श्रमन-सभाश्रों के संयोजक श्रीर संचालक प्रायः ये ही लोग थे।

स्वाधीन देशों में — अस्त, यह तो राजनैतिक मतानुसार बने हुए उन समृहों की बात हुई जो पराधीन देशों में होते हैं। अब हम इस प्रकार के ऐसे समृहों पर विचार करते है, जो स्वाधीन देशों में होते हैं। यहाँ इन समृहों को स्वराज्य प्राप्त करने का कार्य नहीं करना होता, केवल उसकी रक्षा तथा राज्य की उन्नति करना होता है। रक्षा करने का प्रश्न विशेष रूप से उसी दशा में उपस्थित होता है, जब उनके राज्य पर किसी का आक्रमण होता हो, या होने वाला हो। ऐसे अवसर पर राज्य के विविध समृह अपना मेद-भाव मिटाकर सम्मिलित शक्ति से काम करते हैं। इस प्रकार उस समय प्रायः एक ही समृह प्रधानतया कार्यशील रहता है।

राज्य की उन्नित के सम्बन्ध में लोगों के विचारों में काफ़ी मत-मेद रहता है। मत-मेद का विषय प्रायः आर्थिक कार्य-क्रम होता है। एक समूह एक योजना अपने सामने रखता है, दूसरा समूह अन्य प्रकार से ही राज्य की आर्थिक उन्नित होने में विश्वास करता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न मत या श्रादर्श के श्रनुसार राज्य में श्रनेक समूह होते हैं; यथा व्यक्तिवादी, समाजवादी, बोलशेविक, नाज़ी, फैसिस्ट श्रादि । जिस समूह का कार्य-क्रम जनता को श्रिषक उपयोगी तथा व्यवहारिक प्रतीत होता है, उसमें श्रीधक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं; इसके विपरीत, जिस कार्य-क्रमवाला समूह विशेष सफलता प्राप्त करने वाला प्रतीत नहीं होता, उसके सदस्यों की संख्या कम होनी स्वामार्विक ही है। श्राज-कल ये दल नित्य नये बनते रहते हैं, श्रीर प्रत्येक राज्य में इनकी ख़ासी संख्या होती है। जिन राज्यों में डिक्टेटर या श्रीधनायक का प्रभुत्व है, वहाँ प्रायः एक ही समुह प्रमुख रहता है। यह समूह वह होता है जो डिक्टेटर का समर्थक तथा श्रनुयायी होता है। श्रन्य मत सब गौण हो जाते हैं। हाँ, इन समूहों में से भी कोई-कोई जुपचाप प्रचार करके श्रपनी शक्ति श्रीर संगठन बढ़ाता श्रीर उस समय की प्रतीक्षा करता है, जब डिक्टेटर की डिक्टेटरी का श्रन्त हो जाय श्रीर यह समूह प्रमुख समूह का उत्तराधिकारी बन सके।

अन्तर्शष्ट्रीय समूह — अब राजनैतिक मतानुसार बने हुए ऐसे समूहों पर विचार करें, जिनका चेत्र किसी राज्य विशेष तक परिमित न होकर कई-कई राज्यों तक विस्तृत हो। कुछ समूह दो या अधिक राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत धनिष्ट करने का उद्देश्य रखते हैं, ये ऐसी ही योजनाएँ बनाते तथा उन्हें अपल में लाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ समूहों का विचार-चेत्र कोई साम्राज्य विशेष होता है। इनका उद्देश्य उस साम्राज्य के हितों

की रक्षा श्रीर वृद्धि करना होता है। प्रत्येक साम्राज्य में एक राज्य प्रमुख होता है, दूसरे भाग उस राज्य के न्यूनाधिक श्रधीन होते हैं। फलतः उक्त समूह का उद्देश्य विशेषतया उस प्रमुख राज्य (तथा उसके स्वाधीनता-प्राप्त राज्यों का) हित-साधन होता है, चाहे इससे साम्राज्यान्तर्गत श्रधीन देशों की कितनी ही हानि क्यों न हो।

वैज्ञानिक आविष्कारों और उन्नति ने संसार की एकता बढा दी है। अब एक देश के सुख-दुख का प्रभाव कभी-कभी संसार के द्र-दर के देशों पर भी पड़ता है। यदि एक देश में दुर्भिक्ष पड़ता है या भूकम्प आता है तो अन्य देशों के अनेक आदमी उससे सहानुभृति-सूचक न्यवहार करते हैं, उसे धन-जन से सहायता पहुँचाते हैं। इसी प्रकार यह सोचनेवालों की संख्या क्रमशः बढती जाती है कि यदि एक राज्य अपने श्रस्त-शस्त्रों की बहुत श्रधिक बृद्धि करे श्रीर युद्ध के लिए तैयार हो तो श्रन्य राज्यों पर बड़ा संकट उपस्थित हो सकता हैं। श्रतः विविध राज्यों में श्रम्त्र-शस्त्रों तथा युद्ध-सामग्री का परिमाण परिमित रहना चाहिए। ऐसे ही विचारों से पिछले महायद के पश्चात सन् १९२० ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य दो या अधिक राज्यों को परस्पर लड़ने से रोकना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि करना है। इसका प्रधान कार्यालय जेनेबा (स्विटजरलैंड) में है। इसके सम्बन्ध में विशेष, इस पुस्तक के दूसरे भाग में लिखा जायगा । यहाँ हमें कुछ श्रन्य बातों पर विचार कर लेना है ।

राज्य तथा राष्ट्र—किसी राज्य में सब से बड़ा राजनैतिक समूह स्वयं वह राज्य ही होता है। राज्य के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक श्राले परिच्छेदों में लिखा जायगा। संचेप में, राज्य किसी मू-भाग के उस जन-समूह को कहते हैं, जिसका भली-भांति संगठन हो, श्रीर जो स्वाधीन हो, किसी श्रन्य राज्य के श्रधीन न हो। श्रस्तु, यहाँ हमें एक दूसरे राजनैतिक समूह के विषय में विचार करना है; यह समूह है, 'राष्ट्र'। पहले यह जान लेना चाहिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं।

ं संचेप में राष्ट्र उस जन समूह को कहा जाता है, जिस में भाषा, धर्म, जाति, और संस्कृति आदि में से किसी एक या अधिक प्रकार की एकता होने के अतिरिक्त भावों या हृदय की एकता श्रवश्य हो, जो स्वतंत्र हो, या जिसमें स्वतंत्र होने की कामना हो। राष्ट्र की व्याख्या में श्रनेक लेखकों ने विस्तार-पूर्वक लिखा है। उसका श्राशय यही है कि मानव-समाज के किसी श्चंग को राष्ट्र उसी दशा में कहा जाता है, जब उसके व्यक्ति परस्पर ऐसी सहानुभृति से मिले हुए हों, जैसी उनकी अन्य आदिमियों से न हों. उनका परस्पर इतना सहयोग हो जितना दूसरों से न हो, वे एक ही शासन में रहने के इच्छक हों, श्रीर उनकी यह श्रमिलाषा हो कि वह शासन उनका ही हो, अथवा केवल उनमें से ही कुछ -लोगों का। राष्ट्रीयता की यह भावना अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कभी-कभी इसका कारण यह होता है कि वे लोग एक ही जाति के होते हैं। भाषा और धर्म की एकता से इसमें बहत सहायता मिलती है। भौगोलिक एकता भी इसका एक मुख्य कारण होती है, राजनैतिक परम्परा की समानता का तो इसमें बहुत ही भाग होता है। राष्ट्रीय इतिहास, समान समध्टिगत गौरव श्रौर श्रपमान,

सुख-दुख' की स्मृतियाँ और समान भविष्य की आशाएँ राष्ट्र निर्माण की महत्व-पूर्ण सामग्री होती है।

कभी-कभी राज्य और राष्ट्र को एक ही समक्त लिया जाता है।
परन्तु इन दोनों में बहुत अन्तर है। प्रथम तो राज्य के लिए स्वतंत्र
होना अनिवार्य है, राष्ट्र के विषय में यह बात नहीं है, स्वतंत्रता-प्राप्ति
का उद्योग करनेवाला संगठित जन समृह भी राष्ट्र कहा जा सकता
है। दूसरी बात यह है कि राज्य का चेत्र एक देश विशेष तक ही
परिमित रहता है, राष्ट्र का चेत्र अपरिमित है, उसके व्यक्ति अपने देश
से बाहर जाने पर भी राष्ट्र ही कहे जाते हैं।

व्यक्ति, राष्ट्रीयता और मानवता—पहले कहा गया है कि
राष्ट्र के श्रादिमियों में सब से बड़ी एकता भावों या हृदय की एकता होती
है। जहां एक ग्राम, नगर या प्रान्त के निवासियों को कच्ट हो तो श्रन्य
सब श्रादिमियों को चाहिए कि उनसे सहानुभूति रखते हुए उनके
कच्ट को निवारण करने का जी-जान से प्रयत्न करें; श्रीर जब तक
इसमें सफलता न मिले, चैन न लें। राष्ट्र के मनुष्यों को यह समभना
और श्रनुभव करना चाहिए कि इम सब एक मातृ-भूमि (या पितृ-भूमि)
की सन्तान है, परस्पर भाई-बन्धु हैं, दूसरे के सुख-दुख में हमारी भी
लाभ-हानि है। किसी व्यक्ति को भय से या प्रलोभन से भी श्रपने राष्ट्रबन्धुओं को हानि पहुँचाने का विचार न करना चाहिए। व्यक्ति का
कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के हित और उत्थान को श्रपना हित और
उत्थान समभे।

कुछ लोगों का कथन है कि जब किसी देश के मनुष्यों में राष्ट्रीयता

का भाव उदित हो जाता है तो उनके विचारों या कार्यों में स्वतंत्रता नहीं रहती, राष्ट्रीयता के भाव में व्यक्तित्व का भाव विलीन हो जाता है। व्यक्ति के सुख-दुख, आशा-निराशा, दया, स्नेह, प्रेम आदि सुकुमार प्रवृतियाँ राष्ट्रीयता के भार से दब जाती हैं। मनुष्य राष्ट्र-रूपी यंत्र का एक पुर्ज़ा मात्र रह जाता है। यह कथन कहाँ तक ठीक है १ तिनक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि यह राष्ट्रीयता के दुरुपयोग का अतिरंजित चित्र है। वास्तव में राष्ट्रीयता मनुष्य को यह शिच्चा देती है कि वह अपने विचार-चेत्र को विस्तृत करे; मनुष्य केवल अपने लिए या अपने परिवार अथवा जाति के ही लिए नहीं है, उसे देश भर के मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म आदि के क्यों न हों, प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार यह उसको असम्यावस्था की, परिमित चेत्रवाली स्थिति से निकालकर उसके दया, त्याग और सहयोग आदि सद्गुणों के विकास में सहायक होती है।

स्मरण रहै कि वास्तविक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीयता का अभिप्राय यही तो है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख-दुख को अपना सुख-दुख समक्ते, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि न पहुँचावे, और ऐसा करने में उसकी दृष्टि केवल अपने राष्ट्र तक ही सीमित न रहे। हम ऊपर कह आये हैं कि राष्ट्रीयता मनुष्य की संकीर्णता को हटाकर, उसे उदारता का पथ दर्शाती है। मनुष्य की उन्नति या विकास का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसे किसी राष्ट्र या देश की चार-दिवारों में बन्द न रहना चाहिए। मनुष्य श्रंपने परिवार, जाति, ग्राम, नगर, राज्य, राष्ट्र श्रादि की विविध मंज़िलों को पार कर जुकने पर भी श्रंपनी यात्रा का श्रन्त न समक्त ले, उसे श्रौर श्रागे चलना है, उसे विशाल मानव-समाज में मिलना है; तभी उसे मानवता का श्रनुभव होगा श्रौर इतना विकलित होने पर ही वह वास्तव में 'मनुष्य' पद का श्राधिकारी होगा।



नवाँ परिच्छेद

राज्य ऋौर उसके तत्व

क्य और अन्य समूहों में भेद पिछले परिच्छेदों में मनुष्यों के कई प्रकार के समूहों का वर्णन किया गया है। वे समूह कुछ बातों में राज्य से मिलते हैं; राज्य स्वयं एक बड़ा समूह है। परन्तु राज्य में कई विशेषताएँ ऐसी हैं, जो उनमें नहीं हैं। अन्य समूहों से सम्बन्ध रखना न रखना, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है; वह चाहे तो उनका सदस्य बने और चाहे न बने; सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ व्यवसायानुसार कई समूह होते हैं, कोई व्यक्ति चाहे जिस एक का सदस्य हो सकता है; अन्य समूहों से उसका सम्बन्ध न रहेगा। यहीं नहीं, वह चाहे तो इन समूहों में से किसी का भी सदस्य न हो। ऐसा करने से वह सम्भवतः उन सुविधाओं से वंचित रहेगा जो उस समूह के सदस्यों को प्राप्त होती हैं, तथापि कोई उसे इस बात के लिए वाध्य नहीं कर सकता कि वह किसी समूह का सदस्य अवश्य ही बने। किन्तु राज्य के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। राज्य का सदस्य तो प्रत्येक

व्यक्ति की बनना ही पड़ेगा । जो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं है, वह उसका पूरा सदस्य नहीं है, तथापि उस पर राज्य का श्रिषकार या नियन्त्रण तो रहता ही है। यदि कोई व्यक्ति श्रपने राज्य को छोड़कर बाहर श्रन्य राज्य में चला जाता है, तो वहाँ वह उस राज्य के नियन्त्रण से मुक्त नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी राज्य के श्रधीन रहना पड़ता है।

र्याद किसी अन्य समृह का व्यक्ति अपने समृह के प्रति कुछ, अपराध करे तो उसे परिमित परिमाण में दंड दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ वह कुछ जुर्माना आदि कर सकता है। व्यक्ति चाहे तो उस दंड को सहन करने के बजाय उस समृह से पृथक् हो सकता है। परन्तु राज्य के विषय में यह बात नहीं; राज्य से पृथक् तो वह हो ही नहीं सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि वह एक राज्य से पृथक् होता है, तो दूसरे से सम्बन्ध हो जाता है। रही दंड की बात, सो राज्य व्यक्ति को फाँसी तक का दंड दे सकता है। इस प्रकार का दंड देने का अधिकार अन्य समृहों को नहीं होता।

राज्य में एक विशेषता यह भी है, कि वह अन्य सब समूहों से ऊपर है। वह सब समूहों पर नियंत्रण करता है, उनके कार्य-चेत्र की मर्यादा निश्चित करता है, और प्रत्येक समृह को दूसरे के उचित कार्य में बाधा उपस्थित करने से रोकता है।

पुनः अन्य बहुत-से समूहों के सम्बन्ध में यह बात है कि उनका होना सर्वत्र अनिवार्य नहीं है, किसी समूह का किसी देश में होना वहाँ की परिस्थिति या जनता की आवश्यकता पर निर्भर है। परन्तु राज्य एक ऐसा समृह है जो मनुष्य की सम्यता के साथ श्रनिवार्थ हो गया है। भिन्न-भिन्न देशों में राज्य का स्वरूप या संगठन श्रदि भिन्न प्रकार का हो सकता है, परन्तु सम्य कहे जानेवाले प्रत्येक देश में राज्य होगा श्रवश्य ही।

यह ठीक है कि कुछ समूहों का चेत्र राज्य की सीमा से बाहर भी होता है, परन्तु अन्य सब समूह एक सीमा तक राज्य के अधीन होते हैं, उन्हें राज्य के नियंत्रण में रहना पड़ता है, और उसकी आशाओं अर्थात् कानूनों का पालन करना होता है। राज्य का निर्माण ही उस समय होता है, जब वह अपने चेत्र के सब व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकता है, उन पर अपनी आशा चला सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य अन्य समूहों से बहुत भिन्न प्रकार का होता है।

'राज्य' राज्य का व्यवहार कई जगह आ चुका है, और आगे भी होगा। हमें अञ्झी तरह जान लेना चाहिए कि राज्य से क्या अभिपाय है, राज्य किसे कहते हैं, और उसके मुख्य तत्व कौन-कौन से हैं।

राज्य के तत्व अनेक लेखकों ने राज्य की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ की हैं। उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। संदोप में राज्य उस जन-समूह को कहा जा सकता है जो एक निर्धारित भूभाग पर रहता हो, जिसका राजनैतिक संगठन हो, और जो अपने दोत्र में पूर्ण स्वतंत्र हो, किसी अन्य सत्ता के अधीन न हो। इस प्रकार राज्य

के निम्ने लिखित तत्व होते हैं:-

- (१) जनता,
- (२) भूमि,
- (३) राजनैतिक संगठन, श्रीर
- (४) प्रभुत्व शक्ति

श्रव हम इन के विषय में क्रमशः विचार करते हैं।

जनता

यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में कम-से-कम इतनी जन संख्या होनी ही चाहिए। प्राचीन-काल में, कितने ही देशों में नगर-राज्य थे, उनकी सीमा एक नगर विशेष तक ही थी। उन राज्यों के नागरिकों की संख्या कुछ हज़ार ही होती थी। पारस्तरिक युद्धों के भय, एकता की भावना, तथा यातायात के साधन श्रीर सुविधाएँ बढ़ जाने पर राज्य बड़े-बड़े होने लगे; नगर-राज्यों का स्थान देश-राज्यों ने लिया। श्रव कुछ लाख जन-संख्यावाले राज्य भी कम हैं, तथा उनका श्रास्तत्व विशेष कारणों पर श्रवलम्बत है। इस समय कितने ही राज्यों की संख्या कई-कई करोड़ की है। यदि वर्तमान विविध राज्यों का विचार करें तो उनकी जन-संख्या की विषमता की सहज ही कल्पना हो सकती है; बड़े राज्यों की जन-संख्या छोटे राज्यों की श्रपेका कई-कई गुनी हैं।

राज्य में कम से कम जन-संख्या कितनी हो, श्रौर श्रिथिक-से-श्रिधक कितनी, इसके सम्बन्ध में कोई भी सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता । हाँ, यह कहा जा सकता है कि जनता इतनी होनी चाहिए जिसका

संगठन श्रव्छो तरह हो, श्रीर जिसमें शासन-प्रबन्ध श्रव्छी तरह हो सके। जनता का कम-ज्यादह होना एक श्रंश तक भूमि के विस्तार पर भी निर्भर है। श्र श्रात्त अपनी जन-संख्या बढ़ाने के लिए श्रिषकाधिक भूमि पर श्रिषकार करना चाहते हैं। बहुधा राज्य श्रपनी जन-संख्या बढ़ाने के लिए जनता को तरह-तरह के प्रोत्साहन देते हैं। वे समभते हैं कि जनता ही राज्य का बल है। परन्तु जन-संख्या की वृद्धि एक सीमा तक ही श्रमीष्ट है, उससे श्रिषक होने पर राज्य को यह चिन्ता होनी स्वाभाविक है कि इस बढ़ी हुई जनता के रहने के लिए खुली जगह मिले श्रीर उसे खाने-पीने श्रादि के साधन सुलभ हों। इस प्रकार वह राज्य जन-संख्या की वृद्धि से भूमि-विस्तार पर श्रा जाता है, जिसका परिणाम भिन्न-भिन्न राज्यों की पारस्परिक प्रतिहन्दिता श्रीर युद्ध होता है।

भूमि

राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व—भूमि—का मनुष्य पर विलक्षण प्रमाव पड़ता है। जो व्यक्ति एक ही भूमि पर कुछ समय रह चुकते हैं, अथवा स्थायी रूप से रहने लगते हैं, उनके रहन-सहन, भाषा, खान-पान और व्यवहार में बहुत समानता हो जाती है। उनका उस भूमि से बड़ा प्रेम हो जाता है। मानु-भूमि (अथवा पिनृ-भूमि) शब्द में यही भाव है। एक भूमि में रहनेवाले एक-दूसरे को बन्धु-भाव से देखते हैं। उनका संगठन, दूसरी भूमि के निवासियों से भिन्न

^{*}रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ या समुद्रवाली भूमि का चेत्रफल अधिक होने पर भी, इन भागों की जन-संख्या अपेचाकृत बहुत कम होती है।

तथा पृथक् हो जाता है। इससे राज्य-निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। भूमि के सम्बन्ध में कुछ बातें ऊपर जनता के प्रसंग में कही जा चुकी हैं। यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि राज्य में कम-से-कम श्रीर श्राधिक से-श्राधिक कितनी भूमि होनी चाहिए। प्राचीन लेखकों का मत था कि किसी राज्य में भूमि इतनी होनी चाहिए कि उससे वहाँ के रहनेवालों को अपने भरण-पोषण की सामग्री पर्याप्त परिमाण में मिल सके। पर आज-कल श्रौद्योगिक संगठन श्रादि के कारण इस विचार को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इस समय इंगलैंड श्रादि कितने ही राज्य ऐसे हैं, जिनका अपने यहां की खाद्य-सामग्री से साल में केवल चार छ: महीने ही काम चलता है। पर ये राज्य अपने कल-कारख़ानों से विविध प्रकार का इतना सामान उत्पन्न करते हैं कि उसके विनिमय में प्राप्त खाद्य वस्तुओं से ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सहज ही कर सकते हैं, ये प्रायः उस विषय की चिन्ता से मुक्त ही रहते हैं; हाँ युद्ध-काल में जब बाहर से खाद्य सामग्री आनी बन्द हो जाती है. तब इन्हें कुछ कठिनाई का श्रनुभव श्रवश्य होता है।

पुनः प्राचीन-काल में राज्य के लिए प्रायः ऐसी ही भूमि अच्छी समभी जाती थी, जिसके बीच में बड़ी-बड़ी निदयाँ, समुद्र, या पहाड़ आदि न हों, और जो बहुत अधिक विस्तृत भी न हो। कारण, इससे लोगों को एक भाग से दूसरे भाग में जाने-आने को असुविधा होती थी, और शासन-प्रबन्ध करना भी किठन होता था। अब यातायात के साधनों की उन्नित हो जाने से यह बात नहीं रही। पहाड़ों के बीच से, और निदयों के ऊपर से रेल और मोटर आदि मज़े से जाती-आती हैं।

समुद्र में जहाज़ चलते हैं। श्रीर, हवाई जहाज़ तो स्थल या जल की वाधा की परवाह ही नहीं करते। श्रतः भूमि सम्बन्धी उपयुक्त बात श्राज-दिन चरितार्थ नहीं होती।

तथापि राज्य से भूमि का सम्बन्ध महत्व-पूर्ण है। उसके लिए भूमि श्रानिवार्थ है। केवल जनता से ही—जब तक उसका निर्धारित भूमि पर स्थायी रूप से निवास नहीं होता, जब तक वह खाना-बदोश रहती है, श्राज यहाँ, कल वहाँ धूमती-फिरती है, तब तक—राज्य का निर्माण नहीं होता। उदाहरणवत् यहूदी एक प्राचीन जाति है, परन्तु उसके कहीं स्थायो रूप से न रहने के कारण उसका कोई राज्य नहीं बन सका है। श्रतः राज्य के लिए भूमि होनी ही चाहिए। भूमि कहने से नदी, समुद्र, श्रादि का भी भाव ग्रहण किया जाता है। परन्तु यद्यपि राज्य के लिए समुद्र का यथेष्ट महत्व है, तथा वागुयानों के उपयोग की वृद्धि होने से श्राकाश की भी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, कोई जन-समूह चिरकाल तक केवल जल-भाग (समुद्र) में श्रयवा श्राकाश में नहीं रह सकता; श्रतः प्रत्येक राज्य में उसके निवासियों के लिए यथेष्ट स्थल-भाग होना श्रावश्यक है।

साधारण विचार से, श्राधिक भूमि तथा श्राधिक जन संख्यावाले राज्य को बड़ा राज्य, श्रीर कम भूमि तथा जन-संख्यावाले राज्य को छोटा कहा जाता है। परन्तु श्रानेक बार यह श्रानुभव में श्राता है कि जिसे सर्व-साधारण बड़ा राज्य कहते हैं, वह दुर्वल सिद्ध होता है; श्रीर इसी प्रकार जिसे छोटा राज्य कहा जा सकता है, वह शक्तिशाली ठहरता है। हमारे ही ज़माने की बात है, रूस जैसे विशाल राज्य से जापान

जैसा छोटा राज्य भिड़ बैठा, और उसने विजय भी प्राप्त कर ली। अब चीन और जापान की ठन रही है। चाहे इस में अन्ततः जापान की विजय न हो, उसका अपने से कई गुने चेत्रफल और जन-संख्यावाले राज्य पर आक्रमण करने से, यह स्पष्ट है कि केवल भूमि और जन-संख्या के आधार पर राज्यों को बड़े या छोटे राज्य समम्पना भूल है।

राजनैतिक संगठन - जनता श्रीर भूमि राज्य के श्रावश्यक तत्व ज़रूर हैं, परन्तु इनसे ही राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। इनके श्रविरिक्त राजनैतिक संगठन की भी श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। जनता का संगठन भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति आदि कई आधारों पर हो सकता है। भाषा, घर्म आदि की एकता से संगठन में बहुत सहायता मिलती है। किन्त राज्य बनने के लिए जिस संगठन की सब से अधिक श्रावश्यकता है, वह है राजनैतिक संगठन । इस का श्राशय यह है कि वहाँ शान्ति श्रीर सुव्यवस्था रखने के लिए एक ऐसी संस्था हो, जिसकी श्राजाएँ. श्रथवा जिसके बनाये हुए नियम वहाँ सर्व-मान्य हों। यह संस्था लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती है, जो वहाँ नियम-विरुद्ध हों। नियम भंग करनेवालों को दंड देकर या उनमें शिक्षा आदि का प्रचार करके यह उनका सुधार करती है। यह संस्था सामुहिक हित के कुछ ऐसे कार्य भी करती है, जिनको श्रादमी श्रलग-श्रलग न कर सकें. या जिनके करने में बहुत आर्थिक तथा अन्य प्रकार की किउनाई हो। इस संस्था को सरकार ('गवमेंट') कहते हैं। जब तक ऐसी संस्था का संगठन न हो, तब तक किसी भू-भाग की जनता को राज्य नहीं कहा जा सकता। इस संस्था के चेत्र के अनुसार ही किसी राज्य का चेत्र माना

जाता है। यदि किसी भू-भाग की जनता में एक सरकीर की जगह दो सरकारें स्थापित हो जायँ, तो उसे एक राज्य कहने के बजाय दो राज्यों में विभक्त समक्ता जायगा।

स्मरण रहे कि यदि राज्य की जनता के आदिमयों में, परस्पर रक्त-सम्बन्ध है, अर्थात् वे एक ही जाति (आर्य जाति, मंगोल जाति आदि) के हैं, तथा उनकी भाषा, धर्म और इतिहास आदि एक ही हैं तो उनका ऐक्य स्वामाविक है, तथा विशेष रूप से स्थिर रहने वाला होता है, अन्यथा उनके ऐक्य का आधार कृत्रिम होगा। हाँ, यह हो सकता है कि कृत्रिम एकतावाली जनता भी कुछ समय एक राज्य में रहने से अधिकाधिक सम्पर्क में आजाय, और उसमें भाषा, तथा इतिहास आदि की एकता बढ़ती जाय। आधुनिक राज्यों में यह बात विशेष रूप से मानी जाती है। अस्तु, विशेष ध्यान देने की बात यह है कि राज्य की जनता में धर्म, भाषा, सम्यता आदि में चाहे जितना मेद-भाव हो, जहाँ तक राज्य के कार्यों का सम्बन्ध है, उन्हें मिल कर, संगठित रूप से कार्य किरना आवश्यक है। अन्यथा राज्य की शिक्त का हास होगा, राज्य निर्वेल होगा।

प्रभुत्व-शक्ति——अच्छा, यदि एक निर्धारित भूभाग में जनता स्थायी रूप से रहती है, श्रीर उस जनता का राजनैतिक संगठन भी है, तो क्या उसे राज्य समभता ठीक होगा। उदाहरणवत् भारतवर्ष की सोलह लाख वर्ग-मील वाली भूमि में लगभग पैंतीस करोड़ भारतीय जनता का स्थायी निवास है,* श्रीर यहाँ सरकार रूपी संस्था भी

^{*}बर्मा श्रव भारतवर्ष से पृथक् कर दिया गया है।

संगठित है, जिसकी आजा जनता मानती है, तो क्या भारतवर्ष को राज्य कहा जायगा ? नहीं; बात यह है कि भारतवर्ष आभी स्वाधीन नहीं है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन है, अतः इसे राज्य नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत, हंगलैंड, जापान आदि का लेत्रफल और जन-संख्या अपेचाकृत कहीं कम होते हुए भी वे राज्य कहे जाने के अधिकारी हैं। राज्य के लिए स्वाधीन होना आवश्यक है। इसी बात को हम यों भी कह सकते हैं कि प्रभुत्व-शक्ति राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। राज्य की आजा, उसकी समस्त जनता को मान्य होती है, परन्तु राज्य किसी आन्तरिक अथवा वाह्य शक्ति के अधीन नहीं होता, वह किसी की आजा मानने के लिए वाध्य नहीं रहता।

प्रभुत्व-शक्ति के सम्बन्ध में विशेष आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा।

राज्य श्रीर सरकार

यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण करदेना आवश्यक जान पड़ता है। बहुघा पाठक राज्य और सरकार का भेद नहीं समभते, वे एक की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग कर बैठते हैं। इम ऊपर बता आये हैं कि सरकार किसी राज्य के अन्तर्गत वह संस्था है जिसकी आजाएँ राज्य के सब व्यक्ति मानते हैं। राज्य में ऐसी संस्था उसका एक आवश्यक आंग होती है; परन्तु समरण रहे कि वह उसका एक आंगमात्र ही है। राज्य अपने इस आंग के द्वारा अपनी नीति का पालन

करता है, श्रथवा यों कह सकते हैं कि श्रपनी इच्छा की पूर्ति कराता है। राज्य में देश की समस्त जनता का समावेश होता है, सरकार में कुछ थोड़े-से ही व्यक्ति होते हैं। सरकार को जो श्रधिकार होते हैं, वे राज्य द्वारा दिये हुए होते हैं। सरकार का स्वरूप तथा संगठन समय-समय पर बदलता रहता है। परन्त इससे राज्य में कोई अन्तर नहीं त्राता; उसमें बहुत स्थायित्व होता है। उदाहरण्वत् इंगलैंड की पार्लिमेंट में कभी उदार दल की प्रधानता होती है, कभी अनुदार श्रौर कभी भजदूर दल की। बहुघा श्रल्य-संख्यक दल नया निर्वाचन होने के बाद बहु-संख्यक दल हो जाता है। जो दल पार्लिमैंट में बहु-संख्यक होता है उसी दल का नेता मंत्रि-मंडल (या सरकार) बनाता है। पर इस प्रकार सरकार के परिवर्तन होते रहने पर भी राज्य ज्यों का त्यों बना रहता है। यही नहीं; इस समय इंगलैंड में बादशाह है, श्रीर उसे परिमित श्रधिकार हैं, श्रर्थात् वहाँ वैध राजतंत्र है। यदि किसी समय वहाँ शासन-कार्य में बादशाह का भाग न रहे, वहाँ प्रजा-तंत्र की ही स्थापना हो जाय तो इससे भी इंगलैंड के, राज्य होने में कोई अन्तर न आयेगा।

इससे स्पष्ट है कि सरकार राज्य का एक अनिवार्थ श्रंग होते हुए भी स्वयं राज्य नहीं है; दोनों में निश्चित श्रौर महत्व-पूर्ण मेद है।

दसवाँ परिच्छेद राज्य की उत्पत्ति

कि पाज्य किसे वहते हैं तथा उसके मुख्य-मुख्य तत्व क्या-क्या हैं। अब हम राज्य की उत्यत्ति के सम्बन्ध में विचार करेंगे। यह तो स्पष्ट ही है कि समाज को मांति राज्य एक अति प्राचीन संस्था है। उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई बात निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन हैं। तथापि इस विषय में, भिन्न-भिन्न विचारकों के सिद्धान्त जान लेने से हमें समाज की उन अवस्थाओं का बोध होगा, जिनके कारण उक्त सिद्धान्त स्थर किये गये हैं। इससे हम बहुत-से राजनैतिक प्रश्नों पर विचार कर सकेंगे, तथा अनेक समस्याओं को इल करना अपेक्षाकृत सुगम होगा।

मुख्य-मुख्य सिद्धान्त--राज्य की उत्पत्ति के मुख्य-मुख्य

विचारणीय सिद्धान्त ये हैं:--

- (१) दैवी सिद्धान्त।
- (२) श्रार्थिक सिद्धान्त।
- (३) शकि-विद्वान्त।
- (४) सामाजिक इक्ररार-सिद्धान्त।
- (५) विकास-सिद्धान्त ।

इन सिद्धान्तों पर क्रमशः विचार किया जायगा। यहाँ यह उल्लेख कर देना श्रावश्यक है कि जिन देशों में जनता श्रात प्राचीन काल में उन्नत श्रोर सम्य तथा संगठित हुई, उन देशों में ही राज्य की उत्पत्ति पहले हुई। इस प्रकार राज-सत्ता का प्रारम्म पहले मारत-वर्ष, चीन श्रोर मिश्र में ही होने का पता चलता है। भारतीय साहित्य श्राति प्राचीन-काल का वृत्तान्त उपस्थित करता है। यहाँ वेदों, पुराणों, स्मृतियों श्रोर महाभारत श्रादि में राज्य-सम्बन्धी श्रनेक प्रकार की विचार-धाराएँ मिलती हैं। योरप में जो भी राजनैतिक विचार प्रचलित हैं, उनका मूल श्राधकतर यूनान श्रोर रोम का है, श्रोर यद्यपि योरप-वालों की हिंद्र से वे श्रत्यन्त प्राचीन माने जाते हैं, भारतीय पाठकों के लिए वे ऐसे पुराने नहीं है, वरन् बहुत समय पीछे के हैं। श्रस्त, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धान्तों के विवेचन में हम प्रसंगानुसार यह भी बतलायेंगे कि भारतीय साहित्य इस सम्बन्ध में क्या प्रतिपादन करता है।

देवी सिद्धान्त--राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धान्त यह है कि राज्य-संस्था मनुष्य-द्वारा बनायी हुई नहीं है, वह ईश्वर-प्रणीत है।

प्राचीन काल में भारतवर्ष तथा अन्य देशों की जनता में भी दैवी शक्तियों पर बहुत विश्वास करने की प्रवृत्ति थी। वहाँ राजा को ईश्वर का अवतार तक माना जाता था, उसे देवता का अंश कहा जाता था, उसमें दैवी विभूति की कल्पना की जाती थी। महाभारत में कहा गया है कि राजा को साधारण आदमी समफकर कोई उसका अपमान न करे, क्योंकि राजा इस भूमंडल पर मनुष्य के रूप में देवता है। यह विचार लोगों में आधुनिक काल तक चला आया है, जैसा कि 'दिल्लीश्वरो वा जगदोश्वरो वा' उक्ति से सिद्ध है।

प्राचीन श्रीर मध्यकालीन योरप में भी लोगों में यह भावना बहुत प्रबल रही कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। जिन-जिन देशों में जिस समय यह विचार-धारा प्रधान रही, वहाँ एक-तंत्र राज्य-पद्धति बहुत प्रचलित रही है। हाँ, प्राचीन काल में यहाँ इस बात की यथेध्य व्यवस्था रही कि राजा निरंकुश या स्वेच्छाचारी न हो जायँ। राजा स्वयं कात्न नहीं बना सकते थे, वे ऋषि-मुनियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही शासन कर सकते थे, वे धर्म-शास्त्रों श्रीर परम्परा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार राजा प्रजा की हित-कामना करने के लिए सतर्क रहते थे, श्रीर जब कभी उन्हों ने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, तो उन्हें प्रजा की सहानुभूति श्रीर सहयोग से वंचित ही नहीं होना पड़ा, प्रजा द्वारा दंखित भी होना पड़ा। इस विषय में श्रनेक उदाहरण रामायण महाभारत में मिलते हैं। पीछे यहाँ राजतंत्र क्रमश: दूषित हो गया, श्रादमी राजाश्रों के

स्वेच्छाचार को सहन करने लगे, श्रौर कुछ श्रंशों में उसे उचित भी उहराने लगे।

राज्य के देवी िखदानत ने योरप के देशों में कहीं-कहीं बड़ा अनर्थ किया। अनेक बादशाहों और सम्राटों ने यह दावा किया कि हम ईश्वरीय सत्ता से शासन करते हैं, हमें अपने अधिकार जनता द्वारा प्राप्त नहीं हैं। किसी को हमारी नीति या कार्यों की आलोचना करने, या हमारे विपक्ष में कुछ कहने-सुनने का अधिकार नहीं है। हमारे विरुद्ध आचरण करने वाला उसी प्रकार अपराधी और दंडनीय है, जैसे ईश्वर का विरोध करनेवाला। शासकों ने अपने इस दावे की पुष्टि ईसाई धर्म के अन्यों से की। अच्छे-अच्छे विद्वान लेखकों ने बहुत प्रभावशाली भाषा में इस सिद्धान्त का समर्थन किया।

फलतः इस सिद्धान्त ने लोगों के मन में ख़ूब जगह कर ली। पर संसार ठहरा परिवर्तनशील! यहाँ कोई बात अमर नहीं। कालांतर में लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा, धर्म और धर्माधिकारियों पर उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास कम होने लगा। उन्होंने सोचा कि राज्य-सम्बन्धी यह सिद्धान्त अम-जाल है, धोखे की टट्टो है। इसका प्रतिपादन या प्रचार, जनता पर मनमाना शासन, दमन और अत्याचार तथा शोषण करने के लिए ही, किया जा रहा है। धर्म और विश्वास की जगह अब विज्ञान और तर्क ले रहा है। अब यह सिद्धान्त प्रायः मूला दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी देवता या ईश्वर ने की है। अब राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जाता। योरप में बहुत समय तक पोप (प्रधान धर्माधिकारी) की बड़ी सत्ता रही है, उसकी

घाक बादशाहों श्रीर सम्राटों तक पर रही है। श्रव यह बात भी हवा है। गयी है। निदान, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धान्त श्रव प्रायः केवल ऐतिहासिक बात रह गयी है।

श्राधिक सिद्धान्त — कुछ राजनीतिशों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण मनुष्यों की श्रार्थिक परिस्थिति है। मनुष्यों की प्रारम्भिक श्रावश्यकताएँ भी कई-एक हैं, श्रीर कोई मनुष्य श्रपनी सब श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति केवल श्रपने बल-भरोसे नहीं कर सकता, उसे दूसरों के शारीरिक या मानसिक सहयोग की श्रावश्यकता रहती है। इसलिए उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करना होता है। समाज में सब व्यक्ति श्रपना-श्रपना कार्य निर्विध करते रहें, कोई दूसरे के कार्यों में श्रनावश्यक हस्तचेप न करे, इसके लिए नियम श्रीर व्यवस्था को श्रावश्यकता होने लगी। इस हेतु सरकार का संगठन किया गया, श्रीर, राज्य का निर्माण हो गया। इससे विदित है कि नागरिकों की श्रार्थिक कठिनाइयों ने ही श्रन्ततः राज्य-निर्माण के लिए प्रेरणा की है।

निस्सन्देह राज्य नागरिकों को एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखने, किसी की सम्पत्ति आदि न हरने के लिए आदेश देता है, तथा वह ऐसे भी कार्य-सम्पादन करता है, जिन्हें नागरिक आलग-अलग करने में असमर्थ रहते हैं, अथवा जिनके लिए बड़ी पूँजी की ज़रूरत होती है। तथापि इसी बात के आधार पर राज्योत्पत्ति के मूल कारण का निश्चय करना भूल है। राज्य के निर्माण में और भी बातों का विचार किया जाना चाहिए, इन पर आगे प्रकाश डाला जाता है।

शक्ति-सिद्धान्त-राज्योत्पत्ति के शक्ति-सिद्धान्त के मानने-वालों का कथन है कि राज्य का मूलाधार शारीरिक शक्ति है। बलवान व्यक्ति निर्वल को दवाता है, इसी प्रकार शक्तिशाली समृह दुर्वल समूह पर त्राक्रमण करता तथा उसे अपने श्रधीन करता है। सुसंगठित समुदाय श्रसंगठित समुदाय पर श्रपना श्रातंक जमाता है। इस प्रकार शासन के मूल में शक्ति, विजय, प्रभुता ऋदि भाव है। जो ज़बरदस्त होता है, द्सरों पर उसकी हकूमत चलती है। प्रभाव-शाली श्रीर बलवान व्यक्ति कबीले का नायक या नेता बन जाता है। कबीला शक्तिवान होकर राज्य का स्वरूप ग्रहण करता है। राज्य ज्यों-ज्यों अधिक शक्तिवान होता है, वह अपना आकार बढ़ाता जाता है, यहां तक कि वह क्रमशः साम्राज्य बन बैठता है। यह सब शक्ति का खेल है। आज दिन भी व्यक्ति हो या संस्था, सर्वत्र शक्तिशाली की ही तूर्ती बोलती है। बड़े-बड़े राज्य श्रीर साम्राज्य शक्ति के ही सहारे बड़े बने हुए हैं, संसार में अपनी घाक जमा रहे हैं। यद्यपि राज्य नागरिकों को यह त्रादेश करता है कि उन्हें नियम-पालन करना चाहिए, दूसरे नागरिकों से सहयोग श्रीर सहानुभृति का व्यवहार करना चाहिए, जिसकी लाढी उसकी भैंस की नीति का परित्याग करके, क़ानून का श्रादर करना चाहिए। तथापि राज्य बहुघा स्वयं इस श्रादेश को भूलकर श्रपने श्राप को श्रधिकाधिक शक्तिशाली बना कर दुसरों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इस प्रकार शकि-सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के श्राधार पर, या इस के द्वारा हुई है।

इस सिद्धान्त में एक अंश तक सचाई अवश्य है। राज्य के लिए जो गुण अनिवार्य हैं उन में एक शक्ति भी है। परन्तु एक-मात्र शक्ति से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। केवल शक्ति पर निर्मर रहनेवाला राज्य चिणक होता है, शक्ति के विलुप्त होते ही वह नष्ट भी हो जायगा। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति शक्तिवान है, और कुछ आदमी उस के अनुयायी बन जाते है, अब अगर उसे उन अनुयायियों का समर्थन तथा सहयोग ग्राप्त नहीं रहता तो उसका नेतृत्व, प्रभुता या शासन कैसे रह सकता है!

प्रकृति में यह नियम अवश्य देखने में आता है कि छोटा बड़े की अधीनता तथा संरक्षण में रहता है। बच्चा माता-पिता के अधीन रहता है, परन्तु इसमें दमन की ही भावना नहीं है, वरन् दया की भी है। माना कि केवल पशु-बल या शरीर-बल से दूसरे का दमन अथवा हनन किया जा सकता है, परन्तु वह राज्य करना नहीं है।

सामाजिक इकरार-सिद्धान्त—महाभारत के शान्ति-पर्व में इस सिद्धान्त का बहुत सुन्दर और विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है। उसमें बतलाया गया है कि पहले 'मस्स्य-न्याय' प्रचलित था, अर्थात् जैसे बड़ी मछली छोटो मछली को खा जाती है, इसी प्रकार बलवान दुर्वल को सताता था। तब सब लोगों ने मिलकर नियम किया कि जो कोई किसी से कटु भाषण करेगा, उसे मारेगा या किसी की स्त्री अथवा द्रव्य का हरण करेगा, उसको हम त्याग देंगे। यह नियम, सब के लिए एक-सा है। परन्तु जब इसका परिपालन नहीं हुआ, तब सारी प्रजा ब्रह्मा के पास गयी और

कहने लगी कि हमें हमारा प्रतिपालन करनेवाला श्रिधपित दो। तब ब्रह्मा ने मनु को श्राज्ञा दी। उस समय मनु ने कहा, 'मैं पाप-कर्म से डरता हूँ; श्रसन्मार्ग पर चलनेवाले मनुष्यों पर राज्य करने से मैं पाप का भागी हूँगा।' तब लोगों ने कहा 'राष्ट्र में जो पाप होगा, वह कर्ता को लगेगा। तू मत डर, तुमें हम पशुश्रों का पचासवाँ हिस्सा श्रीर श्रमाज का दशमांश देंगे। शस्त्र-श्रस्त्र श्रीर वाहन लेकर हमारे मुख्या लोग तेरे साथ रहेंगे। तू सुख श्रीर श्रानन्द से राज्य कर।' इसकों स्वी-कारकर मनु राज्य करने लगे। श्रधमीं श्रीर शत्रु को दंड देकर, उन्होंने धर्म के समान राज्य किया।

इस बृत्तान्त में राज्योत्पत्ति के इक्तरार-सिद्धान्त की कल्पना की गयी है; राजा धर्म के अनुसार राज्य करे और अपराधियों का दमन करे; प्रजा उसे निर्धारित कर और सहायता प्रदान करे। हिन्दू शास्त्रों का यह सिद्धान्त कई सुप्रसिद्ध पाश्चात्य लेखकों द्वारा भी मान्य किया गया है। अनेक अन्थ लिखे गये। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के अवसर पर रूसो के 'सोशल कन्ट्राक्ट' नामक अन्य का जनता पर विलक्षण प्रभाव था। 'सोशल कन्ट्राक्ट' नामक अन्य का जनता पर विलक्षण प्रभाव था। 'सोशल कन्ट्राक्ट' का अर्थ है 'सामाजिक इकरार'। इस अन्थ में यह प्रतिपादन किया गया है कि आदमी अपनी सामृहिक सुविधा के लिए अपने अधिकार समाज को देते हैं। फिर समाज अपने अधिकार राजा तथा अन्य अधिकार समाज को देता है। इस प्रकार राजा का अधिकार प्रजा की सम्मति पर निर्भर है, प्रजा के मत के विरुद्ध राजा कुछ नहीं कर सकता; वास्तविक सत्ता जनता की है, राजा की नहीं। कितने ही देशों की राज्य-क्रान्तियों में इन्हीं विचारों का प्रावल्य था। राजा

श्रीर र्प्रजा दोनों प्रतिज्ञा-वद्ध हैं, इन दोनों पक्षों में से राजा प्रजा की रक्षा श्रीर उन्नति करे, तथा प्रजा राज्य के नियमों का पालन करे एवं श्रावश्यक कर श्रादि दे। श्रव यदि राजा श्रपना कर्तव्य ठीक तरह पालन नहीं करता तो प्रजा भी श्रपनी प्रतिज्ञा से वँधी नहीं रहती; उसे श्रिषकार है कि राज-नियम भंग करे, राजा को पद-च्युत करे, श्रीर उसे दिये हुए श्रिषकार श्रीर सत्ता उससे वापिस ले ले।

इस सिद्धान्त का प्रचार होने से राज्य के दैवी सिद्धान्त को गहरा धका पहुँचा। श्रादमी सोचने श्रीर तर्क-वितर्क करने लगे। क्रमशः उनका यह विश्वास उठ गया कि राजा ईश्वर की विभूति है. श्रीर इसलिए वह जो कुछ करे सो न्याय है। श्रव शासकों के कार्यों का जनता खुले-श्राम विचार करने लगी। उनमें यह भावना उत्तरोत्तर बढती गयी कि राजा भी एक मनुष्य ही है। वह शासक तभी तक रह सकता है, जब तक उसका कार्य-व्यवहार द्वारा श्रनुमोदित हो; यदि वह श्रत्यन्त स्वार्थी श्रौर स्वेच्छान्वारी है तो उसे राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन विचारों के प्रचार का परिणाम यह हुआ कि जनता को अब स्वेच्छाचारी और श्रनियंत्रित शासन श्रसहा हो उठा; वह उनके विरुद्ध खड़ी हो गयी. उसने उनका ख़ब सामना किया। किसी देश में निरंकुश राजा को राज्य छोड़कर भागना पड़ा; कहीं उसे फौंसी या सूली पर चढना पड़ा; श्रौर कहीं-कहीं तो राज-परिवार तक की बुरी तरह खबर ली गयी। पर लोगों के चिरकाल के संस्कारों का सर्वथा विख्रप्त होना सहज नहीं है। इस समय भी कुछ आदमी पुराने विचारवाले मिलते हैं, तथापि

श्रव कोई विवेकशील व्यक्ति यह स्वीकार या प्रतिपादन नहीं करैता कि राज्य कोई दैवी संस्था है, श्रीर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, या देवता का श्रंश है। इस प्रकार जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य का दैवी सिद्धान्त उन्नत समाज में प्रायः इतिहास की वस्तु रह गया है।

राज्योत्पत्ति का सामाजिक इकरार-सिद्धान्त सतरहवीं और विशेषतया त्राठारहवीं शताब्दी में खूब ही प्रचलित रहा। पीछे क्रमशः इसकी आलोचना होने लगी। इस का खंडन किया जाने लगा। इस सिद्धान्त के विपन्न में बात यह है कि इतिहास में इस का आधार नहीं मिलता। किसी सुनिश्चित समय पर ऐसा नहीं हुआ कि एक राजा और प्रजाने इस प्रकार का इकरार किया हो, और इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई हो। ऐसी प्रतिज्ञा सम्य और उन्नत तथा संगठित जनता ही कर सकती है, और जनता की ऐसी अवस्था होने के लिए राज्य का होना आवश्यक है। इकरार सिद्धान्त के समर्थकों के पास उपर्युक्त तर्क का कोई उत्तर नहीं है, अतः यह सिद्धान्त कल्पना-मात्र ही रह जाता है।

विकास-सिद्धान्त — राज्य की उत्पत्ति के जो विद्धान्त ऊपर बताये गये हैं, वे भ्रमात्मक हैं, उनमें कुछ सञ्चाई हो सकती है, परन्तु वे व्यापक रूप में ग्रहण नहीं किये जा सकते। बात यह है कि राज्य कोई ऐसी संस्था नहीं है, जिसके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सके कि अमुक समय इसका आविष्कार या प्रारम्भ हुआ। वरन् यह तो एक ऐसी संस्था है जिसका क्रमशः विकास हुआ है, जो सुदूर भूत-काल से अब तक धीरे-धीरे उन्नत होती आ रही है। मनुष्य समाज की किसी समय ऐसी अवस्था रही होगी, जब उसे राज्य की कल्पना भी न हो। पीछे कल्पना भी हुई तो कुछ विशेष विचारवान लोगों के मन में ही हुई। उन्होंने अपने विचार का जनता में प्रचार किया। कुछ समय कल्पना-जगत में ही रह कर, राज्य ने स्थूल रूप घारण किया; इसका प्रारम्भिक स्वरूप कैसा अ-विकसित रहा होगा! पीछे देश-काल मेद से इसमें आवश्यक परिवर्तन होता रहा। और अब तो विविध भू-भागों में इसके भिन्न-भिन्न जटिल स्वरूप विद्यमान हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि मानवसमाज किसी ख़ास समय, अमुक मानसिक तथा शारीरिक उन्नति करके, यह विचार करने लगा कि अब राज्य का निर्माण किया जाय। राज्य रूपी संस्था का तो धीरे-धीरे विकास हुआ है।

क्रमिक विकास का यह सिद्धान्त सामान्यतया ठीक जँचता है, श्रीर श्रासानी से समक्त में श्रा जाता है। तथापि सामाजिक उन्नति की भिन्न-भिन्न मंज़िलों को निश्चित करने में बड़ी कि ठिनाई उपस्थित होती है। एक साधारण कल्पना यह है कि राज्य के प्रारम्भिक स्वरूप का परिचय परिवार में मिलता है, बच्चे पिता के श्रधीन, उसके नियंत्रण में रहते हैं। यही भावना श्रागे बढ़ती है। परिवार बढ़ जाने पर, कई परिवारों के इकट्ठे रहने की दशा में, जो व्यक्ति बड़ा-बूढ़ा होता है, उसकी श्राज्ञा उस चेत्र के सब स्त्री-पुरुष मानते हैं। बहुत से श्रादमियों की जाति या समूह पर एक चौधरी या मुखिया का श्रनु-शासन रहता है। इसमें उपर्युक्त पारिवारिक पद्धति से ही कार्य होता है। पीछे समाज का विकास होने पर जब शान्ति श्रीर सुव्यवस्था की श्रावश्यकता होती है, तो इसी पद्धति से उसके शासन-प्रबन्ध का

विचार किया जाता है। एक योग्य, वयोवृद्ध श्रीर समर्थ व्यक्ति को सरदार या नेता मानकर सब उसकी श्राज्ञा या सलाह से काम करने लगते हैं। इस प्रकार राज्य-संस्था का प्रादुर्भाव होता है। इसमें स्मरण रखने की बात यह है कि जिस प्रकार कुटुम्ब में पुरुष की प्रधानता होती थी, उसी प्रकार राज्य-प्रबन्ध में भी पुरुष ही प्रधान रहा। इसे पैत्रिक सिद्धान्त कहते हैं। चिरकाल तक विद्वानों को यही मत मान्य रहा।

परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के इतिहास-सम्बन्धी श्राविष्कारों ने यह स्चित कर दिया कि राज्य की उत्पत्ति का यही एक-मात्र, पूर्णतया व्यापक सिद्धान्त नहीं है। परिवार सर्वत्र पुरुष-प्रधान ही नहीं रहे; श्रनेक स्थानों में, समय-समय पर स्त्री-प्रधान भी रहे। श्रव भी, जैसा कि पाँचवें परिच्छेद में कहा गया है, कहीं-कहीं ऐसे परिवार मिलते हैं, जिनमें स्त्री हो मुखिया रहती है, श्रीर बालक माता (या नानी श्रादि) के वंश के माने जाते हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति के विकास-सिद्धान्त में, पैत्रिक स्वरूप हो सर्वत्र प्रचलित रहा; वरन् श्रनेक स्थानों में मातृ-स्वरूप भी रहा है। इस मत के समर्थकों का कथन है कि श्रारम्भ में जब मनुष्य शिकार करके निर्वाह करता था श्रीर जहाँ-तहाँ जंगलों में धूमकर रहता था, स्त्री-पुरुषों में श्राज-कल की तरह विवाह-शादी करके स्थायी रूप से साथ-साथ रहने की रीति नहीं थी। किसी स्त्री का किसी पुरुष-विशेष से सम्बन्ध न होकर कई पुरुषों से सम्बन्ध हो सकता था। उस दशा में बच्चों पर माता का ही श्रीष्कार था; श्रीर उनको माता के ही वंश का माना जाना स्वाभाविक

था। इस पद्धति से जिस राज्य-प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, वह स्वभावतः मातृ-सिद्धान्त की हुई, न कि पितृ-सिद्धान्त की। हाँ, पीछे जब मनुष्य कृषि-कार्य करने लगा, और स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगा, किसी स्त्री से एक पुरुष-विशेष का ही सम्बन्ध होने लगा, तो परिवार पितृ प्रधान होने लगे, और फलतः राज्य-पद्धति का स्वरूप भी पैत्रिक सिद्धान्त के अनुसार होने लगा।

श्रास्त, यद्यपि श्राज कल पैत्रिक सिद्धान्त का ही श्राधिक समर्थन किया जाता है, और अधिकांश स्थानों में इसके अनुसार राज्य-पद्धति का स्वरूप पाया जाता है; दुसरा पक्ष (मातृ-सिद्धान्त) भी उपेक्षणीय नहीं है. इसके समर्थकों के कथन में भी बहुत-कुछ सार है। हाँ, यह निश्चय करना कि किस स्थान पर पहले कब कौनसा सिद्धान्त व्यवहार में श्राया, कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं एक सिद्धान्त व्यवहार में आया होगा, कहीं द्सरा । यह भी आवश्यक नहीं कि जहाँ एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई, वहाँ निरंतर वही क्रम बना रहा। समय और परिस्थिति के अनुसार एक प्रकार के क्रम का दूसरे रूप में बदल जाना श्रसम्भव नहीं। सारांश यह कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस विषय के अन्यान्य सिद्धान्तों में विकास सिद्धान्त ही श्रव श्रधिक तर्क-संगत श्रीर मान्य है । हाँ, इसके श्रनुसार, कहीं राज्य-पद्धति का स्वरूप मातृ-प्रधान रहा, श्रीर कहीं पितृ-प्रधान; तथा इन रूपों में से एक का समय पर दूसरे में परिवर्तित हो जाना भी सर्वथा सम्भव है।

श्राधुनिक राज्यों के विकास की कोई ख़ास पद्धति या कारण निश्चित्

करना, लेखक के लिए बड़ी जोखम उठाना है; क्योंकि उछके विपक्ष या खंडन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ लेखकों ने राज्य के बिकास का प्रधान कारण सैनिक बल माना है। इसमें सन्देह नहीं कि समय-समय पर ऐसा हुआ होगा कि एक गांव या नगर के आदिमियों की आवश्यकताएँ बढ़ने पर उसके प्रमुख व्यक्तियों ने दूसरे गांव या नगर से सम्बन्ध जोड़ने की बात सोची। यह कार्य सदैव मित्रता-पूर्ण ढंग से न होकर कभी-कभी संघर्ष-मय भी रहा होगा। अथवा, शक्तिवान लोगों के मन में लोभ समाया, तो उन्होंने पास की दूसरी बस्तियों पर बल-पूर्वक अधिकार जमाने का प्रयत्न किया होगा। इस प्रकार जबिक इस समय भी राज्यों के जीवन में युद्ध का ख़ासा भाग है, प्रारम्भ में ऐसा होना सर्वथा सम्भव और स्वाभाविक है। परन्त इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति ही युद्ध से हुई। हाँ, युद्ध से राज्य की वृद्धि हो सकती है, और, हो सकता हैं विनाश भी।

इसी प्रकार समाजवादियों के इस कथन पर विचार किया जा सकता है कि श्रन्य सामाजिक संस्थाओं की भाँति राज्य के विकास का श्राधार श्रार्थिक है। राज्य के संगठन में श्रार्थिक परिस्थियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। श्राज-कल भी हम देखते हैं, कि प्रजातंत्र कहे 'जाने वाले राज्यों का सूत्र-संचालन बहुत-कुळु पूंजीपितयों द्वारा होता है। जहाँ समाज में धन-वितरण की श्रसमानता होती है, वहाँ प्रजातंत्र नाम-मात्र का ही होता है। वहाँ वास्तव में धनिक-तंत्र बन जाता है। परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि राज्य की उत्पत्ति का एक-मात्र कारण श्रार्थिक परिस्थितियाँ ही हैं। निदान, राज्य की उत्पत्ति या विकास में समय-समय पर विविध बातों का प्रभाव पड़ा है, परन्तु किसी एक बात को ही उसका मूल कारण नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न समय में राज्य का कमशः विकास हुआ है। कोई राज्य एक दिन में नहीं बन गया। उसके निर्माण का रहस्य बड़ा पेचीदा रहा है। इसी प्रकार किसी राज्य के भविष्य के विषय में भी यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसका विकास किस प्रकार होगा अथवा उसका क्या रूप होगा। हाँ, आधुनिक राज्य प्राचीन राज्य से कई बातों में स्पष्टतया भिन्न हैं; दोनों में सुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं:—

- (क) अब राज्य बहुत बड़े-बड़े होने की प्रवृत्ति है। कई आधुनिक साम्राज्य प्राचीन साम्राज्यों से कहीं अधिक विस्तृत हैं, छोटे-छोटे राज्यों की मूमि तथा चेत्रफल भी पहिले से अधिक है। अब नगर-राज्यों का तो युग गया ही समभो।
- (ख) प्राचीन राज्यों की कार्य-पद्धति में स्थिरता कम थी, उदाहरखबत् किस अपराध का क्या दंड होगा, इसका कोई नियम न था। अब राज्य की प्रत्येक बात सुनिश्चित है, उसके लिए नियम या कानून बने हुए हैं, तथा बनते जाते हैं।
- (ग) श्रव जनसाधारण में राजनैतिक जायित श्रधिक है, 'कोउ नृप होउ हमें का हानी' की बात नहीं; राज्य के कार्यों में जनता श्रधिक भाग लेती है, श्रीर उनकी चर्चा बहुत होती है। राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र बढ़ रहा है, श्रवैध राजतंत्र तो लुप्त-प्राय ही है।

(घ) पहले राज्य के कार्य में घर्म तथा धर्माधिकारियों का बड़ा भाग होता था; श्रव धर्म श्रीर राजनीति को यथा-सम्भव पृथक रखा जाता है, राज्य के विषयों को धार्मिक दृष्टि-कोण से नहीं देखा जाता। राज्य सब धर्मों से समानता का व्यवहार करता है। फल-स्वरूप किसी विशेष धर्म के श्रनुयायियों का पक्षपात नहीं होता श्रीर न किसी धर्म के श्रनुयायियों पर पहले की तरह श्रत्याचार ही होते हैं।

इस प्रकार, इस परिच्छेद में हमें मालूम हुआ कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में विकास-सिद्धान्त ही अधिक सत्यता-पूर्ण है। यह भी ज्ञात हो गया कि आधुनिकराज्य प्राचीनराज्य की अपेक्षा विशेषतया किन-किन वातों में भिन्न हैं।



ग्यारहवाँ परिच्छेद राज्य की प्रभुत्व-शक्ति

मुहित बताया जा चुका है कि राज्य के तत्वों में से एक, प्रभुत्व-शक्ति है। इस परिच्छेद में इसी के सम्बन्ध में विशेष विचार करना है। प्रत्येक राज्य में कोई संस्था—चाहे वह एक व्यक्ति हो, या

प्रत्येक राज्य मं कोई संस्था—चाई वह एक व्यक्ति हो, या व्यक्ति-समूह—ऐसी होती है, जिसके द्वारा राज्य अपनी प्रमुख सत्ता का उपयोग करता है। यह संस्था किसी के अधीन नहीं होती, इसकी आज्ञा राज्यभर में सबको शिरोधार्य होती है। इस संस्था की शिक्ति को प्रमुख-शक्ति कहते हैं, और इसकी आजाओं या आदेशों को कानून।

राज्य की प्रमुत्व-शाक्ति अपिरिमित तथा अवाध होती है। यदि कोई दूसरी संस्था इसमें बाधक हो सकती है, तो फिर वहीं संस्था प्रमुत्व-शक्तिवाली समभी जायगी; राज्य की प्रमुत्व-शक्ति नहीं रहेगी, और पिरिगाम-स्वरूप राज्य भी वास्तव में राज्य न रहेगा। राज्य और प्रमुत्व का एक दूसरे से अनिवार्य और अटूट सम्बन्ध है। राज्य के बिना प्रमुत्व नहीं, और प्रमुत्व बिना राज्य नहीं।

पशुत्व-शक्ति के लक्षण—अन्यान्य लेखकों में यूनान के प्रसिद्ध नीतिज्ञ अरस्तू ने प्रभुत्व-शक्ति की परिभाषा बहुत सरल और स्पष्ट तथा व्यवहारिक रूप में की है। उसका कथन है कि 'प्रभुत्व-शक्ति वह है जो (दूसरे राज्यों से) युद्ध और शान्ति, मित्रता स्थापित करना और संधि मंग करना, आदि विषयों का निर्णय करती है, जो क़ानून, प्राण-दंड, अर्थ-दंड, देश-बहिष्कार, आय-व्यय की जांच, और शासकों की परीचा का निश्चय (उनके सेवा-काल की अवधि पूरी होने पर) करती है।" इस परिभाषा के अनुसार, प्रभत्व-शक्ति के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं:—

- (१) युद्ध श्रौर शान्ति का निश्चय करना।
- (२) टकसाल चलाना।
- (३) कानून बनाना।
- (४) प्रजा से कर लेना श्रौर उसका व्यय करना।
- (१) अपराधियों पर जुर्माना करना।
- (६) अपनी शासन-पद्धति को निश्चित करना।

इन लक्ष्यों के श्राधार पर, पाठकों को यह विचार करने में सुविधा होगी कि कोई राज्य वास्तव में कहाँ तक राज्य कहे जाने का श्राधकारी है।

प्रभुत्व-शक्ति अवाध होती हैं — पहले कहा गया है कि राज्य की प्रभुत्व-शक्ति नागरिकों तथा उनके समस्त समूहों पर सर्वोपरि और निर्वाध होती है। राज्य-शासकों से भी ऊपर है। शासक वही कार्य तो कर सकते हैं, जिनके लिए राज्य अनुमृति दे, इस प्रकार राज्य

का प्रमुख श्रपने च्रेत्र में सर्व-प्रधान होता है। किन्तु यह तो राज्य के भीतर की बात हुई। बाहरी शिक्यों के हस्तच्रें से भी राज्य मुक्त रहता है।* यदि ऐसा न हो तो फिर उसकी स्वतंत्रता ही क्या हुई। राज्य की प्रमुख-शिक्त श्रविभाज्य होती है, राज्य में उसका पूर्णाधिकार होता है। जिस प्रकार एक मियान में एक ही तलवार रहती है, उसी प्रकार एक राज्य में एक ही प्रमुख-शिक्त रह सकती है, उसमें दूसरे का दख़ल नहीं हो सकता। दूसरी प्रमुख-शिक्त के हस्तच्ये हो सकने का श्रयं यह होगा कि उस राज्य की प्रमुख-शिक्त श्रपूर्ण या विभाजित है और यह श्रद्धाभाविक है।

राज्य की प्रभुत्व-शक्ति के पूर्णाधिकारी होने के सम्बन्ध में लेखकों में बड़ा मतभेद रहा है। प्रोफ़ेसर वर्गस के इस कथन का ख़ूब विरोध हुन्ना है कि मैं व्यक्ति या व्यक्ति-समूहों पर राज्य की प्रभुत्व-शक्ति को न्नपरिमित, पूर्ण न्नौर व्यापक मानता हूं। परन्तु मली-मौति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें विरोध करने योग्य कोई बात नहीं है। राज्य मनुष्यों का संगठित समाज है, उसकी उत्यक्ति ही तब होती है, जब उसके चेन्न के व्यक्ति राज्य का नियंत्रण मानते हो न्नौर उसकी श्राज्ञात्रों श्रर्थात् क़ानूनों का पालन करते हो। राज्य का श्रह्तित्व तभी तक है, जबतक कि व्यक्ति उसके

^{*}प्रायः राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, समम्भीतों, संधियों और कृत्नूनों के अनुसार कार्य करता है। पर इससे उसकी प्रमुख-शक्ति में अन्तर नहीं आता। कारण कि वह अन्तर्जातीय नियमों आदि का विचार स्वेच्छा से, अपने तथा अन्य राज्यों के हित की दृष्टि से, करता है।

अनुवर्तों हैं। इस प्रसंग में सुप्रसिद्ध अंगरेज नीतिज जान-आस्टिन का का कथन है कि यदि कोई निश्चित और समर्थ व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह) ऐसा हो, जो किसी के भी अधीन न होते हुए अपनी आजा समाज के अधिकांश भाग पर चलाता हो तो वह व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह) उस समाज में प्रभु है, और वह समाज राजनैतिक और स्वतंत्र समाज है।

प्रभुत्व-शक्ति के सिद्धान्त की आलोचना— प्रभुत्व-शक्ति के सिद्धान्त पर अनेक आलोचनाएँ हुई हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि राज्य को लोगों के वैयक्तिक धर्म तथा जीवन में हस्तचेष करने का अधिकार नहीं। परन्तु वैयक्तिक धर्म और जीवन का चेत्र क्या हो, जिसमें राज्य हस्तचेष न कर सके, इसका निर्णय भी तो जनता की बहु-सम्मति से होता है। इस प्रकार प्रभुत्व-शक्ति का प्रतिबन्ध-रिहत होना एवं पूर्वोंक आचेष का महत्व-हीन होना स्पष्ट है।

प्रभुत्व-शक्ति पर विशेष विचारणीय श्राचेप सर हेनरी मेन का है। यह महाशय भारतवर्ष में सात वर्ष तक सरकार के क़ानून-सदस्य रहे थे। इन्होंने श्रनुभव किया कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष श्रादि पूर्वीय राज्यों में क़ानून बनाने का भाव नहीं रहा है। प्राचीन प्रथा श्रीर नियम के श्रनुसार ही शासन होता रहा। स्वेच्छाचारी शासक भी मनमाने नये क़ानून न बनाते थे। इस प्रकार यहाँ प्रभुत्व-शक्ति ऐसी श्रपरिमित कभी नहीं हुई कि वह प्राचीनप्रयाश्रों श्रीर प्राचीन-नियमों को श्रवहेलना करे वरन् वह तो सदैव इनके द्वारा परिमित रही है। यह बात उड़ श्रशों में श्राधुनिक पाश्चात्य देशों के सम्बन्धमें भी चिरतार्थ होती है।

इस द्रिट से मेन ने यह प्रतिपादन किया कि प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमितः या प्रतिवन्ध-रहित नहीं कहा जा सकता।

इस विषय में कुछ राजनीतिशों का कथन है कि प्रभुत्व शक्ति का सिद्धान्त आधुनिक राज्यों के सम्बन्ध में ही चरितार्थ होता है। अन्य लेखकों ने प्राचीन और मध्य-कालीन राज्यों पर भी प्रभुत्व-शक्ति का विद्धान्त लगाने, और साथ ही सर हेनरी मेन द्वारा किये हुए पूर्वोक्त आद्येप से बचने के लिए राज्य और कानून का अर्थ व्यापक कर दिया है। वे क़ानून के अन्तर्गत समाज के उस आचार विचार को भी सम्मिलित करते हैं जिसको राज्य ने मान्य करके नियम का स्वरूप प्रदान कर दिया है।

राज्य की प्रभुत्व-शक्ति कहाँ होती है ?— प्रत्येक राज्य में ऐसी शक्ति होती है जो सर्वोपिर या सर्वोच्च होती है; पर वह शक्ति कहाँ पायी जाती है ? उसका निवास-स्थान कहाँ है ? इस विषय पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य का उदाहरण लें। इंगलैंड का उदाहरण सहज ही समभ में आ सकता है। यद्यपि यहाँ क़ान्न से बादशाह समस्त शक्ति का स्रोत है, वह सब कार्य अपने प्रधानमंत्री के परामशं से करता है। प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों का सहयोग प्राप्त होता है। श्रीर, सब मंत्री ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार पार्लिमेंट को ही कानूनी प्रभुताप्राप्त है। पार्लिमेंट का पारिमाषिक अर्थ बादशाह के श्रितिरक्त सरदार-सभा और प्रतिनिधि-सभा है। जिस झानून को वह बनाती है, वह वैध होता है; किसी न्यायालय में उसके श्रीवित्य या न्यायानुकूलता का प्रश्न नहीं उठ सकता; परम्परा

रिवाज या पुराने क़ानून या श्रिषिकार पत्र उस प्रयोग में वाधक नहीं हो सकते । कोई संस्था उसे रद वा संशोधित नहीं कर सकती। किसी नागरिक का कोई ऐसा श्रिषकार नहीं है, जिसे पार्लिमेंट रद न कर सके।

श्रव्छा, संयुक्त-राज्य-श्रमरीका में प्रभुत्व-शक्ति का निवास कहाँ है ? यहाँ प्रभुत्व शक्ति के निवास-स्थान की बात कुछ पेचीदा है। यहाँ की भिन्न-भिन्न रियासतों की प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक (नियामक) शक्तियाँ परिमित हैं। इसी प्रकार संघ सरकार के राष्ट्रपति तथा काँग्रेस में से प्रत्येक की, तथा सम्मिलित रूप से दोनों की, शक्तियाँ भी परिमित हैं। ब्रिटिश पार्लिमेंट की तरह अमरीका की कांग्रेस को मनचाहा क़ानून चनाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय में संघ सरकार तथा प्रत्येक रियासत के बनाये क़ानून की न्यायानुकूलता पर विचार हो सकता है, श्रौर श्रगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त कानून श्रमरीका के शासन-विधान के विपरीत है तो वह उसे रह कर सकता है। परन्त इससे यही तो श्रभिपाय: निकला कि श्रमरीका में कांग्रेस, राष्ट्रपति श्रथवा (श्रमरीका की) रियासतों में से किसी एक को प्रभुत्व-शक्ति -पाप्त नहीं है। मुख्य अधिकारी कोई और ही है। यहाँ प्रभुत्व-शक्ति उस संस्था के पास है जिसे मनचाहा कानून बनाने का - अर्थात् अमरीका के शासन-विधान का संशोधन करने का कानूनी अधिकार है। * इस

^{*}काँग्रेस के दो-तिहाई सदस्य, या विविध रियासतों के तीन-चौथाई व्यवस्थापकों द्वारा श्रनुमोदित विशेष सभा के सदस्य, श्रमरीका के शासन-विधान को बदल सकते हैं।

संस्था के बनाये नियमों पर न्यायालय को कोई ऋधिकार नहीं है। इसके ऋधिवेशन केवल विशेष दशाश्रों में ही होते हैं। तथापि सिद्धान्ततः इसका ऋस्तित्व है।

राजनेतिक प्रभुत्व-शक्ति श्रोर जनता — कुछ लेखकों के विचार से प्रभुत्व-शिक्त की एक कल्पना क़ानूनी है श्रोर दूसरी राजनेतिक । क़ानूनी प्रभुत्व-शिक्त वह है जिसका श्रस्तिख केवल कानून की हिन्द से हो, राजनैतिक प्रभुता का सम्बन्ध दैनिक श्रर्थात् व्यव-हारिक राजनीति से होता है। स्वेच्छाचारी या श्रनियंत्रित राज्यों में राजा में प्रभुत्व-शिक्त मानी जाती है, क़ानून से वही सर्वे-सर्वा, कर्ता-पर्ता है। परन्तु बहुधा वह कुछ विशेष कार्य नहीं करता, करने-घरनेवाले तो उसके मंत्री श्रादि होते हैं, वास्तविक या राजनैतिक प्रभुत्व इन्हीं का होता है। कहीं-कहीं पुरोहित, सेनापित, पूँजीपित श्रादि राज्य के वास्तविक (राजनैतिक) प्रभु होते हैं; कहने-सुनने को (क़ानून से) प्रभु-पद राजा श्रादि का रहता है।

फ्रांस की राज्य कान्ति के बाद यह विचार फैला कि राजनैतिक प्रमुख जनता के हाथ में है, जनता ही समस्त अधिकार और सत्ता का स्रोत है। जनता ही राज्य को बनाती है, और एक विशेष प्रकार की शासन-पद्धति प्रचलित करती है, वही (जनता) जब चाहे शासकों को पदच्युत कर सकती है, शासन-पद्धति का स्वरूप बदल सकती है। प्रजा-तन्त्र राज्यों में जनता अपने व्यवस्थापकों (नियामकों) को, और कहीं-कहीं अपने शासकों को चुनती है। निर्धारित अविध के पश्चात् इन व्यवस्थापकों और शासकों का नया निर्वाचन होता है।

ऊपर कहा गया है कि इंगलैंड में प्रभुत्व-शक्ति ब्रिटिश पार्लिमेंट के हाथ में है। वहाँ केवल क़ानूनी प्रभुता का आशय लिया जाना चाहिए। राजनैतिक प्रभुता तो वहाँ जनता की ही समभनी होगी। बात यह है कि पार्लिमेंट के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, वे जनता के विचारों और इच्छाओं की अबहेलना नहीं कर सकते। उन्हें वहीं क़ानून बनाने का विचार करना पड़ता है, जिसे, उनकी समभ से, जनता का प्रभावशाली भाग चाहता है। वे अपनी पच्च के समर्थन में जनता की इच्छा की ही बात कहते हैं।

यहाँ हमने इंगलैंड के सम्बन्ध में विचार किया है। यह एक वैष राजतंत्र है। अन्य वैध राजतंत्र या प्रजातंत्र राज्यों के विषय में भी यही बात (प्रभुत्व-शक्ति का जनता में होना) सहज ही समम में आ सकती है। परन्तु अवैध राज-तंत्र में यह बात कुछ अस्पष्ट रहती है। वहाँ राजा ही क़ानून बनाता है और वही उसका पालन कराता है इस प्रकार वही व्यवस्थापक और शासक होता है। यही नहीं, उसके बारे में तो यह कहावत ठीक ही है कि 'राजा करे सो न्याय'। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा में ही प्रभुत्व-शक्ति रहती है। परन्तु इस सम्बन्ध में विचार करना होगा कि उपयुक्ति राजा भी प्रायः किसी न किसी मित्र, मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि से विचार-विनिमय करता है, सलाह लेता है, चाहे वह नियमित रूप में न हो। प्राचीन भारत में जबिक एक तंत्र राज-पडित बहुत प्रचित्तत थी, राजा स्वयं-क़ानून नहीं बनाते थे, वरन् धर्मशास्त्रों में विधित क़ानूनों के अनुसार शासन करते थे। नये क़ानून बनाने, या क़ानूनों की व्याख्या करने का काम

विद्वान ब्राह्मणों ब्रादि का था, ब्रौर ये लोग जनता के भावों, विचारों तथा उसकी ब्रावश्यतात्रों का यथेष्ट ध्यान रखते थे। इस प्रकार एक-तंत्र राज्य में भी प्रभुत्व-शक्ति का निवास-स्थान ब्रन्ततः जनता में ही होना सिद्ध होता है।*

एक विद्वान का कथन है कि 'प्रभुत्व उसीका होता है, जो शिक्तशाली है। जो आजा का पालन करा सके और राज्य को नियंत्रित रखे, उसी को राज्य का प्रभु समझना चाहिए। यदि हम जनता को प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न मानें तो क्या समस्त जनता शक्तिशाली होती है? जनता में तो बालक, बूढ़े, स्त्रियाँ और रोगी भी होते हैं। फिर संगठित तथा नियंत्रित जनता और असंगठित तथा अनियंत्रित जनता में भी बहुत अन्तर है।

क्या जनता के राजनैतिक प्रभुत्व का अर्थ निर्वाचकों की प्रभुत्व-शक्ति समभा जाय ? अनेक राज्यों में निर्वाचक कुल जनता में से आधे से लेकर पंचमांश या इससे भी कम होते हैं। क्या इन्हें ही जनता समभा जाय ? परन्तु ये तो निर्धारित समय पर केवल प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और कुछ, नहीं करते। फिर इन्हें प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न कैसे माना जाय ? जिन राज्यों में, किसी विशेष विषय पर, अथवा कोई विशेष नियम बनाने के लिए, निर्वाचकों का मत लेने की पद्धति है.

^{*}जान श्रास्टिन का मत है कि प्रमुख-शक्ति ऐसे ख़ास व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के हाथ में रहती है, जो निश्चित या प्रत्यच्च हो। परन्तु जनता में यह बात नहीं होती। जनता का कोई निश्चित स्वरूप नहीं हैं, कोई खास व्यक्ति या व्यक्ति-समूह अपने श्रापको वास्तव में जनता नहीं कह सकता।

वहाँ उस सीमा तक अवश्य ही शासन-कार्य में उनका कुछ विशेष अधिकार माना जा सकता है; परन्तु स्मरण रहे कि अधिकांश निर्वाचकों पर उनके सम्बन्धियों तथा पैसेवालों आदि का इतना प्रभाव पड़ता है कि वे अपने स्वतंत्र मत का उपयोग बहुत कम करने पाते हैं। इस प्रकार निर्वाचकों को भी प्रमुख का आधार मानना कहाँ तक ठीक है ?

अच्छा अब प्रतिनिधियों की बात लें। आजकल प्रतिनिधि-निर्वाचन कार्य बहुत कष्ट श्रीर व्यय-साध्य है। श्रधिकाँश स्थानों में या तो धनी-मानी व्यक्ति प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको धनी-मानियों का समर्थन प्राप्त हो। फिर दलबन्दी का युग ठहरा। जिस दल का व्यवस्थापक सभा में बहुमत होता है, वही दल मंत्रि मंडल बनाने में सफल होता है, शासन-सूत्र उसी के हाथ में रहता है। अन्य दलों में जो सब से बलवान होता है, वह इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि कव उसके लिए अनुकृत समय आवे और कब उसका बहुमत बन सके। हिसाब लगाने पर मालूम हो सकता है कि बहुधा पदारूढ दल वास्तव में जनता के बहुत थोड़े भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग निर्वाचन-कार्य में, श्रार्थिक वाघाओं के कारण सफल नहीं होते, श्रथवा प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाने पर भी दलवन्दी में श्रनुराग नहीं रखते, उनकी शासन कार्य में कुछ नहीं चलती। फिर भी श्राधुनिक प्रतिनिध्यात्मक शासन को जनतंत्र या जनता का ही राज्य कहा जाता है। बात यह है कि जनता को शासन-कार्य में भागीदार बनाने का अभी कोई इससे बेइतर तरीका मालूम नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में प्रयत्न चल रहा है। सम्भव है, घीरे-घीरे इस दिशा में कुछ सुधार हो श्रीर कालान्तर में, शासन में श्रधिकाधिक जनता की शक्ति का उपयोग हो। श्रस्त, चाहे निर्वाचन-पद्धित श्रीर दल-निर्माण श्रादि में सुधारों की कितनी ही श्रावश्यकता हो, यह तो स्वीकार करना ही होता है कि राज-सत्ता या प्रभुत्व-शक्ति का निवास, श्रीर किसी की श्रपेक्षा जनता में ही श्रधिक है।

विशेष वक्तव्य-यहाँ यह प्रश्न भी उठ सकता है कि जब जनता में प्रभुत्व-शक्ति का निवास है तो वह शासकों का अत्याचार क्यों सहती है। बात यह है कि जनता में अज्ञान होता है. उसे अपनी शक्ति का बोध नहीं होता, उसमें संगठन का अभाव होता है. वह अपने बल का यथेष्ट उपयोग करने की अत्युत्तम विधि नहीं जानती. उसके, भिन्न-भिन्न भागों में, विभाजित होने से श्रीर उन भागों के आपस में लड़ने-भगड़ने से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो राजाओं का जोर बढ जाता है, वह मनमाना शासन करते हैं। जनता को यह विचार ही नहीं होता कि राजा के कार्य का विरोध कर उसे सत्वय पर लाने का प्रयत्न करे। तथापि उस दशा में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब राजाश्रों का श्रत्याचार बहुत श्रिधक होने लगा और वह प्रजा की सहन-शक्ति को लाँघ गया, तो प्रजा में क्रमशः विद्रोह की भावना जाएत हो गयी और वह यहाँ तक बढ़ी कि अन्ततः राजा को अपने अधिकार और पद से हाथ धोना पड़ा । 🦠

श्रस्तु, श्रव प्रत्येक सम्य समाज में यह बात मानी जाती है कि

राजनैतिक प्रभुत्व का निवास जनता में है, चाहे वह अपनी शिक्त कुछ विशेष अधिकारियों को ही क्यों न देदे। अतः उन्नत समाजों में बिना विद्रोह के ही जनता शासन-पद्धति में आवश्यकता- नुसार परिवर्तन और संशोधन कर लेती है। हाँ, प्रभुत्व-शक्ति की हिण्ट से संसार में वास्तविक जनता का युग आने में अभी विलम्ब है।



बारहवाँ परिच्छेद राज्य श्रीर व्यक्ति

शक्ति अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होती है। तो क्या राज्य में व्यक्ति या नागरिक की कोई स्वतंत्रता नहीं होती ? क्या प्रभुत्व-शक्ति के साथ व्यक्ति-स्वातंत्र्य का सामंजस्य नहीं है ?

क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र था ?—
प्रायः यह समभा जाता है कि प्रारम्भिक श्रवस्था में, जब राज्य का
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, मनुष्य प्राकृतिक या नैसर्गिक जीवन व्यतीत
करता था, तो वह सर्वथा स्वतंत्र था; जो जी में श्राता वह करता श्रीर
जहाँ इच्छा होती, वहाँ जाता । राज्य की उत्पत्ति के बाद मनुष्य के
स्वच्छन्द जीवन में बाधा उपस्थित हो गयी । उसके कार्यों पर नियंत्रण
होने लगा । श्रव वह श्रपनी मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, राज्य
से उसकी स्वच्छन्दता विज्ञप्त होगयी । इस कथन में कहां तक सचाई
है श्रिया वास्तव में, राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य स्वतंत्र जीवन
व्यतीत करता था ?

उस अवस्था की कल्पना करो, जब मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। मोहन के मन में आया, उसने गोविन्द की कोई चीज़ उढाली, सोहन को पीटा और यमुना को अपशब्द कहा। इस दशा में मोहन बलवान है, वह स्वच्छन्दता का व्यवहार कर रहा है। अब यदि केवल उसी की दृष्टि से विचार करना हो तो कहा जा सकता है कि उस समय स्वतंत्रता थी। परन्तु मनुष्य अकेला नहीं रहता, वह समाज में रहता है, और हमें समाज की दृष्टि से ही विचार करना है।

सामाजिक जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता—उपर्युक्त उदा-हरण में मोहन की स्वतंत्रता का अर्थ गोविन्द, सोहन और यमना की स्वतंत्रता का अपहरण है। इसी प्रकार, अन्य उदाहरण लेकर यह दर्शाया जा सकता है कि यदि मोहन बीस आदिमियों की मंडली में सबसे बलवान है, और अपनी स्वतंत्रता के उपभोग में सब को कष्ट पहुँचाता है, तो समाज की दृष्टि से यहाँ स्वतंत्रता का अभाव ही है। यदि मोहन अकेला रहता तो वह चाहे जहाँ जाता, और चाहे जो वस्तु लेता, वह अपनी प्राकृतिक या नैसर्गिक स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर सकता था। परन्तु यह बात तो है नहीं, वह समाज में रहता है। और, समाज में व्यक्तियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं रह सकती। आज दूसरे लोगों को मोहन के विरुद्ध शिकायत है, कल ऐसा अवसर आ सकता है कि कोई मोहन को सताने लगे, तब मोहन को उसके विरुद्ध शिकायत होगी।

निदान, समाज में व्यक्तियों की सुख-शान्ति और वैयक्तिक स्वतंत्रता अभीष्ट है तो मोहन और उसके जैसे और भी सब व्यक्तियों के उन कार्यों का नियंत्रण करना होगा, जिनसे दूसरों को हानि होती है,

या कष्ट पहुँचता है। यदि यह नियंत्रण करने वाली सत्ता अपूर्ण हुई, उसे अपने अधिकार के उपयोग करने में कुछ बाधा रही तो उसी सीमा तक वह समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ रहेगी। इस प्रकार व्यक्ति-स्वातंत्र्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोई शक्ति ऐसी हो जिसका सब व्यक्तियों पर अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण नियंत्रण हो। जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों की जान-माल की सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है तो राज्य की शक्ति अवश्य ही अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होनी चाहिए। किसी नागरिक का राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं माना जा सकता, बिना भेद-भाव के सभी नागरिकों पर राज्य की पूर्ण सत्ता होनी चाहिए।

श्रराजकता की दशा में कुछ व्यक्ति-विशेष मनमाना कार्य करते हैं, दूसरों के कार्य-व्यवहार में हस्तच्चेप करते श्रीर उन्हें हानि या क्षित पहुँचाते हैं। इसके श्रितिरक्त यह भी होता है कि किसी चीज़ को सभी श्रादमी लेना चाहते हैं। इससे श्रापस में भगड़ा होता है, मार-पीट की नौवत श्राती है श्रीर श्रनेक व्यक्ति हताहत हो जाते हैं; भावी कलह की नींव पड़ जाती है, समाज छिन्न-भिन्न हो जाता है। इसलिए समाज की दृष्टि से, श्रिष्टिकांश व्यक्तियों के विचार से, श्रराजकता श्रवांछनीय है। राज्य का निर्माण करके, समाज के व्यक्ति मनमाने कार्य करने या मनचाही चीज़ प्राप्त करने के श्रिष्टकार पर राज्य का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राज्य के प्रादुर्भीव से व्यक्तियों के श्रिष्टकार सीमित हो जाते हैं।

स्मरण रहे कि वास्तव में स्वतंत्रता श्रीर बात है तथा स्वच्छन्दता

या उच्छुङ्खलता श्रीर बात । दोनों को एक समभाना भयंकर भूल है। दोनों में ज़मीन श्रासमान का अन्तर है। स्वच्छन्दता का आशय, बिना किसी व्यक्ति या संस्था का लिहाज किये मनमाना कार्य करने का है। स्वच्छन्द व्यक्ति किसी के सुख-दुख या हानि-लाभ का विचार नहीं करते। यह समाज के लिए ऋहितकर है, बहत श्रनिष्टकर है। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता का अर्थ दिना किसी भी प्रकार की बाधा के, जो जी में आये, वह करने का लिया जाय, तो ऐसी स्वतंत्रता सम्भव या व्यवहारिक नहीं है। समाज में एक-से-एक ऋधिक बलवान हैं, इस प्रकार एक की स्वतंत्रता में दूसरा बाधक हो सकता है, दूसरे की स्वतंत्रता में तीसरा बाधक हो सकता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा, यहाँ तक कि अन्त में एक ही व्यक्ति ऐसा रहेगा. जिसकी स्वतंत्रता में कोई अन्य व्यक्ति बाधक न हो सके। पर उसकी स्वतंत्रता में भी कोई अन्य दो या अधिक व्यक्ति मिलकर बाधक हो सकते हैं। इस प्रकार किसी की भी स्वतंत्रता सर्वथा निर्वाध नहीं हो सकती।

इससे स्पष्ट है कि ऐसी निर्वाध श्रीर पूर्ण स्वतन्त्रता सब व्यक्तियों को एक-साथ एक ही समय में नहीं हो सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न राज्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, श्रीर न उसके बिना ही। श्रतः स्वतन्त्रता का श्रर्थ दूसरों को कम-से-कम हानि पहुँचाते हुए श्रपनी इच्छाश्रों को पूरा कर सकने का लिया जाता है। समाज में कोई व्यक्ति श्रपने व्यवहार में वहाँ तक ही स्वतन्त्र रह सकता है, जहाँ तक कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न करे। एक की

स्वतन्त्रता का आशय, दूसरों की स्वतन्त्रता पर श्राघात पहुँचाना नहीं है। वह स्वतन्त्रता ही क्या हुई जो सब नागरिकों के लिए समान रूप से नहों।

इरवर्ट स्पेन्सर ने बहुत ठीक कहा है कि एक आदमी अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतन्त्र है, बशतें कि वह किसी दूसरे आदमी की वैसी स्वतंत्रता में बाधक न हो। अथवा हम यों भी कह सकते हैं कि मनुष्य को वैसा कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए, जैसे कार्य की स्वतन्त्रता वह दूसरों को देने को तैयार नहीं है। उदाहरखवत् में नहीं चाहता कि कोई मेरा माल चुरावे, मुफे मारे-पीटे या गाली दे, तो मुफे भी ऐसी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती कि में किसी दूसरे का माल चुराऊँ, किसी को मारूँ या अपशब्द कहूँ। यदि स्वतन्त्रता की यह मर्यादा न रहेगी तो समाज का जीवन कितना संकटमय हो जायगा, यह स्पष्ट ही है।

समाज में स्वतन्त्रता की मर्यादा रखने के लिए, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' न होने देने के लिए, यह आवश्यक है कि मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार की सुविधा के लिए कुळ नियम या क़ानून रहें, जिनका सब व्यक्ति पालन करें। क़ानून का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य सुख-शान्ति का जीवन व्यतीत करे, परन्तु उसके किसी कार्यव्यवहार में दूसरों की हानि, असुविधा या कष्ट आदि न हो। साधारण्यत्या आदमी क़ानून को स्वतन्त्रता में वाधक समका करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि क़ानून और स्वतन्त्रता का परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है। वे तो इन्हें सर्वथा बे-मेल मानते हैं। उनका

कथन है कि जहां कानून होगा, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं रह सकती । परन्तु विचार करने पर यह जात हो सकता है कि इस कथन में कुछ सार नहीं है। ऊपर उदाहरण द्वारा यह बताया जा चुका है कि सर्वथा अमर्यादित स्वतन्त्रता केवल उसी दशा में सम्भव है, जब अकेले एक ही व्यक्ति की बात हो। समाज में, जहाँ अनेक आदमी मिल-जुलकर पास-पास रहते हैं, वैसी स्वतन्त्रता व्यवहारिक नहीं है, हितकर भी नहीं है। राज्य में नागरिकों को वही स्वतन्त्रता रहती है, जो सब के लिए सम्भव होती है। इसी स्वतन्त्रता का क़ानून द्वारा अनुमोदन होता है; इसी की रक्षा क़ानून करता है।

त्रव यह अच्छी तरह ध्यान में आ सकता है कि वास्तविक अर्थात् व्यवहारिक स्वतन्त्रता का राज्य की नियन्त्रक शक्ति से कोई विरोध नहीं है। मुफ्ते दूसरे व्यक्तियों के हस्तच्चेप से मुक्ति तभी मिल सकती है, जब उस इस्तच्चेप को बल-पूर्वक रोक सकनेवाली शक्ति का अस्तित्व हो। यह शक्ति राज्य में होती है। नागरिक अपने कार्य में दूसरों के हस्तच्चेप और वाधाओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपाय यही है कि वे राज्य की सत्ता को अपरिमित, निर्वाध और स्वतन्त्र माने। यही बात राज्य की प्रभुत्व-शक्ति के सिद्धान्त में निहित है। नागरिकों को व्यवहारिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने के लिए राज्य की प्रभुत्व-शक्ति मान्य करनी होती है।

वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा—नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित दो तरह से आधात पहुँचने की सम्भावना हुआ करती है:—

- (१) जबिक एक नागरिक (व्यक्ति या व्यक्ति-समूह) के कार्य-व्यवहार में दूसरा नागरिक (व्यक्ति या व्यक्ति-समूह) श्रनुचित हस्तच्चेप करता है; अर्थात् जब नागरिकों का त्रापस में ही भगड़ा होता है।
- (२) जबिक सरकार (सरकारी कर्मचारी) किसी नागरिक के अधिकार को अपहरण करना चाहती है; अर्थात् जब नागरिक का सरकार से विरोध हो।

दोनों दशाओं में राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब दो नागरिकों का पारस्परिक भगड़ा होता है तो यह निर्णय करना होता है क़ानून की दृष्टि से किसका पक्ष उचित है और किसका अनुचित। इसके लिए राज्य में स्थान-स्थान पर दीवानी तथा क्षीजदारी आदि के सरकारी न्यायालय स्थापित रहते हैं। छोटे न्यायालयों के फ़ैसलों की अपील बड़े न्यायालयों में हो सकती है, जिससे यदि यह आशंका हो कि निचले न्यायालय में निर्णय ठीक नहीं हुआ, तो उसका पुनर्विचार या संशोधन हो सके।

सरकार (श्रथवा उसके किसी श्रधिकारी) को भी यह श्रधिकार नहीं है कि नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का श्रपहरण करें। उन्नत राज्यों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि यदि सरकार नागरिकों के श्रधि-कारों में हस्तच्चेप करे तो वे श्रपनी रक्षा कर सकें। शासन-पद्धति की कुछ धाराएँ इसी उद्देश्य से बनायी जाती हैं; क्योंकि शासन-पद्धति में संशोधन तथा परिवर्तन करने का श्रधिकार नागरिकों (श्रर्थात् उनके प्रतिनिधियों) को ही होता है, श्रतः जब ऐसा प्रतीत होता है कि

वर्तमान धाराएँ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं. तो उनमें श्रावश्यक परिवर्तन या परिवर्द्धन कर दिया जाता है। इसलिए अधिकारियों को सहसा यह साइस नहीं होता कि नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आघात करें। हाँ, जिन राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ यथेष्ट श्रिधिकार-सम्पन्न नहीं हैं श्रर्थात् जहाँ नागरिकों को शासन-पद्धति में श्रावश्यक परिवर्तन श्रादि करने का अधिकार नहीं है और जहाँ न्यायालय भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, वहाँ सरकार द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता पर श्राघात होने की श्राशंका बनी रहती है। इंगलैंड में पार्लिमेंट को शासन-पद्धति सम्बन्धी पूर्ण स्वतंत्रता है, वह जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। उसने नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता सम्बन्धी कई क्वानून बना रखे हैं। इसके अतिरिक्त, इंगलैंड में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा में वहाँ के न्यायालयों का भी बड़ा भाग है। वे उपयुक्त काननों की आलो-चना तथा व्याख्या बड़ी उदारता से करते रहते हैं। जब कोई स्वेच्छाचारी श्रिधकारी —चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो — उक्त क़ानूनों की अवहेलना करता है, तो उसे पर्याप्त दंड दिया जाता है। बहुत समय से वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा होते रहने से, अब तो वहाँ उसकी परम्परा ही बन गयी है। नागरिक उसका तनिक भी अपहरण सहन नहीं कर सकते।

अमरीका में, शासन-विधान में ही वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की व्यवस्था है। कोई राज्य उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। पुनः वहाँ संघ न्यायालय है, जो व्यवस्थापक सभा से भी ऊपर है। यदि वहाँ कोई क़ानून शासन-विधान की भावना के विरुद्ध वन जाय तो संघ-न्यायालय उसे तुरन्त रह कर सकता है। श्रस्तु, इंगलैंड, श्रमरीका श्रादि में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की विधि कुछ भिन्न होते हुए भी नागरिकों को प्राय: समान रूप से ही स्वतंत्रता प्राप्त है। योरप श्रमरीका में राज्य-नियम स्पष्ट तथा सुनिश्चित हैं, उनका सम्यक् पालन किया जाता है श्रीर सब नागरिक समान समके जाते हैं। इससे वहां वैयक्तिक स्वतंत्रता पूर्णत: सुरक्षित है।

राज्य का सावयव सिद्धान्त -राज्य श्रीर व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध को समभत्ने के प्रसंग में राज्य का सावयव सिद्धान्त भी बहुत विचारणीय है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है. राज्य श्रीर मनुष्य में बहत-कुछ समानता है। राज्य एक राजनैतिक संस्था है। दोनों शरीरघारी हैं। मनुष्य के शरीर के रक्त-विन्दुओं (Cells) का जो सम्बन्ध शरीर के साथ है, वहीं सम्बन्ध मनुष्यों का राज्य के साथ है। जिल प्रकार शरीर के किसी श्रंग को श्राघात पहुँचने से समस्त शरीर पीड़ा का श्रनुभव करता है, उसी प्रकार (वास्तविक) राज्य को भी अपने किसी नागरिक के पीड़ित होने पर कष्ट होता है । मनुष्यों की ही तरह राज्य उत्पन्न होता, बढ़ता श्रीर श्रन्त में नष्ट होता है। मनुष्य के भिन्न-भिन्न श्रंगों की भाँति राज्य के विविध श्रंग श्रपना-अपना कार्य करते हैं। राज्य मनुष्य का विराट-स्वरूप है। भिन्न-भिन्न लेखकों ने मानव शरीर के साथ राज्य की तुलना बहुत आ्राकर्षक ढंग से की है। एक ने मनुष्य के सिर की तुलना राज्य की सर्वोच सत्ताः

से, मित्तिष्क की राज्य के कानून और प्रथाओं से, इच्छाओं की जों और मित्रिस्ट्रेटों से, मुंह और पेट की ज्यापार, खेती और उद्योग धंघों से, तथा रक्त की सार्वजनिक कोष से तुलना की है। इससे इस सिद्धान्त का भाव सहज ही समभ में आ सकता है।

श्रव तिनक यह भी विचार करें कि इस के विपत्त में क्या कहा जाता है। इस सिद्धान्त के विरोधियों की मुख्य बातें ये हैं:—

- (क) शरीर में रक्त विन्दुओं की स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शिक्त नहीं है; वे शरीर के साथ रहने की दशा में, उसकी किया में सहायक अवश्य हैं, पर शरीर से पृथक होने पर उनका उपयोग नहीं रहता। इसके विपरीत मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शिक्त है, चाहे सह राज्य में रहे या अलग।
- (ख) मनुष्य चेतन प्राणी है, उसका जनम, विकास श्रीर मृत्यु होती है। उसके शरीर के साथ ही उसके भिन्न-भिन्न श्रंगों की वृद्धि होती हैं; परन्तु यह श्रावश्यक नहीं है कि राष्य की वृद्धि के साथ उसके श्रंग-भूत मनुष्य की भी वृद्धि हो होती हो। बहुधा इसके विपरीत भी श्रनुभव में श्राता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की भौति राष्य चेतन प्राणी नहीं है।
- (ग) चेतन प्राणी का विकास और विनाश स्वयं प्राकृतिक नियमों से होता रहता है, किसी दूसरे के आधार पर नहीं। परन्तु राज्य का प्रादुर्भाव, विकास और विनाश मनुष्य के आश्रित है। मनुष्य जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन या परिवर्द्धन आदि कर सकता है।

दीनों पक्ष की बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि राज्य श्रीर व्यक्ति में कुछ समानता तो श्रवश्य है, पर वह समानता एक श्रंशा में ही है. पूर्ण रूप से नहीं। अस्तु, मुख्य प्रश्न तो यह है कि इस तलना से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। राज्य के सावयव-सिद्धानत को स्वीकार करने से यह मानना होता है कि व्यक्ति का स्वतंत्रः श्रस्तित्व नहीं है, वह जो कुछ है, समाज या राज्य का श्रंग होने से है ॥ श्रत: व्यक्ति को चाहिए कि श्रपने-श्रापको राज्य के श्रपंश करदे श्रीर उसकी इच्छा या उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहे। इस प्रकार राजनीति में व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं रहता। परन्तु, जैवा कि ऊपर कहा गया है, राज्य श्रीर व्यक्ति में समानता पूर्ण रूप से नहीं है: कई बातें राज्य के सावयव-सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। श्रतः राज्य श्रीर व्यक्ति की तुलना से जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वही पूर्ण रूप से उचित नहीं है। राज्य श्रौर व्यक्ति एक दूसरे से पृथक या स्वतंत्र नहीं हैं, दोनों को एक दूसरे का सहयोग चाहिए। राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और व्यक्ति राज्य की प्रभुता को मान्य करे। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है; इसका विशेष विचार ऊपर हो ही चुका है।

स्वतंत्रता का विशेष ऋर्य—राज्य के नियंत्रण में प्राप्त होने-वाली वैयक्तिक स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिबटीं), कहते हैं। राजनैतिक साहित्य में 'स्वतंत्रता' शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में भी किया जाता है। उदाहरणार्थ इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव अहण किया जाता है। जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं है, यह देश स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए आन्दोलन कर रहा है, तो स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता होता है, जो प्रत्येक देश के लिए अत्यन्तः आवश्यक है।

पुनः जब इम यह कहते हैं कि श्रमरीका या इंगलैंड में स्वतंत्रः सरकार है तो हमारा श्राशय ऐसी सरकार से होता है, जो जनता के मत से बनी है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, श्रीर क़ानून द्वारा स्थापित है। इन देशों की राजनैतिक परिस्थित के दिगृदर्शन के लिए इम उसे वैधानिक या विधानात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं। ऐतिहासिक प्रसंग में हम ऐसी सरकार को भी वैधानिक सरकार कह देते हैं, जिसके निर्माण या संगठन में राज्य के कुछ ही श्रादमियों ने भाग लिया था, सब ने नहीं। उदाहरणवत् इंगलैंड में मताधिकार का विस्तार तथा तत्सम्बन्धी सुधार प्रथम बार बिशेषतया सन् १८३२ ई० में हुआ, उस से पूर्व वहाँ जनता के बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही शासन-पद्धति निर्घारित करने का अवसर प्राप्त था। परन्तु चूँ कि वे थोड़े से व्यक्ति (मतदाता) भी जनता का प्रतिनिधित्व करते तथा लोगों को सरकार की ज्यादतियों से बचाने का प्रयत करते थे, इसिलए इंगलैंड की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति को भी 'वैधानिक स्वतंत्रता' कहा जा सकता है। तथापि वास्तव में इस शब्द का प्रयोग हमें ऐसे देश के सम्बन्ध में ही करना चाहिए, जहाँ जनता अर्थात् सर्वेषाधारण नागरिकः श्रपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं।

तेरहवाँ परिच्छेद राज्यों के भेद

हिन्द्विछले परिच्छेदों में राज्य सम्बन्धी कुछ बातों का विचार किया गया है। अब हम यह विचार करेंगे कि राज्य कितने प्रकार के होते े हैं, प्राचीन काल में उनके कितने भेद किये जाते थे, और पीछे उस वर्गीकरण के विषय में लोगों का क्या मत हुआ। इस विषय की भी चर्चा की जायगी कि किस प्रकार के राज्य में क्या गुण-दोष होते हैं।

नगर-राज्य त्रौर देश-राज्य-पत्येक राज्य में भूमि श्रौर जनता श्रनिवार्य रूप से होती हैं। क्या इनके श्राधार पर राज्यों का वर्गीकरण करना ठीक होगा ? यह कहना कि इतनी जनता वाला इतना मृ.भाग एक प्रकार का राज्य माना जाय, श्रीर उससे बड़ा दूसरे प्रकार का, शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं जचता। तथापि भृमि श्रीर जनता

के विचार से राज्य के दो मेद किये जाते हैं, नगर-राज्य श्रीर देश-राज्य! नगर-राज्यों का उदाहरण विशेषतया प्राचीन यूनान में मिलता है। वहाँ एक-एक नगर का एक-एक राज्य था। नगर के निवासियों को नागरिक कहा जाता था, श्रीर वे श्रपना शासन-प्रवन्ध करते थे। कालान्तर में वहाँ राज्य बड़े-बड़े होने लगे, उनका चेत्र एक-एक देश तक होने लगा। इन्हें देश-राज्य कहा जाता है। एशिया में तो ऐसे राज्य चिरकाल से रहे हैं।

राष्ट्र-राज्य — सोलहवीं शताब्दी से कई देश-राज्य राष्ट्र-राज्य बनने लगे । उस समय राष्ट्रीयतां की लहर बड़े वेग से चलने लगी थो । किसी एक जाति या संस्कृति के आदमी जब अपने राज्य का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे राष्ट्र कहा जाता है । राष्ट्रीयता के लिए एक निर्धारित भूमि का होना तो आवश्यक है ही, इसमें और भी कई बातें सहायक होती हैं. यथा जाति श्रीर भाषा की एकता, धर्म की एकता अ।दि। किन्तु सब से अधिक महत्व भावों या हृदयों की एकता का होता है, जिससे उस चेत्र के सब श्रादमी परस्पर प्रेम श्रौर सहानुभृति से रहते हैं, श्रीर एम्मिलित रूप से श्रपनी उन्नति का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीयता के श्राघार पर बने हुए राज्य राष्ट्र-राज्य कहलाते हैं। योरण में फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की श्रादि राज्यों का निर्माण इसी प्रकार हुआ। किन्तु अब तो कोई राज्य किसी विशेष राष्ट्रीयता के ही आदिमयोंवाला नहीं होता। प्रत्येकराज्य में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति रहते हैं; उन्नत राज्यों के व्यक्ति अपनी भिन्नता की बातें सुलाकर राज्य-कार्य में भली भौति सहयोग प्रदान करते हैं। इसिलए

श्रव राष्ट्रीयता के श्रनुसार राज्यों का वर्गीकरण किया जाना निरर्थक है।

प्रोहित-राज्य श्रीर लौकिक राज्य-राज्यों का एक वर्गीकरण इस विचार से भी किया जाता है कि उसमें या तो धर्म-सम्बन्धी विषयों को प्रधानता दी जाती है, या सांसारिक विषयों को । पहले को पुरोहित राज्य श्रीर दूसरे को लौकिक राज्य कहा जाता है। प्राचीन काल में प्रोहित-राज्य की बहुतायत थी। त्रादमी समभते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तथा राज्य को श्रपने चेत्र में विशेष धर्म के प्रचार का कार्य करना चाहिए। ऐसी अवस्था में राज्य में पुरोहितों श्रीर पंडितों का विशेष प्रभाव होना स्वभाविक ही था। पीछे क्रमशः ऐसे विचारों का हास होता गया। श्रव एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न धर्मों के माननेवाले रहते हैं श्रीर यह श्रावश्यक समभा जाता है कि राज्य को लौकिक विषयों पर ही ध्यान देना चाहिए, श्रौर उसे पुरोहितों। श्रादि के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इस प्रकार श्रव पुरोहित-राज्य का प्राय: लीप ही हो गया है। अधिकाँश में लौकिक राज्य ही रह जाने से, राज्यों के इस वर्गीकरण में कुछ तत्व नहीं रहा।

पशुत्व शक्ति के विचार से राज्यों के भेद, अरस्तू का मत—प्राचीन राजनीतिज्ञों में यूनान के सुप्रसिद्ध लेखक अरस्तू (ऐरिस्टाटल) श्रादि ने राज्यों के भेद करते हुए विशेष ध्यान इस बात पर दिया था कि सर्वोच्च राज-सत्ता या प्रभुत्व-शक्ति कितने व्यक्तियों में

होती है। श्ररस्तू ने राज्यों के तीन भेद किये थे:-

√१—राजतंत्र; एक व्यक्ति द्वारा शासन (Monarchy)

२-- उच्च-जन-तंत्र; कुञ्ज व्यक्तियों द्वारा शासन (Aristocracy)

३-प्रजातंत्र; बहुजन प्रजा द्वारा शासन (Polity)

अरस्तू का कथन है कि राज्यों के उपर्युक्त नाम उसी दशा में प्रयुक्त होने चाहिए, जब शासन-कार्य लोक-हित की दिष्ट से हो। इसके विपरीत, जब शासक स्वार्य भाव से शासन करें, लोक-हित की परवाह न करें, तो राज्यों का स्वरूप विकृत हो जाता है। विकृत दशा में उपर्युक्त मेदों का नाम क्रमशः इस प्रकार होना चाहिए:—

हितकर स्वरूप विकृत स्वरूप

राजतंत्र स्वेच्छाचारी तंत्र (Tyranny) उच्च-जन-तंत्र कुलीन या धनी तंत्र (Oligarchy)

प्रजा-तंत्र भुन्ड-तंत्र (Ochlocracy)

श्ररस्त् ने इसी वर्गीकरण में, बहुत-कुछ प्राचीन नगर-राज्यों के इतिहास के श्राधार पर, राज्य के स्वरूप-परिवर्तन का क्रम भी सूचित किया है। उसका मत है कि श्रारम्भ में राजा का शासन हुआ। कारण, उस समय नगर ही राज्य थे। ये नगर छोटे-छोटे थे तथा इनमें विशेष गुण-सम्पन्न व्यक्ति कम थे। ये व्यक्ति लोक-हितैषी थे। पीछे गुणवानों की संख्या बढ़ी, उन्हें एक व्यक्ति की प्रभुता सहन न हुई। उन्होंने श्रपना एक समूह बनाया और शासन करने लगे। कालान्तर में इन शासकों का पतन हुआ, ये जनता के घन से घनी होने लगे। घन से जनता में आदर मान होने लगा। इस प्रकार घनिकों के शासन

का सूत्रपात हुआ। पीछे धन-तृष्णा से शासकों का हास हो जाने से, इनके स्थान पर स्वेच्छाचारी व्यक्ति का शासन आया। इससे जनता को बल मिला और अन्ततः भुंड-तंत्र की स्थापना हुई।

कुछ लेखकों ने अरस्त् के पूर्वोक्त वर्गांकरण का स्वामाविक कम इस प्रकार निर्धारित किया है:—पहले राजतंत्र होता है, फिर कमशः स्वेच्छाचारी तंत्र, उच्च-जन-तंत्र, धनिक-तंत्र, प्रजातंत्र श्रीर अन्त में भूँड-तंत्र। भुंड-तंत्र के बाद पुनः राजतंत्र की सम्मावना होती है। इस प्रकार बार-बार दोहराये जानेवाला एक चक बन जाता है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि अनेक राज्य ऐसे होते हैं, जिन्हें न तो विशुद्ध राजतंत्र ही कहा जा सकता है, और न विशुद्ध उच्च-जन-तंत्र या प्रजातन्त्र ही। उनमें, इन मेदों में से दो-दो के, और किसी-किसी में तो तीनों के ही लक्षण मिलते हैं। इन्हें 'मिश्रित राज्य' कहा जाना चाहिए।

यद्यपि श्रव नये नये स्वरूपवाले श्रनेक राज्यों के श्रस्तित्व में श्रा जाने के कारण श्ररस्त् का वर्गीकरण उतना ठीक नहीं है, जितना उसके समय में था। तथापि वह है बहुत विचारणीय। उसका क्रमशः विचार किया जाता है। पहले राजतंत्र को लें।

राजतन्त्र

राजतन्त्र, राज्य का वह स्वरूप है, जिसमें शासनाधिकार एक व्यक्ति में (राजा या बादशाह) में केन्द्रित हों, सब राज-काज उसकी इच्छानुसार चले; राज-कर्मचारियों को जो अधिकार हों, वे राजा के दिये हुए हों। राजतंत्र के दो भेद होते हैं:—(१) श्रानियंत्रित या श्रवैघ राजतंत्र श्रौर (२) नियंत्रित या वैध राजतंत्र।

श्रवैध राजतंत्र — अवैध राजतन्त्र में राजा को शासनाधिकार पूर्ण रूप से रहता है, उसमें कोई इस्तच्चेप नहीं कर सकता । वह जैसा चाहता है, करता है; कानून या विधान से उसकी इच्छा या कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। श्रथवा यों कह सकते हैं कि उसकी इच्छा ही कानून है। 'राजा करे सो न्याय' से यही भाव व्यक्त होता है। ऐसी दशा में, यदि राजा में दया. सेवा श्रीर परोपकार का भाव हो तो वह प्रजा की बहुत आर्थिक, और नैतिक आदि उन्नति करता है, जनता को खूब मुख शान्ति श्रीर समृद्धि प्राप्त होती है, शिक्षा का प्रचार होता है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, श्रौर राज्य उत्तरोत्तर उन्नत तथा सभ्य होता जाता है। इसके विपरीत, यदि राजा भोग-विलास में रत, अपने ऐरवर्य की चिन्ता में लीन हुआ तो प्रजा के दुख का ठिकाना नहीं रहता। प्रजा की गाढ़ी कमाई का पैसा राजा तथा उसके मुँ इ-लगे यार-दोस्तों द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है, जनता की उन्नति या विकास की बात दूर रही, उसे खाने पीने के भी यथेष्ट साधन नहीं रहते; राज्य की दशा दिन-प्रति-दिन श्रवनत होती जाती है। इस प्रकार श्रनियंत्रित राजतंत्र में प्रजा की दशा राजा के अञ्छे या बुरे होने पर निर्भर है; वह बहुत उन्नत भी हो सकती है श्रीर बहुत श्रवनत भी। इतिहास में दोनों ही प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। प्रायः अनियंत्रित राजाओं के बुरे होने का अनुभव अधिक हुआ है।

कुछ श्रादमी श्रनियन्त्रित राज्य के अच्छे होने के उदाहरण-स्वरूप

राम-राज्य का उल्लेख किया करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि रामचन्द्र जी बहुत साधु-स्वमाव के, संयमी श्रीर लोकोपकारी थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी श्रीर संतुष्ट थी। उनका श्रादर्श ही प्रजा की सेवा करना था। वे प्रजा के लिए श्रपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहते थे। किन्तु हम राम-राज्य को श्रानियंत्रित राज्य नहीं समक्षते। जैसा कि हमने श्रन्यत्र कहा है, उस समय शासन विधि धर्म-शास्त्र द्वारा निर्धारित थी। श्रच्छे श्रनुभवी, त्यागी श्रीर परोगकारी विद्वान राजा को समय-समय पर उचित निर्देश करते थे। राजा उनके परामर्श का श्रादर करता था, उसका पालन करता था। निदान तत्कालीन राज्य वास्तव में श्रानियंत्रित नहीं था, वह प्रक प्रकार से नियंत्रित था वैध ही था। वैध राजतंत्र का विचार श्रागे किया जाता है।

वैध राजतंत्र—वैध राजतंत्र में, राजा की शिक्त मर्यादित रहती है। वह मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, उस पर मंतियों या व्यवस्थापक सभा आदि का नियंत्रण रहता है। प्राचीन काल में भारतीय प्रजाओं के वैध शासक होने की बात ऊपर कही जा चुकी है। आधुनिक काल के वैध शासक का एक अच्छा उदाहरण इंगलैंड का बादशाह है।

बादशाह होने की हैि स्थित से उसे अपिरिमित अधिकार है। वह यदि चाहे तो पार्लिमेंट की अनुमित बिना ही सेना के हिथयार रखवा सकता है, सरकारी नौकरों को बर्ज़ास्त कर सकता है। इस प्रकार अंगरेज़ी शासन-पद्धित के अनुसार चलता हुआ भी बादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनका देश की आन्तरिक उन्नति तथा

श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बहुत प्रभाव पड़े; परन्तु जैसाकि श्रन्यत्रं कहा गया है, श्राज कल वह कोई भी कार्य, केवल श्रपनी इच्छा के श्रनु-सार नहीं करता। प्रत्येक शासन-कार्य का निश्चय प्रधान मन्त्री करता है, जो श्रन्य मंत्रियों सहित ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी है। शासन-नीति का निश्चय पार्लिमेंट करती है, मंत्री उसे अमल में लाते हैं। हां, सब मुख्य कार्य बादशाह के नाम और हस्ताक्षर से होता है। बादशाह को न्याय सम्बन्धी मामलों में भी हस्तच्चेर करने का श्रिधिकार नहीं, वह केवल विशेष दशाश्रों में श्रिपराधियों को चमा-दान कर सकता है। राज-कोष पर भी बादशाह का कुछ अधिकार नहीं, उसे निर्धारित रक्तम प्रतिवर्ष मिलती है। यदि वह इस रक्तम से कुछ भी श्रिषक चाहे तो पार्लिमेंट की नियमानुशार स्वीकृत लेनी होतो है। बादशाह पार्लिमेंट में जो भाषण देता है, वह प्रधान मंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा लिखा होता है। उसका श्रन्य राज्यों से जो पत्र-व्यवहार होता है, वह भी मंत्रियों से छिया नहीं रहता । यदि वह किसी अन्य राज्य के शासक या प्रवान कर्मचारीसे मिलना चाहे तो जब तक प्रधान मन्त्री इसमें सहमत न हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। यहां तक कि बादशाह अपने विवाह-शादी के मामते में भी सर्वेषा स्वतंत्र नहीं है। कुछ ही समय की बात है, इंगलैंड के बादशाह ने प्रधान मनत्री की इच्छा की श्रवहेलना कर श्रवनी पसंद की महिला से विवाह किया, तो एंसी परिस्थित पैदा हो गयी कि बादशाह ने राजगही छोड़ देना ही उचित समभा। इससे स्पष्ट है कि वैध राजतंत्र में राजा की शक्ति कितनी परिमित होती है। यदि राजा बहुत अच्छा हो तो वह एक

सीमा तक ही शासन-नीति को प्रभावित कर सकता है, स्रौर यदि वह बहुत बुरा हो तो शासन-कार्य जनता के लिए विशेष हानिकर नहीं होने पाता।

पुरतेनी या पेतिक राजा—राजतंत्र में (वह अवैध हो या वैध), राजा दो प्रकार का होता है:—(१) पुरतेनी, जो वंश-परम्परा के आधार पर राजा बनता है, या (२) निर्वाचित । पुरतेनी राजा में कोई विशेष गुण या योग्यता होने की आवश्यकता नहीं। उसके राजा बनने के लिए, यही पर्यात होनो के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर बैंडता है। यदि सबसे बड़ा पुत्र जीवित न हो तो उस पुत्र के सबसे बड़े पुत्र को (और पुत्र न होने की दशा में पुत्री को) राजगही पाने का अधिकार होता है। यदि बादशाह के बड़े पुत्र की कोई संतान न हो तो बादशाह का दूसरा पुत्र, या उसके भो जीवित न होने पर उसकी संतान अधिकारी होती है। यदि बादशाह का कोई पुत्र अथवा किसी पुत्र की संतान जीवित न हो तो बादशाह का कोई मा जीवित न होने पर उसकी संतान अधिकारी होती है। यदि बादशाह का कोई पुत्र अथवा किसी पुत्र की संतान जीवित न हो तो बादशाह की सबसे बड़ी लड़की या उसकी संतान अधिकारी होती है।

निर्वाचित राजा — आजकल प्रायः राजतंत्र में राजा पुश्तैनी ही होता है, परन्तु वह निर्वाचित भी हो सकता है। प्राचीन भारतवर्ष में अनेक राजा लोगों द्वारा चुने गये थे। यहाँ के वैदिंक तथा बौद्ध साहित्य में राजाओं के निर्वाचन के विषय में बहुत-कुळ लिखा मिलता है। अन्य देशों में भी राजाओं का निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन में राजा की व्यक्तिगत योग्यता की आरेर ध्यान दिया जाता है, देश-काल

के अनुसार भिन्न भिन्न गुणों का महत्व अधिक माना जाता है। तथापि प्रायः यह अवश्य देखा जाता है कि राजा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाय जिसका अधिक से-अधिक जनता पर नियंत्रण हो सके, जो सब पर प्रभाव डाल सके। प्राचीन काल में राजा होनेवाले व्यक्ति में विशेषतया सैनिक गुणों को आवश्यकता बहुत समभी जाती थी। अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जनता एक वीर योद्धा का नेतृत्व अधिक मानती थी। अतः अनेक राजा ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जो सुयोग्य सेनापित थे। समरण रहे कि जब राजा एक बार निर्वाचित हो जाता है तो साधारणत्या उसे हटाने का प्रसंग बहुत कम आता है। उसके हाथ में सत्ता होती है, अनेक आदमी उसके समर्थक होते हैं। जब तक कि उसके व्यवहार में विशेष असंतोष और लोम पैदा करनेवाली बात न हो, वह अपने पद पर आकृत रहता है, जनता उसके विरुद्ध खड़ी नहीं होती। इस प्रकार प्रायः जब प्रजा ने उसे एक बार चुन लिया तो वह जन्म भर के लिए ही चुना गया समभा जाता है।

राजतंत्र के गुण-दोष — संसार में राजतंत्र बहुत पुराना है। अनेक राजाओं का प्रजा से पुत्रवद् व्यवहार रहा है, उन्होंने जनता का खूब हित-साधन किया है। इसमें एक लाम यह है कि शासन-शक्ति एक जगह केन्द्रित रहती है, कुलोन-तन्त्र या प्रजातन्त्र की मांति बिखरी हुई नहीं होती। जहां जनता में यथेष्ट राजनैतिक जाग्रति नहीं है, प्रजा में शिक्षा की कमी है, सम्यता का विकास नहीं हुआ है, वहां राजतन्त्र बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। राजाओं ने अपने पैत्रिक या वंशागत गुणों तथा अनुभवों से जनता का बड़ा कल्याण किया है।

र्यह बात अब्छे राजतन्त्रों को लक्ष्य में रख कर कही गयी है, जिन्हें सुयोग्य श्रीर सेवा-भाव-युक्त राजा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। परन्तु सदैव क्या, साधारणतया भी ऐसा नहीं होता। राजतन्त्र बहुत बुरा भी हो सकता है, श्रीर श्रनेक बार हुआ है। राजतन्त्र से हमारा श्रभिप्राय यहाँ श्रवैध राजतन्त्र से है। बात यह है कि श्रमियंत्रित राजतन्त्र में राजा के व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजा अञ्चा हुआ तो शासन बहुत अञ्झा होता है श्रीर वह बुरा हुआ तो शासन बिगड़ने में शंका नहीं होती। इस पद्धति में राजा के हाथ में अपरि-मित शक्ति तथा धन-वल रहता है। इससे उसकी प्रवृत्ति अपने सुख-भोग की त्रोर बढ़नी स्वाभाविक है; किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से उसके, अपने स्वार्थ के लिए जनता के हित को बलिदान करने की सम्भावना बहुत होती है। लाखों आदिमियों पर हकूमत करनेवालों में ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं जो संयमशील श्रीर कष्ट-सहिष्ण बने रहें। अनियन्त्रित राजाओं का जीवन प्रायः ऐश्वर्य-भोगी, विलासी श्राराम-तलब, स्वेच्छाचारी श्रीर श्रत्याचारी हो जाता है। पुनः यदि श्रनियन्त्रित राज्य में राजा श्रन्छा भी हुआ, और उसके कारण से शासन-कार्य लोक-हित की दृष्टि से ही संचालित हुआ, तो भी इसमें यह दोष रह जाता है कि जिन लोगों पर शासन होता है, उनका श्रपने शासन में कोई भाग नहीं होता । फलतः न उनमें राजनैतिक जायति होती है और न वे शासन-सम्बन्धी कार्य करने की थोग्यता या समता शास कर सकते हैं। शासन-कार्य में योग देने से ही जनता में अपने उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है. श्रीर इससे उसके विकास में

सहायता मिलती है। श्रानियन्त्रित राज्य में यह बात नहीं; होती यह तो वैध राजतन्त्र (श्रथवा प्रजातन्त्र में) ही हो सकती है। वैध राज-तन्त्र में, जनता शासन-कार्य में भाग लेती है और श्रपनी जिम्मेवरी सम-कार्ती है। इस प्रकार उसमें राजनैतिक भावना का उदय होता है श्रीर उसका विकास होता है। राजा भी भोग-विलास में जीवन व्यतीत नहीं करता, वह योग्य श्रीर श्रनुभवी व्यक्तियों के सम्पर्क में श्राता श्रीर उनके बहुत-कुछ नियन्त्रण में रहता है। इससे वह श्रानियन्त्रित राजा की तरह पतित होने से बचा रहता है।

अब पुरतेनी और निर्वाचित राजतन्त्र के विषय में विचार करें।
आयः पुत्र में एक सीमा तक पिता के गुण आते हैं। पुत्र को तिता
के अनुभवों का लाभ भी सहज ही मिल जाता है। साधारणतया
आदमी यह आशा और अनुमान करते हैं कि अच्छे खानदान का
लड़का सद्गुण्-सम्पन्न होगा। परन्तु यह आशा सदैव ही पूरी नहीं
होती। कितने ही सज्जनों के पुत्र दुर्जन और गुणवानों के पुत्र अयोग्य
हुए हैं। इतिहास में इसका स्पष्ट उल्लेख होते हुए, किसी व्यक्ति
को, उसके गुण कर्म का विचार किये बिना केवल उसके वंश के
विचार से ही, राजा के उत्तरदायी पद पर बैठाना बहुत अनुचित है।
बहुधा जो व्यक्ति अपने वंश के कारण ही राजा, और विशेषतया
अनियंत्रित राजा, बन जाते हैं, वे बहुत शोक्रोन, आराम-तजब और
विलासी होते हैं। उन्हें शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने का
अभ्यास नहीं होता, उनकी शक्ति या गुणों का विकास नहीं होता,
फिर उनके संगी-साथी भी उन्हें विगाड़नेवाले ही मिलते हैं। फलतः

वे प्रजा को केवल अपने सुख या स्वार्थ का साधन मानते हैं, उसे दास या गुलाम समभते हैं, उसे यथा-सम्भव कम अधिकार देते हैं। ऐसे राज्य में साधारणतया राजा और प्रजा दोनों का पतन होता है। निर्वाचित राजाओं की बात दूसरी है। जहां राजा के निर्वाचन की प्रथा होती है वहां व्यक्तियों में अपने गुण या योग्यता बढ़ाने की भावना होती है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, उनमें प्रतियोगिता होती है कि योग्यता-वृद्धि में कौन आगे बढ़े। हमने ऊपर कहा है कि बंगागत राजतंत्र में कभी-कभी अब्छे सुयोग्य राजा का होना असंभव नहीं, पर उनकी संख्या अपेचाकृत कम रहती है, वे अपवाद-स्वरूप ही रहते हैं। नियम की बात करते हुए अपवाद को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

उच्च-जन-तन्त्र

उच्च जन-तन्त्र में प्रमुख शासनाधिकार न तो एक ही व्यक्ति को होता है, और न समस्त जनता को ही। यह एक तंत्र और प्रजा तंत्र के बीच का है। इसमें राज-सत्ता कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ में रहती है। ये व्यक्ति (१) उँचे घरानों के, (२) धनवान या (३) पंडित और पुरोहित, इन तीन वर्गों में से किसी एक के हो सकते हैं।

उच-जन-तंत्र के समर्थकों का कथन है कि इसमें शासन-सूत्र उन व्यक्तियों के हाथ में होता है, जो इसके योग्य होते हैं, जिनमें राज-कार्य के संचालन के लिए आवश्यक गुण होते हैं। इस प्रकार इसमें संख्या की अपेद्धा गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि इस सिद्धांत की रक्षा होती रहे, अर्थात् शासन-सूत्र संभालनेवाले व्यक्ति ऐसे ही रहें जिनमें इस कार्य का अनुभव, दक्षता और योग्यता हो, ते नि:सन्देह कार्य बहुत उत्तम हो। उच जनतंत्र सेाच विचार कर आगे बढ़ता है, एकदम क्रांति करने के पक्ष में नहीं होता, यथा-सम्भव प्राचीन प्रणाली को बनाये रखने का प्रयत्न करता है, इसमें बहुत-से व्यक्ति अनुभवी और गम्भीर होते हैं। देश-काल का विचार करते हैं। इसमें, उन लेगों का प्रावल्य नहीं होता, जो अयोग्य होते हुए भी शासन जैसे उत्तरदायी कार्य में योग देने लगते हैं, जैसांक प्रजातंत्र में प्रायः होता है।

परन्तु यह केवल श्रादर्श की बात ठहरी। व्यवहार की बात लीजिए। शासन-कार्य के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों का चुनाव कैसे किया जाय, चुनाव का श्राधार क्या हो ? जन्म या वंश के श्राधार मानें तो यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह श्रावश्यक नहीं है कि योग्य पिता की सन्तान येग्य ही हो, फिर इस बात की तो संभावना श्रीर भी कम है कि श्रव्छे ख़ानदान के व्यक्ति श्रवश्य ही शासन-कार्य में दक्ष होंगे। घन को भी उत्तम व्यक्तियों के चुनाव का श्राधार नहीं माना जा सकता। घनवानों की संतान को शिक्षा-दीक्षा के साधन श्रपेक्षाकृत सुलम श्रवश्य होते हैं, परन्तु वे प्रायः श्रालसी या श्राराम-तलब होते हैं। उन्हें जीवन-संग्राम की कठिनाइयों का श्रनुभव नहीं होता, श्रतः वे सर्व-साधारण के लिए हितकर नियमों का निर्माण करने में श्रसमर्थ रहते हैं। निदान, जैसांक एक राजनीतिश ने कहा है, 'उच्च-जन-तंत्र, जिसका पाया धन श्रीर जन्म पर है, केवल शरारत

भरा हुआ ही नहीं है, वरन् भयंकर भी है। ' उच्च-जन-तंत्र में जाग्रित या विकास का अवसर थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है, सर्व साधारणः जनता को नहीं।

प्रजातन्त्र

उत्तम राज्य वही है, जिसमें जनता को जाग्रति या विकास का अवसर अधिक से-अधिक मिले। इसकी सब से अधिक सम्भावना प्रजा-तंत्र में होती है। प्रजातंत्र में शासन सूत्र का संचालन कोई व्यक्ति विशेष (राजा, बादशाह), या कुछ (कुलीन, धनी या पंडित) व्यक्तियों का समूह नहीं करता, वरन जनता करती है। अब यहाँ प्रशन यह उठता है कि जनता किसे कहते हैं; अथवा, जनता में किन-किन व्यक्तियों का समावेश किया जाता है।

पागल तथा कोढ़ी व्यक्ति जनता के विकृत अंग माने जाते हैं, और नाबालिंग अपरिपक्व अवस्था के। अतः इन्हें शासन-सम्बन्धी विषयों में, मत देने योग्य नहीं समभा जाता। प्राचीन काल में स्त्रियों को भी इस कार्य से पृथक रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन यूनान और रोम आदि में दास-प्रथा बड़े जोर पर थी, कुल आबादी में उनकी ख़ासी संख्या होती थी। वे भी शासन सम्बन्धी बातों में भाग लेने से वंचित रखे जाते थे। इन सब को निकाल देने पर जो व्यक्ति शेष रहते थे, वे ही प्राचीन यूनान आदि में, राजनैतिक विषयों का विचार करने में भाग लेते थे। तथापि इसे उस समय जनतंत्र या प्रजा-तंत्र कहा जाता था।

यह तो उस समय की बात हुई, जब राज्य छोटे-छोटे होते थे, नगर-राज्यों का युग था, राज्य की सीमा एक नगर तक ही परिमित रहती थी। पीछे राज्य बड़े होने लगे। तब सब जनता का उसमें भाग लेना सम्भव न रहा। क्रमशः प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार हुआ। यह विचार किया गया कि नियम-निर्माण में जनता नहीं, उस के चुने हुए प्रतिनिधि ही भाग लें; हाँ, प्रतिनिधियों के चुनाव में श्रधि-काँश जनता भाग ले। कालान्तर में दास-प्रथा का हास हुआ, और अन्त में वह उठ भी गयी। इस प्रकार जनताका यह वहिष्कृत अंग अब जनता में समाविष्ट हो गया। इसी प्रकार घीरे-घीरे स्त्रियों पर से भी प्रतिबन्ध उठा। यद्यपि इस समय कई देशों में लोगों के इस विषय सम्बन्धी पुराने संस्कारों के स्मृति-स्वरूप, स्त्रियों को निर्वाचन-श्रधिकार बहुत कम है, अधिकाँश सम्य राज्यों में उन्हें बहुत-कुछ मताधिकार प्राप्त है।

प्रजातंत्र की विशेषता यह है कि जिन लोगों के लिए शासन होता है, उनकी अधिकांश संख्या (पागल, कोढ़ी और नाबालिंग छोड़कर) परोच्च रूप से ही सही, अपने लिए कानून बनाने में कुछ भाग लेते हैं; वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कानून बनाते हैं; और सरकार का संगठन करनेवाले होते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र में शासन-सम्बन्धी अन्तिम अधिकार जनता को होता है। जनता में अपने उत्तरदायित्व का भाव पैदा होता है, उसमें राजनैतिक जायित होती है, उसका विकास होता है, उसमें शासन-कार्य की क्षमता होती

है। प्रजातंत्र में आदर्श यह रहता है कि अधिक-से-अधिक जनता की उन्नित हो, किसी समूह-विशेष की नहीं। इसमें जन्म या वंश के आधार पर ही किसी व्यक्ति को विशेष गुण-सम्पन्न नहीं समभा जाता। इसमें राजतंत्र या उच-जन-तंत्र की अपेक्षा अधिक जनता के हित, तथा उसकी जाएति या विकास का लक्ष्य रहता है। अतः इसे उनकी अपेक्षा उत्तम माना जाता है।

इसका यह आश्रय नहीं कि प्रजातंत्र निर्दोष है। प्रजातंत्र जनता का शासन है, इसमें गुणों का ध्यान न रख कर संख्या को महत्व दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि सब मनुष्यों में शासन करने की क्षमता है, अर्रीर यह चमता सब में समान रूप से है। ऐसा समभा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने हिताहित को समभने की शक्ति है, श्रीर वह अपना कार्य विचार श्रीर विवेक-पूर्वक करता है। परन्तु यह बात कहाँ तक ठीक है, इसका हम आये दिन, निर्वाचन श्रादि के श्रवसर पर, श्रनुभव करते हैं। मतदाता श्रनेक बार यह जानते हुए भी कि अमुक व्यक्ति अञ्छा प्रतिनिधि सिद्ध न होगा, भय या प्रलोभन अप्रादि के कारण उसके लिए अपना मत दे देते हैं, श्रीर पीछे श्रयोग्य प्रतिनिधियों के चुने जाने तथा श्रहितकर कानून बनाये जाने की शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि प्रजातंत्र के विफल होने की घोषणा की जाती है। वास्तव में प्रजातन्त्र उसी दशा में सफल हो सकता है, जब मनुष्यों में पर्याप्त बुद्धि, योग्यता, श्रीर श्रपने उत्तरदायित्व की भावना हो। जहाँ इस शर्त के पूरी होने में जितनी न्यूनता रहती है, वहाँ उतने

ही श्रंश में प्रजा-तन्त्र का श्रसफल रहना स्वाभाविक है। तथापि इस में यह विशेषता बड़े महत्व की है कि इसका श्रादर्श मानव समाज से जन्म या वंश श्रादि की श्रसमानताश्रों को दूर कर सब के लिए समान रूप से उन्नति या विकास का श्रवसर उपस्थित करना है।

निदान, राज्यों के विविध मेदों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य शासन-पद्धतियों की अपेद्धा प्रजातन्त्र में राज्य का उद्देश सफल होने की सम्भावना अधिक है। हां, प्रजातन्त्र में भी कुछ न्यूनता या त्रुटियां होती हैं, इन्हें दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्न होते रहने की आवश्यकता है।



चोदहवाँ परिच्छेद

शासन-पद्धति

~~~~~

दिन्द खते परिच्छेद में हमने राज्य के मेदों का विचार किया था,
उसमें वर्गीकरण का आधार विशेषतया यह रखा था कि प्रमुख-शिक्त
एक व्यक्ति में है, कुछ में है, अथवा अधिकाँश जनता में है। राज्यों के
मेद सरकार के संगठन अर्थात् शासन-पद्धति के स्वरूप के आधार पर
भी किये जाते हैं। इस परिच्छेद में हम शासन-पद्धतियों के कुछ मुख्यमुख्य मेदों का विचार करेंगे। कोई राज्य किसी भी तरह का हो, उस
की एक कार्य-प्रणाली होती है, उसके शासन, व्यवस्था और न्यायसम्बन्धी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार उसके विविध
अधिकारियों का संगठन होता है, और शासकों तथा शासितों के
पारस्परिक सम्बन्ध, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इन
नियमों के संग्रह को शासन-पद्धति या विधान कहते हैं। वास्तव में निरंकुश राज्यों में विधान नहीं होता, वहाँ तो राजा स्वेच्छाचारी होता है,

उस पर क़ानून का प्रतिबन्ध नहीं होता। विधान का उद्देश्य यह होता है कि राजा के स्वेच्छाचार को हटाकर, उसकी जगह क़ानून का शासन स्थापित करे।

शासन-पद्धतियों का वर्गोंकरण करने की कोई एक निर्घारित विधि नहीं है। भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोणों से उनके अनेक वर्गोंकरण हो सकते हैं। शासन-पद्धति का, एक वर्गोंकरण के अनुसार किया दुआ मेद, दूसरे वर्गोंकरण के अनुसार किये हुए मेद से सर्वथा मिन्न नहीं होता, कोई-कोई शासन-पद्धति तो कई-कई वर्गोंकरणों में आ जाती है।

शासन-पद्धतियों का एक वर्गीकरण इस दृष्टि से किया जाता है कि राज्य के भिन्न-भिन्न भागों की सरकारों का सम्पूर्ण राज्य की केन्द्रीय सरकार से क्या सम्बन्ध है। यहाँ पहले इस का ही विचार करते हैं।

संगात्मक और एकात्मक शासन-पद्धति—जब कुछ निकटवर्ती राज्यों को किसी अन्य राज्य के आक्रमण का भय होता है, अथवा, वे समस्टि-रूप से अपनी उन्नति करने के अभिलाषी होते हैं, और वे सब मिलकर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार का संगठन करते हैं जो उनकी आत्म-रक्षा अथवा आर्थिक या राजनैतिक हित के लिए उनकी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि विभागों का प्रवन्य सामूहिक रूप से करती हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना 'संघ' बनाया। संघ-शासन में सम्मिलित राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य-सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आन्तरिक विषयों में स्वाधीन रहती हैं। ऐसी

शासन-पद्धित आस्ट्रेलिया, संयुक्त-राज्य श्रमरीका श्रादि में प्रचलित है। \*
यह ऐसे राज्यों के लिए श्रिषक उपयुक्त होती है, जिनका कुल मिलाकर
विस्तार बहुत हो, श्रीर जहाँ के विविध भागों के निवासियों की श्रावश्यकता, भाषा, रहन-सहन और रीति-रस्म श्रादि में भिन्नता हो। कारण,
इस शासन-पद्धित के श्रनुसार विविध राज्यों को श्रपने श्रान्तिरक शासनप्रवन्ध में स्वतन्त्रता होती है। ये श्रपनी श्राय का कुछ भाग श्रीर श्रपने
कुछ श्रिषकार संध-सरकार को दे देते हैं, जो इन राज्यों के पारस्परिक
भगड़े मिटाने तथा बाहरी श्रापत्ति से रच्चा करने के श्रितिरक्त उनकी
सामूहिक उन्नति की व्यवस्था करती हैं।

विविध संघों में देश-काल के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर होता है, तथापि उनमें कुछ बातें प्रायः मिलती हैं। संघ के समस्त शासन-अधिकार संघ-सरकार तथा संघान्तरित राज्यों की सरकारों में बँटे रहते हैं। प्रत्येक राज्य को अपने-अपने च्लेत्र में शासन-ज्यवस्था और न्याय-सम्बन्धी कुछ अधिकार रहते हैं। विधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता है कि किन विषयों में संघ-सरकार को अधिकार होगा, और किन-किन विषयों में संघान्तरित राज्यों को। बहुधा कुछ विषय ऐसे भी होते हैं, जिनमें संघ-सरकार को, और साथ ही संघान्तरित राज्यों की सरकारों को, अधिकार होता है। इस कार्य-विभाजन के सम्बन्ध में विधान में ब्यौरेवार उल्लेख होने पर भी व्यवहार में कभी-कभी संघ सरकार और संघान्तरित राज्यों की सरकारों में मत-भेद उपस्थित हो जाता है, उसका निपटारा संघ-न्यायालय करता है।

<sup>\*</sup> भारतवर्ष में भी ऐसी ही शासन-पद्धति जारी करने का विचार हो रहा है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ राज्य मिलकर किसी विशेष उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं, वे संघ की पूर्ण श्रवस्था को नहीं पहुँच पाते। उनका संगठन शिथिल रहता है। इसे मित्र संघ या 'कानफैडरेशन' कहते हैं। प्रायः यह श्रवस्था स्थायी नहीं होती, या तो इसमें योग देने वाले राज्य पृथक् पृथक् हो जाते हैं, श्रयवा क्रमशः संघ का ही निर्माण कर लेते हैं।

संघ-शासन-पद्धति के विपरीत जो शासन-प्रणाली होती है, वह एकात्मक कहलाती है। इसमें सब शासन-कार्य केन्द्र से होता है। प्रान्तीय सरकारों या स्थानीय शासन-संस्थाओं को जो अधिकार दिये जाते हैं, वह केवल सुभीते की हिंद से। केन्द्रीय सरकार जब चाहे, उन अधिकारों को वापिस ले सकती है। एकात्मक राज्य में एक केन्द्रीय सरकार, एक केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल, और एक केन्द्रीय न्यायालय की प्रमुख शक्ति होती है। प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाएँ इनके अधीन तथा इनके नियंत्रण में कार्य सम्पादन करती हैं। ऐसी शासन-पद्धति उस राज्य के लिए उपयुक्त होती है, जो छोटा हो, तथा जिसके निवासियों की आवश्यकताएँ, भाषा, रहन-सहन और रीति-रस्म आदि प्रायः समान ही हों, जैसे इंगलैंड आदि।

एकात्मक शासन-पद्धति लिखित भी हो सकती है, श्रीर श्रिलिखत भी; किन्तु संघात्मक शासन-पद्धति तो लिखित ही होती है। शासन पद्धति के लिखित श्रीर श्रिलिखित भेदों के सम्बन्ध में श्रागे लिखा जाता है। लिखित और अलिखित शासन-पद्धित — लिखित शासन-पद्धित वह है जिसमें शासन-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य सब सिद्धान्तों का, एक शासन-पत्र में उल्लेख होता है। समय-समय पर इसमें, पीछे उपयोगी प्रतीत होने वाली बातों — प्रथाओं, रिवाजों, समभौतों या संधियों — आदि का भी समावेश होता रहता है। कुछ लिखित विधान ऐसे भी होते हैं, जिनमें थोड़े-से ही विषयों का उल्लेख होता है, और शेष बातों के विचार के लिए साधारण कानून की सहायता ली जाती है। संयुक्त-राज्य अमरीका तथा फ्रांस आदि में शासन-पद्धित लिखित है।

श्रालित शासन-पद्धति वह होती है जिसमें श्राधकांश बातें प्रथाओं, रिवाजों या समभौतों के श्रनुसार होती है जिनका विकास धीरे-धीरे होता है, जिनके लिए किसी ख़ास समय कोई विशेष क़ानून नहीं बनाया जाता। उदाहरणवत् इंगलैंड की शासन-पद्धति श्रालित है। वहाँ के श्राधकांश शासन-सम्बन्धी नियम रीति-रिवाज़ पर निर्भर हैं, इनके श्रनुसार वहाँ भिन्न-भिन्न समय से कार्य हो रहा है। इंगलैंड के प्रतिनिधि या श्रन्य व्यक्ति किसी ख़ास समय यह निश्चय करके नहीं बैठे कि श्रव से देश का शासन श्रमुक रीति से होगा। मंत्री-मंडल का क्या श्राधकार हो, उसका राजा तथा व्यवस्थापक समा से क्या सम्बन्ध रहे, नागिरकों के श्राधकार क्या, रहें, श्रादि विषय वहां कानून से निर्धारित नहीं है। वहाँ शासन-पद्धति में क्रमशः श्रीर स्वाभाविक वृद्धि हुई हैं। इसीलिए जैसा कि श्रागेब ताया जायगा,

इसमें परिवर्तन मी आसानी से हो सकते हैं।

स्मरण रहे कि कोई शासन-पद्धति न तो पूर्णतः लिखित होती है, श्रीर न पूर्णतः श्रलिखित ही । लिखित शासन-पद्धति में भी कुछ बातें श्रलिखित रहती हैं, इसी प्रकार श्रलिखित शासन-पद्धति श्रंशतः लिखित रहती है। ऊपर कहा गया है कि इंगलैंड की शासन-पद्धति श्रलिखित मानी जाती है, किन्तु यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कानून सुभीते के लिए लिखे भी गये हैं। इन्हें पार्लिमेंट ने समय-समय पर स्वीकार किया था। यथा, मताधिकार-विस्तार का क़ानून, जो सन् १९१८ श्रीर सन् १९२८ में बना था, सरदार सभा श्रीर प्रतिनिधि सभा के पारस्परिक सम्बन्ध का क़ानून जो १९११ में बना।

परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील शासन-पद्धित— शासन-पद्धितयों का एक वर्गीकरण इस विचार से किया जाता है कि उनमें परिवर्तन-संशोधन या सुधार सुगमता-पूर्वक हो सकता है, या बहुत किंदिनाई से। जिस शासन-पद्धित में परिवर्तन आसानी से हो सकता है उसे नमनशील, लचीली या परिवर्तनशील शासन-पद्धित कहते हैं। इसके विपरीत, जिस शासन-पद्धित में परिवर्तन करने के लिए नियमानुसार बहुत-सी कार्रवाई करनी पड़ती है, अथवा परिवर्तन होने में बहुत समय लगता है, उसे कठोर, दुष्परिवर्तनशील या अपरि-वर्तनशील शासन-पद्धित कह सकते हैं। यों तो संसार में कोई वस्तु अपरिवर्तनशील नहीं है, यहाँ केवल दुलनात्मक दृष्टि से हो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।

शासन-पद्धतियों का यह भेद एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। इंगलैंड की शासन-पद्धति में त्रावश्यक फेर-बदल श्रासानी से हो सकता है। उसके लिए बहुत श्रांदोलन नहीं करना पड़ता। शासन-नियमों का मंशोधन करने के लिए विशेष बन्धन नहीं है। मंत्री-मंडल जब जैसा चाहे. संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। इसलिए शासन-पद्धति में एकदम महान् परिवर्तन होना, यहां तक कि उसका रूपान्तर हो जाना भी, श्रसम्भव नहीं है। यह बात श्रवश्य है कि मंत्री-मंडल इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके प्रस्ताव के पक्ष में पार्लिमेंट का बहमत हो: श्रीर पार्लिमेंट भी किसी प्रस्ताव को स्त्रीकार करने में लोकमत का विचार करेगी. श्रीर इंगलैंड का लोकमत प्रगतिशोल न होकर संरचणशील ही है। तथापि जब शासन-पद्धति-सम्बन्धी कोई परिवर्तन करने का एक बार निश्चय हो जाय तो उसमें क़ानूनी प्रतिबन्घ वाघक नहीं होता। रोज़मरी की साधारण कार्रवाई की ही तरह परिवर्तन हो सकता है। सन् १९१८ श्रौर सन् १९२८ ई॰ में मताधिकार-विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताक जिसका शासन-पद्धति पर बहुत प्रभाव पड़ा, साधारण रीति से ही स्वीकार हो गया था । उसके लिए किसी विशेष प्रणाली के अवलम्बन की आ-वश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी वर्ष (१९४०) की बात है, युद्ध के सङ्कट का श्रनुभव होने पर पार्लिमेंट में शासन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना भटपट स्वीकृत हो गया।

श्रव, इसके विपरीत, दुष्परिवर्तनशील शासन-पद्धित की बात लीजिए। इसके बदलने में बहुत-सी किटनाइयों का सामना करना पड़ता है, श्रमाधारण प्रणाली श्रवलम्बन करनी होती है। कहीं तो उसका प्रस्ताव दोनों व्यवस्थापक समाय्रों से निर्धारित बहुमत से स्वीकार कराना होता है, कहीं उसे लोक-मत के लिए उपस्थित किया जाकर, उसके पक्ष में निर्धारित बहुमत संग्रह करना श्रावश्यक होता है। कहीं केवल शासन-विधान के परिवर्तन को लक्ष्य में रखकर ही नया निर्वाचन होता है, श्रथवा विधान-समा का संगठन किया जाता है। संग्रुक-राज्य श्रमरीका श्रादि में दुष्परिवर्त्तनशील शासन-पद्धित ही प्रचलित है। वहीं शासन-विधान-सम्बन्धी संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए कांग्रेस के दो-तिहाई सदस्यों या वहां की विविध रियासतों की व्यवस्थापक समाय्रों के सदस्यों में से तीन-चौथाई सदस्यों की, श्रावश्यकता होती है। वर्तमान योरपीय महायुद्ध को लक्ष्य में रख कर, श्रमरीका का राष्ट्रपति इंगलैंड को सहयोग देने के लिए जैसा प्रस्ताव स्वीकार कराना चाहता था, शासन-विधान की कठिनाइयों के ही कारण न करा सका।

सभात्मक और अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति—व्यवस्थापक मंडल और प्रबन्धकारिणी सभा के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर भी शासन-पद्धति के दो भेद किये जाते हैं:—(१) सभात्मक, मंत्री-मंडल-मूलक या पार्लिमेंटरी, और (१) अध्यद्धात्मक या प्रेसी-डैंशल। सभात्मक शासन-पद्धति के उदाहरण के लिए इंग्लैंड की ज्ञासन-पद्धति अच्छी है। यहाँ जब नया चुनाव होता है तो बादशाह मंत्री-मंडल बनाने का कार्य उस दल के नेता को देता है, जिसका प्रतिनिध-सभा में बहुमत हो। जब वह अपने मंत्री चुन लेता है तो वह

प्रधान मंत्री बनता है, श्रीर मंत्री-मंडल में समापित का पद ग्रहण करता है। मंत्री-मंडल प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, जब उसकी नीति का प्रतिनिधि-सभा के बहुमत द्वारा समर्थन नहीं होता तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है; श्रीर उसकी जगह नये मंत्री-मंडल का पूर्वोक्त विधि से संगठन किया जाता है। त्मरण रहे कि इस पद्धति में मन्त्रियों का उत्तरदायित्व सामृहिक रूप से होता है। कोई, मंत्री श्रकेला पदच्युत नहीं होता। एक मंत्री के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव पास होने पर सब मन्त्री त्याग-पत्र इकट्ठा ही देते हैं। क्योंकि मन्त्री पार्लिमेंट के प्रति, श्रीर उसके द्वारा मतदाताश्रों के प्रति, उत्तरदायी होते हैं, इस पद्धति को उत्तरदायी शासन-पद्धति भी कहते हैं।

इस पद्धित में शासकों (मिन्त्रयों) को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पड़ता है। जब मतदाता या प्रतिनिधि सभा मिन्त्रयों के कार्य से असन्तुष्ट हों, तो वह सरकार (मन्त्री-मंडल) को पलट सकते और नयी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार मतदाताओं या प्रतिनिधि सभा का सरकार पर ख़ूब नियन्त्रण रहता है। युद्ध आदि की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर मन्त्री पार्लिमेंट के सदस्यों में से ही होते हैं। मुख्य-मुख्य मंत्री पार्लिमेंट में बैठते उस पर अपना प्रभाव डालते तथा उसमें प्रकट किये जानेवाले लोकमत से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इस पद्धित में सरकार के इन दोनों अंगों का परस्पर में धिनष्ट सम्बन्ध बना रहता है।

अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति को समभने के लिए संयुक्त-राज्य अम-रीका की शासन-प्रणाली का विचार कीजिए। वहाँ एक व्यक्ति अध्यक्ष या राष्ट्र-पति होता है। वह प्रवन्धकारिया का सभापति होता है, जिसके अदस्य स्वयं उसके द्वारा ही चुने हुए होते हैं। श्रध्यक्ष का चुनाव जनता (निर्वाचकों) द्वारा होता है, श्रीर वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। वह निर्धारित समय तक अपने पद पर रहता है, उससे पूर्व व्यवस्थापक मंडल के श्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव से भी नहीं हटाया जा सकता । यहाँ के व्यवस्थापक मंडल में, जिसे कांग्रेस कहते हैं, दो सभाएँ होती हैं, प्रतिनिध-सभा ( निचली सभा ) और सिनेट (ऊपरली सभा)। व्यवस्थापक मंडल के सदस्य भी जनता (निर्वाचकों) द्वारा चुने जाते श्रीर उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार श्रध्यक्ष तथा कांग्रेस दोनो जनता के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं, परस्पर एक दूसरे के प्रति नहीं। यह शासन-पद्धति सभात्मक पद्धति की अपेक्षा अधिक स्थायी है। इसमें श्रध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मंडल दोनों का कार्य-काल निर्धा-रित है, एक बार चुनाव होने के बाद, निर्घारित श्रवधि तक दोनों श्रपने अपने पद पर रहेंगे। निर्वाचकों या प्रतिनिधियों का कोई दल वह-संख्यक होकर सरकार को पद-च्युत नहीं कर सकता । अध्यक्त की अधी-नता में सरकार इढ रहती है। यदि ऐसा विवाद उपस्थित हो कि सरकार किसी विषय में अपने अधिकार की सीमा से बाहर काम कर रही है, तो उसका श्रंतिम निर्णय राज्य के संध-न्यायालय द्वारा होता है। इस प्रकार सरकार पर एक तरह से न्यायालय का नियंत्रण है, श्रीर, जनता का तो है ही। इस शासन-पद्धति के अनुसार

प्रबंधकारिणी सभा के सदस्य व्यवस्थापक मंडल में नहीं बैठते; शासक श्रीर व्यवस्थापक एक दूसरे से श्रलग रहते हैं, श्रीर ये दोनों, न्यायाधीश-समृह से श्रलग हैं।

एक-सभात्मक श्रौर द्विसभात्मक शासन-पद्धति-शासन-पद्धतियों के भेद एक श्रीर प्रकार से भी किये जाते हैं। जब व्यवस्थापक मंडल में एक ही सभा होती है, तो शासन-पद्धति एक-सभात्मक कहलाती है, श्रीर जब दो सभाएँ होती हैं, तो द्विसभात्मक । दो सभात्रों में से जिसमें जनसाधारण के प्रतिनिधि होते हैं, उसे छोटी सभा, निचली सभा अथवा 'लोश्रर हाउस' कहते हैं। दूसरी सभा, जिसमें धनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं. श्रथवा (संघ-शासन की दशा में) जिसमें भिन्न-भिन्न राज्यों की श्रोर से प्रतिनिधि होते हैं, उसे बड़ी सभा ऊपरली सभा, या 'श्रपर हाउस' कहते हैं। स्मरण रहे कि निचली सभा में सदस्यों की संख्या श्रधिक होती है, श्रीर विशेषतया श्रार्थिक विषयों में इसके अधिकार भी, ऊपरली सभा की अपेक्षा, अधिक होते हैं। दुसरी सभा पहली सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार श्रीर श्रावश्यक होने पर उनमें संशोधन करती है। इस प्रकार वह जिन क़ानूनों को अञ्छा नहीं समभती उनके बनने में देर लगाती है। साधारण कानून दोनों सभाश्रों की स्वीकृति से बनते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव पहले एक सभा में तीन बार उपस्थित किया जाता है, वहाँ उसके पास हो जाने पर फिर उसे दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ भी उस पर तीन बार विचार होता है। यदि ऐसा होने पर वह उसी रूप में पास हो जाता

है, जिस रूप में वह इस समा में आया था, तो दोनों समाओं से पास समका जाता है। यदि यहाँ इसमें कोई संशोधन हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव पहली समा में लौटा दिया जाता है, और वहाँ उस पर पुनः नियमानुसार विचार होता है। यदि दोनों समाओं में मत-मेद बना ही रहता है, समक्षीता नहीं हो सकता तो या तो प्रस्ताव रोक दिया जाता है, या दोनों समाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, और इस अधिवेशन में जो निखय होता है, उसे दोनों समाओं का निखंय मान लिया जाता है।

साधारणतया आर्थिक विषयों को छोड़कर, दोनों समाओं की शिक्त समान होती है। परन्तु निचली सभा में सर्वधारण के प्रतिनिधि होने से, अर्थात् मताधिकार अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को होने से, वही जनता का मत स्चित करने वाली मानी जाती है। ऊपरली सभा का महत्व बहुत कम रह गया है। उदाहरणवत् इंगलैंड में सरदार सभा (धन-सम्बन्धी प्रस्तावों को छोड़कर) सार्वजनिक क़ानून के प्रस्तावों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक क़ानून बनने से रोक सकती है। उसके पश्चात्, उसके विरोध करने पर भी, प्रतिनिधि-सभा द्वारा तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, प्रस्ताव क़ानून का रूप धारण कर लेता है। धन-सम्बन्धी (आय का हो, चाहे व्यय का), क़ानून का प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा में उपस्थित किया जाता है, और उनकी स्वीकृति होने पर वह अन्य सार्वजनिक क़ानूनों प्रस्तावों के समान सरदार सभा में भेजा जाता है। इस सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी वह बाद-शाह की मंज़ूरी के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-

सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

साधारणतया दूसरी सभा के होने से ये लाभ सममे जाते है:---इससे, कानून बनने में बहुत जल्दबाज़ी नहीं होती। काम धीरे-धीरे होता है। धनी-मानी आदि ऐसे स्वार्थ और हितों वाले व्यक्तियों का भी क़ानून बनाने में काफ़ी भाग रहता है: जो देश में श्रल्प-संख्यक होते हैं। यदि एक ही सभा हो तो-इस भेगी के अधिकारों का सहज ही अपहरण हो सकता है। दसरी सभा से उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है, उनका दृष्टि-कोस् विचारार्थ उपस्थित होता है। इस सभा में कुछ सदस्य सरकार द्वारा नामज़द रहते हैं। स्वाधीन देशों में सरकार का उद्देश्य यह नहीं होता. कि जनता के हितों के विरोधी, और अपने पक्ष के आदिमियों को ही नामजुद करे। वहाँ सरकार सदस्यों को नामजुद करने के अवसर का उपयोग इसलिए करती है कि सभा में कुछ विशेष अनुभवी और विचारवान व्यक्ति पहुँच जायँ। पुनः दूसरी सभा से एक लाभ यह भी है कि प्रबन्धकारिगी सभा व्यवस्थापक सभाश्रों से पृथक श्रौर स्वतंत्रः रहतीहै। यदि एक ही व्यवस्थानक सभा हो तो वह प्रबन्धकारिणी परः अपना बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है; यहाँ तक कि प्रवन्धकारिग्री: के उसके श्रधीन ही हो जाने की सम्भावना रहती है।

अब इस सभा से होनेवाली हानि की बात लीजिए। पहले कहा गया है कि दूसरी सभा जल्दबाज़ी को रोकती है। परन्तु जब जनता बहुत प्रगतिशील होती है, आदमी क्रान्तिकासी सुधार चाहते हैं, तो दूसरी सभा की कार्यवाई बड़ी वाधक हो जाती है। काम में इतनी देख

लगने की सम्भावना रहती है कि जनता का जोश ही ढंडा हो जाय।
ऐसी अवस्था में दूसरी सभा का होना राज्य के लिए अहितकर होता,
है ? फिर धनवान और पूँजीपित तथा महन्त या ज़मीदार आदि प्रायःसंरक्षणशील और पुराने विचारों के होने के अतिरिक्त, पराधीन देशों में
सरकार के समर्थक, उसकी हाँ में हाँ मिलानेवाले होते हैं। इससे देश
की स्वाधीनता-प्राप्ति के मार्ग में चिन्तनीय विष्न बना रहता है। कितने
ही राजनीतिजों का मत है कि व्यवस्थापक मंडल में दूसरी सभा रहने से
दो में से एक बात होती है; दूसरी सभा प्रतिनिधि-सभा से सहमत होती
है, अथवा उसको विरोधी। पहली दशा में यह सभा अनावश्यक
प्रतीत होगी, और दूसरी दशा में केवल वाषक रहेगी। अतः दूसरी
सभा न रहनी चाहिए।

कई राज्यों में दूसरी सभा की समस्या बनी ही हुई है, इसे हटाना तो किंद्रन प्रतीत हो ही रहा है, इसमें यथेष्ट सुधार भी सहज नहीं है। उदाहरखवत् सन् १९११ में इंगलैंड में यह निश्चय किया गया था कि सरदार-सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया करें। परन्तु श्रभी तक इस विषय की ऐसी योजना तैयार नहीं हुई, जो सब दलों को मान्य हो। यदि सदस्यों को निर्वाचित करने का ही निश्चय किया जाय तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसके लिए किन व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाय। जब सरदार-सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी तो वह धन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर श्रिधिकार रखना तथा मंत्रियों का नियंत्रख करना भी चाहेगी। प्रतिनिधि-सभा इसे ये श्रिधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाश्रों के कार्य में बड़ी उलभत पैदा होगी। इन किनाइयों के कारण सरदार-सभा के संगठन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव कार्य में परिण्यत नहीं हो पाता। यह इंगलैंड की बात है। श्रन्य राज्यों में भी, जहाँ द्विसभात्मक शासन-पद्धति है, ऐसी द्वी समस्या है।

भिन्न-भिन्न शासन पद्धतियों को तुलाना—शासनपद्धतियों के मुख्य-मुख्य वर्गीकरणों का विचार हो चुका। प्रायः किसी
वर्गीकरण के सम्बन्ध में निरपेक्ष रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि
उसका अमुक भेद दूसरे भेद से अवश्य ही अच्छा होगा। उदाहरणवर्त यह निश्चय करना किंदन है कि लिखित और अलिखित, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, या अध्यक्षात्मक और समात्मक
शासन-पद्धतियों में से कौनसी दूसरे से अधिक उपयोगी है। बात यह
है किसी शासन-पद्धति का अच्छा या जुरा अथवा अधिक या
कम लाभदायक होना देश-काल पर निर्भर है। किसी देश के लिए
हस समय एक शासन-पद्धति उपयुक्त है तो यह सर्वथा सम्भव है कि
कालान्तर भें परिस्थिति बदल जाने पर उसकी उपयोगिता घट-बढ़
जाय, या न ही रहे।

श्रस्तु, श्राज-कल साधारण तौर से यह समका जाता है कि इस समय छोटे-छोटे राज्यों का श्रास्तित्व संकट में है, वे पृथक् पृथक् रूप से न तो श्रपनी रहा ही कर सकते हैं, श्रीर न वे यथेष्ट उन्नित करने में ही सफल हो सकते हैं। श्रतः जिन राज्यों का एक संघ बन सकता है, उन्हें मिलकर संघ निर्माण करना चाहिए; श्रीर साथ ही संघ की केन्द्रीय सर्द्वार को यथेष्ट श्रिधकार देकर उसे यथा-सम्भव बलवान बताना चाहिए। बड़े राज्य भी अपने भिन्न-भिन्न भागों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना कर इसी प्रकार संघ-शासन-पद्धित का अवलम्बन करें तो अच्छा है। इससे एक तो प्रान्तों को अपनी उन्नित और विकास का अवसर मिलेगा, दूसरे वे एक-दूसरे की सहानुभूति और सहयोग से लाभ उठावेंगे। भारतवर्ष की भावी शासन-पद्धित की ब्यौरेवार बातों में, राजनीतिजों का चाहे जो मतभेद हो, यह सर्वमान्य हैं कि शासन संघातमक होना चाहिए।

शासन-पद्धति एक सभारमक हो या द्विस्मारमक १ संघारमक शासन-पद्धति में तो व्यवस्थापक मंडल में प्रायः दो सभाश्रों का होना श्रावस्थक समफा जाता है, एक में संघ की जन-संख्या के श्रनुपात से जनता के प्रतिनिधि होते हैं, श्रीर दूसरी सभा में संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि समान संख्या में रहते हैं। एकारमक राज्य श्रथवा संघ के किसी एक भाग में दो सभाश्रों का होना कुछ ठीक नहीं है। बहुधा दूसरी सभा के सदस्य बहुत धनी-मानी ज़मीदार या पूँजी-पति श्रथवा उच्च समफे जानेवाले घरानों के होते है। इनके स्वार्थ सर्वसाधारण के स्वार्थों से भिन्न होते हैं, ये पुराने संरज्ञणशील विचारों के होने से प्रगति-विरोधी प्रमाणित होते हैं। इस सभा के कारण श्रनेक बार लोकहितकर क़ानून बनने या संशोधन स्वीकृत होने में श्रनावश्यक विलम्ब लग जाता है।

<sup>\*ि</sup>कसी संवातमक राज्य की बल-वृद्धि का उद्देश्य दूसरे राज्यों पर श्रत्याचार करना न होना चाहिए। चाहिए यह कि ने संसार यह विविध राज्य श्रपने श्राप को एक विशाल परिवार का सदस्य मानते हुए परस्पर में मैत्री-भाव से रहें।

र्मिक्सी राज्य की शासन-पद्धित का निश्चय करने के लिए श्रावश्यक है कि वहाँ के राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न शासन-पद्धितयों की साधारण समीचा करने के साथ श्रपने राज्य की परिस्थित तथा श्रनुभवों पर भली भौति विचार करें श्रीर तदुपरान्त जो पद्धित उचित जचे, उसका श्रायोजन करें। इसके श्रितिक यह भी श्रावश्यक है कि किसी शासन-पद्धित के श्रन्ध-भक्त न होकर, जब-जब उसमें (गम्भीर विचार के बाद) जैसा परिवर्तन या संशोधन करना उचित प्रतीत हो, उसके करने के लिए तैयार रहें IJ



# पंद्रहवाँ परिच्छेद राज्य का कार्य-चेत्र

- CONTENT

स्वाम राज्यों तथा शासन-पद्धतियों के मेदों का विचार कर चुके ।
स्व इमें देखना यह है कि राज्य का कार्य-चेत्र क्या हो और यह कि इस
विषय में राजनीतिशों के क्या विचार हैं ! उन्होंने क्या सिद्धान्त स्थिर
किये हैं ! इस सम्बन्ध में विचार करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए
कि राज्य का निर्माण इसलिए किया जाता है कि समाज में रहनेवाले
व्यक्तियों को श्रिषक-से-श्रिषक स्वतंत्रता मिले, किसी की स्वतंत्रता में
कोई दूसरा हस्तचेप न करें, राज्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा
करें। इसलिए राज्य के कार्य-चेत्र सम्बन्धी जो भी सिद्धान्त निश्चित किये
जायँ, उनमें वाह्य क्य से, उनको कार्य में परिणत करने की विधि में
चाहे जितना श्रन्तर हो, पर उन सबके उद्देश्य में तो समानता ही रहेगी।
प्रत्येक सिद्धान्त के प्रतिपादक श्रपने-श्रपने दक्त से नागरिकों की स्वतंत्रता-प्रित का लक्ष्य रखेंगे। श्रन्तर केवल मार्ग का होगा; पहुँचना
सब को एक ही स्थान पर है।

## व्यक्तिवाद

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त मुख्य हैं, व्यक्तिवाद श्रीर समाजवाद। पहले व्यक्तिवाद को लेते हैं। श्रव से एक पीढ़ी पहले तक इसी का बोलवाला था। प्रत्येक सम्य सरकार इसी को श्रपनाये हुए थी। विद्धान लोग इसी का समर्थन करते थे। इस मत के श्रनुसार, राज्य एक बुराई है;यद्यि समाज की वर्तमान दशा में वह श्रनिवार्य है, उसके विना काम नहीं चल सकता। श्रतः राज्यका कार्य-चेत्र कम-से-कम रहना चाहिए। राज्य उन्हीं कार्यों का सम्पादन करे, जिनसे व्यक्तियों के जान-माल की रक्षा हो, वे धोखे श्रादि से बचें, उनके नागरिक जीवन के मार्ग की वाधाएँ दूर हो, श्रीर उन्हें श्रावश्यक सहायता मिले। राज्य को कोई श्रधिकार व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का नहीं है। व्यक्तियों को श्रपना-श्रपना कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक करने देना चाहिए। हाँ, जब उनमें परस्पर विवाद या भगड़ा हो तो राज्य को उसका निपटारा चाहिए करना।

व्यक्तिवादियों का मत है कि राज्य का कार्य केवल शासन करना है, जिसका चेत्र आन्तरिक शान्ति और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, होना चाहिए। राज्य एक राजनैतिक संस्था है, उसे उन अनेक कार्यों से कुछ प्रयोजन नहीं, जो जनता की मलाई के लिए आवश्यक हैं, यथा—शिचा, स्वास्थ्य, आजीविका, नागरिकों की बीमारी, बद्धावस्था या बेकारी में उनका जीवन-विवाह, अनाथों और दरिद्रों का भरण-पोषण, जनता की नैतिक या संस्कृतिक उन्नति आदि।

नागरिकों के बहुत-से कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से श्रार्थिक होते हैं। हम अपनी (भौतिक) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग करते हैं, इसमें हम दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेते हैं. भांति-भांति की वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं बना सकते, उन्हें दूसरों से लेते हैं, श्रीर बदले में उन्हें उनकी श्रावश्यकता की वस्तु देते हैं, श्रथवा उन्हें उन वस्तुश्रों की क़ीमत देते हैं। इस प्रकार पदार्थों की उत्पत्ति, विनिमय श्रीर व्यापार श्रादि होता है। व्यक्ति-वादियों का मत है कि इन श्रार्थिक कार्यों में राज्य कोई इस्तचेप न करे । उनकी नीति, "व्यक्ति जैसा चाहें, करें," होती है । उदाहरणवत् एक कारख़ाने में माल बन रहा है तो राज्य को इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि वहाँ मज़दुर कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, रात को भी काम होता है, या केवल दिन में ही, काम करनेवालों की उम्र क्या है, क्या वहाँ बालक और स्त्रियाँ भी काम करती हैं, कारख़ाने का स्थान कहां तक स्वास्थ्य-प्रद है, मज़दूरों को वेतन कितना मिलता है, छुट्टी कितनी श्रीर कब मिलती है, इत्यादि । ये बातें पूँजीपति श्रीर मज़दरों में परस्पर तय करने की हैं, श्रगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो फिर राज्य के बीच में दख़ल देने की क्या ज़रूरत है ?

इसी प्रकार जब माल तैयार हो गया है तो उसकी क़ीमत क्या हो, मुनाफ़ा कहां तक रहे, अथवा कितना माल देश में रखा जाय और कितने का विदेशों में निर्यात हो, विदेशों से कौन-कौन-सा सामान कितने परिमाण में मँगाया जाय इन बातों को ख़रीदने-बेचनेवाले तथा आयात-निर्यात करनेवाले जानें, राज्य को इनसे क्या मतलब ? श्रायात-निर्यात-कर निर्धारित करने में, श्रयवा श्रन्य क़ानूनों से, राज्य न तो किसी पदार्थ के श्रायात या निर्यात को प्रोत्साहन दे, श्रीर न उस पर कोई प्रतिबन्ध ही लगावे।

व्यक्तिवादी यह मानकर चलते हैं कि पूँजीपति श्रौर मज़द्र. केता श्रीर विकेता (ख़रीदनेवाला श्रीर वेचनेवाला ) श्रीर निर्यात करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति श्रपने-श्रपने हित को पूरी तरह समभ्रता श्रीर तदनुसार कार्य करता है। व्यक्तिवादी भूल जाते हैं कि बहुधा जिन दो पक्षों को परस्पर व्यवहार करना होता है, उनमें से एक बुद्धिमान श्रीर सम्पन्न हो सकता है श्रीर दूसरा श्रल्पञ्च तथा श्रसमर्थ । इन दो पक्षों में पारस्परिक समभौता वास्तव में स्वतंत्र समभौता नहीं है। उदाहरणार्थ जब एक श्रादमी बहुत दरिद्र है, वह तथा उसका परिवार भूख से व्याकुल है, उसे एक कारख़ाने का मालिक कहता है कि तुम काम करना चाहो तो करो, तुम्हें दिन भर के काम के पाँच आने मिलेंगे। मज़रूर जानता है कि पाँच आने से जो भोजन मिलेगा, उससे उसका तथा उसके परिवार का दोनों वक्त का गुज़ारा न होगा। पेट भरने का ही काम न होगा, फिर कपड़े की तो बत ही क्या ? परन्तु वह सोचता है कि इस कार्य को करना स्वीकार ही कर लिया जाय, ऐसा न हो कि यह भी हाथ से निकल जाय और पूरा उपनास ही करना पड़े। निदान, वह अपनी इच्छा से कारख़ाने में काम करना स्वीकार करता है। परन्तु तनिक सोचिए, उसकी इच्छा कहाँ तक स्वतन्त्र इच्छा है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों से बताया जा सकता है कि आर्थिक कार्य करने वाले दो पत्नों में एक पत्नों अपनी

परिस्थिति से लाचार होने के कारण अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता। अपने निर्णयमें वह स्वतन्त्र दिखायी देता हुआ भी वास्तव में स्वतन्त्र नहीं होता। व्यक्तिवाद सिद्धान्त इस बात की सर्वथा उपेक्षा कर देता है।

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के कार्यों की सूची का बहुधा छोटा-सा रहना स्पष्ट ही है। इस सूची के कार्यों में मुख्य ये होंगे:— सेना (जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना) रखना, पुलिस रखना, न्यायालयों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य और सफ़ाई आदि के नियम बनाना और यह देखना कि इनको भंग तो नहीं किया जा रहा है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का यह कार्य नहीं है कि वह नागरिकों के हित की दृष्टि से डाक, तार, रेल, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का भी प्रबन्ध करे।

गत शताब्दी के पूर्वांद में इस सिद्धान्त का बड़ा प्रचार था। उस समय भी इसका विरोध हुआ था। पीछे विशेषतया कल-कारज़ानों की वृद्धि ने परिस्थिति में बहुत परिवर्तन कर दिया। व्यक्तियों की स्व-तन्त्रता के आधार पर, सरकारों ने कल-कारख़ानों के संवालन में किसी प्रकार इसत्त्वेप न किया। इससे अमजीवियों की दशा चिन्तनीय हो गयी, काम करने के घंटे बहुत अधिक रहे, स्वास्थ्य के विषयों पर व्यान न दिया गया, अल्पायु बालकों (नाबालिगों) से काम लिया गया, मज़दूरी कम दी गयी। इससे लोगों को स्पष्ट मालूम हुआ कि व्यक्तिवाद का सिद्धान्त कितना दोष-पूर्ण है। सरकार की अ-इस्तच्चेप नीति के विरुद्ध लोकमत प्रवल हो उठा। तब भिन्न-भिन्न राज्यों में ऐसे

नियम बनने लगे, जो उपर्यु क सिद्धान्त के प्रतिकृत थे। उदाहरणवत् इंगलैंड में सन् १८३३, १८४४, १८५० और इसके बाद बने हुए कानूनों से स्त्रियों और बालकों के काम करने के घंटे सीमित किये गये। इस से व्यक्तिबाद सिद्धान्त के दूसरे पहलू का कुछ आभास मिल सकता है।

### समाजवाद

श्रव इम राज्य के कार्य स्वेत्र सम्बन्धी दूसरे सिखान्त का विचार करते हैं। वह है समाजवाद। वह व्यक्तिवाद का विरोधी है। वह राज्य को केवल शासन करनेवाली संस्था न मान कर उसे सांस्कृतिक संस्था समझता है। समाजवाद के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता के अज्ञान और दरिद्रता का भी निवारण करे। समाजवाद नागरिकों को अधिक-से-अधिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता देने के पत्त में है. पर उसका मत है कि यह स्वतन्त्रता उसी दशा में हो सकती है, जब राज्य के हित को घक्का न लगे; क्योंकि राज्य श्रीर नागरिक में कि-भिन्नता नहीं, उनके उद्देश्य में समानता है, दोनों एक दूसरे के सहंयोग पर निर्भर है। समाजवाद के श्रनुसार राज्य को नागरिकों के आर्थिक जीवन पर भी अधिकार होना चाहिए, वह आर्थिक च्रेत्र में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का व्यवहार करके समाज की अधिक-से-अधिक भलाई करने का श्रादर्श रखता है। समाजवादियों का विचार है कि व्यक्तिवादियों की 'श्र-इस्तचेप' या 'जैसा चाहे करो' की नीति समाज के लिए श्रनिष्टकर है।

समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूप- यद्यपि कुछ दार्शनिकों ने समाजवाद की मूल बातें बहुत प्राचीन समय से जनता के सामने रखी हैं, तथापि इस मत का विशेष प्रचार श्राधिनिक काल में ही हुआ है। श्रौद्योगिक क्रान्ति. यंत्रों श्रोर कल कारखानों द्वारा बड़े पैमाने की उत्पत्ति होने से धन-वितरण की असमानता बहुत बढ गयी। एक श्रोर कुछ इने-गिने व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनगये तो दूसरी श्रोर असंख्य जनता मज़दूरों की हो गयी । पूँजीपतियों को ऐशवर्य और भोग विलास से छुटकारा न रहा श्रीर मज़दूरों को श्रपने शरीर को जीवित रखने के लिए रोटी-कपड़ा भी यथेष्ट पिमाण में न मिलने लगा। इससे लोगों का ध्यान समाजवाद की श्रोर श्रिषकाधिक गया। देश काल के अनुसार भिन-भिन्न स्थानों में इसके अनेक रूप हो गये, कोई वहत उग्र, कोई थोड़ा उग्र, कोई नर्म श्रौर कोई विशेष नर्म। कोई किसी बात पर ज़ोर देता है, कोई किसी बात पर । उन सबकी चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । उनमें से विशेष उल्लेखनीय राज्य-समाज-वाद ( स्टेट सोशालिज्म ), समाष्टवाद ( कम्यूनिज्म ), वोलशेविजम, श्रीर वैज्ञानिक समाजवाद हैं।

राज्य-समाजवाद राज्य के कार्य-चेत्र को देश-रक्षा, शान्ति और सुप्रवन्ध तक ही परिमित नहीं रखता, वह जनता की समस्त आवश्यक ताओं को राज्य द्वारा पूरा कराने के पक्ष में है। वह धनोत्पत्ति, व्यवसाय और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण चाहता है, उत्पत्ति के सब साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो; मूमि, खान, और पूँजी सरकार की हो। कोई व्यक्ति ज़मीदार या पूँजीपति न हो। रेल, तार,

डाक. टेलीफोन, नहर, कल-कारख़ाने सब राज्य के रहें। स्कूल, श्रस्पताल श्रादि भी सरकारी ही हो। प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी शक्ति के श्रनुसार कार्य करे, परन्तु वह कोई कार्य श्राने लिए या श्रपने परिवार आदि के लिए न करे। वह जो कुछ करे, सब राज्य के लिए करे। उत्पन्न पदार्थों पर राज्य का स्वामित्व हो । राज्य नागरिकों को उनकी श्रावश्यकता के श्रनुसार पदार्थ दे, वह भोजन-वस्त्र के श्रातिरिक्त शिक्षा. स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था करे। सन्तान के भरण-पोषण के लिए मावा-पिता को चिन्ता करने की श्रावश्यकता नहीं, यह कार्य भी राज्य का है। बेकारी, बीमारी, या बृद्धावस्था के लिए किसी व्यक्ति को कुछ बचाकर रखने की ज़रूरत नहीं, इसका भार भी राज्य प्रहण करेगा। राज्य नागरिकों का श्रधिक-से-श्रधिक हित साधन करे। व्यक्ति अनेक दशाओं में अपना हित नहीं सममते. श्रीर समभते भी हैं तो उसे लक्ष्य में रखकर उचित श्राचरण नहीं करते । उदाहरणार्थं अनेक आदमी खूब शराब पीते हैं, इससे उनके द्रव्य श्रौर स्वास्थ्य दोनों की क्षति होती है, पर वे इसे बन्द नहीं करते। परन्तु जब शराब का उत्पादन राज्य के अधिकार में होगा तो यह दशा न रहेगी; इसमें सहज ही सुधार हो जायगा। अस्तु, राज्य समाजवादी राज्य को अधिक-से-अधिक अधिकार दिये जाने के पत्त में हैं। स्मरण, रहे कि वे सब कार्य शान्तिमय उपायों से ही करना चाहते हैं।

इसके विरुद्ध समष्टिवादी या कम्यूनिष्ट उग्र मतावलम्बी हैं, वे अपना (समाज की भलाई का) कार्य-क्रम शक्ति के बल पर, हिंसात्मक उपायों से भी पूरा करने में संकोच नहीं करते। वे शक्ति का प्रयोग उस समय तक करने के पक्ष में है, जब तक समाज से वर्ग-विभिन्नता मिट न जाय। पूँजीपित और अमजीवी, ज़मीदार और किसान, साहूकार और ऋगी आदि का भेद न रहे। इस मत के अनुसार समस्त वस्तुओं पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, कोई व्यक्ति अपनी निज की वस्तु नहीं रख सकता।

'बोलशेविज्म' समाजवाद का रूसी संस्करण है। यह शब्द रूसी भाषा के उस शब्द के आधार पर बना है, जिसका अर्थ मताधिकार या बहुमत है। रूस में अमजीवियों का शासन है। इसकी स्थापना वहाँ सन् १९१७ ई० से हुई, जब इस देश का शासन-सूत्र लेनिन के हाथ में आया।

श्राधुनिक काल में समाजवाद का मुख्य प्रवर्तक कार्लमार्क्स हुआ है। इस महान् दार्शनिक ने इस विषय का प्रतिपादन ऐसे वैज्ञानिक दक्ष से किया है कि इसकी 'दास केपिटल' नामक पुस्तक समाजवादियों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ हो गयी है, इसने संसार भर के विचारकों का ध्यान अपनी श्रोर श्राकर्षित किया है। श्रव समाजवाद कहने से प्रायः कार्लमार्क्स के ही समाजवाद का श्राशय लिया जाता है। श्रिषकाँश समाजवादी कार्ल-मार्क्स को ही श्रपना गुरू समभते हैं। वे श्रपने मिन्न-भिन्न सिद्धान्तों का मूल श्राधार उसके ही वाक्यों या लेखों को मानते हैं। बात यह है कि कार्ल-कार्क्स के ग्रन्थ के मिन्न-भिन्न भागों के विविध श्रर्थ किये जाते हैं। समाजवाद के इस महान श्राचार्य

के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

्र-हितहास की आर्थिक व्याख्या। समाज में जो विविध परिवर्तन होते हैं, उनका मूल कारण आर्थिक होता है। जितने मत,
सम्प्रदाय, आन्दोलन आदि होते हैं, जितने आविष्कार या अनुसंधान
किये जाते हैं, सबका मुख्य कारण आर्थिक होता है। सब लड़ाईभगड़ों की तह में धन का प्रश्न होता है। प्रत्येक सभ्यता का मूलाधार धन है। लोगों का रहन-सहन, उनके राजनैतिक, सामाजिक आदि
विचार उनकी आर्थिक परिस्थिति से निश्चित या नियन्त्रित
होते हैं। मनुष्य के विकास का हितहास समाज के आर्थिक विकास की
कहानी है।

्र—वर्गवाद । समाज में दो वर्ग हैं, पूँजीपित श्रीर मज़दूर । यंत्रयुग के पूर्व इन वर्गों में विशेष श्रन्तर न था । जब से मशीनों के
द्वारा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होने लगी, इनका श्रन्तर एवं संघर्ष क्रमशः
बढ़ने लगा । श्रार्थिक जगत में तो पूँजीपित सर्वेसर्वा हो ही गये, राजनीति में भी इनकी ही प्रधानता हो गयी, श्रिधकाँश निर्वाचनों के सूत्र
इनके हाथमें होते हैं, ये जिस उम्मेदवार को चाहते हैं, उसे विजयी बना
सकते हैं । मार्क्ष का मत है कि पूँजीपित श्रीर मज़दूरों के संघर्ष का
कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था है । यह संघर्ष तभी समात होगा,
जब व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था हटा दी जायगी । श्रतः समी सम्पत्ति
सरकारी समभी जानी चाहिए । ऐसा होने पर जनता के निर्धनता
तथा श्रार्थिक विषमता से होनेवाले कष्टों का श्रन्त हो जायगा ।

J ३-मूल्य का अम-सिद्धान्त । प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछ

अम लगता है। मशीनों का प्रयोग होने से पहले अम का जो मूल्य लगाया जाता था, वह एक सीमा तक उचित था। पर जब से मशीनों द्वारा वस्तुएँ बनने लगीं, अमजीवियों को तो मूल्य का थोड़ा-सा ही भाग मिलता है, शेष मूल्य बचत के रूप में पूँजीपित के पास रहता है, अर्थात् पूँजीपित वस्तुओं पर बेहद सुनाफ़ा लेता है। आदमी समभते हैं कि वस्तुओं की उत्पत्ति में बुद्धि का भाग विशेष है, अतः वे ग्ररीब मज़दूरों के अम से अनुचित लाभ उठाते हैं। वस्तुओं का मूल्य विशेषतया (शारीरिक) अम के अनुसार लगाया जाय तभी उसका सुधार हो सकता है।

मार्क्स के समाजवाद के ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। इसके आति-रिक्त समाजवाद धर्म अर्थात् मज़हबको एक व्यर्थ का ढोग समक्तता है। उसके अनुसार धर्म, जो भाग्यवाद, संतोषवाद आदि का प्रचार करता है, सामाजिक उन्नति में बाधक हैं। महन्त और पुजारी आदि मुफ्ताक़ोर है।

समाजवाद के गुण-दोष— आधित आर्थिक व्यवस्था ऐसी कि एक श्रोर तो पूँजीपति श्रिषकाधिक धनवान होते जाते हैं, श्रीर उनकी संख्या इनी-गिनी ही रहती हैं, दूसरी श्रोर श्रिषकाँश श्रमजीवियों की दशा बहुत चिन्तनीय होती है, उन्हें खाने-गीने के यथेष्ट साधन नहीं, बीमारी श्रीर बुढापे में उन्हें कोई पूळुनेवाला नहीं, वैसे भी श्रसंख्य च्यक्ति बेकारी से पीड़ित रहते हैं। समाजवाद का दावा है कि वह इन बुराइयों को दूर

करेगा। वह लोगों की आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। व्यक्ति अपने लाभ के लिये कुछ न करेंगे, इससे पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता का अन्त होगा, उसका स्थान सहकारिता ग्रहण करेगी। मनुष्य समाज-हित के कार्य करने पर वास्तव में सामाजिक बनेगा, और अपने अन्दर सामाजिक जीवन के उपयोगी गुणों की बृद्धि करेगा। इस प्रकार समाजवाद मनुष्य को नरक-यातना से मुक्ति दिलाकर स्वर्गीय सुख प्रदान करेगा।

निस्सन्देह इस समय पीड़ित मानव समाज ऋपने कष्टों को दूर करने के लिए समाजवाद का संदेश बड़ी आशा और उत्सुकता से सुन रहा है। भला, रोगी उस वैद्य का स्वागत क्यों न करेगा, जो उसकी बीमारी दूर कर, उसे आरोग्यता प्रदान करने का निश्चित आश्वासन दिला रहा है। तथापि हमें यह जान लेना चाहिए कि समाजवाद के विपक्ष में क्या कहा जाता है। इस सिद्धान्त के आलो-चकों का कथन है कि यह अधिकाँश में अव्यवहारिक है; मूमि, कारख़ाने श्रीर उद्योग-धंधें पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से व्यक्तियों को श्रपने परिश्रम, बुद्धि श्रीर प्रतिभा का फल न मिलेगा। काम में उनका स्वार्थ न रहेगा तो उन्हें उसके करने में उत्साह या प्रवृति भी कम होगी. इससे एक तो काम का परिमाण घट जायगा, दूसरे वह होगा भी घटिया दर्जे का। इससे राज्य को सामृहिक दृष्टि से हानि होगी, श्रीर फल-स्वरूप व्यक्तियों की भी क्षति हागी। पुनः समाजवाद मनुष्यः मनुष्य से पूँजीपति श्रीर मजदूर, ज़मीदार श्रीर किसान, बड़े श्रीर छोटे का भेद मिटा कर समानता स्थापित करना चाहता है। यह एक आदर्श

मात्र है। इसका पूरा होना कपोल कल्पना है। मनुष्यों में योग्यता, प्रतिभा या शारीरिक क्षमता आदि की हिन्ट से कुछ-न-कुछ भेद रहता है। यदि दो व्यक्तियों का पद आज कृतिम रीति से समान कर दिया जाय तो कुछ समय बाद वे पुन: असमान स्थिति के हो जायँगे। फिर वही असंतोष और कन्टों का अनुभव होगा। इस प्रकार राज्य के कार्यों का चेत्र बहुत अधिक बढ़ाये जाने से भी वह उद्देश्य पूर्णतया सिद्ध न होगा, जिसे समाजवाद प्राप्त करना चाहता है। समाजवाद का प्रधान सूत्र इतिहास का आर्थिक विवेचन है। परन्तु मानव जीवन के अनेक हिन्टकोण है, उसकी अनेक समस्याएँ हैं उन सबका एक ही हल कैसे हो सकता है, चाहे वह हल कितने ही महत्व का क्यों न हो।

#### उचित मार्ग

कपर व्यक्तिवाद और समाजवाद के पक्ष एवं विपक्ष में संचेप में लिखा गया है। व्यक्तिवाद राज्य द्वारा केवल अत्यन्त आवश्यक सार्य कराना चाहता है, और समाजवाद राज्य को सभी (आवश्यक भी और लोक-हितकर भी) कार्यों के करने का उत्तरदायी मानता है। दोनों मत एक-दूसरे के विपरीत हैं। यद्यपि जैसाकि हमने इस परिच्छेद के आरम्भ में कहा है, दोनों का उद्देश्य एक ही है—अर्थात् व्यक्ति की उन्नति—पर दोनों का मार्ग भिन्न-भिन्न है; एक उत्तर, तो दूसरा दक्षिण। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि उचित क्या है? इधर कुछ समय से दोनों सिद्धान्तों की कटुता लुस हो रही हैं। कुछ

श्रॅश तक दोनों में कुछ समभौता-सा हो गया है श्रौरर मानों बीच का मार्ग निकल रहा है। व्यक्तिवादी यह श्रमुभव कर चुके हैं कि नागरिकों के श्रार्थिक कार्यों में भी राज्य की श्र-हस्तत्त्वेप नीति दोष-पूर्ण है। व्यक्तियों की श्रमीमित स्वतंत्रता से बहुत हानि होती है, उनकी स्वतंत्रता वहीं तक रहनी उचित है, जहाँ तक राज्य का हित हो। श्रप्रतिवन्ध प्रतिद्वन्द्विता का परिणाम बहुत हानिकर होता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी समाजवाद की श्रोर बढ़ रहे हैं, हाँ, वे श्रमी पूर्णतः सार्वजनिक श्रधिकार के पन्न में नहीं हुए हैं। श्रस्त, राज्य के कार्य-त्तेत्र सम्बन्धी विचारों में बहुत परिवतन होरहा है, श्रव राज्य को केवल शासन-संस्था न मानकर उसे नागरिक जीवन के सब चेत्रों में भलाई करने का साधन माना जा रहा है।

इस प्रकार राज्य को शान्ति-स्थापक कार्य तो करने ही चाहिए। लोक-हितकर कार्यों में से वे कार्य उसके करने के हैं, जिन्हें देश-काल के अनुसार करना उपयोगी हो। इस विचार से राज्य के कार्य क्यान्या होंगे, इसका ब्योरेवार वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा। यहाँ हम पाठकों का ध्यान केवल इस बात की आरे दिलाना चाहते हैं कि जब हम यह कहते हैं कि राज्य को लोक-हितकारी कार्य भी करने चाहिए तो इसमें कोई चौकने की बात नहीं है। यह शंका करने का कारण नहीं है कि इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वाधा उपस्थित होगी। हम तो स्वयं यह कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का युग है, प्रत्येक व्यक्ति आव राज्य और नागरिकों के हितों में कोई वास्तविक विरोध नहीं कि अव राज्य और नागरिकों के हितों में कोई वास्तविक विरोध नहीं

माना जाता। दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक और उपयोगी हैं, होनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों को एक दूसरे की उन्नति में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

राज्य श्रीर व्यक्ति के उद्देश्य की समानता—प्राचीन काल में यूनान श्रीर रोम श्रादि में राज्य को एक प्रकार से साध्य माना जाता था, श्रीर उसके सम्मुख व्यक्ति केवल एक साधन मात्र था। व्यक्ति का समस्त जीवन राज्य के श्रधीन था। किसी व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्ता प्राप्त करनी चाहिए, कौन-सा धर्म स्वीकार करना चाहिए, श्रादि बातों का निर्णय राज्य ही करता था। उस समय राजनीतिज्ञों का मत था कि नागरिकों का, राज्य से पृथक, कोई जीवन नहीं, कोई श्रधिकार नहीं। उन्हें राज्य के लिए जीना चाहिए, श्रीर श्रावश्यकता होने पर उसके लिए मरना भी चाहिए। कालान्तर में यह सिद्धान्त कम मान्य रह गया। दूसरे मत का प्रचार बढ़ा, इसके श्रनुसार राज्य को स्वयं साध्य नहीं माना जाता, वह एक साधन-मात्र है। उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता-रज्ञा, उन्नति श्रीर विकास करना है। इस प्रकार राज्य एक साधन है, श्रीर साध्य है नागरिक।

वास्तव में उपयु क दोनों विचारों में एक श्रंश तक सचाई है, तो कुछ भ्रम भी है। राज्य श्रौर नागरिक के उद्देश्य में भिन्नता नहीं, समानता है। राज्य जब नागरिकों की उन्नति करता है तो वह श्रपनी ही उन्नति करता है; कारण, वह नागरिकों का ही सामूहिक रूप है। इसी प्रकार जब नागरिक राज्य के उत्थान में सहयोग प्रदान करते हैं, तो इससे उनका भी हित-साधन होता है; क्योंकि वे राज्य के ही तो श्रंग हैं। निदान, राज्य इस हिंट से एक साध्य है कि नागरिकों को उसकी उन्निति श्रोर सेवा करनी चाहिए। किन्तु दूसरी हिंट से वह एक साधन भी है; क्योंकि उसका उद्देश्य नागिरकों की उन्निति श्रोर विकास है।

भारतवर्ष श्रोर समाजवाद — इस परिच्छेद को समास करने से पूर्व एक प्रश्न पर विचार कर लेना श्रप्रासंगिक न होगा। श्रक्षसर इस विषय की चर्चा की जाती है कि भारतवर्ष भें समाजवाद का प्रचार होगा या नहीं। एक पच्च का मत है कि भारतवर्ष श्रोर रूस में बहुत समानता है, रूस की तरह यह देश खूब लम्बा-चौड़ा है। समाजवाद के प्रचार से पूर्व रूस कृषि प्रधान था, वहाँ निरंकुश शासन-पद्धित थी, श्रनेक धर्म प्रचलित थे, जनता श्रत्यन्त दरिद्र थी। ये सक बातें भारतवर्ष में भी हैं। श्रतः यहाँ समाजवाद के लिए बहुत श्रनु कूलता है। दूसरे सजनों का कथन है कि भारतवर्ष में श्राध्यात्मिक भावों का प्रचार विशेष है, यहाँ श्रार्थिक बातों को बहुत कम महत्व दिया जाता है। श्रतः यहाँ समाजवाद के लिए विशेष चेत्र नहीं है।

यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तिविक स्थिति क्या है ? भारत-वर्ष में अब समाजवाद का विचार और प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है । विचारों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता । इस युग में, कोई वाद किसी देश विशेष तक परिमित नहीं रह सकता । इम देखते हैं कि यहाँ स्थान-स्थान पर समाजवादी संस्थाओं का संगठन हो रहा है, जिनमें युवक तथा बड़ी उम्र के विद्यार्थी बहुत भाग

लेते हैं। स्वयं कांग्रेस के अन्दर एक समाजवादी दल बन गया है. जिसका उद्देश्य यह है कि यहाँ की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था श्रपने कार्य-क्रम में समाजवाद को श्रपनाये। इस दल में कितने-ही सुप्रसिद्ध नेता सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्र के महान नेता पं • जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारतवर्ष की बेकारी और निर्धनता की भयंकर समस्या समाजवादी आधार पर किये हुए संगठन से ही हल हो सकती है। इस प्रकार यहाँ समाजवाद के पक्ष में मत बढता जाता है। परन्तु इसका आश्यय यह नहीं कि यहाँ रूस के ही दङ्ग का समाजवाद हो। प्रत्येक देश की परिस्थित भिन्न-भिन्न होती है. सामाजिक। तथा सांस्कृतिक वातावरण पृथक् पृथक् होता है। जीवित जारत जातियाँ किसी वाद या मत को लेते समय उसे आने अनुकल कर लेती हैं। इमारा विचार है कि भारतवर्ष में जो समाजवाद फैलेगा. वह भारतीय रूप-रेखा वाला होगा। यद्यपि प्रत्येक देश की विचार-धारा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी उसमें कुछ विशेषता बनी रहती है, जिसके कारण उसे किसी अन्य देश की विचार-धारा से पृथक श्रीर स्वतंत्र समभा जा सकता है। यदि यहाँ कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता के विचार प्रकट कर सकता है तो वह महात्मा गांधी है। श्रतः श्रागे—महात्मा जी के शब्दों में -यह बताया जाता है कि यहाँ समाजवाद किस दक्त तथा किस प्रकार का होने की सम्भावना अधिक है-

"श्रार्थिक समानता श्रर्थात् जगत् के सब मनुष्यों के पास एक समान सम्पत्ति का होना, यानी सब के पास इतनी सम्पत्ति का होना कि जिसंसे वह अपनी कुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। कुदरत ने ही एक आदमी का हाज़मा अगर नाज़ुक बनाया हो, और वह केवल पाँच ही तोला अन खा सके, और दूसरे को बीस तोला अन खाने की आवश्यकता हो, तो दोनों को अपनी-अपनी पाचन-शक्ति के अनुसार अन मिलना चाहिए। सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर होनी चाहिए। आहिंसक समाज को दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिए। मानािक पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, मगर उसे नज़र में रखकर हम विधान तो बनायें, और व्यवस्था तो करें। जिस हद तक हम आदर्श को पहुँच सकेंगे, उसी हद तक सुख और सन्तोष प्राप्त करेंगे, और उसी हद तक सामािजक आहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेगी।

"इस श्रार्थिक समानता के धर्म का पालन एक श्रकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरों के साथ को उसे श्रावश्यकता नहीं रहती। श्रार एक श्रादमी इस धर्म का पालन कर सकता है, तो ज़ाहिर है कि एक मंडल भी कर सकता है। यह कहने की ज़रूरत इसलिए है कि किसी भी धर्म के पालन में जहाँ तक दूसरे उसका पालन करते जायँ, वहाँ तक हमें रके रहने की श्रावश्यकता नहीं। श्रीर फिर, श्राख़िरी हद तक न पहुँच सकें, वहाँ तक कुछ भी त्याग न करने की वृत्ति बहुधा देखने है श्राती है: यह भी हमारी गति को रोकती है।

"श्रहिंसा के द्वारा श्रार्थिक समानता कैसे लायी जा सकती है, इसका विचार करें। पहला क़दम यह है। जिसने इस श्रादर्श को श्रपनाया हो, वह श्रपने जीवन में श्रावश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तान की ग्ररीब प्रजा के साथ श्रपनी तुलना करके श्रपनी श्रावश्यकताएँ कम

करे। अपनी धन कमाने की शक्ति को नियम में रखे। जो धन कमाये, उसे ईमानदारी से कमाने का निश्चय करे। छहे की वृत्ति हो, तो उसका त्याग करे। घर भी अपना सामान्य आवश्यकता पूरी करने लायक ही रखे, और जीवन को हर तरह से संयमी बनाये। अपने जीवन में सम्भव सुधार कर तेने के बाद अपने मिलने-जुलनेवालों और पड़ोंसियों में समानता के आदर्श का प्रचार करे।

''आर्थिक समानता की जड़ में धनिक का ट्रस्टीपन निहित है। इस श्रादर्श के श्रनुसार धनिक को श्रपने पड़ोशी से एक कौड़ी भी ज़्यादा रखने का श्रिथकार नहीं। तब, उसके पास जो ज्यादा है, क्या वह उससे छीन लिया जाय १ ऐसा करने के लिए हिंसा का श्राश्रय लेना पड़ेगा। श्रीर, हिंसा के द्वारा ऐसा करना सम्भव हो, तो भी समाज को उससे कुछ फ़ायदा होनेवाला नहीं है, क्योंकि द्रव्य इक्ट्रा करने की शक्ति रखनेवाले एक आदमी की शक्ति को समाज खो बैठेगा। इसलिए अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सके, उतनी अपनी श्चावश्यकताएँ पूरी करने के बाद जो पैसा बाक़ी बचे उसका वह प्रजा की आर से ट्रस्टी बन जाये। अगर वह प्रामाणिकता से संरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा, उसका सद्व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने श्रापको समाज का सेवक मानेगा. समाज की ख़ातिर घन कमायेगा, समाज के कल्याण के लिए उसे ख़र्च करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता आयेगी। उसके साइस में भी श्रहिंसा होगी। इस प्रकार की ं कार्य-प्रयाली का श्रायोजन किया जाय, तो समाज में बगैर संघर्ष के मूक क्रान्ति पैदा हो सकती है।

''इस प्रकार मनुष्य-स्वभाव में परिवर्तन होने का उल्तेख इति-हास में कहीं देखा गया है ? व्यक्तियों में तो ऐसा हुआ ही है । बड़े पैमाने पर समाज में परिवर्तन हुआ है. यह शायद सिद्ध न किया जा सके। इसका अर्थ इतना ही है कि व्यापक अहिंसा का प्रयोग आज तक नहीं किया गया। इस लोगों के हृदय में इस भूडी मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। दरअवल बात ऐसी है नहीं। श्रहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्म के तौर पर उसे विकलित किया जा सकता है, यह मनवाने का मेरा प्रयत और प्रयोग है। यह नयी चीज़ है, इसलिए इसे भुड़ समभ कर फेंक देने की बात इस युग में तो कोई नहीं करेगा। यह कठिन है, इसिलर त्रास्य है, यहमी इस युग में कोई नहीं कहेगा; क्योंकि बहुत-सी चीजें श्रानी श्रांखों के सामने नयी-पुरानी होती इमने देखी हैं; जो श्रशक्य लगता था, उसे शक्य बनते इमने देखा है। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसा के चेत्र में इससे बहुत ज्यादा साहस शक्य है, श्रीर विविध धर्मों के इतिहास इस बात के प्रमाणों से भरे पड़े हैं। समाज में से धर्म को निकाल फेंक देने का प्रयत्न बांभ के घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्कत है, श्रीर श्रगर कहीं सफल हो जाये तो समाज का उसमें नाश है। धर्म के रूगन्तर हो सकते हैं। उसमें निहित प्रत्यक्ष वहम, सड़न और अपूर्णताएँ दूर हो सकती हैं; हुई हैं, श्रीर होती रहेंगी। मगर धर्म तो जहाँ तक जगत् है, वहाँ तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जगत् का एक धर्म ही आधार है। धर्म की श्रन्तिम व्याख्या है, ईश्वर का क़ानून। ईश्वर श्रौर

उसका क़ानून अलग-अलग चीलें नहीं हैं। ईश्वर अर्थात् अचिलत जीता-जागता क़ानून । उसका पार कोई नहीं पा सका । मगर अवतारों ने और पैगम्बरों ने तपस्या करके उसके क़ानून की कुछ-कुछ आंकी जगत् को करायी है।

"किन्तु महा प्रयत्न करने पर भी घनिक संरक्षक न बनें, श्रीर भूखों मरते हुए कराड़ों को श्रिक्षा के नाम से श्रीर श्रधिक कुचलते जायें, तब हम क्या करें है हस प्रश्न का उत्तर हूँ दने में ही श्रिक्षिक कानून-भंग प्राप्त हुआ। कोई घनवान गरीबों के सहयोग के बिना घन नहीं कमा सकता। मनुष्य को श्रपनी हिंसक शक्ति का भान है, क्योंकि वह तो उसे लाखों वर्षों से विरासत में मिली हुई है। जब उसे नार पैर की जगह दो पैर श्रीर दो हाथवाले प्राणी का श्राकार मिला, तब उसमें श्रिक्षिक शक्ति भी आई। हिंसा-शिक का तो उसे मूल से ही भान या, मगर श्रिक्षा-शिक्त का भान भी धोरे-शिरे, किन्तु श्रचूक रीति से रोज़-रोज़ बढ़ने लगा। यह भान गरीबों में प्रचार पा जाये, तो वह बलवान बनें श्रीर श्रार्थिक शरीक श्रक्ता तो के से हूर करना सीख लें।"\*



<sup>\*&#</sup>x27;हरिजन सेवक' से

# सोलहवाँ परिच्छेद

#### राज्य के कार्य

किया गया है। इस विषय में दो सिद्धान्त मुख्य हैं:—व्यक्तिवाद और समाजवाद। व्यक्तिवादी चाहते हैं कि राज्य का कार्य-चेत्र बहुत परिमित रहे, वह वे ही कार्य करे, जो शान्ति-स्थापना के लिए आन्वश्यक हों। इसके विपरीत समाजवादियों का मत है कि राज्य का कार्य-चेत्र अधिक-से-अधिक हो, वह शान्ति-स्थापक कार्यों के आतिरक्त, लोक-हितकर कार्य भी करे। अब राज्य का स्वरूप अधिकाधिक प्रजातंत्रात्मक होता जाता है, व्यक्ति और राज्य का मेद मिटता जाता है, व्यक्तियों को राज्य द्वारा कार्य कराने में अपनी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करना होता, उन्हें इसमें सुभीता मालूम होता है। इसलिए राज्य का कार्य-चेत्र बढ़ता जाता है। अस्तु, राज्य के कार्यों के प्रधानतया दो मेद किये जा सकते हैं:—(१) शान्ति-स्थापक, और (२) लोक-हितकर।

## शान्ति-स्थापकं कार्य

पहले राज्य के, शान्ति स्थापना के लिए किये जानेवाले कार्यों का विचार करते हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैं:—

- (१) राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा।
- (२) राज्य के भीतर शान्ति सुव्यवस्था रखना ।
- (३) न्यायकार्य ।

इनमें पहले दो कार्य, एक ही कार्य के दो रूप हैं, श्रौर वह एक कार्य है, व्यक्तियों के जान-माल की रज्ञा। विवेचन की सुविधा के लिए उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है।

रक्षा— लोभ बुरी बला है। इससे प्रेरित होकर कितने ही राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसके जन-धन पर अपना अधिकार जमाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे संशार का वातावरण बहुत दूषित हो गया है। बहुत-से राज्य, विशेषतया छोटे और अल्प शक्तिमान राज्य सदैव इस चिन्ता में रहते हैं कि न-मालूम कब उन पर दूसरे राज्य का धावा हो जाय। इसलिए वे अपनी आत्म-रच्चा का प्रबन्ध करते हैं। पहले विशेषतया स्थल-मार्ग से आक्रमण हुआ करते थे, उस समय रक्षा के लिए स्थल-सेना की ही योजना की जाती थी। पीछे जल-मार्ग से भी आक्रमण होने लगे, और राज्यों का जल-सेना का प्रबन्ध करना पड़ा। अब वैज्ञानिक उन्नति से हवाई जहाजों द्वारा भी नगरों को ध्वंस करने का कार्य किया जाता है; फलत: वायु-सेना का महत्व बढ़ता जा रहा है। निदान, अब सेना तीन प्रकार की होती हैं:—स्थल-सेना,

जल-सेना श्रोर वायु-सेना। श्राज-कल राज्य वायु-सेना की वृद्धि के लिए विशेष रूप से दत्त-चित्त हैं।

संसार में बहुत वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निशस्त्रीकरण की बात चल रही है। यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य की सेना तथा सैनिक सामग्री बहुत परिमित रहे, कोई दूसरे पर श्राक्रमण न करे. श्रीर यदि कोई युद्ध का प्रसंग श्राने लगे तो श्रन्य राज्य श्राक्रमण-कारी को समकावें-बुकावें, श्रीर इससे काम न चलने पर सब राज्य मिलकर आक्रमणकारी का विरोध करें। ऐसे ही विचारों से विछले योरपीय महायुद्ध के बाद, सन् १९१९ ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई थी। इसके सम्बन्ध में विशेष रूप से तो एक स्वतन्त्र परिच्छेद में ही लिखा जायगा। यहाँ यही कहना अभीष्ट है कि राष्ट्र संघ को इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली श्रौर उपयु क विचार कार्य-रूप में परिखत न हए। इस समय तो योरप में चारों श्रोर 'त्राहिमाम्' का करुण कन्दन है, युद्ध की लपटों का प्रभाव एशिया और अक्तरीका तक व्याप्त है। मानव संसार इतना परेशान है कि श्रहिन्सा-प्रचारक महात्मा गाँधी का सन्देश सुनने की उसमें चमता ही नहीं रह गयी; उनका सन्देश नकारख़ाने में तृती की तरह हो रहा है। श्रीरों की तो बात ही क्या, स्वयं भारतवर्ष में, यद्यपि कांग्रेस ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए श्राह्नसात्मक कार्य-क्रम अपनाया था, तो भी यहाँ अनेक आदमी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए (तथा देश की भीतरी अशान्ति या अञ्यवस्था का नियन्त्रण करने के लिए भी) सैनिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

श्राज-कल किसी राज्य की दूसरे राज्य से जो सन्ध श्रादि होती है, वह या तो श्रात्म-रत्ना के हेतु की जाती है, या श्राना राज्य बढ़ाने (श्रयवा दूसरे राज्य में श्रार्थिक सुविवाएँ प्राप्त करने) के लिए। प्रत्येक दशा में श्रयना स्वार्थ मुख्य रहता है। श्रावश्यकता इस बात की है कि भिन्न-भिन्न राज्यों का परस्पर सहयोग हो, श्रीर यह कार्य एक दूसरे की ही नहीं, मानव जाति की हित-चिन्तना की हिष्ट से हो। श्रवेले श्रयना-श्रपना उद्धार करने की चेष्टा से हमारा यथेष्ट उद्धार कदापि न होगा। मानव समाज एक विशाल परिवार है; श्रत: सबकी भलाई में हमारी भी भलाई है।

शान्ति श्रोर सुव्यवस्था—सेना, राज्य के व्यक्तियों की जान-माल की रक्षा, बाहर से हानेवाले श्राक्रमणों से, करती है। राज्य में इस बात की भी श्रावश्यकता होती है कि उसके भीतर शान्ति रहे, चोरी या लूट-मार श्रादि न हो, किसी व्यक्ति का दूसरे से लड़ाई-भगड़ा न हो। यदि सब व्यक्ति समभ-दार श्रोर सुशिक्षित हों तो वे श्रयना-श्रयना कार्य भली-भांति करते रह सकते हैं। पर यह तो श्रादर्श की बात ठहरी। व्यवहार में तो नित्य पारस्परिक भगड़ों का श्रनुभव होता है, लोगों के जान-माल को ख़तरा रहता है। इसे रोकने के लिए राज्य में पुलिस की व्यवस्था करनी होती है। (कभी-कभी विशेष श्रवसरों पर तो उग्रदिवयों को दमन करने के लिए सेना की भी श्रावश्यकता पड़ती है।) राज्य में नागरिकों को घूमने फिरने, सभा करने, मिलने जुत्रने, श्राजीविका प्राप्त करने श्रादि के विविध श्रीकार होते। हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी

नागरिक के इस श्रिष्ठकार के उपभोग में बाधक होता है, तो राज्य का कार्य है कि वह ऐसा न होने दे। राज्य इस कार्य के लिए पुलिस रखता है, जो श्रिपराध करनेवालों की खोज करती, उन्हें गिरफ्रतार करती तथा उन्हें न्यायालय पहुँचाती है।

राज्य की आन्तरिक शान्ति और सुव्यवस्था के लिए पुलिस ही पर्याप्त नहीं है। वह तो केवल, अपराधियों को तलाश करने का काम करती है तथा ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़ार करती है, जिनके सम्बन्ध में यह शंका हो कि उन्होंने राज्य का कोई नियम भंग किया है। किसी व्यक्ति में नियम भंग किया है। किसी व्यक्ति ने वास्तव में नियम भंग किया है या नहीं, क़ानून के अनुसार वह अपराधी है या नहीं, इसका निर्णय पुलिस नहीं कर सकती। यह कार्य न्यायालय का है। राज्य स्थान-स्थान पर न्या-यालयों की स्थापना करता है। जब दो या अधिक नागरिकों का परस्पर भगड़ा होता है तो उन में से किसका पन्न उचित है और किसका अनुचित, इसका विचार न्यायालय में होता है। कभी-कभी नागरिक का सरकार से भी विरोध होता है; नागरिक समभता है कि वह उचित मार्ग पर है, और सरकार उसे दोषी मानती है। इसका भी निपटारा न्यायालय ही करता है।

न्याय—न्याय का उद्देश्य है कि जनता कृत्न का पालन करे, उसके हृदय में कृत्नून का सम्मान हो, नागरिक परस्पर में सद्भाव से है, रहें, राज्य में शान्ति और सुज्यवस्था हो। यह उद्देश्य तभी पूरा होता जब न्याय-कार्य सस्ता और निस्पक्ष हो। एक और तो अदालती फीस तथा अन्य खुर्च इतना अधिक न होना चाहिए कि न्याय ग्रीबों की पहुँच से बाहर हो जाय, दूषरों श्रोर उसमें रंग, जाति या पद के कारण किसी से पक्षपात न होना चाहिए। पराधीन देशों में, विशेषतया राजनैतिक विषयों में, शासकों के त्रुंट-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने श्रीर शासक जाति के श्रादमियों से श्रनुचित्र रियायत होने की सम्मा-बना रहती है। इसके निवारण का उपाय होना चाहिए।

जो व्यक्ति राज्य का नियम भंग करता है, उसे न्यायालय द्वारा खंड दिया जाता है। प्रायः इसमें बदले की भावना ऋषिक रहती है, अपराधी के सुधार की भावना कम। जब अपराधियों को दंड-स्वरूप निर्धारित समय तक क़ैद की सज़ा दी जाती है तो उन्हें जेल में रखा जाता है, और अधिकतर स्थानों में जेलों की व्यवस्था ऐसी होती है कि अपराधी को जितने अधिक समय की क़ैद होती है, उतना ही वह अधिक अपराधी बन जाता है; सुधार को तो बात ही दूर रहा। फिर, जब किसी बड़े अपराध में प्राया-दंड दिया जाता है तो सुधार किये जानेवाले व्यक्ति का ही अन्त हो जाता है। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाने लगा है, दंड के वजाय सुधार की पड़ित का अवलम्बन हो रहा है। बालकों (नाबालिगों) के लिए तो अब भी दंडशाला की जगह सुधार शाला ('रिफारमेटरी') की व्यवस्था की जाने लगी है।

<sup>\*</sup>यह कहा जाता हैं कि कठोर दंड से अन्य नागरिकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता हैं, वे अपराध करने से रुकते हैं। परन्तु अनुभव बतलाता है कि इस कथन में विशेष तत्व नहीं है। इस विषय का विस्तार-पूर्वक विचार श्री० केला जो की "अपराध चिकित्सा" पुस्तक में किया गया है।

### लोक-हितकर कार्य

यह तो राज्य के उन कार्यों की बात हुई जो उसे शान्ति-स्थापना के लिए करने होते हैं। श्रव लोक-हितकर कार्यों की बात लीजिए— जो नागरिकों की शारीरिक, मानिसक या सांस्कृतिक उन्नित श्रादि के लिए उपयोगी होते हैं। इन कार्यों में से किस-किस को राज्य करे श्रीर कहाँ तक करे, यह सामयिक परिस्थित पर निर्भर है।

शिक्षा—शिक्षा की उपयोगिता सर्व-विदित है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि शिक्षा का आशय केवल कुछ पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त करना ही नहीं है। शिक्षा से अभिप्रायः है, सभी आवश्यक विषयों का ज्ञान—शारीरिक शिक्षा अर्थात् बलवान और स्वस्थ होने का ज्ञान, अर्जीविका प्राप्त करने और स्वावलम्बी होने का ज्ञान, कर्तव्याकर्तव्य और नागरिकता का ज्ञान, जिसे प्राप्त कर कोई व्यक्ति अपने राज्य का सुयोग्य नागरिक बनता है, इत्यादि। इस शिक्षा के लिए पाठशालाएँ या स्कूल पर्याप्त नहीं होते। आवश्यकता है कि राज्य में पुस्तकालय, वाचनालय, अजायबघर, व्यायामशाला, अनुसंघानशाला आदि भी यथेष्ट संख्या में हों। आज-कल अनेक उन्नत राज्य भी अपने यहाँ की शिक्षा-पद्धति में संशोधन या सुधारों की बड़ी आवश्यकता अनुभव करते हैं, फल-स्वरूप कई स्थानों में बहुत सुधार हो भी रहा है। तथापि अभी इस दशा में बहुत ध्यान दिये जाने की जरहत है। घहुत से देशों में तो साधारण शिक्षा की ही बहुत कमी

है। भारतवर्ष में लगभग नब्बे फ़ी-सदी जनता के श्रज्ञानांधकार में रहने से राज्य की इस श्रोर अपने कर्तव्य-पालन में श्रवहेलना सूचित होती है। गत वर्षों में जब कि यहाँ प्रान्तों में लोक-प्रिय (काँग्रेसी) सरकारें थीं, शिक्षा-प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर कार्य श्रारम्म किया गया था। वैसा प्रयत्न निरन्तर बना रहने की श्रावश्यकता है।

स्वास्थ्य — 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्'। जिसराज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य-रक्षा की उचित व्यवस्था नहीं, वह कैसे उन्नित करेगा!
स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी कितने ही कार्य ऐसे हैं, जिन्हें नागरिक व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। नगर या गाँव की सफ़ाई, मोरियों या नालियों की व्यवस्था, स्वच्छ, जल के लिए नलों का प्रबन्ध, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना, संकामक रोगों का निवारण, भिन्न-भिन्न प्रकार के रोगियों के लिए विशेष रूपसे चिकित्सा का प्रवन्ध श्रादि श्रानेक कार्य ऐसे हैं, जिनके लिए राज्य को यथेष्ट व्यवस्था करनी चाहिए। जनता में स्वास्थ्य-सम्बन्धी ज्ञान के प्रचार के लिए सिनेमा श्रीर लाद् की लालटैन के द्वारा भी बहुत काम किया जा सकता है। इस विषय के उपयोगी साहित्य के प्रचार की भी बहुत श्रावश्यकता है।

निर्धन देशों में आदिमियों को अच्छा और पर्यात मोजन-वस्त्र मिलना किंदन होता है, और रहने के लिए साफ हवादार मकानों की भी एकवड़ी समस्या है। अतः राज्य को लोगोंकी आर्थिक दशा सुधारने

<sup>\*</sup> सिनेमा श्रादि का उपयोग एक सीमा तक ही होना श्रमी है । कोई सिनेमा ऐसा न हो जो मन में कुविचार पैदा करनैवाला हो, इस दृष्टि से इस पर काफ़ी निर्थंत्रण रहना श्रावरयक है।

के लिए श्रीद्योगिक श्रीर शिल्प-सम्बन्धी योजनाश्रों को श्रमल में लाने की श्रोर समुचित ध्यान देना चाहिए। बहुधा सम्पन्न व्यक्ति, जिन्हें श्रावश्यक भोजन, वस्त्रादि का श्रमाव नहीं होता, श्रपनी श्रारामतलबी, विलासिता, शौक्षीनी श्रादि के कारण रोगी रहते हैं। श्रातः राज्य में सादगी के जीवन का प्रचार होना चाहिए तथा इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

यातायात के साधन--राज्य में यातायात या श्रामदरकत के साधनों की उन्नति की बहुत श्रावश्यकता होती है। भिन्न-भिन्न भागों के ब्राटिंगयों के ब्रापस में मिलने-जुलने ब्रौर विचार-विनिमय करने से ज्ञान और अनुभव की बृद्धि होती है, भावों की संकीणता हटती है, ्हिष्ट-कोण विशाल होता है, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता श्रीर उदा-रता की बृद्धि होती है। यह तो मानसिक तथा नैतिक उन्नति की बात हुई। यातायात के साधनों से राज्य की आर्थिक उन्नति में भी बहुत सहायता मिलती है, व्यापार की वृद्धि होती है, भिन्न-भिन्न भागों के श्रादमी एक-दूषरे की श्रावश्यकता श्रीर श्रभावों को जानते, श्रीर उनको पूर्ति में योग देते हैं। इससे दैनिक जीवन में सुख श्रीर सुवि-धात्रों की बृद्धि होती है। इस जिए गाँव-गाँव श्रीर नगर-नगर तक -सड़कों का विस्तृत जाल बिछा होना चाहिए; रेल, डाक, तार, टेली-फोन, रेडियो आदि के प्रचार की भी आवश्यकता स्पष्ट है। इन कार्यों का श्रायोजन व्यक्तियों के बश का नहीं, राज्य ही इन्हें श्रव्छी तरह कर सकता है। कहीं-कहीं कुछ काम कम्मनियों द्वारा भी किये जाते

हैं। इस दशा में राज्य का सहयोग श्रौर नियन्त्रण रहना बहुत उपयोगी है।

श्राधुनिक सम्यता में, शहरों में तो यातायात के साधनों को बढ़ाने की श्रोर कुछ विशेष ध्यान दिया जाता है, पर गाँवों की प्रायः उपेक्षा की जाती है। नागरिकता के विचार से गाँववात भी उपर्युक्त सुविधाश्रों के वैसे ही श्रिधकारी हैं, श्रीर कोई राज्य केवल नगरों के उत्थान से उन्नत नहीं हो सकता। श्रतः गाँवों की श्रोर भी पर्याप्त ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है।

समाज-सुधार — राज्य की समाज-सुधार के सम्बन्ध में क्या नीति रहनी चाहिए ? समाज-सुधार से हमारा आशय लोंगों की सामाजिक रीति-रस्मों, विवाह-शादी और जन्म-मरण सम्बन्धी लोक-व्यवहार से है। प्रायः समाज में कोई प्रथा आरम्भ में किसी विशेष कारण या आवश्यकता-वश आरम्भ होती है; पीछे आदमी उसकी मूल बात मूल जाते हैं और आवश्यकता न रहने पर भी उस प्रथा के प्रति अन्ध-विश्वास रखते हैं तथा उसका पूर्णतथा पालन करते हैं, चाहे यह कितनी ही हानिकर क्यों न हो गयी हो। उदाहरणवत् भारतवर्ष में बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, श्रीसर-मौसर (किसी के मरने पर विरादरी की दावत) आदि, अथवा मद्यपान, या जुआ इत्यादि। ऐसे विषयों में विचारशील नेता समाज का नेतृत्व करते हैं, और लोकमत तैयार करके आवश्यक सुधार करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। परन्तु बहुधा ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको यथेष्ट सफलता नहीं मिलती और राज्य की सहायता, या कानून की मदद की ज़रूरत

पड़ती है। राज्य को चाहिए कि ऐसे सुधारों के लिए प्रोत्साहन दे;
श्रीर श्रावश्यक क़ानून बना कर सुधारकों का सहायक हो। भारतवर्ष
में कन्या-वध श्रीर सती-दाह प्रथा बन्द होने में तभी सफलता मिली,
जब श्रावश्यक क़ानून बन गया। इस विषय के श्राधुनिक उदाहरणों
में बाल-विवाह-निषेध श्रीर श्रस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी क़ानून बहुत
विचारणीय हैं।

बहुत समय से बाल-विवाह का प्रचार यहां सुधारकों के लिए चिन्ता का विषय था। सन् १९३०ई० में, ब्रिटिश भारत में इस आशय का क़ानून बना कि चौदह वर्ष से कम की लड़की का, श्रीर श्रठारह वर्ष से कम के लड़के का. विवाह न हो। इस क़ानून के प्रस्तावक के नाम पर इसे 'शारदा ऐक्ट' कहा जाता है। कुछ समय हुआ इस क्रानून को श्रविक उपयोगी बनाने के लिए कुछ संशोधन भी हुआ। स्कुलों में केवल अविवाहित लडके भरती करने, तथा कालिजों में विवाहित लड़कों को छात्रवृत्ति न दी जाने के नियम कहीं-कहीं प्रचलित हैं। इनसे भी बाल-विवाद-निषेध में श्रच्छी सहायता मिल रही है। बड़ौदा आदि कुछ देशी राज्यों में भी एक निर्धारित आयु से पूर्व विवाह करना क़ानूनी श्रपराध माना जाता है। श्रावश्यकता है कि जिन देशी राज्यों में इस विषय का यथेष्ट क़ानून नहीं है, वहाँ भी क़ानून बनाया जाय; साथ ही सुधारक इस क़ानून का उपयोग करने में, एवं इस विषय सम्बन्धी प्रयत्नों के लिए लोकमत तैयार करने में कटिवद्ध रहें।

इसी प्रकार ऋस्प्रश्यता-निवारण की बात है। विकुली शताब्दियों

में यहां छूत-छात का विचार बहुत बढ़ गया था। नेताओं और स्वयं राष्ट्रीय महासभा के प्रयत्न से कुछ सुधार हुआ, पर विशेष सफलता के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता रही। अब ऐसा क़ानून बन गया है कि 'हरिजन' सार्वजनिक कुओं, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग अन्य व्यक्तियों की मांति कर सकें। उनमें स्वच्छता, स्वास्थ्य-रत्ता तथा शिक्षा, विशेषतया शिल्प-शिक्षा के प्रचार के लिए प्रान्तीय सरकारें तथा म्युनिसिपैलिटियां आदि यथा-सम्भव सहायता कर रही हैं। अस्तु, राज्य का एक कार्य समाज-सुधार भी है।

आथिक हित-साधन—नागरिकों के निर्धन रहने की दशा में न उनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो सकती है, और न उनका स्वास्थ्य ही अच्छा रह सकता है। नागरिकों का जीवन एक-दूसरे से इतना घनिष्ट सम्बन्धित है कि कुछ लोगों के अज्ञान या बीमारियों का बुरा असर कैवल उन्हीं व्यक्तियों तक परिमित नहीं रहता, दूसरों को भी उसका परिणाम सुगतना होता है। इस प्रकार जनता के एक भाग के निर्द्धन या दरिद्र रहते हुए राज्य उन्नत नहीं हो सकता, चाहे जनता का दूसरा भाग कितना ही सुखी और समृद्ध क्यों न हो। अतः आवश्यकता है कि (१) नागरिकों की आर्थिक उन्नति की व्यवस्था की जाय और (२) नागरिकों की आर्थिक विषमता दूर की जाय।

श्रार्थिक उन्नित सम्बन्धी एक बात का उल्लेख ऊपर हुआ है। इमने बताया है कि यातायात के साधनों की वृद्धि होनी चाहिए। इसके श्रितिरक्त राज्य को कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, वैंकिंग श्राहि विषयों की श्रोर यथेष्ट ध्यान देने की श्रावश्यकता है। इस प्रसंग में क्यौरेवार बातों में जाने का यहाँ स्थान नहीं है। हमें विशेष वक्तव्य यही है कि श्रन्य विषयों की मांति इनमें राज्य श्रीर नागरिकों में खूब सहयोग होना चाहिए। जिस सीमा तक ये कार्य नागरिकों द्वारा हो सकें, राज्य उन्हें सहायता श्रीर प्रोत्साहन दे, तदुपरान्त जो कार्य राज्य के करने का हो, उसे वह सम्पादन करे। रूस में बड़े पैमाने की खेती श्रीर सिंचाई श्रादि का कार्य राज्य द्वारा किया जाता है। देश-काल का विचार कर, जहां इस विषय की श्रनुकूलता हो, ऐसा करने का विचार होना चाहिए। निदान, राज्य को जनता की श्रार्थिक उन्नति के विविध उपायों को काम में लाना चाहिए।

श्रव श्रार्थिक हित-साधन की दूसरी बात का विचार करें। प्राचीन काल में विविध वस्तुएँ बनाने का काम प्रायः छोटे पैमाने पर होता था, एह-शिल्प का प्रचार था, मालिक-मज़दूर का ऐसा मेद-भाव न था, पूँजीपित श्रीर निर्धन की विषमता न थी। किन्तु, जब से भाफ या बिजली श्रादि से चलनेवाली मशीनों या यंत्रों का प्रचार हुश्रा, उत्पादन-कार्थ बड़े पैमाने पर होने लग गया। पूँजीपित श्रीर श्रम-जीवियों का श्रन्तर बढ़ चला। श्रमजीवियों की स्थिति शोचनीय हो गयी। कालान्तर में कारखानों सम्बन्धी कानृन ('फेक्टरी-ला') बनाये गये। राज्य का नियंत्रण श्रधिक होने लगा। नियंत्रण से स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार हुए, कुळ, श्रसुविधाएँ भी दूर हुईं, पर श्रार्थिक विषमता तो बनी ही रही। एक श्रोर पूँजीपित ऐरवर्थ

के सब साधनों का उपयोग करते हुए भी प्रतिमास हजारों रुपये बैंक में जमा करे, श्रीर दूसरी श्रोर मज़दूर को श्रपने परिवार के जीवननिर्वाह के लिए भोजन-वस्त्र की भी कमी रहे, (उसके बालकों की शिक्षा श्रादि की बात ही क्या)! ऐसी परिस्थित के कारण, गत वर्षों में विचारशीलों का ध्यान श्रार्थिक विषमता दूर करने की श्रोर गया है। इसी का परिणाम समाजवाद की उत्पत्ति तथा प्रचार है, जिसके सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। समाजवादी चाहते हैं कि राज्य ही खेती श्रीर उद्योग-धन्धों श्रादि की व्यवस्था करे तथा उत्पन्न समग्री को नागरिकों में इस प्रकार वितरण करे कि सबकी श्रावश्यकताएँ पूरी हो जायँ।

राज्य के लोक-हितकर कार्यों की कोई निर्धारित सूची नहीं बनायी जा सकती। ये कार्य देश-काल के अनुसार घट-बढ़ सकते हैं। राज्य को चाहिए कि नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की यथेष्ट ज्यवस्था करे।

# सतरहवाँ परिच्छेद

# सरकार के अङ्ग

- SEE

पिछले परिच्छेद में राज्य के कार्यों का विचार किया गया है।
राज्य जो कार्य करता है, वे सरकार द्वारा ही किये जाते हैं। सरकार
किसे कहते हैं, उसमें श्रीर राज्य में क्या श्रन्तर है, यह नवें परिच्छेद
में बताया जा चुका है। श्रव हमें यह विचार करना है कि सरकार के
भिन्न-भिन्न श्रङ्ग कौन-से हैं, श्रीर सरकार का गठन किस प्रकार
होता है।

सरकार के कार्यों के भेद-- सरकार के अज्ञों को जानने के लिए उसके कार्यों का जान प्राप्त करना आवश्यक है; सरकार के भिन्न-भिन्न श्रृङ्ग, उसके कार्यों की दृष्टि से होते हैं। सरकार को अनेक कार्य करने होते हैं, इन कार्यों की संख्या देश-काल के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। परन्तु वे कार्य चाहे जितने हों, और सरकार का स्वरूप भी चाहे जैसा हो, उसके कार्यों के तीन भेद किये जा सकते हैं। सरकार का कोई भी कार्य हो, वह तीन भेदों में से किसी

न किसी के अन्तर्गत होता है। (१) सरकार देश-रत्ता, तथा नागरिकों की शान्ति और सञ्यवस्था के लिए कानून बनाती है, और पुराने कानूनों में देश-कालानुसार परिवर्तन या संशोधन करती है यह कार्य व्यवस्था-कार्य कहलाता है। (२) सरकार राज्य की निर्घारित व्यवस्था को कार्य में परिखत करती है, उसे अमल में लाती है, वह देश की बाहरवालों के आक्रमण से रचा करती है, और भीतर शान्ति श्रीर सुप्रबन्ध रखती है। सरकार नागरिकों से क़ानून का पालन कराती है, श्रीर क़ानून भंग करनेवालों को दंड देती है। इन कार्यों के लिए सेना तथा पुलिस रखी जाती है तथा जेलों का प्रबन्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार नागरिकों की भलाई और उन्नति के लिए शिक्षा. स्वास्थ्य, चिकित्सा, न्यापार, उद्योग श्रादि से सम्बन्ध रखनेवाली विविध संस्थात्रों का संचालन करती है। यह कार्य शासन-कार्य कहलाता है। (३) सरकार लोगों के क़ानूनी अधिकारों की रक्षा करती है। वह नागरिकों के पारस्परिक वाद-विवाद का निपटारा करती है। वह यह निर्णय करती है कि आपस में भगड़नेवाले दो व्यक्तियों (या संस्थाश्रों ) में किस का पच्च क़ानून के श्रनुसार ठीक है, श्रीर कौन गलती कर रहा है। यह कार्य न्याय-कार्य कहलाता है।

सरकार के प्रत्येक कार्य का पहत्व—पाचीन काल में अनेक स्थानों पर राजा की इच्छा ही क़ानून थी। अब यह बात बहुत कम रह गयी है, और लोक-जायित के साथ-साथ इसके उदाहरण कम रहते जाते हैं। अस्तु, प्राचीन काल में सरकार के कार्यों में

व्यवस्था का स्थान चाहे गौण रहा हो, अब तो इसका महत्व अधिका-धिक हो चला है। कितने ही राजनीतिज्ञों का मत है कि सरकार के कार्यों में सबसे श्रधिक महत्व क़ानुन-निर्माण कार्य को दिया जाना चाहिये। शासकों का कार्य इसी पर निर्भर है, जो शासन नीति निर्धा-रित होगी. उसके अनुसार ही तो शासकगण राज्य में प्रबन्ध-कार्यः करेंगे । विद्धान्त से यह बात बहुत-कुछ ठीक ही है । तथापि व्यवहार की बात लीजिए । युद्ध, संघि, पर-राष्ट्र-सम्बन्ध त्रादि कितने ही महत्व-पूर्ण कार्यों में शासक प्रायः स्वतंत्रता-पूर्वक काम कर लेते हैं, बात-बात में व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता। सेना और पुलिस पर शासकों का अधिकार रहता है, और ये अपने आचरण से नियमों की कठोरता को सहज ही घटा अथवा बढा सकते हैं। जनता को इतना नियमों से प्रयोजन नहीं, जितना इस बात से है कि नियमों का व्यवहार किस तरह किया जाता है। अच्छा शासक, बुरे नियम के होते हुए भी, जनता से ऐसा व्यवहार कर सकता है कि लोगों को वह नियम विशेष रूप से न ऋखरे। पुनः किसी भी राज्य में शासकों की संख्या बहुत अधिक रहती है। भिन्न-भिन्न शासन-विभागों में छोटे-बड़े पदों पर काम करनेवाले व्यक्ति, चार-पाँच करोड़ की जन-संख्या वाले राज्य में, लाखों होते हैं। जनता को दिन-रात इन्हीं से काम पड़ता है। क़ान्न बनानेवालों से तो बहुत कम लोगों का परिचय होता है।

न्यायकर्तात्रों की भी संख्या, शासनाधिकारियों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इनसे भी कुछ थोड़े-से आदिमयों को ही काम पड़ता है, श्रीर वह भी कभी-कभी ही। तथापि कुछ राज्यों में न्यायालय की शिक्त का महत्व बहुत श्रिविक है। उदाहरणवत् श्रमरीका के संयुक्त राज्य में उच्च न्यायालय को यह निर्णय करने का श्रिविकार है कि कोई क़ानून वहाँ की शासन-पद्धति के श्रनुसार बना है या नहीं। इस प्रकार वह क़ानून बनानेवालों के निश्चय को रह कर सकता है, श्रीर इस श्रर्थ में वह उनकी श्रमेक्षा श्रिविक समर्थ श्रीर श्रिविकार- युक्त है।

निदान व्यवस्था, शासन, श्रीर न्याय इन तीनों का श्रपना-श्रपना महत्व है, प्रत्येक श्रपने चेत्र में प्रधान है।

सरकार के अङ्ग- सरकार के तीन कार्य हैं: - व्यवस्था, शासन और न्याय। कहीं-कहीं हनमें से दो या अधिक कार्य सरकार के एक ही अङ्ग द्वारा भी किये जाते हैं, तथा पिविषय-विवेचन की सुविधा के लिए हमें हनमें से प्रत्येक कार्य के करनेवाले, सरकार के अङ्ग का पृथक् पृथक् विचार करना उचित है। सरकार का जो अङ्ग कानून बनाता है उसे व्यवस्थापक मंडल (व्यवस्थापक समा) कहते हैं, शान्ति और सुप्रवन्ध करनेवाला अङ्ग शासक वर्ग, प्रवन्धकारिणी या कार्यकारिणी कहलाता है, और निर्णय या न्याय करने वाला अङ्ग न्यायाधीश वर्ग कहा जाता है।

प्रत्येक श्रङ्ग के श्रावश्यक गुण् — सरकार के इन तीन श्रङ्गों में से प्रत्येक के कार्यकर्ताश्रों में भिन्न-भिन्न गुणों की श्रावश्यकता होती है। व्यवस्थापक सभा एक विचार करनेवाली संस्था है। उसके सदस्यों में दूरदर्शिता, तथा व्यापक हिन्दकोण होना चाहिए, जिससे वह यह सोच सके कि अमुक नियम का, समाज के भिन्न-भिन्न अङ्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भिन्न-भिन्न स्वार्थ, मत या समूह के व्यक्ति उसे किस भाव से प्रह्मा करेंगे। शासकों को क़ानून अमल में लाना होता है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार काम करना है, उनमें विचार करने की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कार्य-तत्परता की। न्यायाधीशों को नियम का जाता होने की आवश्यकता हैं, साथ ही उनमें यह भी गुण चाहिए कि वे यह निर्णय कर सकें कि अमुक नियम का प्रयोग, किस स्थित में किस प्रकार करना ठीक होगा।

श्रव हम सरकार के प्रस्पेक श्रंग के विषय में कुछ विशेष विचार करते हैं। पहले व्यवस्थापक मंडल को लें।

व्यवस्थापक मंडला—समाज में अनेक जातियों, मतों, स्वाथों और सम्प्रदायों के आदमी होते हैं। नियम या कानून बनाते समय इन सबके हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः जितने अधिक हिष्टिकोणों से विचार हो सके, अञ्झा है। और, विचार करने के लिए एक व्यक्ति की अपेक्षा दो, और दो की अपेचा दस व्यक्तियों का होना बेहतर है। इस प्रकार व्यवस्थापक सभा में जितने अधिक सदस्य हों, अधिक हिष्टिकोणों को सूचित करनेवाले हों, उतना ही अञ्झा है। हों, इसकी भी एक मर्यादा है, सदस्य-संख्या बहुत बड़ी होने पर विचार में बाघा उपस्थित होती हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं। अस्तु, यह निश्चय करना बहुत ही कठिन है कि व्यवस्थापक सभा में कितने सदस्यों का होना ठीक होगा। इंगलैंड की प्रतिनिधिस्मा (हाउस-आफ-कामन्स) में ६१५ सदस्य हैं, और भारतवर्ष

की व्यवस्थापक सभा ( इंडियन लेजिस्लेटिव एसेम्बली ) में १४३ । संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापक सभा में इस समय २२८ सदस्य हैं।

व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या बहुत श्रिषक होने से विषय के गम्भीरता-पूर्वक विचार किये जाने में जो बाधा उपस्थित हो सकती है, उसके निवारण के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों ने अपने-अपने श्रम्भव के श्राधार पर भिन्न-भिन्न विधियाँ श्रवलम्बन की हैं। आज-कल उन्नत राज्यों में, प्रायः क्रानून के मसौदे को व्यवस्थापक सभा में तीन बार पढ़े जाने की पद्धति है, जिससे किसी विषय का एकदम निर्णय न हो जाय, श्रीर सदस्यों को उस पर श्रन्तिम विचार करने के लिए काफी समय मिल जाय।

बहुत-से राज्यों में, केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में, श्रीर कुछ राज्यों में तो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में भी एक ही सभा न होकर दो सभाएँ होती हैं:—(१) निचली सभा (लोग्नर हाउस) श्रीर (२) ऊपरली सभा (श्रपर हाउस)। इनके सम्बन्ध में पहले (चौदहवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है। इनमें से निचली सभा में जनसायरण के प्रतिनिधि रहते हैं, श्रीर ऊपरली सभा में विशेष धनी-मानी सजनों के। कुछ राजनीतिज्ञों का मत है कि ऊपरली सभा उठा दी जानी चाहिए; कारण, जब कभी दोनों सभा श्रों में बहुत मत-मेद हो तो संकट उपस्थित होने की सम्भावना हो जाती है। विगत वर्षों में ऊपरली सभा की शक्त बहुत परिमित कर दी गयी है, विशेषतया आर्थिक विषयों में उसका श्रधिकार नाममात्र का रह गया है। तथापि जिन राज्यों में दो सभाओं की पद्धित थी, उन्होंने उसकी जगह एक सभात्मक

पद्धति अवलम्बन नहीं की । इससे विदित होता है कि क़ान्न-निर्माण में जल्दबाज़ो रोकने आदि के लिए दूसरी सभा की उपयोगिता मानी जाती है। कितने-ही देश यह सोचते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति को उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक श्रृङ्खला बनाये रखेगी और आकर्रिमक परिवर्तन न होने देगी।

व्यवस्थापक मंडल के संगठन का आधार (१) निर्वाचन, (२) वंश और (३) नियुक्ति या नामज़दगी होता है। निचली सभा में निर्वाचन को ही महत्व दिया जाता है; वंश की प्रधानता अब जन-तन्त्रता के युग में नहीं रही, और नामज़दगी किसी विशेष दशा में ही होती है। ऊपरली सभा में, विशेषता वंश की रहती है; चुनाव में ऐसी शर्त रहती है कि अमुक परिमाण में सम्पत्ति रखनेवाला, अथवा हतना टैक्स या मालगुज़ारी देनेवाला ही निर्वाचक हो। ये निर्वाचक भी धनी-मानी या उच्च कुलोत्पन्न व्यक्तियों को बहुधा निर्वाचित करते हैं। निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तार से एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा जायगा।

शासक-वर्ग — शासक वर्ग सरकार का वह अंग है, जो व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये हुए क़ानून को अमल में लाता है, तथा नागरिकों द्वारा उस पर अमल कराता है। यह देश की रक्षा करता है, तथा मीतर शान्ति और सुप्रवन्ध रखता है। सर्वोच्च शासक प्रायः एक व्यक्ति होता है, जिसे राजतन्त्र में बादशाह या राजा आदि कहते हैं, और प्रजातंत्र में राष्ट्र-पित, अध्यक्ष या प्रेसीडैन्ट आदि। कहीं-कहीं, जैसे स्विटज्रलैंड में, सर्वोच्च-शासक एक व्यक्ति न होकर एक सभा होती है।

वैध राजतंत्रों में जब सर्वोच्च श्रिषकारी एक व्यक्ति होता है, तो उसे व्यवहार में नाम मात्र के ही श्रिषकार रहते हैं। उदाहरण्यावत् जैसा कि श्रम्यत्र बताया गया है, हंगलेंड में बादशाह श्रपने प्रधान मन्त्री के परामर्श बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके विपरीत, प्रजातंत्रों में सर्वोच्च शासक को बहुत श्रिषकार रहता है, जैसे कि संयुक्त-राज्य श्रमरीका में राष्ट्र-पित को है। राजतंत्र में प्रधानशासक प्रायः पुश्तेनी होता है, श्रमीत् पिता के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का श्रिषकारी होता है। परन्तु प्रजातन्त्र में वह व्यवस्थापक मंडल श्रथवा जनता (निर्वाचकों) द्वारा चुना जाता है।

जब सर्वोच-शासक (कोई समा न होकर) एक व्यक्ति होता है
तो उसकी सहायता के लिए एक सभा होता है, इसे कहीं मन्त्री-मंडल
( 'केबिनेट') कहते हैं, और कहीं प्रवन्धकारिणा। इंगलैंड में मंत्री-मंडल का संगठन वादशाह प्रधान मन्त्री के परामर्थानुसार करता है,
और प्रधान मन्त्री वह व्यक्ति होता है, जो प्रतिनिधि-सभा के बहुसंख्यक-दल का नेता हो। मन्त्री-मंडल के सब सदस्य प्रतिनिधि-सभा
या सरदार-सभा के सदस्य होते हैं, ओर पार्लिमेन्ट के प्रति, अपने
प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त-राज्य अमरीका में
राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रवन्धकारिणी सभा है; उसके सब सदस्यों
को राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार चुनता है। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं; व्यवस्थापक मंडल के प्रति नहीं। वे व्यवस्थापक मंडल
के सदस्य भी नहीं होते।

प्रबन्धकारिशी या मन्त्री-मंडल के अधीन कई विभाग (डिपार्टमेंट)

होते हैं। एक विभाग देश की, बाहर के आक्रमणकारियों से, रक्का करने के लिए सेना का प्रबन्ध करता है। सेना तीन प्रकार की होती है:--जल-सेना, स्थल-सेना श्रीर वायु-सेना, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। श्रस्तु, यह विभाग रक्षा-विभाग या सेना विभाग कह-लाता है। दसरे विभाग का कार्य देश के भीतर शान्ति श्रौर सुप्रवन्ध रखना है। यह पुलिस आदि की व्यवस्था करता है। इसे स्वदेश विभाग, या गृह-विभाग ( 'होम डिपार्टमैंट' ) कहते हैं। एक श्रीर महत्व-पूर्ण विभाग है, अर्थ विभाग। यह विभाग राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के वार्षिक श्राय-व्यय का चिट्ठा श्रर्थात् वजट बना कर उसे व्यवस्थापक मंडल में उपस्थित करता है, श्रौर उसकी स्वीकृति के अनुसार सर्व-साधारण से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त करता है. श्रीर प्राप्त श्राय को ख़र्च करता है। एक विभाग का काम यह होता है कि अन्य राज्यों से सम्बन्ध बनाये रखे, वहाँ अपना राजदृत रखे, जो वहाँ राज्य के हितों की रक्षा करता रहे। यह विभाग विदेश-(या वैदशिक) विभाग कहलाता है। इनके श्रातिरिक्त राज्य में श्रीर भी कई विभाग हो सकते हैं, यथा कानून-विभाग, शिक्षा-विभाग, कृषि-विभाग, डाक-विभाग, तार-विभाग, उद्योग-विभाग, स्वास्थ्य-विभाग श्रादि । राज्य में प्रबन्ध-कार्य की गुरुता देखकर यह निश्चय किया जाता है कि वहाँ शासन सम्बन्धी कुल कितने विभाग हों, कौनसा विभाग पृथक् या स्वतंत्र रूप से रहे, श्रीर कौनसा विभाग किस दूसरे विभाग के साथ मिला हुआ हो। प्रत्येक विभाग या विभाग-समृह प्रबन्धकारिगा के एक-एक सदस्य, अथवा एक-एक

मंत्री के सुपुर्द रहता है। देश-काल के श्रनुसार किसी विभाग का कार्य तथा महत्व घटता-बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्रबन्धकारिया। या मंत्री-मंडल के सदस्यों की संख्या भी बदलती रहती है।

प्रत्येक विभाग में, मंत्री के श्रधीन कितने-ही स्थायी कर्मचारियों की श्रावश्यकता होती है। जैसा कि हमारी 'ब्रिटिश साम्राज्य शासन' में बताया गया है, मंत्री तो अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्घारित करता है, उस नीति के अनुसार शासन-कार्य करना सरकारी कर्मचारी का काम है। ये कर्मचारी अपने पद पर बराबर बने रहने के कारण अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत-सी बारीकियों को जानते हैं। मंत्री-मंडल, समय-समय पर, नये निर्वाचन के बाद बदलते रहते हैं। नये मंत्री नियुक्त होते हैं. इन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने कार्य के लिए उक्त कर्मचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कर्मचारियों की ही बदौलत शासन-कार्य का सिलिसला जारी रहता है, ट्टता नहीं। अस्तु, यदि कोई मंत्री अपने विभाग की भीतरी बातों में इस्तत्तेप करने लगे तो सरकारी कर्मचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बातें बतला सकते हैं कि मंत्री कागजों के बोक्त से दब जाय. उसे पार्लिमेंट के आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे, और अन्त में लाचार होकर उसे सरकारी कर्मचारियों की ही शरण लेनी पड़े।

इससे इन कर्मचारियों का महत्व स्पष्ट है। प्रत्येक विभाग के मुख्य कर्मचारियों की नियुक्ति या तो खास परीक्षाएँ लेकर होती है, या चुनाव द्वारा। इंगलैंड में सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा की पद्धित प्रचलित है, अर्थात् जिस वर्ष जितने कर्मचारियों की आवश्यक-ता होती है, उस वर्ष उतने आदमी उन व्यक्तियों में से ले लिये जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, और क्रमानुसार अधिक-से-अधिक नम्बर पाये हों। इनका वेतन निश्चित रहता है, और क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से पृथक् नहीं किये जा सकते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहें।

शासक-वर्ग राज्य के शासन-सूत्र को संभालनेवाला होता है।
नागरिक जीवन में उसकी शक्ति का परिचय पद-पद पर मिलता है।
किसी-न-किसी शासन-विभाग से नागरिकों को हर समय काम पड़ता
है। शासकों की उच्छुङ्खलता से राज्य का हास होने लगता है।
अतः यह बहुत आवश्यक है कि उन पर यथेष्ट नियंत्रण रखा जाय।
यही कारण है कि उन्नत और विकसित राज्यों में शासक पूर्णतया
व्यवस्थापकों अथवा निर्वाचकों के प्रति उतरदायी बनाये जाते हैं।
जिस समय यह जान पड़ता है कि शासक अपना कर्तव्य ठीक
तरह पालन नहीं करते, उन्हें उनके पद से इटाने का प्रयत्न किया
जाता है। बहुत-से अनुभवों से मंत्री-मंडल को पद-ज्युत करने के
लिए एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो गया है। वैभ
राजतंत्र या लोकतंत्र राज्य में व्यवस्थापक सभा को असन्तुष्ट देलकर
या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने पर त्याग-पत्र दे देते हैं।

बड़े राज्यों में शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा जिलावार होता है (छोटे राज्यों में केवल केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासक रहते हैं)। अपने-अपने होत्र में निर्धारित अधिकार रखते हुए, जिलों के शासक

तो प्रान्तीय शासक के अधीन होते हैं, श्रीर प्रान्तीय शासक, देश-काल के अनुसार, कुछ बातों में केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं।

न्यायाधीश-वर्ग — न्यायाधीशों का काम है कि विवाद करनेवाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विषय में यह निश्चय करें कि कानून के अनुसार किस का पक्ष ठीक है, और कौन गलती पर है, तथा, किस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ने अपने कार्य-व्यवहार से कानून मंग किया है। कानून मंग करनेवालों के लिए दंड निर्धारित किया जाता है, अथवा उनके सुधार का उपाय बताया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति किसी कानून का अर्थ अलग-अलग लगाते हैं; वास्तव में कानून का अर्थ क्या होना चाहिए, इसका निश्चय न्यायाधीश करते हैं। संघ-न्यायालयों को छोड़कर (जो संघ-शासनवाले राज्यों में होते हैं), अन्य न्यायालय कानून की जाँच करके यह निर्णय नहीं दे सकते कि अमुक कानून ठीक है, या नहीं; वह शासन-विधान के अनुसार है, या नहीं। वे केवल इतना ही कह सकते हैं, कि जो कानून बना हुआ है, उसका अर्थ क्या लिया जाना चाहिए।

इस बात की बड़ी श्रावश्यकता है कि न्यायाघीश श्रपना कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक कर सकें । बहुधा ऐसा प्रसंग श्रा जाता है कि नागरिकों का स्वयं शासकों से ही किसी विषय में मत-मेद श्रयवा विरोध होता है। ऐसी दशा में यह काम न्यायाधीश-वर्ग का है कि उचित निर्णय दें। स्वतंत्र न्यायाधीश ही नागरिकों के श्राधकारों की समुचित रक्षा, कर सकते हैं, श्रन्यया उनके द्वारा शासकों के त्रुटि-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने की श्राशंका रहती है। इस प्रकार न्यायाधीशों का कार्य बड़े उत्तरदायित्व का है। इसिलए उनकी नियुक्ति बहुत सावधानी से होने की श्रावश्यकता है।

नियुक्ति के तीन प्रकार हैं:--(१) न्यायाधीशों को व्यवस्थापक सभा द्वारा चुना जाता है। यह दङ्ग स्पिटज़रलैंड में प्रचलित है। इसमें श्रापत्ति यह है कि न्यायाधीश-वर्ग श्रीर व्यवस्थापक मंडल एक-दसरे से श्रलग नहीं रह सकते, न्यायाधीशों पर व्यवस्थापको का प्रभाव पड़ता है, श्रीर यह प्रभाव कुछ दशाश्रों में बहुत श्रनुचितः भी हो सकता है। (२) वे जनता (निर्वाचकों ) द्वारा चुने जाते हैं। यह समभा जाता है कि इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव होगा। संयुक्त-राज्य श्रमरीका में यह पद्धति बर्ती जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि इस पद्धति से बहुधा ऐसा भी होता है कि श्रच्छे व्यक्ति चुनाव में श्रास्पत्त रह जाते हैं, और उनसे कम योग्य, किन्तु कुछ अधिक चलते हुए तथा मेल मुहब्बतवाले, आदमी विजयी हो जाते हैं। निर्वाचन-पद्धति में यह दोष है ही कि बहुत-से आदमी उम्मेदबार की योग्यता का समुचित विचार न कर अपनी जाति. सम्प्रदाय अथवा मेल-मुलाहजे आदि का विचार करते हैं। जो व्यक्ति इन विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, उन में से भी कितने-ही दलबन्दी के भाव से मुक्त नहीं हो सकते। वे अपनी पार्टी के एक कम योग्य अथवा अयोग्य व्यक्ति को, दूसरी पार्टी के अधिक योग्य व्यक्ति से, बेहतर समभाने लगते हैं। फिर जनता (निर्वाचकों) द्वारा न्यायाधीशों के चुने जाने की दशा में सबसे अञ्छे व्यक्तियों के चुनाव में आपने की श्राशा बहुत नहीं रहती। (३) श्रधिकौंश राज्यों में न्यायाधी**शो**ं

की नियुक्ति सर्वोच शासक द्वारा की जाती है। उदाइरणवत् इंगलैंड के उच न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के बादशाह द्वारा, श्रीर संयुक्त-राज्य श्रमरीका के उच न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारतवर्ष में संघ-न्यायालय तथा हाईकोटों के जजों को सम्राट् (इंगलैंड का बादशाह) नियुक्त करता है। न्यायाधीशों का पद स्थायी होता है। केवल दुराचार, या शारीरिक श्रथवा मानसिक निर्वेलता की दशा में ही वे श्रपने पद से हटाये जा सकते हैं।

उच्च न्यायालयों को छोड़ कर अन्य न्यायालय प्रायः दो प्रकार के होते हैं :—दीवानी श्रीर फौजदारी। विशेषतया फौजदारी मामलों में यह सर्वथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश आभयोग को समुचित रूप से न समके, अथवा उसका निर्णय यथेष्ट विचार-पूर्ण न हो। श्रवः उन्नत राज्यों में निर्णय-कार्य अभियुक्त की जाति तथा देश के कुछ सुयोग्य सज्जनों की जूरी या पंचायत द्वारा होता है। जूरी यह विचार करती है कि श्रमियोग सम्बन्धी वास्तविक घटनाएँ क्या है। जूरी के मत के आधार पर, जज तत्सम्बन्धी कानूनी निर्णय स्चित करता है। छोटी अदालतों के निर्णय के विश्व, उनसे बड़ी श्रदालतों में अपील हो सकती है। प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, जहाँ उस राज्य के अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों की अपील सुनी जाती है।



# अठारहवाँ परिच्छेद

## श्कि-पार्थक्य और अधिकार-विभाजन

- 100 March

पिछते परिच्छेद में सरकार के तीनों श्रंगों के विषय में श्रावश्यक बातों का विचार हो चुका । श्रव यह देखना है कि (१) इन श्रंगों की शांक कहाँ तक एक-दूसरे से पृथक् रहे, श्रीर कहाँ तक परस्पर में सम्बन्धित हो । (२) राज्य के किस चेत्र पर इन शांकियों का कहाँ तक श्रिषकार हो; केन्द्रीय प्रांतीय श्रीर स्थानीय सरकारों में श्रधिकार किस प्रकार विभाजित हों।

## शक्ति-पार्थक्य

सरकार के प्रत्येक श्रङ्क की शक्ति दूसरे श्रङ्क की शक्ति से पृथक् रहे, उनकी श्रापस में धनिष्टता न हो, इसे शक्ति-पार्थक्य\* सिद्धान्त कहते हैं। प्राचीन काल से श्रनेक लेखकों ने इसके सम्बन्ध में श्रपना

<sup>\*</sup>Seperation of Powers.

मत सूचित किया है। आधुनिक लेखकों में मानटेस्क्यू इस िखाँत का विशेष प्रतिपादक माना जाता है। उसने लिखा है:—'यदि व्य-वस्थापक और शासन-शक्ति इकट्ठी एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के पास रहे तो स्वतंत्रता विलकुल नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का भय रहेगा कि व्यवस्थापक समा या राजा अत्याचार-पूर्ण क़ानून बनाये, तथा उनका अत्याचार-पूर्ण रीति से प्रयोग करे। इसी प्रकार यदि न्याय-शक्ति व्यवस्थापक और शासन-शक्ति से पृथक् न हो, तो भी स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। यदि न्याय-शक्ति को व्यवस्था पक-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो नागरिकों का जान-माल सुरक्षित रहने का भरोसा न रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश ही क़ानून बनानेवाला होगा। यदि न्याय-शक्ति को शासन-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो नागरिकों का जान-माल सुरक्षित रहने का भरोसा न रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश ही क़ानून बनानेवाला होगा। यदि न्याय-शक्ति को शासन-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो न्यायाधीश में अत्याचार करने की शक्ति आ जायगी।

इसका अर्थ यह है कि सरकार की तीनों शक्तियों को अलग-अलग रहना चाहिए, उनके सम्मिलित हो जाने से नागरिकों की स्वतन्त्रता न रह सकेगी। योरप के कई राज्यों की, और विशेषतया संयुक्त-राज्य अमरीका की शासन-पद्धति इसी सिद्धान्त पर बनायी गयी है। अमरीका की शासन-पद्धति में इस बात का होना चौदहवें परिच्छेद में दर्शाया जा जुका है।

सिद्धान्त से सरकार के तीनों श्रङ्ग श्रवश्य पृथक्-पृथक् हैं, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। इंगलैंड की शासन-पद्धति की बात लीजिए। साधारण हिंद से वहाँ सरकार के तीनों श्रङ्ग श्रलग-श्रलग

हैं; पार्त्तिमेंट क्रान्त बनाती है, मंत्री-मंडल शासन-कार्य करता है, श्रीर विवी कोंसिल वहाँ सर्वोच न्याय-संस्था है। परन्तु तनिक सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इन तीनों श्रङ्गों का परस्पर में काफ़ी सम्बन्ध है। पार्लिमेंट की दो सभाओं में से, सरदार सभा ( हाउस-आफ़-लार्डस् ) का सभापति लार्ड चान्छलर मंत्री-मंडल का खदस्य होता है, श्रीर पिनी कौंतिल का प्रधान भी । इस प्रकार एक न्यक्ति सरकार के तीनों श्रङ्गों के कार्य में महत्व-पूर्ण भाग लेता है। पुनः वहाँ मन्त्री-मंडल के सब सदस्य पार्लिमेंट के भी सदस्य होते हैं, श्रीर उसमें भाग लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में वहाँ शक्ति-पार्थक्य नहीं है। तीनों श्रङ्ग एक दूसरे से बहुत सम्बन्धित हैं, एक का दूसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अन्य राज्यों की शासन-पद्धति पर गम्भीर विचार करने से वहाँ भी यही बात प्रतीत होती है। उत्तरदायी शासन-पद्धति में व्यवस्थापक मंडल शासन-कार्य का निरीक्षण और नियन्त्रण करता है, और अपने श्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव द्वारा शासक-वर्ग को पदच्युत कर सकता है। न्यायाधीश-वर्ग कानून का अर्थ लगाते समय कानून की तुटियों का संकेत करते हैं, इस प्रकार क़ानून के संशोधन अथवा नये क़ानून बनाने में सहायक होते हैं।

जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न श्रङ्गों का श्रपना-श्रपना कार्य-चेत्र पृथक पृथक होते हुए भी, सब एक-दूसरे के सहायक रहते हैं। इसी प्रकार सरकार के तीनों श्रङ्गों की कार्य-कुशलता भी तीनों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। कल्पना करो, व्यवस्थापक मंडल ने एक क़ानून बनाया श्रीर शासक-वर्ग ने उसका नागरिकों द्वारा पालन कराने में उपेचा की, श्रयवा न्यायालय ने उस कानून मंग करनेवाले के लिए दंड निर्धारित नहीं किया तो कानून की मर्यादा क्या रही। श्रयवा, जब न्यायालय ने किसी श्रयराधी के लिए दंड निर्धारित ही कर दिया परन्तु शासक-वर्ग ने न्यायालय के निर्णय के श्रवसार श्रयराधी को केद में नहीं रखा या उससे जुर्माना वसून नहीं किया तो नागरिकों को दृष्टि में न्यायालय का क्या सम्मान रहा हिशी प्रकार, यदि न्यायालय शासकों के प्रत्येक कार्य के विरुद्ध निर्णय देने लगें, तो शासकों की प्रतिष्ठा क्या रहे, शासन-कार्य का संचालन ही कैसे हो ! निदान, जब सरकार के तीनों श्रङ्कों में सहयोग न हो तो राज्य में कुव्यवस्था होगी; राज्य-निर्माण का उद्देश्य ही नए हो जायगा। हाँ, यह श्रावश्यक है कि कोई एक श्रङ्क इतना श्रविकार युक्त न हो जाय कि वह दूसरे श्रङ्कों पर श्रनुचित प्रभाव डाल सके।

सरकार की शक्तियों का पार्थक्य कहाँ तक होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो सब राज्यों में ठीक रहे। प्रत्येक राज्य की परिस्थिति भिन्न-भिन्न होती है, श्रौर वहाँ देश-काल के श्रनुसार ही शक्ति पार्थक्य हो सकता है। हाँ, कुछ बातें हर जगह विचारणीय है। न्यायाधीश-वर्ग के पार्थक्य तथा स्वतंत्रता में सब राजनीतिज्ञ सहमत हैं, न्यायालय पर किसी का प्रभाव न पड़ना चाहिए। व्यावस्थापक मंडल को शासक-वर्ग के नियंत्रण का यथेष्ट श्रिषकार होना चाहिए; जनता पर कर लगाने तथा सार्वजनिक द्रव्य को ख़र्च करने के विषय में व्यवस्थापक मंडल ही श्रिषकारी होना चाहिए।

#### अधिकार-विभाजन

र अब इस इस बात का विचार करना चाइते हैं कि राज्य में, केन्द्रीय, प्रान्तीय श्रीर स्थानीय सरकारों में श्रिधकारों का विभाजन कैसे होता है. इस विषय में सिद्धान्त क्या है, तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अधिकार-विभाजन का प्रश्न विशेष रूप से बड़े राज्यों में ही उपस्थित होता है। श्राधनिक काल में राज्यों का विस्तार बढने की सुविधा श्रौर प्रवृत्ति तो श्रधिक है ही, श्रब उनका कार्य-तेत्र भी पहले की अपेक्षा बहत बढा हुआ है। अतः अधिकार-विभाजन समस्या ने वर्तमान राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। इस समय बड़े-बड़े राज्य अपनी सीमा और चेत्र के अन्तर्गत उपस्थित होने वाले शासन-सम्बन्धी समस्त विषयों पर, केन्द्रीय संसार द्वारा. यथेष्ट ध्यान नहीं दे सकते । ऐसा करना बहुत कठिन है, यदि इसका प्रयत्न भी किया जाय तो शासन-प्रबन्ध जैसा चाहिए वैसा न हो सकेगा। श्रतः यह श्रावश्यक हो गया है कि केन्द्रीय सरकार, जितने कार्यों का दायित्व स्थानीय सरकारों को दे सके, दे दे। इससे उसका कार्य-भार इल्का होगा, श्रीर कार्य भी श्रच्छी तरह सम्पादित होगा 🗡

्श्राधुनिक राज्यों में बहुचा ऐसा होता है कि जिन विषयों का सम्बन्ध समस्त राज्य से होता है, या जिनका सम्बन्ध उस राज्य और अन्य राज्य (या राज्यों) से होता है, उन विषयों सम्बन्ध अधिकार केन्द्रीय सरकार को होता है, और जिन विषयों का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष के व्यक्तियों से होता है, वे स्थानीय सरकार को

सोंपे जाते हैं। इस प्रकार विदेश-नीति, देश-रक्षा, आयात-निर्यात, सिक्का, डाक, तार, यातायात के बड़े साधन (बड़ी रेल, जहाज आदि), मनुष्य-गण्यना आदि विषय केन्द्रीय होते हैं, इन पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार रहता है, और सड़क, नल, रोशनी, आदि विषय स्थानीय माने जाते हैं; इनके सम्बन्ध में अधिकार स्थानीय सरकारों को दिया होता है।

संघात्मक राज्यों में शासन-विधान में ही यह स्पष्ट लिखा रहता है कि अमुक-अमुक विषयों में केन्द्रीय सरकार का अधिकार है और अमुक-अमुक विषयों में संघान्तरिक सरकारों का । इसमें न तो संघ-सरकार ही कुछ फेर-बदल कर सकती है, और न संघान्तरित सरकारें ही । किसी को दूसरे के चेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता । संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक में सरकार के कार्य का केन्द्रीय और स्थानीय मेद से विचार रहता है, इसका निर्णय संघान्तरित राज्य की सरकार करती है, और फलत: उसे इसमें समय-समय पर परिवर्तन करने का भी अधिकार होता है।

संघ-निर्माण का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति-वृद्धि श्रीर श्रात्म-रक्षा होता है। इसलिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि सेना के नियंत्रण का श्रिधकार संघ-सरकार को हो। पुन: श्रन्य राज्यों से व्यवहार करने में संघ को एक इकाई की भौति कार्य करना श्रावश्यक है। अतः विदेशों से जो सम्बन्ध हो, उसका भी निश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा होना चाहिए। युद्ध तथा विदेश-नीति के संचालन के लिए द्रव्य की श्रावश्यकता होती है। इसलिए यह श्रावश्यक है कि संघ सरकार को श्राने नागरिकों पर कर लगाने का निर्धारित श्रिषकार हो। कभी-कभी कुछ द्रव्य की श्रावश्यकता श्रकस्मात श्रा पड़ती है, यह श्रावश्यकता किसी सामायिक कार्य के लिए होतों है, जिसे तत्काल करना होता है। ऐसे कार्मों के लिए संब-सरकार को श्राण लेने का भी श्राधकार होना चाहिए।

इस प्रकार युद्ध श्रीर श्रात्म-रत्ता, बाहरी मामलों का नियंत्रण, श्रीर द्रव्य संग्रह करने की शक्ति ये तीन ऐसे त्रावश्यक कार्य हैं, जिनका अधिकार संघ-सरकार को रहे बिना संघ-राज्य बना ही नहीं रह सकता। संघ सरकार के करने के, दूसरी श्रेणी के कार्य वे हैं, जिनका राज्य भर के लिए समान रूप से होना लाभकारी होता है। उदाहर खवत् सिक्का, पेटंट ( कोई वस्तु बनाने का सर्वाधिकार ), मुद्रणाधिकार का नियंत्रण, डाक, तार, बेतार के तार का कार्य-संचालन। तीसरे दर्जे पर वे सार्वजनिक कार्य हैं, जिनमें यद्यपि समानता की अत्यन्त श्रावश्यकता नहीं है, तथापि राष्ट्र-हित की दृष्टि से उसकी बहुत उपयो-गिता है, जैसे यातायात के बड़े पैमाने के कार्य-रेल आदि, नहर, वैंकिंग. श्रीर यातायात-ग्रहक-निर्धारण । चौथी श्रेणी में ऐसे कार्य हैं जिनका संघ-सरकार के पास रहने या संघान्तरित राज्य के पास रहने के सम्बन्ध में राजनीतिशों में मत-मेद है। इनका विभाजन बहुत-कुछ संघ-राज्य की परिस्थिति पर निर्भर है, इनके उदाहरण शिचा-प्रचार, विवाद-शादी तथा सम्बन्ध-विच्छेद के विषय हैं। शेष कार्य संघान्तरित राज्यों के लिए छोड़ दिये जाने चाहिएँ। इनके सम्बन्ध में भी मत-भेद रहता है, तथापि इनमें स्थानीय उपयोगिता के

कार्यों का समावेश हो सकता है।

भारतवर्ष की स्थित कुछ निराली ही है। यह स्वतंत्र राज्य नहीं है। यहाँ प्रभुत्व-शिक्त बिटिश पार्लिमेंट में है। सम्राट् (इङ्गलैंड-नरेश) की श्रोर से यहां गवर्नर-जनरल तथा भारत-सरकार कार्य करते हैं। यहाँ संघ शासन की बात तो वास्तव में श्रभी कुछ वर्ष से चली है। यरन्तु देश बड़ा होने से केन्द्रोय सरकार, प्रान्तीय सरकारों को ख़ासे श्राधिकार दिये बिना, शासन-प्रबन्ध अच्छी तरह संचालित नहीं कर सकती थी। यद्यपि प्रान्तों को कुछ विशेष श्रिधिकार देने की बात पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद, सन् १९११ ई० से श्रारम्भ हुई, जब कि इस विषय में लोकमत काफी प्रवल हो गया था, प्रान्तीय सरकारों का श्रास्तत्व यहाँ पहले से रहा है। प्रान्तीय सरकारों को श्रपने चेत्र में निर्धारित श्रिधिकार मिले रहते थे; इन श्रिधिकारों से ही, भिन्न-भिन्न प्रान्तों में, भारत सरकार द्वारा प्रेरणा होने पर, स्थानीय संस्थाओं का कानून बनाया गया, जिसके श्रनुसार म्युनिस्पैलिटियों, श्रीर जिला-बोर्डों श्रादि की स्थापना की गयी। ✓

✓एकात्मक राज्यों में केन्द्रीय सरकार को मुख्य-मुख्य सब अधिकार होते हैं। वही यह निश्चय करती है कि स्थानीय कार्य क्या हों, और उनके करने के लिए कार्यकर्ताओं का संगठन किस प्रकार का रहे। बहुधा वही मुख्य-मुख्य स्थानीय अधिकारियों को नियत तथा बर्ख़ास्त करती है, तथा समय-समय पर उनके कार्यों और अधिकारों में परिवर्तन करती है। ✓

श्राज कल यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि स्थानीय विषयों का

चेत्र बढ़ता रहे; लोगों को अपनी स्थानीय आवश्यकता-पूर्ति के विषयों अधिकाधिक अधिकार हों, उनमें केन्द्रीय सरकार का इस्तचेप बहुत कम रहे। केन्द्रीय सरकार केवल यह व्यवस्था करे कि स्थानीय सरकारों में परस्पर कोई विवाद न हो। यदि विवाद उपस्थित हो तो उसे निपटा दिया जाय; राज्य की एकता में विश्न उपस्थित न हो। इससे अधिक केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण न रहे।

अधिकार-विभाजन की पद्धति—अधिकार-विभाजन के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं:—

- (१) केन्द्रीय राज्य क्वानून बना दे; उसके श्रनुसार, शासन-प्रबन्ध का कार्य स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाय।
- (२) केन्द्रीय राज्य साधारण नियम बनाने का कार्थ स्थानीयः संस्थाओं को सौंप दे, और उनके शासन-प्रबन्ध आदि का स्वयं निरीच्या करे।

पहली पद्धित में प्रायः होता यह है कि स्थानीय संस्थाओं को जो नियम अच्छे नहीं लगते, उन पर वे विशेष अमल नहीं करतीं, स्थानीय अधिकारी स्वच्छन्द हो जाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय संस्था उनके कार्य में इस्तच्चेप करती है; और, दोनों में विवाद बना रहता है। शासन शिथिल हो जाता है। आदमी अपने स्थानीय विषयों को महत्व देते हैं, और केन्द्रीय विषयों को उपेक्षा करने लगते हैं। हाँ, इस पद्धित में जनता की स्वतंत्रता बनी रहती है। वह स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उसे अपनेक आदमी अवैतिनक सेवा करनेवाले मिलते रहते हैं, सर्वसाधारणा

को सार्वजनिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत-से आदमी जब तक स्थानीय संस्था के पदाधिकारी होते हैं, शासन-कार्य करते हैं, और निर्घारित अवधि के पश्चात् अवकाश प्रह्रण करके सर्वसाधारण में मिल जाते हैं; यह नहीं होता कि सरकारी पदाधिकारियों की कोई स्थायी अेणी बनी रहे, जो अपने आपको सर्वसाधारण से पृथक् समके। इस प्रकार, जब जनता में अनेक आदमी ऐसे होते हैं जो समय-समय पर स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी रह चुकते हैं तो जनता को सार्वजनिक कार्य करने का अनुभव अधिक होता है, और साथ ही उसका मान भी, स्थायी शासकों की हिट में, अधिक होता है।

श्रव दूसरी पद्धति की बात लीजिए। इसमें केन्द्रीय सरकार का स्थानीय संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, स्थानीय श्रविकारी मनमानी नहीं कर सकते। शासन-प्रवन्ध विवाद-रहित श्रीर स्थिरता-पूर्वक चलता है। परन्तु स्थानीय जनता का श्रविकार नगण्य हो जाता है। उसके स्वार्थों श्रीर हितों की उपेक्षा की जाती है। स्थायी शासकों के कारण, सर्वसाधारण को सार्वजनिक कार्यों का विशेष श्रनुभव नहीं होता; जनता, श्रविकारियों की हिष्ट में, कम सम्मानित होतो है। स्थानीय संस्थाश्रों के कर्मचारी अपने उच्च श्रविकारियों को संतुष्ट करते रहते हैं; जब कि वास्तव में जनता उनकी श्राराध्य-देव होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों पद्धतियों में कुछ गुण हैं, तो कुछ दोष भी। प्रायः राज्य दोनों के बीच का मार्ग प्रहण करते हैं। पहली पद्धतिवाले राज्य स्थानीय संस्थाश्रों को नियम बनाने के

सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से कुछ मुक्त कर उन्हें इस विषय के अधिकार अधिकाधिक देते हैं। वे स्थानीय प्रबन्ध पर अपना निरीक्षण बढ़ा रहे हैं; वे अपने शासन को हढ़ कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी पद्धतिवाले राज्यों में केन्द्रीय सरकार के शासन को कुछ शिथिल करने की प्रवृत्ति है, केन्द्रीय सरकार स्थानीय संस्थाओं के शासन प्रवन्ध में अपना इस्तचेप कम करती है।

स्थानीय संस्थाओं की विशेषता—हमने पहले कहा है कि स्थानीय कार्य, केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा, स्थानीय संस्थाओं द्वाराण अच्छी तरह हो सकते हैं। बात यह है कि प्रत्येक गांव, नगर अथवा ज़िले की अपनी विशेष परिस्थित होती है; तीर्थ-स्थान औद्योगिक नगर, ऐतिहासिक केन्द्र की अपनी-अपनी समस्या होती है। वहाँ का प्रवन्ध आदि करने के लिए उसकी विभिन्नता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। केन्द्रीय सरकार उनके लिए नियम बनाने में ज्यौरेवार विचार नहीं कर सकती। किर, स्थानीय संस्थाओं को वहाँ के लिए कुछ योग्य अनुभवी लोगों की सेवाएँ निश्शुलक या अवैतनिक भी मिल सकती है। बाहर के आदिमियों को वहां के सम्बन्ध में न हतना ज्ञान होता है और न उन्हें वहां के कार्य में ऐसी दिलचस्पी होती है।

इसके श्रितिरिक्त स्थानीय शासन-संस्थाओं के संगठन के पक्ष में एक श्रीर भी महत्त-पूर्ण बात है। ये संस्थाएँ सर्व साधारसा की राजनैतिक शिक्षा का बहुत उत्तम साधन है। प्रायः यह श्रानुभव में श्राया है कि जिन राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का काम फला-फूला है, वहां लोक-तंत्रात्मक भावनाओं के प्रचार में विशेष सफलता मिली है। गांव या नगर का चेत्र इतना छोटा होता है, कि साधारण योग्यता का व्यक्ति भी उससे भली-भांति परिचित हो सकता है, और वहां सार्वजनिक कार्य करके अपनी उपयोगिता का परिचय स्वयं पा सकता है, तथा औरों को दे सकता है। स्थानीय कार्य में सफलता प्राप्त कर आदमी अपनी योग्यता एवं आत्म-विश्वास की वृद्धि करता है, तथा अपने जीवन को विशेष उपयोगी बनाने का मार्ग प्रहण कर सकता है। उसे संगठन, नियम-निर्माण, दूसरे के दृष्टि-कोण को समक्षने, सिह्मणुता का व्यवहार करने आदि का प्रारम्भिक ज्ञान हो जाता है; ये बार्ते भावी राजनैतिक जीवन के लिए उपयोगी होती हैं।



## उन्नीसवाँ परिच्छेद

### प्रतिनिधि-निर्वाचन

हुन्ना है। त्राज कल विकित राज्यों में कानून बनाने का काम व्यवस्थापक सभाएँ करती हैं; इन सभात्रों के सदस्य नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इस परिच्छेद में इस बात का विचार किया जाता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, उन्हें कौन चुनता है, और इस विषय श्रन्य जातव्य बातें क्या हैं।

प्रतिनिधि-प्रणाली — प्राचीन समय में यूनान आदि देशों के क्रोटे-छोटे राज्यों में सैकड़ों वर्ष तक शासन-सम्बन्धी विषयों पर निर्धा-रित आयु के समस्त नागरिक \* एकत्रित होकर अपना मत प्रकट करते थे, और उनकी सर्व-सम्पति या बहु-सम्मति से ही, क़ानून बनते थे।

यूनान आदि में बहुत-से गुलाम (दास) होते थे, उन्हें तथा क्षियों को नागरिक नहीं माना जाता था।

इस प्रकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ के व्यवस्था-कार्य में भाग लेने का अधिकार था। जब तक राज्य बहुत छोटे रहे, इस पद्धित से व्यवस्था-कार्य चलता रहा। परन्तु क्रमशः उनके बड़े और विस्तृत हो जाने पर एवं उनको जन-संख्या बहुत बढ़ जाने पर शान्ति तथा सुगमता से कार्य सम्पादन होना असम्भव हो गया।

तव प्रतिनिधि-प्रणाली का श्राविष्कार हुआ। यह सोचा गया कि राज्य के प्रत्येक भाग ( ग्राम या नगर ) के समस्त नागरिक व्यवस्था-कार्य में योग देने के बजाय अपना यह श्रधिकार कुछ चुने हुए सजनों को देदें, जो उनकी श्रोर से श्रावश्यक क्वानून की रचना श्रीर शासन-कार्य किया करें। ऐसे चुने हुए सज्जन 'प्रतिनिधि' कहलाने लगे। इस प्रकार यदि राज्य की जन संख्या लाखों ही नहीं, करोड़ों भी हो तो उनकी श्रोर से केवल दो-चार सौ श्रादमी उक्त कार्य कर सकते हैं। सुविधा या श्रावश्यकता होने पर यह संख्या बढ़ायी जा सकती है। प्रतिनिधि-प्रणाली से कानून बनाने के कार्य में लोक-सत्तात्मक भावों की रत्ता करना कितना सुविधाजनक है, यह स्पष्ट है। इससे बड़े-बड़े राज्यों में दूर-दूर से असंख्य आदिमियों को एक स्थान पर इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं रहती। उनकी श्रोर से थोड़े-से श्रादमी शान्तिपूर्वक विचार-विनिमय करने श्रीर क़ानून बनाने का काम करते हैं। साथ ही सर्व-साधारण को यह सन्तोष रहता है कि जो श्रादमी क़ानून बनाते हैं, वे इमारे चुने हुए हैं; इमने उनको भेजा है, वे हमारे लाभ-हानि का विचार करके ही क़ानून बनायेंगे। एक प्रकार से इस अपने ही बनाये हुए क़ानुनों से शासित होंगे; इस अपने ही अधीन होंगे अर्थात् हम स्वराज्य-भोगी होंगे।

प्रतिनिध-प्रणाली में जनता अर्थात् सर्वसाधारण स्वयं कानून नहीं बनाते, वरन् उनके प्रतिनिधि यह कार्य करते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली का अवलम्बन करनेवाले राज्य में, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नहीं होता (उसका होना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं होता) हां, इसे परोक्ष प्रजातन्त्र कह सकते हैं। विशेष सुविधाजनक होने के कारण इस प्रणाली का प्रचार क्रमशः बहुत-से देशों में हो गया। प्रत्येक देश में व्यवस्थापक सभाआों के लिए जनता की सर्व-सम्मत्ति या बहुमत के अनुसार प्रतिनिधि चुने जाने लगे। एक निर्धारित अवधि के पश्चात् इन प्रतिनिधियों का नया निर्वाचन करने की रीति पढ़ गयी।

प्रत्यक्ष श्रोर परोक्ष निर्वाचन—प्रतिनिधियों का चुनाव दो तरह से हो सकता है—प्रत्यक्ष रीति से, श्रीर परोच्च रीति से। कल्पना कीजिए कि एक प्रान्त है, जिसकी कुल श्रावादी चार करोड़ है, इसमें नावालिगों श्रादि को छोड़कर दो करोड़ श्रादमी ऐसे हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। ये दो करोड़ श्रादमी श्रपने-श्रपने नगर की म्युनि-सिपैलटो या जिला-बोर्ड श्रादि के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। मान लो प्रान्त की स्थानीय संस्थाश्रों के कुल प्रतिनिधियों की संख्या १५०० है। अब, उस प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन करना है। यदि उसके कुल दो करोड़ मत दाता इन सदस्यों का चुनाव करें तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जायगा; श्रीर यदि व्यवस्थापक परिषद् के सदस्यों के चुनाव करें तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जायगा; श्रीर यदि व्यवस्थापक परिषद् के सदस्यों के चुनाव का श्रीवकार केवल इनके चुने हुए उपर्यंक १५०० सदस्यों को ही हो तो इसे परोक्ष निर्वाचन कहा जायगा।

परोक्ष निर्वाचन की दूसरी विधि यह है कि साधारण मत-दाता पहले कुछ निर्वाचकों का चुनाव करते हैं। फिर, ये निर्वाचक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। परोक्ष निर्वाचन के पद्म में यह कहा जाता है कि यह सरल, सुगम तथा कम-खर्चीली है। एक बार स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन हो चुकने के बाद, प्रान्तीय या केन्द्रीय व्य-वस्थापक संस्थाओं के चुनाव के लिए फिर वैसा ही मंफ्ट उठाना नहीं पढ़ता। करोड़ें। श्रादमियों को बार-बार मत देने का कष्ट उठाने की श्रावश्यकता नहीं होती। मध्यस्य संस्था (म्युनिसिपल बोर्ड श्रादि) के सदस्य सर्वसाधारण जनता की श्रपेद्धा श्रिक योग्य होते हैं, श्रीर वे श्रपने प्रतिनिधि विशेष रूप से सोच-समम कर मेज सकते हैं।

श्रव, इसके विपच्च की बात लीजिए। स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव करने से सर्वधाघारण मत-दाताओं में स्थानीय राज-नीति में अनुराग उत्पन्न होता है, परन्तु इससे उन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों के बारे में विचार करने का, तथा व्यापक राजनीति की शिचा पाने का, यथेष्ट श्रवसर नहीं मिलता। वे देश या प्रान्त के प्रश्न और समस्याओं से श्रपरिचित रहते हैं। पुनः इस प्रथा में साधारण मत-दाताओं और प्रतिनिधि में सीधा सम्बन्ध नहीं रहता; इसलिए वे उसके चुनाव की श्रोर उदासीन से रहते हैं। इस प्रकार प्रान्त या देश की राजनीति निधीरित करने में उनका यथेष्ट भाग नहीं होता। इससे प्रजानतन्त्र शासन-पद्धति का उद्देश्य ही बहुत-कुछ विफल हो जाता है। श्रतएव प्रायः प्रतिनिधियों का सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होना ही उत्तम माना जाता है; श्रर्थात् परोक्ष निर्वाचन की श्रपेक्षा, प्रत्यच्च

निर्वाचन बहुत श्रच्छा समभा जाता है।

निर्वाचक-संघ-निर्वाचक-संघ दो प्रकार के होते हैं-साधारण श्रीर विशेष । साधारण निर्वाचक-संघ में निर्वाचक सर्वधाधारण में से होते हैं, किसी श्रेणी या समूह ऋादि से ही नहीं। विशेष निर्वाचक-संघ में कुछ विशेष श्रेणी या संस्थाओं के न्यक्ति होते हैं। उदाहरणक्त भारतवर्ष में जमीदारों, मज़दूरों, विश्वविद्यालय तथा व्यापार-सभा (चेम्बर-ब्राफ़-कामर्स ) ब्रादि को श्रपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष अधिकार है। इनके निर्वाचक-संघ विशेष निर्वाचक-संघ कहलाते हैं। इनके निर्वाचक साधारण निर्वाचक-संघों के श्रतिरिक्त. श्रपने विशेष निर्वाचक-संघों में भी मत दे सकते हैं, अर्थात् इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके समर्थकों का कहना है कि उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों की संख्या या प्रभाव कम होने से, ये साधारण निर्वाचक-संघों से चुनाव में नहीं श्राते. श्रथवा कम श्राते हैं। इसलिए इन्हें श्रपने विशेष प्रतिनिधि मेजने का श्रिवकार मिलना चाहिए। परन्त स्मरण रहे कि किसी विशेष जन-समृह को प्यक् प्रतिनिधित्व देना समाज को छिन्न-भिन्न करना है। यही बात जातिगत-निर्वाचक-संघों के विषय में है। भारतवर्ष में इनकी व्यवस्था विशेषतया मुसलमानों की माँग के श्राधार पर हुई है। क्रमशः फूट की बेल बढ़ती ही गयी। अन्य जातियों में भी साम्प्रदायिकता का रोग लग गया। श्रतः पृथक् निर्वाचन की प्रथा बहुत। घातक है; सर्वत्र संयुक्त निर्वाचन ही होना चाहिए। हाँ, विशेष दशा में, निर्धारित समय के लिए, श्रह्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सुरक्षित की जा सकती है।

मताधिकार — जिन व्यक्तियों को मताधिकार (प्रतिनिधि चुनने में मत देने का अधिकार) होता है, वे यह अनुभव करते हैं कि राज्य के शासन में हमारा भी कुछ भाग है, चाहे वह परोच्न रूप से ही क्यों न हो। इस लिए यह आवश्यक है कि यह अधिकार देश के अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को हो; केवल किसी विशेष श्रेणी, विशेष जाति, धर्म या पेशे-वालों को ही न हो। इसमें अमीर-गरीव, स्त्री-पुरुष, कुषक-ज्मीदार आदि का विचार न होना चाहिए। हाँ, राज्य के अपरिपक्त या विकृत अंगों को मताधिकार मिलना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्नत प्रजातंत्र राज्यों में भी बालकों (प्रायः अठारह-वीस वर्ष से कम आयु वालों) को, तथा पागलों को, यह अधिकार नहीं दिया जाता; कारण, साधारणतया उनमें नागरिक प्रश्नों पर विचार करके उचित मत देने की योग्यता नहीं होती।

कैदियों का कैद रहना ही इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उन्होंने राज्य के नियमों का उलंघन किया है। इसलिए उन्हें बहुधा कैद की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए मताधिकार से वंचित रखा जाता है। परन्तु प्रत्येक राज्य में राजनैतिक तथा अन्य (चोरी आदि करनेवाले) कैदियों में स्पष्ट अन्तर होना चाहिए; और कम-से-कम, अहिन्सक राजनैतिक कैदियों को कैद की अवधि के बाद तो किसी भी दशा में मताधिकार से वंचित न किया जाना चाहिए।

विदेशियों (या अनागरिकों) को भी प्रायः किसी देश में मता-धिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी इस देश से उतनी सहानुभृति नहीं होती, जितनी अपने देश से होती है। इसी विचार से एक प्रान्त, जिले या नगर के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करने में बहुधा दूधरे प्रान्त, जिले, या नगर के निवासियों को मताधिकार नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ समय निवास करने तथा कुछ नियमों का पालन करने पर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाता है।

उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़ कर श्रीर कोई व्यक्ति निर्वाचक होने का श्रनिषकारी नहीं माना जाना चाहिए। निर्वाचक होने के लिए किसी प्रकार की सम्पत्ति रखने या उसके कुछ शिक्षित होने श्रादि की शर्त रखना श्रनुचित है। नावालिग, पागल या कुछ श्रपराधी व्यक्तियों को हमने निर्वाचक होने का श्रनिषकारी बताया है। उन्हें छोड़ कर श्रन्य सब व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिए। इसे 'बालिग मताधिकार' कहा जाता है।

स्त्रियों को मताधिकार देने के विषय में पहले बहुत मत-भेद था, अब विरोध क्रमशः हटता जा रहा है। उन्नत राज्यों में स्त्रियों के लिए प्रायः पुरुषों के समान ही मताधिकार की व्यवस्था है।

िखान्त से यह माना जाता है कि धर्वधाधारण की इच्छा ही प्रमुख-शक्ति है, श्रीर सब नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वा-चन में भाग लेकर इस इच्छा को प्रगट करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिनिधि-निर्वाचन का श्रधिकार प्रत्येक नागरिक का स्वाभाविक . श्रीर जन्म-सिद्ध श्रधिकार है। किन्तु व्यवहार में यह बात पूरी नहीं होती। प्रत्येक राज्य में कुछ,न-कुछ नागरिक अपने मताधिकार से बंचित रहते हैं। जो राज्य जितना अवनत, या कम विकसित होता

है, उतने ही श्रधिक नागरिक वहाँ इस श्रधिकार से वंचित मिलेंगे।

निर्वाचकों को चाहिए कि वे ऐसे सजन को ही मत देकर अपना
अतिनिधि चुनें जो समुचित रूप से योग्य, अनुभवी, तथा उदार और
सुधारक हो, निस्वार्थ कार्य, त्याग और सेवा का उच्च आदर्थ
रखता हो। उसकी जाति-पाँति का विचार करना ठीक नहीं। इस
बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह निर्मीक और स्वतंत्र
प्रकृति का हो; खुशामदी, अधिकारियों के रौब में आनेवाला न हो।
मतदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मत देकर
वे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वह जो-कुछ, व्यवस्थापक सभा में
कहेगा, वह उनकी तरफ से कहा हुआ समभा जायगा; इसलिए वे
खुब सोच-समभ कर मत दें।

कुछ नागरिक निर्वाचन के अवसर पर मत देने के लिए नहीं जाते। यह उचित नहीं है। उनकी उपेक्षा से सम्भव है, योग्य उम्मेदवारों के वास्ते मतों में कमो रह जाय, और अयोग्य उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा के सदस्य वन जायँ, जिसका दुष्परिशाम सब नागिरिकों को अगले निर्वाचन तक भुगतना पड़े। अस्तु, मतदाता की हैसियत से नागरिकों का कर्तव्य है कि वे मत का अवश्य उपयोग करें; मत देने में कभी उपेक्षा न करें।

मत देना—मताधिकार से यथेष्ट लाम तभी हो सकता है, जब कि मतदाताओं का अपना मत देने में पूरी स्वतंत्रता हो। जिस व्यक्ति को वे प्रतिनिधि बनाने के लिए अधिक उपयुक्त समर्के, उसे ही मत दे सकें, उन पर किसी का अनुचित दबाव न पड़े, और न उन्हें कोई प्रलोभन श्रादि दिया जाय । बहुधा जब मतदाता यह जान लेता है कि श्रमुक उम्मेदवार, सदस्य बनने के लिए, सबसे श्रिषक योग्य है, तो भी यदि कोई दूसरा उम्मेदवार उसका मित्र या रिश्तेदार है, श्रथवा उसकी जाति या धर्म का है, या विशेष प्रतिष्ठा वाला है, तो उसके मन में उसका लिहाज़ हो जाता है। श्रीर, श्रगर सब के सामने मत देना पड़े तो सम्भव है कि मतदाता श्रपनी वास्तविक सम्मति के विरुद्ध इस दूसरे उम्मेदवार के लिए मत दे दे। इस वास्ते मत गुत हम से देने की प्रथा चलायी गयी है।

मत देने की विधि — आज कल निर्वाचन प्रायः इस तरह होता है — पहले सरकार द्वारा निर्वाचन स्थान, तिथि और समय निश्चित किया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन स्थान के लिए एक या अधिक निर्वाचन अफसर नियुक्त किया जाता है। जब निर्वाचक मत देने की जगह जाता है तो उसका नाम, निर्वाचक नम्बर, और पता पूछा जाता है। आवश्यक होने पर उम्मेदवार या उसके एजंट को निर्वाचन अफसर के सामने निर्वाचक की शनाख्त करनी होती है। शिच्चित निर्वाचक को अपने इस्ताक्षर करने, और अशिक्षित को अपने अंगूठे का निशान लगाने पर एक पर्चा दिया जाता है, जिसे निर्वाचन पत्र, मत-पत्र, या 'बेलट-पेपर' कहते हैं। निर्वाचन-अफसर निर्वाचक को यह बता देता है कि वह अधिक-से-अधिक कितने मत दे सकता है। पर्चा लेकर शिच्चित निर्वाचक, नियत किये हुए एकान्त स्थान में जाकर, उस पर्चे पर अपने अभीष्ट उम्मेदवार के नाम के सामने निर्दाष्ट चिन्ह ( + या × ) कर देता है; और उस पर्चे को मोड़ कर एक सन्दूक

में डाल देता है, जो वहाँ इस विशेष कार्य के लिए तैयार करा कर रखा जाता है। यदि निर्वाचक अशिक्तित या बीमार हो, या बेकार हाथ वाला हो तो निर्वाचन-अफसर, उम्मेदवारों तथा उनके एजंटों की उपस्थित में, उसके बताये हुए नाम के सामने निशान लगा कर पर्चें को उस संदुक में डलवा देता है।

श्रशिक्षित निर्वाचकों का मत गुप्त रखने के लिए कहीं-कहीं गंगीन सन्दूकों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक उम्मेदवार के लिए एक-एक रंग नियत कर दिया जाता है, श्रोर उस रंग के संदूक पर उसका नाम भी लिख दिया जाता है, (या उसका फोटो चिपका दिया जाता है)। जब निर्वाचन-श्रक्षसर किसी निर्वाचक को मत-पत्र देता है तो वह उसे यह समभा देता है कि किस उम्मेदवार का क्या रंग है, श्रोर उसे कह देता है कि जिस उम्मेदवार के लिए उसे मत देना हो, उसके रंगवाले संद्क में वह श्रपना मत-पत्र डाल दे। निर्वाचक श्रपनी इच्छानुसार मत-पत्र श्रभीष्ट संदूक में डाल देता है।

निर्घारित समय के पश्चात् प्रत्येक संदूक में डाले हुए मत-पत्रों की संज्या गिन ली जाती है। जिन उम्मेदवारों के लिए श्रिषक मत श्राते हैं, उनके निर्वाचित होने की विज्ञिति की जाती है।

निर्वाचन की एक विधि और है। इसके अनुसार निर्वाचक अपना मत किसी व्यक्ति को नहीं देते, वरन भिन्न-भिन्न दलों द्वारा तैयार की हुई उम्मेदवारों की सूचि को देते हैं। उदाहरणार्थ, कल्पना कीजिए किसी नगर को म्युनिसिपैल्टी का चुनाव होनेवाला है, श्रौर वहाँ तीन दल मुख्य हैं—उग्र दल, कांग्रेस दल, श्रौर स्वतंत्र दल। श्रव यदि निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या बारह निर्धारित की गयी है, तो प्रत्येक दल श्रपने बारह-बारह उम्मेदवारों की सूची या फहरिस्त (लिस्ट) तैयार करता है। यह श्रावश्यक नहीं है कि प्रत्येक सूची के नाम अन्य सूचियों के नामों से सर्वथा भिन्न हो, कुळ उम्मेदवारों के नाम दो या श्रीवक सूचियों में होना सर्वथा सम्भव है। श्रस्तु, मत-दाता श्रों को तीनों सूचियों के नाम बता दिये जाते हैं। प्रत्येक मतदाता को श्रीवकार है कि वह चाहे जिस सूची के सम्बन्ध में श्रपना मत दे। जिस दल की तैयार की हुई सूची के पच्च में सब से श्रीवक मत श्राते हैं, उसी दल की विजय होती है, उस दल के सब उम्मेदवारों के निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है।

इस प्रणाली को 'लिस्ट सिस्टम' कहते हैं। इस की विशेषता यह है कि मतदाता व्यक्तिगत उम्मेदवार की अपेद्या, उनकी पार्टी या दल का अधिक ध्यान रखते हैं। इस से भिन्न-भिन्न दलों के संगठन में सहायता मिलती है।

मत-गणना भणाजी, एकाकी मत भणाजी —िक शी उम्मेदबार के पक्ष में आये हुए मत गिनने की दो प्रणालियाँ है:— (१) एकाकी-मत-प्रणाली, \* और (२) अनेक-मत-प्रणाली । एकाकी

<sup>\*</sup>Single Voting.

<sup>†</sup>Plural Voting.

मत-प्रणाली बहुत सरल है। जिस नगर या प्रान्त आदि के प्रतिनिधि चुनने होते हैं, उसे सुविशानुसार कुछ निर्वाचन-चेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक से एक-एक प्रांतिनिधि लिया जाय। जिस निर्वाचन-चेत्र में एक ही उम्मेदवार होता है, उसके मतदाताओं को मत देने की आवश्यकता नहीं होती। पर जब एक निर्वाचन-चेत्र में कई-कई उम्मेदवार होते हैं तो मत लिये जाते हैं। एकाकी-मत-प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता का एक-एक ही मत होता है, जिस उम्मेदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत आते हैं, वह प्रतिनिधि चोषित किया जाता है।

यह प्रणाली जैसी सरल है, वैसी ही सदोष है। जब एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, तब जिस-जिस मतदाता ने उसे मत दिया, उस-उस मतदाता का ही प्रतिनिधित्व होता है। शेष सब मतदाता अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रहते हैं, वे व्यवस्थापक सभा के संगठन और निर्णयों के प्रति उदासीन होते हैं। यह सम्भव है कि विजयी उम्मेदवार नाम-मात्र के ही बहुमत से जीत जाय। उदाहरणवत् यदि एक निर्वाचन चेत्र से क को ५०० मत मिलें, और ख को ५०२ तो ख को प्रतिनिधि घोषित किया जायगा। इस प्रकार१००२ मतदाताओं में से ४०० अर्थात् लगभग आषे मत-दाताओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

इस प्रयाली का दोष उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है, जितने अधिक उम्मेदवार निर्वाचन में खड़े होते हैं। परन्तु जिन निर्वाचक-संघों से, केवल एक-एक ही प्रतिनिधि लिया जानेवाला हो, उनमें इस प्रणाली के उपयोग के सिवाय श्रीर कुछ चारा नहीं है।

स्रनेक-मत-प्रणाली-इस प्रणाली का व्यवहार वहाँ किया जाता है, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन-चेत्र से एक-एक ही नहीं, कई-कई प्रतिनिधि निर्वाचित करने होते हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता इतने मत दे सकता है, जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन-चेत्र से चुने जानेवाले हों। इस प्रणाली के अनुसार मत सैकड़ों प्रकार से दिये जा सकते हैं, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:—(क) 'एक उम्मेदवार, एक मत'-पद्धति, (ख) एकत्रित-मत\* पद्धति, श्रौर (ग) 'एकाकी हस्तान्तरित'-मत† पद्धति।

(क) 'एक उम्मेदवार, एक मत' पद्धति—इस प्रणाली में प्रत्येक निर्वाचक एक प्रतिनिधि के लिए एक मत दे सकता है। यदि किसी निर्वाचन-स्त्रंत्र से तीन प्रतिनिधि चुने जानेवाले हैं, और वहाँ पाँच उम्मेदवार हैं तो प्रत्येक निर्वाचक इन उम्मेदवारों में से किन्हीं तीन के लिए एक-एक मत दे सकता है; वह चाहे तो तीन से कम, दो या एक उम्मेदवारको ही अपना एक-एक मत दे; परन्तु तीन से अधिक को मत नहीं दे सकता। इस प्रणाली में बहुमत का बोलबाला रहता है, अल्प-मत का प्रतिनिधित्व नहीं होता।

उदाहरखवत् कल्पना करो, एक निर्वाचन-त्तेत्र से चार प्रतिनिधि लिये जानेवाले हैं, और वहां तीन दल हैं—उग्र, नर्म और स्वतन्त्र । उग्र दल के ४००, नर्म दल के ८००, और स्वतन्त्र दल के १,०००

<sup>\*</sup> Cumulative Vote. † Single Transferable Vote.

मतदाता हैं। प्रत्येक दल अपने चार-चार उम्मेदवार खड़ा करता है। श्रव होगा यह कि उग्र दल के प्रत्येक उम्मेदवार को चार-चार सौ मत मिलेंगे, नर्म दलवाले को श्राठ-श्राठ सौ, श्रौर स्वतन्त्र दल वाले को एक-एक हजार। इस प्रकार स्वतन्त्र दल के चारों उम्मेदवार जीत जाते हैं, श्रौर श्रन्य दनों का कोई भी उम्मेदवार प्रतिनिधि चोषित नहीं होता।

एकत्रित पत पद्धित-इसके अनुसार मतदाताओं को अधि-कार होता है कि वे अपने मत अपनी इच्छानुसार वितरण करें; यहाँ तक कि जो मतदाता चाहे. वह श्राने समस्त मत एक ही उम्मेदवार को भी दे सकता है। इस दशा में निर्वाचन-चेत्र का जो दल अपने-श्रापको कमज़ोर श्रर्थात श्रल्य संख्यक समभ्तता है. वह श्रपने एक ही उम्मेदवार को अपने समस्त मत दे देता है. इससे उसका कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य हो जाता है। परन्तु इससे कुछ प्रसिद्ध उम्मेदवारों को तो इतने श्रविक मत मिल जाते हैं. जितनी की उन्हें श्रावश्यकता नहीं होती; इसके विषरीत दूसरे उम्मेदवार मतों की कमी रहने से, हार जाते हैं। मतदाताओं के बहुत से मत व्यर्थ जाना इस प्रणाली का स्पष्ट दोष है। पुनः इस प्रणाली के श्रनुसार कार्य करने से भिन्न-भिन्न दलों के नेताश्रों को, मतदाताश्रों का संगठन करने में, जी-तोड़ परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी अनेक दशाओं में उन्हें अपने दल की संख्या के अनुसार प्रतिनिधि भेजने में सफलता नहीं मिलती।

एकाकी-हस्तान्तरित-मत-प्रणाली - इस प्रणाली का उपयोग ऐसे निर्वाचन-चेत्रों में ही किया जाता है, जहाँ से कई-कई ( प्राय: तीन से सात तक ) प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने वाला हो । इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता को यह सचित करने का अवसर दिया जाता है कि वह सब उम्मेदवारों में. सबसे अधिक किसे पसन्द करता है, श्रीर उससे कम किसे, श्रीर इसी प्रकार तीसरे श्रीर चौथे नम्बर पर किसे । जिस उम्मेदवार को वह सबसे श्रधिक पसन्द करता है. उसके नाम के आगे वह '१' लिख देता है, उससे दूसरे नम्बर पर जिसे पसन्द करता है उसके नाम के आगे '२' और इसी प्रकार अन्य उम्मेदवारों के नाम के श्रागे श्रपनी पर्यन्द के श्रनुसार '३', '४', 'भ' आदि लिख देता है। इस प्रकार मतदाता यह सचित कर सकता है कि सर्व-प्रथम उसके मत का उपयोग किस उम्मेदवार के लिए हो, श्रीर यदि उस उम्मेदवार को उसके मत की श्रावश्यकता न हो (वह उम्मेदवार श्रन्य मत-दाताओं के मतों से ही चुन लिया जाय), तो उस मत का उपयोग किस दूसरे या तीसरे, चौथे श्रादि उम्मेदवार के लिए हो।

उम्मेदवारों की सफलता का हिसाब लगाने के लिए पहले यह देखा जाता है कि किसी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने मतों की आवश्यकता है। मतों की इस संख्या को 'कोटा', \* 'पर्याप्त संख्या', या 'आनुपातिक माग' कहते हैं। पहले कहा जा चुका है कि इस प्रणाली का उपयोग ऐसी दशा में होता है, जब कई प्रतिनिधि चुनने होते हैं.

<sup>\*</sup> Quota

परन्तु 'पर्यात संख्या' को श्रन्छी तरह समझने के लिए कल्पना कीजिए, एक निर्वाचन-दोत्र से एक उम्मेदवार चुनना है, श्रौर वहाँ सौ मतदाता है। श्रव जिस उम्मेदवार को कम-से-कम ५१ मत मिल जायँगे, वह चुन लिया जायगा, क्योंकि दूसरे उम्मेदवार को श्रधिक-से-श्रधिक ४९ ही तो मत मिल सकते हैं।

इस प्रकार इस दशा में पर्याप्त संख्या ५१ है, जो कुल मतों के आधि अर्थात् ५० से एक अधिक है। यदि दो उम्मेदवार जुनने हैं, ता जिन उम्मेदवारों को ३४, ३४ मत मिल जायँगे, वे सफल हो जायँगे; क्यों कि तीसरे को यदि शेष सब मत भी मिल जायँ तो उसके प्राप्त मतों की संख्या अधिक-से-अधिक ३२ होगी। इस प्रकार इस दशा में पर्याप्त संख्या कुल मतों की तिहाई अर्थात् ३३ से एक अधिक है। निदान, कुल मतों को, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में एक जोड़ कर, उससे भाग दे देने तथा भजन-फल में एक जोड़ देने से पर्याप्त संख्या मालूम हो जाती है। संस्वेप में—

पर्याप्त संख्या = मत संख्या + १

जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के मत पर्याप्त संख्या के समान या इस से अधिक प्राप्त कर लेते हैं, वह निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने मत पर्याप्त संख्या से अधिक होते हैं, उन्हें 'सरप्लस' फाजिल या अतिरिक्त मत कहा जाता है। ये मत अपर्याप्त मतवाले उम्मेदवारों में, (एक निर्धारित हिसाब से) बंटि जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्मेदवार निर्वाचित नहीं होते तो पर्याप्त संख्या से कम मत वाले उभमेदवारों में से जिसके मत सबसे कम होते हैं, उसे असफल घोषित करके, उसके प्राप्त मतों का उपयोग उन उममेदवारों के लिए किया जाता है, जिनके लिए वे मत दूसरी पसन्द में रखे गये हों।

इस प्रणाली से यह लाभ है कि मतदाता का कोई मत व्यर्थ नहीं जाता। भारतवर्ष में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए यही प्रणाली निर्धारित की गई है। कांग्रेस ने भी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों तथा ऋखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के निर्धाचन के लिए इसी प्रणाली को अपनाया है।

उम्मेदवार — पहले यह बताया गया है कि (प्रतिनिधि बनने के)
उम्मेदवारों को मत किस प्रकार दिये जाते हैं। अब उम्मेदवार के विषय
में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। उम्मेदवार ऐसे व्यक्ति नहीं हो
सकते, जिनमें निर्वाचक या मतदाता होने की योग्यता न हो, या जिनकी
आयु निर्धारित आयु से कम हो। सरकारी नौकरी करनेवाले, व्यवस्थापक
सभा की मेम्बरी के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकते; हाँ, मंत्री-मंडल
के सदस्य, उम्मेदवार हो सकते हैं। जहां साम्प्रदायिक या जातिगत
निर्वाचक संघ हैं, वहां उन संघों में से किसी संघ से वही व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, जो उस जाति या सम्प्रदाय का हो, जिसका कि वह
संघ है। अन्य व्यक्ति उम्मेदवार नहीं हो सकते।

<sup>\*</sup>स्थानामाव से यहां इस प्रणाली के उपयोग का उदाहरण नहीं दिया जाता। निर्वाचन के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'निर्वाचन पद्धति' पुस्तक (लेखक —श्री० दुवे श्रीर केला) उपयोगी है।

उम्मेदवार काफ़ी उम्र के, गम्भीर, योग्य, निर्मीक और अनुभवी होने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो लोभ-रहित हों और निःस्वार्थ भाव से काम कर सकें। भारतीय आदर्श को घ्यान में रखकर ऐसी व्यवस्था होना अच्छा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवस्थायक समा आदि का सदस्य होने के लिए न तो स्वयं उम्मेदवार बने, और न अपने पक्ष में मत-याचना करने के वास्ते मतदाताओं के दरवाले खट-खटाता फिरे। जब निर्वाचक किसी व्यक्ति से उम्मेदवार होने की प्रार्थना करे तो अगर वह अपने आपको योग्य और उपयुक्त समफ्ते तो यह स्वित कर दे कि में उम्मेदवार होना स्वीकार करता हूँ; यदि मेरा निर्वाचन हो जायगा, तो मैं कार्य-भार संभाल लुंगा।

प्रतिनिधि और निर्वाचक—बहुषा यह शिकायत सुनने में आती है कि प्रतिनिधि बननेवाले सजन (उम्मेदवार), केवल जुनाव के समय ही, निर्वाचकों से कुछ सम्पर्क रखते हैं, पर जहाँ वे एक बार प्रतिनिधि जुने गये, वे निर्वाचकों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वे उनकी कुछ नहीं सुनते। हाँ, प्रतिनिधियों का कार्य-काल परिमित होता है और दुवारा जुने जाने की इच्छा से वे उनका कुछ ख़्याल रखते तो हैं। पर वह पर्याप्त नहीं होता। निर्वाचकों का प्रतिनिधियों पर विशेष नियंत्रण नहीं रहता। फिर उन्हें प्रतिनिधि जुनने, अर्थात् मताधिकार से लाम हो क्या? इसिलए कुछ राजनोतिजों का मत है कि प्रत्येक प्रतिनिधि को उसके निर्वाचक-संघ से निश्चित हिदायतें या आदेश मिलना चाहिए। जो प्रतिनिधि इसका पालन न करे, उसे वापस जुलाने और उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि मेजने का अधिकार

निर्वाचकों को होना चाहिए।

इस मत की कड़ी श्रालोचना हुई है। इस मत के विपद्ध में कहा जाता है कि यदि निर्वाचक अपने प्रतिनिधि से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो श्रमले निर्वाचन में वे उसको मत न दें, परन्तु उन्हें उसको वापिस बलाने का अधिकार न होना चाहिए। प्रतिनिधि सामान्य नीति की बात का ध्यान रख सकते हैं, परन्तु यह सम्भव तथा व्यावहारिक नहीं है कि वे व्यवस्थापक सभा में उपस्थित होनेवाले विविध प्रश्नों में से प्रत्येक के विषय में अपने निर्वाचकों का मत लेते रहें। पन: निर्वाचकों के सामने उनके च्रेत्र का ही विचार रहता है, वे उसी हिष्टकोण से प्रत्येक प्रश्न को सोचते हैं, परन्तु प्रतिनिधि को राज्य के सामूहिक हित का विचार करना होता है, श्रवः उसका दृष्टिकोण भिन्न होना स्वाभाविक है। और ऐसा होने से कोई हानि भी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बात श्रीर भी है। बहुधा प्रतिनिधि श्रपने चेत्र के साधारण निर्वाचकों की अपेदा अधिक कुशल और बुद्धिमान होता है। अतः निर्वाचक उसे हिदाय तें देने योग्य नहीं होते. इसके विपरीत प्रतिनिधि ही श्रपने निर्वा-चकों को बहुत से विषयों का ज्ञान करा सकता है।

इस प्रकार, इस मत के पक्ष और विपन्न दोनों श्रोर की बातें पाठकों के विचारार्थ उपस्थित हैं। साधारणतया बुद्धिमानी मध्यम मार्ग ग्रहण करने में है। प्रतिनिधि को चाहिए कि वह जनता के भावों का विचार श्रवश्य रखे, श्रोर साथ ही श्रपनी स्वतंत्र निर्णय-शक्ति का भी उपभोग करे। जब जैसी परिस्थित हो, उसका ध्यान रखते हुए वह जनता का हित-साधन करे। वह किसी दल-विशेष या चेत्र-विशेष का प्रतिनिधित्व करने की इतनी चिंता न करे, जितनी राज्य का प्रतिनिधित्व करने की । उसका कर्तज्य राज्य की, सर्वधाधारण जनता की, भलाई करना है। निर्वाचक-संघ के मतदाताओं को भी चाहिए कि जिस व्यक्ति को उन्होंने भली-भाँति सोच-समफकर अपना प्रतिनिधि चुना है, उसकी योग्यता और विचारों पर विश्वास रखें तथा यह आशा न करें कि बात-वात में वह उनका मत लेने के लिए आया करेगा। व्यवस्थापक सभा में बहुत से विषय तत्काल उपस्थित होते हैं, उन पर तुरन्त मत देने की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधि को अपनी बुद्धि तथा प्रतिभा के भरोसे ही काम करना होता है।

श्रव संघ-शासन के सम्बन्ध में विचार करें। संघ-राज्य की उपर-ली व्यवस्थापक सभा में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वे भिन्न-भिन्न संघान्तरित राज्यों की श्रोर से होते हैं। उनकी सरकार उन्हें जो श्रादेश दे, उसका पालन किया जाना श्रावश्यक कहा जा सकता है। परन्तु इसकी भी प्रथा नहीं है। प्रतिनिधियों पर निर्वाचकों का विशेष नियंत्रण उचित नहीं समभा जाता। हाँ, जब प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूप से उम्मेदवार न होकर किसी दल-विशेष की श्रोर से प्रतिनिधि बनता है तो उस दल का उस पर यथेष्ट नियन्त्रण रहता है। यदि वह किसी विषय पर श्रपने दल के विरुद्ध मत देता है, तो उस पर उसके दल की श्रोर से श्रनुशासन की कार्रवाई की जाती है; श्रीर, श्रन्ततः उसे त्याग-पत्र देना होता है। यदि वह चाहे तो इसके बाद दूसरे ऐसे दल का सदस्य बन सकता है, जिसकी नीति को वह मानता हो। उस दल की श्रोर से, श्रथवा स्वतन्त्र रूप से वह फिर उम्मेदवार बन

जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन होने का आदर्श बहुत उत्तम है; परन्तु यथेष्ट प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार हो, यह विषय सीधा या सरल नहीं है। समय-समय पर निर्वाचन-पद्धति सम्बन्धी नये-नये आविष्कार हुए हैं; किन्तु इस समय भी इसमें कई दोष हैं। इनका सुधार होना चाहिए। तथापि, प्रजातंत्रात्मक-शासन के लिए प्रतिनिधि-प्रणाली से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है।

# वीसवाँ परिच्छेद नागरिकता

कुष पुस्तक के पहले परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि
नागरिक किसे कहते हैं। आज-कल प्रत्येक राज्य में वहाँ के अधिकाँश
निवासियों को जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है। प्राचीन योरप में
ऐसा नहीं था। उदाहरखार्थ यूनान और रोम के राज्यों में स्त्रियों को
नागरिक नहीं माना जाता था; विदेशियों को, तथा युद्ध में जीतकर लाये
हुए अथवा ख़रीदे हुए दासों और उनकी सन्तान को भी, नागरिक नहीं
समका जाता था। अब तो राज्य के अधिकाँश व्यक्तियों का नागरिक
होना, उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है, वे नागरिकता मानों विरासत मेंपाते
हैं, स्त्रियों को अब नागरिक माना जाने लगा है, दासता की प्रथा, कमसे-कम प्राचीन रूप की, अब प्राय: हट गयी है। तथापि प्रत्येक राज्य
में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो वहाँ के नागरिक नहीं होते। इस
प्रकार राज्य की कुल जन-संख्या के दो भाग किये जा सकते हैं—जनता
का बहुत बड़ा भाग नागरिको का होता है, और शेष छोटा-सा भाग
अ-नागरिकों का।

श्रव हम यह विचार करेंगे कि किसी राज्य में उन मनुष्यों की क्या स्थिति होती है, जो वहाँ के नागरिक नहीं होते। क्या उन्हें नागरिक ता प्राप्त हो सकती है, यदि हो सकती है तो किस प्रकार ? हम यह भी विचार करेंगे कि जो व्यक्ति नागरिक माने जाते हैं, क्या उनकी नागरिकता कभी विद्युत भी हो जाती है ? ऐसा किन-किन दशाओं में होता है ?

श्र-नागरिक—राज्य के जो व्यक्ति नागरिक नहीं हैं, जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हैं, वे श्र-नागरिक कहलाते हैं। इन्हें भी राज्य में कुछ श्रिष्ठिकार श्रीर कर्तव्य श्रवश्य रहते हैं। उदाहरण्यत् ये नागरिकों की मांति राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा श्रा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, समा-सम्मेजन में भाग ले सकते हैं। राज्य के स्कूल, श्रस्पताल, न्यायालय श्रादि संस्थाओं से लाम उठां सकते हैं। राज्य इनके जान-माल की रक्षा करता है।

श्रव कर्तन्यों की बात लीजिए। इन्हें राज्य के सब नियम पालन करने होते हैं, श्रोर राज्य के निर्धारित कर देने पड़ते हैं। यदि ये इसमें त्रुटि करते हैं तो इन्हें नियमानुसार दंड दिया जाता है।

इन बातों में अ-नागरिक और नागरिक को स्थिति समान ही होती है। मेद होता है उन अधिकारों के सम्बन्ध में, जिन्हें राजनैतिक अधि-कार कहा जा सकता है। उदाहरणवत् अ-नागरिकों को मताधिकार नहीं होता, हसलिए वे व्यवस्थापक समा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं ते सकते, और राज्य की शासन-पद्धति पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इसी प्रकार उन्हें कुछ खास-खास ऊँचे सरकारी पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाता।

श्र-नागरिक दो प्रकार के होते हैं -- स्वदेशी और विदेशी। पहले स्त्रियाँ नागरिक नहीं मानी जाती थीं, अब भी बहुत से राज्यों में उन्हें यथेष्ट राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, और बहुत-सी स्त्रियाँ अ-नागरिक हैं। राजद्रोह आदि विशेष प्रकार के बड़े अपराध करनेवाले व्यक्ति, जिन्हें लम्बी सजा मिलती हैं, कुछ समय के लिए, श्रयवा सदैव के ही लिए श्र-नागरिक माने जाते हैं। पागल या कोढी शारीरिक श्रथवा मानसिक विकारों के कारण श्र-नागरिक ठहराये जाते हैं। दूसरे राज्यों के नागरिक बन जानेवाले भी प्रायः श्र-नागरिक समके जाते हैं। ये सब व्यक्ति स्वदेशी अन्तागरिक हैं। विदेशी अन्तागरिक वे हैं, जो राज्य के बाहर से, दूसरे देश से रोज़गार श्रादि के लिए श्राये हुए हों, श्रौर जिन्हें राज्य के निर्धारित नियमों के श्रनुसार नागरिकता प्राप्त न हुई हो। राज्य इनके ज्ञान-माल की रक्षा अपनी सीमा में तो वैसी ही करता है, जैसी अपने नागरिकों की, परन्तु उनके अन्य देशों में जाने पर उसे इसकी चिन्ता नहीं होती। युद्ध-काल में, जो विदेशी व्यक्ति शत्रु-राज्यों के निवासी होते हैं, उन्हें अपने देश नहीं जाने दिया जाता; वे राज्य के किसी माग में नजरबन्द की तरह रखे जाते हैं।

नागरिकता की प्राप्ति—नागरिकता में विशेषतया उन अधि-कारों का समावेश माना जाता है, जो राज्य में नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है, यह पहले कहा जा चुका है। नागरिक राज्य का सदस्य है, उसे विविध अधिकार प्राप्त होते हैं, तथा उसे कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस प्रकार नागरिकता किसी व्यक्ति के उन अधिकारों और कर्तव्यों का चित्र निश्चत करती है, जिनकी और समु-चित ध्यान देने से उसके जीवन का विकास होता है। नागरिकता सम्बन्धी व्यौरेवार नियमों में, विविध राज्यों में कुछ विभिन्नता है। साधारण्तया नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त होती है—(१) जनम या वंश से। किसी राज्य के मूल निवासियों तथा उनके वंशजों को उस राज्य का जनम-जात या स्वाभाविक नागरिक कहा जाता है। उसकी नागरिकता को स्वाभाविक नागरिकता कहते हैं। (२) नागरिकत्य द्वारा अर्थात् राज्य से नागरिकता की सनद लेकर। इस प्रकार नागरिक वननेवाला अंगीकृत या कृतिम नागरिक, और उसकी नागरिकता कृत्रिम नागरिकता कृत्य नागरिकता कृत्रिम नागरिकता कृत्रिम नागरिकता कृत्य नागरिकता कृत्य नागरिकता कृत्य नागरिकता कृत्य नागरिकत

प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ के उसके माता-ियता नागरिक होते हैं। अधिकाँश राज्यों में, नागरिकता के लिए, वंश का विचार पुरुष-क्रम से होता है। अर्थात्, कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ का उसका पिता नागरिक होता है। इन राज्यों में यदि किसी पुरुष से कोई विदेशी स्त्री विवाह करें, तो वह स्त्री अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती, वह उस राज्य की नागरिक बन जाती है, जिस राज्य का उसका पिता नागरिक होता है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ नागरिकता के लिए वंश का विचार स्त्री-क्रम से होता है।

इंगलैंड श्रादि कुछ देशों में राज्य की सीमा के भीतर जन्म लेने से विदेशियों की सन्तान को भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये व्यक्ति एक ही समय में दो राज्यों के नागरिक हो जाते हैं—
(क) श्रपने राज्य के, श्रीर (ख) दूसरे उस राज्य के जो उनका जन्महो। परन्तु श्रिषकाँश राज्यों में किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान
स्थान करने के लिए यह श्रावश्यक समभा जाता है कि वह श्रन्य किसी
भी राज्य का (श्रपनी मातृ-भूमि का भी) नागरिक न रहे। इस
प्रकार इन राज्यों में कोई व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य
का नागरिक हो सकता है।

ब्रिटिश क़ानून यह है कि ऋँगरेजी जहाज़ पर जन्म लेनेवाला भी (चाहे उसके माता-पिता ऋंगरेज न भी हों) ब्रिटिश नागरिक माना जाय। इंगलैंड तथा संयुक्त-राज्य अमरीका आदि कुछ राज्यों में, इनके नागरिकों की सन्तान को चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य में क्यों न हो, इन राज्यों की नागरिकता प्रदान की जाती है।

जब किसी व्यक्ति को दो राज्यों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है (एक माता-पिता के राज्य की, श्रीर दूसरे उस राज्य की, जहाँ उस व्यक्ति का जन्म हुआ है) तो यह निश्चय करना होता है कि वह व्यक्ति उन दोनों में से किसी एक राज्य का नागरिक रहना पसन्द करता है; कारण, कोई व्यक्ति प्रायः एक-साथ दोनों राज्यों का नागरिक नहीं रह सकता। इसमें व्यावहारिक किंदनाई है। कल्पना कीजिए कि एक जर्मन दम्पत्ति इंगलैंड गया, श्रीर वहाँ उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। अब यह नवजात व्यक्ति नियम से तो दोनों राज्यों का नागरिक हो

गया। परन्तु अव न्यावहारिक दृष्टि से विचार करें। यह न्यक्ति सदैव दोनों राज्यों के प्रति मिक-भाव नहीं रख सकेगा। साधारण स्थिति में तो कोई बात नहीं है, पर विशेष दशा विचारणीय है। यदि इंगलैंड और जर्मनी में युद्ध छिड़ जाय, या इनमें से किसी एक का किसी अन्य राज्य से युद्ध उन जाय तो और दूसरे की उससे मित्रता रहे, तो इंग-लैंड उपर्युक्त न्यक्ति से यह आशा करेगा कि वह इंगलैंड के पक्ष में लड़े, और जर्मनी यह चाहेगा कि वह जर्मनी का पक्ष ले। अब उस उपक्ति का दोनों और अपना उत्तरदायित्व निभाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति न आने देने के लिए, ऐसे न्यक्तियों के बालिंग होने पर उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि वह दो राज्यों में से किस एक का नागरिक रहेगा। दूसरे राज्य की नागरिकता का उसे परित्याग करना होगा।

अस्तु, स्वाभाविक नागरिकता की प्राप्ति में प्रायः दो बातें मुख्य होती हैं—वंश और जन्म-स्थान। वंश का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कितना होता है, यह सर्व-विदित है। माता-पिता और परिवार के अन्य व्यक्तियों के गुण, कर्म और स्वभाव का प्रतिबिम्ब सन्तान में प्रायः देखने में आता है। अवस्य हो कुछ दशाओं में इसका अपवाद भी मिसता है, पर इससे उक्त कथन की यथार्थता में दोष नहीं आता।

जन्म-स्थान का भी मनुष्य की भाषा, रहन-सहन श्रीर व्यवहार श्रादि पर बहुत प्रभाव पड़ता है; इसी से जन्म-भूमि को मातृ-भूमि कहा जाता है। परन्तु कुछ दशाश्रों में जन्म-स्थान का सम्बन्ध च्यिक या स्थायी ही होता है, उस दशा में उसका प्रभाव भी बहुत कम होना स्वामाविक है। आज-कल आमदरप्रत के साधन पहले की अपेक्षा बहुत सुलम हैं। यात्रा खूब होती है। स्त्रियों भी बहुत यात्रा करने लगी हैं। बहुधा वे थोड़े समय के लिए ही किसी स्थान में चली जाती हैं। अतः अनेक व्यक्तियों का जन्म ऐसे राज्यों में हो सकता है, जहाँ उन्हें विशेष समय तक उहरना न हो, और जिसके प्रति भविष्य में उसकी ममता या भक्ति बिल्कुल न हो, अथवा बहुत ही कम हो। आज-कल अनेक बालकों का जन्म हवाई जहां में ही हो जाता है। अतः प्रायः राजनीतिशों का मत यह है कि नागरिकता-प्राप्ति में जन्म-स्थान की अपेक्षा वंश को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

पहले कहा गया है कि नागरिककरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिककरण का आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य की निर्घारित शर्तों तथा नियमों का पालन करके, या पालन करने की प्रतिज्ञा करके, उस राज्य से से नागरिकता की सनद और स्वत्व प्राप्त कर ले। ये शर्तें तथा नियम भिन्न-भिन्न राज्यों में पृथक्-पृथक् होते हैं, तथापि नागरिकता-प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों को प्रायः निम्नलिखित बातों में से एक या अधिक का पालन करना होता है, (इनमें से प्रथम तो प्रायः सभी राज्यों में आवश्यक समभी जाती हैं, अन्तिम का भी बहुत महत्व है)—

- (१) निर्धारित समय तक निवास करना, (यह समय भिन्न-भिन्न राज्यों में एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक होता है)।
- (१) राजभक्ति श्रथवा राष्ट्र-भक्ति की श्रपथ लेना।

- (३) राष्ट्र-भाषा का ज्ञान प्राप्त करना।
- ं (४) राज्य की तत्कालीन शासन-पद्धति श्रौर सिद्धान्तों में विश्वासः रखना ।
  - (५) नैतिक चरित्र उच्च रखना।
- (६) श्रपना भरगा पोषण कर सकना, श्रावारा न रहना।
  - (७) कुछ ज्मीन या जायदाद ख़रीदना ।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के उपर्युक्त नियम पालन करने से कोई राज्य उसे अवश्य ही नागरिक बना ले, अथवा, यदि नागरिक बनाये तो उसे सभी राजनैतिक अधिकार प्रदान करें। योरप अभरीका में प्रायः एशिया-निवासियों को नागरिकता प्रदान करने में बहुत अनुदारता का व्यवहार किया जाता है। पिछले वर्षों में जापान-वालों के लिए मार्ग कुछ प्रशस्त हुआ है, अन्य देशों के निवासियों के लिए तो अब भी प्रायः मार्ग बन्द ही है। यद्यपि भारतवर्ष विटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत है, भारतीयों को विटिश उपनिवेशों में नागरिकता-प्राप्त लगभग असम्भव है। इसमें गोरे-काले का मेद माना जाता है। परन्दु वारतिक बात यह है कि भारत पराधीन है। और पराधीन देश के निवासियों का सम्मान जब अपने ही घर में न हो तो बाहर क्या आशा की जा सकती है!

यह तो नागरिकता-प्राप्त की बात हुई। अब इस बात का विचार करें कि नागरिकता विलुत किस प्रकार होती है।

नागरिकता का लोप — पहले बताया जा चुका है कि नाग-रिकता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक श्रीर कृत्रिम। दोनों ही प्रकार की नागरिकता, प्रायः निम्नलिखित बातों से जाती रहती है:-

१—एक राज्य की स्त्री दूसरे राज्य के नागरिक से विवाह करने पर, अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती।

्र-एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य का नागरिक बन जाने पर प्रायः अपने राज्य की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है।

३—जो व्यक्ति अपने राज्य से भिन्न इंगलैंड आदि दूसरे राज्य में, या उसके जहाज पर ही जन्म लेने के कारण, दूसरे, राज्य के भी नागरिक बन जाते हैं, वे बालिंग होने पर सूचना देकर एक राज्य की नागरिकता छोड़ सकते हैं।

४—यदि कोई नागरिक अपने राज्य के निर्धारित अधिकारी को सूचना दिये बिना, बहुत समय तक विदेश में रहे तो उसकी अपने राज्य की नागरिकता जाती रहती है। यह समय मिन्न-मिन्न राज्यों में दस वर्ष या कुछ कम ज़्यादह है। इस प्रकार अपने राज्य की नागरिकता खोनेवाला व्यक्ति, यदि अपने नये निवास-स्थान के राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेता तो वह किसी भी राज्य का नागरिक नहीं रहता। [ सूचना देकर कोई नागरिक चाहे जितने समय तक अपने राज्य से बाहर रहे, जब तक वह अपना कर्तव्य पूरा करता रहेगा और अपने राज्य के प्रति भक्ति-माव रखेगा, वह उसका नागरिक बना रहेगा।

५ — घोर ऋपराध तथा दुर्व्यवहार के कारण भी नागरिकता का लोप हो जाता है। नागरिकता का विस्तार—पहले कहा गया है कि प्राचीन काल में राज्यों का चेत्रफल बहुत छोटा होता था। बहुत से राज्य एक नगर तक ही परिमित होते थे। फल-स्वरूप उन राज्यों के नागिरिकों की नागरिकता का चेत्र भी बहुत सीमित रहना स्वाभाविक था। फिर, इन नगर-राज्यों में भी खियों को नागरिक नहीं माना जाता था, इसके अतिरिक्त उस समय नगरों की जनता में बहुत बड़ी संख्या दासों की होती थी। इस प्रकार हिसाब लगाने से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उस समय नागरिकता का चेत्र कितना कम था। अब दास-प्रथा के हटने तथा खियों को नागरिक अधिकार मिलने से तो नागरिकता का चेत्र बढ़ा ही है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी इस चेत्र की वृद्ध हुई है।

प्राचीन काल में नगर-राज्यों के कारण, नगर-निवासी ही नागरिक माने जाते थे; गाँववालों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। प्रामवासी इसके योग्य ही नहीं सममें जाते थे। उनके हितों की नितान्त उपेद्धा की गयी। अभी तक भी यह बात बहुत-कुळु पायी जातों है। अस्तु, जब राज्यों का चेत्र क्रमशः बढ़ा, तो न केवल प्रधान नगर के निकटवर्ती गांव ही, वरन अन्य नगर भी राज्य के भाग होने लगे। राज्य के चेत्र की वृद्धि का परिणाम नागरिकता का विस्तार था ही। आज-कल एक-एक राज्य का चेत्रफल लाखों वर्गमील, तथा जन-संख्या करोड़ों व्यक्तियों की है; और, राज्य में स्त्रियों तथा दासों अदि की कोई श्रेणी ऐसी नहीं है जो नागरिक अधिकारों से वंचित हो। इसलिए अब नागरिकता का चेत्र पहले की अपेद्धा कई गुना विस्तृत है। अद एक नागरिक के अधिकारों श्रोर कर्तव्यों का सम्बन्ध दूर-दूर तक विस्तृत है।

कुछ राज्यों ने बढ़कर साम्राज्य का स्वरूप घारण किया है। यों तो साम्राज्य प्राचीन काल में भी थे, पर उस समय. एक समय में प्रायः वे एक-दो ही होते थे, अब तो इकट्ठे एक-साथ कई साम्राज्य हैं। अधिकाँश भू-भाग इन साम्राज्यों में से किसी-न-किसी के अन्तर्गत हैं। ऋस्तु, अब होना तो यह चाहिए था कि नागरिकता का चेत्र भी उसी परिमाण में बढता, जिस परिमाण में साम्राज्यों का आकार-प्रकार बढा है। साम्राज्य के अन्दर रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को साम्राज्य भर में घूमने फिरने श्रौर नागरिक श्रधिकारों के उपयोग करने का श्रवसर मिलता । परन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं । प्रायः प्रत्येक साम्राज्य के अन्तर्गत कुछ भाग स्वाधीन, कुछ अर्द्ध-स्वाधीन और कुछ पराधीन होते हैं। स्वाधीन भागों के निवासियों को जो अधिकार होते हैं, वे अन्य भागों के निवासियों को नहीं होते। इस समय कई-एक साम्राज्य गौरांग लोगों के हैं और इन साम्राज्यों के स्वाधीन भागों में भी प्राय: गोरांग लोगों की ही विशेषता है। इस प्रकार साम्राज्यों में गोरे और काले ( श्रथवा पीले ) का प्रश्न उपस्थित है, श्रीर इसके कारण नागरिकता का विस्तार बुरी तरह रुका हुआ है। साम्राज्य की नाग-रिकता का अर्थ लोगों के लिए. अपने देश की स्वाधीनता या पराधीनता के परिमाण के श्रनुसार, भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरणवत् ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता का जो अर्थ केनेडा या आस्ट्रेलिया आदि के नागरिकों के लिए हैं. वह भारतवासियों के लिए नहीं।

श्रमेक विचारशील सजन नागरिकता के लिए श्राधुनिक साम्राज्यों की सीमा को भी ठीक नहीं समम्तते। उन्हें इससे श्रमुदारता के ही भावों का परिचय मिलता है। भिन्न-भिन्न साम्राज्यों के पारस्परिक मनोमालिन्य श्रीर संघर्ष को देखकर यह घारणा उचित ही है कि साम्राज्यवाद का श्रन्त होना चाहिए। प्रत्येक राज्य श्रपने-श्रपने कार्य का संचालन करने में स्वतंत्र हो तथा एक-दूसरे की यथा-शक्ति सहायता करे। श्रीर, सद्गुण-सम्पन्न प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का निवासी हो, संसार भर का नागरिक माना जाय। वह कहीं जाय, कहीं रहे, वह श्रपने कर्तव्यों का पालन करे, श्रीर सर्वत्र उसके न्यायोचित श्रिषकारों की रक्षा हो। इसमें गोरे-काले का, ब्राह्मण श्रीर श्रद्भ का, पूँजीपति श्रीर मज़दूर का, योरपियन श्रीर एशियाई नगर-नवासी श्रीर ग्राम-निवासी श्रादि का मेद न होना चाहिए। यह मेद हमारी चुद्रता का स्चक है। हमें विश्व-नागरिक बनना चाहिए।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या विश्व-नागरिक सम्बन्धी बात बहुत ऊँची है। नागरिकता-सम्बन्धी इस आर्दश की भावना कुछ लोगों को बेहद ऊंची प्रतीत होगी, वे इसे शेखचिल्ली का स्वप्न या अव्यावहारिक भी कहें तो आश्चर्य नहीं। निस्सन्देह, वर्तमान परिस्थित में बहुत कम आदिमियों ने विशाल मान-वता का, अथवा मनुष्य-मात्र की एक विशाल आत्मा की कल्पना की है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाकर भी अपना स्वार्थ-साधन करने में

लगा है। परन्तु आशा है, इस चुद्रता पर मानवता विजय प्राप्त करेगी। प्राचीन काल से नागरिकता का च्लेत्र क्रमशः बढ़ता आया है, यह इम ऊपर बता चुके हैं। इस वृद्धि में समय-समय पर कुछ स्कावटें भी आयी है, पर वे अस्थायी रही हैं। विन्नों ने प्रगति को कुछ समय के लिए रोका है, परन्तु अन्ततः प्रगतिशीलता की ही विजय हुई है। इम पहले से इतने आगे आ गये हैं, तो क्या अब और भी आगे न बढ़ें गे? प्राचीन नगर-राज्य की नागरिकता का सम्बन्ध अधिक-से-अधिक कुछ हज़ार व्यक्तियों तक सीमित या। अब बड़े-बड़े राज्यों में नागरिकता का चेत्र करोड़ों व्यक्तियों तक विस्तृत है। स्वयं भारतवर्ष को, स्वतंत्रता प्राप्त करने पर, इस दिशा में और भी अच्छा उदाहरण उपस्थित करना है। भारतीय नागरिकता का चेत्र साधारण तौर से यहाँ की चालीस करोड़ जनता तक होगा। इम अगने भारतीय बंधु औं से विश्व-नागरिकता का विशाल और व्यापक तथा अनुकरणानीय हण्टांत उपस्थित किये जाने की प्रतीक्षा में हैं।

नागरिक आदशं — इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व एक बात की श्रोर पाठकों का ध्यान दिलाना आवश्यक है। राज्य में नागरिक भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। किसी नागरिक का अपने लिए कोई काम निश्चित करना उसकी धिच, योग्यता, शक्ति या परिस्थिति पर निर्भर होता है। परन्त वह चाहे जो काम करे, उसे जी लगा कर करे, अधिक-से-अधिक उत्तम रीति से करे, और लोक-हित का ऊँचा आदर्श रख कर करे। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का निरन्तर ध्यान रखता है, और इस विचार को कार्य-रूप में परिस्थत करता रहता है,

वहीं सयोग्य नागरिक है। कुछ श्रादमी सोचा करते हैं कि नागरिकता सम्बन्धी इन बातों को सोचने-विचारने का काम कैवल कुछ ख़ास-ख़ास मुट्टी-भर श्रादमियों का है। साधारण किसान, मज़द्र श्रीर दकानदारों को इन बातों से क्या प्रयोजन ! ये तो अध्यापकों, लेखकों और संपा-दकों श्रादि से ही सम्बन्ध रखती हैं। हमारा साग्रह निवेदन है कि उक्त घारणा बहुत दृषित एवं अनिष्टकारी है। नागरिक शास्त्र केवल पढ़ने-लिखने या सोचने विचारने का विषय नहीं है। वह मनुष्य को कर्तव्य-पालन की प्रेरणा देता है। हम चाहे जिस चेत्र में काम करनेवाले हों. हमें अपने नागरिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। जिस मानव-समाज में हमारा जन्म हुआ है, जिससे हमने नाना प्रकार के विचार तथा सुविधाएँ प्राप्त की हैं, उसका यथा-शक्य हित करना इमारा कर्तव्य है। इमने संसार को जिस रूप में पाया, उससे यथा-संभव कुछ बेहतर हालत में छोड़ने का हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। इमसे यह आशा की जाती है कि इम समाज की सभ्यता. संस्कृति श्रादि को कुछ-न-कुछ श्रागे बढ़ाने में सहायक हों। इसको मलना नागरिक आदर्श की अवहेलना करना है। यह उचित नहीं। श्रस्तु, किसान या मज़दूर श्रादि भी, यदि वह श्रपने श्रधिकारों का ठीक उयपोग करनेवाला, श्रीर श्रपने कर्तव्यों का सम्यक पालन करनेवाला है, तो वह सुयोग्य नागरिक है। (अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में विशेष श्रागे लिखा जायगा) । इसके विपरीत, जो व्यक्ति श्रपने अधिकारों का दुरुपयोग या कर्तन्यों की अवहेलना करता है, वह नागरिकता की डिब्ट से निम्न-भेगी का है, चाहे वह कोई भी कार्य

करे, चाहे वह जिस उच्च पर प्रासीन हो, श्रथवा चाहे वह ऊँची कही जानेवाली जाति का ही क्यों न हो।

श्रस्तु, प्रत्येक नागरिक का श्रादर्श श्रपनी परिस्थित के श्रनुसार श्रात्म-विकास के साथ, दूसरों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वा-धीनता, मनोरञ्जन, भ्रातु-माव श्रीर समानता प्रचार श्रादि में कोई एक या श्रधिक होना चाहिए। हम सत्य की खोज करनेवाले हों. हमारे कार्यों में शिव (कल्याण ) की भावना हो, हम सौन्दर्य के प्रेमी हों। केवल सत्य, या केवल शिव या केवल सौंदर्य से इध्ट-सिद्धि न होगी। श्रयवा विचार कर देखें तो यों भी कह सकते हैं कि वास्तव में सत्य वही जो शिव श्रीर सौन्दर्य-युक्त है, श्रीर शिव वही है जो सत्य श्रीर सौन्दर्य सहित है। विविध मानवी गुण सत्य, शिव श्रीर शौन्दर्य के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। हमें चाहिए कि इनमें से किसी एक या अधिक को आदर्श मान कर इस इस सुष्टि की पूर्णता में सहायक हों। संसार-यात्रा में, नागरिक जीवन में, सहयोग की बड़ी श्रावश्यकता है। प्रत्येक नागरिक अपने साथ दूसरों की उन्नति का लक्ष्य रखकर, सबके लिए हो, तथा सब नाग-रिक समिष्ट रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत उन्नति का पर्य प्रशस्त करने वाले हों। इस प्रकार प्रत्येक सबके लिए, और सब प्रत्येक के लिए हों। तभी नागरिकता वास्तव में नागरिकता है और नागरिक शास्त्र का ज्ञान सार्थक है।



## इक्कीसवाँ परिच्छेद नागरिकों के अधिकार

नागरिकता में अधिकारों और कर्तन्यों का समावेश होता है। अब हमें इन्हों के सम्बन्ध में विचार करना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, और आगे भी बताया जायगा, अधिकारों और कर्तन्यों का स्रानिवार्य सम्बन्ध है, प्रत्येक अधिकार के साथ एक विशेष कर्तन्य भी सम्बद्ध है। परन्तु विषय-विवेचन की दृष्टि से हम इनका अलग-अलग विचार करेंगे। इस परिच्छेद में अधिकारों में विषय में, और अगले में कर्तन्यों के विषय में लिखा जायगा।

अधिकारों के लक्षण—श्रिषकारों का हेतु यह होता है कि नागरिक, समाज में रहते हुए श्रिपना जीवन भली भाँति व्यतीत कर सके, उसके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता रहे. उसमें बाधाएँ न आवें। जिन बाधाओं के श्राने की सम्भावना हो, उनके सम्बन्ध में राज्य समुचित व्यवस्था करें। श्रापने श्रिषकार प्राप्त कर नागरिक श्रिपना विकास करता है, तो इससे उसका तो हित होता ही है, समाज का भी लाभ है। अधिकारों के उपयोग से नागरिकों को इस योग्य होने में सहायता मिलती है कि वे दूसरों की सेवा अधिक कर सकें, और उनके विचारों, कार्यों तथा अनुभवों से समाज का अधिक कल्याया हो।

राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकार सम्बन्धी मांग का महत्व बराबर समऋना चाहिए। नागरिकों में कुछ प्रा-कृतिक अन्तर होता है। यथा, उनके शरीर के आकार, स्वास्थ्य, सुडौल-पन, रंग श्रादि में श्रसमानता रहती है। प्रायः राज्य इसे दुर नहीं कर सकता । परन्त जहाँ तक उसका सम्बन्ध है वह नागरिकों से समान व्य-वहार कर सकता है, वह उनकी उस श्रसमानता को बहुत-कछ कम कर सकता है, जो सुविधाओं के न्यूनाधिक होने से होती है। राज्य को चाहिए कि सब नागरिकों को अपनी उन्नति करने का अवसर समान रूप से दे; स्कूल, चिकित्सालय, सार्वजनिक सड्कें, कुएँ, उद्यान, पुस्तकालय, वाचनालय श्रादि के उपयोग का अवसर सब को के समान मिले । कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान हों। न्यायालय सब के लिए खुले हों, तथा न्याय-शुल्क अर्थात् अदालती क्रीस आदि इतनी कम हो कि ग्रीव श्रादमी भी न्याय से वंचित न रहे। इसी प्रकार राजनैतिक श्रिधिकारों के सम्बन्ध में भी राज्य नागारिकों की जाति, रंग, माली हालत, श्रथवा धर्म या मत श्रादि के कारण उनमें कोई मेद-भाव न रखे, उसकी दुष्टि में सब समान हों।

कोई श्रधिकार वास्तव में श्रधिकार उसी दशा में कहा जा सकता है, जब वह राज्य की श्रोर से मान्य हो। उसका स्वरूप क़ानुन द्वारा निश्चित हो, श्रीर वह न्यायालय में सिद्ध किया जा सके। जिस श्रिधिकार के विषय में यह बात नहीं होती, उसका श्रिस्तित्व हमारी कल्पना में ही है, व्यवहार में उसका कोई मूल्य नहीं।

राज्य में नागरिकों के अधिकार देश-काल के अनुसार बदलते रहते हैं। नये-नये क़ानून बनते हैं उनसे पुराने अधिकारों के स्व-रूप में संशोधन होता है और नये अधिकारों की सृष्टि होती जाती है। \* बहुधा नागरिकों को अपने अधिकार राज्य द्वारा मान्य कराने के लिए काफी संघर्ष लेना पड़ता है। इंगलैंड आदि जो राज्य अपनी नागरिक स्वतंत्रता का गर्व करते हैं, उनका इतिहास इस बात की सचाई को सबित करनेवाली घटनाओं से भरा पड़ा है।

एक प्रश्न हो सकता है। जब अधिकारों का हेतु यह है कि
नागरिकों का विकास हो, अधिकार वह शक्ति है, जिसे प्राप्त कर नागरिक अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह करने में समर्थ होता
है, और जब नागरिकों को उन्नित और हित में राज्य की उन्नित
और हित है, तो अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य और नागरिक में संघर्ष
क्यों होता है? नागरिक अपने विकास के लिए जो परिस्थिति चाहते
हैं, वह उन्हें तत्काल क्यों नहीं प्राप्त होती? बात यह है कि
मनुष्य की मौति राज्य भी विकास-शील है, उसमें उन्नित की अभी
बहुत गुआहश है, वह अभी पूर्णता को नहीं पहुँचा है। राज्य के क़ानून
भी अपूर्ण हैं। अतः जब उसका कोई विशेष अंग—बुद्धिमान और

<sup>\*</sup>क भी-क भी युद्ध आदि विशेष परिस्थिति भर के लिए नागरिकों के अधिकार सीमित भी कर दिये जाते हैं।

प्रतिभाशाली नागरिक — अपने विकास के लिए किसी अधिकार की माँग करता है तो राज्य उसकी उपयोगिता तुरन्त नहीं समक्त पाता। फलतः दोनों में मत-मेद होता है, जो कमी-कभी भीषणा अवस्था को पहुँच जाता है। नागरिकों को कानून भंग करने की, और फल-स्वरूप कठोर दंड सहन करने की जोखम उठानी पड़ती है। साहसी नेता पीछे हटना नहीं चाहते। अन्ततः राज्य को अपने कानून का संशोधन करना या नया क्रानून बनाना, और नागरिकों के प्रस्तावित अधिकार को मान्य करना पड़ता है। इस प्रकार राज्यादि मानवी संस्थाओं के विकास की मंजिलें कितनी दुर्गम और कठिन हैं! अस्तु, संचेप में नागरिक अधिकारों के मुख्य लक्षणा ये होते हैं:—

- (क) वे नागरिकों के पूर्णता प्राप्त करने तथा अपनी विविध शक्तियों का विकास करने में सहायक हो।
- (ख) राज्य के सब व्यक्ति उनका समान उपयोग कर सकें; ऐसा न हो कि कुछ विशेष व्यक्ति या संस्थाएँ ही उनसे लाम उठावें, और दूसरे उसी प्रकार की स्थितिवाले होने पर भी उनसे विचित रहें।
- (ग) वे राज्य द्वारा मान्य हों; यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति सनूह, नागरिकों द्वारा उनके उपयोग किये जाने में बाधा उपस्थिति करे, तो राज्य के न्यायालय उनकी समुचित रक्षा करें।

श्रिषिकारों का श्राधार; योग्यता—नागरिकों के श्रिषकारों का श्राधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, इसमें स्त्रीयुक्ष, धनी - निर्धन का, या जाति श्रथवा धर्म श्रादि के भेद

का विचार किया जाना अनुचित है। अधिकाँश देशों में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों की अपेचा बहुत कम रहे हैं। इस समय भी कितने-ही राज्य स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी के श्रिधिकार देने में सहमत नहीं हैं। बहुत-से राजनीतिशों का मत है कि कुछ नागरिक अधिकार तो स्त्रियों को विशेष दशा में ही मिलने चाहिए। अनय अधिकारों के वास्त कानून के अनुसार पुरुषों के लिए जितनी उम्र की आवश्यकता हो. उसकी अपेचा स्त्रियों के लिए अधिक परिमाख रखा जाय. जिससे उस अधिकार को प्राप्त करनेवाली स्त्रियों की संख्या कम रहे । त्राधिनक काल में. इस विषय में लोगों के विचार क्रमशः उदार होते जा रहे हैं। श्रव हित्रयों को ऐसे श्रधिकारों से वंचित करना उचित नहीं समभा जाता, जिन्हें प्राप्त कर वे राष्ट्र की उन्नति में सद्दायक हो सकती हैं। श्रवश्य ही स्त्रियों के वास्ते एक महत्व-पूर्ण कार्य संतान का पालन-पोषण श्रीर सुयोग्य नागरिक तैयार करना है। तथापि जिन महिलाश्रों की रुचि श्रीर प्रवृत्ति पारिवारिक दोत्र की श्रपेक्षा सार्वजनिक दोत्र में कार्य करने की विशेष रूप से हो. उन्हें, स्त्री होने के कारण उससे वंचित रखना ठीक नहीं है।

बहुत-से देशों में कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में व्यक्तियों की आर्थिक क्षमता को बड़ा महत्व दिया जाता है। उदाहर एपार्थ अधिकांश देशों में ऐसे नियम प्रचलित हैं कि इतने रुपये मासिक किराये के मकान में रहने वाले को, या इतने रुपये मालगुज़ारी या टैक्स के रूप में देने-वाले को मताधिकार प्राप्त हो। ऐसे नियमों से वे व्यक्ति इन अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, जिनकी आर्थिक क्षमता इससे कम हो। ऐसे व्यक्तियों में अनेक आदमी ऐसे हो सकते हैं, और होते हैं जिनकी राजनैतिक योग्यता दूसरों से किसी प्रकार कम नहीं होती, वरन् अनेक दशाओं में ज़्यादा ही होती है। इसिलए इम अधिकारों के लिए साम्पत्तिक सामर्थ्य का ऐसा प्रतिबन्ध अनुचित समभते हैं, जिसके कारण अनेक नागरिक अपने राज्य की सेवा या उन्नति करने में भाग न ले सकें। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित रखना ठीक है, जो शरीर तथा मन से अम करने योग्य होकर भी परावलम्बी हों, और मुफ्त की रोटो खाते हों। ऐसी व्यवस्था करने से नागरिकों में स्वावलम्बन के भाव की वृद्धि होगी, जो राज्य की उन्नति एवं स्वयं उन व्यक्तियों के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में एक श्रीर भी बात विचारणीय है। समाज में कुछ श्रादमी त्याग श्रीर परोपकार के भाव से जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं। वे ऐसा काम करते हैं जिससे श्रार्थिक प्राप्ति विशेष नहीं होती, यों वह काम राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। श्रथवा वे सार्वजनिक संस्थाओं में श्रवैतनिक या बहुत कम पुरस्कार लेकर सेवा करते हैं। उनका रहन-सहन साधारण होता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिए भूषण हैं। श्रव यदि श्रार्थिक क्षमतावाला उपर्युक्त नियम राज्य में प्रचलित हो तो ऐसे सज्जन श्रपने श्रधिकार से वंचित रहते हैं श्रीर राज्य उनके तत्संबन्धी बहुमूल्य सहयोग से लाम नहीं उठा सकता। यह बात श्रत्यन्त चिन्तनीय है।

्रश्रिषिकारों के सम्बन्ध में जाति धर्म, या सम्प्रदाय श्रादि का विचार करना भी श्रनुचित है। राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह

किसी भी जाति या धर्म का हो, उतना ही श्रिधिकार मिलना चाहिए. जितना अन्य धर्म या जातिवालों को: उससे अधिक या विशेष नहीं। जब राज्य में कई जातियों तथा धर्मों के ब्रादमी रहते हैं तो किसी एक जाति या धर्मवालों को स्वतन्त्र अर्थात् विशेष अधिकार देने का. अधि-कारों को जाति-गत या धर्मानुसार निर्धारित करने का. परिखाम यह होता है कि कुछ लोगों के साथ पक्षपात होता है. श्रीर दसरों को हानि पहेँचती है। इस प्रकार नागरिक जीवन की सुख-शान्ति नष्ट होती है। श्रतः जाति-गत या धर्म-गत श्रिधकारों की विष्वंसक कल्पना को तिलांजिल दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को, कभी-कभी विशेष आवश्यकता होने की दशा में, कुछ निर्धारित समय के लिए, कुछ विशेष सुविघाएँ भले ही दे दी जायँ, परन्तु जाति या धर्म के श्राघार पर किसी के साधारण और स्थायी नागरिक श्राधकारों में कुछ कमी-वेशी नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष में मुसलमानों को विशेष मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व दिये जाने का परिणाम कितना भयानक हुआ है, श्रौर उससे साम्प्रदायिकता तथा नित्य प्रति का पारस्परिक कलह और राग-द्रेष कितना बढ़ गंया है, इसका दुखदायी अनुमव समाज के सामने है।

नागरिक श्रिषिकारों के सम्बन्ध में कुछ व्यापक बातों का विचार करने के उपरान्त श्रव हम कुछ मुख्य-मुख्य श्रिषकारों में से प्रत्येक के विषय में श्रवग-श्रवग विखते हैं।

जान-माल की रक्षा -- यदि नागरिक का जीवन सुरिच्चित न

हो तो वह न अपनी उन्नित कर सकता है, श्रीर न दूसरों की उन्नित में सहायक हो सकता है। इसिलए राज्य में नागरिकों की रक्षा के वास्ते सेना श्रीर पुलिस रखी नाती है। इसके विषय में श्रन्यत्र लिखा जा चुका है। अस्तु, पुलिस आदि की सहायता प्रत्येक अवसर पर मिलनी कठिन होती है, और संकट चाहे जब आ सकता है। अतः प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होता है कि आवश्यकता उपस्थित होने पर वह स्वयम् ही शत्रु या आक्रमणकारी से अपनी तथा दूसरे बन्धुओं की रक्षा कर सके। इसके लिए नागरिकों को हथियार रखने की श्रनुमतिरहती है।

यह कहा जा सकता है कि क्या शान्तिमय उपायों से श्रात्म रक्षा नहीं की जा सकती ? क्या श्राहंसा का बल कुछ बल नहीं है ? हमारे लिए श्रवश्य ही यह श्रामिमान का विषय है कि महात्मा गांधी श्रादि महानुभाव मनुष्य को श्राने प्रेम-बल से परिचित कराने का उद्योग कर रहे हैं। मानव-जाति के लिए वह दिन बड़े सौमाग्य का होगा जब उसे इस बात का श्रनुभव हो जायगा कि श्रव्य-बल तो पशु-बल का स्वरूप है, मनुष्य के योग्य नहीं। मनुष्य को तो दूसरे मनुष्य (एवं पशुश्रों) पर विजय प्राप्त करने के लिए श्राहंसात्मक उपायों से ही काम लेना चाहिए। किन्तु वह दिन श्रभी दूर प्रतीत होता है, जब श्राहंसात्मक उपायों का प्रयोग कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक परिमित न रहकर सर्वंदाधारण द्वारा सफलता-पूर्वक हो सकेगा। श्रव्यु, वर्तमान श्रवस्था में नागरिकों को श्रात्म-रक्षा के लिए श्रस्त रखने का श्रविकार होना चाहिए। किसी राज्य के नागरिकों को हिथार न रखने देना, उन्हें दूसरों का श्रत्याचार सहन

करनेवाला बना देना श्रनुचित है। राज्य के लिए भी यह हानिकर है। निदान, नागरिकों को श्रावश्यक श्रस्त्र रखने में कोई क़ानूनी बाधा न होनी चाहिए।

 यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या इत्यारों श्रीर विद्रोहियों को भी जीने का अधिकार है ? पहले असम्यावस्था में आदमी प्राय: जान के बदले जान लेते थे। श्रव सभ्यावस्था में भी यह प्रथा चली श्राती है। हाँ, प्राचीन काल में हत्यारे की जान मृत व्यक्ति के सम्बन्धी क्षेते थे, अब यह काम जनता की एक संगठित संस्था अर्थात सरकार करती है। इत्यारों के श्रतिरिक्त कुछ ख़ास राज-विद्रोहियों को भी फौंंंंंंंं की सज़ा दी जाती है । प्राया-दंड की बात सुनने के इस इतने श्रादी हो गये हैं कि हमें इसके श्रीचित्य के विषय में विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सोचना चाहिए कि किस परिस्थित में, किन कारणों से प्रेरित होकर, किसी ने इत्या की है. श्रीर इसमें सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक व्यवस्था कहाँ तक उत्तर-दायी है। . खून करने का कारण प्रायः क्षणिक आवेश, शराबख़ोरी, पागलपन, विषय-वासना, तृष्णा, या राजनैतिक श्रसंतोष की पराकाष्टा श्रादि हुश्रा करती है। इन बातों को दूर अथवा नियंत्रित करने का समाज तथा राज्य की श्रोर से यथा-शक्ति प्रयत्न होना चाहिए। ऐसा न करके प्राया-दंड से काम चलाना राज्य की बड़ी भारी त्रुटि है। प्राया-दंड का कुछ, श्राच्छा फल नहीं निकलता। जिसे यह दंड दिया जाता है, उसे आल्म-सुधार करने का कोई अवसर ही नहीं रहता। रही, उसके जनता पर होनेवाले प्रभाव की बात; सो लोगों

के युद्धों में भाग लेने, या उनका हाल पढ़ते या सुनवे रहने के कारण, उन पर सरकार का इस दंड से विशेष आतंक नहीं जमता। जो लोग राज-विद्रोह आदि में मृत्यु-दंड पाते हैं, उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे अपने विचार-स्वातंत्र्य या देश-प्रेम के कारण बिल-वेदी पर चढ़े। इस बात से दूसरों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। किर, भूल सबसे होती है और निदीं आदिमियों को जजों की भूल से प्राण-दंड मिल चुकने पर भूल सुघारने का कोई उपाय नहीं रहता। यह भी तो सम्भव है कि जिन आदिमियों को आज क्षिणिक अपराध के लिए फौंसी दी जाती है, यदि उनके जीने के अधिकार की रक्षा की जाय, और उनका उचित सुघार किया जाय, तो कालान्तर में उनमें से कुळ व्यक्ति बहुत उपयोगी कार्य कर सकें, वे स्वदेश तथा संसार के हितेषी प्रमाणित हों। हर्ष का विषय है कि धीरे-धीरे प्राण-दंड उठता जा रहा है। पर अभी इस दिशा में बहुत कार्य होना शेष है।

श्रात्म-रक्षा से मिलती हुई एक श्रौर बात भी विचारणीय है। कभी-कभी नागरिक स्वयं ही अपने श्रात्म-रच्चा सम्बन्धी श्रिषकार को भूल जाते हैं। बहुधा श्रज्ञान, श्रन्थ-विश्वास, मदान्धता, श्रत्यन्त कोध, निराशा, शोक, श्रथवा कभी-कभी भूख-प्यास के ही घोर कष्ट के कारण, मानस्कि विकार की श्रवस्था में, श्रादमी श्रात्म-इत्या करने लगते हैं। ऐसे श्रवसर पर श्रादमी श्रपने श्रापको निरर्थक समभति हैं। परन्तु, उनका यह निर्णय किसी गम्भीर विचार पर निर्भर नहीं होता, वे श्रावेश में ऐसा सोचते हैं। बहुधा जब कोई व्यक्ति श्रात्म-हत्या के

प्रयत्न में एफल नहीं होता तो वह पीछे शान्ति से विचार करने पर अपनी मूल का अनुभव करता है, और अपने जीवन की भली भांति रक्षा करने का प्रयत्न करता हुआ मिलता है। अनेक दशाओं में उसका जीवन बहुत उपयोगी भी प्रमाणित हुआ है। फिर, मनुष्य के जीवन की उपयोगिता का विचार केवल उसी की हिष्ट से नहीं किया जाना चाहिए, राज्य के हिष्ट-कोण से भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता, जो राज्य के वास्ते सदैव के लिए निर्थंक हो गया हो। अतः आत्म-हत्या निन्दनीय है, वह एक अपराध है, अपने प्रति, कुटुम्ब के प्रति, और राज्य के प्रति भी। राज्य का कर्तव्य है कि उसका दमन करे, और यथा-सम्भव उन कारणों को दूर करे जिनसे नागरिक अपनी प्यारी जान स्वयं खो देने को उद्यत

कभी-कभी दूसरों की सेवा या हित का विचार करके, कोई महानुभाव श्रामरण उपवास प्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुःख
को श्रपना दुःख मानता है, श्रीर श्रपने प्राणों की बाज़ी लगाकर
उसे दूर करने का श्रिभलाषी होता है। मेक्स्विनों ने श्रायरलैंड की
स्वतंत्रता के लिए चौहत्तर दिन उपवास करके श्रपने प्राण त्याग
दिये। महात्मा गांधी ने हरिजनों को निर्वाचन कार्य में हिन्दुश्रों से
से पृथक् किये जाने के प्रस्ताव पर श्रामरण उपवास किया था। श्रन्त
में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा जी की बात मान ली, श्रीर उनके
प्राण बच गये। ऐसे महानुभावों को श्रात्म-हत्या का श्रपराधी कहना
कहां तक उचित है १ इन्हें कोई दंड भयमीत नहीं कर सकता। इन्हें

'श्रात्म-इत्या' के प्रयत्न से बचाने के लिए समाज श्रीर राज्य को इनका हिन्द-कोण समभत्ना श्रीर यथा-सम्भव इनके मतानुसार व्य-वहार करना चाहिए।

सम्पत्ति की रक्षा — नागरिकों की जान की भाँति उनके माल की रचा भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए खाने-पीने आदि के खामान की ज़रूरत होती है। इसिए प्रत्येक नागरिक को चोर-डाकुओं से इसकी सुरचा करने का अधिकार दिया जाता है। इसके वास्ते भी नागरिकों को इथियार रखने की आवश्यकता होती है। और उन्हें इस की अनुमति दी जाती है। अस्त्र रखने के सम्बन्ध में विशेष विचार पहले किया जा चुका है। यदि राज्य ही नागरिकों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व ले लेता हैं, और नागरिकों को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का निषेध कर देता है, जैस कि रूस की सम्यवादी सरकार का प्रयत्न है, तो नागरिकों को अपनी निजी सम्पत्ति रखने की आवश्यकता नहीं रहती। फल-स्वरूप वहाँ सम्पत्ति-रक्षा सम्बन्धी अधिकार का प्रश्न भी नहीं रहता।

सम्पत्ति की केवल चोर-डाकुओं से ही रह्मा की जानी आवश्यक नहीं है। इस बात की भी बहुत ज़रुरत है कि लोगों द्वारा उत्पन्न किये हुए धन में से राज्य ही किसी-न-किसी बहाने से, बहुत-सा भाग न ले लिया करे। यदि किसान को यह भय रहे कि जो-कुळ धन वह उत्पन्न करेगा, उसका बड़ा भाग राज्य मालगुज़ारी या आवपाशी आदि के रूप में ले लेगा, तो उसे दिन-रात कड़ी मेहनत करने, और धूप-छाँह, सर्दी-गर्मी तथा बरसात सहने का हेतु ही क्या रहे। भारतवर्ष में श्रमेक किसान ऐसे हैं जिन्हें श्रपने उत्पन्न धन से श्रपने गुजारे लायक श्रन-वस्त्र भी नहीं मिलता। उन्नत राज्य मालगुज़ारी या टैक्स श्रादि लेने में यह ध्यान रखते हैं कि नागरिकों के पास सुख-पूर्वक जीवन न्यतीत करने योग्य श्राय श्रवश्य रहे। उन्हें यथेष्ट भोजन-वस्त्र श्रीर मकान ही नहीं, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य श्रादि के भी साधन मिलने चाहिए। ऐसा न होने की दशा में नागरिक के न्यक्तित्व का विकास नहीं होता श्रीर नागरिक राज्य की जैसी चाहे वैसी सेवा नहीं कर सकता।

श्रार्थिक स्वतंत्रता—प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि अपनी आजीविका के लिए वह खेती, व्यापार, नौकरी या मज़दूरी आदि जो भी काम उसे सुविधाजनक प्रतीत हो, करे। जब उसका मन चाहे, वह अपने पहले धंधे को छोड़ कर दूसरा धंधा करने लग जाय; हाँ, ऐसा करने में वह अन्य नागरिकों का, अथवा सार्वजनिक सुविधा का यथेष्ट ध्यान रखे। नागरिक का अधिकार है कि वह अपने अम का उचित प्रतिफल ले, और इतने अधिक समय या ऐसी प्रतिकृत परिस्थिति में काम न करे, जिससे उसके स्वास्थ्य की हानि हो। अनेक कारखानेवाले तथा अन्य मालिक अपने यहाँ मज़दूरों से इतने अधिक घंटे काम लेते हैं, तथा काम करने की जगह ऐसी रखते हैं कि मज़दूर बीमार पड़ जाते हैं। राज्य को चाहिए कि इस विषय में समुचित प्रवन्ध करे। अब जगह-जगह कारखाना-क़ानून बनजाने से मज़दूरों के हितों की कुछ रक्षा होने लगी है, पर अभी इस दिशा में और भी बहुत कार्य होने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरों से मज़दूरों के हितों की अछ रक्षा होने लगी है, पर अभी इस दिशा में अगैर भी बहुत कार्य होने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरों से मज़दूरों के हितों की अधिक अधिक होने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरों से मज़दूरों के हितों की अधिक अधिक होने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरों से सज़दूरों में मज़दूरों होने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरों के हितां की अधिक अधिक स्वत्य होने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरों

(तथा श्रन्य व्यक्तियों से) श्रव तक भी वेगार ली जाती है, यह श्रमुचित है। यह प्रथा बन्द की जानी चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है, उसे उसके पारिश्रमिक से श्रंशतः वंचित रखना भी श्रम्याय है, फिर पूर्णतः वंचित रखना तो नितान्त श्रम्रह्म समभा जाना चाहिए।

श्राधुनिक समय में कल-कारखानों के प्रचार तथा उत्पत्ति के साधन—भूमि, पूँजी श्रादि—पर कुछ पूँजीपतियों का श्राधिपत्य होने से प्रत्येक राज्य में बेकारों की संख्या बहुत बढ़ चली है श्रीर उत्तरीत्तर बढ़ती जाती है। श्रातः यह श्रावश्यक है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के कायों पर राज्य का समुचित नियंत्रण रहे, देश में यह शिल्प का प्रचार हो, श्रीर जिन श्रादिमियों को श्रपने निर्वाह-योग्य काम-धन्धा न मिले, उन्हें राज्य की श्रोर से श्रावश्यक कार्य दिये जाने का श्रायोजन रहे। साथ ही इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि किसी व्यक्ति को विना श्रम, मुक्त में ही, दूसरों की कमाई के श्राधार पर मौज न उड़ाने दिया जाय।

्हमने कहा है कि जो व्यक्ति बेकार हो, उसकी आजीविका की व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए। इसकी तह में भाव यह है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यदि वह भोजन-वस्त्र के अभाव से कष्ट पाता है, और प्राण छोड़ता है, तो इसके लिए राज्य उत्तरदायी है। चाहे यह बात आधुनिक स्थिति में पूर्णतः व्याव-हारिक प्रतीत न हो, तथापि कोई व्यक्ति विचारणीय तो अवस्य है। प्रायः उन्नत राज्य इस दिशा में भरसक ध्यान देते हैं। पाठक

भारतवर्ष की बात देखकर इस विषय में अपना मत स्थिर न करें।
यहाँ तो प्रतिवर्ष अनेक आदमी भूख और प्यास से विकल होकर मर
जाते हैं और सरकारी रिपोर्टों में उनकी मृत्यु का कारण कोई-न-कोई
बीमारी लिख दी जाती है। अधिकारी यह देखते हुए भी नहीं देखते
कि यहाँ कितने ही आदमियों को सात भर में कभी दिन में दो
वक्त भर-पेट भोजन नहीं मिलता। उत्तरदायी राज्यों में यह बात
असहनीय होती है। वहाँ नागरिकों के भरण-पोषण की भरसक व्यवस्था
की जाती है।

इस प्रसंग में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य की जन-संख्या चाहे जितनी बढ़ जाने की दशा में भी राज्य पर सबके भरणा-पोषण का भार होना चाहिए ? आखिर, राज्य की आर्थिक शक्ति परिमित होती है, वह जन-संख्या के अपरिमित रूप से, अत्यधिक बढ़ जाने पर इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन कैसे करेगा ? क्या जन-संख्या की वृद्धि की कुछ मर्यादा न रहनी चाहिए ? और, यह किस प्रकार किया जाय ?क्या कृत्रिम उपायों से संतान-निग्रह किया जाय, या केवल जनता में संयम के भावों का प्रचार किया जाय ?

इस विषय में बहुत मत-भेद है। यहाँ इस संबंध में विस्तार से लिखने का अवसर नहीं है। संदोग में यही वक्तव्य है कि नागरिकों में उत्तरदायित्व और दूरदर्शिता का भाव पैदा किया जाय, जिससे वे यथा-संभव संयम और सदाचार का भाव रखें, और संतानोत्पत्ति की इच्छा होने पर आगो पीछे की परिस्थिति का विचार करके उसे जहां तक सम्भव हो सके, दमन करें। अस्तु, इम नागरिकों का एक अधिकार आर्थिक स्वतन्त्रता मानते हैं, जिसके अन्तर्गत हम समभते हैं कि प्रत्येक नागरिक के जीने का आधिकार सम्मिलित है।

विचार, भाषण और लेखन की स्वतन्त्रता--मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह एक-दूसरे के सहयोग का लाभ तभी उठा सकता है, जब परस्पर में विचार-विनिमय हो। यदि मैं अपने साथी से अपना विचार प्रकट न कर सकुँ और मेरा वह साथी अपना विचार मुभी न बता सके, तो इम दोनों न तो एक-दूधरे के दुख-सुख को जान सकते हैं, और न कोई किसी को कछ सहायता ही प्रदान कर सकता है। इससे सामाजिक जीवन का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। मनुष्य के सब कार्य उसके विचारों के ही परिसाम होते हैं; सामाजिक, श्रार्थिक राजनैतिक या धार्मिक सब प्रकार की उन्नति के लिए विचार-विनिमय की आवश्यकता है। यह कार्य दो प्रकार से होता है भाषण या वार्ता-खाप द्वारा, श्रीर लेखों द्वारा । इस प्रकार नागरिकों को सभा में भाषरा करने, लेख लिखने और छपाने की अर्थात् पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकें श्रादि प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य की श्रोर से इसमें प्रतिबन्ध केवल दुरुपयोग रोकने के लिए ही हो, इससे अधिक नहीं। जहाँ प्रतिबन्ध अधिक होता है, लोगों के विचारों की स्वतन्त्रता रोकी जाती है, वहां समाज श्रंब-विश्वासी श्रौर श्रल्पज रहता है, उसे नयी-नयी विचार-घाराओं, आविष्कारों आदि का ज्ञान नहीं होता, और वह अपनी रोति-रस्मों तथा कार्य-प्रणाली, आदि में त्रावश्यक सुधार नहीं कर पाता। वह कृप-मंडूक बना रहता है: समय के साथ ज्ञान-विज्ञान आदि में प्रगति नहीं कर पाता।

सामाजिक स्वतन्त्रता-नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार खान-पान करें श्रीर कपड़े पहिने। (मादक पदार्थी आदि पर नियन्त्रण किया जा सकता है)। नाग-रिकों के विवाह-शादी, उनके बालकों के भरण-पोषण, रीति-रस्म, खेल-कद. तथा स्वदेश के भिन्न-भिन्न भागों में, एवं विदेशों में जाने-श्राने में कोई श्रनचित बाघा न हो। ये बातें इतनी साधारण हैं कि कल पाठकों को इनके लिखने की श्रावश्यकता भी प्रतीत न होती होगी। परन्त वे विचार कर देखें। श्रनेक बार समाज से इन बातों में बाघा उपस्थित की जाती है। बहुघा समाज चाहता है कि अमुक समय पर व्यक्ति अमुक प्रकार के कपड़े पहनें, अमुक रीति-रहम पूरी की जाय. विवाद-शादी निर्घारित चेत्र में एक विशेष प्रकार से सम्पन्न हो। श्रस्तु, यदि समाज की श्रोर से नागरिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता श्रप-हरण करने की चेष्टा की जाय तो राज्य को उनकी समुचित सहायता करनी चाहिए। श्रावश्यकता होने पर समाज-सुधार के क़ानून भी बनते रहने चाहिएँ। श्रवश्य ही समाज-सुधार के लिए मुख्य श्रावश्यकता लोक मत तैयार करने की होती है. श्रीर हम इस बात के समर्थंक नहीं है कि बात-बात में कानूनों का आश्रय लिया जाय। परन्त यह भी तो निर्विवाद है कि कुछ दशाश्रों में राज्य की सहायता श्रमिवार्य हो जाती है. श्रौर उसे लेने में श्रापत्ति न होनी चाहिए। भारतवर्ष में सर्वी-दाइ श्रीर कन्या-बध कानून द्वारा ही रोका गया, श्रीर श्रव बाल-विवाह को रोकने एवं हरिजनों सम्बन्धी कई सामाजिक बाधाएँ दूर करने के लिए क़ानून की सहायता बहुत महत्व-पूर्ण रही

है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

धार्मिक स्वतंत्रता—नागरिकों को सामाजिक स्वतन्त्रता की मौति धार्मिक स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए। इसका आशय यह है कि वे चाहे जिस धर्म को मानें, चाहे जिस अवतार, पीर, पैग्रम्बर आदि की पूजा करे, मंदिर में जायँ या मसजिद में; घर बैठकर ही भगवद् भजन करें, अथवा न भी करें। इसमें कोई हस्तच्चेप न करे, न भय दिखलाये, और न किसी प्रकार का प्रलोभन दे। राज्य को चाहिए कि नागरिकों की सामृहिक सुविधाओं का ध्यान रखकर समुचित तथा निष्पक्ष नियम बनाये। कुछ नागरिकों के धार्मिक कृत्य से अन्य नागरिकों के मुख-शान्ति या रोज़मर्रा के विविध कामों में कोई वाधा उप-स्थित न हो। यदि बाधा का प्रसंग आये तो राज्य नागरिक अधिकारों की समुचित रक्षा करे।

धार्मिक स्वतन्त्रता की बात बहुत से राज्यों में कुछ समय से ही मान्य हुई है। विगत शताब्दियों में, विशेषतः योरप में, इसके लिए नागरिकों की जान केवल इस वास्ते ली गयी है कि उन्होंने उस धर्म को श्रङ्गीकार न किया, जिसके श्रनुयायी वहाँ के सत्ताधारी श्रौर शासक थे। बहुधा एक धर्म वालों का त्यौहार दूसरे धर्म वालों के लिए घोर संकट-काल रहा है। इस समय वे बार्ते नहीं रहीं, पर पद्मपात की कुछ, कुछ छाया तो श्रव भी विद्यमान है। कई सम्यताभिमानी देशों में सर्वोच्च शासक (बादशाह) का पद किसी विशेष धर्म के श्रनुयायी को ही मिल सकता है, उसका ज्येष्ठ पुत्र कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर ले तो उसे राजगहीं से हाथ धोना पड़े। यह बात कहीं-कहीं कुछ श्रन्थ

पदों के लिए भी है, वे पद घर्म-विशेष के अनुयायियों के लिए सुरिच्छत हैं। वे अन्य नागरिकों को योग्यता होने पर भी नहीं दिये जाते। आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता रहे; राज्य सभी धर्मवालों को समान समभे।

शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार—नागरिकों का उद्देश्य अपना विकास तथा राज्य की उन्नति करना है। पर उनके श्रशिक्षित रहने की दशा में यह कार्य सम्भव नहीं । अतः उन्हें शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। केवल कुछ लिखना-पढ़ना श्रा जाने से ही मतलब विद न होगा । उन्हें इस बात की भी सुविधा मिलनी चाहिए कि वे अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को समभें तथा योग्य काम-घंघा करते हुए अपनी आजीविका प्राप्त कर सकें, जिससे वे दूसरे नाग रिकों श्रथवा राज्य पर भार-स्वरूप न वनें। श्रवः राज्य की श्रोर से न केवल प्रारम्भिक श्रीर माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए. वरन् उद्योग और शिल्प की शिक्ता की भी उसके साथ ही व्यवस्था होनी चाहिए। प्रौढ़ पुरुष-स्त्रियों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ, पुस्तका-लय, वाचनालय, श्रजायबघर श्रादि का भी सम्यक् प्रवन्ध होना चाहिए। अन्यान्य देशों में, भारतवर्ष में, इसकी बहुत आवश्यकता है। विगत वर्षों में, यहाँ जिन प्रान्तों में काँग्रेस सरकारें थीं, उनमें इस विषय की योजनाएँ वनीं और कुछ कार्य भी आरम्भ हुआ। पर पीछे उनके त्याग-पत्र के बाद बहुत-सा कार्य जहाँ का तहाँ रुक गया; कुछ थोड़ा-सा ही कार्य चलता रहा। उसमें भी युद्ध के कारण आर्थिक बाधाएँ श्रा गर्यो । यदि भारतवर्ष में नागरिकों का शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार

मान लिया जाय तथा राज्य की आर से इस विषय की आवश्यक ज्यवस्था हो तो यहाँ के निवासियों को सुयोग्य नागरिक होने में बड़ी सुविधा हो जाय।

राजनैतिक अधिकार—अब नागरिकों के उन अधिकारों की बात लें. जिन्हें 'राजनैतिक' श्रिधकार कहा जाता है। इन श्रिधकारों में मताधिकार, प्रतिनिधि चुने जाने का श्रधिकार और पदाधिकार सिम-लित हैं। मताधिकार के सम्बन्ध में पहले एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा जा चुका है। श्राज-कल लोक-मत प्रायः प्रत्येक बालिग्र व्यक्ति को मताधिकार देने के पक्ष में है: उन्नत राज्यों में जो योड़े-से व्यक्ति इस श्रधिकार से बंचित रहते हैं. वे विशेष कारणवश ही वंचित रहते हैं। जो व्यक्ति मताधिकारी होते हैं, वे प्रायः प्रतिनिधि चुने जाने के भी अधिकारी होते हैं। यदि जनता उनमें आवश्यक गुण समभती है श्रीर इनके पक्ष में श्रधिक मत देती है तो वे प्रतिनिधि चन लिये जाते हैं। इसमें जाति, धर्म या सम्यत्ति आदि का प्रतिवन्ध नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता है कि राज्य में मेरा भी एक स्थान है, शासन-पद्धति के निर्माण अथवा संशोधन में थोड़ा-बहुत, प्रत्यच्च या परोक्ष रूप से मेरा भी भाग है। नागरिक की राज्य के प्रति ममता और भक्ति बढ़ती है, वह समभता है कि मैं राज्य का हूँ श्रीर राज्य मेरा है।

श्रव पदाधिकार की बात लीजिए। नागरिकों को शासन-प्रवन्ध में प्रत्येक पद प्राप्त कर सकने का श्रधिकार होना चाहिए, इससे हमारा यह श्रभिप्राय नहीं कि कोई भी नागरिक चाहे जो पद मांगे,

उसे वह पद श्रवश्य दे दिया जाय । नहीं, हमारा श्राशय केवल यह है कि प्रत्येक शासन-पद के लिए कुछ योग्यता निर्धारित रहनी चाहिए, जो नागरिक उतनी योग्यता का परिचय दे, उसे वह पद दे दिया जाय. उसका रंग, जाति या धर्म श्रादि इसमें बाधक न होना चाहिए। इस श्रिवकार से केवल यही लाभ नहीं है कि कुछ नागरिकों के लिए आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाता है-यद्यपि निर्धन देशों में इसका भी कुछ कम महत्व नहीं होता-वरन् यह भी है कि नागरिकों को राज्य की न्याय-बुद्धि का परिचय मिलता है, उनमें सन्तोष श्रीर राज-मिक के भावों की बृद्धि होती है। इसके श्रतिरिक्त, जब एक नागरिक अपना सार्वजनिक जीवन श्रारम्भ करते समय श्रपनी दृष्टि द्र तक पहुँचा सकता है, जब वह सममता है कि योग्यता प्राप्त करने पर राज्य का कोई भी पद मेरी पहुँच से बाहर नहीं है. तो उसमें एक विशेष प्रकार का स्वाभिमान और उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है, श्रौर उसके विकास में बड़ी सहायता मिलती है। इसके विपरीत, जब नागरिक यह अनुभव करता है कि उच पदों पर नियुक्तियां पत्त-पात-पूर्वक होती हैं तो उसमें श्रात्म-विश्वास श्रीर साहस की मात्रा कम रह जाती है और राज्य का हास होने लगता है।

भारतीय पाठकों के लिए सोचने का विषय यह नहीं है कि उन्हें कौन-कौन-सा पद मिल सकता है, वरन यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन इतने समय तक होते रहने पर भी कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो उन्हें नहीं मिल सकते, चाहे उनमें कितनी ही योग्यता क्यों न हो। कितने ही भारतीय युवक अपने देश में कभी जंगी लाट, गवनंर-जनरल, ग्रह-सदस्य ( होम मेम्बर ), या अपने प्रान्त का गवर्नर आदि होने का स्वप्न देखते हैं ? हमारा अपने देश के शासन पर कितना नियन्त्रण है ? अस्तु, नागरिकों को राजनैतिक अधिकार यथेष्ट रूप में मिलना आवश्यक है।

विशेष वक्तव्य — नागरिक अधिकारों की कोई निर्धारित संख्या नहीं है। हमने ऊपर उदाहरण-स्वरूप कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों के सम्बन्ध में लिखा है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से हो सकते हैं। यथा — न्याय-प्राप्ति का अधिकार, यात्राधिकार, भाषा और लिपि की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अधिकार राज्य द्वारा स्पष्ट और लिखित रूप में मान्य हो। उत्तरदायी और लोक-तन्त्रात्मक शासन में राज्य पर नागरिकों का यथेष्ट नियंत्रण रहता है, और वह नागरिकों के विकास के लिए प्रत्येक उचित मार्ग प्रहण करता है, इसलिए वह नागरिकों के अधिकारोपभोग में बाधक न होकर सदैव प्रगतिशीलता का परिचय देता है। इससे स्वयं उसका भी कल्याण है।

श्रिषकारोपभोग के साथ विशेष स्मरण रखने की बात यह है कि किसी नागरिक श्रिषकार का दुरुपयोग न होना चाहिए। प्रत्येक श्रिषकार का एक मर्यादा या सीमा के भीतर ही उपभोग होना उचित है। हमें भाषण करने का श्रिषकार है, तो किसी को बुरा-भला कहने का नहीं। हमें लेख लिखने या उसे छुपाने का श्रिषकार है तो श्रश्लील या मान-हानि-स्चक कार्य न करना चाहिए। हमें धार्मिक स्वतन्त्रता है, तो ऐसे धार्मिक जलूस श्रादि निकालने का श्रिषकार नहीं, जिससे दूसरे कमें के श्रनुयायियों का जी दुखे, इत्यादि। श्रर्थात् हमें दूसरे के भावों

का म्रादर करना श्रौर उनकी सुविधाश्रों का विचार रखना चाहिए।

पुनः इमारे प्रत्येक श्रिषकार के साथ कर्तव्यों का भी सम्बन्ध है। इम श्रिषकारों का उपभोग करना चाहते हैं तो कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कर्तव्यों के सम्बन्ध में श्रगते परिच्छेद में स्वतन्त्र-रूप से लिखा जायगा। हमें भली भांति स्मरण रखना चाहिए कि हमारे किसी श्रिषकार के उपयोग से दूसरे नागरिकों का श्रिहत न हो; दूसरे नागरिकों का श्रिहत होने से राज्य का श्रिहत होगा। श्रीर, क्योंकि हम भी राज्य के श्रंग हैं, इसलिए उससे हमारा भी श्रिहत होगा।

## बाईसवाँ परिच्छेद नागरिकों के कर्तव्य

हिन्दि छते परिच्छेद में नागरिकों के श्रिषकारों के विषय में लिखा

गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य यह होता है कि नागरिकों के जीवन का विकास हो। यह तभी होगा जब वे अपना कर्तव्य भली भौति पालन करेंगे। वास्तव में अधिकारों का उपयोग ही इसलिए किया जाना चाहिए कि नागरिकों को अपने विविध कर्तव्यों का पालन करने में सुविधा हो, उनके विकास के मार्ग की वाधाएँ दूर हों, और वे राज्य की उन्नति में समुचित भाग ले सकें। इस परिच्छेद में कर्तव्यों के विषयों में विशेष विचार किया जाता है।

श्रिविकार श्रोर कर्तन्यों का सम्बन्ध—श्रिवकार श्रोर कर्तन्य दो पृथक-पृथक वस्तुएँ नहीं हैं, वरन् वे भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखी हुई, एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। श्रीवकार को यदि हम 'लेना' कहें तो कर्तन्य को हम 'देना' कह सकते हैं। सुके अपने मित्र से पुस्तक लेनी है, या मेरे मित्र को मुके पुस्तक देनी है, किसी

मी तरह कहें, बात एक ही है। मेरी दृष्टि से, या मित्र की दृष्टि से कार्य भिन्न-भिन्न हैं, पर पुस्तक की दृष्टि से तो एक ही है। अधिकारों की आधुनिक लहर पाश्चात्य देशों से आयी है। भारतवर्ष में, प्राचीन साहित्य में, कर्तव्यों पर विशेष ज़ोर दिया गया है, अधिकारों का प्रश्नकम उठाया गया है। परन्तु कर्तव्यों के सम्यक् विवेचन में अधिकारों का विचार हो ही जाता है। हमारे प्राचीन नियम-निर्माताओं ने प्रजा के कर्तव्य वतलाये तो राजा और राज-कर्मचारियों के भी कर्तव्यों का वर्णन किया। और, राजा तथा राज-कर्मचारियों के जो कर्तव्य है, वे ही तो प्रजा के अधिकार हैं। राजा और राज-कर्मचारी अपना कर्तव्य पालन न करने की दशा में दंडनीय है, वे अपने पद से च्युत किये जा सकते हैं। इसी बात को हम यों भी कह सकते हैं कि यदि नागरिकों के अधिकारों को सम्यक् रचा न की जायगी, तो इसके लिए राजा और राज-कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

हमने पहले कहा है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है। अब उदाहरण लीजिए। नागरिकों का अधिकार है कि शिक्षा प्राप्त करें, तो राज्य की ओर से इस विषय की समुचित व्यवस्था हो जाने पर शिच्चा-प्राप्ति नागरिकों का कर्तव्य भी है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसके साथ धार्मिक सहनशीलता उनका कर्तव्य भी है। मैं चाहता हूँ कि मुक्ते अपनी भाषा और लिपि का व्यवहार करने में स्वतन्त्रता रहे, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं दूसरों की भाषा और लिपि के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव न रखूँ। मुक्ते सभा या सम्मेलन करने और भाषण देने का श्रिषकार है, तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं दूसरों की निन्दा न करूँ। मुक्ते मताधिकार श्रीर योग्यता होने पर प्रतिनिधि चुने जाने का श्रिषकार है तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं योग्य व्यक्ति के लिए ही मत दूँ, उसमें मित्रता, बिरादरी या सम्प्रदाय श्रादि का लिहाज़ न करूँ। श्रीर यदि मैं प्रतिनिधि चुना जाऊँ तो कानून बनाने में सार्वजनिक हित का ध्यान रखूँ न कि किसी श्रपने समूह-विशेष का। इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। निदान, प्रत्येक श्रिषकार के साथ उससे सम्बन्ध रखनेवाला कर्तव्य लगा हुआ है।

कतं व्य-पालान — मनुष्य जो कार्य करता है, उससे उसकी उस कार्य के करने की शिक्त या योग्यता बढ़ती है, उस कार्य के करने में जिन गुणों की श्रावश्यकता होती है उनका कमशः विकास होता है। उदाहरणवत् जो व्यक्ति दूसरों के दुःख से दुःखी होकर उनसे सहानुभृति दिखाता है, स्वतंत्रता से प्रेम करता है, साहस श्रीर वीरता का स्वागत करता है, सत्य के लिए कष्ट सहता है, उसमें इन गुणों की वृद्धि होती है। इससे उसके चरित्र तथा शारीरिक, मानसिक श्रीर नैतिक शक्तियों का विकास होता है। यह तो कर्तव्य-पालन से नागरिक के दित की बात हुई। इससे समाज या राज्य का भी हित-साधन होता है। नागरिक राज्य के प्रति जो कर्तव्य-पालन करते हैं, उससे तो राज्य का दित होना स्पष्ट ही है। जो कर्तव्य वे श्रपने प्रति पालन करते हैं उनसे भी राज्य का हित होता है। श्रतप्य, राज्य नागरिकों का ही तो बना है। श्रतप्य जब राज्य

के भिन्न-भिन्न श्रंगों की—व्यक्तियों की—उन्नति होगी, तो राज्य की समध्य रूप से भी उन्नति हो जायगी।

कर्तव्यों का क्षेत्र-कर्तव्य-पालन के लिए नागरिक जीवन का कोई विशेष समय निर्घारित नहीं है। जब से मनुष्य होशा संभा-लता है, तभी से उसके कर्तव्य श्रारम्भ हो जाते हैं। इस प्रकार बालको श्रीर युवकों के भी कर्तव्य हैं। ज्यों ज्यों मनुष्य की शक्ति श्रीर योग्यता बढती है, त्यों-त्यों उसके कर्तव्य का चेत्र भी विस्तृतः होता जाता है। एक श्रॅंगरेज किंव ने ठीक कहा है, ''मैं सोया तो मुक्ते मालूम हुआ कि जीवन सौन्दर्यमय है। मैं जागा, और मुक्ते अनुभव हुआ कि जीवन कर्तव्यमय है।" निस्संदेह चेतन और जाएत व्यक्तियों के लिए चारों श्रोर कर्तव्य ही कर्तव्य है। श्रोर, यह कर्तव्यों का चेत्र निरंतर बढता जाता है। श्रारम्भ में बालक श्रपने माता-पिता को जानता है, श्रीर उनकी श्राज्ञा के पालन करने को ही श्रपना कर्तव्य मानता है, क्रमशः श्रन्य रिश्तेदारों तथा मित्रों से परिचितः होता है, पीछे वह गांव या नगरवालों से सम्बन्ध जोड़ता है, वह इनके मुख-दु:ख में अपना मुख-दु:ख समभता है। कालान्तर में वह अपने देश या राज्य को श्रपनी जन्म-भूमि कहता है श्रीर इसके लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। यदि उसके संस्कार श्रन्छे हों, श्रीर उसे बातावरण की अनुकूलता मिले तो वह एंसार भर से अपनेपन का अनुभव करने लगता है, मनुष्य-मात्र को अपना भाई समभ्रता है। जिस प्रकार पहले वह ग्राम श्रीर नगर की दीवार तोड़कर श्रागे बढ़ा था, और देश या राज्य को अपनाने लगा था, अब वह राज्य

की सीमा को भी संकीण समक्तकर विशाल मानव जाति से सम्बन्ध स्थापित करता है। उसका आदर्श विश्व-बंधुत्व होता है। नहीं, वह इससे भी आगे बढ़ता है, और अन्य प्राण्यों को भी अपनी सहानुभूति, दया और प्रेम का अधिकारी मानता है। उसका सिद्धान्त 'वसुधैव कुडुम्बकम्' हो जाता है। जाति, रंग, देश, धर्म आदि के बन्धन उसके लिए नहीं रह जाते, वह बन्धनों से मुक्त होता है। उसकी आत्मा विश्व भर में व्याप्त होना चाहती है। पशु-पक्षियों में भी वह अपनेपन का अनुभव करता है। वह जहीं जाता है, जहीं रहता है, सर्वत्र उसके सामने उसका कर्तव्य उपस्थित होता है, और वह भी अपने कर्तव्य में रत रहता हुआ अपने मानव जीवन को सार्थक करता है।

मानव जीवन कर्तव्यमय है । कर्तव्यों की कोई संख्या या सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कर्तव्यों का कोई सर्वमान्य वर्गीकरण नहीं हो सकता। तथापि कुछ मुख्य बातों का विचार हो सकता है। इस परिच्छेद में हम नागरिकों के कुछ प्रधान कर्तव्यों का विचार करेंगे। स्मरण रहे कि बहुका एक प्रकार के कर्तव्यों का दूसरे प्रकार के कर्तव्यों से धनिष्ट सम्बन्ध रहता है, और बहुत से कर्तव्यों के विषय में यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता, कि उन्हें किस वर्ग में रखा जाय। परन्तु इससे मुख्य वक्तव्य में अन्तर नहीं आता।

त्रपने प्रति कर्तेव्य-प्रत्येक नागरिक राज्य का एक श्रंग है, श्रोर उसकी उन्नति एक सीमा तक राज्य की उन्नति है। जितना श्रधिक

कोई नागरिक स्वयं उन्नत होगा, उतना ही ऋधिक वह दूसरे नाग-रिकों की. और इसलिए राज्य की, उन्नति में सहायक होगा। श्रतः प्रत्येक नागरिक को अपनी शारीरिक. मानसिक और आर्थिक आदि उन्नीत की श्रोर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए। उसे श्रपने स्वास्थ्य, शिक्षा, सदाचार की उन्नति करनी चाहिए, स्वावलम्बी होना चाहिए, श्रर्थात् श्रपने भरण-पोषणादि के लिए दूसरों के श्राश्रित न होना चाहिए। उसे मितव्ययी होना चाहिए श्रौर सादगी का जीवन-व्यतीत करना चाहिए । स्वास्थ्य श्रीर शिक्षा के विषय में तो प्रायः मंत-भेद नहीं होता । हाँ. श्रमेक व्यक्ति स्वावलम्बन को विशेष महत्व नहीं देते । प्रत्येक राज्य में कुछ धनवान, पूँजीपति, ज़र्मीदार, या महन्त श्रादि ऐसे होते हैं, जो समाज या राज्य के लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा या उत्पादक कार्य नहीं करते, श्रीर फिर भी खूब विलासिता तथा ऐशवर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा जो द्रव्य है, वह इमारे बाप-दादा, या इमारे सेवकों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त होने से, उस पर इमारा पूर्णाधिकार है, यदि इम उसे स्वेच्छानुसार खुर्च करते हैं तो इसमें दूसरों को कुछ कहने सुनने का क्या अधिकार है ? यह दृष्टि-कोगा बड़ा श्रनर्थकारी है।

पहले कहा जा जुका है कि मनुष्य जो कार्य करता है, उसमें दूसरे के सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता होती है। बिना दूसरों के सहारे हम प्राय: कुछ भी करने में सफल नहीं हो सकते। अतः हमारे बाप-दादा आदि ने जो सम्पत्ति उपार्जित की है, उसमें समाज का (श्रन्य नागरिकों का) बड़ा भाग है। हम समाज के सहयोग से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग

करना चाहते हैं तो हमें भी बदले में कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए। वह कार्य हमारी शारीरिक या मानसिक स्थित तथा योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का क्यों न हों, वह समाज के लिए उपयोगी अवश्य होना चाहिए। जब तक कोई नागरिक अम नहीं करता, उसे विविध पदार्थों के उपभोग का कोई अधिकार नहीं है। निस्सन्देह बहुत से आदमी दान-पुण्य करनेवाले रहते हैं, और हट्टे-कट्टे मिखारियों आदि को तरह-तरह के भोजन-वस्त्र आदि देते रहते हैं। परन्तु वास्तव में भिक्षा या दक्षिणा आदि प्रहण करने का अधिकार केवल ऐसे ही व्यक्तियों को है, जो या तो अपाहिज (लँगड़ा, लूला आदि) होने के कारण कुछ अम करने में असमर्थ होते हैं, अथवा जा अपना जीवन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर, निःस्वार्य माव से समाजसेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आअथ देना समाज का कर्तव्य है। अन्य सब व्यक्तियों को अपनी आजीविका के लिए यथेष्ट काम करना चाहिए, परोपजीवी न होना चाहिए।

भारतवर्ष में सर्वसाधारण में श्रम का यथेष्ट महत्व नहीं है। हाथ का काम नीचे दर्जे का समभा जाता है; नाई, धोबी, बढ़ई, जुहार, चमार श्रादि का समाज में श्रादर नहीं है, दफ़्तरों में क्रकीं करनेवाले 'बाबू जां' कहे जाते हैं, दिन-भर कुछ भी काम न करनेवाले, ब्याज की श्रथवा पूर्वजों की कमाई पर गुलछरें उड़ानेवाले को 'सेठ साहब' कहा जाता है, श्रौर गेठशा वस्त्र धारण करके भिक्षा-गृत्ति से निर्वाह करनेवालों को 'साधु महाराज' कह कर सम्बोधन किया जाता है। ये सब बातें स्वावलम्बन की भावना के विरुद्ध हैं। जिस व्यक्ति में

अपना निर्वाह करने की सामर्थ्य तथा योग्यता हो, उसका दूसरों के आश्रित रहना निन्दनीय है।

हमने नागरिकों के लिए मितव्ययी होने की बात कही है। मित-व्ययिता से भविष्य में ऐसे समय हमारे स्वावलम्बी होने का निश्चय रहता है, जब संयोग से हमारे ऊपर कोई श्राकिस्मक श्रापित श्रा जाय, हम बेकार हो जायँ, या बीमार पड़ जायँ। नागरिकों को दूरदर्शिता-पूर्वक ऐसे श्रवसरों के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। यदि सौभाग्य से ऐसा श्रवसर न श्राया तो हम श्रपने संचित द्रव्य से श्रपने दूसरे श्रनाथ या श्रासमर्थ बन्धुश्रों की सहायता कर सकेंगे, समाज या राज्य की उन्नति का कोई कार्य करने में भाग ले सकेंगे, श्र्यात् हम दूसरों के प्रति श्रपना कर्तव्य पालन करने के श्रिषक योग्य होंगे, जिसके विषय में श्रागे लिखा जायगा।

परिवार के प्रति कर्तव्य — प्रत्येक व्यक्ति अपने भरण-पोषण और उन्निति के लिए अपने माता-पिता आदि का बहुत ऋणी होता है। हम सहज ही यह समभ सकते हैं कि यदि बाल्यावस्था में हमें अपने बड़ों की यथेष्ट सहायता न मिलती, तो हमारा जीवन कितना कष्ट-मय और प्रायः असम्भव होता। परिवार से हमें नाना प्रकार के सुख तथा सुविधाएँ मिली हैं। इसके उपलक्ष्य में हमें भी चाहिए कि बड़े होने पर हम भी अपने माता-पिता, चाचा-चाची और भाई-बहिन आदि की समुचित सेवा-सुभूषा करें, उनकी बीमारी या बृद्धावस्था में उन्हें यथा-संभव आराम पहुँचावें। विवाह-शादी हो जाने पर पुरुष को स्त्री के उत्थान में, और स्त्री को पुरुष की सुख-शान्ति की बृद्धि में सहायक

होना चाहिए। हमें श्रपनी सन्तान के प्रति भी श्रपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना चाहिए; हमारा कर्तव्य है कि सन्तान को सदाचारी, स्वस्य श्रीर सुयोग्य नागरिक बनाने की भरसक चेष्टा करें। हमें इस प्रसंग में, श्रपने घरू नौकरों का भी विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करके, हमारे लिए नाना प्रकार की सुविधाएँ प्रस्तुत करताहै, उसके सुख-दुख में सहानुभूति रखना श्रीर उसे विविध श्रार्थिक तथा श्रन्य चिन्ताश्रों से मुक्त रखना हमारा कर्तव्य है। परिवार समाज की इकाई है, यह एक छोटो-सी दुनिया है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि इस दुनिया की सुख-शान्ति श्रीर उन्नति के लिए वह जितना उद्योग कर सके, उसके करने में कमी न करे।

समाज के प्रति कर्त ज्य — ऊपर यह बताया गया है कि नाग-रिक का अपने माता-पिता आदि के प्रांत क्या कर्त ज्य है। जैसे हम अपने जीवन में माता-पिता आदि के ऋगी हैं, उसी प्रकार हम अपने शिक्षकों के भी बहुत ऋगी हैं। शिच्कों से हमारा अभिप्राय यहाँ केवल अध्यापकों से ही नहीं है, हम इनमें उपदेशक, लेखक और सम्पादक आदि उन सभी व्यक्तियों का समावेश करते हैं, जो हमें किसी भी जगह, या किसी भी रूप में शिक्षा देते हैं, जो हमें मौखिक उपदेशों द्वारा, या लेखों और पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा हमें जीवन-यात्रा के अधिक योग्य बनाते तथा मनुष्यत्व-प्रदान करते हैं।

माता-पिता श्रीर शिक्तक के बाद श्रव इस पड़ोिं स्थि का विचार करें। बहत-से नागरिक यह नहीं सोचते कि हमें अपने पास के गली-

महल्लेवालों के प्रति भी कुछ कर्तव्य पालन करना है। हमें उनकी सविधा श्रौर उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके बीमार, भग-डाल या मर्ख होने की दशा में हमें समुचित सुख-शान्ति की प्राप्ति की श्राशा कदापि न करनी चाहिए। क्रमश: हमारा पडोस का चेत्र बढता है, गली-मोहल्लेवाले ही नहीं, नगर श्रौर गाँव-भर के नागरिकों से इमारा सम्बन्ध हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के विषय में. यहाँ प्रथक-प्रथक ब्योरेवार बातें नहीं लिखी जा सकतीं। परिस्थिति के अनुसार ही उनका निर्णय करना होगा । सख्य बात यह है कि सब से इमारा व्यवहार-प्रेम श्रीर सहयोग का हो: श्रपनी विद्या, योग्यता या सम्पत्ति से जिस-किसी को जितनी सहायता इमसे बन आये. करने के विमल नहीं होना चाहिए । हमें अपने कर्तव्य-सम्बन्धी विचार-तेत्र को बढाते ही रहना चाहिए। हमारी सहायता, सहयोग या सहानुभृति केवल हमारे परिवार, जाति, ग्राम या नगर तक ही परिमित न रहकर उसका उपयोग स्वदेश-भर के, नहीं-नहीं, एंसार-भर के मन्त्यों के लिए होना चाहिए।

समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के लिए नागरिकों को जिस खास बात का समुचित ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख-भोग और स्वार्थ को मर्यादा में रखे, और दूसरों की सेवा और सहायता करने में यथा-शक्ति तत्पर रहे। समाज पारस्परिक सहयोग के आधार पर रहता है। हम अपनी विविध शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में न केवल समाज के वर्तमान जीवन से लाम उठाटे हैं, वरन बहुधा हम उसके पूर्व-काल

में किये हुए अनुभवों और अन्वेषणों का उपयोग करते हैं। हमें चाहिए कि अपने वल और बुद्धि से, समाज को, जहाँ वह है, उससे और आगे बढ़ाने में, उसे उन्नत करने में, भाग लें। कोई भी समाज पूर्ण या आदर्श-रूप में नहीं होता, प्रत्येक राज्य में समाजोन्नति की थोड़ी-बहुत आवश्यकता बनी ही रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को, इस कार्य में यथा-शक्ति सहयोग प्रदान करना चाहिए। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार नागरिकों के सामाजिक कर्तव्यों में कुछ, भिन्नता हो सकती है। किन्तु यह रमरण रहे कि समाज के किसी अंग की उपेन्ना न की जाय। नागरिकों को चाहिए कि वे प्रत्येक समूह की यथोन्नित उन्नति में सहायक हों। साधारणतया आजकल स्त्रियों, दिलतों (निम्न जातियों) और अमजीवियों की परिस्थिति अनेक राज्यों में चिन्तनीय है। नागरिकों को इनकी दशा सुधारने का हरदम ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें समानता, सहयोग और सहिष्णुता हमारा आदर्श होना चाहिए।

धर्म सम्बन्धी कर्तिन्य — अब नागरिकों के उन कर्तन्यों का विचार किया जाता है, जिनको धर्म-सम्बन्धी कहा जा सकता है। धर्म से हमारा आशय यहाँ मत या मज़हब से है। मिन्न-भिन्न देशों में तरह-तरह के धर्म हैं; यही नहीं, एक-एक राज्य में कई-कई धर्मों के अनु-यायी रहते हैं। मारतवर्ष तो अनेक धर्मों का श्रोत तथा संगम-स्थल ही है। अस्तु, धर्म-विभिन्नता स्वामाविक है। यह थोड़ी-बहुत प्रत्येक देश में रही है, इस समय विद्यमान है, और, इसके भविष्य में भी बने रहने का अनुमान है। परन्तु यह कोई अनिष्टकारी या भय-प्रद बात

नहीं है। इससे विचार-वैचिन्य का अनुभव होता है। हाँ, धर्म विभिन्नता होने की दशा में, नागरिकों में सहनशोलता को अत्यन्त आवश्यकता है। जब कोई धार्मिक कार्य हमारो इच्छा या भावना के प्रतिकृत्ल होता मालूम हो, तो हमें दूसरों से लड़ने-भिड़ने या गाली-गलौज करने के लिए तैयार न हो जाना चाहिए। हमारी असहिष्णुता, अनुदारता, मज़हबी दीवानापन, और अनुचित न्यवहार दूसरों की दृष्टि में हमारे धर्म की महत्ता कभी न बढ़ायेंगे। दया, परोपकार, दूसरों की मां-बहिनों की इज़्ज़त तथा संकट-प्रस्तों की सहायता करके ही हम दूसरों को यह बता सकते हैं कि हमारा धर्म कितना महान है। इसी से हम उनके हदयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं; धार्मिक असहिष्णुता से कदाणि नहीं।

हमारे धर्म या सम्प्रदाय की कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो नागरिकता या देश-हित के विरुद्ध हो। जब कोई ऐसी बात जान पड़े तो तुरन्त उसका संशोधन किया जाय। प्रत्येक सम्प्रदायवालों की विविध संस्थाओं को चाहिए कि अपने-अपने चेत्र में न्यायोचित उपायों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कला-कौशल आदि की दृद्धि करें, और नागरिकों को सुयोग्य बनाने में दत्त-चित्त हों। समाज-हित और मनुष्य-सेवा सब धर्मों से ऊपर हैं। इस बात को भुला देने से समय-समय पर साम्प्र-दायिक ऋगड़ों का दुखदायी दृश्य देखने में आता है। नागरिकों को इस और सतर्क रहने की आवश्यकता है।

ग्राम और नगर के प्रति कर्तव्य — नागरिकों के, दूसरों के श्रेष्ठित क्या कर्तव्य हैं, यह ऊपर बताया जा चुका है। उन कर्तव्यों में हो

नागरिकों के उन कर्तव्यों का समावेश हो जाता है, जो उन्हें ग्राम, नगर तथा राज्य के प्रति पालन करने चाहिए। पर विषय महत्व का होने से. इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से विचार करना श्रावश्यक है। श्रपने प्राम या नगर की उन्नित का ध्यान रखना, नागरिकों को स्वयं अपने हित की दृष्टि से भी ज़रूरी है; कारण, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न-कुछ श्रंश तक अपने निकटवर्ती वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। श्राधनिक सभ्यता में ग्रामों की बरी तरह उपेक्षा की जा रही है। विशेषतया भारतवर्ष के गांव तो निर्धनता, अविद्या, अस्वच्छता, त्रीर बीमारियों के स्थायी निवास हैं। श्रामदरफ्त और यातायात के नये साधन-रेल, तार, टेलीफ़ोन, रेडियो-का वहां अभाव है; डाक भी अनेक स्थानों में कई-कई दिन में पहुँचती है, फिर कोई सम्य व्यक्ति वहां रहे तो कैसे रहे ! अतः वहां धन के अतिरिक्त बुद्धि का भी कुछ श्रंश तक दीवाला निकला रहता है। सेवा-समितियों. सह-कारी समितियों, पंचायतों, कृषि-सुघार श्रीर शिक्षा-प्रचार-सभाश्रों की वहाँ बहुत जरूरत है। सरकारी श्रीर ग़ैर-सरकारी सभी प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए । यहां गत वर्षों में इस श्रोर ध्यान दिया गया था। ग्राम सुधार विभाग अब भी है-पर प्रान्तों में कांग्रेस शासन समाप्त होने के समय से इस श्रोर कुछ उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो रही है। यद्यपि यथेष्ट सुधार तो सरकार द्वारा ही, और काफी समय में होगा, नागरिकों को यथा-शक्ति अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए।

श्रव नगरों की बात लीजिए। इनमें स्वास्थ्य, सफाई श्रौर चिकित्सा

सम्बन्धी कल नये साधनों का आयोजन गावों की अपेदा अवस्य ही श्रिषिक है। शिद्धा का प्रचार भी गाँवों से बहुत ज्यादह है। तो भी यहाँ का स्वास्थ्य चिन्तनीय है। शौकीनी, श्रारामतलबी, विला-िंता श्रीर वाह्य श्राडम्बर-प्रेम ने उनका जीवन बहुत कष्टमय बना रखा है। साल्विकता, सादगी और संयम की बहत आवश्यकता है। सयोग्य नागरिक के नाते हमें अपने व्यवहार से अव्हा उदाहरण श्रीर श्रादर्श उपस्थित करना चाहिए। नागरिकों के लिए श्रपनी म्युनिसिपैलटी श्रादि के नियमों का पालन करना श्रावश्यक है। यही नहीं, उन्हें अपनी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण, संगठन और सघार में भी भरसक भाग लेना चाहिए। अपने नगर को यथा-सम्भव आदर्श नगर बनाने के हेत्. हमें अपने यहा की म्युनिसिपैलटी आदि से सहयोग करते हुए ऐसी संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए जो बेकारी. मनोरंजन सफ़ाई. श्रीद्योगिक शिक्ता श्रीर मद्यपान सम्बन्धी समस्याश्री को इल करने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति किसी कारणा या परिस्थित-वश अपने नगर से बाहर रहने लगे. उन्हें भी अपने नगर को स्मरमा रखना, उसका श्रमिमान करना उससे सम्बन्ध बनाये रखना श्रीर उसके सुधार में सहायक होने का ध्यान रखना चाहिए।

राज्य के प्रति कर्तव्य — शाचीन काल में, जब नगर-राज्य वे, तो नगरों के प्रति कर्तव्य-पालन करने से, राज्य के प्रति भीं कर्तव्य-पालन हो जाता था। श्रव तो एक-एक राज्य में सैकड़ों नगर हैं। श्रतः राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्यों का विषय पृथक रूप से विचारणीय हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि साधारणतया नागरिक को

राज्य के विविध क्रायदे-क्रान्नों को मानना और करों को चुकाना चाहिए। निर्धारित आयु तथा योग्यता प्राप्त करने पर इन क्रायदे-क्रान्नों के बनाने तथा कर की दर निश्चत करने में उसे स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा, सम्यक् माग लेना चाहिए। उसे राज्य की उन्नति में, शिचा, स्वास्थ्य, उद्योग, कला-कौशल आदि की वृद्धि में तन-मन-धन से सहायक होना चाहिए। उसे शत्रुओं से राज्य की रच्चा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, और इसके वास्ते आवश्यक सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

यह प्रश्न हो एकता है कि क्या नागरिकों को सैनिक शिक्षा के लिए वाध्य किया जा एकता है, अथवा वाध्य किया जाना उचित है। बहुधा राज्यों में राज्य-विस्तार आदि के लिए सेना का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में नागरिकों का सेना में बल-पूर्वक भर्तों किया जाना सर्वथा अनुचित है; इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हाँ, जो राज्य आत्म-रचा के लिए, या निस्वार्थ भाव से दूसरे राज्य की रचा के लिए अपनी सेना रण-चेत्र में उतारता है, उसकी सेना में भर्ती होना नागरिक का कर्तव्य है। परन्तु कुछ नागरिक ऐसे हो सकते हैं, जो अपने राज्य की रक्षा (या आत्म-रचा) के लिए भी हिंसक उपाय से काम लेना न चाहते हों। इन्हें भर्ती होने के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सैनिक भर्ती के लिए हमें राज्य की झानूनी ज़बरदस्ती पसन्द नहीं; यह विषय नागरिकों की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। वे राज्य के युद्ध-उद्देश्य तथा अपने मन की स्थिति का विचार करके स्वयं

ही भर्ती होने या न होने का निश्चय करें।

पहले कहा गया है कि नागरिकों को राज्य के क़ानूनों का पालन करना चाहिए तथा निर्घारित कर चुकाने चाहिएँ। इसमें यह समभा लिया गया है कि राज्य की स्थापना नागरिकों के सामृद्धिक द्वित के लिए है. और नागरिकों के मत के विरुद्ध न तो कोई क़ानून बनेगा. श्रीर न किसी प्रकार का कर ही लगाया जायगा। हाँ, यह श्रावश्यक नहीं है कि क़ानून-निर्माण या कर-निर्धारण में सब ही नागरिक सहमत हों. कोई भी विरुद्ध न हो । नागरिकों में प्राय: मतभेद रहता है, श्रौर प्रजातंत्र के श्राधुनिक ििद्धान्तों के श्रनुसार बहुमत से कार्य सम्पादन होता है। ऐसी दशा में जिन नागरिकों के मत के विरुद्ध निर्णय होता है, उन्हें भी क़ानून का पालन करना चाहिए। वे यह कह कर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि वे उस क़ानून के प्रस्ताव से सहमत न थे। क़ानून बनने से पूर्व उन्हें पूर्ण अधिकार था कि वे इसके विरुद्ध यथा-शक्ति श्रान्दोलन करते। पर जब उनके नागरिक बंधुओं ने एक बात बहुमत से तय कर दी है तो उसे मानना ही उनका कर्तव्य सममा जाता है। हाँ, उक्त क़ानून के बन जाने पर भी वे चाहें तो उसे संशोधित या परिवर्तित करने का उद्योग कर सकते हैं, परन्तु जब तक वे इसमें सफल न हों, उस क़ानून का पालन करना उनका कर्तव्य है।

परन्तु इसमें एक बात विचारणीय है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई स्वतंत्र विचार करनेवाला, प्रतिमावान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि राज्य का एक क़ानून उसकी भावना, या निर्धारित सिद्धांत के विरुद्ध है। उसकी श्रात्मा उसे अनुचित मानती है। वह उसका पालन करना श्रपने ऊतर श्रत्याचार करना समस्ता है। श्रतः वह उसका पालन करने से इनकार कर देता है। फल-स्वरूप उसमें श्रोर राज्य में संवर्ष उपस्थित होता है। राज्य अपने बल का प्रयोग करता है, तो नागरिक श्रपने श्रात्मिक बल का परिचय देता है, श्रोर राज्य द्वारा प्राप्त प्रत्येक कष्ट को सहर्ष स्वीकार करता है। जैसा हमने पिछुले परिच्छेद में बताया है, ऐसा प्रसंग श्राने का कारण यह होता है कि राज्य श्रपूर्ण है।

श्रस्तु, जब उपर्यु क संघर्ष उपस्थित होने की श्राशंका हो तो राज्य को चाहिए कि उक्त क़ानून के सम्बन्ध में पुनर्विचार करे श्रीर जहाँ तक बने श्रपने स्वतंत्र विचारवाले प्रतिभावान नागरिकों को कष्ट न दें। किन्तु जब ऐसा न हो—श्रीर, प्रायः ऐसा नहीं होता—तो राज्य के सुयोग्य नागरिक का यह कर्तव्य है कि राज्य की श्रप्रसन्ता सहकर तथा भाँति-भाँति के कष्ट उठाकर भी श्रपनी निर्भीकता का परिचय दे। उससे दूसरे नागरिकों में स्वतंत्र विचार करने की भावना का उदय होगा, श्रीर श्रन्ततः थोड़े-बहुत समय में, क़ानून में श्रावश्यक सुधार होगा। श्रीर, इससे राज्य का तो हित होगा ही, नागरिकों का भी कष्ट-सहन सफल हो जायगा। स्मरण रहे कि यह बात विशेष परिस्थिति के सम्बन्ध में, अपवाद-रूप से कही गयी है। इसका यह श्रयं कदापि नहीं कि जब किसी नागरिक को राज्य का कोई क़ानून छोक न जचे तो वह उसकी श्रवहेलना करने लग जाय। ऐसा क़दम उठाने से पूर्व नागरिक को श्रपने मन में कई बार गंभीरता तथा शांति

से सोचना चाहिए, और संभव हो तो अन्य विचारवालों से भली भौति विचार-विनिमय कर लेने पर ही अन्तिम निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

देश-भिक्ति—राज्य के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य है, यह कपर बताया जा चुका है। स्वाधीन देशों में राज्य श्रीर स्वदेश दोनों का स्वार्थ एकसा होता है, राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करने में स्वदेश-भांक श्रा ही जाती है। देश-भक्तों का राज्य में सम्मान होता है, वे राज्य के स्त्रधार होते हैं। विन्तु पराधीन देशों में यह बात नहीं होती। वहाँ देश-भक्ति श्रोर राज-भक्ति परस्पर विरोधी होते हैं, राज्य को देश-भक्त नहीं सुहाते, वह उनके लिए नये-नये प्रलोभन उपस्थित करके, या उन्हें तरह-तरह की यंत्रणा देकर उन्हें देश-भक्ति से विमुख करने को चेष्टा करता है। साधारण व्यक्ति ऐसी दशा में पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं; जब देश-भक्ति या राज-भक्ति में से किसी एक को छांटने का प्रश्न उनके सामने श्राता है तो वे लोभ में फंस जाते या कष्टों से घबरा जाते हैं। श्रीर देश-भक्ति के भाव को तिलांजित दे, राज-भक्तीं की श्रेणी में श्रा जाते हैं।

परन्तु सब ऐसे ही नहीं होते । अनेक माई के लाल न प्रलोभन में फॅसते हैं, और न कप्टों से विचलित होते हैं। वास्तव में देश-भक्ति की भावना मनुष्य के लिए स्वामाविक है; हाँ, साधारण व्यक्तियों में वह बाह्य कारणों से दब जाती है। जो महानुभाव बाहरी वाधाओं का सामना कर सकते हैं, उनमें वह भावना बराबर बनी रहती है। जिसक भूमि में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया. जहाँ हमारे माता-पिता ने अपना जीवन व्यतीत किया, जहाँ के श्रव पानी से हमारा भरण-पोषण हश्रा जो हमारी संतान की जन्म-मूमि एवं कर्म-मूमि है, उसके प्रति आदर-सम्मान श्रीर भक्ति भाव होना ही चाहिए। मातृ भृमि के लिए हमें सब प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करने को उद्यत रहना चाहिए। स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, और यदि स्वदेश परा-चीन हो, तो उसे स्वाधीन करने के वास्ते, नागरिकों को अपने प्राख न्यौद्यावर करने से भी संकोच न करना चाहिए। देश-भक्तों के लिए मरने का प्रसंग तो कभी-कभी ही आता है; हाँ, विविध कठिनाइयों के न्ह्य में हमारी देश-भक्ति की परीचा समय समय पर होती रहती है। नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे अवसरों पर कर्तव्य-पालन से कभी विमुख न हों, और त्याग और सेवा का त्रादर्श रखते हए सदैव -अपनी देश-भक्ति का परिचय देते रहें। स्मरण रहे कि देश विशाल मानव परिवार का एक श्रंग है। श्रतः हमारी देश-भक्ति का कोई काम ऐसा न होना चाहिए, जिससे अन्य देशों के निवासियों को हानि पहुँचे । सब के मुख में ही हमारा मुख है । देश-भक्ति का श्रादर्श मानव समाज की सेवा के धर्वथा अनुकृल है, और होना ही चाहिए।

कर्तव्यों का संधर्ष — उपर नागरिकों के विविध प्रकार के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। इस प्रसग में एक बात विचारणीय है। यदि मिन्न-भिन्न प्रकार के कर्तव्यों का परस्पर विरोध हो तो क्या करें, अथवा जब एक ही प्रकार के दो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित हो, तो किसे प्रधानता दी जाय ? उदाहरणार्थ राष्ट्रीय माँग है कि हम स्वयंसेवकों में मतीं होकर, जहाँ-कहीं हमारे नेता की आजा हो, वहाँ

जाय: इसके साथ ही हमारा पारिवारिक कर्तव्य चाहता है कि हम घर पर ही रहते हुए स्त्री श्रौर बचों के भरण-पोषण श्रौर चिकित्सा श्रादि का प्रवन्ध करें। क्या ऐसे श्रवसर पर राष्ट्र-हित के सम्मुख पारिवारिक हित को त्याग देना उचित न होगा ? महात्मा बुद्ध ने संसार को धर्म का नया प्रकाश दिया, पर क्या उन्होंने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना न की ? उनके हृदय में सेवा और धर्म-प्रचार का भाव श्रत्यन्त प्रबल था, श्रीर स्वार्थ उन्हें छु नहीं गया था। भला ऐसे महापुरुष के कार्य या निर्णय को श्रातुचित कैसे कहा जा सकता है! यह तो यथा-सम्भव अनुकरणीय है। हमारा यह आशय नहीं कि इम सर्वसाधारण के लिए पारिवारिक कर्त्वय की अवहेलना का आदेश करते हैं। हाँ, विशेष दशा में, वृहत जनता के वास्तविक हित श्रीर अपनी अन्तरात्मा की आजा के पालन की तुलना में, इम उसे गौण स्थान दे सकते हैं। नीति का वाक्य है, परिवार (कुल ) के लिए एक को, गाँव के लिए कुल को, राष्ट्र के लिए गाँव को, श्रीर श्रपनी श्रात्मा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए।

कर्तव्य सम्बन्धी आद्श्र—कर्तव्य निर्णय करने में हमें क्या आदर्श रखना चाहिए ? जिन कार्यों में, समाज में मेद-भाव न रख कर, समता का आदर्श रखा जाता है, जिन के करने में हम अपनी आत्मा की विशालता का अनुभव करते हैं, जिनमें स्वार्थ-परार्थ का प्रश्न नहीं उठता वे ही हमारे कर्तव्य हैं। हमारे मन में अपने कर्मों के फलाफल का विचार नहीं आना चाहिए। हमारा प्रत्येक कार्य निष्काम माव से हो, और हमारा जीवन, केवल हमारे ही लिए

न होकर सब के हित के लिए हो। इमें अपने कार्य को अपना कर्तव्य समभक्तर करना चाहिए। कोई निन्दा करें या स्तुति, हमें मुख मिले या दुख, हमें अपने निर्दिष्ट कर्तव्य-पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन कर्तव्य-पालन के लिए हो, और कर्तव्य-पालन के लिए मरना पड़े तो हमें अपने क्षया-भंगुर शरीर का कोई मोह न हो। अपनी मृत्यु से भी हम कर्तव्य-पालन का आदर्श उपस्थित करें।



## तेईसवाँ परिच्छेद

## लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ

क्रिंडले बताया जा चुका है कि सरकार के प्रायः तीन कार्य होते हैं:—(१) शासन, (२) व्यवस्था, और (३) न्याय। इन तीनों कार्यों का अपना-अपना महत्व है। पर शासन-कार्य से सर्वसाधारण को रोज़मर्रा काम पड़ता है। गाँव-के-गाँव ऐसे मिल सकते हैं, जिनके अधिकांश निवासियों को यह ज्ञात न हो कि व्यवस्थापक सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन है। न्यायाधीशों से काम उन्हें ही पड़ता है, जिनका अपना था किसी मित्र आदि का मुक़दमा हो, और यह सर्वथा सम्भव है कि किसी नागरिक को वर्षों ऐसा प्रसंग न आवे। परन्तु शासक वर्ग के किसी-न-किसी कमेचारी या अधिकारी से तो नागरिकों को रोज़ काम पड़ता है। और, शासन-प्रवन्ध का ही काम

ऐसा है जिसे करने के लिए राज्य में छोटे बढ़े सहसों व्यक्ति नित्य स्थायी रूप से लगे रहते हैं, श्रीर उनका संगठन इस प्रकार होता है कि कोई भी स्थान उनसे रहित नहीं होता । छोटी-सी-छोटी बस्ती में भी कोई शासक कर्मचारी श्रवश्य रहता है । फिर, श्राज-कल हमारा नागरिक जीवन इस प्रकार का हो गया है कि शासन-प्रबन्ध का कार्य देश-रचा श्रादि अत्यावश्यक कार्यों तक ही परिमित न रहकर लोक-हितकारी कार्यों से भी सम्बद्ध हो गया है, जिनकी संख्या और परिमाण की कोई सीमा ही नहीं है, जो निरन्तर बढ़ सकते हैं, श्रीर वास्तव में बढ़ते ही जा रहे हैं । इस प्रकार शासन-कार्य संचालन करनेवालों की अत्येक राज्य में बढ़ी भारी फ्रीज-पलटन-सी रहती है ।

लोकमत का प्रभाव—इस विशाल और व्यापक शासन-कार्य पर जनता अपना प्रभाव किस प्रकार डालती है ? इसका निरीक्षण या नियन्त्रण किस प्रकार होता है ? राज्य इतना बड़ा होता है कि कोई व्यक्ति, क्या व्यक्ति-समूह भी उस पर सम्यक् प्रभाव नहीं डाल सकता। उस पर तो लोकमत का ही प्रभाव विशेष रूप से पड़ सकता है। यंसार में लोकमत की शक्ति भी कैसी विलक्षण है! कोई व्यक्ति कितना ही धनवान, गुण्यान या उच्च पदाधिकारी हो, उसे यह चिन्ता अवश्य रहती है, कि उसके विषय में लोकमत क्या है। अपने स्वेच्छाचार में उन्मत्त व्यक्ति भी कभी-न-कभी यह सोचता ही है, कि उसके विषय में लोकमत क्या है।

श्रवश्य ही जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य के कार्यों या विचारों पर दूसरों के मत का बहुत प्रभाव पड़ता है तो इसका आश्रय यह नहीं है कि देश-भर के श्रादमी उसके सम्बन्ध में विचार करते हैं या यह कि वह देश के सभी श्रादमियों के मत से प्रभावित होता है। वास्तव में हममें से प्रत्येक व्यक्ति की श्रपनी-श्रपनी एक दुनिया है, हम कुछ श्रादमियों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं, मिलते-जुलते हैं, विचार-विनिमय करते हैं, उनका मत जानने के इच्छुक रहते हैं, यथा-सम्भव एक-व्यवहार करते हैं। उन्हें हम श्रपने चेत्र का समभते हैं। उन लोगों से ही हमारी दुनिया बनती है। इस दुनिया के कहने-सुनने का हम पर विशेष प्रभाव पड़ता है; हम प्रत्येक कार्य को करते समय यह सोचा करते हैं कि दुनिया इस विषय में क्या कहेगी। इस 'दुनिया' के विचार का लिहाज़ करके श्रनेक बार हम श्रपने इरादे को बदल देते हैं, श्रथवा कुछ विशेष साहस के या प्रत्यक्ष हानिकर कार्यों को भी कर वैठते हैं।

मारत वर्ष में बहुत से आदमी विवाह शादियों में अपनी है सियत से कहीं अधिक द्रव्य खर्च कर डालते हैं, सिर्फ इसलिए कि कम खर्च करने की दशा में उनकी विरादरीवाले उन्हें कंज्स कहेंगे या निन्दा करेंगे। दूसरे प्रकार का भी उदाहरण लिया जा सकता है, जो आदमी सुभार सभाओं में भाग लेते हैं, जिनके मित्र या मिलनेवाले सुभारक ही होते हैं, उन्हें सामाजिक कायों के प्रसङ्घ में यह सोचना पड़ता है कि यदि हमने अद्वय किया, सादगी से काम न लिया तो मित्र-मंडली में हमारी चर्चा होगी, सब हमारे साहस और दूरदर्शिता की कमी की निन्दा करेंगे; अतः सोच-समभ कर ही खर्च करना चाहिए, व्यर्थ की रीति-रस्मों में पैसा नष्ट न करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि लोकमत का प्रमाव हमारे कार्यों पर अवश्य पड़ता है।
यह प्रभाव अच्छा भी पड़ सकता है, और बुरा भी। दूसरों का मत,
एक वड़ी सीमा तक हमारे कार्यों का नियंत्रण करता है, और प्रायः
हम यह चाहते रहते हैं कि हमारे कार्य दूसरों की हिंदर में अच्छे
जचें। हाँ, 'दूसरों' से मतलब यहाँ उन्ही व्यक्तियों से हैं, जिनसे
हमारा सम्पर्क या सम्बन्ध है, जो हमारी 'दुनिया' में हैं, इनमें से
कुछ हमारे गाँव, नगर या ज़िले के हो सकते हैं, कुछ हमारे प्रान्त
या देश के, और सम्भव है कोई इससे भी बाहर का अर्थात् दूसरे
देश का हो। यह स्पष्ट ही है कि कितनी ही बार हम अपने गाँव
या नगर आदि के भी सब आदिमयों के मत का विचार नहीं करते।
वास्तव में हम जो अपनी दुनिया बनाते हैं, इसका कोई मौगोलिक
आधार या सीमा नहीं होती। हाँ, साधारण आदिमयों का सम्बन्ध
अपने पास के लोगों से ही होता है, उनकी 'दुनिया' में दूर-दूर के
आदिमी नहीं होते।

कपर हमने दूसरों के मत का प्रभाव दिखाने के लिए एक सामा-जिक उदाहरण लिया है। इसी प्रकार धार्मिंक, आर्थिक तथा राज-नैतिक जगत में भी लोकमत का प्रभाव कुछ कम नहीं पड़ता। महा-जनों या साहूकारों की यह कहावत 'जाय लाख, रहे साख' कितनी अर्थ-पूर्ण है। उनका यह सिद्धान्त रहता है कि यथा-सम्भव हानि सहकर भी अपने व्यवहार के विषय में लोकमत अच्छा बनाये रखें। धार्मिक संस्थाओं की बात लीजिए। प्रत्येक धर्मवाले इस बात का प्रचार करते रहते हैं कि उनका धर्म सचा तथा उदार है, और उसमें बड़ी शक्ति है। जब जनता साधारण बुद्धि की होती है तो वे यह प्रचार करते हैं कि हमारे धर्म के प्रवर्तकों, श्राचायों, देवता श्रों श्रादि ने विलक्षण, श्राश्चर्य जनक चमत्कार किये; इसके विपरीत, बुद्धिमान श्रोर विवेकशील व्यक्तियों में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि हमारा धर्म बहुत तर्क-संगत श्रोर वैज्ञानिक है, हमारे प्रत्येक धार्मिक कृत्य में ऊँचे सिद्धान्तों का समावेश है। इस प्रकार वे श्रपने धर्म के पक्ष में लोकमत श्रच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, तभी तो उनके श्रनुयायियों की संख्या बढ़ती है। व्यक्ति हों या संस्थाएँ, लोकमत का विचार सब करते हैं। लोकमत हमारे सार्वजनिक कार्यों तथा व्यवहारों को बहुत प्रभावित श्रोर नियंत्रित करता है। बहुधा लोकमत को देखकर ही हम किसी विषय सम्बन्धी नीति निर्धारित करते हैं।

राज्य आरे लोकमत — अन्य एंस्थाओं की भाँति प्रत्येक देश की सरकार भी इस बात की ओर यथा-सम्भव ध्यान देती है, कि उसके सम्बन्ध में लोकमत अञ्झा रहे। वह समय-समय पर ऐसी विश्वतियाँ निकालती रहती हैं, जिनसे उसके कार्ये का औचित्य सिद्ध हो, राज्य के अधिक -से अधिक आदमी उसका समर्थन करनेवाले रहें। यही नहीं, प्रत्येक राज्य यह भी चाहा करता है कि अन्य राज्यों को हिन्ट में उसकी आन्तरिक तथा वैदेशिक नीति ठीक मालूम पड़े। उदाहरणवत् ब्रिटिश सरकार बार-बार यह कहा करती है कि भारतवर्ष को यदि स्वतंत्र नहीं किया जाता तो इसका कारण भारतवासियों का आन्तरिक मत-मेद है,

यहाँ हिन्दू-मुसलिम समस्या है, हरिजनों की रह्मा का प्रश्न है, देशी नरेशों के साथ भूत काल में की गयी संधियों का विचार है। हम अल्प-संख्यकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ सकते।

यद्यपि यहाँ राष्ट्रीय नेताओं ने इसके जवाब में स्पष्ट कह दिया है श्रीर भारतीय जनता भी श्रव यह समभने लग गयी है कि ये समस्याएँ स्वयं ब्रिटिश सरकार की पैदा की हुई हैं, ब्रिटिश सरकार श्रपने कथन को भिन्न-भिन्न रूप में दोहराती ही रहती है, जिससे योरप श्रमरीका श्रादि के राज्य ब्रिटिश सरकार की नेकनीयती में विश्वास रखें श्रीर उनमें इसके सम्बन्ध में लोकमत श्रव्हा रहे।

दूसरे राज्यों में लोकमत अनुकूल होने से बहुत लाम होता है।
कभी-कभी तो यह लाम प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। पिछले
योरपीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने इस बात का खूब प्रचार किया
कि युद्ध में भाग लेने का हमारा उद्देश्य छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की
रच्चा करना, तथा प्रत्येक राज्य को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार
दिलाना है। ब्रिटिश सरकार के इस प्रचार का एक विशेष फल
यह हुआ कि अमरीका की उसके साथ बहुत सहानुमूति हो गयी,
और उसने इंगलैंड की जी खोल कर आर्थिक सहायता की। इसके
अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की उपर्युक्त घोषणा का मारतवर्ष पर भी
बहुत प्रभाव पड़ा। कुछ आदमी इंगलैंड की उदारता की बात से
ही उसके पच्च में हो गये, कुछ ने सोचा कि जब इंगलैंड छोटे-छोटे
राष्ट्रों की रक्षा के लिए इतना त्याग और बिलदान कर रहा है, वह
भारत-जैसे बड़े और प्राचीन सभ्यता वाले राष्ट्र की अवहेलना नहीं

करेगा, वह इसे अवश्य ही स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार देगा। इस प्रकार भारतीय लोकमत इंगलैंड के पच्च में होने से यहाँ से उसे जन-धन की, और खास तौर से रंगरूटों और सैनिकों की, खूब सहायता प्राप्त हुई। विशेषतया अमरीका और भारतवर्ष की सहायता ने ही पिछले महायुद्ध का पासा पलट दिया। इंगलैंड की शानदार विजय हुई।

निदान, कोई राज्य अपने सम्बन्ध में होनेवाले लोकमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। लोकमत में विल ख्ण बल है। लोकमत राज्य का स्वरूप बदल सकता है, उसका काया-कल्प भी कर सकता है। इस विषय में भारतवर्ष का ही उदाहरण लें तो कह सकते हैं कि यदि लोकमत ठीक तरह संगठित और व्यक्त हो तो शासन सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तन होने में कुछ देर न लगे। वर्तमान अवस्था में यदि राष्ट्र-सभा कांग्रेस कुछ माँग उपस्थित करती है, और मुसलिम लीग उससे सहमत न हो अपना अलग ही सुर अलापती है, तथा देशी नरेश अपने स्वार्थवश निराला ही प्रस्ताव करते हैं तो ब्रिटिश सरकार को सहज ही राष्ट्रीय माँग की अवहेलना करने का बहाना मिल जाता है। परन्तु यदि भारतवर्ष के सब सम्प्रदाय और सब दल मिल कर एक ही प्रस्ताव सामने रखें किसी का मत-मेद न हो, तो ब्रिटिश सरकार इस करना पड़े।

इस प्रकार लोकमत का प्रभाव व्यक्ति से लेकर, संस्था, समाज और राज्य पर पड़ता है। अब हम तिनक यह विचार करें कि लोकमत वास्तव में क्या होता है, कैसे बनता है, श्रीर उसमें किन-किन दोशों की श्राशंका रहती है।

लोकमत और उसका निर्माण — लोकमत का अर्थ है, जनता का मत। किसी समूह, जाति, संस्था, समुदाय, या सम्प्रदाय आदि के मत को उस संगठन का मत कहा जा सकता है। पर वह लोकमत नहीं है। लोकमत तो समस्त जनता के ही मत को कहना चाहिए। परन्तु इसमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्पूर्ण जनता का तो कभी एक मत होना ही दुर्लम है। अतः लोकमत उस मत को कहा जाता है जिसमें समस्त जनता के हित का विचार हो, किसी वर्ग विशेष के ही हित का नहीं।

प्रायः समाज में विभिन्न मतों का प्रचार होता है, एक समूह या दल एक मत का समर्थक या अनुयायी होता है, दूसरा समूह या दल दूसरे मत का। भिन्न-भिन्न मत कुछ बातों में एक-दूसरे से मिलते हैं, और कुछ बातों में सर्वथा भिन्न होते हैं। एक मत दूसरे के सम्पर्क में आता है। कभी-कभी दो मतों का परस्पर में खूब संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष के फल-स्वरूप एक तीसरा मत और बन जाता है। और, कभी-कभी एक मत दूसरे के बहुत निकट आ जाता है, यहाँ तक कि उसमें ही मिल जाता है। यह तो भिन्न-भिन्न मतों पर एक-दूसरे के प्रभाव की बात हुई। इसके अतिरिक्त मतों के निर्माण और लोप के और भी कारण होते हैं। समय-समय पर समाज में कुछ परि-वर्तन होते रहते हैं। नयी आवश्यकताएँ उपस्थित होती हैं। नवीन

परिस्थित पैदा होती है। इस दशा में कुछ पुराने मत अनावश्यक होने से खुस हो जाते हैं तथा देश कालानुसार कुछ नये मतों की सुष्टि हो जाती है।

लोकमत को दृषित करने वाली बातें, और उन्हें दूर करने का उपाय--भिन्न-भिन्न मतों में दो प्रकार के दोषों की श्राशंका रहती है:--(१) उनका श्राधार श्रज्ञान-मूलक हो, (२) वे स्वार्य-जनित हो। प्रायः सर्वेषाधारण का ज्ञान बहुत परिमित होता है, उन्हें दूर-दूर की यात्रा करने का प्रसंग नहीं आता, वे कूप-मंडूक रहते हैं, वे परिस्थिति का सम्यक् अध्ययन नहीं कर पाते। शिक्षा के श्रमाव में वे श्रावश्यक साहित्य का श्रवलोकन या मनन नहीं कर सकते: श्रीर, हाँ, इसका भी तो निश्चय नहीं रहता कि जो साहित्य वे देखते हैं, वह कहीं तक सत्य या उचित मत का सूचक है। भारतवर्ष की बात लीजिए। कुल जनता में नब्बे फीसदी अशिक्षित ही हैं, गाँबों में तो अनपढों की संख्या और भी अधिक है। एक आदमी कोई पुस्तक या अख्वार पढ़ता है, दूसरा उसकी बात सुनता है श्रीर अपनी बात तीसरे को सुनाता है। इस प्रकार क्रम आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को उस विषय की प्रत्यक्ष जानकारी हुई थी, वह बहुत दर रह जाता है, श्रीर वास्तविक बात श्रधिकाँश श्रादमियों के पास बहुत कट छंट कर पहुँचती है, इसमें बहुत मिलावट हो जाती है। श्रीर, इस अधूरी श्रीर श्रशुद्ध बात पर लोगों का मत बनता है। यह मत विकार-रहित कैसे हो सकता है! फिर, जब इन लोगों की भावनाएँ संकृचित हों, दृष्टि-कोख अनुदार हो, अपने कुटुम्ब, परिवार

जाति या सम्प्रदाय का इनमें पक्षपात हो, राज्य-हित की अवहेलना कर प्रत्येक विषय को अपने स्वार्थ की दृष्टि से ही सोचने की मनोवृत्ति हो तो इनका मत कितना दृष्ति और हानिकर होगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

स्वार्थ ऐसी वस्तु है जो ज्ञानवान को भी व्यवहार में मूर्ख बना देती है। मूर्खों की त्रुटियाँ तों फिर भी चम्य हैं, आज वे विवश हैं, लाचार हैं, पर उनके सम्बन्ध में यह आशा तो है कि उनकी परिस्थिति में सुधार की सम्भावना है, शिक्षा प्राप्त करने पर वे अपनी भूल को स्वीकार करेंगे, अपना मत परिवर्तन करेंगे, और समाज-हित की भावना से प्रेरित होकर विचार तथा कार्य करेंगे । परन्तु जो व्यक्ति स्वार्थ-वश श्रन्धे हैं, उनके विषय में क्या कहा जाय ! प्रत्येक राज्य में कितने-ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञानवान होकर भी स्वार्थवश अनुचित या श्रमत्य मत ग्रहण करते हैं. श्रयोग्य उम्मेदवारों के पक्त में मत देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं: हां-हजूरी श्रीर खुशामद को बुरा समभते हुए भी श्रपने श्रधीनस्य कर्मचारियों से उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, एवं अपने उच्च अधिकारियों की सेवा में उसे अपण करते हुए नहीं लजाते । ये लोग रिश्वत देते हैं, श्रीर लेते हैं; हाँ, कुछ सम्यता-पूर्वक, नये श्राधनिक ढङ्ग से, जिससे कानून की पकड़ में न आवें। ये लोग किसी क़ानून को जनता के लिए हानिकर समभते हुए भी इसलिए उसके प्रस्ताव के पक्ष में मत दे देते हैं कि उच श्रिधकारियों की ऐसी इच्छा थी। ये लोग बहुधा श्रपनी शिक्ता या ज्ञान के बल पर श्रशिक्षितों को श्रपने जाल में फँस लेते हैं, उनका नेतृत्व ग्रहण

कर अपना मतलब सिद्ध किया करते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति राज्य के लिए बहुत घातक होते हैं।

श्रस्तु, लोकमत के दो दोष प्रधान हैं-श्रज्ञान श्रौर स्वार्थ। इन्हें दर करने का भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिससे सच्चे लोक-मत के निर्माण में सहायता मिले । इसका एक उपाय जनता में शिक्षा-प्रचार करना है। जैसा कि इमने अन्यत्र कहा है, शिक्षा का अर्थ कुछ लिखना-पढ़ना गीखना ही नहीं समभाना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वह है जो इमारे मानवी गुणों का विकास करे, इमें विशाल नागरिकता का पाठ पढावे, जिससे इम अपने अधिकारों को समर्फों, और अपने कर्तव्यों का पालन करे। अतः स्कूजों का पाठ्य-क्रम इस लक्ष्य को सामने रखते हुए निर्घारित हो, प्रौढ़-शिद्धा की भी व्यवस्था हो, पत्र-पत्रिकाएँ श्रौर सामियक पुस्तकों तथा अन्य उच्च साहित्य का प्रचार हो. नागरिक, श्रार्थिक श्रौर राजनैतिक ज्ञान के प्रचार के लिए यथेष्ट संस्थाएँ स्थापित हों, इनमें व्याख्यान, अनुसंधान, वाद-विवाद, लेख श्रीर निबन्ध-पाठ का प्रबन्ध हो। ऐसे राजनैतिक दलों का भी संगठन होना बहुत आवश्यक और उपयोगी है, जो राज्य के व्यापक हितों से सर्वसाधारण को परिचित करें, जो संकीर्ण साम्प्रदायिक भावों को दूर करनेवाले हो। दलों के सम्बन्ध में एक पृथक परिच्छेद में विशेष विचार किया जायगा; श्रीर, पत्र-पत्रिकाश्रों श्रादि के विषय में श्रागे इसी परिच्छेद में लिखा जायगा।

इसके श्रविरिक्त नागरिकों को दूर-दूर की यात्रा करने के लिए श्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में, तीर्थ-यात्रा करने में

पहले यही उद्देश्य रहता था। त्रादमी दूर-दूर के भागों की यात्रा करने के साथ अपने अन्य नागरिक वन्धुओं के रीति-रिवाज, प्रथाओं. विचार श्रीर श्रादशों का ज्ञान प्राप्त करते थे. श्रपनी स्थित की उनसे जुलना करते थे। इससे उन्हें अपनी बुराइयों को छोड़ने और दूसरे के गुर्खों को प्रहर्ख करने की प्रेरखा होती थी, उनकी दृष्टि उदार होती थी, उनकी संकीर्णता तथा कृप-मंडकता इटती थी, श्रीर वे मानव समाज -सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर व्यापक हिष्ट-को स विचार करने में समर्थ होते थे। प्राचीन काल में अनेक आदमी प्रति वर्ष नियमित रूप से कुछ यात्रा करके अपने ज्ञान और अनुभव की वृद्धि करते थे। कुछ लोग तो एक साथ दो-दो तीन-तीन मास की यात्रा कर लेते थे। अब नागरिक जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। साधारण नागरिकों को इतना श्रवकाश ही नहीं मिलता कि वे ऐसी यात्रा करने का इरादा करें। श्रीर. यदि वे इरादा भी करें तो श्रार्थिक वाघाएँ बहुत हैं। भारतवर्ष में श्रामदरक्त की सविधाएँ कम हैं। लोगों की माली हालत की दृष्टि से, यहाँ रेलों का किराया बहुत अधिक है। कुछ रेलवे कम्पनी विशेष यात्रा करनेवालों के साथ कुछ रियायत करती हैं, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य घनोपार्जन ही रहता है, नागरिकों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना नहीं । इसमें सुधार होने की अत्यन्त श्रावश्यकता है।

बाहरी दुनिया का जान श्रीर श्रनुभव प्राप्त करने के लिए नागरिकों को विदेश-यात्रा भी पर्याप्त रूप में करनी चाहिए। भारतवासियों के लिए विदेश यात्रा करने में श्रार्थिक वाघाएँ तो हैं ही, सामाजिक श्रीर राजकीय वाधाएँ भी हैं। यद्यपि इस विषय में लोकमत क्रमशः सुघर रहा है, कुछ समाजों में विदेश-यात्रा श्रमी तक भी निषद्ध है। विदेश-यात्रा के लिए 'पासपोर्ट' श्रर्थात् सरकारी श्रनुमित मिलने में बहुषा किनाई होती है। वर्तमान श्रवस्था में विदेश-यात्रा कुछ राजा श्रीर रईसों के ही वश की रह गयी है, श्रीर ये लोग प्रायः कुछ ज्ञान या श्रनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश नहीं जाते, वरन् जाते हैं श्रीक या मनोरंजन के लिए। कुछ युवक शिक्षा प्राप्त करने, श्रीर बहुत-से मजदूर श्रपनी श्राजीविका प्राप्त करने की चिन्ता में भी विदेश जाते हैं। ये भी प्रायः वहाँ से विशेष श्रनुभव लेकर नहीं लौटते। श्रस्तु, नागरिक श्रव्छा लोकमत निर्माण करने में सहायता प्रदान कर सकें, इसके लिए उन्हें स्वदेश तथा विदेशों में यात्रा करने की यथेष्ट सविधाएँ मिलनी चाहिएँ।

## पत्र-पत्रिकाएँ

समाचार-पत्र— लोकमत का विकास करनेवाले साधनों में पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है। वास्तव में ये हमारे 'कम-खर्च, बालानशों' अध्यापक, उपदेशक, सुधारक और आन्दोलक हैं। ये लोकमत-निर्माण करने तथा उसे प्रकाशित करने में बहुत सहायक होते हैं। परन्तु नागरिकों के लिए इनका आँख मीच कर उपयोग करना ठीक नहीं है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कई बातें विचारणीय हैं। कुछ समाचार-पत्र स्वतंत्रता और निर्भीकता-पूर्वक अपना महान कर्तव्य पालन करते हैं। उनके सामने वास्तव में समाज-सेवा और लोक-हित का आदर्श रहता है। उनके सम्पादक श्रापने उत्तरदायित्व को समभते हैं श्रौर सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक वाधात्रों का सामना करते हुए भी कभी विचलित नहीं होते। उन्हें, समाज के कुछ धनी-मानी व्यक्तियों की सहानुभूति या सहायता से वंचित होना पड़े तो वे परवाह नहीं करते, श्रार्थिक कठिनाहयों श्रौर राज्य की कोप-हिष्ट को वे सहन करते रहते हैं, पर श्रपने पत्र में सत्य घटनाश्रों को ही प्रकाशित करते हैं, उनके सम्पादकीय लेखों या टिप्पियों में किसी वर्ग, समप्रदाय या स्वार्थवालों का पक्ष नहीं लिया जाता, वे प्रत्येक विषय पर निष्पक्ष मत प्रकाशित करते हैं, श्रौर श्रपनी लेखनी से लोक-हित की बात सुमाते रहते हैं।

परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे पत्रों की संख्या इनी-गिनी ही होती है। बहुत-से आदमी पत्र-सम्पादन को आजीविका-प्राप्ति या लाम का साधन समभते हैं। उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता, अथवा, यदि आदर्श होता है तो अधिक-से-अधिक आय प्राप्त करना। उन्हें अपने महान उत्तर-दायित्व का विचार नहीं होता। वे शिक्षित होते हैं, अतः उन्हें ज्ञान तो होता है, पर स्वार्थवश उस ज्ञान का उपयोग जनता के हित के लिए न होकर उलटा अहित के लिए होता है। रईसों या राजा-महाराजाओं को खुश करने के लिए कामुकता-पूर्ण लेख या कहानियां आदि तथा श्रांगर-मय चित्र या कविताएँ प्रकाशित करना, किसी सम्प्रदाय या जाति-विशेष की बातों का बिना विचारे समर्थन करना, दूसरे पच्चवालों की व्यर्थ की निन्दा करना, अपने व्यक्तिगत राग-देषात्मक भावों को प्रकट करना, अपने विरोधियों के प्रति विष उगलते रहना—

यह उनका नित्य-कर्म होता है। अनेक पत्र कुछ पूँजीपितयों के आश्रय से, उनके विशेष स्वार्थों की रक्षा के लिए प्रकाशित किये जाते हैं। उनकी अपनी कोई नीति नहीं होती, इनकी वागड़ोर इनके स्वामियों के हाय होती है। जिघर वे इशारा करते हैं, उघर ही ये उत्तक पड़ते हैं। यदि मालिक कहे दिन, तो ये सूर्य उगा दें, और मालिक कहे रात तो ये तारे गिना दें। मला ऐसी उल-मुल नीतिवाले, स्वार्थी पत्र-पत्रिकाएँ लोकमत के विकास में क्या सहायक हो सकते हैं। ये तो उसे भरसक विगाड़ने, लोगों को पय-भ्रष्ट करने तथा उन्हें परस्पर में लड़ानेवाले ही होते हैं।

सरकार पत्र-पत्रिकाओं के महत्व को खूब समभती है, श्रतः प्रायः वह ऐसी नीति रखती है कि जो पत्र उसका समर्थन करें, उसकी हाँ में हाँ मिलावें उनको सहायता दी जाय, श्रीर जो पत्र उसके कामों की खरी श्रालोचना करें, जनता के सामने उसका रहस्योद्घाटन करें उनका दमन हो। श्रपनी प्रसन्नता या श्रप्रसन्नता स्चित करने के लिए सरकार के हाथ में श्रनेक उपाय होते हैं। जिस पत्र पर कृपा-दृष्टि हो, उसे सरकारी विशापन, इश्तहार श्रादि दिये जाते हैं, श्रथवा उसकी कुछ कापी प्रचारार्थ खरीदी जाती हैं। श्रीर, ये बाते पत्रों को जीवन प्रदान करनेवाली होती हैं। सरकार की सहायता पानेवाले पत्र खूब हुन्ट-पुष्ट श्रीर सचित्र रहते हैं, इससे वे श्रल्पण तथा शौकीन लोगों के भी प्रिय हो जाते है, श्रीर इनका भी श्राश्रय उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्रव उन पत्रों की बात लीजिए, जो प्रत्येक बात को सरकार की श्राखों से न देख कर जनता के दृष्ट-कोगा से विचार करले

हैं, श्रौर सरकार को प्रसन्न करने के लिए घटनाश्रों को तोड़ते-मरोड़ते नहीं, सदैव सत्य श्रौर न्याय का पक्ष लेते हैं। ये सरकार को समय-समय पर उचित सलाइ देते हैं, चाहे वह उसे श्रिय ही लगे। सरकार प्राय: ऐसे पत्रों पर वक हिंदर रखती है, वह इनसे ज़मानत माँग लेती है, श्रवसर पाकर उस जमानत को पूरी या किसी श्रंश में ज़प्त कर लेती है, फिर नयी ज़मानत माँग लेती है, पत्र की प्रतियाँ जप्त कर लेती हैं। इस प्रकार बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ बे-श्रायी मौत मर जाते हैं। समरण रहे कि पत्रों के दमन की बात उसी देशा में होती है जब सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, उसका हिंदर कोण जनता के हिंदि कोण से भिन्न होता है। लोक-प्रिय सरकार तो सची श्रालोचना का सहर्ष स्वागत करती है, श्रौर उस पर सम्यक् विचार कर उससे श्राक्षा प्रहण करती है।

अस्तु, मुख्य ध्यान देने की बात यह कि पूँजीपतियों की भाँति सरकार भी पत्रों को प्रमावित करती है, और इस प्रमाव के कारण एवं सम्पादकों की निर्वलता के कारण, बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ अपने महान् कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन नहीं कर पातीं! तथापि नागरिक जीवन में, लोकमत के निर्माण और विकास में, उनका बड़ा भाग होता है। जो पाठक पत्र-पत्रिकाओं को बराबर देखते हैं, उन्हें कुछ समय बाद यह अनुमान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है कि पत्रों में प्रकाशित किसी बात का वास्तव में क्या मूल्य है। विज्ञापनों के विषय में समक्षदार पाठक यह अनुमन करने लगते हैं कि इसमें सचाई बहुत कम है। किसी पत्र में अन्य बातों को पढ़ते हुए

भी वे यह ध्यान रखते हैं कि यह पत्र किसके संरक्षण में निकल रहा है, यह किस दल या सम्प्रदाय का है, इसमें कैसी-कैसी बातों को द्रवाया जाता है, और किस प्रकार की बातों को अत्युक्ति-पूर्वक अतिरंजित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार वे हंस की मौति नीर-क्षीर-विवेक नीति से काम लेते हैं। फिर समाचार-पत्रों में बहुत-सी बातें तो ऐसी भी होती है, जिनसे किसी दल या सम्प्रदाय आदि का सम्बन्ध नहीं होता, वे सार्वजिनक विषयों पर प्रकाश डालने-वाली तथा देश-विदेश की विविध विषयों की जानकारी करानेवाली होती हैं। इन बातों से पाठकों का ज्ञान बढ़ता है, विचार-चेत्र विस्तृत होता है, उन्हें दूसरों का हिन्ट-कोण जानने और फल-स्वरूप कमशः उससे सहानुभूति रखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, समाचार-पत्रों के द्वारा लोकमत के विकास में कुछ-न-कुछ सहायता अवश्य मिलती है। हां, जितने ये योग्य और उत्तरदायी व्यक्तियों के हाथ में होंगे, उतना ही ये अधिक उपयोगी होंगे।

श्रन्य सामयिक साहित्य— ऊपर हमने समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में लिखा है। ये श्रधिकतर दैनिक या साप्ताहिक होते हैं। कुछ योड़े-से श्रर्क-साप्ताहिक या पाक्षिक भी होते हैं। जो पत्र जितने श्रधिक समय के बाद निकलता है, उतना ही उसमें रोजमर्रा की साधारण घटनाश्रों को कम महत्व दिया जाता है, श्रीर प्रस्तुत समस्याश्रों पर श्रधिक गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाता है। सामयिक साहित्य में मासिक पत्रिकाश्रों का स्थान महत्व-पूर्ण है, त्रेमासिक कम निकलती हैं, श्रीर श्रर्द-वार्षिक या

वार्षिक उनसे भी कम । इनमें से कुछ तो किसी सम्प्रदाय या समुदायविशेष की श्रोर से निकलती हैं, कुछ साहित्य, विज्ञान, भूगोल,
दर्शन, इतिहास, श्रर्थशास्त्र विषय सम्बन्धी होती हैं, श्रोर कुछ बालकों
या महिलाश्रों श्रादि सम्बन्धी होती हैं। इनमें से भी श्रधिकांश
में, पाउकों की जानकारी के लिए उस विशेष विषय सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामयिक घटनाश्रों पर प्रकाश डाला जाता है। कुछ पत्रिकाएँ
ऐसी भी होती हैं, जिनमें मुख्यतया राजनैतिक विषयों की ही चर्चा
होती है। प्रत्येक पत्रिका, जिस उद्देश्य से निकालो जाती है, उसका,
तथा श्रप्ने संचालन या संरक्षकों की नीति का, ध्यान रखकर
चलती है। कुछ श्रंश तक इन में भी वे दोष हो सकते हैं, जो ऊपर
समाचार-पत्रों में बताये गये हैं। श्रतः इनके द्वारा लोकमत के निर्माण
में जनता के हित का यथेष्ट ध्यान रहे, इसके लिए यह श्रावश्यक है
कि इन्हें उक्त दोषों से यथा-संभव बचाया जाय।

बहुषा सार्वजनिक विषयों पर कुछ ट्रेक्ट या पुस्तिकाएँ भी समय-समय पर प्रकाशित होतो हैं। इनमें से श्रिषकांश का उद्देश्य किसी दल या सम्प्रदाय-विशेष के दृष्टिकोण को उचित उहराना तथा उसका जनता में प्रचार करना होता है। प्रायः इनकी माषा, विचार या शैली में गम्भीरता कम होती है। इनका जीवन श्रल्पकालीन होता है। श्रान्दोलन शान्त होने पर इनकी कुछ उपयोगिता नहीं रहती, हाँ, कुछ समय के लिए इनसे लोगों में काफ़ी हलचल रहती है। कुछ पुस्तकें बहुत विचार-पूर्ण होती है, इनमें सिद्धान्त की चर्चा बहुत खोज, परिश्रम तथा गम्भीरता से की जाती है। श्रिक्षत श्रीर विद्वान तथा

समाज-नेता इनका भली-भांति मनन करते हैं और इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। ये लोकमत के विकास में स्थायी सहायता प्रदान करती हैं। अतः जो लोग किसी प्रकार का साहित्य प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेवारी का भली भांति विचार करना आवश्यक है, उनके द्वारा समाज हितकारी लोकमत का ही निर्माणः होना चाहिए।

# चौबीसवाँ परिच्छेद राजनैतिक दल

मिन्न-भिन्न दलों का भी बहुत भाग होता है। इस परिच्छेद में राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाता है। बहुषा 'दल' शब्द से भी 'राजनैतिक दल' का अर्थ लिया जाता है।

राजनैतिक दल ऐसे नागरिकों के समृद्द को कहते हैं, जिनका राजनैतिक विषयों या स्थिति के सम्बन्ध में एक विशेष मत होता है, और जो सरकार द्वारा एक विशेष नीति काम में लाये जाने का प्रयस्न करते हैं। इस प्रयस्न का व्यवाहारिक रूप यही होता है कि प्रत्येक दल अपने अधिक-से-अधिक सदस्य व्यवस्थापक समार्थों में मेजने का उद्योग करता है। इसके लिए निर्वाचनों के समय दलों की खूब धूम रहती है। प्रत्येक दल अपनी नीति, उद्देश्य और सिद्धान्तों की प्रशंसा करता है, और सर्वसाधारण में उनका प्रचार करता है, जिससे अधिक-से-अधिक निर्वाचक उस दल के उम्मेदवार को ही अपना

मत दें। विभिन्न दल अपने इस आन्दोलन में एक-दूसरे से बाजी मार ले जाना चाहते हैं, इसिलए बहुषा यह आन्दोलन मर्यादा-विहीन हो जाता है। दलों के नेता, अपने दल की प्रशंसा करने में, दूसरे दलों पर कीचड़ उछालने में संकोच नहीं करते। वे विपक्षी उम्मेदवारों के व्यक्तिगत कार्यों की आलोचना करके उन्हें जनता की हष्टि में गिराने की कोशिश करते हैं। निर्वाचकों को खुश करने के लिए जो-कुछ किया जा सकता है, उसे करने में कोई कसर नहीं रखी जाती। उसे देख-सुन कर निर्वाचन-आन्दोलन से अनेक भले आदिमियों को घृणा होने लगती है।

यह निर्वाचन-आन्दोलन तथा राजनैतिक दलबन्दी प्रजातन्त्र शासन-पद्धित का परिणाम है। (अवैध) राजतन्त्र में तो राजा या बादशाह को ही शासनाधिकार होता है, राजनैतिक दलों का निर्माण नहीं होता; शासन-कार्य की आलोचना करनेवाला व्यक्ति दंड पाता है। इसके विपरीत, प्रजातन्त्र में नागरिकों को इस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि अपने विचार निर्भीकता-पूर्वक प्रकट करें। वे समाएँ कर सकते हैं, और उनमें भाषण देकर लोगों को सरकार के दोषों का ज्ञान करा सकते हैं। प्रेस की भी आज़ादी रहती है, पत्र-पत्रिकाएँ, ट्रेक्ट और पुस्तकें छापने में रोक नहीं लगायी जाती। निदान, नागरिकों को अधि-कार रहता है कि वे अपना मत स्पष्ट-रूप से प्रकट करें, उन्हें उसको दबाये रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि तानाशाही में होता है (बो अवैध राजतन्त्र का ही एक उग्र स्वरूप है)। तानाशाही में नागरिकों को अपना मत उसी दशा में प्रकट करने की स्वतंत्रता

होती है. जबिक वे तानाशाही में किये जानेवाले कार्यों के समर्थक हों। यदि उनका तानाशाही की नीति या कार्यों से विरोध होता है तो या तो उन्हें श्रपना मत दबा कर रखना पड़ता है, श्रयवा उन्हें सरकार के कोप-भाजन बनने के लिए, श्रयवा राज्य से बाहर भटकते रहने के लिए, वाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार तानाशाही में एक ही दल होता है, अलग-अलग कई दल नहीं होते: या यों कह सकते हैं कि दलबन्दी नहीं होती। तानाशाही में नीचे से ऊपर तक सब कर्मचारी एक ही दल के होते हैं, अलग-अलग विचार रखनेवालों को शासन-कार्य में स्थान नहीं दिया जाता. उनका राज्य में रहना भी सहन नहीं किया जाता। भिन्न-भिन्न दलों के न होने में तानाशाही में वे मत्त्रहे और कलह भी नहीं होते. जो दलों की विभिन्नता में अनिवार्य-से होते हैं। इस प्रकार प्राय: समस्त नागरिकों की शक्ति अपने राज्य की उन्नति में लगी रहती है। परन्तु जैसाकि पहले कहा गया है, इसमें स्वतन्त्र मत रखनेवालों का जान-माल सदैव संकट में रहता है।

दलावन्दी से लाभ-हानि — प्रजातन्त्र शासन-पद्धित के संचा-लन के लिए भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का होना श्रनिवार्थ है। श्रच्छा, इस दलबन्दी से लाभ क्या है? राजनैतिक दल अपने-अपने सदस्यों की संख्या और प्रभाव बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव और नगर-नगर में घूम-फिर कर अपना प्रचार करते हैं। वे राज्य की नीति और कार्यों की आलोचना करते हुए उनके सम्बन्ध में अपनी नीति और कार्ये-अभ की चर्चा करते हैं। वे अपने पत्रक या विज्ञातियाँ खुपा कर लोगों में बाँटते हैं। इस प्रकार राज्य भर में, साधारण व्यक्तियों को भी, राजनैतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर उपस्थित होता है। राजनैतिक दलों के उपर्युक्त आन्दोलन के अभाव में ऐसा होने की संभावना नहीं होती; अनेक आदिमियों को न राजनैतिक शिद्धा मिलती है, न अपने अधिकारों तथा रचनात्मक कार्यों का ही ज्ञान होता है। राजनैतिक दल नागरिकों में जाग्यित पैदा करते हैं, और उनकी योग्यता तथा शिक्त बढ़ाते हैं। इस प्रकार वे राज्य का विकास करने तथा उसका बल बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं।

परन्तु इस दलबन्दी से लाभ ही लाभ हो, यह बात नहीं हैं। इससे हानियां भी हैं। दलों के निर्माण में जो अनीति बरती जाती है, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कुछ दल ऐसे होते हैं, जो जन-हित के सिद्धान्त पर नहीं बनाये जाते। उनका उद्देश्य उनके सूत्रधारों का, या सम्प्रदाय विशेष का हित-साधन करना होता है। इससे नागरिकों में सङ्गीर्याता तथा दुर्भावना उत्पन्न होती है। प्रत्येक दल दूसरे दल की निन्दा करना अपना आवश्यक कार्य समभता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि एक दल के सूत्र-संचालकों की मान-प्रतिष्ठा को देखकर कुछ आदमी अपने व्यक्तिगत देख-भाव के कारण, उस दल के विरुद्ध अपना नया दल बना लेते हैं और विविध कूटनैतिक चालों से उस दल में फूट पैदा करने तथा उसे कमजोर बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसमें नागरिकों की कितनी शिक्त नध्ट होती है! पुनः जब मिन्न-भिन्न दलों के नेता अपने-अपने कार्य और नीति की प्रशंसा करते हैं। उन्हें

यह निर्णय करते नहीं बनता कि किस दल का कथन ठीक है अथवा, किस दल का अनुकरण करना राज्य के लिए हितकर होगा। इस प्रकार ये दल नागरिकों का मार्ग प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें पथ-भ्रष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त दलबन्दी का यह तो एक सिद्धान्त-सा हो गया है कि प्रत्येक न्यक्ति अपने दल की उचित-अनुचित अथवा सच्ची-भूठी प्रत्येक बात का समर्थन करे। इसमें वह अपनी विचार-स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता, अपनी आत्मा के आदेश का पालन नहीं कर सकता। किसी प्रस्ताव पर मत देने में वह यह सोचने का कष्ट नहीं उठाता कि पक्ष में मत देना ठीक है, या विरोध में। वह केवल यह देखता है कि दल के नेता का हाथ किघर उठता है; जिघर उसका हाथ उठेगा, उघर ही उस दल के समस्त व्यक्तियों को मत देना चाहिए। जो व्यक्ति इसके विरुद्ध आचरण करेंगे, उनका दल से वहिष्कार कर दिया जायगा। यह मत-स्वातन्त्र्य पर कैसा आधात है और कैसा आत्मिक पतन है!

द्तों का उपयोग — सर्वसाघारण में नागरिक और राजनैतिक शिचा प्रचार के लिए राजनैतिक दल बहुत उपयोगी होते हैं। ये दल निर्वाचन के लिए योग्य उम्मेदवारों को चुनते हैं, और इस प्रकार व्यवस्थापक सभाश्रों में नागरिकों के अच्छे प्रतिनिधि मेजने में सहायक होते हैं। ये जनता तथा सरकार के सामने अपने कार्य-काल के लिए, और कभी कभी पाँच या दस वर्ष या न्यूंनाधिक समय के लिए सुधार सम्बन्धी योजनाएँ तथा निर्धारित कार्य-कम का प्रस्ताव

उपस्थित करते हैं।

दलों की सफलता के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक यह है कि दलों की संख्या बहत श्रिधक न हों। जब दल बहत श्रिधक होते हैं. श्रीर निर्वाचन के लिए प्रत्येक दल की श्रीर से उम्मेदवार खड़े किये जाते हैं तो निर्वाचकों के लिए मत देने में बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है: किसे मत दें श्रौर किसे न दें । पुनः जब राज्य में दलों की संख्या श्रधिक होती है श्रीर कई दलों के उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा में पहुँचते हैं तो मंत्री-मंडल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है; कभी-कभी ऐसा होता है कि एक दल का मंत्री-मंडल वन ही नहीं सकता, कई दलों का मिश्रित मंत्री मंडल बनता है। फिर जो मंत्री-मंडल बनता है वह बहुत स्थायी या बलवान नहीं होता। उसके विरोधी कई दलों के सदस्य होते हैं, श्रौर जब भी इनमें से कुछ दलों के सदस्य श्रापस में समभौता कर लेते हैं तो वे मन्त्री-मंडल का पतन कर सकते हैं। मिश्रित मन्त्री-मंडलों के बनाने श्रीर भंग करने में प्राय: बड़ी कुट चालें चली जाती हैं। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, श्रिधिक दलों का निर्माण न होना चाहिए, थोड़े-बहुत साधारण मत-मेद के कारण एक पृथक दल न बनाया जाना चाहिए। राज्य में दलों की संख्या परिमित ही रहनी ठीक है।

दलों की सफलता के लिए दूसरी श्रावश्यक बात यह है कि उनका श्राधार जाति-गत, साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक न होना चाहिए । ऐसे दलों को विचार-धारा बहुत संकीर्ण रहती है, इनके दृष्टि-कोण में बहुत श्रनुदारता होती है, ज्यापकता और उदारता का श्रमाव होता

है। इनसे समाज में फूट और द्रेष की वृद्धि होती है। ये प्रत्येक बात को अपने संकीर्ण भावों के अनुसार सोचते हैं, और किसी बात को उसी दशा में मान्य करते हैं, जब उनका स्वार्थ-सिद्ध होता हो। इस प्रकार राज्य के हित की अवहेलना होती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि दलों का आधार विशाल होना चाहिए, उनका उद्देश्य जनता या सर्वेसाधारण का हित होना चाहिए।

हमने पहले बतलाया है कि साधारणतया नागरिकों की प्रकृति या विचारों की विभिन्नता के आधार पर तीन दलों का रहना स्वाभाविक-है:—(१) प्रगतिशील या उग्र, (२) रूढ़ियों का पृष्ठ-पोषक या स्थिति-रक्षक, (३) इन दोनों के बीच का, स्वतंत्र। यह बात विशेषतया समात्मक या पार्लिमेंटरी शासन-पद्धित के सम्बन्ध में लागू होती है। संध-शासन-पद्धितवाले राज्य में तो दो ही दल ठीक रहते हैं, (१) केन्द्रीय या संध सरकार को मजबूत करने के पक्षवाला, (२) सदस्य-राज्यों की सरकारों में अधिक-से-अधिक शक्ति विभाजित करने के पक्ष वाला। परन्तु अब तो मानों दलबन्दी का युग है। किसी राज्य में दलों की संख्या को सीमा नहीं रहती; इसे यथा-सम्भव बचाया जाना चाहिए।

राजनैतिक दलों के विषय को अच्छी तरह समभने के लिए यह जान लेना उपयोगी होगा कि भारतवर्ष में राजनैतिक दल कब से हुए, श्रीर वर्तमान अवस्था में यहां कौन-कौन से दल ऐसे हैं, जिन्हें राजनैतिक दल कहा जाना चाहिए, तथा उन दलों में मुख्य मेद क्या है। भारतवर्ष में राजनैतिक दल —यह तो पहले कहा ही जा

चका है कि राजनैतिक दलों का निर्माण प्रजातंत्र में होता है। प्राचीन भारतवर्ष में श्रधिकतर राजतंत्र की प्रधानता रही; हां, राजनीति में 'राजा प्रकृति रंजनात' अथवा ''जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो वप अवश्य नरक अधिकारी" का विद्धान्त मान्य रहा। अधिकांश राजा प्रजा की हित-चिन्तना में तन्मय रहते थे। वे प्रजा के मत का कितना श्रादर करते थे, इसका श्रनुमान एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के कथन से, रामचन्द्रजी द्वारा सीता का परित्याग करने से हो सकता है। तथापि राजतंत्र में, चाहे वह कितना ही प्रजा-हितेषी हो. जन मत के संगठित होने. या विभिन्न दलों के निर्माण होने की संभावना नहीं होती। राजपत, मुगल या मराठा शासन में भी यहाँ राजनैतिक दल नहीं बने; प्रधान शासक के निर्णय के विरुद्ध प्रजा ने कभी संगठित रूप से मत प्रकट नहीं किया । इस के बाद, कम्पनी के शासन में, राज-काज बहुत क्छ स्वेच्छाचारिता-पूर्वक होता रहा। दलों के संगठन की उस समय मी बात न थी। जनता का विरोध प्रगट हुआ तो सन् १८५७ की सशस्त्र क्रान्ति के रूप में। तदनंतर ब्रिटिश पार्लिमैंट ने यहां का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया, परन्तु शासन-कार्य में बहुत समय तक प्रजातंत्रवाद का परिचय न दिया गया । फल-स्वरूप यहां राजनैतिक दल मी नहीं बने । सन् १८८४ ई० में कांग्रेस की स्थापना के बाद, लोगों में सरकार की शासन-नीति के प्रति अपना विरोध वैध रीति से प्रकट करने की भावना जाायत हुई।

सन् १९०५ तक यहाँ जन-मत-विरोधी इतने कार्य हो चुके थे, कि उक्त वर्ष में होने वाले बंग-बिच्छेद ने यहाँ अनेक व्यक्तियों को

राजनैतिक सुधारों के सम्बन्ध में निराश कर दिया। कितने-ही व्यक्ति बेचैन तथा उग्र विचार वाले हो गये। राजनीतिज्ञों के दो मेद हो गये-गर्म और नर्म। नर्म दल घीरे-घीरे, इंगलैंड के सहयोग से. वैध रीति से शासन-सुधार प्राप्त करने के पक्ष में था। गर्म दल इससे सहमत न था. वह शीव्र स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। उस समय की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाक्षों में लोकमत यथेष्ट रूप से प्रकट होने की व्यवस्था न थी। कुछ सदस्य गैर-सरकारी श्रवश्य होते थे. पर उन्हें मनोनीत करने का श्रविकार सरकारी अधिकारियों को ही था: फल-स्वरूप गर्म दल के व्यक्ति व्यवस्थापक सभाश्रों में नहीं पहुँच पाये. उनके नेताश्रों को तो सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा । श्रस्तु, यहाँ उत्तरदायी शासन-पद्धति का श्रंशत: सूत्रपात पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद सन् १९१९ ई० से हुआ। श्चब व्यवस्थापक सभाश्चों में लोकमत प्रकट होने लगा। परन्त व्यवस्थापक सभाश्रों का श्रिष्ठकार बहुत सीमित था। उनके प्रस्ताव केवल िफारिश के रूप में होते थे. जिन्हें प्रधान शासक चाहे तो अस्वीकार कर सकता था। इससे व्यवस्थापक सभाश्रों में भाग लेने के लिए बहत-से व्यक्तियों को कोई आकर्षण न हुआ, श्रीर कुछ सदस्य कुछ समय के असंतोषप्रद अनुभव के बाद उनसे बाहर चले आये। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों के श्राधिकार सन् १९३५ ई० के क्रान्न से, बढ़ाये गये हैं, जिसका उद्देश्य प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। यह क़ान्त १९३७ ई० से अमल में आने लगा।

श्रातु, हमें विचार यह करना है कि भारतवर्ष में श्रव राजनैतिक

दल कौन-कौन से हैं। इस प्रसंग में स्मरण रहे कि कुछ दल तो साम्प्रदायिक या धार्मिक आधार पर हैं, यथा मुसलिम लीग और हिन्द महासभा। इनकी, राजनैतिक दलों में गणना नहीं की जानी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ कुछ मुसलमान नेता श्रपना श्रलग ही संगठन करके सरकार के सामने समय-समय पर अपनी प्रथक मौग उपस्थित करते रहे हैं. श्रीर सरकार ने भी उनके संगठन की श्रवहेलना करने का सत्कार्य नहीं किया। मुसलमानों की देखा-देखी हिन्दुओं ने भी अपनी पृथक् माँग उपस्थित करना आवश्यक समस्ता। यही नहीं, सिक्ख, हरिजन श्रादि जातियों ने देखा कि हमें हिन्दुश्रों के साथ रहने की अपेक्षा. अपनी पृथक्ता की दशा में कुछ अधिकार अधिक मिलने की सम्भावना है तो उन्होंने अपनी हिन्दु श्रों से पृथक माँग उपस्थित करना हितकर समभा। इस प्रकार इन सब सम्प्रदायों या जातियों के अलग-अलग दल बने हुए हैं। ये दल अपने को राजनैतिक दत कहते हैं तथा राजनैतिक माँग रखते हैं। हाँ, संतोष की बात यह है कि प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय में कुछ विचारशील सजन ऐसे हैं जो साम्प्रदायिक या जाति गत संगठनों को राजनैतिक संगठन से सर्वेया पृथक् रखना उचित समभते हैं. श्रीर वे संकीर्ण दृष्टिकीया-वाले दलों में भाग नहीं लेते। उदाइरणवत् कितने ही योग्य और प्रतिष्ठित मुखलमान मुखलिम लीग के राजनैतिक दल होने और राज-नैतिक माँग उपस्थित करने के दावे को अस्वीकार करते हैं, और वे मुसलिम लीग का सदस्य बनना सिद्धान्त-विरुद्ध मानते हैं। यही बात हिन्दुओं तथा इनके अन्तर्गत अन्य जातियों के व्यक्तियों की है

यह कहा जा सकता है कि हिन्दू महासभा का दृष्टि-कोगा वैसा साम्प्रदायिक नहीं है. जैसा मुसलिम लीग का। परन्तु जिस संस्था के सदस्य किसी विशेष धर्म या जाति के ही व्यक्ति होते हैं, या हो सकते हैं, उसे विशुद्ध राजनैतिक दल नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मुसलिम लीग तथा हिन्दू महासभा श्रादि का उद्देश्य अपने-अपने चेत्र में समाज-सुधार या शिचा-प्रचार आदि होना चाहिए। राज-मैंतिक दल वे ही होने चाहिएँ, जिनमें धर्म या जाति आदि का कोई बन्धन न हो. सब नागरिक स्वतंत्रता-पूर्वक भाग ले सकें। उनका संगठन केवल राजनैतिक सिद्धान्तों पर किया जाना उचित है। परन्तु एक तो दलों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने ेलिए अधिक-से-अधिक व्यापक आधार रखना चाहते हैं और इसलिए कई-कई प्रकार के विद्धान्तों पर अपना संगठन करते हैं। दूसरे, आज-कल राजनीति की बढ़ी महिमा है; शिक्षा और समाज-सुधार विषय भी एक बढ़ी सीमा तक व्यवस्थापक सभाश्रों के श्राश्रित हैं। इसलिए अपनेक आदमी किसी समा. संस्था या दल को उसी दशा में कुछ -महत्व का मानते हैं, जबकि उसका सम्बन्ध राजनीति से भी हो। इस्तिए सम्प्रदायिक संगठनों में, राजनैतिक दल का वेष घारस करने की, प्रवृत्ति होती है।

यद्यपि यदा पर छोटे-बड़े सब मिला कर राजनैतिक दल कई-एक है, वास्तव में देखा जाय तो यहाँ मुख्य दल केवल दो हैं:—कांग्रेस दल और लिबरल दल। कांग्रेस का सगठन बहुत अञ्छा है। इसका प्रभाव गाँव-गाँव और नगर-नगर में है। बचा-बचा इसके नाम, इसके नारों, इसके गायनों, और इसके तिरंगे मंडे से परिचित है। जब इसका जल्म निकलता है या इसकी सभाएँ होती हैं तो तमाम बस्ती में धूम मच जाती है। इसका उद्देश्य भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है। श्रीपनिवेशिक पद ('डोमिनियन स्टेटस') या साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य इसे स्वीकार नहीं है। हौं, स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए यह केवल श्रहिन्सात्मक उपायों का श्रवलम्बन करती है। सशस्त्र क्रान्ति की यह घोर निन्दा करती है। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्य पर बहुत ज़ोर दिया है। इसके सम्बन्ध में श्रन्थक लिखा गया है।

कांग्रेस का अनुशासन दृढ़ है। प्रायः कोई सदस्य इस संस्था का नियम मंग नहीं करता; यदि कोई ऐसा करता है तो उसके सम्बन्ध में यथेष्ट कार्रवाई की जाती है। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष नियमा-नुसार होता है। इसकी स्थायी समिति और कार्यकारिणी कमेटी की मीटिंग समय-समय पर होती है। यह उपस्थित समस्याओं पर विचार करके देश का पथ-निर्देश करती है। भिन्न-भिन्न ज़िलों में इसका कार्यालय है, प्रान्तों में प्रान्तवार संगठन है। निदान, यह इतना बड़ा विशाल संगठन, संसार के राजनैतिक दलों का एक अच्छा नमूना है।

कांग्रेस दल के अन्तर्भत किसान दल, मज़दूर दल, समाजबादी दल आदि अनेक दल हैं। ये कांग्रेस दल की नीति और उद्देश्य सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों को मानते हुए अपने कुछ विशेष विचार भी रखते हैं। इनमें से कांग्रेस समाजवादी दल विशेष महत्व-पूर्ण है ।

यह इस बात में तो कांग्रेस दल से सहमत ही है कि देश को स्वतंत्र होना चाहिए, साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य से संतुष्ट न होना चाहिए। किन्तु इस दल का सिद्धान्त है कि शासन-सूत किसानों भौर श्रम-जीवियों के हाथ में हो; राजाश्रों ज़मीदारों श्रादि को श्रिषकार ज्युत किया जाय, प्रमुख या श्राधार-भृत व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण हो। यह दल श्रपने इन सिद्धान्तों का समावेश कांग्रेस की नीति में करवाना चाहता है, श्रीर इसके लिए कांग्रेस के श्रन्दर रह कर ही प्रयत्न करता है। श्रमी इसके सदस्यों की संख्या तथा बल कम है। परन्तु इनमें वृद्धि हो रही है। समय का प्रवाह इस दल के अनुकृत जान पड़ता है; बहुत सम्भव है कि निकट भविष्य में इसका देश में काफी प्रभाव हो जाय। श्रस्तु, श्रमी यह दल कांग्रेस से सम्बद्ध श्रीर उसके श्रन्तर्गत ही है।

कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरा उल्लेखनीय राजनैतिक दल लिकरल दल है। कांग्रेस की व्रलना में इसका कुछ विशेष महत्व नहीं है, तथापि यह काफी पुराना है। पहले बताया जा चुका है कि जब यहाँ गर्म और नमें दल का विभाजन हुआ तो बहुत समय तक व्यवस्थापक सभाओं में नमें दल की ही पहुँच हो सकी। एक प्रकार से, उस समय के गर्म और नमें दल अब कांग्रेस दल और लिकरल दल हैं। लिकरल दल का उद्देश्य बिटिश सरकार से सहयोग करते हुए ही राजनैतिक सुधार प्राप्त करना है। यह ऊँची-ऊँची फौजी तथा मुल्की नौकरियाँ भारतवासियों को दिलाने का आन्दोलन करता है। इसका आदर्श औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारतवर्ष

के बाहर होने को यह अञ्छा नहीं समभता। इसे सभाएँ करने और प्रार्थना-पत्र या प्रतिनिधि-मंडल (डेप्युटेशन) भेजने में विश्वास है: सत्याग्रह श्रीर श्रमहयोग श्रादि का मार्ग इसे पसन्द नहीं। इसका वार्षिक श्रिववेशन होता है। समय-समय पर कुछ श्रब्छे देश-प्रेमी इस दल में रहे हैं। परन्तु सर्वधाधारण पर इसका विशेष प्रभाव नहीं है। शहरों में रहनेवाले कुछ विशेष विदान वकील. वैरिस्टर श्रादि ही इस दल में सम्मिलित हैं। इनका कार्य-क्रम कुछ लेख लिखना, भाषण देना श्रादि है, जिसमें विशेष परेशानी उठानी नहीं पड़ती, जो श्राराम से परा होता रहता है। ये जनता को उतावला न होने तथा शान्ति श्रीर धैर्य रखने का श्रादेश करते हैं। परन्त जब इनसे पूछा जाता है कि श्राखिर यथेष्ट शासन-सुधारों के लिए प्रतीक्षा कब तक की जाय. श्रीर इनका बताया वैध उपाय सफल न होने की दशा में क्या किया जाय, तो इनके पास इसका कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं है। सर्व साधारण जनता पर इसका विशेष प्रभाव न होने के कारण सरकार इसे साधारण ही मान देती है। सरकार यह अनुभव करती है कि देश में सबसे मुख्य दल कांग्रेस दल है, यही जनता का विशेष प्रतिनिधित्व करता है।



## पचीसवाँ परिच्छेद

## नैतिक श्रीर धार्मिक प्रभाव

सम्बन्धी एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण से प्रभावित होता है। किसी व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी हो सकता है, जब उसके निकटवर्ती तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए भी वैसे ही जीवन की व्यवस्था हो। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे तो यही पर्याप्त नहीं है कि मेरा घर साफ़-सुथरा रहे। सम्भव है कि पास-पड़ोस के मकान गन्दे रहते हों, या मेरे मकान के सामने की नाली अच्छी तरह साफ़ न की जाती हो। इस दशा में मेरे घर में रहनेवाले व्यक्ति कैसे तन्दुरुस्त रह सकते हैं! वातावरण का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यदि हमारी गली या मोहल्ले में भी स्वास्थ्य-सम्बन्धी बांतों का समुचित प्रवन्त रहे तो सम्भव है, हमारे नगर के अन्य भागों में गन्दगी रहने से, वहाँ की, और उसके परिणाम-

स्वरूप नगर-भर की हवा ख्राब हो जाय। ऐसी हालत में भी हमारे स्वास्थ्य बिगड़ने की भारी श्राशंका रहेगी।

इससे प्रतीत हुआ कि मेरे घर के श्रादिमयों का स्वास्थ्य श्रव्छा रहने के लिए नगर-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था उचित रीति से होनी चाहिए। इस विचार-धारा को श्रीर श्रागे बढाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, हमारे नगर-भर में स्वास्थ्य श्रीर सफाई श्रादि की श्रावश्यक व्यवस्था है, श्रीर लोगों की तन्दुरुस्ती श्रव्ही है। अब इस प्रान्त में अथवा किसी दूसरे प्रान्त में रहनेवाले हमारे कुछ रिश्तेदार या मित्र हमारे यहाँ आते हैं, उनके नगर में प्लेग आदि बीमारी थी, श्रीर वे उस बीमारी के कीटा एए हमारे यहां ले श्राते हैं। इसका स्वभावतः यह परिखाम होगा कि हमारे घर में श्रौर फिर धीरे-धीरे इमारे नगर में भी बीमारी फैल जायगी । इससे विदित हुआ कि इमारे नगर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य अव्जा रहने का निश्चय तभी हो सकता है, जब हमारे प्रान्त या राज्य-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्य-वस्था ठीक रीति से हो। इसी प्रकार और आगे बढ़ कर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि कुछ श्रंश में संसार के मिल-मिल देशों का भी एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है।

ऊपर इमने स्वास्थ्य की बात ली थी | इसी तरह शिद्धा की बात ली जा सकती है | मैं अपने बचों को शिक्षित बनाना चाहता हूँ | इस लिए मैं उन्हें प्रति-दिन नियमित रूप से स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर दूँ तो यही पर्याप्त न होगा | बच्चे स्कूल में तो दिन के केवल पांच-छः घंटे ही रहेंगे | उनका शेष समय तो घर में, मोहल्ले में, बाजार में, या नगर

के भिन्न-भिन्न भागों में न्यतीत होगा। इस समय में वे बहुत-सी बातें देखेंगे. सनेंगे श्रीर कहेंगे। उन्हें जिन-जिन व्यक्तियों से काम पड़ेगा, उनकी श्रादतों, बोल-चाल, या विचारों का उन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। बहुघा अच्छे घरों के, और शिक्षा पानेवाले युवकों की ज़वान पर भी गनदे शब्द चढ जाते हैं. उन्हें गाली-गलौज करने में संकोच नहीं होता । इसवात की शिक्षा उन्हें कहां से मिली ? मां-बाप ने उन्हें ऐसा करना नहीं सिखाया, स्कूलों में भी उन्हें ऐसी बात नहीं सिखायी जाती। तो फिर उसका उत्तरदायित्व किस पर है ! बात यह है कि जिस वातावरण में बालक रहते हैं, उसका प्रत्यक्ष या गौण प्रभाव उन पर पड़े विना नहीं रहता। जो बालक ऐसे साथियों में रहता है जो लडते-भगडते श्रीर गाली-गलीज करते हैं. वह भी घीरे-घीरे ऐसा श्राचरण करने लगता है। बहत-सी बुरी बातें बालक श्रपने माता-पिता श्रीर शिच्कों से भी सीख लेते हैं, यद्यपि माता-पिता या शिक्षक की यह इच्छा नहीं होती कि बालक उन बातों को सीखें। बात यह होती है कि जब बालक यह देखता है कि वे लोग क्रोध में या हुँसी-दिल्लगी में अमुक प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उसके भी मन में उनका अनुकरण करने की भावना पैदा हो जाती है। श्रतः माता-पिता या शिक्षक श्रादि को इस श्रोर भी समुचित ध्यान देना चाहिए।

श्चस्तु; बात केवल बालकों की ही नहीं है। ।वड़ी उम्रवालों पर भी, वातावरण का, श्रर्थात् देश-काल का प्रभाव पड़ता है; हां, इयों-ज्यों मनुष्य श्रधिक श्रायु का होता जाता है, उस पर दूसरों का प्रभाव कम पड़ता है, पर पड़ता अवस्य है। प्रायः कोई आदमी जिस देश में तथा जिस जाति और धर्म के आदिमियों में जन्म लेता है, उस पर उस देश, जाति, या धर्म का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। जिनकी प्रतिमा, आत्म-बल या विचारशीलता विशेष है, उन पर देश-काल का प्रभाव कम पड़ता है। अन्य साधारण व्यक्ति अपने समय की सामाजिक या धार्मिक रीति-रस्मों पर स्वतंत्र विचार नहीं करते, वे उन्हें चुपचाप मानते हैं और उनके अनुसार अमल करने लगते है। कमी-कभी तो 'महान' कहे और समक्ते जानेवाले व्यक्ति भी अपने देश-काल से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। युविष्ठिर और नल जैसे राजाओं का जुए की हानियों पर विचार न करना, अथवा हानियों को जानते हुए भी इस कार्य में प्रवृत्त होना, तथा यूनान के कितने ही सुयोग्य दार्शनिकों का यह विचार कि समाज-संगठन के लिए दास-प्रथा अनिवार्य है, उपर्युक्त कथन के उदाहरण हैं।

इसके साथ ही, यह बात भी सत्य है कि जैसे हम पर दूसरों का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हम भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं; अर्थात् द्सरों पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। हाँ, यदि हमारा अग्रात्म-बल, प्रतिभा आदि विशेष है तो हमारा प्रभाव अधिक होगा; नहीं तो कम। साधारण व्यक्तियों का प्रभाव अपने बहुत निकट के व्यक्तियों पर ही पड़ता है, और विशेष गुण-सम्पन्न महानुभावों का, दूर-दूर के व्यक्तियों पर भी। भृत काल में गौतम बुद्ध, अशोक, हन्नरत ईसा मसीह और मोहम्मद साहब ने दूर-दूर की जनता पर अपने विचारों की छाप लगा दी। आधुनिक काल में लेनिन, हिटलर,

स्टेलिन श्रादि के सैनिक बल ने ही नहीं, इनकी विचार-घारा ने भी किस देश के व्यक्तियों पर श्रपना विलक्षण प्रभाव नहीं डाला ? भारतवर्ष की ही बात लीजिए। महात्मा गाँघी ने बिना प्रत्यक्ष प्रयत्न किये अपना प्रभाव योरप, श्रमरीका, अफरीका आदि सभी भू-खंडों के व्यक्तियों पर डाल रखा है। श्रमंख्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने महात्मा जी को कभी देखा नहीं, श्रौर सम्भवतः कभी देख भी न पावेंगे, तथापि वे श्रपने जीवन में कितने ही कार्य महात्मा जी के आदेशानुसार कर रहे हैं। अवश्य ही ऐसे महापुरुष किसी समय में इने-गिने ही होते हैं, जो वातावरण को विशेष रूप से बदल देते हैं, और उसे एक श्रंश तक श्रपनी इच्छानुरूप बना डालते हैं।

स्मरण रहे कि प्रायः निकटवर्ती वातावरण का प्रभाव अपेदाकृत श्रिक होता है, श्रोर जैसे-जैसे वातावरण दूर का होता जाता है, उसका प्रभाव कम होता जाता है। तथापि हम पर अपने नगर या राज्य का ही नहीं, दूर-दूर की जनता के धार्मिक, समाजिक, नैतिक, श्रोर सांस्कृतिक विचारों का भो प्रभाव पड़ता है। हमारे मकान बनाने श्रोर नगर बसाने का दङ्ग, वेष-भूषा श्रोर खान-पान का स्वरूप कितना पाश्चात्य लोगों के दङ्ग से प्रभावित हुश्चा है, हमारी भाषा पर तथा हमारे साहित्य में अन्य देशों की भाषा श्रोर साहित्य की कितनी छाप है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। हमारी राजनीति ने श्राज दिन प्रायः ब्रिटिश राजनीति का चोला पहन रखा है। निर्वाचन पद्धित, व्यवस्थापक सभाश्रों का संगठन और कार्य-पद्धित, सरकार श्रीर जनता के सम्बन्ध श्रादि के विषय में हम

जो विचार करते हैं. उसमें प्रायः इंगलैंड की नीति हमारे लिए 'माडल' या नमूने का काम देती है। अर्थ-नीति में यहाँ के बहुत-से सुधारक रूस के समाजवादी कार्य-क्रम से प्रभावित हैं। युद्ध-नीति में इम योरप की नीति को व्यावहारिक मानते हैं; महात्मा गांधी की अहिन्सात्मक नीति पर विश्वास न कर उसे अव्यावहारिक कहते हैं।

### नैतिक वातावरण का प्रभाव

इस प्रकार हमें मालूम होता है कि नागरिक जीवन पर वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम इस बात का कुछ विशेष विचार करें कि नैतिक वातावरण का नागरिक जीवन पर किस प्रकार तथा क्या प्रभाव पड़ता है। नागरिक जीवन के अनेक पहलू हैं, और स्थानाभाव के कारण उसके सब पहलुओं की दृष्टि से विचार नहीं किया जा सकता। यहाँ संचेप में यही विचार किया जायगा कि नैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन और न्याय पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले व्यवस्था की बात लीजिए।

व्यवस्था का मूल निर्वाचन है। यदि नागरिकों का नैतिक मान (स्टैंडर्ड) ठीक है तो कोई निर्वाचक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किसी अयोग्य उम्मेदवार के पक्ष में मत नहीं देगा, वह खूब सोच-विचार कर अपने मत का उपयोग करेगा, वह किसी की बेजा धमकी में नहीं आयेगा, और न किसी प्रलोभन के कारण पथ-अष्ट होगा। किसी व्यक्ति की यह हिम्मत ही नहीं होगी कि निर्वाचक से यह कहे कि अमुक उम्मेदवार तो तुम्हारी जाति-विरादरी का है, श्रतः उसे वोट (मत) दिया जाना चाहिए; या, देखो श्रमुक उम्मेद-वार ने उस समय तुम्हारे विरुद्ध काम किया था, उसे मत नहीं देना चाहिए, यदि तुम उस मत दोगे तो तुम्हें इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा; श्रथवा तुम श्रमुक उम्मेदवार के लिए मत देने की ऋषा करो तो उसके प्रतिफल-स्वरूग तुम्हें यह पुरुकार मिलेगा। इस प्रकार नैतिक वातावरण ठीक होने की दशा में निर्वाचन-कार्य श्राधुनिक विकारों से मुक्त रहेगा, व्यवस्थापक समाश्रों में योग्य श्रीर विचारशील व्यक्ति ही पहुँचेंगे। श्रीर, ये भी वहाँ श्रपना कर्तव्य-पालन मली भाँति करेंगे, श्रालस्य या प्रमादवश उसकी श्रवहेलना न करेंगे, श्रपनी हिष्ट उदार रखेंगे, नियम या क्रानून बनाते समय अपने सम्प्रदाय या जाति का ही विचार न करेंगे, वरन राज्य के हित की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार देश में क्रानून-निर्माण का कार्य सुदृढ़ श्राधार पर किया जायगा, वह प्रत्येक बात में कल्याणकारी होगा।

अब शासन की बात लोजिए। राज्य-हित के लिए अच्छे कानून बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। उन कानूनों को अमल में लानेवाले अर्थात् शासक भी अच्छे होने चाहिएँ। राज्य में छोटे से लेकर बड़े तक अनेक कर्मचारी रहते हैं। बहुधा पदाधिकार पाकर आदमी कुछ उन्मत्त-से हो जाते हैं। वे अपने कर्तन्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। वे सर्वसाधारण पर रौब गाँठते हैं, बहुधा उनसे डाली, भेंट या रिश्वत आदि के रूप में अनुचित रीति से द्रव्य एंठते हैं, किसी नागरिक का कोई काम करने से उस पर बड़ा श्रहसान जताते हैं। योड़ी देर में हो सक्नेवाले काम को डील-डाल से करके उसमें

स्तृब समय लगा देते हैं, श्रीर इस प्रकार नागरिकों को काफ़ी परेशान करते हैं। बेचारे नागरिक चुपचाप श्रिषकारी-वर्ग की यह श्रानीति देखते श्रीर सहते रहते हैं। परन्तु यदि राज्य में नैतिक वातावरस श्रान्ता हो, तो कर्मचारी-वर्ग की यह श्रानीति कदापि न चले।

श्रव रही, न्याय की बात । साधारणतया, नैतिक वातावरण ठीकः न होने की दशा में न्याय के प्रसंग में अनेक बातें अन्याय-मुलक हो जाती हैं। श्रदालत में भूठ बोलना एक मामूली बात हो जाती है। अनेक आदमी शपय लेकर बयान देते हैं. तो भी असत्य-भाषण करते हैं। छोटे-मोटे लालच के वश ही बहत-से व्यक्ति चाहे-जैसी गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। साधारण वकील गवाहों को पाठ पढ़ाते हैं कि अमक बात इस तरह से कही जायगी तो मुकहमा जीतने में सहा-यता मिलेगी। जो वकील बैरिस्टर श्रादि बड़े होते हैं, वे स्वयं ऐसा काम नहीं करते. पर उनके सहायक तो उनके लिए यह सब कर ही देते हैं। अनेक अच्छे-अच्छे वकीलों का भी यह सिद्धान्त रहता है कि बात सची होनी चाहिए, फिर उसे अदालत में साबित करने के लिए चाहे-जितनी भूदी कार्रवाई की जाय। फिर, कुछ श्रादमी न्याय की कुर्सी पर बैठ कर भी श्रन्याय करते हुए मिलते हैं, केवल भूल-वश नहीं, लोम-वश, श्रथवा सरकार का रुख देख कर। ऐसी बातें उसी दशा में सम्भव है, जब राज्य में लोगों का नैतिक मान या श्रादर्श निम्न कोटि का हो। जब नैतिक वातावरण शुद्ध होता है, तो उपर्युक्त दोषों की गुंजायश नहीं रहती। न गवाह भुठ बोलता है, न वकील उसे भूठ बोलने को प्रेरखा करता है; न्यायाधीश भी निष्पक्ष निर्णय सुनाकर

#### अपना पद सार्थक करता है।

इससे विदित हुआ कि नैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन और न्याय पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इस बात का विचार किया जा सकता है कि उसका नागरिक जीवन के अन्य अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अस्तु अब हम धार्मिक वातावरण के प्रभाव का विचार करेंगे।

## धार्मिक वातावरण का प्रभाव

प्रत्येक धर्म या मज़हब में दया, सहानुभृति, परोपकार, आदि की शिचा का समावेश होता है, यदि नागरिक उन पर भली भांति विचार करें तो सार्वजनिक जीवन की अनेक वाधाएँ दूर होकर विविध प्रकार की सुविधाएँ होने लगें। परन्तु बहुधा होता यह है कि आदमी धर्म का बड़ा संकीर्ण अर्थ लेते हैं, वे उसे अपने स्वार्थ का साधन बना लेते हैं। इससे राज्य की उन्नति या प्रगति में बहुत रुकावटें पैदा हो जाती हैं। व्यवस्था का ही विचार करें। जब धार्मिक वातावरण अच्छा नहीं होता, आदमी अपने-अपने सम्प्रदाय के ही हित की बात सोचा करते हैं; वे राज्य के सामुहिक हित की उपेक्षा करते हैं। निर्वाचन के प्रसंग पर उम्मेदवारों की योग्यता का विचार न कर, मतदाताओं से धर्म के नाम पर अपील की जाती है कि वे अमुक उम्मेदवार को मत दें, अथवा अमुक को न दें। वास्तव में निर्वाचन जैसे राजनैतिक विषय में धर्म की हिन्द से विचार करना नितान्त अनुचित है। इसी प्रकार व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के दल साम्प्रदायिक आधार पर बनाना, और क़ानून बनाने में साम्प्रदायिक हित की हिन्द रखना नागरिक जीवन को कल्लावत

करना है। यदि व्यवस्थापक सभा में, भिद्धकों पर नियंत्रण करने, या दान धर्म को नियमित कराने आदि के विषय में, आदमी नागरिकता का विचार न कर अपनी 'धार्मिकता' का प्रदर्शन करने लगें तो आवश्यक कानून किस प्रकार बनें!

कुछ समय की बात है, बृन्दाबन में बन्दरों का बड़ा उत्पात था। श्रादिमयों का कोई चीज़ लेकर बाजार में से निकलना किंदन था। अनेक बार ऐसा हुआ कि आदमी जा रहा है; पीछे से बन्दर त्रा कर उसकी टोपी उतार कर ले गया। श्रब श्रादमी हाय में सामान लिये टोपी के वास्ते बन्दर का कहाँ तक पीछा करे ! श्राखिर, वह उससे हाथ घोकर ही रहता। बालकों या स्त्रियों को तो बहत ही कष्ट होता था, कई बार किसी बच्चे को बन्दर ने छत की मंडिर पर से घका दे दिया श्रीर बच्चे की मृत्यु हो गयी। यह देख कर म्युनिधिपैलटी में बन्दर पकड्वाने का प्रस्ताव श्राया, तो बहुत-से नागरिकों ने उसका विरोध किया। यह विरोध केवल बन्दरों पर दया-भाव रखने के कारण ही न था। बात यह थी कि कुछ श्रादमियों को बन्दरों को चने डालने के लिए खासी रक्तम मिलती थी। उसमें से कुछ तो बन्दरों के लिए खर्च होती और शेष उन लोगों के काम श्राती। इन लोगों ने देखा कि यदि बृन्दावन में बन्दर न रहे तो फिर इन्हें बन्दरों के नाम पर रुपया मिलना भी बन्द हो जायगा। इस प्रकार इन्होंने अपने स्वार्थ को लच में रख कर और घर्म का भाव जता कर बन्दरों के पकड़े जाने के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया, परन्तु आखिर बात प्रगट हो गयी और इनकी विशेष न चली। म्युनिसिपल बोर्ड में

प्रस्ताव पास हो गया। कहने का तात्पर्य यह कि आदमी धर्म की आड़ में स्वार्थ-सिद्धि का प्रयत्न करते हैं, यह बड़े शोक का विषय है। यह सर्वथा त्याच्य है। धार्मिक मावनाएँ नागरिकों के लिए उपयोगी कानून बनाये जाने में वाधक न होनी चाहिएँ।

श्रव शासन-सम्बन्धी चेत्र का विचार करें। धार्मिक प्रभाव इस चेत्र में कितना पडता है. इसका थोड़ा-बहुत अनुभव सभी राज्यों के निवा-सियों को समय समय पर विशेष रूप से होता रहा है। योरप के देशों में मध्य-काल में, जनता के लिए बहुवा विचारशीय विषय यह नहीं होता था कि राजा किस योग्यतावाला हो। वरन वे सोचा करते ये कि राजा इमारे धर्म को माननेवाला हो तभी इम सुल की नींद सो सर्केंगे। -रोमन केथलिक ईसाइयों के लिए किसी प्रोटेस्टैन्ट ईसाई का राज-वद ग्रहण करना एक महामारी से कम नहीं होता था। अनेक बार एक धर्म के मानने वालों के त्यौहार दूसरे लोगों के लिए रोने और कराइने के दिन हुए हैं। अब योरप उस अन्वकार-काल से मुक्त हो गया है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष इस समय भी साम्प्रदायिक भागड़ों का देश बना हुआ है। शासकों की कितनी शक्ति इससे नष्ट होती है! विजयदशमी या दिवाली हो, ईद हो या मोहर्रम, अथवा अन्य कोई न्यौहार हो: अधिकारियों को नागरिक शान्ति के लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। अनेक बार तो रोजमर्रा की साधारस बातों से ही हिंदू--मुस्लिम भगड़े का सूत्रपात हो जाता है। जिन शहरों में इन दोनों जातियों के काफ़ी श्रादमी रहते हैं, वहाँ का नागरिक जीवन हर समय -ख़तरे में रहता है; न-मालूम, किस घड़ी क्या उत्पात हो जाय। कई बार

ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने दूसरे के पीछे जाकर अकरमात छुरा मौंक दिया, और उसे मार दिया या अधमरा कर दिया। हमला करने-वाले को ज़ख्मी आदमी के विरुद्ध कोई शिकायत न थी; वह केवल यह जानता था कि वह दूसरी जाति या दूसरे धर्म का है। जिस व्यक्तिः ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, जिसके प्रति हमें कुछ शिकायत नहीं, उसके साथ यह दुर्व्यवहार कैसा चिन्तनीय या निन्दनीय है! इससे भी अधिक दुःल का विषय यह है कि आक्रमणकारी व्यक्ति की जाति या धर्मः वाले अन्य कितने-ही नागरिक ऐसे अनुचित कार्य की स्पष्ट शब्दों में निन्दा नहीं करते, वरन जहां तक सम्भव होता है, वे अपराधी से सहा-गुभृति ही प्रकट करते हैं, और उसे क़ानूनी-दंड से बचाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार यह मामला दो व्यक्तियों का न रह कर दो जातियों का हो जाता है। दोनों जातियों का पारस्परिक दुर्भाव अनेक रूपों में समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इस लिए पुलिस की शिक्त बढ़ायी जाती है, और साथ ही दमनकारी क़ानूनों का प्रयोगः बढ़ता है, जिससे सभी को असुविधा या कष्ट होता है।

यह स्थिति श्रंगरेज श्रिष्ठकारियों के लिए भारतवर्ष को स्वराज्या-षिकार न देने का बहुत बिद्ध्या बहाना है। विचारशील नागरिकों के बास्ते यह बात बहुत चिन्तनीय है। श्रावश्यकता है कि नागरिक बन्धु धर्म का ठीक श्रर्थ समर्फें। यदि धर्म एक दूसरे का सिर फोड़ना सिखाता है, तो उसे 'धर्म' कहना निरर्थक है। वह तो श्रध्म है। कोई व्यक्ति श्रपने श्रापको सच्चा हिन्दू या सच्चा मुसलमान कैसे कह, सकता है, जब वह श्रपने नागरिक बन्धुओं से प्रेम श्रीर सहानुभृति का व्यवहाइ नहीं करता । यदि हम धर्म का ठीक अर्थ ग्रहण करें तो हम दूसरों के दुख दूर करना, उनकी शान्ति और समृद्धि में आनन्द मानना ही अपना कर्तव्य समर्कें। सरकार जो कार्य नागरिक जीवन की उन्निति के लिए करे, उसमें हम जी खोल कर सहयोग प्रदान करे; और यदि किसी सरकारी कर्मचारी का व्यवहार समाज के किसी वर्ग के लिए अहितकर हो तो सब मिलकर उसका विरोध करें। प्रत्येक धर्म एक परमिता परमेश्वर को मानता है, तो समस्त धर्मों के अनुयायियों में आतृ-भाव होना ही चाहिए। ऐसा होने की दशा में हम अपने राज्य के शासन को कितना उत्तम बना सकते हैं!

व्यवस्था और शासन की भाँति न्याय-कार्य पर भी घर्म का बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तविक धर्मानुयायी के विचार तो सदैव न्याय-मूलक ही होते हैं। प्रत्येक देश में सयय-समय पर ऐसे अनेक उदाहह एा हुए हैं, जब किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य करनेवाले को उस अवस्था में भी दंड दिया या दिलवाया, जब कि अपराधी स्वयं उसका भाई, पुत्र या अन्य रिश्तेदार आदि था। परन्तु धर्म की मिथ्या भावना रखनेवालों की तो बात ही दूसरी है। वे न्याय को उसी दशा में न्याय सममति हैं, जब उससे उनके सम्प्रदायवालों का हित हो, जब वह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायिक भगड़ों के सम्बन्ध में ऐसा अनुभव हुआ। है कि मुक्रदमा अदालत में गया, पर जिस पक्ष के विरुद्ध फैसला हुआ, उसका उस फैसले से सन्तोष न हुआ, उसने उसकी अपील की, और वहाँ भी मन-चाहा फैसला न हुआ तो उस अपील की भी अपील हुई। फिर यदि ऊँची-से-ऊँची अदालत ने भी वही फैसला बहाल

रखा तो उस फैसले की अवहेलना की गयी। कभी-कभी तो न्याया-धीशों को धमकी दी जाती है कि यदि वे अमुक पक्ष में फैसला न देंगे तो उनके लिए अच्छा न होगा। ऐसे उदाहरणों का भी अभाव नहीं है कि किसी न्यायाधीश पर धातक प्रहार इसलिए कियागया कि उसने लोगों की सम्प्रदायिक भावनाओं का बिल्कुल विचार न कर निर्भीकता-पूर्वक अपना निष्पक्ष निर्णय दिया। नागरिकों की सम्प्रदा-यिक भावनाओं का ऐसा कलुषित हो जाना कि उनकी न्याय-बुद्धि का इस प्रकार लोप हो जाय, बहुत दुखदायी है। आवश्यकता है कि हमारी धार्मिक भावना हमें अधिक-से-अधिक न्याय-प्रेमी बनाने में सहायक हो। वह धर्म ही क्या जो मनुष्यों में न्याय आदि सद्गुणों की वृद्धि करनेवाला न हो! धर्म तो मनुष्यों में मनुष्यत्व और नागरिकों में नाग-रिकता बढ़ानेवाला ही होता है। इसलिए लोगों पर धर्म एवं नीति का ऐसा ही प्रभाव पढ़ना चाहिए, जो उनके नागरिक जीवन का यथेष्ट विकास करने में सहायक हो।

# दूसरा भाग भारतीय नागरिकता

# ञ्रब्बीसवाँ परिच्छेद हमारा देश

उसकी सेवा-पूजा करना चाहते हैं। इम उसकी उजति के अभिलाधी हैं। उसकी दीन-हीन दशा हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। इम उसकी राजनैतिक उत्थान-करना आवश्यक समसते हैं तो हमें चाहिए कि इम इस देश की परिस्थिति का सम्यक् अध्ययन करें, उसे मली मौति सोर्चे-विचारें। हमें यह भी जानना चाहिए कि इस समय भिजनीन चेत्रों में क्या-क्या समस्याएँ विद्यमान हैं, उन्हें हल करने के लिए गत वर्षों में क्या-क्या आन्दोलन हुआ है। यह आन प्राप्त करने पर इम देश सेवा या देशोन्नति करने के लिए अधिक योग्य होंगे। अन्यया, 'नादान की दोस्ती, जी का जंजाल' साबित होगी। कोरी भावकता, जान के सहयोग से वंचित रहने पर, लाम के बदले हानि करनेवाली होती है। माता की, अपनी सन्तान के प्रति कितनी समता होती है,

28

वह उसके मुख की कितनी इच्छुक होती है, यह सब जानते हैं। पर अपनेक दशाओं में माता के अज्ञानमय अनुचित लाड़-प्यार से सन्तान का कितना अहित हो जाता है, यह भी कोई रहस्य नहीं है। अस्तु, प्रत्येक भारतीय पाठक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी जन्म-भूमि सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों से सुपरिचित होने का प्रयत्न करे। अगले पृष्ठों में हम इस देश की भौगोलिक, सामा- जिक, आर्थिक, सांकृतिक और राजनैतिक परिस्थित का विचार करते हैं। आशा है, इसके अध्ययन और मनन से भारतीय नागरिक इस देश के प्रति अपना कर्तव्य अच्छी तरह पालन कर सकेंगे, और वे सुयोग्य नागरिक कहे जाने के अधिकारी होंगे।

इस पुस्तक के प्रथम भाग में यह बताया जा चुका है कि मनुष्या के सामाजिक जीवन, रहन-सहन, भोजन, व्यवहार आदि पर उसके निवास-स्थान की भौगोलिक स्थिति का, जलवायु, और वर्षा आदि का बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः भारतीय जनता सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व हस देश की प्राकृतिक स्थिति का जान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए पहले इसी के सम्बन्ध में लिखा जाता है।

भौगोलिक स्थिति—भारतवर्ष एक विशाल भू-खरड है। इसक अधिक-से-अधिक लम्बाई और चौड़ाई लगभग दो-दो इजार मील है, और इसका चेत्रफल सोलह लाख वर्ग मील है। इसके उत्तर में पर्वत-शिरोमिश हिमालय की कँची, वर्फ से ढकी, दीवार है; शेष तीन और यह समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका तट लगभग तीन हज़ार मील है। भिन्न-भिन्न प्रकार की जल-वायु, तरह-तरह की मूमि, विचिन्न-विचिन्न दृश्य श्रीर मांति-भांति की पैदावार देकर मानों प्रकृति ने इसे जगत् की प्रदर्शनी बनाया है। मानवी श्रावश्यकताश्रों को पूरा करनेवाली मुख्य मुख्य वस्तुश्रों में से ऐसी कोई नहीं, जो यहाँ पैदा न हो सकती हो। कञ्चे पदार्थों का भगड़ार होने से इसे श्रीचोगिक पदार्थों के निर्माण के लिए विशेष सुविधा प्राप्त है। पूर्वीय गोलार्द्र का केन्द्र होने से इसकी स्थित एशिया, योरप श्रीर समरीका से व्यापार करने के श्राकृल है। भीतरी श्रामदरफ़ की हिष्ट से दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की स्थित कञ्छी है, कारण, यहाँ पर एक तो ऐसी नदियां हैं, जिनमें नाव श्रञ्छी तरह जा-श्रा सकतो है, दूसरे यहाँ भूमि समतल है। सड़कें श्रीर रेलें बनाने में बहुत सुविधा रहती है, जबिक दिख्या में पहाड़ों के, या पथरीली मूमि के, होने से इसमें बड़ी कठिनाई होती है।

पाकृतिक भाग—मारतवर्ष प्राकृतिक दृष्टि से चार भागों में विभक्त है:—

- (१) उत्तरी पहाड़ी भाग,
- (२) सिन्ध गंगा का मैदान,
- (३) दिच्या भारत, श्रौर
- (४) समुद्र तर।

उत्तरी पहाड़ी भाग में हिमालय १५०० मील बल खाता हुआ चला गया है। इस भाग की अधिक-से-अधिक चौड़ाई २०० मील है। हिमालय बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा उत्तरी भारत को हरा-भरा रखता है। इसके पश्चिमी भाग का जल विविध निदयों में बह कर सिन्ध में, तथा पूर्वीय भाग का गंगा में जा मिलता है। यहाँ तरह-तरह की लकड़ियां तथा बनौष्षियां पैदा होती हैं!

सिंध-गंगा का मैदान हिमालय से निकली हुई नदियों की घाटियों से बना हुआ है, और हिमालय की पश्चिमी शाखाओं से पूर्वीय शाखाओं तक फैला हुआ है। इसका चेत्रफल तीन लाख वर्गमील से अधिक है। सारा उत्तरीय भारत इसमें शामिल है। पश्चिमी रेतीले भाग को छोड़ कर यह बहुत उपजाऊ, व्यापार के अनुकूल और घनी आबादीवाला है। सिंध और गंगा से इसकी सिंचाई अञ्छी तरह हो गती है।

दक्षिण भारत सिंध-गंगा के मैदान के दक्षिण में पहाड़ों से घिरा हुआ तिकोना पठार (ऊंचा मैदान) है। इसमें छोटे-छोटे पेड़ और भाड़ियां अधिक है। जहाँ पानी बहुत है, या निकट है, वहाँ बड़े-बड़े बुक्षों के जंगल भी हैं। पत्थरों से बनी हुई मिट्टी काले रंग की है। इस पर आना जाना कठिन है, सड़कें और रेलें भी कठिनाई से बनती हैं। इस पठार की ऊँचाई १२०० से ३००० फुट तक है।

दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम में सकरे (कम चौड़े) समुद्र-तट का मैदान है। इसका बहुत-सा भाग समुद्र-जल से ढका हुआ है। यहां समुद्र अधिक-से-अधिक २०० गज गहरा है। पश्चिमी और पूर्वीय समुद्र-तट की चौड़ाई क्रमशः २० से ६० मील और ५० से १०० मील तक है। इन समुद्र-तटों में नारियल आदि की पैदावार अच्छी होती है।

जल-वायु—भारतवर्ष का दिख्यी भाग भू-मध्य रेखा के पास ( उत्तर में ) है, परन्तु तीन श्रोर समुद्र से घरा होने के कारण यहाँ गर्मी का प्रभाव बहुत श्रविक नहीं होता । स्थल का घरातल समुद्र से कहीं तो बहुत ऊँचा है, और कहीं कम, इससे देश के भिन्न-भिन्न भागों में एक ही तरह का जल-वायु नहीं है । प्रायः दिख्या में गर्मी, श्रोर उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सदीं, रहती है, बीच में तरह-तरह की जल-वायु मिलती है । मध्य-मारत और राजपूताना समुद्र से दूर और शुष्क हैं, इसलिए ये प्रायः जाड़े में ठंडे श्रीर गर्मियों में बहुत उष्ण रहते हैं ।

यहाँ अपेचाकृत योड़ा ही परिश्रम करने से मनुष्य के निर्वाह-योग्य सामग्री प्राप्त हो सकती है। गर्म भागों में बस्तों की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वहाँ साधारसत्या आदमी वर्ष का अधिकाँश समय लंगोट लगा कर, या अंगोल्ला लपेटे बिता सकता है। भोजन भी, ठंडे भागों की अपेक्षा कम ही चाहिए। बड़े मकान की भी बहुत ज़रूरत नहीं होती। गर्म देश में मनुष्य जलदी यक जाते हैं, और बहुधा उनके आरामतलब, रोगी, व्यसनी, दुर्वल या अल्गायु होने की प्रवृत्ति रहती है।

वर्षा — वर्ष के सम्बन्ध में यहाँ यह विशेषता है कि साल में दो मौसमी हवाएँ निश्चित हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पहाड़ आदि के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, अप्रेल से सितम्बर तक दक्षिण-पश्चिम (समुद्र) की आरे से, और अक्तूबर से मार्च तक उत्तर-पूर्व अर्थात् स्थल की आरे से हवा चलती है। इनमें से पहली हवा से ही वर्षा विशेष होती है। साधारण्वया पश्चिमी तट, गंगा के डेल्टा, आसाम और सुरमाघाटो में वर्षा बहुत अधिक, और गंगा की घाटो में इलाहाबाद तक तथा पूर्वी तट पर अच्छी होती है। दक्षिण में तथा मध्य भारत के पठार में खुशकी रहती है, और अरवली के पश्चिम में, तथा सिन्ध, राजपूताना और विलोचिस्तान में तो बहुत ही खुशकी होती है।

भारतीय जनता अधिकतर कृषि-प्रधान है, और वह बारिश का बहुत आसरा ताका करती है। जिन भागों में वर्षा अञ्छी होती है, और लोगों को खाने को अपेक्षाकृत अधिक मिलता है, वहाँ आबादी आयः धनी होती है।

निद्याँ—भारतवर्ष में पंजाब की पाँचों नदी उस प्रान्त के अधिकाँश माग को इरा-भरा रखती है। उनके द्वारा इस प्रान्त का माल सिन्ध तक आ सकता है। गंगा, यसुना, ब्रह्मपुत्र, और गोदावरी तथा इनकी शाखाओं से पूर्वी भारत सींचा जाता है। गंगा में एक हज़ार और ब्रह्मपुत्र तथा सिन्धु में आठ-आठ सौ मील तक बड़ी नाव या छोटे जहाज़ आ जा सकते हैं। गंगा १५०० मील और सिन्धु १८०० मील लम्बी है। दक्षिण भारत में नदियाँ छोटी है, और माल ढोने या सिंचाई करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है।

जंगल् - भारतवर्ष में पश्चिमी घाट, आसाम श्रीर हिमालय प्रदेश में घने जंगल बहुत हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के भी काम आती हैं। पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्य-प्रान्त श्रीर मध्य भारत के जंगलों में श्रीर हिमालय की तलहटी में साल के पेड़ होते हैं। माला-बार में सागीन श्रीर आबगूस के वृक्ष अधिक होते हैं, हसकी लकड़ी कड़ी, ठोस और बहुत टिकाऊ होती है। मैसूर के जंगलों का चन्दन और श्राबनूस प्रसिद्ध हैं। नारियल के वृक्ष समुद्र के किनारे ही अधिक होते हैं। श्रनजास और केले गर्मतर जल-वायुवाले भागों में पाये जाते हैं। हिमालय के मुख्य फल सेव, नास्त्राती और अखरोट हैं। सिंघ और गङ्का के मैदान का, तथा दिख्या का, मुख्य फन श्राम है।

कृषि-योग्य भूमि—यहाँ के मिन्न-भिन्न मागों की जल-वायु.
उच्याता तथा तरी आदि विविध प्रकार की होने से यहाँ सब प्रकार
के खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अनों में यहाँ चावल, गेहूँ, चना,
क्वार, बाजरा, जौ, मकई आदि मुख्य हैं। दानों में मूँग, उरद,
अरहर, मटर, मस्र आदि पैदा होती हैं। तेलहन में तिल, सरसों,
अल्सी आदि प्रधान हैं। अन्य खाद्य-पदार्थों में गन्ना विविध फन्न,
सब्ज़ी, मसाले, और मेवा आदि होती है। शेष पदार्थों की पैदावार में कपास, सन (जूट), नील, अफ़ीम, चाय, कहवा, तमाख़्
और पशुओं का चारा उल्लेखनीय हैं। कृषि-जन्य पदार्थों की मात्रा
की दृष्टि से मारतवर्ष का संसार में तीसरा नम्बर है। सब देशों की
सन की मौग यही पूरा करता है; और गेहूँ, कपास, चावल आदि
की पैदावार में भी इसका अच्छा स्थान है।

खानें — प्राचीन समय से यह देश खनिज पदायों के लिए प्रसिद्ध -रहा है, इसे रत्न-गर्मा भूमि कहा गया है। लोहा यहाँ काफी मात्रा में मिलता है। बंगाल बिहार लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कोयले की खानों के निकट ही होने से विशेष उपयोगी हैं। मध्य-प्रान्त, मैसूर और मदरास से भी लोहा खासे परिमाख में मिलता है।

कोयला यहाँ विशेषतया बंगाल तथा बिहार में मिलता है; कुल कोयले का आधा माग भरिया से, और एक-तिहाई रानीगंज से, आता है। पंजाब, मध्य-प्रान्त, मध्य-भारत, आधाम, हैदराबाद और बिलो-चिस्तान में भी कुछ खानें हैं। मैंगनीज़ की खानें मध्य-प्रान्त और मदरास में हैं, यह धातु इस्पात बनाने के काम आती है। नमक की खान मेलम के किनारे से सिंघ के पार कुछ दूर तक चली गयी हैं। सांभर की भील में, तथा समुद्र-तट पर खारी पानी से भी नमक बनाया जाता है। शोरा प्रायः उत्तरी बिहार में मिलता है। सोने की खानें मैसूर में हैं। अभ्रक की खानें अजमेर, मदरास और बिहार में हैं; संसर-मर के खर्च के लिए आधे से अधिक अभ्रक भारत से ही जाता है।

पाकृतिक शक्ति—भारतवर्ष प्राकृतिक शक्तियों का अतुल भंडार है। यहां पर्वत-शिरोमिण हिमालय तथा अन्य बड़े-बड़े और कँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, जिनमें अनेक जल-प्रपात हैं। बड़ी-बड़ी निदयों की भी यहां कमी नहीं। समुद्र तो इस देश को तीन ओर से धेरे हुए है। इस प्रकार यहां जल-शक्ति खूब विद्यमान है, जिसका बिजली बनाने में उपयोग हो सकता है, और कुछ अंश में हो भी रहा है। भारतवर्ष में बायु-शक्ति भी प्रयाप्त है; हां, उससे काम लेना बहुत लाभदायक नहीं होता। भारतवर्ष का बहुत-सा भाग उष्ण किंदबन्ध में होने से यहां सूर्य के प्रकाश (धूप) की शक्ति भी अनन्त है, परन्तु उसका अभी संचालन-शक्ति के रूप में प्राय: कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। जिदान, शाकृतिक या मौगोलिक शक्ति के विचार से भारत-माता को

स्वर्ण-मूर्मि, रत्न-गर्भा, या अनन्त-शक्ति-श्रोत कहना वास्तव में सार्थक है। इसकी सन्तान सुखी और संतुष्ट नहीं है तो इसका उत्तरदायित्व सन्तान पर ही है। जनता में ही कुछ न्यूनताएँ या दोष हैं। उनका विचार आगे किया जायगा।

भारतीय जनता - यदावि इस विषय में कुछ मत-मेद है. प्रायः यह माना जाता है कि भारतवर्ष में आर्य जाति के मन्ध्यों ने पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया। आरम्भ में वे बहुत समय तक पंजाब आदि में रहे। पीछे जन-संख्या बढने तथा पश्चिमीत्तर से और भी समृहों के आने से वे भारतवर्ष के भीतरी भागों में आने लगे। अब उनका यहां के कोल श्रीर द्राविडों से संघर्ष हुआ, जो क्रमशः विंध्याचल को पार करके दक्षिण में आने को बाध्य हुए। इस प्रकार भारतवर्ष में मोटे हिसाब से दो एंस्कृतियों ने स्थान पाया। उत्तर भारत प्रधानतया आर्थ एंस्कृति का रहा, और दक्षिया द्राविड संस्कृति का। पीछे पश्चिमोत्तर मार्ग से यूनानी, शक, सिथियन, हुख, यूनानी, मंगील ब्रादि जातियों के आदमी आते रहे और यहां के निवासियों में मिलते गये। कुछ लोग पूर्वोत्तर मार्ग से भी आये। परन्त उनका यहां की जनता पर विशेष प्रभाव न पड़ा। भारतीय आयों की संस्कृति इतनी ऊँची थी. कि जो भी विदेशी आये. वे क्रमशः इनमें डी हिल-मिल गये. उनका प्रथक अस्तित्व न रहा। भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों के निवासियों की शारीरिक रचना आदि की सूक्ष्म जाँच करने पर इस बात का कुछ अनुमान हो सकता है कि यहाँ के किस-किस भाग में किन-किन जातियों का मिश्रण हुआ है। यह स्पष्ट है कि यह मिश्रण जितना उत्तर भारत में हुआ, उतना दिख्ण में नहीं हुआ। विन्ध्याचल ने भारतीय जनता को प्रायः दो भागों में विभाजित करने का कार्य किया है। यद्यपि साधनों की उन्नति के कारण अब आवाग्यमन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है. अब भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के निवासियों में कुछ स्वष्ट मेद पाये जाते हैं।

भारतवर्ष में आनेवाले विदेशियों में अन्तिम वर्ग अरबों या तुकीं का, तथा योरिपयनों का है। योरिपयनों की संख्या तो अत्यल्य ही है, ये यहाँ सोलहवीं शताब्दी से आने लगे। मुसलमान यहाँ विशेषतया बारहवीं सदी में आये। उन के आने के समय यहाँ हिन्दुओं (भारतीय आयों के उत्तराधिकारियों) का रहन-सहन, विचार आदि ऐसे संरक्षणशील हो गये थे कि वे उन्हें अपने में न मिला सके। यद्यपि समय-समय पर इस दिशा में दोनों ओर से कुळ प्रयत्न हुआ, इस समय भी भारतवर्ष में दो प्रधान जातियों या धर्मों का मेद स्पष्ट है। हिन्दू अपने आपको यहाँ के ही निवासी मानते हैं, परन्तु कुळ मुसलमान अब भी आने को उनसे पृथक्, और बाहरी देशों से बहुत सम्बन्धित, समभते हैं।

भाषा—प्राचीन समय में चिरकाल तक यहाँ आर्य जाति की मुख्य भाषा प्राकृत या संस्कृत रही, अब भी संस्कृत देश-भर के हिन्दुओं की धार्मिक भाषा है, और पूजा-पाठ तथा धर्म, ज्योतिष और वैद्यक आदि प्रन्थों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। समय-समय पर यहाँ के निवासियों में अन्य जाति के आदिमियों का मिअग्र होता रहा। देश इतना बड़ा है, और प्राचीनकाल में आवागमक

के साधन कम होने से लोगों का परस्पर में सम्पर्क कम था। इस लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न प्रान्तों की भाषा में पृथक्ता आ गयी। जो प्रान्त दूसरे प्रान्त से जितना दूर था, उसकी भाषा दूसरे प्रान्त से उतनी ही भिन्न हो गयी। कहा जाता है कि भारतवर्ष में इस समय डेढ़ सौ से श्रिधिक भाषाएँ प्रचलित हैं, परन्तु यह समभ भ्रम-पूर्ण है। इसमें भाषा श्रीर बोली की श्रवश्यम्भावी विभिन्नता को भुला दिया गया है। बोलियाँ तो. थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदला ही करती हैं। शिक्षा श्रीर त्रावागमन के राघनों की न्यूनता की दशा में, प्रत्येक दस-बारह कोस के अन्तर पर रहनेवाले आदिमियों की बोली में कुछ भेद हुआ करता है। परन्त कई-एक बोलियाँ एक-ही भाषा के अन्तर्गत होती हैं। श्रस्त, भारतवर्ष में प्रचलित बोलियों की छंख्या चाहे जितनी हो, यहाँ की मुख्य भाषाएँ ऋँगुलियों पर गिनी जा सकती हैं। वे हैं —हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, श्रासामी, उड़िया, कनाडी, तथा तामिल श्रोर तेलगू। इन भाषाश्रों में से भी कई-एक संस्कृत से घनिष्ट सम्बन्ध रखती हैं श्रीर इसलिए, एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं। पुनः इनमें से हिन्दी एक ऐसी भाषा है जो विहारी, राजस्थानी, पंजाबी आदि अपनी रूपांतरित भाषात्रों श्रीर बोलियों सहित भारतवर्ष के प्रत्येक सात श्रादिमियों में से तीन की मातृ-भाषा है, जिसे वे दिन-रात बोलते हैं। तीन चौथाई से अधिक भारतवासी हिन्दी समभ सकते हैं। कुछ वर्ष पहले दिल्या में मदरास और पूर्व में आसाम प्रान्त के आदमी हिन्दी नहीं समभ सकते थे। परन्तु हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन आदि संस्थाओं के उद्योग से इन प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रचार बढ़ता जाता है। भारत-

वर्ष की राष्ट्र-सभा काँग्रेस ने हिंदी-हिन्दुस्तानी को अपने व्ववहार की भाषा माना है, हाँ; भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कुछ आदमी अपने पारस्परिकः पत्र-व्यवहार आदि के लिए अंगरेजी का उपयोग करते हैं, परन्तु इसका कारण यह भी है कि उनके मन पर आंगरेजी का बहुत संस्कार जमा हुआ है, जिसे वे सहसा नहीं छोड़ सकते।

श्रन्य भेद-भाव - जाति श्रीर भाषा के श्रातिरिक्त श्रीर भी कई विषयों में यहां बहुत विभिन्नता वायी जाती है। यहां अनेक धर्मों के-श्रन्यायी हैं, कोई किसी मत या सम्पदाय को मानता है, कोई किसी को। लोगों के रीति-रिवाज, रहन-सहत, खान-पान और वेश-भूषा में भी पर्याप्त अन्तर है। गावों में और नगरों में, ब्रिटिश भारत श्रीर देशी राज्यों में त्रार्थिक तथा राजनैतिक जीवन कुछ श्रलग-श्रलग है। इस प्रकार जब कोई विदेशी, भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में, यात्रा करता है तो उसे यहां इतनी विभिन्नताएँ मिलती हैं कि वह यह कल्पना नहीं कर सकता कि भारत एक देशा कहा जा सकता है। उसे यहा की जनता एक देश की अपेक्षा एक महाद्वीप की प्रतीत होती है। परन्तु इसका कारण उसका अज्ञान या ग्रल्पज्ञता होती है; उसकी दृष्टि केवल बाहरी बातों की श्रोर जाती है, जिसमें बहुत विभिन्नता है ही। बहुधा श्रंगरेज़ श्राधिकारी तथा उनके श्रनुयायी भी भाषा, लिपि, रीति-रिवाज़, धर्म, जाति श्रादि के श्राधार पर भारतवर्ष की अनेकता की घोषणा किया करते हैं, परन्तु इसमें सत्य कम श्रीर स्वार्थ तथा राजनैतिक प्रचार ही विशेष होता है। हां भिन्नता की खोज करनेवालों के लिए यहाँ भिन्नता की अनेक बातें

रीमल सकती हैं।

भारतवर्ष की एकता-भारतवर्ष में. बाहर से दिखायी देने-वाली भिन्नता में भीतर तात्विक एकता है। हाँ. इसके लिए केवल ऊपर-ही-ऊपर देखने से काम न चलेगा । गम्भीरता-पूर्वक गहराई तक देखने श्रीर विचारने पर मालूम होगा कि जैसे खरबूज़े में ऊपर से श्रलग-श्रलग फांक दिखायी देती हैं. परन्त भीतर सब एक ही चीज़ मिलती है, उसी प्रकार भारतवर्ष की विभिन्नता भी अधिकांश बाहरी ही है, भीतर तो एकता का विलक्षण प्रवाह है। श्रीर वाहर भी, जहाँ तक प्रकृति का सम्बन्ध है, उस ने इसे एक देश का ही स्वरूप पदान किया है। इस मुखंड के उत्तर में हिमालय की ऊँची, दुर्गम श्रीर विशाल दिवार खड़ी है. तथा इसके शेष तीन श्रोर हिन्द महा-सागर के रूप में अपार जल-राशी है। केवल पश्चिमीत्तर की श्रोर पर्वत मालाओं के बीच में से एक तंग रास्ता है। प्राचीन समय में बाहर देशों से जो आदमी यहाँ आये, वे इसी मार्ग से होकर आ सके ये। भारतवर्ष के भीतर कुछ बड़ी-बड़ी निदया तथा पहाड़िया अवश्य हैं. पर उनसे इसका विभाजन नहीं होता। अस्तु, भौगोलिक दृष्टि से इस देश के एक होने में कोई संदेह नहीं है। यह एशिया महाद्वीप में एक सर्वथा पृथक् देश हैं।

यह तो वाह्य द्रष्टि की बात है। अब तिनक भीतरी अवस्था पर विचार कीजिए। अतीत काल से यहाँ के निवासी इस भू-खंड को एक देश मानते आये हैं। पूजा-पाठ और संकल्प में हिन्दू समस्त देश को अद्धा-पूर्वक स्मरण करता है। स्नान के समय गंगा, यमुना, सरस्वती,

गोदावरी. नर्वदा. सिंधु श्रीर कावेरी इन सात नदियों के नाम भक्ति-भाव से लिये जाते हैं, जो देश के किसी विशेष भाग की न होकर समस्त देश में फैली हुई हैं। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंग, श्रीर चारों घाम श्रादि प्राचीन हिन्दुश्रों की देश-सम्बन्धी विशाल कल्पना के परिचायक हैं। बौद्धों के मठ, आश्रम, विहार, श्रीर स्तूप भी किसी एक स्थान में न होकर भारतवर्ष-भर में फैले हुए हैं. श्रीर इस देश की एकता का स्मरण करा रहे हैं। राम और कृष्ण आदि केवल उत्तर भारत में ही पूज्य नहीं हैं. उनकी कथा सर्वत्र प्रचलित है। वेद. पुराण, श्री भगवद्गीता, रामायण श्रीर महाभारत सब की समिलित सम्पत्ति है। जन्म-मरण या विवाह-शादी की रीति-रहम, होजी, दिवाली, श्रावणी और विजय-दशमी के त्यौहार सर्वत्र मनाये जाते हैं। भावों, श्रीर व्यवहारों की इस श्रद्भुत एकता से भारतवर्ष बहुत प्राचीन काल में अत्युन्नत हो गया था। यही कारण था कि यूनानी. हुए। सीयियन आदि जो जातियाँ याँ आयीं, वे अन्ततः यहाँ की ही हो गर्यो ।

इस समय यहाँ दो ही जातियाँ प्रधान हैं—आर्य और द्राविड़।
मुसलमान अधिकांश में, भारतीय आर्यों के ही वंशज हैं। बाहर से तो
बहुत थोड़े-से ही व्यक्ति आये थे, उनका भी प्राय: यहाँ के वंशजों से
रक्त सम्बन्ध हो गया। द्राविड़ों ने आर्यों की वर्णाश्रम आदि की प्रथा
स्वयं आर्यों से भी अधिक अपनाली है; और, वे अब मानों आर्य ही बन गये हैं। कुछ व्यक्ति हिन्दुओं और मुसलमानों की संस्कृति की
पृथकता पर बहुत ज़ोर दिया करते हैं। परन्तु इसमें अतिशयोक्ति है। आरम्भ में मुसलमानों का घनिष्ठ सम्बन्ध अरबी संस्कृति से था, और श्रीर हिन्दुश्रों का श्रार्थ संस्कृति से । परन्तु मुसलमानों के यहाँ श्राकर बस जाने से, श्रीर सैकड़ों वर्ष हिन्दुश्रों के साथ मिल जुल कर रहने से. इन दोनों जातियों की संस्कृतियों की एक-दूसरे पर गहरी छाप पड़ती-गयी, श्रीर दोनों संस्कृतियों के मेल से एक नयी संस्कृति बनने लगी। कबीर जैसे साधु संतों ने, और अकबर जैसे शासकों ने, इसमें अद्भुत योग दिया । किन्तु श्रंगरेजों के यहाँ आने के समय तक संयुक्त संस्कृति की जड़ नहीं जमी थी. श्रत: वह श्रंगरेज़ों की (पाश्चात्य) संस्कृति के संघर्ष को सहन न कर सकी, और हिन्दू और सुसलमान दोनों अपने पृथक-पृथक श्रादशों को खोजने लग गये। फिर, कितने ही श्रंगरेज अधिकारियों की कूट नीति से यहाँ विभिन्नता बढ़ती गयी। इस समय कभी-कभी उक्त दोनों जातियों के पारस्परिक व्यवहार में बहुत कदुता दिखायी देती है, तथापि गावों की स्थित का विचार करने से, निराशा का कोई कारण नहीं है। वहाँ हिन्दुओं के त्योहारों में मुसलमान, श्रीर मुसलमानों के त्यौहारों में हिन्दू खुशी मनाते हैं। रक्षा-बन्धन के दिन मुसलमान लड़कियाँ हिन्दुओं के वोहची बाँबती हैं। दिवाली के दिन श्रनेक मुसलमान भी अपने-अपने घरों पर रोशनी करते हैं। बालक बड़ी उम्रवालों को, चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाचा, ताऊ, बाबा श्रादि कहते हैं। इस प्रकार ग्राम-जीवन इमारी एकता का सजीव प्रमाण है। जो अन्तर दिखायी देता है, वह प्रायः नगर-निवासियों में है, जिनकी संस्था कुल भारतीय जनता की दस फी-सदी से अधिक नहीं है।

धर्म की बात लीजिए। भारतवर्ष की धार्मिक सहनशीलता तो सदैव 'प्रशंसनीय रही है। मुसलमानों के समय में भी, इने-गिने बादशाहों या उनके कुछ कहर सहधिमंथों के दुराग्रह के श्रांतिरक्त, जनता में कोई विशेष धार्मिक भगड़ा नहीं हुआ। सर्वधाधारण हिन्दू मुसलमान यहाँ उस समय तक बराबर प्रेम-पूर्वक रहे जब तक कि योरिपयनों ने यहाँ आकर शासन-सत्ता प्राप्त न की, और अपने स्वार्थ-वश उनमें फूट न डाली। अस्तु, इस समय भी दोनों धर्मवालों में हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। दोनों में मूर्ति-पूजक है और मूर्ति-विरोधी भी, भाग्यवादी हैं, और कर्मवादी भी। बंगाल और विहार के कितने- ही मुसलमान, ब्राह्मणों के द्वारा हिन्दू मंदिरों में पूजा करवाते हैं। इसी तरह अनेक हिन्दू मुसलमानों के मकवरों और ताजियों पर शीरनी चढ़ाते हैं, तथा स्वयं ताज़िये रखते और मनौतियां करते हैं।

हिन्दुओं मुसलमानों की रीति-रिवाज में भी समानता के उदाहरणों का अभाव नहीं है। 'उत्तर भारत में हर हिन्दू शादी के समय 'नौशाह' बनता है। हिन्दू की शादी बिना सेहरे और जामे के नहीं होती, और करोड़ों मुसलमानों की शादी बिना कंगने के। सेहरा और जामा मुसलमानों हैं, और कंगना हिन्दू।' पोशाक की बात यह है कि साधा-रण्तया मुसलमान जिस-जिस प्रान्त में रहते हैं, प्रायः वहाँ की ही पोशाक पहनते हैं। पोशाक से जाति-मेद की अपेक्षा प्रान्तीयता का परिचय अधिक मिलता है। और, कुछ वस्नों में प्रान्त की हिन्द से भी मेद नहीं मालूम होता। अनेक हिन्दू और मुसलमान अब ईसाइयों की भांति

टोप लगाने लगे हैं, गांधी-टोपी को तो सर्वधाधारण जनता ने अपना रखा है।

श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक दृष्टि से भी भारतवर्ष में यथेष्ट एकता पायी जाती है। कृषि, उद्योग श्रीर व्यापार श्रादि की समस्याएँ सब श्रादिमयों के लिए समान हैं। रेल, तार, डाक श्रादि से सबको बराबर लाभ है। श्रीर हाँ, हानि है तो वह भी सब को बराबर है। जनता में सम्पर्क, पत्र-व्यवहार श्रीर श्रामदरफ़्त बढ़ रही है। शिक्षा श्रीर साहित्य भी देश को एक करने में योग दे रहे हैं। श्रापरेजों के शासन में राजनीति के प्रयोग प्रायः सर्वत्र समान हो रहे हैं। स्वराज्य-प्राप्ति के ध्येय में सब एकमत हैं, चाहे मार्ग भले ही भिन्न-भिन्न हों। राष्ट्रीय श्रान्दोलन की वृद्धि हो रही है, श्रीवकाधिक राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हो रही है; श्रानेक सामाजिक श्रीर धार्मिक श्रान्दोलनों में भी राष्ट्रीय दृष्टि-कोण की श्रवहेलना नहीं की जाती।

श्रस्तु, जाति, संस्कृति, धर्म, श्रर्थ, राजनीति श्रादि विविध दृष्टियों से किये दृुए उपर्यु क विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में बहुत-कुछ एकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़ी-बहुत विभिन्नता भी श्रवश्य है, परन्तु ऐसी विभिन्नता तो सभी देशों में होती है; उसके कारण किसी देश की एकता श्रस्वीकार नहीं की जा सकती। फिर, भारतवर्ष तो एक विशाल मृखंड है, श्रतः इसकी छोटी-मोटी विभिन्नताएँ नगएय हैं। उनके कारण किसी को इस देश की एकता में संदेह करना श्रनुचित है।

## सत्ताईसवाँ परिच्छेद धर्म श्रोर धार्मिक सुधार

~ COXCUS

एक मुख्य विशेषता उसकी धर्म-प्रधान देश है। यहाँ विशेषतया हिन्दू जनता की, एक मुख्य विशेषता उसकी धर्म-प्रधानता है। सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार का कार्य हो, उसे धार्मिक हिन्द से देखा जाता है, और यदि ऐसा ही प्रतीत हो कि धर्म उसकी स्वीकृति नहीं देता, तो या तो यथा-सम्भव उसे करने का विचार ही छोड़ दिया जाता है, अथवा उसे धार्मिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया जाता है। बालक का जन्म, शिचा-प्रवेश, त्यौहार, विवाह-शादी, स्नान, भोजन, शयन, मित्रों या विरादरी को जिमाना, यात्रारम्भ, उत्सव, भवन-निर्माण, दुकान आदि खोलने या कोई संस्था त्थापित करने आदि प्रत्येक कार्य का श्रीगणेश धार्मिक भावना से किया जाता है; यहाँ तक कि किसी के मरने पर जो कृत्य किया जाता है, वह भी धार्मिक विचारों से युक्त होता है। हिन्दुओं के जीवन का मूल आधार धर्म है। कुछ अंश तक मुसलमानों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। सबेरे उठने के समय से सोते वक्त

तक, वे प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ते हैं; खाने-पाने की वस्तुओं में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि धर्म की पुस्तक (कुरान आदि) में उसकी अनुमति है, या नहीं। रुपया व्याज पर देने के आर्थिक कार्य से भी वे इसलिए परहेज़ करते हैं कि धर्म की दृष्टि से वह निषिद्ध है। अस्तु, भारतीय जीवन सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व यहां के धर्म तथा धार्मिक सुधारों का परिचय देना आवश्यक है।

भारतवर्ष के. श्रारम्भ से ही, धर्म-प्रधान होने में यहाँ की प्राकृतिक स्थिति बहुत सहायक रही है। पहले बताया जा चुका है कि यहाँ के जल-वायु के कारण मनुष्य की भोजन, वस्त्रादि की शारीरिक श्रावश्यकताएँ कम रहती हैं. फिर भिम बहुत उपजाऊ होने से उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहज ही, श्रलप परिश्रम से, थोड़े ही समय में हो सकती है। पनः उत्तर में पर्वत तथा शेष तीन श्रोर समुद्र से घरा होने के कारण यह देश विदेशियों के श्राक्रमण से भी सुरक्षित रहा । श्राकाश-मार्ग से आक्रमण होने की बात तो आधुनिक सभ्यता की है। अस्तु, निश्चिन्त श्रीर यथेष्ट अवकाश-प्राप्त होने से, अति प्राचीन काल में ही आयों ने साहित्य, कला, विज्ञान श्रादि की श्रोर विशेष ध्यान दिया। सांसारिक विषयों में लीन रहने की उन्हें आवश्यकता न थी। उन्होंने अपने समय का उपयोग पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक बातों का चिन्तन श्रीर मनन करने में किया। फिर, बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे जंगलों में रहने से उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने का यथेष्ट श्रवसर मिलता था। श्रव सूर्योदय होता है, मध्याह होता है, सूर्यास्त होता है, तारे श्रोर चन्द्रमा दिखायी पड़ते हैं, कभी श्राकाश

मेघाच्छन्न होता है, कभी बिजली चमकती है, इत्यादि हश्यों को देख कर मन में यह विचार आना स्वाभाविक ही है कि सुष्टि की ये आद्मुत् चीजें किसने बनायीं, सृष्टि का रचियता कौन है, मनुष्य और इतर प्राणियों का जन्म-दाता कौन है, मनुष्य क्यों मरता है, मर कर कहाँ जाता है और मरने के बाद क्या होता है। इस प्रकार के विचारों से, प्राचीन आयों ने पारलौकिक विषयों में खूब प्रगति की, और इन विषयों का ऐसा गम्भीर और महत्व-पूर्ण साहित्य प्रस्तुत किया कि इस समय भी संसार में उसका विशेष स्थान है, अच्छे-अच्छे दिगाज विद्रान उसे आश्चर्य और सम्मान की हिन्द से देखते तथा उसके प्रति अपनी अदाञ्जलि आर्पित करते हैं।

धार्मिक साहित्य — आर्य जाति के प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। हिन्दू इन्हें अनि मानते हैं, अन्य धर्मावलम्बी — इससे सहमत न होते हुए भी — यह तो स्वीकार करते ही हैं कि ये सृष्टि के अनि प्राचीन ग्रन्थ हैं। वेद चार हैं — ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेंद, अथवंवेद। इनमें ऋग्वेद सब से प्राचीन समभा जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत है, जो इनकी रचना के समय यहाँ बोल-चाल की भाषा थी। वैदिक संस्कृत आधुनिक संस्कृत से भिन्न, उसका पूर्वरूप है। वेद को 'श्रुति' भी कहते हैं, जिसका अर्थ है, सुना हुआ। प्राचीन काल में अधिकतर जान सुनकर ही प्राप्त किया जाता था, पढ़कर नहीं। पुस्तकों की परिपाटी बहुत पीछे, चली। वेद के तीन भाग हैं — संहिता या वेदमत्रों का समूह, ब्राह्मण-ग्रन्थ अर्थात् वेद-मंत्रों की व्याख्या, और उपनिषद् (रहस्य) अर्थात् गृढ़ ब्रह्म-विद्या और तत्वज्ञान की शिक्षा।

वैदिक साहित्य और विशेषतया उपनिषदों का, संसार की अनेक भाषाओं में, अनुवाद हो चुका है, और इनका बहुत सम्मान है।\*

भारतवर्ष का प्राचीन घार्मिक तथा दार्शनिक साहित्य अनन्त और अथाह है। हाँ, उपगु क साहित्य अधिकतर उच्च कोटि के विद्वानों के काम का है। सर्वेसाघारण की उसमें गित नहीं। सबसे लोक-प्रिय धर्म-ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता है। इसमें उपनिषदों का सार है। यह वास्तव में सागर को गागर में भरने के समान है; यों यह महाभारत नामक विशालकाय प्रन्थ का एक अंश-मात्र है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपना कर्तव्य निश्चित करते नहीं बनता था, वह इस दुविधा में था कि लड़्या न लड़्ं। अन्ततः वह अस्त्र डाल बैठा था। इस अवसर पर श्रीकृष्ण ने उसे समकाया था कि आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है, मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करने में कोई आपित्त नहीं। श्रीकृष्ण का यह उपदेश बहुत सुन्दर और मार्मिक है। संसार-भर में श्रीमद्भगवद्गीता का बड़ा मान है। हज़ारों, लाखों हिन्दू प्रति दिन इसका पाठ करते हैं, और इससे शान्ति प्राप्त करते हैं।

पुराण हिन्दुओं के प्राचीन इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ है। इनकी कुल संख्या १८ है। इनकी भाषा आलंकारिक है। इनमें राजवंशों तथा देवी-देवताओं आदि का वर्णन है। पुराणों में श्रीमद्भागवत

<sup>्</sup>रैं जमें नी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहार ने लिखा है कि उपनिषदों से सुके अपने जीवन में बहुत शान्ति मिली, और अन्त समय में भी शान्ति मिलेगी। प्रोफेसर मेक्समूलर ने भी उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।

पुराण का बहुत प्रचार है। अनेक हिन्दू ख़ास ख़ास अवसरों पर इसका नियम-पूर्वक पाठ करते हैं। पुराणों में इतिहास के आतिरिक्त धर्म, दर्शन, सृष्टि के विकास आदि का भी वर्णन है। एक प्रकार से, ये अपने दंग के विश्व-कोष हैं।

वैदिक धर्म — वेदों में बताया हुआ धर्म बहुत सरल है, उसमें आडम्बर का नाम नहीं। वह लोगों के सामने सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श उपस्थित करता है। मनुष्यों को प्रेम-पूर्वक रहना चाहिए। उनमें परस्पर सहयोग और सहानुभूति का भाव हो। वे मनसा, वाचा और कर्मणा से शुद्ध जीवन व्यतीत करें। सबको ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिए और अधिक-से-अधिक लोकहित करने का विचार रखना चाहिए। वैदिक काल में आर्य पहले सूर्य, अग्नि आदि प्राकृतिक शक्तियों का ध्यान करते थे, पीछे वे इन्हें देवता मानने लगे। इसके अतिरिक्त वे इन्द्र, वरुण और वायु आदि देवताओं की भी उपास्ता करने लगे, परन्तु वे इन सबको ईश्वर के ही भिन्न-भिन्न नाम और रूप मानते थे।

वैदिक काल में आर्थ जाति कई समूहों में विभक्त थी। प्रत्येक समूह का एक राजा होता था, जो 'समा' या 'समिति' की सलाह से काम करता था। नियम-निर्माण का कार्य विद्वान् (ऋषी-मुनि) करते थे। 'राजा नियमों के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता था। यदि वह बा कोई अन्य अधिकारी नियम भंग करता तो उसे, उसके पद की गुरुता के अनुसार, दंड दिया जाता था। राजा के लिए दिनचर्या निर्धारित थी। उसे लोक-हित का यथेष्ट ध्यान रखना होता था। वह

जनता की सुख-शान्ति श्रौर समृद्धि के लिए उत्तरदायी होता था।

वेदों में व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य, यहस्य, बानप्रस्य और संन्यास इन चार आश्रमों की, तथा समाज के लिए ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और सदूद इन चार वर्णों की व्यवस्था की गयी है। समस्त वैदिक साहित्य इसे स्वीकार करता है। पुराणों में भी उसे मान्य किया गया है। इस प्रकार हिन्दू-समाज-व्यवस्था की विशेषता वर्णाश्रम धर्म है, उसकी चर्चा आगले परिच्छेद में की जायगी। यहाँ इस बात का विचार किया जाता है कि भारतवर्ष में वैदिक धर्म के पश्चात् क्रमशः किस-किस धर्म का उदय कैसी-कैसी परिस्थित में हुआ।

बौद्ध धर्म श्रोर जैन धर्म—संसार परिवर्तनशील है। कोई
वस्तु स्थायी नहीं। वैदिक धर्म ने भारतीय जनता के द्धदय पर हज़ारों,
लाखों वर्ष शासन किया, श्रीर इस समय भी हिन्दू धर्म का प्रायः
प्रत्येक स्वरूप उसे मान्य करता है, श्रपने श्रापको उसका ही एक
मेद मानता है। तथापि ईसा के पूर्व सातवीं श्रीर छठी शताब्दी में,
उस धर्म का सर्वसाधारण में प्रचलित रूप बहुत चिन्तनीय श्रवस्था
को प्राप्त हो गया था। जाति-पौति का मेद-भाव बढ़ गया था, यज्ञों
में पशु-बिल की बहुत वृद्धि हो गई थी, शास्त्रों श्रीर धर्म की श्राड़
में भ्रष्टाचार हो रहा था। इस पर कुछ ऐसे उपदेशक चेत्र में श्राये,
जिनके ईश्वर श्रीर धर्म-सम्बन्धी विचारों में वैदिक धर्म से कुछ मिन्नता
होने लगी। इनमें मुख्य हैं, गौतमबुद्ध श्रीर महाबीर तीर्थंकर।

ं गौतमबुद्ध का मूल नाम शाक्य मुनि गौतम था। ये नैपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोदन के इकलौते

पुत्र थे। इनका जन्म ईसा-पूर्व सन् ५५७ में हुन्ना। ये बड़े लाड-दलार में पत्ने थे. श्रीर राजवी वातावरण में रहे थे। परन्तु ये थे बहुत विचारशील; सदैव दूसरों के दुखों श्रीर कष्टों की बात सोचा करते थे। श्राखिर, तीस वर्ष की श्रवस्था में इन्होंने श्रपनी प्यारी स्त्री. नवजात पत्र श्रीर सब राजमहल का ठाठ छोड़कर जंगल का रास्ता लिया। श्रीर. कई वर्ष श्रानेक प्रकार के कष्ट सहकर. तप करके इन्होंने श्रन्ततः वास्तविक सुख का मार्ग खोज निकाला । इनकी शिक्षा बहत सरल और सुबोध है। सब मनुष्य समान हैं. जाति-पाँति के विचार से कोई ऊँच-नीच नहीं। प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण या मोच प्राप्त करने का श्रिधिकारी है। हमारे जीवन में सचाई. पवित्रता श्रीर दया-भाव रहना चाहिए। भोले-भाले जीव भी हमारी दया श्रीर प्रेम के श्रिधकारी हैं। यजों में, धर्म के नाम पर भी, बिलदान करना श्रधमें ही है। सत्य और श्रदिंसा धर्म के मुख्य श्राधार हैं। इनकी बातें जनता ने बड़े चाव से सनी। इनका उपदेश लोगों के हृदय में घर करता गया। थोड़े ही समय में बौद्ध धर्म दूर-दूर तक फैल गया। सम्राट् श्रशोक श्रादि के समय में यह यहाँ राज-धर्म रहा । पीछे यहाँ इसका हास हो गया. पर श्रव भी लंका, ब्रह्मा, श्याम, नैपाल, चीन, जापान श्रादि में इसी धर्म का विशेष प्रचार है। गौतम बुद्ध के शरीर-त्याग का समय सन् ४८० ई० पू० माना जाता है।

बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक श्रौर जातक मुख्य हैं। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों तथा भगवान् बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। यह तीन भागों में विभक्त है; एक भाग में दर्शन, दूसरे में श्रानुशासन, श्रीर तीसरे में उपदेश हैं। जातक में भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ हैं।

महावीर तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे. वैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि महाबीर से पहले २३ तीर्थंकर श्रीर हो चुके हैं. उनमें सबसे प्रथम श्रीऋषभदेव जी थे। श्रस्तु, महावीर स्वामी का नाम पहले वर्धमान था। इनका जन्म ई० पू० सन् ५४७ में हुआ। ये चत्रियों की राजधानी वैसाली (पटना के उत्तर में ) के राजकुमार थे। अतः इनका प्रारम्भिक जीवन भोग-विलास श्रीर ऐश्वर्यमय था। पीछे इन्हें वैराग्य हो गया श्रीर ये मोक्ष की खोज में निकल गये। अन्तत: ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने पहले के तीर्थं करों के उपदेशों का प्रचार करने में अपनी शक्ति लगायी । जैन-धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। 'श्रहिंसा परमो घर्मः' इनका भी सिद्धान्त है। जैनी श्रहिंसा पर बहुत जोर देते हैं। वे यथा-संभव सूक्ष्म जीवों की भी हत्या करने से बचते हैं। इसलिए भोजन, स्नान श्रीर श्वास लेने तक में इस बात का विचार करके कुछ कड़े नियमों का पालन करते हैं। जैन-धर्म के अन्तर्गत दो सम्प्र-दाय हैं:-(१) दिगंबर जो नग्न मूर्ति की उपासना करते हैं, श्रीर जिनके साधु भी नग्न वेश में रहते हैं. (२) श्वेताम्बर जो अपनी मूर्तियों को कपड़े पहनाते हैं. श्रीर जिनके साधु भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जैन धर्म का विशेष प्रचार उत्तर भारत श्रीर राजपूताना में, विशेषतया वैश्यों में हुआ। इसके उपदेशक धर्म-प्रचार के लिए देश से बाहर नहीं गये । इन्होंने दर्शन श्रीर न्याय में बहुत उन्नति को । जैन

दर्शन हिन्दू दर्शन अथवा उपनिषदों से मिलता है। अहिंसा हिन्दू धर्म का आवश्यक आंग है। जैन हिन्दू संस्कृति का मान करते हैं। ये ईश्वर को मानते हैं। हाँ, उसे सर्वज्ञ और बीतराग बताते हैं, सृष्टि का जन्मदाता, पालक-पोषक और संहारक नहीं। अस्तु, कई मुख्य-मुख्य बातों के विचार से जैन-धर्म हिन्दू धर्म का ही एक रूप है, कोई पृथक् मत नहीं।

ऊपर कहा गया है जैन धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती है। दोनों धर्म अहिंसा के प्रचारक हैं, वेदों और ब्राह्मणों का आदर नहीं करते, और यज्ञों की निन्दा करते हैं। तथापि दोनों धर्मों में कुछ मेद भी है, बौद्ध केवल भगवान बुद्ध को मानते हैं, जैनी अपने तीर्थं करों को। दोनों के शास्त्र तथा धार्मिक क्रियाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं। जैनी ब्रत उपवास आदि बहुत करते हैं, बौद्ध इस प्रकार शरीर को कष्ट देने को धर्म का लक्षण नहीं मानते। बौद्धों का मूर्तियों या साधुओं का नम्र रहना भी अदिचकर है।

पौराणिक धर्म — पहले कहा जा चुका है कि जैन धर्म का प्रचार परिमित ही रहा। इसके विरुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्ष में तो हुआ ही, इस देश के बाहर भी हुआ। इस धर्म का ब्राह्मणों से मौलिक विरोध था। ब्राह्मण इसके विरुद्ध प्रचार करने का भरसक प्रयत्न करते थे। इधर गौतम बुद्ध के शरीरांत होने के थोड़े ही समय बाद उनके अनुयायियों में मत-भेद हो गया, पीछे बौद्ध संस्थाओं में अनेक विकार उत्पन्न हो गये। मठों के अधिकारियों और मिद्धुओं का जीवन दूषित और आचार-हीन हो गया। फलतः लोगों की इस धर्म

से अद्धा इटने लगी। सर्वधाघारण ईश्वर के कर्ता-धर्ना, विधाता होने में विश्वास करते और देवी-देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें इन बातों को न माननेवाला बौद्ध धर्म आकर्षक प्रतीत न हुआ। युद्ध- प्रेमी राजपूत इस आहंसा-धर्म को मान्य हो नहीं कर सकते थे। फिर, आहाणों ने जनता की रुचि के अनुसार अपने धर्म में आवश्यक परिवर्तन कर दिया। बस, सातवीं शताब्दी में पौराणिक धर्म का प्रारम्म हुआ, यद्यपि मूल बातों में यह धर्म वैदिक धर्म के अनुसार ही था, पर इसमें कई बातें पुराणों के आधार पर मिलायी गयी थीं, उदाहरणवत् अवतार-पूजा आदि। अब पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा बढ़ी, अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण हुआ, और बहुत-से ऐसे धार्मिक उत्सव किये जाने लगे, जिससे जनता आकृष्ट हो। इसके अतिरिक्त आढवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट ने, और नवीं शताब्दी में स्वामी शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ द्वारा बौद्ध धर्म का ज़ोर शोर से खंडन किया। अन्ततः चहुँ और हिन्दू धर्म की पताका फहराने जगी।

पीछे जाकर पौराणिक धर्म जनता को यथेष्ट रुचिकर न रहा। बार-हवीं शताब्दी में श्रीरामानुजाचार्य ने भक्ति का प्रचार और वैष्ण्य धर्म का प्रतिपादन किया। तेरहवीं सदी में इनके शिष्य स्वामी रामानन्द ने राम की उपासना का प्रचार करते हुए वैष्ण्य धर्म को फैलाने में बहुत सहायता दी। ये धर्म में जाति-पौति का मेद-भाव नहीं मानते ये, इनके कई शिष्य निम्न जातियों के थे। रामानन्द जी के अनु-यायियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ 'भक्तमाल' है। रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्य कवीर पन्द्रहवीं शताब्दी में हुए। इन्होंने सरल सुनोध भाषा में धार्मिक मेद-भावों को दूर करने का विलक्षण प्रयत्न किया । इनके शिष्यों में हिन्दू-मुसलमान दोनों थे, ये श्रल्लाह श्रौर ईश्वर का, मन्दिर श्रौर मसजिद का मेद नहीं मानते थे, ये मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। इनका सिद्धान्त था, 'हर को भजे सो हर का होय, जाति-पौति ना पूछे कोय'।

इनके बाद बल्लभाचार्य जी ने बल्लभ मत का प्रचार किया। इस मत के अनुसार श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार हैं। बहुत-से आदिमियों ने बल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। बम्बई, गुजरात और राज-पूताना में बहुत से धनवान इस मत के अनुयायी हैं।

इसी समय बङ्गाल में चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण-भक्ति का उपदेश हुन्ना। इन्होंने त्रपने प्रेम-भाव से विरोधियों तक को प्रभावित किया और कीर्तन श्रादि से बंगाल में वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। इनके श्रनुयायियों ने बृन्दाबन में राधा-कृष्ण के कई बड़े-बड़े विशाल मन्दिर बनवाये।

सोलहवीं शताब्दी में तुलसीदास ने राम-भक्ति का श्रौर इस प्रकार वैष्णव धर्म का प्रचार किया। वास्तव में इन्होंने हिन्दुश्रों के विभिन्न धर्मों के समन्वय का प्रयत्न किया। इनकी श्रानेक रचनाएँ हैं। रामायण का तो घर-घर प्रचार है। पुरुष-स्त्री, बाल-वृद्ध, सब के लिए यह ग्रंथ श्रत्यन्त श्राकर्षक एवं शिक्षा-प्रद है।

अस्तु, इस समय में, भारतवर्ष में नये-नये धार्मिक विचारों का प्रचार हुआ। भक्ति-भाव की वृद्धि हुई। शिव, राम और कृष्ण के अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ। अनेक भक्तों ने समय-समय पर जनता के सामने धर्म का उदार दृष्टि-कोण उपस्थित किया। सिद्धान्त से प्रत्येक वैष्ण्व यह मानता है कि वैष्ण्व धर्म की दीक्षा लेनेवाले सब व्यक्ति समान हैं, उनमें जाति या वर्ण का कोई मेद नहीं रहता। इसी प्रकार शैव और शाक्त भी अपने-अपने चेत्र में विभिन्नता को दूर कर एकता का विचार रखते हैं। परन्तु प्रत्येक की यह उदारता अपने चेत्र तक ही सीमित है, अन्य मतवालों से बहुधा वाद-विवाद रहता है। बहुधा दलित जातियों के आदिमियों से, वैष्णुव धर्म की दीचा ले लेने पर भी, कुछ बातों में पृथक्ता का विचार किया जाता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है; कुछ तो हो भी रहा है, इसका विचार आगे किया जायगा।

इसलाम धर्म — ऊपर जिन धार्मिक लहरों का विचार किया गया, वे भारतवर्ष में ही उत्पन्न होकर यहाँ के भिन्न-भिन्न भागों में फैलीं। इसलाम धर्म का प्रादुर्माव इस देश से बाहर, अरव में हुआ था। इसके मूल संस्थापक हज़रत मोहम्मद का जन्म वहाँ मक्का में सन् ५७० ई० में हुआ। उस समय अरव में बड़ा अंधकार छाया हुआ था, आदमी परस्पर में लड़ते भगड़ते थे, प्रेम और संगठन का अभाव था। भोग-विलास, मूर्ति-पूजा और स्वार्थ-पूर्ति का दौर-दौरा था। मोह-म्मद साहब आरम्भ से ही विचारशील थे, उन्होंने वहाँ की हालत सुधा-रने का निश्चय किया। पचीस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। चालीस वर्ष की आयु में इन्होंने लोगों को 'ला हलाह, एलिल्लाह' (ईश्वर एक मात्र और अद्वितीय है) यह उपदेश देना आरम्भ 'किया। इनका बहुत विरोध हुआ, इन्हें अनेक कष्ट दिये गये। पर

ये अपने निर्धारित पथ पर डटे रहे। अन्ततः सन् ६२२ ई० में इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस समय से ही इनका संवत् आरम्भ होता है, जिसे हिजरी संवत् कहा जाता है। मदीना में इनके बहुत से अनुयायी हो गये, उनकी सहायता से इन्होंने अरब में अपने धर्म 'इसलाम' का खूब प्रचार किया। इनके उपदेशों का संग्रह् 'कुरान' कहलाता है, जो मुसलमानों का पवित्र धर्म-ग्रन्थ है।

इसलाम धर्म के कुछ सिद्धान्त इस प्रकार है:-ईएवर एक है. श्रीर मोहम्मद उसका पैग्रम्बर (दृत) है। प्रतिदिन पाँच वक्तः 'नमाज़' (प्रार्थना) पढ़नी चाहिए। रमज़ान के महीने में उपवास करना चाहिए। गरीबों को खैरात दी जानी चाहिए। सब मुसलमान समान हैं, जाति-पाति का कोई मेद-भाव नहीं होना चाहिए। गरीब-श्रमीर सब एक स्थान पर सम्मिलित भोजन कर सकते हैं। पड़ोसियों से प्रेम. श्रीर सब पर दया करनी चाहिए। इसलाम धर्म श्रत्यन्त प्रजा-तंत्रात्मक है, यह ऊँच-नीच सबकी एक बिरादरी मानता है। सर्व-साधारण ने इस धर्म का खूब स्वागत किया। मोहम्मद साहब का शरीरान्त सन् ६३२ ई० में हुआ। इसके पश्चात् भी इनके धर्म का प्रचार होता रहा। क्रमशः यह धर्म एशिया योरप और अफ्रोका के दूर दूर के भागों तक फैल गया। इसलाम धर्मानुयायियों का नेता ख़लीफ़ा कहलाता है। कालान्तर में इस धर्म की दो शाखाएँ मुख्य हो गयीं-शिया श्रीर सुन्नी ( कुछ श्रीर भी भेद हुए; यथा-बोहरा, सुफी बादि )। शिया प्रथम तीन इमाम (धर्म-शिक्षक) अबुबकर, उमर श्रीर उसमान को नहीं मानते । वे केवल इसन श्रीर हुसैन को ही इमाम

मानते हैं, इनके शहीद होने की यादगार में ताज़िए निकालते हैं, और मोहर्रम का त्यौहार मनाते हैं। सुन्नी संख्या में श्रिधिक हैं। ये अधिक परम्परावादी तथा कहर हैं।

भारतवर्ष में अरबों का सबसे पहला आक्रमण सिन्ध पर सन् ७१२ में हुआ, जबिक यहाँ का राजा दाहिर था, जो बहुत कमज़ोर था। मुसिलिम सेनापित मोहम्मद बिन क्रासिम ने सिंध को जीत लिया और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। परन्तु उसने कोई अत्याचार न होने दिया।

मुसलमानों की इस विजय का बहुत समय तक भारतवर्ष पर विशेष प्रभाव न पड़ा। दसवीं सदी में अफ़गानिस्तान के शासक सुलुक्तगीन ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब पर धावा किया। उसके बाद महमूद गज़नवी और पीछे मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए। इनका मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की असंख्य धन-राशि को खूटना था। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में जाकर, यहाँ मुस्लिम राज्य की वास्तविक स्थापना देहली और उसके आस पास हुई। फिर तो मुगल राज्य के अन्त तक यहाँ मुसलमानों का राज्याधिकार कमशः बढ़ता गया; साथ ही यहाँ इसलाम धर्मानुयाथियों की संख्या भी बढ़ती गयी। कुछ आदमी भय या प्रलोभन से मुसलमानों में आ मिले। हिन्दू अपनी ही समाज के अत्याचारों से मुसलमानों में आ मिले। इस समय ये लगभग आठ करोड़ हैं। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, बिलोचिस्तान, पंजाब, सिंघ और बंगाल में उनकी संख्या हिन्दुओं से अधिक है।

मुसलमानों श्रीर हिन्दुश्रों का सैकड़ों वर्ष साथ रहा है। एक के सुख में, दूसरे को सुख, श्रीर एक के दुख में दूसरे को दुख हुआ है। प्रत्येक ने कुछ वातें दूसरे से प्रहण की हैं, तो कुछ उसे दी भी हैं। धर्म, समाज, कला-कौशल, साहित्य-प्रत्येक चेत्र में दोनों जातियों का प्रभाव विलक्षण रूप से पड़ा है। यद्यपि कुछ मुसलमान अपने आपको विदेशी श्रनुभव करते हैं, श्रीर श्रपनी नज़र मक्का मदीना पर लगाये हुए हैं, श्रौर संशार के मुसलिम राज्यों से, भारतवर्ष की श्रपेक्षा, श्रिधक सहानुभूति रखते हैं। वास्तव में मुसलमान हिन्दुश्रों से इतनी दूर नहीं है, जितना समभा जाता है। यहाँ की ही नस्ल श्रीर मिट्टी से उनका जन्म हुन्ना, यहाँ के ही अन्न-जल और वायु से उनका पालन-पोषण हुआ। हिन्दुओं की भीत से उनकी भीत, श्रौर खेत से खेत लगा हन्ना है, चोली-दामन का साथ है। इस प्रकार भारत के हित में उनका हित है और देश के श्रहित में उनका भी श्रहित है। बाहरवालों की श्रपनी-श्रपनी ही समस्याएँ काफी है, भारतीय मुसलमानों को उनसे सहायता मिलने की श्राशा न करनी चाहिए। दुख-सुख में भारतंवासी ही उनके काम श्रावेंगे, श्रीर श्राना चाहिए।

सिक्ख धर्म — पन्द्रहवीं शताब्दी में, पंजाब में एक नये धर्म का श्राविभीव हुआ, इसे सिक्ख धर्म कहते हैं। इस के मूल प्रवर्तक गुरु नानक हुए हैं। इनके माता पिता साधारण ग्रामीण थे, तथापि इनमें बाल्यावस्था से ही प्रतिमा के चिन्ह दिखायी देने लगे थे। अठारह वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। इनके दो पुत्र हुए। पर इन्हें साधु-संतों की संगति अधिक पसन्द थी। अतः इन्होंने घर-बार छोड़

दिया। ये हिन्दू धर्म एवं इसलाम धर्म की अच्छी-अच्छी बातें अहण करके उपदेश देने लगे। इनका िखान्त कबीर से मिलता था। ये जाति-पाँति का भेद नहीं मानते थे। इन्होंने भारतवर्ष के मिन्न-भिन्न भागों में अमण करने के अतिरिक्त बग्रदाद मक्का, आदि मुसलिम केन्द्रों की भी यात्रा की। जहाँ-कहीं ये गये, जनता इनके साधु जीवन और सरल सुबोध उपदेशों से बहुत प्रभावित हुई। हिन्दू और सुसलमान दोनों धर्म वाले अनेक व्यक्ति इनके अनुयायी बने और सिक्ख (शिष्य) कहलाये।

सिक्ख धर्म के मुख्य विद्धान्त ये हैं :— सबका पिता परमात्मा एक है, जाति-पाँति या ऊँच-नीच का कोई मेद-भाव नहीं मानना चाहिए। हमारा उद्देश्य हृदय की शुद्धि होना चाहिए। सब धर्मों के संत-महात्माश्रों का श्रादर सम्मान करना चाहिए। सिक्खों का धर्म-प्रन्थ 'प्रन्थ साहब' कहलाता है। गुरु नानक के बाद दस गुरु हुए, उनमें से गुरु गोविंदसिंह जी ने सिक्खों का सैनिक संगठन किया, जिससे वे मुगुल शासकों के श्रत्याचारों का सामना कर सकें। क्रमशः सिक्खों की शक्ति बहुत बढ़ गयी श्रीर इनसे मुगुल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा। रयाजीतिसिंह के समय में सिक्खों की शक्ति शिखर पर पहुँच गयी, पंजाब में इनका ही शासन स्थापित हो गया। इस समय भी नाभा, पिटयाला, कपूरथला श्रादि रियासतों के शासक सिक्ख नरेश ही हैं। सिक्ख एक वीर श्रीर साहसी जाति है, सेना में ख़ूब भाग लेती है। वास्तव में सिक्ख हिन्दू ही हैं। कहर हिन्दू धर्म की कुछ, बातों के विरुद्ध ही इनका

संगठन हुआ। ये प्रजातंत्रात्मक तथा उदार दृष्टि-कोण्यवाले होते हैं, अपन्य धर्मवालों के प्रति सहनशीलता का भाव रखते हैं, परन्तु किसी की ज़्यादती या अत्याचार सहन नहीं करते।

पारसी-पारसी यहाँ विशेषतया बम्बई प्रान्त में हैं श्रीर श्रिधक-तर व्यापार करते हैं। ये एक लाख से कुछ ही अधिक हैं, तथाफि इनमें कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ आदि हुए हैं। ये ज़रदुश्त के अनुयायी हैं जो ईसा के लगभग आठ सी वर्ष पूर्व ईरान में हए। ज़रदुश्त में घर्म श्रीर भक्ति-भाव श्रारम्भ से ही विशेष रूप से था। बीस वर्ष की आयु में इन्होंने गृह-त्याग किया और उसके दस वर्ष बाद आन्तरिक प्रेरणावश ये व्यापक धर्म का उपदेश करने लगे। बियालीस वर्ष की आयु में इन्होंने ईरान के बादशाह तथा अपन्य अधिकारियों को अपने मत का अनुयायी बना लिया। फिर यह धर्म वहाँ राज-धर्म बन गया। इस धर्म का मुख्य ग्रन्थ 'श्रवस्था' है, श्रौर प्रवान इष्ट देव श्रहुर-मज़्द है। पारसी विशेषतया श्रग्नि की पूजा करते हैं। जब ईरान में इस धर्म में बहुत कहरता आ गयी, छुत-छात का भाव बढ़ गया श्रीर सर्वधाधारण पर धार्मिक श्रत्याचार होने लगे तो वहाँ के बहुत-से पारसी भारतवर्ष आ गये। यह देश तो सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध ही था; यहाँ इनसे अच्छा व्यवहार हुआ, और ये भी इस देश को अपना मानकर रहने लगे। ये अब भारत-भूमि के प्रति मिक-भाव रखते हैं, श्रीर श्रपने को विदेशी नहीं समभते।

ईसाई — ईसाई यहाँ साठ लाख से अधिक हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। ये अन्य मतावलिम्बयों को धर्म-परिवर्तन द्वारा ईसाई बनाते रहते हैं। ये इजरत ईसा के श्रनुयायी हैं। जिनका जन्म लघु-एशिया में जूडिया के निकट वेथलम ग्राम में एक बढ़ई के घर हुआ। अंग-रेज़ी सन् इनके ही नाम पर चलता है। इस प्रकार इन्हें हुए अब १९४० वर्ष हो गये। उस समय यहूदी समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थीं। इज़रत ईसा ने अनेक कष्ट श्रीर कठिनाइयों को सहन करके भी तत्कालीन अन्ध-विश्वासों और अनाचारों का विलक्षण प्रेम-भाव से विरोध किया। अपने प्रेम-सन्देश से, सेवा-सुश्रधा और चिकित्सा से, सदाचार-युक्त निर्भीक व्यवहार से, इन्होंने बेंढब हलचल मचा दी । सत्ताधारियों को यह सहन न हुआ, उन्होंने न्याय का ढोंग रच कर इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इनका उपदेश था कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, शत्रु से भी प्रेम करो, जो तुम्हारी दायी गाल पर चपत मारे उसकी श्रोर तम अपनी बायीं गाल भी कर दो। कितना ऊँचा श्रादर्श है! भारतवर्ष में ईसाइयों के बहुत-से अस्पताल और स्कूल आदि हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि संसार में इस धर्म के माननेवालों के आपस में तथा दूसरों के साथ अनेक भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुए श्रीर हो रहे हैं।

आधुनिक धार्मिक सुधार — ऊपर भारतवर्ष में प्रचलित विविध धर्मों का संक्षित परिचय दिया गया। प्रत्येक धर्म में समय-समय पर कुछ-कुछ विकार आ जाता है। धर्म की पुष्प-बाटिका की महा-पुरुषों द्वारा यथेष्ट सार-संभार न होने से उसमें धास-फूस की वृद्धि हो जाती है; यहाँ तक कि फूलों को खिलने की सुविधा ही नहीं रहती, वे दब जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, श्रीर नष्ट हो जाते हैं। श्रम्बकार

काल में, घार्मिक प्रथाश्रों या रीतियों में बहुत श्रनियमितता श्रीर कु-संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, विचार-हीन श्रीर श्रशिक्षित श्रादमियों की संख्या वेहद बढ़ जाती है, तथा ये लोग घार्मिक बातों का मूल उद्देश्य भूल कर, केवल रूढ़ियों के उपासक बन जाते हैं। इस प्रकार श्रन्ध-श्रद्धा श्रीर सङ्घीर्णता फैल जाती है। यह दशा श्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग में, यहाँ विशेषतया बंगाल की थी। इस प्रान्त के श्रादमी धर्म का वास्तविक श्रादर्श भूल गये थे। यहाँ कालीदेवी की बेटब पूजा होती थी, तंत्रवाद का प्रचार था, धर्म के नाम पर साधारण व्यक्तियों पर बहुत श्रत्याचार होता था।

राजा राममोहनराय श्रोर ब्रह्म-समाज —श्री राजा राम-मोहनराय (सन् १७७४-१८३३ ई०) भारतवर्ष की वर्तमान जायति के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उस समय की परिस्थिति पर ख़ृब विचार किया, संस्कृत की कई उपनिषद् श्रादि धार्मिक ग्रन्थ बंगला, हिन्दी श्रीर श्रॅगरेज़ी की टीका सहित छुपवाये, जिससे संस्कृत न जाननेवाले बन्धु भी उन्हें समक्त सकें श्रीर तत्कालीन स्वार्थी पण्डितों के कथना-नुसार उलटा-सीधा श्रथं न मान लिया करें।

राजा साहब ने सन् १८२८ ई० में ब्रह्म-समाज की स्थापना की । इसके कुछ सिद्धान्त इस प्रकार थे:—िनराकार, अनादि, अनन्त परमेश्वर सबका उपास्य देव है; समस्त मनुष्यों को उसकी पूजा का समान अधिकार है। किसी प्रकार का चित्र, प्रतिमा, मूर्ति था ऐसे पदार्थ का उपासना में प्रयोग न किया जायगा, जिसे पीछे ईश्वर के स्थान में माने जाने का भय हो। मंदिर में केवल उसी प्रकार

की प्रार्थना और संगीत होगा, जिससे प्रेम, नीति, भिक्त और दया का प्रचार हो, तथा सब प्रकार के मत-मतान्तरवाले मनुष्यों का बड़ा सङ्गठन हो सके। ब्रह्म समाज का आकार हिन्दू धर्म से पूर्ण है, तथापि सर्वेसाधारण में सभा करके प्रार्थना करना आदि कुछ विदेशीय भाव भी हैं।

ब्रह्म-समाज का चेत्र विशेषतया बंगाल प्रान्त में ही परिमित रहा । यहाँ भी श्रिष्ठिकतर शिक्षित वर्ग ही इसमें सिम्मिलित हुआ। इस समय ब्रह्म-समाजियों की संख्या बहुत साधारण-सी है। यद्यपि इस संस्था ने हरिजन-श्रान्दोलन श्रादि में ख़ासा भाग लिया, प्राय: यह प्रगतिशील न रही। यह जनता की श्रावश्यकताओं की पूर्ति में योग नहीं दे रही है, इसका प्रचार भी सर्वेसाधारण में कम है।

स्वामी दयानन्द और आर्य-समाज—स्वामी दयानन्द जी (सन् १८२४-८३ ई०) ने आजीवन ब्रह्मचारी रह कर वैदिक साहित्य का स्वाध्याय किया और उसे ही धार्मिक सुधार का आधार बनाया। इन्होंने श्रॅगरेज़ी की शिचा नहीं पायी थी, और ये पाश्चात्य सम्यता पर सुग्ध नहीं हुए थे। तथापि इन्होंने देश में स्थान-स्थान पर व्याख्यान और उपदेश देकर सर्वसाधारण में धार्मिक और सामाजिक सुधार का महान कार्य किया। और, इस कार्य को ज़ारी रखने के लिए अपने जीवन काल में ही आर्य-समाज की स्थापना कर दी। इनके बाद और बहुत जगहों में समाजें स्थापित हुईं। इन संस्थाओं ने वैदिक धर्म का प्रचार किया, और मन्दिरों और तीथों के दुर्गुणों को दूर कराने का यन्न किया।

श्रार्य-समाज का सबसे श्रिषक प्रचार पञ्जाब में हुश्रा। श्रन्य प्रांतों में भी इसका ख़ासा प्रभाव पड़ा। इसने श्रपने सामने जनता में सुधार करने का व्यावहारिक कार्य-क्रम रखा है। शिद्धा-प्रचार श्रीर समाज-सुधार में यह ख़ूब भाग लेती है। यद्यपि कहीं-कहीं समाजों में दलबन्दी के कारण कुछ दोष हिन्ट-गोचर होता है, प्रायः श्रार्य-समाजी बड़े उत्साह से काम करते हैं, श्रीर श्रपनी संस्था को समयानुकूल, उपयोगी, श्रीर जीवित-जाप्रत रखने का प्रयत्न करते रहते हैं।

कर्नल आल्काट और थियोसोफी -कर्नल आल्क्ट श्रमरीका निवासी थे । ये यहां सन् १८७९ ई० में पधारे। इन्होंने. श्रीर रूस की मैडेम एच.पी. ब्लेवट्सकी ने न्यूयाके में सन् १८७५ ई॰ में, थियोसोफ़िकल (ब्रह्म-विद्या-सम्बन्धी ) सोसा-यटी स्थापित की थीं । विदेशियों द्वारा, विदेश में ही स्था-पित इस सभा के अधिकाँश सभाषद् भी विदेशी ही हैं, तथापि इसने इस देश का बहुत हित किया है। इसने हिन्दुश्रों को समभाया कि मारतीय धर्म बहुत उच-कोटि का है, उसका गौरव पहिचानो, श्रीर उसमें घुसे हुए दुर्गणों को दूर करो। ईसाई पादिरयों के बहकावे में श्राकर, उससे बिल्कुल न इटो। भारतवर्ष में इस सोसायटी की स्थापना अद्यार ( मदास ) में हुई । परम विदुषी और प्रतिभावान आयरिश महिला भीमती ऐनी विसेन्ट ने इसमें योग दिया। इनके व्यक्तित्व से इस संस्था ने अनेक विद्वानो और नेताओं को अपनी आर आकृष्ट किया। सोसायटी का कार्यालय सुप्रसिद्ध धर्म-केन्द्र काशी में रखा गया। यहाँ सेंट्रल-हिन्द-कालिज स्थापित हुआ, जो अब हिन्द विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत है। विशेषतया छोटे बालक-बालिकाओं की शिद्या के लिए, यह सोसायटी उत्तम व्यवस्था कर रही है। समाज-सुधार में भी इसने अच्छा भाग लिया है।

स्वामो विवेकानन्द श्रीर रामकृष्ण मिशन-श्रमरीका आदि विदेशों में हिन्दू धर्म की घोषणा करने और अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीयों में स्वधमं का अनुराग उलन करने का विशेष यश श्रीरामकृष्ण परमहंस (सन् १८३३-१९०२ ई०) के प्रसिद्ध शिष्य श्री विवेकानन्द जी को है। इन्होंने तथा इनके द्वारा, इनके गुरु के नाम से, संस्थापित राम-कृष्ण मिशन ने जन-साधारण का वेदान्त सम्बन्धी भ्रम दूर करके इसकी समयोपयोगी शिक्षा दी। स्वामी विवेकानन्द जी ने इस बात में भी महत्व-पूर्ण योग दिया कि हिन्दू-जाति अन्य जातियों के सद्गुणों को प्रहण करे. श्रीर इसमें श्रात्म-विश्वास हो. यह श्रपनी शक्ति का अनुभव करे। स्वामी विवेकानन्द और रामवीर्थ ने यह चिद्ध कर दिखाया कि संसार में हिन्दू सभ्यता का एक ऊँचा स्थान है, श्रीर इिन्दुश्रों का वेदान्त धर्म श्रीर तत्व-ज्ञान मनुष्य-मात्र के कल्याया के वास्ते है। रामकृष्ण मिशन की श्रोर से अनेक स्थानों में सेवा आश्रम स्थापित हैं, जो विशेषतया रोगियों की चिकित्सा का अच्छा काम कर रहे हैं।

इन आन्दोलनों का प्रभाव — भारतवर्ष की समस्त जन-संख्या को देखते, उपर्युक्त संस्थाओं के सभासद् विशेष नहीं हैं। अधिकांश आदमी सनातन धर्मावलम्बी हैं। परन्तु इन आन्दोलनों का अभाव थोड़ा-बहुत उन पर भी पड़ा है। अब 'सुधार' से लोगों को पहले के समान घृणा-सी नहीं रही । देश में अनेक समा-सोसायटी हैं, जो अप्रपने-अपने चेत्र में कुछ सुधार-कार्य कर रही हैं । हाँ, कुछ गम्भीर विचार करने पर यह मानना पड़ेगा कि अधिकतर 'धार्मिक' कही जाने-वाली संस्थाओं का हे टि-कोण बहुत संकीर्ण हैं । स्मरण रहे कि किसी भी विशेष आचार्य की बातों को 'बाबा वाक्यम् प्रमाणम्' समभना, विशेष प्रन्थों की दासता, प्रत्येक नये विचार या आविष्कार को प्राचीन प्रन्थों में खोजना और उसमें आगे बढ़ने में असमर्थता सूचित करना 'धार्मिक-सुधार' के प्रवाह के विरुद्ध जाना है।

श्रव इम कुछ प्रस्तुत धार्मिक विषयों का विचार करते हैं।

श्रद्धा का सदुपयोग — मूर्ति-पूजा श्रीर तीर्थ-यात्रा श्रादि में जन-साधारण की जो श्रद्धा बनी हुई है, उसका प्रायः देश-काल के श्रनुसार सदुपयोग नहीं हो रहा है। हमें चाहिए कि मंदिरों श्रीर तीर्थ-स्थानों के साथ-साथ पुस्तकालय, वाचनालय, श्रीषघालय श्रादि जनोपयोगी संस्थाएँ संलग्न कर दें, जिससे भेंट-पूजा श्रादि में जो द्रव्य श्रावे, उसमें से इन संस्थाश्रों को भी यथेष्ट सहायता मिले। मन्दिरों की स्थायों सम्पत्ति तथा जागीर की श्रामदनी का भी इसी प्रकार सद्व्यय हो। पुजारी, पंडों श्रादि के बहुत योग्य श्रीर देश-हितेषी होने की ज़रूरत है।

इसी प्रकार मठों ('श्रखाड़ों') का प्रश्न भी विचारणीय है। अविकांश मठाधीश श्रालस्य, विलासिता या दुराचारमय जीवन व्यतीत करते हैं। कितने ही मठों में श्रपार धन-सम्पत्ति व्यर्थ पड़ी है, लोगों का ध्यान इस अप्रोर आकर्षित हुआ है और इसकी व्यवस्था के लिए क़ानून भी बन रहा है।

दान-धर्म — अधिकांश आदमी दान-धर्म करते हुए पात्रापात्र का विचार नहीं करते । वे अपनी श्रद्धा से ऐसे हट्टे-कट्टे भिखारियों और बनावटी साधु संन्यासियों को भी भोजन-वस्त्र आदि देते रहते हैं, जिनका जीवन देश के लिए किसी प्रकार भी लाभकारी नहीं है । इस प्रकार का दान-धर्म परावलम्बन बढ़ाता है । यदि हम इन्हें मुफ़ में न खिलाएँ-पिलाएँ तो ये अवश्य ही अपने निर्वाह के लिए उत्पादक कार्य करें और देश की आर्थिक स्थित को सुधारने में सहायक हो । अनाथ बालकों, विधवाओं और अपाहिजों आदि की सहायता मनुष्य मात्र को करनी चाहिए । आवश्यकता इस बात की है कि भिन्न-भिन्न समाज इस सम्बन्ध में यथेष्ट लोकमत तैयार करें । इमारा दान-धर्म ऐसा हो कि उससे नागरिकों की कार्य-कुशलता और योग्यता बढ़े।

हरिजन पन्दिर-प्रवेश — हरिजन (श्रस्पृश्य जातियों के श्रादमी) भगवान के राम, श्रीकृष्ण, शिव श्रादि स्वरूपों में, वैसी ही भिक्तिः भावना रखते हैं, जैसी श्रन्य हिन्दू। परन्तु इन्हें मन्दिरों में दर्शन करने नहीं दिया जाता। श्रन्यान्य सज्जनों में, विशेषतया महातमा गांधी को यह श्रनौचित्य सहन न हुश्रा। उन्होंने हसे हटाने का श्रान्दोलन किया। उनकी इच्छा श्रीर श्रनुमित से भारतीय व्यावस्थापक समा में हरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बाधा-निवारण विल श्रीर श्रस्पुश्यता-निवारण बिल उपस्थित करने का विचार किया गया था। किन्तु श्रनेक पुरातन मतवादियों ने इन बिलों का घोर विरोध किया। इसिलए पीछे ये बिल पेश नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में लोकमत जाग्रत करने का प्रयत्न हो रहा है।

मुसलमानों में धार्मिक सुधार-श्रव मुसलमानों की बात लें। जब वे भारतवर्ष में आये. उनमें धार्मिक जोश श्रीर सामाजिक एकता की भावना बहुत प्रबल थी। दसरी श्रोर हिन्दुश्रों में कई कुरीतियाँ श्रीर मेद-भाव थे। इसलिए विशेषतया दलित जातियों के बहुत से हिन्दुओं ने कहीं भय या प्रलोभन से, तो अनेक बार उनकी उदारता से, प्रभावित होकर इसलाम धर्म ग्रहण कर लिया श्रीर वे अपने श्रापको हिन्दुश्रों से भिन्न, श्रीर कुछ श्रंशों में विरोधी समभने लग गये। मुसलमानों के सुक्ती क़क़ीरों ने श्रीर कबीर जैसे महात्मात्रों ने मुसलमानों की कट्टरता घटाने तथा उनका हिन्दुश्रों से विरोध-भाव हटाने का प्रयत्न किया। क्रमशः हिन्दू संस्कृति का भी मुसलमानों पर प्रभाव पड़ा। श्रकबर और जहाँगीर जैसे बादशाहों ने दोनों संस्कृतियों को मिलाने में अच्छा भाग लिया। खान-पान, रहन-सहन श्रादि में मुसलमान हिन्दुशों के निकट श्राने लगे। सतरहवीं शताब्दी से यहाँ योरिपयनों की एंस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। पीछे जिस प्रकार हिन्दुश्रों में स्वामी दयानन्द जी हुए, कुछ-कुछ उसी प्रकार मुसलमानों में शिक्षा-प्रचार और सघार करने का भेय विशेषतया सर सैयद श्रहमद खाँ ( सन् १८१७—९८ ई० ) को है। परन्तु कुछ श्रद्रशी तथा पद-लोलुप मुसलमानों ने श्रपने जाति-बंधुश्रों के नेता बनकर उन्हें नयी रोशनी से बचने और हिन्दुओं से असहयोग करने

की प्रेरणा की। साथ ही उन्हें अधिकारियों का भी कुछ इशारा मिलता गया। बस, कहीं मसजिदों के सामने हिन्दुओं का बाजा रोकने का प्रश्न उठा, कहीं द्वेष-भाव से गाय की कुर्बानी की जाने लगी, कहीं साम्प्रदायिक मांगें उपस्थित की जाने लगी।

भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन से मुसलमानी पर बड़ा हितकर प्रभाव पड़ा। सन् १९२१ ई० में देखने में आया कि सहृदय मसल-मान हिन्दुत्रों का जी दुखानेवाली कुर्बानियों से स्वयं परहेज़ करते हैं. श्रीर यथा-शक्य श्रीरों को भी रोकते हैं। समफदार मुल्ला-मोलवी करान की 'श्रायतों' से जनसाधारण को स्वदेशोन्नति का उपदेश करते हैं। उन्हें शंख या फांफ बजाने का स्वर कर्ण कद्ध प्रतीत नहीं होता था। हिन्दुश्रों का दशहरा श्रीर मुसलमानों की मोहर्रम दोनों साथ-साथ शान्ति-पूर्वक होने लगे। मसजिदों में हिन्दु श्रों का स्वागत. श्रीर हिन्दू- त्यौहारों के अवसर पर मुसलमानों का सेवा-भाव, देखा गया। परन्तु राष्ट्रीय त्रान्दोलन शिथिल हो जाने पर कुछ उद्दंड मुसलमानों ने जहाँ-तहाँ पुनः चिन्तनीय स्थिति उत्पन्न कर दी: श्रीर श्री गरोशशंकर जी विद्यार्थी जैसे नर-रत्नों का बलिदान हुआ । इससे सम्बद है कि सर्वसाधारण मुसलमानों में धार्मिक जायति, सहिष्णुता श्रीर समभाव स्थायी रूप से बहुत कम हुआ है। तथापि सुधारकों का इस दिशा में होनेवाला प्रयत्न प्रशंसनीय है; हां, उन्हें अभी बहुत कार्य करना शेष है।

अन्य धर्मावलिम्बियों में सुधार की भावना—थोड़ा - बहुत सुधार यहां के सभी धर्मों के अनुयायियों में हुआ है। ईसाइयों और पारिसयों में पहले से ही अन्य अद्धा या रूदियां कुछ कम थीं। अतः इनमें सुधार भी अपेचाकृत कम हुआ। हाँ, इनमें संगठन की ओर बहुत ध्यान दिया गया। मिशन स्कूलों में पहले धर्म-प्रचार का लक्ष्य रखा जाता था, उसमें विशेष सफलता न मिली। इसलिए अब प्रायः नयी संस्थाएँ न खोलकर, पहले की ही संस्थाएँ चलायी जा रही हैं, और उनमें शिक्षा-प्रचार का उद्देश्य ही विशेष रूप से रहता है। सुयोग्य पादरी ईसाई धर्म सम्बन्धी बातों की, नवीन बुद्धि-संगत ढक्क् से, व्याख्या करते हैं। विविध स्थानों में मिशन अस्पताल सर्वसाधा-रखा जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। यही बात पारसियों के सम्बन्ध से भी कही जा सकती है। उनकी भी अनेक संस्थाएँ उनके दान-धर्म की घोषणा कर रही हैं। अस्तु, धार्मिक दासता के विरुद्ध चारों ओर आवाज़ उठ रही है। बुद्धि-स्वातंत्र्य का युग है। यह बात थोड़ी-बहुत सभी धर्मवाले समक्त गये हैं और इसलिए अपने आचार-विचार में कमशः परिवर्तन या सुधार कर रहे हैं।

विशेष वक्तव्य — आवश्यकता है कि धर्म केवल कुछ बाहरी बातों में ही न समका जाय । उतना ही, वरन उससे भी अधिक ध्यान हमारे दिन-रात के पारस्परिक व्यवहारों और आन्तरिक शुद्धि की ओर दिया जाना चाहिए । हम सनातन धर्मी हैं तो क्या, आर्य-समाजी, ब्रह्म-समाजी थियोसोफ़िस्ट, एवं हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई या मुसलमान हैं तो क्या, भारत-माता हम सबकी उपास्य देवी हैं । हम सब इसकी सेवा करें तथा अन्य देशों के निवासियों के प्रति भी सहानुभृति रखते हुए अपने विशाल मानव धर्म का परिचय दें।

## श्रद्वाईसवाँ परिच्छेद सामाजिक जीवन

का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यहाँ श्रांति प्राचीन काल से वर्णाश्रम धर्म का प्रचार रहा है; मनुष्यों के कर्तव्य उनके वर्ण तथा श्राश्रम के श्रनुसार निर्धारित हैं। पहले श्राश्रम की बात लीजिए।

आश्रम-ठयवस्था—प्राचीन धर्माचार्यों तथा स्मृतिकारों ने मनुष्यों की श्रायु का परिमाण धी वर्ष मानकर उसे चार भागों में विभाजित करने का श्रादेश किया है—(१) ब्रह्मचर्य श्राश्रम । पच्चीस वर्ष तक मनुष्य ब्रह्मचारी रहें, श्रीर विद्याध्ययन करें। (२) गृहस्थ श्राश्रम । छुन्बीसवें वर्ष से पचासवें वर्ष तक, मनुष्य विवाहित रहें श्रार्थात् गृहस्थ जीवन न्यतीत करें, धनोपार्जन करें, श्रपना श्रीर परिवार का पालन करें श्रीर सांसारिक कार्यों में योग दें। (३) वानप्रस्थ श्राश्रम । इक्यावनवें वर्ष से मनुष्य गृह-त्याग कर स्त्री-सहित बन में

एकांत जीवन व्यतीत करें, स्वाध्याय श्रीर ईश्वर-भिक्त में लीन रहें। (४) पछत्तर वर्ष की श्रायु ाप्त होने पर मनुष्य संन्यास श्राश्रम में: प्रवेश करें, संन्यासी होकर गृहस्थों को उपदेश दें, उनका पथ-प्रदर्शन, करें।

स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य-श्राश्रम साधारणतया सोलह वर्ष का रखाः गया था।

श्रव भी हिन्दू श्राश्रम-व्यवस्था को मानते हैं, परन्तु व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जाता । श्रद्धानवें-निन्यानवें फ़ी-सदी लोगों के लिए दो ही आश्रम रह गये हैं - ब्रह्मचर्य और गृहस्थ । प्राय: विवाह कम उम्र में ही हो जाते हैं। लड़की या लड़का श्रविवाहित रहने तक ब्रह्मचर्य श्राश्रम में मान लिया जाता है. चाहे वे इस श्राश्रम के नियमों का ढीक पालन न भी करें। पश्चात वे आजीवन गृहस्थ रहेंगे.. श्रीर सांसारिक चिन्ताश्रों में फँसे रहेंगे। निस्सन्देड श्राज-कल की बदली हुई परिस्थिति में प्राचीन शैली के अनुसार वानप्रस्थ के नियमों का पालन करना कठिन ही नहीं, वरन असंभव है। आर्थिक संघर्ष बहुत बढा हुआ है, बानप्रस्थियों के लिए जीवन निर्वाह की समस्या कैसे इल हो ! श्रव्हा हो. श्रादमी चालीस, पैतालीस वर्ष की श्रायु से ऐसा कार्य-क्रम रखें जिसका उद्देश्य हो, स्वार्थ और सांसारिक विषयों को छोड़कर परोपकारार्थ जीवन व्यतीत करना, दूसरों की सेवा-सुश्रुषा करना, अन्य नागरिकों के सहयोग से उनकी तथा देश की उन्नति की बातें सोचना और कार्य रूप में परिणत करना । यदि इम उपर्युक्त भाव से वानप्रस्थो की जगह ग्रामप्रस्थी हुआ करें तो उस भारतीय जनता का, जो अधिकांशः

श्रामों में रहती है, यथेष्ट हित होने की बहुत सुविधा हो जाय।

वर्ण व्यवस्था—आश्रम की बात यहीं समाप्त कर अब वर्णों का विषय लीजिए। प्राचीन काल में यहाँ चार वर्ण थे। ब्राह्मणों का कार्य पढ़ना पढ़ाना, दान लेना और देना, यज्ञ करना और कराना था। क्षत्रियों का कार्य समाज और देश की शत्रुद्धों से रक्षा करते हुए उन्हें इस विषय में निश्चिन्त रखना था। वैश्यों पर समाज के भरण-पोषण का कार्य था, ये कृषि, गो-रक्षा और व्यापार करते थे। श्रुद्ध अन्य तीन वर्णों की नाना प्रकार से सेवा करते थे। इस प्रकार वर्ण गुण-कर्मानुसार थे। जो जिस कार्य को करता, वह उस वर्ण का माना जाता था। इनमें परस्पर में विवाह सम्बन्ध होता था। एक वर्ण के परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए दूसरे वर्ण में प्रविष्ट होने में कोई बाधा नहीं थी। प्रत्येक वर्ण की, समाज के लिए, उपयोगिता थी, अतः सभी का समाज में सम्मान था; ऊँच-नीच का मेद-भाव न था। मेद-भाव कालान्तर में जाकर हुआ। तब वर्ण जातियों में परिणत हो गये।

जाति-भेद के गुण-दोष आर्थिक दृष्टि से जाति-भेद के प्रधान लाभ ये मालूम होते हैं—(अ) इससे वंशागत कार्य-कुशलता प्राप्त होतो है; वाप-दादे के किये हुए काम की शिक्षा और उसके रहस्य जल्दी जान लिये जाते हैं। (आ) हर एक जाति के व्यक्तियों का एक संघ होता है, जिसके सदस्य परस्पर एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं तथा कार्य की मज़दूरी नियमित करने में सहायक होते हैं। (इ) इससे कुछ अंश तक स्थूल अम—विभाग होता

है एक जाति के पुरुष एक ही कार्य करते हैं। हाँ, उन्हें किसी नवीन कार्य का आरम्भ करना कठिन भी हो जाता है।

परन्तु हानियों के सामने ये लाभ नहीं के बराबर प्रमाणित होते हैं। जाति भेद से समाज छिन्न-भिन्न हो गया है। संगठन विशाल परिमाण पर हो ही नहीं पाता। प्रत्येक जाति का हिन्ट-कोण बहत संकीर्ण, अनुदार और स्वार्थ-पूर्ण रहता है। वह दूसरी जाति के हितों का विचार नहीं करती। बहुत-सीजातियों को अस्पृश्य अथवा नीच समका जाता है, जनता के सामने अम की महत्ता का आदर्श नहीं रहता; अनेक आदमी दुर्गुणी, व्यसनी और मुक्त़ लोर होते हुए भी केवल जनम के आधार पर ऊँचे माने जाते हैं।

विगत वर्षों में जाति-मेद के दोषों की आर सुधारकों का ध्यान आधिकाधिक आकर्षित हुआ है। ब्रह्म-समाज ने इस दोष के दूर करने के वास्ते प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए अपने उपासना-मन्दिर का द्वार खोल दिया। बिना किसी मेद-भाव के सबको परस्पर मिलने-जुलने का अवसर दिया। पुनः आर्थ-समाज ने वर्ण-व्यवस्था के। गुर्ग-कर्म के अनुसार बतलाते हए कहा कि मनुस्मृति के आधार पर भी जन्म से सब लोग शुद्ध होते हैं, बड़े होंने पर जो जैसा आचार व्यवहार करता है, वह वैसी ही जाति का कहलाये जाने का अधिकारी होता है। थियोसोक्षी ने भी जाति-बन्धनों को शिथिल करने में बड़ा योग दिया है। उसने विश्व-व्यापी आतृ-भाव की घोषणा की तथा खान-पान सम्बन्धी मामलों में छुआ-छूत का विचार हटाया। इस प्रकार उपर्युक्त तथा जाति-पाँति-तोड़क-मंडल आदि सुधारक

संस्थाओं के उद्योग से जाति-मेद-रूपी सुदृढ़ दुर्ग के क्रमशः जीणें होने का लक्ष्ण प्रतीत होता है। बड़े पैमाने पर शिक्षा-प्रचार तथा सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है।

नीच जातियों से सद्भव्यवहार—उच्च वर्षों ने अपने नीच जाति के भाइयों के उद्धार की स्रोर पिछले वर्षों में विशेष ध्यान दिया है। इसका एक कारण यह भी है कि मुसलमान और ईसाइयों ने अपने मत का सबसे अधिक प्रचार अळूत तथा नीच जातिवालों में किया था। राम श्रीर कृष्ण के उपासक जब हजरत ईसा श्रीर मोहम्मद की शरण में जाकर दीक्षा लेने लगे तो हिन्दू धर्माधिकारियों की आँखें खुली और वे क्रमशः इन्हें अपनाने लगे। राजा राममोहनराय ने अनेक युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया कि जन्म ( जाति ) के श्राघार पर ऊँच-नीच का विचार करना श्रनुचित है। श्रार्थ-समाज शुद्धि-संस्कार का श्रांदोलन करने लगी। उसे आरम्भ में कहर हिन्दुओं का बड़ा विरोध सहना पड़ा । तथापि उसने ऋपना काम जारी रखा । ऋार्य-समाज और थियो-सोफ़िकल सोसायटी की संस्थात्रों में सहस्रों अञ्चत बालक शिक्षा पाने लगे। राज्य की श्रोर से भी जहाँ-तहाँ इस कार्य में योग दिया गया। राष्ट्रीय त्रान्दोलन ने तो इसे श्रद्भुत सहायता दी। महात्मा गांधी ने इस कार्य को राष्ट्रीय महासभा के रचनात्मक कार्य में स्थान दिया। तबसे अस्पृश्यता-निवारण का कार्य विशेष रूप से होने लगा। अञ्जूतों को केवल सार्वजनिक कुत्रों पर पानी मरने और बहुत-से स्थानों में मंदिरों में दर्शन कर सकने का ही अधिकार नहीं मिला, वरन् अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं में ये अन्य सज्जनों से हिल-मिलकर विविध कार्य करने लगे।

हरिजन-म्रान्दोलन-महात्मा गांघी ने 'हरिजन'-कार्य को अपने कार्य-क्रम का एक मुख्य श्रङ्ग बना लिया। मताधिकार के सम्बन्ध में उन्हें हिन्दुओं से पृथक न किये जाने के विषय में श्रापने सितम्बर १९३२ में ऐतिहासिक अनशन किया। श्रापने दौरा करके स्थान-स्थान पर हरिजनों की बस्तियों का निरीक्षण किया और उसमें स्वच्छता श्रीर स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से श्रावश्यक सुघार कर-वाने की त्रोर विशेष ध्यान दिया । साथ ही त्रापने हरिजनों को मद्य-पान श्रीर मुद्दार-मांस-भन्नण श्रादि से बचने का उपदेश किया. श्रीर उनकी श्रार्थिक श्रवस्था सघारने श्रीर उन्हें शिल्प-शिक्षा दिलवाने की भी यथा-सम्भव व्यवस्था करायी । इन सब कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए एक केन्द्रीय हरिजन-सेवक-संघ की स्थापना की गयी, जिसकी शाखाएँ विभिन्न स्थानों में कार्य कर रही हैं। ऋँगरेजी, हिन्दी, गुजराती श्रीर बँगला श्रादि में हरिजन सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। उनसे भी लोकमत सधारने में पर्याप्त सहायता मिल रही है। सन् १९३५ ई० के नये शासन-विधान के अनुसार १९३७ में कांग्रेस ने त्राठ प्रान्तों में मंत्री-पद ग्रहण किया । इन प्रान्तों में सरकार की श्रोर से हरिजनों की शिक्षा के लिए श्रधिक-से-श्रधिक प्रयत्न किया गया। यद्यपि श्रव भी समय-समय पर कुछ कहर हिन्दुश्रों की श्रोर से उनके प्रति दुर्व्यवहार के उदाहरण मिलते हैं: तथापि क्रमशः परिस्थिति सुधर रही हैं।

संयुक्त कुटुम्ब-मणाली-भारतवर्ष के बहुत-से भागों में एक कुटुम्ब या परिवार के व्यक्ति इक्ट्ठे मिलकर रहते हैं। सब कमाने- वालों की श्रामदनी घर के एक बड़े-बूढ़े के पास जमा होती है। वह सबकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। इससे श्रनाथों की शिच्चा तथा रचा में कुछ सुविधा होती है तथा बीमारी या बुढ़ापे में कोई व्यक्ति श्रसहाय नहीं होता। परन्तु क्योंकि संयुक्त परिवार में कोई श्रादमी श्रपनी मेहनत का तमाम फल श्रपनी सन्तान के लिए ही नहीं छोड़ सकता, धनोपार्जन में उसे विशेष उत्साह नहीं होता। रोटी-कपड़ा मिलने की श्राशा सब को बनी रहती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में स्वावलम्बन तथा साहस नहीं होता। कोई-कोई व्यक्ति बेकार रहता हुश्रा मुक्त में ही श्रपने दिन काटा करता है।

आज-कल लोगों में वैयक्तिक विचारों की बृद्धि हो रही है। पहले प्रायः एक परिवार के सब आदमी एक ही प्रकार के उद्योग-धन्धे से आजीविका प्राप्त करते थे। अब आमदरफ्त की बृद्धि और यातायात की सुविधाएँ अधिक होने तथा जीवन-संग्राम की कठिनाइयाँ दिनो-दिन बढ़ने से परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार कार्य करने का अवसर मिलता है, वह उसे करने लगता है। इस तरह परिवार के सदस्यों को दूर-दूर रहने का प्रसंग बढ़ता जाता है। इसका परिणाम स्पष्टतः संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली का हास है। यद्यपि स्वावलम्बन और विचार-स्वतन्त्रता का यथेष्ट महत्व है, तथापि समाज की उन्नति के लिए पारस्परिक सहानुभृति, सहयोग और त्याग के भावों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली के अन्तर्गत गुणों की बृद्धि हो और इसके दोषों का निवारण हो। साधारणतया आधुनिक लोकमत, विशेषतया नवयुवकों

का विचार इस प्रणाली के विरुद्ध ही हो रहा है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार—प्राचीन काल में यहाँ घर तथा समाज में महिलाओं का अच्छा स्थान था, खूब आदर-सम्मान था, उनका जीवन सुखमय था, उन्होंने विविध चेत्रों में अच्छा नाम पाया था। पीछे जाकर उनकी स्थिति क्रमशः विगड़ती गयी। बाल-विवाह और पर्दे का प्रचार हो गया। विधवाओं की संख्या बढ़ चली, उनका समाज में बहुत तिरस्कार होने लगा। विगत वर्षों में इन बातों में कुछ सुधार हुआ है।

पहले बाल-विवाद का विचार करें। संगठित रूप से, सर्व-प्रथम ब्रह्म-समाज ने जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। फिर आर्य-समाज ने जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। फिर आर्य-समाज ने ब्रह्मचर्य पर ज़ोर देकर, इस कुरीति के निवारण का प्रयत्न किया। वह स्थान-स्थान पर यह उपदेश करती है कि बाल-विवाह से मनुष्य की शक्तियों का हास होता है। कन्याओं का विवाह कम-से-कम १६ वर्ष में और कुमारों का २५ वर्ष में होना चाहिए। गुरुकुल और कन्या-महाविद्यालय आदि यह सुधार कार्य-रूप में परिणत कर रहे हैं। स्कूलों में केवल अविवाहित लड़के भरती करने के नियम से भी इस आन्दोलन में अच्छी सहायता मिल रही है। बड़ौदा आदि देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत में एक निर्धारित आयु से कम में विवाह करना क़ानूनी अपराध ठहराया गया है। अजनता के विचारों

<sup>\*</sup>विटिश मारत में 'बाल-विवाह-निषेध क़ानून १ अप्रैल सन् १९३० से जारी हुआ है। इसे साधारण बोल-चाल में इसके प्रस्तावक के नाम पर शारदा-एक्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार 'बाल' का अर्थ १८ वर्ष से कम आयु का बालक और १४ वर्ष से कम आयु की बालिका है।

में कमशः परिवर्तन होता है; श्रौर शिक्षा की वृद्धि से इस कुप्रथा के नष्ट होने की श्राशा है।

श्रन्धकार-काल में, माता-पिता या संरत्नक ही यहाँ बर-बधू की जोड़ी मिलाने लगे थे। वे चाहे जिस श्राय की, चाहे जिस कन्या का, चाहे जिस आयु या प्रकृति के लड़के के साथ ( अनेक दशाओं में बूढ़े के साथ भी) गढजोड़ा कर देते थे। प्रत्येक लडकी का विवाह उसी की जाति-बिरादरी के लड़के से श्रीर केवल खास-खास मुहुर्ती में होने की प्रया हो गयी; जाति-पौति की विभिन्नता और प्रांतीयता आदि का मेद-भाव बढ़ने से अनेक दशाओं में बर-बधू का चुनाव बहुत ही परिमित चेत्र में होने लगा। अब इन बातों की हानियों पर विचार होने लगा है। बर-बधू एक-दूबरे के चुनाव में माता-पिता या संरच्नकों के मत के आश्रित न रह कर उसमें स्वयं भी अपनी सम्मति का उपयोग करने लगे हैं। जहा-तहाँ लोकमत इस विषय में बढ़ता जा रहा है कि बर-बधु को एक-द्सरे के चुनाव में श्रधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए; हां, वे अपने माता-पिता श्रादि के परिपक्ष श्रनुभव से भी लाभ उठावें । चुनाव का चेत्र भी क्रमश: विस्तृत होता जा रहा है। श्रन्तर्जातीय विवाहों के भी उदाहरण मिलते जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्तर्पान्तीय विवाहों को भी श्रव्छा समर्थन मिल रहा है। सन् १८७२ ई० में 'स्पेशल मेरिज ऐक्ट' (विशेष विवाह क़ानून) बना था। उसके द्वारा उन मन्द्यों के विवाह को क़ानून की दृष्टि से ठीक माना जाने लगा, जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिक्ख या जैन किसी भी धर्म से सम्बन्ध नहीं रखते। जायदाद के बँटवारे श्रथवा विरासत के मामले में इस क़ानून से लाभ उठानेवालों के लिए यह आवश्यक था कि वे उपर्युक्त धर्मों का अनुयायी होने से इनकार कर दे। अब तो क़ानून मे ऐसा परिवर्तन हो गया है कि दोनों सम्बन्धित पक्षों की स्वी-कृति पर सब प्रकार के अन्तर्जातीय विवाह जायज माने जाय। इसमें वे विवाह भी आ गये, जो उपर्युक्त धर्मों की संस्कार विधि के अनुसार होंगे।

विधवाओं की दशा सुधारने के लिए स्वर्गीय पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से लेकर अब तक अनेक महानुभावों ने उनके पुनर्विवाह के प्रचार के लिए भारी प्रयत्न किया है। आधुनिक सहायकों में श्री गङ्गारामजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने सन् १९१४ ई० में विधवा-विवाह-सहायक सभा, लाहै।र, की स्थापना की, और सभा के खर्च के लिए लाखों की सम्पत्ति का दान दिया। कुछ सुधारकों का मत है कि केवल ऐसी ही बाल-विधवाओं का पुनर्विवाह हो सके, जिनका अपने पति से समागम न हुआ हो। दूसरे पच्च में वे सज्जन हैं जो विधवाओं को इन्द्रिय-संयम आदि का उपदेश देते हुए उनके लिए शिच्चित होने, अपनी आजीविका प्राप्त करने तथा समाज-सेवाओं में भाग लेने के योग्य होने की व्यवस्था चाहते हैं। निस्सन्देह बाल-विवाह आदि कुप्रथाओं के कारण विधवाएँ बहुत होती हैं, अतएव उनको रोकने से विधवाएँ बहुत कम हो जायंगी।

शिक्षित और योग्य स्त्रियाँ अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा उचित अधिकारों को प्राप्त करने का उद्योग करने लगी हैं। अब तो उन्हें अनेक स्थानों में म्युनिसपैलिटियों और कौंसिलों का मेम्बर चुनने तथा स्वयं मेम्बर बनने तक का अधिकार हो गया है। गत वर्षों

में वे मन्त्री भी रही हैं। सहृदय मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे ित्त्रयों के उत्थान में योग दें। हाँ, यह ध्यान रहे कि उन्नित की दौड़ में हमारी बहिनें मर्यादा का उल्लंबन न करें। कहीं कहीं शिक्षित स्त्रियों का रहन-सहन बहुत आडम्बरमय और ख़र्चीला हो गया है। उन्हें गृहस्थ-जीवन अरुचिकर जान पड़ता है। वे स्वच्छन्द मनोवृतिवाली हो गयी हैं। बच्चों का पालन-पोषण उन्हें भार प्रतीत होता है। वे सार्वजनिक जीवन में इतनी अधिक संलग्न हो जाती हैं कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत खुकमय हो जाता है। स्मरण रहे कि उन्हें जितनी आवश्यकता नागरिका बनने की है, उसकी अपेक्षा इस बात की ज़रूरत कम नहीं है कि वे भावी नागरिकों को सुयोग्य बनानेवाली भी हों। सन्तान को गुणवान बनाना बहुत-कुछ माताओं पर ही निर्भर होता है।

हिन्दुश्चों के सम्बन्ध में इतना विचार करके श्रव हम श्रन्य समाजों की जागृति का विचार करते हैं।

मुसलमानों में समाज-सुधार — मुसलमानों में समानता तथा एकता बहुत है, इनके रस्मों-रिवाज़ सरल हैं। साधारणतया इनमें बहुत फ़िज्लख़र्ची नहीं होती। तथापि कुछ सामाजिक सुधारों की आवश्यकता थी। इनके रहन-सहन में कृतिमता होती है। मुसलमान-स्थियों चिरकाल से पदें में रहती आयी हैं। उससे इनका स्वास्थ्य अञ्छा नहीं रहा। शिचा में तो स्थियों क्या पुरुष भी बहुत पिछुड़े हुए थे। इनकी जागृति में अन्यान्य सज्जनों में, सर सैयद अहमद ख़ां का अञ्छा भाग रहा है। आपने समाज-सुधार के विषय में खूब प्रचार किया, 'तहज़ीब-उल-इख़लाक' नामक एक मासिक-पत्र भी निकाला तथा

शिद्धा प्रचार का भी बहुत उद्योग किया। इसके फल-स्वरूप मुसल-मानों में कहरता की कमी होती गयी। श्रव स्त्रियों में पर्दे का बन्धन पहले की श्रपेक्षा शिथिल है। उनमें शिद्धा का प्रचार बढ़ रहा है, श्रौर कुछ ने तो श्रॅगरेज़ी शिक्षा का भी स्वागत किया है। मुसलमान-स्त्रियाँ स्वयं भी श्रपनी दशा उन्नत करने के लिए जहाँ-तहाँ सभाएँ श्रादि करके श्रपने वर्ग में सुधार कर रही हैं, तथापि श्रभी गित मन्द है श्रौर प्रतिक्रियावादियों की प्रधानता है।

अन्य जातियों में प्रकाश—हिन्दू और मुसलमानों के अतिरिक्त, जाग्रति का प्रभाव यहाँ की और भी जातियों में हुआ है। ईसाइयों में यद्यिप बहुतों के सामाजिक व्यवहार अपने पूर्वज हिन्दुओं के समान ही हैं, परन्तु वे अंधकार-काल में घुसी हुई हानिकर रीति रस्मों को त्याग रहे हैं तथा स्वच्छता और शिक्षा के विषय में अपनी श्रेणी के हिन्दुओं से आगे बढ़ रहे हैं। पारसी भी रहन-सहन, शिक्षा और सफ़ाई आदि में यहाँ के योरियन लोगों से अच्छी टक्कर लेते हैं। इनमें समयानुक्लता का विचार बहुत बढ़ा-चढ़ा है। ये देश-काल की गिति को परखकर तदनुसार उन्नित करने में अग्रसर हैं।

श्रव इम एक ऐसे सामाजिक विषय का विचार करते हैं, जिसकी श्रोर सुधारकों एवं सरकार का ध्यान श्राकर्षित हो रहा है, एवं होना चाहिए। यह प्रश्न है, भारतवर्ष की जन-संख्या का।

जन-संख्या का पश्न — भारतवर्ष की जन-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यद्यपि यहाँ मृत्यु-संख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक है, परन्तु जन्म-संख्या उससे भी अधिक होने से, कुल मिलाकर जन-संख्या की वृद्धि ही हो रही है। जैसा आगे बताया जायगा, भारतवासियों की आर्थिक अवस्था इस समय भी शोचनीय है। ऐसी दशा में जन-संख्या की निरंतर वृद्धि होते रहना चिन्तनीय है। इसका परिणाम अकाल या महामारी आदि होता है। जन-संख्या वृद्धि का कुछ कारण यहाँ की जल-वायु की उष्णता, अशिक्षा और निर्धनता है। देश में शिक्षा-प्रचार तथा आर्थिक उन्नति होने पर जन-संख्या की वृद्धि में कुछ रकावट होने की आशा है।

यहाँ हिन्दुओं में, जो अन्य सब जातियों के आदिमयों से अधिक संख्या में हैं, विशेषतया कन्या का विवाह अनिवार्य माना जाता है। पुत्र-प्राप्ति धार्मिक कृत्य समभा जाता है। सम्भवतः अति प्राचीन काल में इस प्रकार के विचारों के प्रचलित होने का कारण यह होगा कि भूमि बहुत थी, बस्ती नयी थी। जन-संख्या कम थी और उसे बढ़ाने की आवश्यकता बहुत थी। अब वह बात नहीं रही। परन्तु समाज में कोई विचार एक बार घर कर लेने के बाद सहसा नहीं हटता। शिद्धा आदि के यथेष्ट प्रचार न होने से अधिकांश भारतवासी स्वतंत्र चिन्तन करके प्राचीन प्रथा या रीतियों और विचारों में देश-काल के अनुसार सम्यक् परिवर्तन नहीं करते।

इसके अतिरिक्त, प्राचीन काल में इस विषय की जो मर्यादाएँ थीं, वे भी अब नहीं रहीं। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि पुरुष-स्त्री योग्य आयु के होकर विवाह करते थे; फिर गृहस्थाभम भी चार आश्रमों में से एक था, शौर उसकी अविध भी पचीस वर्ष की रखी गयी थी। इसके बाद सन्तानोत्पत्ति बन्द हो जाती थी। विगत शताब्दियों में, इस देश में

बाल-विवाह प्रचलित हो गया श्रीर, विवाह होने के बाद लोग श्राजीवन गृहस्थाश्रम में रहने लगे। पुरुष की एक स्त्री के मर जाने पर दसरा. तीसरा, श्रीर कुछ दशाश्रों में चौथा विवाह भी होने लगा। परिग्राम यह हुआ कि एक आर तो अनेक छोटी उम्र के लड़के लड़कियों की सन्तान होने लगी, दूसरी श्रोर कितने-ही बूढ़े श्रादमियों के बेमेल विवाहों से जन-संख्या की वृद्धि हुई। इन शिशुश्रों का दुर्वल, रोगी, श्रल्पायु होना स्वाभाविक ही था। जैसा पहले कहा गया है, श्रव कुछ समय से इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है। हाँ, श्रीर भी बहुत-कुछ सुधार-कार्य होने की गुंजायश है। शिक्षा-प्रचार, श्रार्थिक संघर्ष, कुछ लोगों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा रखने श्रीर स्वच्छंद जीवन बिताने की इच्छा श्रादि से भी जन-संख्या की वृद्धि पर कुछ रकावट होने लगी है; तथापि वर्तमान श्रवस्था में यह समस्या विद्यमान है। श्रव से कुछ समय पहले तक. इसे हल करने के लिए सन्तानीत्पत्ति मर्यादित रखने का एक-मात्र उपाय इन्द्रिय-निम्रह समभा जाता था। आधुनिक काल में कुत्रिम साधनों का उपयोग बढ़ता जाता है। निस्सन्देह वर्तमान -समय में जनता की वृद्धि को यथा-सम्भव रोकना आवश्यक है, परन्तु इसके लिए हम स्त्री-पुरुषों का संयमी जीवन व्यतीत करना ही उचित -समकते हैं।

भारतीय समाज की कमज़ोर कड़ी—किसी भी विचार-शील ब्रादमी को यह बात ब्राश्चर्यंजनक प्रतीत होगी, कि भारतीय जनता के इतने विशाल होते हुए भी, यह देश संसार में ऐसा गया बीता है। बात यह है कि भारतीय समाज सुसंगठित नहीं है। इसकी विविध कड़ियों में से कई-एक बहुत ही कमज़ोर हैं। महिलाओं, अछूतों, और भिखारियों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। इनके अतिरिक्त, जरायमपेशा लोगों तथा वेश्याओं का भी प्रश्न विचारणीय है।

यह तो ठीक है कि किसी जाति में अपराध करनेवाले कम होते हैं, श्रीर किसी में ज़्यादह। परन्तु किसी जाति को 'जरायमपेशा' करार देना या घोषित करना सर्वथा अनुचित है। लोगों का अपराधी होना बहुत-कुछ उनकी परिस्थित पर निर्भर होता है, और सामाजिक वातावरण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर हमने विस्तार-पूर्वक अपनी 'अपराध चिकित्सा' पुस्तक में लिखा है। यहाँ यही वक्तव्य है कि यदि अपराधियों के साथ कढोरता न करके सहानु-भृति का व्यवहार रखा जाय, और उनके सुधार का प्रयत्न किया जाय, तो इसमें क्रमश: बहुत सफलता मिल सकती है।

अब वेश्याओं की बात लीजिए। उन्हें घृिषात या उपेक्षित कह कर, समाज को निश्चिन्त नहीं रहना चािहए। 'पितत बिहनों' में से अधिकांश अपना घंघा आर्थिक या सामाजिक मजबूरी से करती हैं। यदि उनके योग्य आजीविका के मार्ग निकाले जायें तो इनमें बहुत-सी अपनी सेवा और योग्यता से देश का बड़ा हित कर सकती हैं। कितनी-ही वेश्याएँ एहस्थ जीवन की इच्छुक हैं। इनके सुधार का उपाय यह है कि ऐसे आदमी यथेष्ट संख्या में मिलें, जो साहस-पूर्वक इनसे विवाह-सम्बन्ध करें, और इन्हें अपनी एहिंगी के रूप में स्वीकार करें। पुनः वेश्याओं में से जो अपने पितत व्यवसाय को छोड़ चुकी हैं. और एहस्थ-जीवन में प्रवेश करना भी नहीं चाहतीं, वे स्वयं-सेविकाएँ

बनकर आगे बढ़ें, और अपनी अन्य वेश्या बहिनों को सुमार्ग पर लाके का प्रयत्न करें।

सरकारी सहयोग—समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह बात बहुत विचारणीय है कि इसमें सरकारी सहयोग कहाँ तक उपयोगी है। अनेक पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक सुधार के वास्ते सरकारी क़ानून बन जाना चाहिए। हमारा स्पष्ट मत है कि ऐसा परावलम्बन ठीक नहीं। यद्यपि कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं, जो सरकारी क़ानून के द्वारा यथेष्ट रूप से कार्य में परिण्त हो सकती हैं। परन्तु वे बहुत थोड़ी हैं। समाज-सुधार का अधिकांश कार्य हमारे ही करने का है, उसके लिए कौंसिलों के प्रस्तावों की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है लोकमत तैयार करने की। बिना लोकमत, सरकार भी समाज-सुधार में सफलता-पूर्वक अप्रसर नहीं हो सकती हैं, लोकमत तैयार करने का कार्य अच्छी तरह ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो स्वयं अपने व्यवहार में अच्छा उदाहरण उपस्थित करते हों।

सेवा-भाव—हर्ष का विषय है कि देश में स्वयंसेवको तथा सेवा-भाववाले अन्य सज्जनों की वृद्धि होती जा रही है। दुर्भिन्न, बाढ़, महामारी तथा मेले-तमाशों के समय सेवा-सितियाँ और सेवा-दल महत्व-पूर्ण कार्य करते हैं। अनेक अवसरों पर, अपनी जान-जोख़म में डाल कर, दूसरों के। सक्कट से बचाने, लावारिस मुदें उठाने और उनका अन्त्येष्टि संस्कार करने में उन्होंने अपने हृदय की उदारता का सुन्दर परिचय दिया है। जैसे बने, जहाँ बने, सेवा करना इनका उद्देश्य है। ये हिन्दू-मुसलमान, छूत-अछूत, स्त्री-पुरुष, कँच-

नीच, या अपने पराये का भेद-भाव नहीं जानते; जाति-विशेष और प्रांत विशेष का पक्ष नहीं लेते। सूर्य की भाँति, इनके प्रेम का प्रकाश सर्वत्र होता है। इस प्रकार का सेवा-भाव समाज संघार और सामाजिक जारित में विलच्च सहायक होता है। निस्तदेह श्रभी तक कुछ व्यक्ति समाज-सेवा करने में भी अपनी जाति या धर्म के आदमियों का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ संस्थाएँ तो ऐसी है. जिनका उद्देशय एक मात्र अपने ही वर्ग के आदिमयों का हित करना होता है। यह बात हमारी अनुदारता की सूचक है। कम-से-कम, सङ्कट के अवसर पर तो हमें अपनी जुद्रता को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक मुसल-मान तथा प्रत्येक ईसाई श्रादि मानव समाज का श्रङ्ग है, परमात्मा की सन्तान है। उसकी सहायता करने में श्रपने-पराये का विचार न कर हमें विशाल भ्रातृ-भाव का परिचय देना चाहिए। हमें अपने व्यवहार से प्रमाणित करना चाहिए कि इम मनुष्य के बनाये हए बनावटी तंग दायरों से बाहर की बात भी सोच सकते हैं, इस मनुष्य समाज का यथार्थ रूप पहिचान सकते हैं। तभी इम अपने सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दे सकेंगे।



## उन्तीसवाँ परिच्छेद अार्थिक स्थिति

मिरितीय जनता के पेशे—भारतीय जनता श्रिषकांश में गाँवों में रहती है, श्रीर यहाँ लोगों का सब से प्रधान पेशा कृषि है। विछली मनुष्य-गणना के श्रनुसार भिन्न-भिन्न पेशों का कार्य करनेवाले तथा उनके श्राश्रितों का कुल जनता में प्रतिशत श्रनुपात इस प्रकार थाः—

कृषि ६७, उद्योग-धंघे ९७, यातायात १५, व्यापार ५४, सेना और सरकारी नौकरियां १३, पढ़ना-लिखना १७, घरेलू नौकर, अनिश्चित आययाले, और मिखारी आदि अनत्पादक १३७।

इन पर क्रमशः विचार किया जाता है।

कृषि-सम्बन्धी सुधार — प्राचीन काल में यह देश अपने तैयार माल और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। मुग़ल शासन के अधिकांश समय में भी यहाँ का कला-कौशल और शिल्प-चातुर्य बाहरवालों के लिए नमूना बना रहा। परन्तु कम्पनी के शासन-काल में यहाँ की उत्तमोत्तम दस्तकारी नष्ट करके इसे ज़बरदस्ती कृषि-प्रधान (ब्रिटिशः कारख़ानों के लिए कञ्चा माल देनेवाला ) बनाया गया । जनता का भला-बुरा निर्वाह एक-मात्र खेती से होने लगा । फिर खेती की दशा भी अञ्छी न रही । यहाँ अति प्राचीन काल से कहावत चली आरही थी कि 'उत्तम खेती, मध्यम बान (न्यापार), निषिद्ध चाकरी, भीख निदान।' कम्पनी के समय में अनेक किसानों को भर-पेट मोजन और शरीर ढकने को वस्त्र तक का अभाव हो गया। पीछे क्रमशः सुधार हुआ।

कृषि-सम्बन्धी सुधारों की तीन श्रवस्थाएँ कही जा सकती हैं-

- (१) सरकार ने जो सुधार किये, वे विशेषतया अपनी सुविधा या आय-वृद्धि के लिए किये, अथवा अङ्गरेज़ों के हित के लिए किये। भारतीय जनता की दशा सुधारने का उसका लक्ष्य न था।
- (२) सरकार ने जनता की दशा सुधारने की कोशिश की, पर उसी सीमा तक, जहाँ तक सरकार की हानि न हो। फल-स्वरूप जो सुधार हुए, वे बहुत महत्व के नथे।
- (३) प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने पर जो सुधार किये गये, उनका मुख्य लक्ष्य जनता की दशा को सुधारना रहा।

श्रदारहवीं सदी में कम्पनी ने यहाँ भूमि से श्रधिक से श्रधिक से मालगुज़ारों वसूल करने का प्रयत्न किया। उसने बड़ी कड़ाई श्रीर निर्दयता से काम लिया, यह श्रव मली मौति सिद्ध है। उसका फल यह हुआ कि मालगुज़ारी वसूल होनी किंदन हो गयी, ज़मीन परती पड़ी रहने लगी। श्रन्ततः लार्ड कार्नवालिस ने सन् १७९३ में बङ्गाल में मालगुज़ारों का 'स्थायी प्रवन्ध' (इस्तमरारी बन्दोबस्त) कर दिया। यह निश्चय किया गया कि सरकार को निर्धारित परिमाण में मालगुज़ारी

मिले, भविष्य में ज़मीन के सुधार और उन्नति से जो आय बढ़े, उसका लाम ज़मीदारों को मिले। उस समय अधिकारियों का विचार अन्य प्रांतों में भी ऐसी ही व्यवस्था करने का था, पर पीछे स्वार्थ-वश ऐसा नहीं किया गया।

सन् १८६६ में सरकार ने भारतीय कृषि-विभाग की स्थापना की। इसके सम्बन्ध में स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त शाही कृषि-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "यह विभाग इंगलैंड के कपास के व्या-पारियों की इच्छात्रसार १८६९ में फिर हाथ में लिया गया। भारत-सरकार की कृषि-नीति प्रायः इन्हीं व्यापारियों की इच्छानुसार निर्धा-रित होती रही है।" पीछे इस विभाग ने अमरीकन कपास, मिश्र की तमाखू तथा विदेशी गेहूँ श्रादि वस्तुश्रों को यहाँ पैदा करने के श्रनेक प्रयोग इस उद्देश्य से किये कि यदि इनकी काश्त यहाँ श्रच्छी होने लगे तो ब्रिटिश पूँजीपति यहाँ आकर इनका कारोबार कर सकें। यह प्रयोग प्राय: असफल रहे और इनसे केवल प्रसंगवश ही भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि में उचित खादों के उपयोग, उत्तम प्रकार के बीज, पौदों के रोग, उनकी चिकित्सा, नये प्रकार के हलों, मशीनों न्त्रीर श्रीजारों के उपयोग तथा खेती करने के नये तरीकों का ज्ञान प्राप्त हुआ। परन्तु इस ज्ञान का सर्वसाधारण में प्रचार करने का सन्तोषजनक प्रयत्न नहीं किया जाता। यहाँ एक इम्पीरियल कृष-अनुसंधान-समिति (रिसर्च कौंसिल) है; कुछ ख़ास-ख़ास नगरों में चीनी, द्ध, मक्खन, रुई श्रादि के लिए भी श्रनुसंधान-संस्थाएँ हैं। इनके सम्बन्ध में भी ऊपर कही बात चरितार्थ होती है।

अब इम कृषि सम्बन्धी सुधारों की दूसरी अवस्था का विचार करते हैं।

पहले कुछ स्थानों में, विशेषतया बंगाल में, ज़र्मीदार किसानों को बहुत सताते थे, और उनसे मनमाना लगान वसूल करते थे। अब सरकार ने किसानों को बचाने के लिए प्रत्येक प्रान्त में कुछ काश्तकारी कानून बना दिये। सरकार किसानों को कुछ रुपया उघार भी देने लगी। इस प्रकार दी जाने वाली रक्तम को 'तकाबी' कहते हैं। सन् १८८३ में भूमि की उन्नति के लिए और १८८४ में किसानों की सहायता के लिए, इस सम्बन्ध में कानून पास हुए। परन्तु किसानों की संख्या तथा आवश्यकता को देखते हुए 'तकाबी' में दो जानेवाली रक्तम बहुत कम रही है।

किसानों को महाजन आदि के भारी सूद से बचाने के लिए सरकार ने सन् १९०४ ई० में सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में एक क्रानृत बनाया, इसमें पीछे कुछ संशोधन हुआ। तदनुसार अब प्रत्येक प्रान्त में तीन प्रकार के सहकारी बैंक हैं। (१) ग्रामीय बैंक; जिसे एक ग्राम या पास-पास के कई गाँवों के दस-दस या अधिक आदमी मिलकर बना लेते हैं। (१) शहरी बैंक; जो एक नगर के शिल्पकारों, व्यापारियों, मज़दूरों आदि की सहायतार्थ बनाये जाते हैं। (१) सेंट्रल बैंक; जो उपर्युक्त दो प्रकार के बैंकों को धन की सहायता देते हैं। इन बैंकों का प्रबन्ध स्थानीय सहकारी समितियों के समासद ही करते हैं। और, रूपया समासदों को ही उधार मिल सकता है, सो भी उत्पादक कार्यों के लिए ही। अर्थात, इन बैंकों से ऋषा लेकर फ़िज़ुलखर्ची नहीं की

जा सकती। सहकारी बैंकों की, इस निर्धन देश में अत्यन्त आवश्यकता है; पर यहाँ इनका प्रचार अभी बहुत कम है।

भारतवर्ष में, नहरों के निर्माण में, विशेष ध्यान इसी शताब्दी में दिया गया है। सन् १९०३ ई० के आवपाशी-कमीशन की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कई नहरें बनवायी हैं। पंजाब में नहरें निकालने से कई जगह अब्छी सुन्दर नहरी बस्तियाँ हो गयी हैं। इनकी पैदावार तथा आबादी पहले से कई गुना बढ़ गयी हैं। संयुक्त-प्रान्त में शारदा-नहर निकाली गयी है; इससे कई लाख एकड़ मूमि में आवपाशी होगी। सिंघ में सक्खर बांघ बनाया गया है, जिससे सिंघ की लाखों एकड़ बंजर भूमि हरी-भरी और ख़्व उपजाऊ होने की आशा है। तथापि इस समय लगभग १६०० लाख एकड़ अर्थात् ७५ प्रति सेकड़ा जोती हुई भूमि केवल वर्षा के आश्रित है। यह ठीक नहीं। नहरों की बृद्धि की यहाँ बहुत आवश्यकता है; विशेषतया दक्षिण मालवा, गुजरात, मध्यप्रान्त और राजपूताने के अनिश्चित वर्षावाले इलाकों में।

कृषि-सम्बन्धी सुधारों की वर्तमान अवस्था सन् १९३७ ई॰ से आरम्भ होती है, जब से नये शासन-विधान का प्रांतों-सम्बन्धी भाग अमल में आया, और प्रांतीय सरकारें जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हुई। कांग्रेस तो जनता की ही है; उसने पदारूढ़ होते ही किसानों के कहों की ओर ध्यान दिया। संयुक्तप्रांत और बिहार आदि प्रांतों में लगान और मालगुज़ारी के संशोधन सम्बन्धी क्वानून बनाये गये हैं। इन क्वानूनों से किसानों को सुधार की अच्छी किश्त मिल गयी है। किसानों-सम्बन्धी समस्याएँ—अब हम कुषको-सम्बन्धी

उन समस्याश्चों पर विचार करते हैं, जो इस समय बारम्बार हमारे सम्मुख श्चाती हैं। पहले खेतों के बँटवारे की बात लें। भारतवर्ष में बहुत से खेतों का चेत्रफल बहुत थोड़ा रहता है—प्रायः एक एक दो-दो एकड़ मात्र। कितने-ही खेत तो श्चाघे-श्चाघे एकड़ या उससे भी छोटे हैं। प्रत्येक कृषक-परिवार के पास इतनी भूमि श्चवश्य होनी चाहिए कि उसकी उपज की श्चाय से उसका साधारणतया श्रच्छी तरह निर्वाह हो सके। यहाँ बहुत-से किसानों के पास एक-एक से श्चिक खेत हैं, जो एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। इनमें काम करने में समय, शक्ति श्चीर द्रव्य का श्चपव्यय होता है, श्चीर बहुधा किसानों का बीच की ज़मीनवालों से भगड़ा भी होता रहता है। इसका शीध श्चन्त किया जाना चाहिए। इसका उपाय यह है कि प्रत्येक किसान की जोत के खेत एक स्थान में, एक 'चक' में हो जायँ, श्चीर भविष्य में उनका छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाना कानून द्वारा रोक दिया जाय।

भारतवर्ष का बहुत-सा हिस्सा ऐसा है, जिसमें ज़मींदारी या ताल्लुक़ेदारी प्रथा है। ऋँगरेज़ी सरकार से पहले ज़मींदार आदि एक प्रकार के राजकीय कर्मचारी थे, जो लगान वसूल करके सरकारी ख़ज़ाने में भेजते थे। ऋँगरेज़ी सरकार ने देश में अपनी सत्ता जमाने में सहा-यता प्राप्त करने के लिए उनका मान और प्रतिष्ठा बढ़ा दी। इस पर वे अपने आपको ज़मीन का मालिक समक्तने लगे। किसान जितना लगान देते हैं, उसका बङ्गाल में बहुत बड़ा हिस्सा, तथा अन्य प्रान्तों में आधा या उससे भी अधिक भाग, उन्हें मिल जाता है। उन्हें प्रायः बिना परिश्रम ही भोग-विलास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते

हुए, और किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करने की दशा में भी यथेष्ट भोजन-वस्त्र से वंचित रहते हुए देखकर अनेक हृदयों में ज़र्मी-दारी प्रथा के विरुद्ध प्रवल भाव उठ रहे हैं।

जमींदारों का लगान-वस्तुली का काम सरकारी कर्मचारियों द्वारा बहुत कम ख़र्च में कराया जा सकता है, जैसा कि रैयतवारी प्रान्तों (मदरास श्रादि) में हो रहा है। ज़मींदारों को इतनी श्राधिक श्राय क्यों होनी चाहिए, जब कि देश की श्रार्थिक दशा श्रव्छी नहीं है, श्रीर जनता के हित के श्रनेक कामों के लिए द्रव्य की श्रत्यन्त कमी है! इस विचार से सन् १९३७ ई० से बिहार में ज़मींदारों की श्राय पर 'कृषि-श्राय-कर' लगाया गया है। परन्तु श्रनेक श्रादमी इसी से संतुष्ट नहीं हैं। कितने-ही नेताश्रों का मत है कि ज़मींदारों को कुछ मावज़ा या प्रतिफल (जिसकी मात्रा देश-काल के श्रनुसार निश्चित की जाय) देकर ज़मींदारी प्रथा उठा दी जाय। भूमि का राष्ट्रीयकरण हो जाय। भूमि उन्हीं लोगों के पास रहे, जो खेती करें श्रीर, सरकार किसानों से सीधा सम्बन्ध रखे।

परन्तु इसी से ही किसानों की आर्थिक समस्या हल नहीं हो जायगी।
आवश्यकता इस बात की है कि सरकार किसानों से मालगुज़ारी उचित
मात्रा में ले। उपज का ठीक हिसाब लगाया जाय, उसमें से पूरा
लगान ख़र्च घटाया जाय। फिर जो आय रहे, उस पर ही सरकार
निर्धारित दर से मालगुज़ारी ले। वर्तमान अवस्था में उपज का मूल्य
बढ़ा कर, और लागत-ख़र्च घटाकर हिसाब लगाया जाता है। अनेक
किसानों को मालगुज़ारी अपनी मज़दूरी में से देनी पड़ती है, इसलिए

उन्हें कई महीने कुछ मूखा रहना पड़ता है। स्मरण रहे खेती के लागतख़र्च में किसान और उसके कुटुम्ब के उन लोगों की मज़दूरी अवश्य
सम्मिलत होनी चाहिए, जो खेती पर काम करते हैं। यदि इस तरह
लागत-ख़र्च ठीक लगाया जाय तो बहुत-से खेत ऐसे निकलेंगे, जिनकी
आमदनी लागत-ख़र्च से कम होगी। इस प्रकार के खेत जोतनेवालों
से मालगुज़ारी लेना किसी भी दशा में उचित नहीं है। सरकार
को मालगुज़ारी उन्हीं किसानों से लेनी चाहिए, जिनका मरण-पोषण
अच्छी तरह होता हो। साथ ही मालगुज़ारी की दर वर्द्धमान होनी
चाहिए, अर्थात् जैसे-जैसे किसानों की (विशुद्ध) आय अधिक हो,
वैसे-वैसे मालगुज़ारी बढ़ती जानी चाहिए।

श्रव किसान जाग रहे हैं, श्रपना संगठन कर रहे हैं। श्राशा है, वे श्रपनी श्राधिक श्रीर सामाजिक उन्नति करने में सफल होंगे; उनसे प्रत्येक देश-हितेषी की सहानुभृति है। हां, उन्हें भी देश के श्रन्य समूहों के हितों का यथेष्ट ध्यान रखना चाहिए।

उद्योग-धन्धे — पहले कहा जा चुका है कि अति प्राचीन काल से भारतवर्ष तैयार माल में न केवल स्वावलम्बी था, वरन् अन्य देशों की भी बहुत-सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। सत्ररहवीं ही नहीं, अठारहवीं शताब्दी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों तथा अन्य पदार्थों के लिए सारा योरप लालायित रहता था। परन्तु पीछे यह देश वैज्ञानिक उन्नति से लाभ न उठा सकने के, कारण सांसारिक घुड़दौड़ में दूसरे देशों से पीछे रह गया। साथ ही शासकों की व्यापार-नीति ऐसी प्रतिकृत रही कि इस देश से तैयार

माल की रफ्तनी दिनोंदिन घटती गयी। शाल, मलमल श्रादि स्ती रेशमी श्रीर ऊनी वस्त्र, शकर तथा श्रन्य पदार्थों का, करों की श्राधिकता के कारण, विलायत जाना कम हो गया; यह देश केवल रुई, श्रन्न, सन, ऊन, रेशम श्रादि कचा माल बेचनेवाला रह गया। श्रॅगरेज़ों का हित इसी बात में था कि भारतवर्ष उन्हें इंगर्लेंड के कल-कारख़ानों के लिए कच्चे पदार्थ दे।

श्रस्तु, यहां उद्योग-धंघों की दशा बहुत चिन्तनीय हो गयी।
श्राख़िर सन् १८०५ ई० से नेताश्रों का ध्यान इस श्रोर जाने लगा। स्त
कातने श्रीर कपड़ा बुनने की मिलें चलने लगीं। लोहा, फौलाद श्रादि
का माल तैयार करने के भी कई कारख़ाने खुले। इस श्रीद्योगिक
उन्नति में जे० एन० टाटा (जमसेदजी नौशेरवानजी टाटा) का नाम
प्रसिद्ध है। उन्होंने बंगलोर में एक वैज्ञानिक श्रनुसंघान-संस्था भी
स्थापित की।

क्रमशः लोगों में स्वदेशी वस्तुत्रों के उपयोग की मावना बढ़ने लगी। स्वदेशी आन्दोलन को सन् १९०५ ई० के बंग-विच्छेद से बहुत उत्तेजना मिली। इस समय से विदेशी वस्तुत्रों का विद्कार आरम्भ हुआ। पर आवेश में आरम्भ होने के कारण इन बातों का आधार हढ़ न था। कुछ समय बाद इसमें शिथिलता आगयी। तथापि इससे लोगों के अनुभव में अच्छी वृद्धि हुई, और कुछ वस्तु औं के कारखाने स्थायी रूप से चलने लगे। सन् १९१९ ई० में तथा उसके बाद जब राष्ट्रीय आन्दोलन समय-समय पर व्यापक रूप से हुआ, तो उसका एक मुख्य अंग विदेशी-वस्तु-विद्कार भी रहा है। इसका लक्ष्य देश को, विशेषतया वस्त्र-व्यवसाय में, स्वावलम्बी बनाना है।

इस समय यहाँ कल-कारख़ानों की स्थित बहुत असंतोषप्रद है। रेल, ट्रामवे, सोने श्रीर कोयले की खानें, सन, ऊनी वस्त्र, कागज़ पीतल, मिट्टी-के तेल के कारख़ाने और बड़े-बड़े बैंक प्रायः श्रॅगरेजों, के द्वाथ में है। भारतवाही केवल स्ती कपड़ों की मिलों, फ़ौलाद लोहा, चीनी श्रौर वर्फ के कारख़ानों श्रौर श्राटा पीसने की कलों श्रादि के ही मालिक हैं। यहाँ के कारखानों में मज़द्रों की दशा भी अञ्जी नहीं है। यहाँ मज़द्रों के सम्बन्ध में एक क़ानून है, जिससे उनके काम करने के घंटों की सीमा निर्धारित है, तथा कारख़ानों में सफ़ाई रोशनी श्रादि का यथेष्ट प्रबन्ध करने श्रीर मज़द्रों को चोट-चपेट न लगने देने की कुछ व्यवस्था की गयी है। परन्तु यह क़ानून बहुत अधूरा है। इससे मज़दर बहत अरिच्चत अवस्था में रहते हैं। उनके लिए यथेष्ट स्थान का प्रबन्ध नहीं होता, उन्हें बाल-बच्ची सहित तंग, श्रंधेरे श्रीर गंदे मकानों में रहना होता है । ये दुखमय जीवन बिताते हैं. श्रीर प्रायः श्रल्पायु में ही मर जाते हैं। यह परिस्थिति चिन्तनीय है।

कुछ सजनों का मत है कि जब तक समाज का वर्तमान संगठन बना रहेगा, साधारण क़ानूनों द्वारा मज़दूरों की स्थिति में विशेष परिवर्तन न होगा। यथेष्ट सुधार के लिए उत्पत्ति और विनिमय के साधन किसी विशेष श्रेणी के हाथ में न रहकर सर्वसाधारण जनता अर्थात् उत्पादकों के हाथ में रहने चाहिएँ। इस व्यवस्था को समाजवाद कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में विशेष इस पुस्तक के पहले भाग में लिखा जा चुका है।

द्रतकारियों का पुनरुद्धार—श्रमेक सजनों का विचार है कि श्रमजीवियों का वास्तविक हित-साधन तभी होगा जब वे कल-कारख़ानों में दासता का जीवन न विताकर, प्राचीन काल की भौति स्वतंत्र रूप से श्रम करनेवाले होंगे, वे दस्तकारियों के काम में लगेंगे। इससे वे श्रपने घर में, श्रपने परिवार के श्रादमियों के साथ रहेंगे, रूखी-सूखी रोटी खाकर भी सुखी और संतुष्ट रहेंगे, मद्यपान, विलासिता श्रादि के प्रलोभन में फंसने से बचेंगे। उनका शरीर स्वस्थ होगा और उनकी श्रात्मा भी बलवान होगी।

दस्तकारियों में हाथ की कताई-चुनाई का काम प्रमुख है। इसके पुनरुत्थान का संगठित प्रयत्न सन् १९२५ ई० से हुआ, जब कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ की स्थापना हुई। स्थान-स्थान पर इसके सैकड़ों खादी-केन्द्र हैं। इस घंघे द्वारा अनेक खुलाहों, बढ़ई, खुहार, रंगसाज़ एवं व्यापारियों आदि को काम मिल रहा है। प्राम-संगठन का भी अच्छा कार्य हो रहा है। अन्य उद्योग-धंघों की ओर कांग्रेस ने सन् १९३४ ई० के अन्त में ध्यान दिया। वर्घा (मध्यप्रान्त) में अखिल-भारत-ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में हुई। इसका उद्देश्य है, आमों का पुनः संगठन करना, ग्रामोद्योगों को उत्साहित करना तथा उनमें आवश्यक सुधार करना, और ग्राम-निवासी जनता की नैतिक और शारिरिक उन्नति की चेट्टा करना। उपर्यंक संघ की संरक्षकता

में निम्नलिखित ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं-

१ धान से चावल निकालना, २ श्राटा पीसना, ३ गुड़ बनाना, ४ तेल निकालना, ४ मूँगफली छीलना, ६ शहद की मिनख्यां पालना, ७ मछली पालना, ६ दूध-शाला, ९ नमक बनाना, १० कपास लोढ़ाई, ११ कम्बल बनाना, १२ रेशम श्रोर टसर का माल बनाना, १३ सन की कताई-बुनाई, १४ कालीन बनाना, १५ कागज़ बनाना, १६ चटाई बनाना, १७ कंधियाँ बनाना, १८ चाकू क्रैंची श्रादि बनाना, १९ साबुन बनाना, २० पत्थर की कारीगरी, २१ मरे हुए जानवरों की लाशों का उपयोग करना श्रोर चमड़ा तैयार करके उसकी विविध वस्तुएँ बनाना।

सर्वशाधारण को अवकाश के समय घर उद्योग-धंधों की उन्निति में यथा-सम्भव भाग लेना चाहिए। खेती करनेवाले तो साल में कई महीने बेकार रहते हैं। ऐसे समय उन्हें चाहिए कि अपनी सुविधानुसार खेतों में तरकारी ( शाक ) आदि उत्पन्न करने के अतिरिक्त, मूंज या सन की रिस्सियों बटें; टोकरी, चटाई, मोढ़े बनावें, कपास आटें, सूत कार्ते, या कपड़े बुनने आदि का काम करें।

उद्योग-धंधे और सरकार — सरकार उद्योग-धंधों की उन्नित में कई प्रकार सद्यायक हो सकती है — (१) वह प्रार्शमक संस्थाओं में श्रीद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करके बालकों में उद्योग-धंधों के प्रति श्राकर्षण उत्युक्त कर सकती है। यह काम यहाँ बहुत थोड़े परि-माणा में हो रहा है। इस बात की भी श्रावश्यकता है कि देश में बड़ी

बड़ी प्रयोगशालाएँ खोली जायँ, जिनमें उद्योग-धंघों-सम्बन्धी खोज की जाय। (२) स्थान-स्थान पर स्वदेशी वस्तुत्रों की प्रदर्शनियों तथा विज्ञापन की व्यवस्था होनी चाहिए. जिससे सर्वेसाधारण यह जान सकें कि कैसी कैसी वस्तएँ देश में कड़ाँ-कड़ाँ बनती हैं. श्रीर किस प्रकार बनायी जाती है। (३) उद्योग-धंघों के लिए एक प्रधान श्रावश्यकता पुँजी की रहती है। सरकार कभी-कभी बाज़ार-दर से कम ब्याज पर रुपया उधार देती या सहायता-रूप कछ ऐसा रुपया प्रदान करती है, जिसे वापिस नहीं लेती । सरकारी सहायता का एक रूप यह हो सकता है कि वह कुछ मशीनें उत्पादकों को किराये पर दे: एक निर्धा-रित अवधि तक किराया दे चुकने पर मशीनें उत्पादकों की हो जायँ। (४) सरकार अपने विविध विभागों की आवश्यकता के लिए सब सामान देशी ख़रीदे, यदि कोई वस्तु देश में न बनती हो तो उसके बनवाने की स्वयं व्यवस्था करे, श्रथवा दूसरों को सहायता या प्रोत्साहन देकर बनवावे । भारतवर्ष में सरकार, तथा सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त रेलवे कम्पनियाँ आदि, बहुत-सा माल विदेशों से मँगातो है, यह अनु-चित है। (५) सरकार विदेशी वस्तुत्रों के श्रायात पर भारी कर लगा कर उन्हें मँहगा कर सकती है। इससे स्वदेश में बनी हुई वे वस्तुएँ कुछ समय बाद सस्ती होकर, विदेशी वस्तुत्रों की प्रतियोगिता में उहर सकती हैं। इसे 'संरक्षण-नीति' कहते हैं। भारतवर्ष में सरकार को इस विषय में ब्रिटिश सरकार की इच्छा और ब्रिटिश व्यापारियों के हित का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले योरपीय महायुद्ध से पूर्व तो यहाँ उद्योग-घंधों का संरक्षण किया ही नहीं गया। सन् १९२१ ई० में सरकार ने

श्रार्थिक जाँच-समिति नियुक्त की। उसके बाद टेरिक्र-बोर्ड (श्रायात-निर्यात-कर समिति) की स्थापना हुई श्रीर उसकी सिक्रारिश के श्रमु-सार कमश्रः लोहे श्रीर की लाद के सामान, कागज़ कपड़े श्रीर चीनी को संरक्षण दिया गया। परन्तु काँच श्रीर सीमेंट के काम को भी संरक्षण दिया गया। परन्तु काँच श्रीर सीमेंट के काम को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके श्रातिरिक्त, श्रन्य वस्तुश्रों के सम्बन्ध में समय-समय पर जाँच होकर श्रावश्यकतानुसार संरक्षण देने की व्यवस्था होती रहनी चाहिए। इस श्रोर सरकार की गति बहुत मंद है। इसमें सुधार होने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। सरकार को श्रीद्योगिक उन्नति के विविध उपाय काम में लाने के लिए एक पंचवधींय योजना चनानी चाहिए, जिसका लक्ष्य यह हो कि भारतवर्ष श्रपनी सब प्रधान श्रावश्यकता श्रों को पूर्ति के लिए स्वावलम्बो हो जाय, वह किसी बात में परमुखापेक्षी न रहे।

व्यापार — भारतीयों को अपना व्यापार ज्ञान बढ़ाने की भी बड़ी आवश्यकता है। उन्हें केवल कमीशन या दलाली लेकर निर्वाह करते हुए व्यापारी नाम को लिजत नहीं करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि भारतवर्ष के लिए कौन कौन सी वस्तु तैयार होती हैं, वे चीज़ें यहाँ किस प्रकार तैयार को जा सकती हैं, भारतवर्ष का कौन सा पदार्थ संसार की अन्य मंडियों में नफ़ से बेचा जा सकता है। यहाँ से केवल कच्चे माल के कुछ जहाज हर साल विदेशों को भेज देना और विदेशों तैयार माल यहाँ खपा देना कितना हानिकर है! यहाँ के उद्योग धंधों की उन्नति के लिए क्या क्या साधन और परि-स्थिति अनुकुल होगों ?

सन् १९३४ ई० से यहाँ हाट-व्यवस्था के लिए भारत-सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विभाग की स्थापना हुई है, और कुछ स्थानों में फल, श्रंडों श्रौर चमड़े तथा खालों के सम्बन्ध में किस्में निर्धारित करने के केन्द्र खोले गये हैं। सन् १९३७ ई० में केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती से होनेवाले पदार्थों की कक्षा निर्धारित करने श्रौर निशान लगाने ('ग्रेडिंग' श्रौर 'मार्किंग') का कानून पास किया गया है। इस विभाग का काम उत्पादकों को भिन्न-भिन्न स्थानों के बाजारों की परिस्थित बताना श्रौर यह सुम्हाना है कि कहाँ कीनसी वस्तु की माँग घटने या बढ़ने की सम्भावना है। इस विभाग को सर्वसाधारण के सम्पर्क में श्राने की बड़ी श्रावश्यकता है।

गत वर्षों में यातायात की उन्नित के कारण देश के भीतर एक जगह से दूसनी जगह, तथा बन्दरगाहों से, माल का श्राना-जाना बढ़ा है। रेलों ने नयी सड़कों की माँग बढ़ा दी है, व्यापार के पुराने रास्तों को बदल दिया है, श्रीर नये व्यापार-केन्द्र खोल दिये हैं, जो रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं। रेलें श्रीर माल ढोनेवाली मोटरें पुराने ढक्क की बैलगाड़ियों तथा लहू जानवरों का काम कर रही हैं। किन्तु देश के भीतरी भागों में श्रमी उनकी पूरी पहुँच नहीं हुई है। सामान- दुलाई का खर्च कम हो गया है। माल ढोने की दर धीरे-धीरे कम हो जाने के कारण, भारतवर्ष के देशी श्रीर विदेशी व्यापार की वृद्धि में सहायता मिली है। श्रव बन्दरगाहों की उन्नित हो रही है; क्योंकि विदेशों का माल यहीं श्राकर देश भर में फैलता है। परन्तु श्रमी व्यापार के विविध साधनों की उन्नित की बहुत श्रावश्यकता है; साथ

ही रेलों और जहाज़ों आदि पर विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व होने से उनकी दर तथा नियमों से भारतीय व्यापार को यथेष्ट लाभ न हो कर बहुधा चिति पहुँचती है। उन पर भारतीय जनता का ही नियंत्रण होना चाहिए।

विनिषय और बैंक -विदेशी व्यापार पर विनिषय की दर का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समय भारत सरकार ने यहाँ के रुपये का मूल्य एक शिलिंग छ: पेंस अर्थात १८ पेंस निर्धारित कर रखा है। पहले यह समय-समय पर बदलता रहा है। कुछ समय पूर्व यह १६ पेंस था। भारतीय नेता चाहते हैं कि रुपये का मूल्य गिरा कर फिर १६ पेंस या इससे भी कम कर दिया जाय। वर्तमान बढ़े हुए भाव में हमें विलायत से माल मँगाने में तो लाभ है; एक रुपया देकर वहीं का १८ पेंस का माल मिल जाता है (पहले १६ पेंस का ही मिलता था )। इसी प्रकार रुपया विलायत के कारखानों में लगाने या बैंकों में जमा कराने से भी लाभ है। परन्त इससे यहां रुपये की कमी हो जाती है। मतलब यह कि विलायत में भगतान करने में लाभ है। परन्तु हमें अपना माल वहां भेजने में हानि है। विलायतवालों को श्रव उसके दाम (शिलिंग के हिसाब से ) श्रधिक देने पड़ते हैं, श्रतः वे इमारा माल कम मगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि विनिमय की दर बढ़ने से (जैसी कि इस समय है) इमारे शिल्प-व्यवसाय श्रादि को बहुत हानि पहुँचती है।

देश की आर्थिक उन्नति का बैंकों से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। भारतवर्ष में रिज़र्व बैंक और इम्पीरियल बैंक के अतिरिक्त, एक्सचेन्ज (विनिमय) बैंक, जोयंट-स्टाक (मिश्रित पूँजी के) बैंक तथा सहकारी बैंक श्रादि है। पर देश की विशाल जनता को देखते हुए के बहुत ही कम हैं, श्रोर इनका कारोबार भी बहुत थोड़ा है। रिज़र्व वैंक, बँकों का बैंक है, इसमें बैंकों का रुपया जमा रहता है, श्रोर यह उन्हें उधार देता है। इसे नोट निकालने का श्रिधकार है। पर इस पर सरकार का नियंत्रण तथा प्रभुत्व है, श्रोर यह उसी के द्वारा निर्धारित नीति से काम करता है, जो वर्तमान दशा में बहुधा जनता के हित के प्रतिकृत होता है।

भारतवासियों की निर्धनता, त्र्यौर उसे दूर करने के **उपाय-अ**ति प्राचीन समय से लेकर, श्रव से केवल दो सौ वर्ष पहले तक 'सोने की चिडिया' समभी जानेवाली, श्रीर दघ-दही की नदियों के नाम से विख्यात भारत-भूमि की आज दिन यह दशा है कि यहाँ करोडों ब्रादिमयों को रूखा-सूखा भोजन भी भर-पेट नहीं मिलता। जो देश अपने बनाये हुए वस्त्र से अन्य देशों के आदिमियों की लज्जा निवारण करता था. ऋाज अपनी संतान को शरीर ढकने और सर्दी गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं देता। ऐसा निर्धन है यह भारतवर्ष ! परन्तु बहुत-से श्रादमी इस बात पर विश्वास नहीं करते । वे बड़े-बड़े नगरों के विशाल भवनों की श्रोर संकेत करते हैं, विदेशों से श्रानेवाले वस्त्र, खिलौने श्रादि विसातख़ाने के धामान, मोटर, साइकलं, तेल, सांबुन आदि शौकीनी के सामान के आंक उपस्थित करते हैं, और कहते हैं कि भारतवासी सोने-चांदी के ज़ेवर पहनते हैं. श्रानेक त्यौहार मनाते हैं, उनके यहां 'सात बार ( दिन ), नौ त्यौहार' कहावत प्रसिद्ध है। गाँवों के आदमी भी पक्के मकान बनवा रहे

हैं, मामूली श्रमजीवी भी सोडावाटर, चाय, सिगरेट-बीड़ी श्रादि का श्रिषकाधिक सेवन करते जाते हैं। इससे सिद्ध किया जाता है कि देश निर्धान नहीं है, यहाँ जनता की सुख समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। परन्तु क्या यह सत्य है ?

बड़े-बड़े नगरों की श्रोर संकेत करनेवाले तनिक यह विचार करें कि यहाँ केवल दस भी सदी श्रादमी ही शहरों में रहते हैं। श्रीर, इनके भी सब निवासी धनवान नहीं है। राज-पथ को छोड़कर, यदि इम अन्दरूती भागों में जायँ तो सहज ही रहस्योद्धाटन हो जाय। इन पँकियों के लेखक ने तो श्रवि सम्पन्न कही जाने वाली बम्बई, कलकत्ता या इन्दौर श्रादि की सड़कों पर प्रात: काल छज्जों के नीचे, ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा है जिनकी समस्त सम्पत्ति उनके सूखे हाड्-मांस के श्रातिरिक केवल वह लंगोटी या श्रंगोछा था, जिसके बिना उन बेचारों को उन सम्यताभिमानी नगरों में रहने की अनुमति न मिलती। अस्त, भारतवर्ष तो देहातों का देश है श्रीर यहाँ की श्रधिकांश जनता किसान है। इन में से बहुतों को साधारण समय में भी । श्रव्छा तो क्या, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। फिर दुर्भिक्ष के समय की तो बात ही क्या ! यह ठीक है कि कुल गांव वाले तथा अमजीवी अपनी आर्थिक स्थिति को भूल कर कुछ शौक़ीनी का सामान लेते हैं, पुरानी रीतियों का पालन करने के लिए त्यौहार मनाते तथा सामाजिक क्ररीतियों में अपन्यय करते हैं। परन्तु यह मनुष्य का स्वभाव है, उसकी कमज़ोरी है। इसके आधार पर उसे पैसेवाला ठहराना अनुचित है।

निम्नलिखित बातों से यह स्पष्ट है कि यहाँ अधिकांश आदमी

निर्घनता का जीवन बिता रहे हैं:-

- (१) यहाँ के निवासियों की श्रौसत श्राय बहुत कम है। साधा-रणतया एक व्यक्ति की दैनिक श्राय छः पैसे मानी जाती है। कुछ लेखकों ने दस-बारह पैसे तक का भी श्रनुमान किया है। स्मरण रहे कि यह श्रौसत श्राय है। इसमें राजा-महाराजाश्रों, सेठ-साहुकारों, पूँजीपतियों तथा उच्च-वेतन भोगी सरकारी या गैर सरकारी पदाधि-कारियों की श्राय भी सम्मिलित है। इसका श्राशय यह है कि श्रनेक व्यक्तियों की श्राय उपर्युक्त श्रौसत श्राय से भी बहुत कम है।
- (२) अंकशास्त्रियों ने यह हिसाब लगाया है कि यहाँ कुल मिलाकर कौन-कौन सा पदार्थ प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है। उस हिसाब से भली भांति यह मालूम हो जाता है कि यहां घटिया खाद्य-पदार्थों का उपभोग बहुत होता है तथा अञ्च-वस्त्रादि आवश्यक पदार्थों के उपभोग की मात्रा प्रति व्यक्ति बहुत कम रहती है। जनता में इन पदार्थों को यथेष्ट परिमाण से ख़रीदने की क्षमता नहीं।
- (३) यहाँ मनुष्यों की श्रौसत उम्र केवल २३:२ वर्ष, श्रौर की हज़ार प्रतिवर्ष श्रौसत मृत्यु २५ है। यह भी निर्धनता-सूचक है। बात यह है कि श्रिधकांश श्रादमी यथेष्ट भोजन-वस्त्र नहीं पाते; कचा-पक्का सड़ा-गला या मिलावटवाला पदार्थ खाकर उदर-पूर्ति कर लेते हैं, समय पर विश्राम, मनोरखन तथा दवा-दारू भी नहीं होती, श्रौर फल-स्वरूप बीमार पड़ते, श्रौर श्रम्ततः जल्दी मरते हैं। ये सब बातें जनता की निर्धनता सिद्ध करती हैं।

जनता की निर्धनता दूर करने और उसकी श्रार्थिक उन्नित करने के लिए विविध उपायों को काम में लाये जाने की श्रावश्यकता है। इनमें से कुछ का उल्लेख प्रसंगानुसार पहले किया जा चुका है—(१) शिक्षा—विशेषतया श्रीद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी एवं अन्य पेशों सम्बन्धी शिक्षा—की बहुत ज़रूरत है। (२) देश में दस्तकारियों एवं उद्योग धन्धों की उन्नित की जानी चाहिए, जो श्रादमी इन कार्यों में लगें, उन्हें सरकार तथा सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा समुचित सहायता श्रीर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। (३) सामाजिक तथा धार्मिक श्रपव्यय बन्द करके, द्रव्य का उपयोग हितकर कार्यों में किया जाना चाहिए। (४) सरकार के भारी श्रासन-व्यय तथा सैनिक व्यय में काफ़ी कमी करके जन-हितकारी कार्यों की वृद्धि की जानी चाहिए। (५) सरकार की श्रायात-निर्यात-कर-नीति तथा श्रन्य बातों में देश-हित का लक्ष्य प्रधान होना चाहिए।



## तीसवाँ परिच्छेद शिचा श्रोर साहित्य

कितीय जीवन का आधार धर्म रहा है। इसका प्रभाव सक केत्रों में पड़ा है। भारतवर्ष अपनी शिक्षा और साहित्य के लिए चिर-काल से प्रसिद्ध रहा। सच पूछिए तो इनका भी मुख्य आधार पहले धर्म ही था। प्राचीन धार्मिक साहित्य का संक्षिस परिचय पहले दिया जा चुका है। इस परिच्छेद में यह विचार किया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, कालान्तर में उसमें क्या अन्तर हुआ, आधुनिक पद्धति क्या है, और उसके अनुसार क्या कार्य हो रहा है। किन-किन बातों की ओर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है?

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था—पहले बताया जा चुका है कि धर्माचार्यों ने यहाँ आश्रम-धर्म की व्यवस्था की थी। मनुष्य का जीवन चार भागों में विभाजित था। प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम का था। प्रत्येक बालक-बालिका पाँच वर्ष की हो जाने पर गुरुकुल में मेजी जाती थी। वहाँ लड़के पचीस वर्ष तक और लड़कियां सोलह वर्ष

तक, शिचा ग्रहण करती थीं। सबको गुरू के निरीक्षण में शारीरिक श्रोर नैतिक शिक्षा के श्रातिरक्त, भावी जीवन में उपयुक्त नागरिक बनने की शिक्षा मिलती थी। धनी-निर्धन, राजा श्रोर रंक, ऊँच या नीच का वहाँ कोई भेद भाव न था। सबसे समान व्यवहार होता था। सबका खान-पान रहन-सहन एकसा रहता था। वे गुरु तथा गुरु-पत्नी को पिता-माता की तरह समभत्ते थे, श्रोर उनके प्रति श्रादर श्रीर भक्ति-भाव रखते थे। राज-पुत्रों को भी गुरु की सेवा करने में कोई संकोच नहीं होता था। पाठक जानते हैं कि कृष्ण श्रीर सुदामा ने एक ही गुरुकुल में शिच्चा पायी थी, श्रीर श्रावश्यकता होने पर दोनों ही ईचन के लिए जंगल से लकड़ी लाये थे। यद्यपि कभी-कभी राज-पुत्रों की शिक्षा के लिए कुछ, विशेष व्यवस्था की जाने के भी उदाहरण हैं, साधारणतया वे सर्वसाधारण बालकों के साथ ही शिच्चा पाते थे। श्राजकल की तरह राजकुमारों की शिच्चा के लिए पृथक् संस्थाएँ नहीं थी। शिच्चा के विषय व्याकरण, साहित्य, दर्शन, गणित, ज्योतिष, धर्म, तर्क श्रादि होते थे।

हां, भिन्न-भिन्न विद्यार्थियों की शिक्षा में उनके गुण श्रौर प्रकृति या रुचि का ध्यान रखा जाता था। ब्राह्मण गुणवालों को धर्म की शिच्चा विशेष रूप से दी जाती थी, चृत्रिय गुण-प्रधान ब्रह्मचारी को शासन श्रौर राजनीति के श्रतिरिक्त धनुर्विद्या तथा युद्ध-शिच्चा भी दी जाती थी। वैश्य प्रकृतिवालों को पशु-पालन, कृषि श्रौर उद्योग-धंघों सम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया जाता था। शुद्धों को कला-कौशल श्रौर दस्तकारो श्रादि सिखायी जाती थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राचीन काल में

इन कार्यों में ऊँचे-नीचे दर्जें का विचार नहीं किया जाता था। ब्रह्मचारियों में पाठ्य विषयों का मेद करने का कारण यह होता था कि शिक्षा का उद्देश्य भावी नागरिकों को समाज के उस चेत्र के अनुकूल बना देना होता था, जिसमें उन्हें पीछे काम करना होता था। इस प्रकार इस बात की चेष्टा की जाती थी कि समाज त्र्यवस्था यथा- वत् बनी रहे। इसीलिए लड़िकयों को लड़कों से कुछ भिन्न शिचा दी जाती थी। इसमें लक्ष्य यह रहता था कि वे विद्वान होकर भी अपने भावी उत्तरदायित्व को भली मांति निबाह सकें, सुयोग्य यहिंगी और माताएँ बन सकें।

संगीत, चित्रकारी आदि ललित कलाओं की ओर भी यथेष्ट ध्यान दिया जाता था। इसका प्रमाया, उस समय के साहित्य के अतिरिक्त, ऐसे चिह्नों से मिलता है जो अजन्ता या अन्य गुफाओं में सुरचित रह सके हैं, अथवा जो पुराने खँडहरों की खुदाई की जाने पर निकलते हैं। अस्तु, सारांश यह कि प्राचीन भारतीय शिक्ता में नागरिक जीवन के किसी अंग की उपेच्ना नहीं की जाती थी। समाज की सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता था। और, इतिहास इस प्रयत्न की सफलता का साक्षी है। प्राचीन शिक्षा-पद्धित को ही इस बात का अथ प्राप्त है कि भारतवासी अनन्त काल तक सुख-शान्ति और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सके, और संसार को अनेक उथलपुर जाता का लाल-चक्र के विविध प्रवाहों के बाद भी भारतीय संस्कृति अपनी परम्परा बनाये हुए सुरचित एवं जीवित है, और अनुकूल अवसर प्राप्त होने पर मानव समाज के लिए अपना हितकर संदेश प्रदान करने

## की क्षमता रखती है।

प्राचीन शिक्ता-व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि यद्यपि प्रत्येक विषय की शिक्षा के लिए देश में विविध केन्द्र थे. कुछ स्थान विशेष विशेष विषयों के लिए विख्यात थे। उदाहरणार्थ काशी में धर्म और साहित्य की शिक्ता विशेष रूप से दी जाती थी। यदि कहीं कोई शास्त्रार्थ होता. तो काशी के पंडित का मत सर्वोपरि माना जाता. था। उसके कथन का प्रतिवाद नहीं होता था, उसका निर्णय श्रन्तिम समभा जाता था। यही कारण था दूर-दूर के विद्यार्थी यहाँ संस्कृत साहित्य की शिचा के लिए श्राते थे। यहाँ उन्हें शिक्षा तो निःश्रलक मिलती ही थी, भोजन-वस्त्र भी मुक्त दिये जाने की व्यवस्था होती थी। यह परिपाटी कुछ सीमा तक अब भी चली आती है। कितने ही पंडितों के पास कई-कई विद्यार्थी रहते हैं. वे वहीं ऋध्ययन करते तथा भोजन पाते हैं। यह कार्य विविध उदार तथा दानी सेठों और साहकारों की सहायता से किया जाता है। काशी की पूर्व ख्याति के कारण ही, श्राधनिक काल में महामना मालवीयजी ने हिन्द्-विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए इस नगर को चुना। इस प्रकार अब काशी में पुरातन एवं नवीन शिच्चा-पद्धतियों का संयोग हो गया है। श्रस्तु, इसी प्रकार तक्षशिला विश्व-विद्यालय ने संस्कृत व्याकरण में नाम पाया था। देश को सुप्रसिद्ध वैयाकरणी पाणिनी प्रदान करने का श्रेय इसी विश्व-विद्यालय को है। सुविख्यात अर्थशास्त्री और राजनीतिश कौटिल्य तथा श्रन्य श्रनेक महानुमावों ने यहाँ ही शिक्षा ग्रहण की थी। ज्योतिष का सर्वोत्तम केन्द्र उज्जैन था, यहां विविध साधन-

वाली वेघशाला थी, श्रीर ज्योतिष सम्बन्धी प्रत्येक प्रयोग करने श्रीर हिसाब लगाने की सबसे श्रिषक सुविधाएँ यहाँ ही थीं। बौद्ध काल में भी यहां शिक्षा-प्रचार की समुचित ज्यवस्था रही। स्थान-स्थान पर बौद्ध धर्माचार्यों के निरीक्षण में मठों श्रीर विद्यापीठों का संचालन होता था। ये प्रायः स्वावलम्बी होते थे, श्रध्यापक श्रीर विद्यार्थी श्रपने निर्वाहार्थ निकटवर्ती स्थानों से भिक्षा माँग लाते थे। उनके श्रन्यान्य शिक्षा-केन्द्रों में नालंद के विश्व विद्यालय ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। हिन्दू श्रव भी इसका गर्व करते हैं। यहाँ लंका, जावा, चीन, जापान जैसे दूर-दूर के मू-भागों से विद्या-प्रेमी श्राते श्रीर शान की ज्योति श्रपने-श्रपने स्थान को ले जाते थे।

यद्यपि प्राचीन काल में शिक्षक एवं विद्यार्थी बहुत सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, आज कल की तरह वे फैशन या शौकीनी नहीं करते थे, तथापि उनका राज्य एवं समाज में बहुत आदर-मान था। अब तो विद्यार्थियों की कौन कहे, अध्यापकों तक का समाज में कुछ, विशेष स्थान नहीं है, राज्य में तो उनकी प्रतिष्ठा और भी कम है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों का भी आदर-सम्मान था, वे समाज के भावी सूत्र-संचालक के रूप में देखे जाते थे। उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में यथा-सम्भव योग देना प्रत्येक ग्रहस्थ अपना कर्तव्य ही नहीं, सौभाग्य समकता था। यह कहावत प्रसिद्ध थी 'सर्वेषामेव दानानाम् ब्रह्मदानम् विशिष्यते' अर्थात् विद्या-दान सब दानों से बढ़-कर है।

मसलमानों के शासन-काल में शिक्षा की व्यवस्था--जब मुसलमानों के भारत पर श्राक्रमण होने लगे. तो श्रारम्भ में कुछ समय तक अन्यान्य बातों में शिक्षा की भी व्यवस्था बिगडी रही। कुछ श्राक्रमणकारियों तथा उनके श्रनुयायियों ने शिक्ता-संस्थाश्रों पर श्राघात पहुँचाने में कसर न रखी, कितने ही पुस्तकालय श्रादि नष्ट कर दिये गए। पर ये बातें कुछ समय के लिए ही थीं। पीछे मुसलमान यहाँ वस गये, श्रीर इस देश को ही श्रपना घर समफते लगे । ज्यों-ज्यों शांति स्थापित होती गयी, शिचा-प्रचार श्रादि की श्रोर ध्यान दिया जाने लगा । दो तरह की संस्थाएँ स्थापित हुईं । मसजिदों में मकतव थे, इनमें विशेषतया इसलाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, कुरान पढाया जाता था। इनमें स्वभावतः मुसलमानों के ही बालक-बालिकाएँ शिक्षा पाती थीं। लड़कियों को थोड़े समय तक ही लड़कों के साथ पढ़ने दिया जाता था। दूसरे प्रकार की संस्थाएँ मदरसे थे। इनमें धर्म, क़ानून, इतिहास, दर्शन, काव्य, हिकमत (वैद्यक) श्रादि की उच शिक्षा दी जाती थी। मदरहों को राज्य की श्रोर से सहायता मिलती थी। इनके कुछ मुख्य केन्द्र बदायूँ, जौनपुर, श्रागरा, देहली श्रीर मुलतान श्रादि में थे। मुसलमानों की संस्थाओं में शिक्षण श्ररबी या फ़ारसी में होता था। हिन्दुओं ने जहाँ तक वन त्राया, त्रपनी पुरानी संस्थात्रों को जीवित रखने का प्रयत्न किया। इस प्रकार मुसलमानों के यहाँ आने का परिणाम यह हुआ कि दो प्रकार की भाषाओं तथा संस्कृतियों को साथ-साथ रहने का श्रवसर मिला। पीछे जाकर दोनों संस्कृतियों का क्रमशः सम्मिश्रण हुआ। हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों ने एक-दूसरे की कुछ बातें लीं, श्रौर कुछ दीं। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

विशेषतया मुगुल शासकों ने शिक्षा श्रीर साहित्य के प्रचार में बहुत श्रनराग दिखाया. श्रीर इस कार्य को श्रपनी श्रार्थिक सहायता तथा श्रन्य प्रकार से बहुत प्रोत्साइन प्रदान किया । बाबर ने श्रपना जीवन चरित्र लिखा, हमायँ ने ऋपने जीवन में विविध कठिनाइयों को सहते हए भी एक विशाल पुस्तकालय बनाये रखा । श्रकबर ने कवियों श्रीर लेखकों का वडा श्रादर किया। उसके नवरतों में उस समय के धरन्घर विद्वान. कवि श्रौर राजनीतिश्च थे। श्रक्तवर के समय में ही महाकवि तु सीदास ने हिंदी संसार को अपनी अमर कृति राम-चरित-मानस श्चर्यात रामायण की भेंट की। सुप्रसिद्ध वार्ता-विनोदी बीरबल तथा संगीतज्ञ तानसेन श्रकबर को बहुत प्रिय थे। जहाँगीर ने भी विद्या-प्रेमियों का त्रादर-सम्मान किया। शाहजहाँ की, भवन-निर्माण में, बहुत रुचि थी। उसने श्रागरा में जमुना तट पर संसार-प्रसिद्ध ताजमहत्त का निर्माण कराया। श्रीरंगज़ेब को छोड़ कर सब मुगल बादशाहों ने श्रपने इतिहास-प्रेम का श्रच्छा परिचय दिया। उन्होंने स्वयं श्रपने समय का इतिहास लिखवाया. जो साहित्य में ऋपना विशेष स्थान रखता है।

ऋँगरेज़ी शिक्षा का पारम्भ—भारतवर्ष में श्रॅगरेज़ी शिक्षा का प्रचार सबसे पहले ईसाई पादिरयों ने किया। इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था। इनकी संस्थाओं से जनता को देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्हें ईस्ट-इंडिया-कम्पनी (उस समय की सरकार) द्वारा सहायता मिली। इसके श्रातिरिक, राजा

राम मोहनराय त्रादि सुधारकों ने भी इस कार्य में योग दिया। सन् १८१६ ई० में एक लाख रुपये के चंदे से कलकत्ते में पूर्वीय और पश्चिमीय विद्याश्रों की शिक्षा के हेतु हिन्दू-कालिज की स्थापना की गयी।

श्रारम्भ में ईस्ट-इंडिया-कम्पनी शिक्षा-प्रचार में बहुत उदाधीन थी। पीछे ब्रिटिश पार्लिमेंट की प्रेरणा से, उसने यहाँ प्राचीन शिक्षा-प्रणाली प्रचलित रखने में सहायता दी। सन् १७८१ ई० में कलकत्ते में एक 'मदरसा' फारसी को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया, जो कि उस समय श्रदालतों की भाषा थी। इसके दस वर्ष बाद बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया। इन दोनों संस्थाश्रों का उद्देश्य यह था कि श्रारेज़ी जजों को दीवानी के मुक़दमों का फैसला करने में सहायता देने के लिए हिन्दू श्रीर मुसलमानों के धर्म-शास्त्र जाननेवाले तैयार हों। सन् १८१३ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने निश्चय किया कि कम्पनी प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपया शिक्षा-प्रचार में लगावे। सन् १८२३ में देहली श्रीर श्रागरे में कालिज खोले गये, जिनमें श्रा-रेज़ी की भी क्लामें थीं। सन् १८२६ ई० में मदरास में एक स्कूल श्रीर कुछ ग्राम-पाठशालाएँ खोली गर्यी।

सरकार का नीति-परिवर्तन — एन १८३० ई० तक सरकार अपनी उपेत्ता-पूर्ण नीति को त्याग कर शित्ता-प्रचार की समर्थक हो गयी। इसके कई कारण थे। प्रथम तो यह कि अब तक के अँगरेज़ी शित्ता के कार्य का जनता में विरोध नहीं हुआ था, जिसकी सरकार को विशेष आशंका थी। दूसरे, कम्पनी को अपना कारोबार चलाने के लिए

दफ्तरों के वास्ते सस्ते क्लकों की श्रावश्यकता थी। तीसरे, कम्पनी को श्राशा थी कि श्रंगरेज़ी शिक्षा पाकर युवक शौक़ीन होंगे, उनकी श्रावश्यकताएँ बढ़ेंगी, श्रौर वे हमारा सामान ख़रीदेंगे। इन सबसे श्रिष्ठक महत्व की बात सरकार के क़ानूनी सलाहकार मेंकाले के इन शब्दों से सूचित होती है—'हमें श्रपनी सारी शिक्त लगाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम भारतवासियों की एक ऐसी भेगी तैयार कर सकें, जिसके श्रादमी, हमारे श्रौर हमारी लाखों प्रजा के बीच, दुभाषिये का काम कर सकें, जो रक्त श्रौर रङ्ग में तो भारतीय ही रहें, परन्तु रुचि, विचार, भाषा श्रौर भावों में पूरे श्रंगरेज़ हों।'

अस्तु, सन् १८३५ में सरकार ने निश्चय किया कि देशी भाषाएँ केवल प्रारम्भिक शिक्षा के लिए काम में लायी जायँ, उच्च-शिक्षा का माध्यम अँगरेज़ी हो। सन् १८३७ में फ़ारसी को हटा कर उर्दू सरकारी दफ़रों को, तथा अदालतों को, भाषा बना दी गयी। अँगरेज़ी भाषा की परीक्षाएँ पास करनेवालों को उच्च नौकरियाँ मिलने लगीं। इन बातों ने अँगरेज़ी और उर्दू की शिक्षा बढ़ायी, और संस्कृत तथा अरबी फ़ारसी का प्रचार घटाया।

शिक्षा को प्रगति—सन् १८५३ ई० में कम्मनी की सनद बदलने का समय आया। अब तक शिक्षा-प्रचार की गति मन्द ही रही थी। अब उसे अँगरेज़ी राज्य की दृढ़ता में सहायक समक्ता गया और इसिलए उसका प्रचार बढ़ाने का निश्चय किया गया। सन् १८५७ में कलकत्ता बम्बई और मदरास में विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये। सन् १८८१

में शिचा-कमीशन ने ट्रेनिंग कालिज ब्रादि खोलने की सिफ़ारिश की। लार्ड कर्जन के समय में विद्यार्थियों को 'राजनैतिक वायु से सुरचित' रखनेके लिए यूनीवर्षिटियों पर ब्राजकारियों का नियंत्रण बढ़ाया गया। सन् १९१० ई० से सरकार का एक पृथक् शिक्षा-विभाग स्थापित किया गया। सन् १९१३-१४ ई० से प्रतिवर्ष शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। सन् १९१९ ई० से कलकत्ता विश्व-विद्यालय कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके ब्राधार पर बहुत-से स्थानों में इंटरमीजियट (एफ० ए०) कालिज खोलकर इन क्लासों को विश्व-विद्यालय से पृथक् रखने की व्यवस्था की गयो, एवं मुसलमानों को शिच्चा-प्राप्ति में उत्साहित करने की ब्रार ध्यान दिया गया। इस समय देश में १८ विश्व विद्यालय हैं, इनमें पाँच तो संयुक्त-प्रान्त में ही हैं, इलाहाबाद, बनारस, ब्रागरा, लखनऊ ब्रीर ब्रालगढ़ के। ब्राधकांश विश्व-विद्यालय शिक्षा-कम निश्चित करने तथा परीक्षा लेने का काम करते हैं। इनसे राष्ट्रोपयोगी ब्रनुसन्धान का कार्य बहुत कम होता है।

लार्ड रिपन की स्थानीय स्वराज्य की योजना के अनुसार कार्य आरम्भ हो जाने पर, सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा का भार म्युनिसपैलिटियों श्रीर ज़िला-बोर्डों के सुपुर्द कर दिया, पर विशेष उन्नति
न हो पायी। सन् १९११ ई० में स्वर्गीय गोखले ने प्रारम्भिक शिक्षा आनिवार्य करने के लिए बिल पेश किया था, परन्तु सरकार ने आर्थिक किठनाइयों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। पश्चात् सन् १९१८ ई० से विविध प्रांतीय व्यवस्थापक परिषदों ने समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा

का क़ानून पास किया। प्रायः जो म्युनिसपैलटियाँ इस शिक्षा को स्त्रनिवार्य (श्रौर निःश्रुल्क) करने के लिए एक-तिहाई ख़र्च देना स्वीकार करती हैं, उन्हें शेष ख़र्च के लिए सरकारी सहायता मिलती है।

गैरसरकारी और राष्ट्रीय संस्थाएँ —देश की श्रिष्ठकतर शिक्षा-संस्थाओं पर सरकारी निरीक्षण तथा नियन्त्रण है। कुछ संस्थाएँ ऐसी भी हैं, जिनका संचालन तथा ख़र्च जनता द्वारा होता है, श्रीर जो सरकार से सम्बन्ध न रख कर श्रपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करती हैं। गुरुकुल, ऋषिकुल और विद्यापीठ श्रादि संस्थाएँ बहुत-कुछ प्राचीन ढज्ज की हैं। वे गैर-सरकारी हैं। उनमें प्रायः राष्ट्रीय शिद्धा दी जाती है। कहीं-कहीं राष्ट्रीय शिद्धा-संस्थाएँ श्राधुनिक ढज्ज की भी हैं। राष्ट्र-भाषा हिन्दी में विविध विषयों की परीक्षाएँ लेनेवाली संस्थाओं में में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मुख्य है। इसका प्रधान कार्यालय प्रयाग में है। इसकी परीक्षाओं के, देश के भिन्न-भिन्न भागों में, लगभग छः सौ केन्द्र हैं। लोक-सेवा के लिए कुछ स्थानों में बालचर (स्काउट्स) संक और सेवा-समितियां श्रादि स्थापित हैं।

नवीन शिक्षा-योजना—प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित होने पर विशेषतया काँग्रेसी सरकारवाले प्रांतों में शिक्षा की कमी एवं वर्तमान शिक्षा-प्रशाली के दोषों को दूर, करने का प्रयत्न किया गया । नवीन शिक्षा-योजना की मूल प्रेरणा महात्मा गांधी द्वारा हुई है, और इसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार-विनिमय अधिकतर वर्षा में हुआ। इसलिए साधारण बोल-चाल में इसे 'वर्षा-शिक्षा-योजना' कहा जाता है। इसकी मुख्य बात यह है कि विद्यारियों को सात साल से लेकर १४ साल की उम्र तक आधार-भूत या बुनियादी शिक्षा दी जाय, जिसमें दस्तकारी की शिक्षा अवश्य हो, जिसे पूरी करने पर युवक अपनी आजीविका कमा सकें, और गाँवों में लौटकर वहाँ बस जाने की इच्छा रखें। इस शिक्षा का ध्येय ऐसे बालक-बालिकाएँ तैयार करना है, जो नौकरी की चिन्ता न करें, वरन् स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें; साथ ही वे यह भी ज्ञान प्राप्त करें कि राष्ट्र तथा समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इसलिए उन्हें नागरिक ज्ञान ('सीविक्स') आदि समाज-शास्त्र की भी शिच्या दी जाय। इस योजना के अनुसार कुछ स्थानों में शिच्या दी जाने लगी है।

गांवों में वाचनालय तथा साधारण एवं गश्ती पुस्तकालय स्थापित करने तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करने का कार्य भी किया जा रहा है। आशा है, इन उपायों से देश का अविद्यांधकार क्रमशः दूर होगा, और शिच्चितों की बेकारी की समस्या भी कुछ अंशों में तो अवश्य ही इल होगी।

साहित्य-प्रचार — शिक्ता-प्रचार के साथ-साथ साहित्य की माँग बढ़ना स्वाभाविक ही है। अत: अब स्थान-स्थान पर साहित्य की बृद्धि तथा प्रचार का भी प्रयत्न अधिक हो रहा है। कितनी-ही सभाओं, और सम्मेलनों के समय-समय पर अधिवेशन होते हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्राचीन हस्तिलिखित पुस्तकों की खोज, नवीन पुस्तक और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकारान, लेखकों को पुरस्कार देना, सरकार का देशी भाषाओं के प्रति-ध्यान आकर्षित करना आदि विविध कार्य बड़े

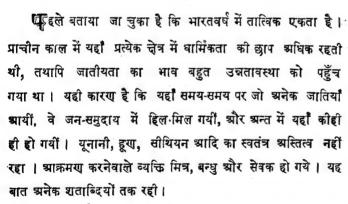
उत्साह से किये जाते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकारों को अभिनन्दन-प्रन्थ समर्पित किये जाते हैं; एवं उनके नाम पर साहित्यक मेलों की व्य-वस्था होने लगी है। इस प्रकार के आयोजन भविष्य में अधिकाधिक होने की आशा है। सुविख्यात साहित्य-महारिथयों की जयन्तियां मनाने की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। प्रचारक संस्थाएँ सभी मुख्य-मुख्य देशी भाषाओं की हैं। भारतीय राष्ट्र-सभा अर्थात् कांग्रेस का कार्य सन १९१५ ई० तक अधिकतर ऑगरेज़ी में रहा। पश्चात् उसका चेत्र सर्वसाधारण में बढ़ने पर, हिन्दी या हिन्दुस्तानी का उप-योग अधिकाधिक बढ़ने लगा। कई नयी प्रन्थमालाएँ, भिन्न-भिन्न विषयों की, निकलने लगीं। पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रचार बढ़ रहा ई; हां, इनके कार्य में कई आर्थिक तथा राजनैतिक बाधाएँ हैं। आशा है इन्हें क्रमशः दूर किया जायगा।

शिक्षा और साहित्य के प्रताप से हमारे देश में उत्तर-दिल्या का अंतर घट रहा है। एक स्थान की विचार-घारा जल्दी ही दूसरे स्थान में जा पहुँचती है। इस प्रकार भारतीय शरीर में एकता और राष्ट्रीयता का संचार सुगम हो रहा है। साहित्य-सेवियों को अपने उच आदर्श का सदैव ध्यान बनाये रखना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को अपना अहिंसा, प्रेम, त्याग और विश्व-वंधुत्व का संदेश संसार में फैलाना है; आवश्यकता इस बात की है कि इस महान कार्य में हमारा साहित्य समुचित योग दे।



## इकतीसवाँ परिच्छेद

## राष्ट्रीय आन्दोलन



पश्चात् स्थिति क्रमशः बदल गयी । सम्राट् श्रशोक के बाद यहाँ शासन-सत्ता प्रायः निर्वल व्यक्तियों के श्रिषकार में रही । प्रत्येक प्रान्त तथा जाति के श्रादमी श्रपने श्रापको दूसरों से श्रलग समभने लगे। जब मुसलमान यहाँ श्राये, भारतीय समाज छिन-भिन्न, श्रनुदार, श्रस्वस्थ

तथा रोगी था। उधर मसलमानों में उत्साह श्रीर साहस था. श्रीर था नये धर्म का जोश । हिन्दू समाज उन्हें अपने में मिलाने में असमर्थ रहा; यही नहीं; हिन्दुश्रों के पारस्परिक भेद-भाव श्रीर फूट के कारण मसलमानों का यहाँ कितने-ही भागों में राज्य स्थापित हो गया। परन्त पीछे मुसलमान यहाँ विदेशी के रूप में न रह कर यहां के ही हो गये। श्रन्यान्य मुसलिम शासकों में श्रकवर ने यहां राष्ट्र-निर्माण का यथेष्ट प्रयत्न किया। पर उसकी-सी नीति यहाँ पर्याप्त समय तक नहीं बतीं गयी, फल-स्वरूप िक्लो श्रीर मराठों ने श्रपना-श्रपना शासन श्रीर स्वतंत्र संगठन करना शुरू कर दिया । हिन्द श्रौर मुसलिम संस्कृतियों के मिलजाने का काम अभी अधुरा ही था कि अंगरेज़ आदि योरियन जातियों का यहाँ श्राना हो गया, श्रीर उनकी कूटनीति से यहाँ पुन: संगठन-हीनता या अ-राष्ट्रीयता का दुखदायी परिचय मिला। श्रीर. उन्होंने एक भारतीय शक्ति को दूसरी से भिड़ाने का तथा स्वयं एक पक्ष का साथ देकर और उसके जीत जाने पर उससे कुछ मूमि या व्यापारिक अधिकार लेते रहने का खूब प्रयत्न किया।

कुछ श्राँगरेज़ इतिहास-लेखक यह कहा करते हैं कि भारतवर्ष में श्राँगरेज़ों का श्रिषकार श्रकस्मात संयोग से हो गया, उन्होंने इसके लिए कोई श्रायोजन नहीं किया। साधारण व्यक्ति इसपर बहुत श्राश्चर्य किया करते हैं कि सात समुद्र पार से श्राये हुए योर्पपयनों ने विसातस्तानों श्रीर गिरजाधरों से निकल कर कैसे रण-चेत्र में उतरने का साहस किया, श्रीर वे विजय-लक्ष्मी से क्यों कृतार्थ हुए। वास्तविक बात यह है कि श्रंगरेज़ों की ईस्ट-इंडिया कम्पनी के गवर्नर-जनरलों के सामने आरम्भ से मुख्य कार्य यह रहा कि यहाँ के शासकों को निर्वल करते हुए अधिकाधिक राज्याधिकार प्राप्त करते जायें। पुनः यह कोई रहस्य नहीं कि कम्पनी ने भारतवर्ष के एक प्रान्त के सिपाहियों को कुछ सिक्कों का प्रलोभन देकर उनके बल पर दूसरे प्रान्त को, श्रौर कभी-कभी उसी प्रान्त को 'विजय' किया है। इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने ही इस देश के एक-एक भाग को ऋँगरेज़ों के अधीन करने में मुख्य भाग लिया है। यह कहा जा सकता है भारतवासियों की पराजय का कारण इनकी संगठन-हीनता या अ-राष्ट्रीयता है। ये दूसरों से नहीं हारे. चरन् अपने ही आदिमियों से पराजित हुए हैं। एक प्रान्त के इस्तगत हो जाने पर अँगरेज़ों को दूसरे प्रान्त पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यथेष्ट धन-जन मिलता गया । इस प्रकार उन्होंने कूटनीति, छल-बल श्रौर कौशल से, यहाँ के शासकों के पारस्परिक लड़ाई-फगड़ों तथा फूट से, दो सौ वर्ष के भीतर, सन् १८५७ ई॰ तक, भारतवर्ष के अधिकांश भाग पर प्रत्यक्ष अथवा गौगा रूप से अपना अधिकार जमा लिया। ही, पीछे उनकी श्रधीनता में यहाँ एकता श्रीर राष्ट्रीयता की बृद्धि अवश्य होने लगी।

राष्ट्रीयता का विकास — अठारहवीं शताब्दी में घर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य सभी चेत्रों में भारतवासी अपनेपन को खोकर कैसा चिन्तनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, और उन्नीसवीं शताब्दी में किस प्रकार यहाँ जाग्रति का कार्य आरम्भ हुआ, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, थियोसोफ़िकल सोसायटी और रामकृष्या मिशन आदि संस्थाओं के संस्थापकों और सदस्यों ने विविध चेत्रों में क्या-क्या सुधार किया, यह

हम पिछले परिच्छेदों में बता चुके हैं। यद्यपि इनके अपन्दोलनों का प्रधान विषय राजनीति नहीं था, इस चेत्र में भी इनसे बहुत सहायता मिली। राजा राममोइनराय ने शिक्षा-प्रचार के अतिरिक्त कई राजनैतिक सुघारों का भी प्रयत्न किया। स्वामी दयानन्दजी ने अपने 'सत्यार्थ-प्रकाश' नामक प्रन्थ में निर्भीकता-पूर्वक लिखा कि विदेशी राज्य से, चाहे वह कितना ही श्रब्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें कितनी ही त्रिटियाँ क्यों न हों, अञ्छा होता है। स्वामीजी के उपदेश से लोगों में स्वदेशी श्रौर स्वराज्य की भावना पुनः जागृत हुई। थियोसोफ़िकल सोसायटी की अध्यक्ष ऐनीविसेन्ट ने तो राजनैतिक तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में क्रियात्मक भाग लिया, और इसके लिए वे इषं-पूर्वक जेल गयीं। श्री रामकृष्ण परमहंस श्रीर उनके शिष्य श्री० विवेकानन्दजी ने विदेशों में भारतवर्ष की महत्ता बतायी। इन विविध महानुभावों के परिश्रम से यहाँ लोगों में स्वाभिमान उदय हन्ना, और इस प्रकार राष्ट्रीयता के भावों के विकास में सहायता मिली।

राष्ट्रीयता-दृद्धि के कारण — आधुनिक काल में यहाँ एकता और राष्ट्रीयता के भावों का प्रचार करने में कई बातों ने योग दिया है। उसमें योरिययनों और विशेषतः श्रॅंगरेज़ों के संसर्ग का भी श्रच्छा स्थान है। भारतवासी उनके नये रहन-सहन और श्रनोखे रंग-ढङ्ग को देखकर चिकत हुए, और उनके उस समय के संकुचित विचारों को प्रगतिशील पाश्चात्य विचारों का सामना करना पड़ा। इधर, ईसाई पादियों आदि ने हमारे अवगुणों को खून बढ़ा-चढ़ाकर

दिखाया और हमें विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि हमारे पूर्वज जंगली थे, और भारतवर्ष अब भी असम्य है। उनका जादू चल गया, और हम उनका अंघाधुन्घ अनुकरण करने लग गये। कुछ समय पश्चात् इसमें परिवर्तन होने लगा; परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह था कि संस्कृत साहित्य के कुछ अंशों का योरपीय भाषाओं में अनुवाद होने से, योरपवाले भारतीय उच्च विचार, ज्ञान और सम्यता से परिचित होकर उसे सम्मान की हिष्ट से देखने लगे। योरपीय विद्वानों का मत अपने देश के विषय में अच्छा पाकर, भारतवासी भी अपना प्राचीन गौरव समरण करने लगे। अब पश्चिमी बातों में वैसी अद्धा न रही, विदेशी विचारों की परख की जाने लगी, और स्वदेशी भावों का संचार हुआ।

शिक्षा श्रोर विज्ञान — ईस्ट-इंडिया-कम्पनी ने श्रपने व्यापार का काम चलाने के लिए क्लर्क पैदा करने के वास्ते लोगों को पढ़ाने-लिखाने का प्रयत्न किया। इससे देश के निम्न श्रेणी के भी कुछ श्रादिमयों में शिक्षा का प्रचार होने से उनके विचारों में उथल-पुथल होने लगी। साथ ही, धर्म-ग्रन्यों का किटन संस्कृत से सुगम प्रचलित माषाश्रों में श्रनुवाद होने श्रीर छापेख़ाने की सहायता से यह साहित्य देशी भाषाश्रों में बहुत सस्ता ही मिल जाने के कारण, जन-साधारण को उसका ज्ञान सुलभ होगया। उनमें सोचने-विचारने की भावना बढ़ी; वे श्रपनी तथा देश की परिस्थित समभने लगे। इसके श्रितिरक्त, पाश्चात्य संसर्ग के साथ यहाँ भौतिक विज्ञान का भी प्रचार बढ़ा। देश में शिक्षा, श्रोर वैज्ञानिक श्राविष्कारों तथा यंत्रों के प्रचार की दृद्धि होने से

लोगों को विविध प्रकार की विचार-सामग्री मिली, श्रौर जागृति तथा राष्ट्रीयता का मार्ग सुगम हुआ।

श्रन्य देशों की जागृति का प्रभाव—जापान ने वैध राज्य-प्रणाली स्थापित की श्रौर पश्चिम के विशाल रूस देश को रण-चेत्र में परास्त किया। श्रर्स, मिश्र, ईरान, श्रक्तग्रानिस्तान श्रादि देशों ने मी श्रव्छी प्रगति कर दिखायी। चीन जैसे प्राचीन रूढ़ियों के समर्थक तथा स्वेच्छाचारी शासनवाले देश ने प्रजातंत्र राज्य-पद्धति का स्वागत किया। निदान, एक प्रकार से समस्त एशिया महाद्दीप में जागृति का संचार हुआ। यह लहर भारतवर्ष में आये बिना कैसे रहती! श्रागे-पीछे इसने भारतीय जागृति श्रौर राष्ट्रीयता को किसी न-किसी रूप में सहायता प्रदान की है।

पवासी भारतीयों की दुरवस्था—समय समय पर, भिन्न कारणों से कुछ भारतीय विदेशों में गये थे। उनका अपने देश में आदर न था, बाहर उन्हें क्या सम्मान मिलता! ब्रिटिश सम्मान्य में, दक्षिण अफ्रीका आदि में भारतीय पुरुष-स्त्रियों को बहुत कष्ट-पूर्ण और अपमानजनक जीवन बिताना पड़ा। इससे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को अनुभव हो गया कि पराधीन रहने के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य में, हमारी कैसी बुरी अवस्था है; और इन कष्टों को दूर करने का रहस्य भारतवर्ष की स्वाधीनता में ही है। निदान, प्रवासी भारतीयों पर होने- बाले अत्याचारों ने इस देश से ब्रिटिश साम्राज्य का मोह इटाने में, और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की भावना में भारी सहायता दी है। पुनः जिस सत्याग्रह और असहयोग को, शान्ति और अहिंसा को, यहाँ

श्वान्दोलन का प्राण बनाया हुआ है, उसका प्रथम प्रयोग भी दक्षिण श्रफ़ीका में ही हुआ था। इससे स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों की दुर्रवस्था का हमारी राष्ट्रीयता-बृद्धि में महत्व-पूर्ण भाग है।

राष्ट्रीयता की परीक्षा-भारतवर्ष के हिन्दू मुसलमान सामन्तों श्रीर जागीरदारों श्रादि ने मिलकर सन् १८५७ ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध में भाग लिया। इससे विदित होता है कि भारतवर्ष में उस समय राष्ट्रीय भावों का प्रचार श्रारम्भ हो गया था। परन्तु उस युद्ध की असफलता से यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय तक राष्ट्रीयता का विकास बहुत अपूर्ण और अपर्याप्त हो पाया था। राष्ट्रीय आन्दोलन ऊपर की सतह तक परिमित था, उसे सर्वसाधारण जनता ने नहीं अपनाया था। सन् १८५७ ई० की असफलता के बाद देश में कोई ऐसा संगठित दल न रहा जो विदेशी सत्ता का इस प्रकार सामना करे। तत्कालीन समाज-संगठन के श्रनुसार दो ही विचार-घाराएँ मुख्य थौं-(१) सरास्त्र युद्ध या (२) पराधीनता की स्वीकृति । युद्ध, राजात्र्यों श्रीर सामन्तों के नेतृत्व में हो हो सकता था, इसलिए उनकी विफलता के बाद राजनैतिक अवस्था ऐसी हो गयी कि इमने विदेशी राज्य को स्वीकार कर लिया. श्रीर उसके श्रनुसार श्रपने को ढालने का कार्य श्रारम्भ कर दिया। हाँ, जब-कभी कोई बात विशेष कष्टदायक या अपमानजनक प्रतीत हुई तो उसे सुधारने की, सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार स्वातंत्र्य युद्ध की अधफलता ने देश में विधानवाद श्रौर ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया के समर्थकों को नेतत्व प्रदान किया। ऐसे ही विचारों के परिणाम-स्वरूप यहाँ आगलें पच्चीस वर्ष में कई संस्थाएँ स्थापित होकर अन्ततः सन् १८८५ ई० में कांग्रेस या राष्ट्र-सभा का जन्म हुआ।

कांग्रेस या राष्ट्र-सभा—श्रारम्भ में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रह कर ही शासन-सुधार प्राप्त करना था, धीरे-धीरे इसने राजनैतिक स्वाघीनता का आदर्श ग्रहण किया। राष्ट्रीयता के प्रचार में इसने प्रमुख कार्य किया है। भारतीय राष्ट्र-सभा कहने से इसी का बोघ होता है। इसका जन्म सन् १८८५ ई० में हुआ। इस प्रकार इसके पीछे पचान वर्ष से अधिक का इतिहास है। इसने देश की राजनैतिक प्रगति श्रीर स्वाधीनता-श्रान्दोलन में जो भाग लिया है, उस का विचार आगे किया जायगा। उसके अतिरिक्त इसने यहाँ राष्ट्र-निर्माण और रचनात्मक कार्य को विलक्षण उत्तेजना दी है। पहले उसके कार्यक्रम में (१) हिन्द्-मुसलिम या साम्प्रदायिक एकता. (२) अस्पृश्यता-निवारण, (३) मद्यपान-निषेत्र और (४) खादी मुख्य थी। पीछे कांग्रेस ने (५) ग्राम-उद्योग श्रौर (६) बुनियादी (बेसिक) शिक्षा का भी कार्य श्रारम्भ किया गया। श्रव तो महात्मा गांधी के कथनानुसार, (७) ग्राम-सफाई, (८) प्रौढ़-शिक्षा, (९) स्त्री-सेवा, (१०) त्रारोग्य-शिक्षा (११) राष्ट्र-भाषा-प्रचार (१२) मातृ-भाषा-प्रेम श्रीर (१३) श्रार्थिक समानता भी रचनात्मक कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीयता में बाधाएँ; (१) प्रान्तीयता — प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और पराधीनता के विकार अभी तक हमारे राष्ट्र- ह्या शरीर में बने हुए हैं! जब तक ये दूर न होंगे, राष्ट्र-निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सकता, राष्ट्रीयता का आन्दोलनपूर्णतया सफल नहीं

कहा जा सकता। प्रान्तीयता की बात लीजिए। हमारे संकीर्ण विचारों के कारण कहीं बंगाली-बिहारी समस्या है, कहीं बंगाली-मारवाड़ी, श्रीर कहीं महाराष्ट्री-हिन्दुस्तानी श्रादि का सवाल है। इन समस्यात्रों को इल करने के लिए आवश्यक है कि इम इस बात को अच्छी तरह समभ लें कि राष्ट्रीय एकता को बढाने तथा बनाये रखने के लिए संकुचित प्रान्तीयता के भाव को मिटा देना चाहिए। हाँ, जब तक राष्ट्र की उन्नति में बाघा उपस्थित न हो, तथा दूसरे प्रान्त के उचित स्वार्थ की हानि न हो, हमें अपने-अपने प्रान्त की भरसक सेवा और उन्नित करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रान्त से भिन्न किसी अन्य प्रान्त में रहते हों. उनका कर्तब्य है कि वे उस प्रान्त की भाषा को सीखें, वहाँ की संस्कृति और संस्थाओं का आदर करें एवं वहाँ के निवासियों से मिल-जुल कर रहें, तथा पारस्परिक स्नेह श्रीर सद्भावना-पूर्वक उस प्रान्त का हित-साधन करें। प्रत्येक प्रान्त के निवासियों का कर्तव्य है कि वे अन्य प्रान्त से वहाँ आकर बसे हुए व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार का द्रोष-भाव न रखें; अन्य प्रान्तवाले भी तो भारतीय -राष्ट्र के ही है, जो हम सब की मातृभूमि होने के कारण, हम सब के लिए श्रादरणीय है।

श्रावश्यकता है कि प्रत्येक प्रान्त श्रपनी भाषा, संस्कृति श्रीर साहित्य श्रादि की उन्नति करता हुत्रा, कम-से-कम श्रपने निकटवर्ती प्रान्तों से सम्यक् श्रादान-प्रदान करता रहे । श्रादमी श्रापस में मिलने-जुलने श्रीर विचार-विनिमय करने तथा एक-दूसरे का रहन-सहन, भाषा श्रीर व्यवहार श्रादि जानने का, यथेष्ट श्रवसर निकालें । तीर्थ- यात्रा में इमारा ध्यान इस श्रोर रहे तो सहज ही बहुत लाभ हो सकता है। इसके श्रातिरिक्त, प्रत्येक प्रान्त में ऐसे दलों का श्रायोजन होना चाहिए जो समस्त देश का श्रमण करें, भिन्न-भिन्न प्रान्तों के दो-तीन शहरों श्रौर पाँच-सात गावों में उहरें, विविध स्थानों की संस्कृति का श्रध्ययन करें, श्रौर एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें। इन दलों के सज्जनों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी का ज्ञान होना श्रावश्यक है। जिन्हें यह भाषा न श्राती हो, वे सहज ही इसे सीख सकते हैं। ऐसे सज्जनों के द्वारा श्रन्तर्प्रान्तीय सहयोग में बहुत सहायता मिल सकती है।

(२) साम्प्रदायिक संस्थाएँ—भारतवर्ष में अनेक धर्म और विविध जातियाँ है, श्रीर इनके अपने-अपने संगठन हैं। इनमें से कुछ का स्वरूप श्रिखल भारतवर्षीय है श्रीर कुछ का प्रान्तीय या स्थानीय। प्रायः प्रत्येक संस्था श्रपना चेत्र अधिक-से-श्रिधक विस्तृत रखने की इच्छुक होती है। बहुधा जो संस्थाएँ श्रारम्भ में स्थानीय होती हैं, वे क्रमशः प्रान्तीय श्रीर पीछे श्रिखल भारतीय स्वरूप धारण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। कुछ संस्थाएँ अपने चेत्र में शिक्षा का प्रचार, अनाथ-रक्षा, विधवा सहायता श्रादि का बहुत उपयोगी कार्य भी करती हैं। परन्तु इनमें श्रागे-पीछे एक दोष श्राने की श्राशंका रहती है। परनेतु इनमें श्रागे-पीछे एक दोष श्राने की श्राशंका रहती है। प्रत्येक संस्था अपने सदस्यों तथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों की उन्नति करने के प्रयत्न में यह बात भूल जाती है कि श्राख़िर, उस संस्था के चेत्र से बाहर के व्यक्ति भी तो भारतीय राष्ट्र के नागरिक हैं। एक जाति या धर्मवालों के लिए नौकरियों या राजनैतिक श्रिधकारों

की विशेष माँग करना, दूसरी जाति या घर्मवालों के हित की अव-हेलना करना है, और इस लिए ऐसी माँग राष्ट्र-हित-घातक है। वास्तव में जाति या घर्म के आधार पर जो संगठन हो, उन्हें राजनीति में उसी दशा में पड़ना चाहिए जब कि उनमें बहुत उदार या ब्यापक हृष्टि-कोण रखने की चुमता हो।

वर्तमान अवस्था में प्रायः ऐसा नहीं है। उदाहरणवत् मुसलिम लीग अपने आपको समस्त भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्थाः बताती हुईं, मुसलमानों के लिए ऐसे राजनैतिक अधिकार चाहती है, कि उनसे अन्य जातिवालों का सामंजस्य नहीं हो पाता उसका हिंद-कोण सिद्धान्त-हीन और राष्ट्र-विरोधी है। वह मुसलमानों के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में विशेष प्रतिनिधित्व तथा सरकारी नौकरियों में अपनी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान चाहती है। कुछ समय से वह यह भी माँग करने लगी है कि पंजाब, करमीर, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, विलोचिस्तान और सिंध इन पांच प्रान्तों में मुसलमान अधिक संख्या में बसते हैं, अतएव इन सब को एक में मिलाकर, इनका 'पाकिस्तान' नाम रखकर एक पृथक् मुसलिम राष्ट्र बनाया जाय। यह बात अनुचित होने के साथ कितनी अव्यावहारिक है. यह स्पष्ट है।

संतोष का विषय है कि मुसलिम लीग की आवाज़, मुसलिम जनता की आवाज़ नहीं है, और न सब मुसलिम नेताओं की ही। बहुत-से मुसलमानों ने व्यक्तिगत और सामृहिक रूप से मुसलिम लीग के प्रस्तावों का घोर विरोध किया है और वे आज भी कर रहे हैं। तथापि साम्प्रदायिक नेता अपनी ज़िंद्द पर अड़े हुए हैं। साम्प्रदायिक विचार-धारा में फैलने की प्रकृत्ति बहुत होती है। मुसलिम लोग की माँगों को देखकर भारतवर्ष की अन्य अलग-संख्यक जातियाँ भी अपने-अपने लिए विशेष अधिकारों की माँग करने लगी हैं। कुछ सिक्ख और हरिजन नेताओं ने अपना साप्रदायिक हिन्द-कोग्य, सरकार के सामने, उपस्थित किया है। कुछ अन्य हिन्दुओं में भी प्रतिक्रया हुई है। यह सब अत्यन्त चिन्तनीय है। साम्प्रदायिक विचारवाले व्यक्ति अपने सामने अखंड भारत का आदर्श नहीं रखते; इसका दोष कुछ अंश तक अधिकारियों पर ही है। वे साम्प्रदायिक नेताओं को आरम्भ से ही हतोत्साह करने की नीति रखें तो यह रोग इस सीमा तक बढ़ने न पाये।

३—राजनैतिक अनेकता—भारतीय राष्ट्र-निर्माण का कार्य पूरा होने में एक बाधा इस देश की राजनैतिक अनेकता है। भारतवर्ष के कुछ नगर फ्रांस और पुर्तगाल के अधीन हैं, आप से कुछ कम भाग देशी राज्य कहलाते हैं, और शेष भाग ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत में क़ानून का शासन हैं, और कुछ अंश में उत्तरदायी शासन-पद्धति भी है। यहाँ स्वतंत्रता का आन्दोलन हो रहा है। इसके विपरीत देशी राज्यों में (जहाँ तक भीतरी शासन का सम्बन्ध है) एक-तंत्र राज्य है। उनमें अनुत्तरदायी शासन-पद्धति है। इन देशी राज्यों की संख्या ५६० है, इन में से कितने ही तो मामूली गाँव सरीखे ही हैं। अधिकांश राज्यों का चेत्रफल, जन-संख्या और आय अञ्छे शासन की सुविधा के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इनके सम्बन्ध में कुछ विस्तार से

श्रागे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा। यहाँ यही कहना है कि ये सब ब्रिटिश सरकार के न्यूनाधिक श्राचीन हैं। इनके शासन का निरीक्षण या नियंत्रण सम्राट-प्रतिनिधि श्रार्थात् वायसराय के द्वारा होता है। श्रस्तु, श्रावश्यकता इस बात की है कि पूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्र हो, उस का कोई भाग किसी श्रन्य शक्ति के श्राधीन न हो।

राष्ट्रीय आन्दोलन के संचालकों के सामने ये सब बाधाएँ हैं, और वे यथा-सम्भव इनके निवारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में एक महत्व-पूर्ण कार्य स्वतंत्रता-प्राप्ति का होता है। इसके सम्बन्ध में अगले परिच्छेद में लिखा जायगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन का फल-राष्ट्रीयता के अभाव में, पहले भारतवर्ष केवल विचार-जगत् की वस्तु था। व्यवहार में यह देश अलग-अलग दुकड़ों में बटा हुआ था। एक प्रान्त के आदमी दूसरे प्रान्तवालों की भाषा ही नहीं समभते थे, फिर उनके सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानने की तो बात ही कैसे होती! एक ओर धर्म था जाति का भेद, दूसरी ओर प्रान्त-भेद, तीसरी ओर राजनैतिक भेद-भाव। फिर संगठन हो तो कैसे हो! अब भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीयता का थयेष्ट प्रचार हो गया है, तथापि हम बहुत-कुछ आगे बढ़े हैं। पिछले वर्षों से भारतवर्ष के दूर-दूर के भागों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार हो रहा है। अब मदरासी और आसामी तक उत्तर भारतवालों की भाषा सीख रहे हैं, उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने भाव प्रकट करने में विदेशी भाषा अँगरेजी का आअय न लेना होगा। और, जब हम एक-दूसरे की

भाषा समर्भेगे तो उनके दुख या कठिनाइयों को जानकर उसकी सहायता में भी भाग ले सकेंगे।

यद्यपि साम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता आदि के रोग से हम पूर्णत: मुक्त नहीं हुए हैं, देश में उन सज्जनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है जो अपने-आप को भारतवासी कहते और समभते हैं, जिनके लिए भारतवर्ष माता के समान पूज्य है, जो इस माता की सेवा-सुश्रूषा और उन्नति के लिए सुयोग्य सन्तान की भाँति तन-मन-धन से प्रयत्नशील हैं। कांग्रेस ने जनता के सामने राजनैतिक स्वाधीनता का विषय उपस्थित करके, उनकी संकीर्ण भावनाओं को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

श्रारम्भ में काँग्रेस मुद्वी भर श्रादमियों की संस्था थी, श्रातः उसके प्रचार का कार्य भी कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक ही परिमित था। श्राव उसका संगठन नगर-नगर श्रीर गाँव-गाँव में हो जाने से वह यथानाम राष्ट्रीय संस्था हो गयी है। ग्राम-सुधार यौर ग्रामीया उद्योग-धंघों की उन्नति का कार्य-क्रम रखने से उसका सम्मर्क प्रत्येक परिवार से है। वह जनता की संस्था है, श्रोर जनता में राष्ट्रीयता की भावना फैला रही है। नगर-निवासी श्रव गाँववालों के प्रति श्रपना कर्तव्य समक्त रहे हैं। इसी प्रकार यह श्रनुभव किया जा रहा है कि देश को ब्रिटिश भारत श्रीर देशी राज्यों में बाँटना कृत्रिम है; भारतवर्ष एक है श्रीर श्रखंड है।

श्रव हम स्वदेशी वस्त्र तथा स्वदेशी वस्तुश्रों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय संस्थाश्रों, स्वदेशी कला-कौशल, भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, और इस प्रकार इमारा स्वदेश-प्रेम काल्पनिक न होकर कियात्मक होता जा रहा है। इमारी शिक्षा और इमारा साहित्य अव राष्ट्रीय जाग्रति में सहायक हैं, देश-भक्ति के पाठ और गायन बालक बालिकाएँ प्रकट रूप से पढ़ती और सीखती हैं। इससे युवकों और युवतियों के हृदय में स्वदेश-प्रेम की लहर स्वतंत्रता-पूर्वक बहती है, और उन्हें राष्ट्र-सेवा के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार भावी नागरिकों को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का न केवल ज्ञान होगा, वरन् वे यथा-समय उस महान कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने आपको तैयार भी पार्येगे।

त्रव स्थान-स्थान पर युवक सम्मेलन तथा महिला सम्मेलन हैं, जो अपने-अपने चेत्र में राष्ट्र-सेवा के विविध श्रंगों में तन-मन-धन से लगे हुए हैं। इनके द्वारा नवयुवकों तथा महिलाओं की उन्नति का खूब प्रयत्न हो रहा है। सेवा समिति या बालचर (स्काउट्स) संस्था, रात्रि-पाठशालाएँ, नागरी प्रचारणी सभाएँ, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, ज्यायाम-सम्मेलन, ग्रह-निर्माण सभाएँ, सहकारी समितियाँ, मादक-द्रव्य-निषेध समितियाँ, किसान-हितकारिणी सभाएँ, मज़दूर सभाएँ आदि संस्थाएँ हमारी आधुनिक राष्ट्रीय जागरित का परिचय देती हैं।

## बत्तीसवाँ परिच्छेद

#### राजनैतिक विकास

है कि यहाँ श्रॅगरेज़ों के समय में, इस देश के शासन में क्यान्या परिवर्तन हुए श्रोर जनता ने स्वाधीनता के लिए क्या श्रान्दोलन किया। मोटे हिसाब से सन् १६०० से १७५७ ई० तक लगभग डेढ़ सौ वर्ष यहाँ ईस्ट-इंडिया-कम्पनी के व्यापार की वृद्धि हुई। फिर सन् १८५७ ई० तक, सौ वर्ष कम्पनी के राज्य का विस्तार हुआ। सन् १७७३ ई० से पालिमेंट प्रति बीसवें वर्ष कम्पनी के प्रबन्ध की जाँच करती थी, श्रोर कम्पनी को नयी सनद देती थी। समय-समय पर भारतवर्ष के शासन के कई क़ानून बने। उनके सम्बध में विशेष विचार न कर, केवल यही वक्तव्य है कि उस समय शासन-व्यवस्था में भारतवासियों का कुछ हाथ न था। सन् १८५८ ई० से भारतवर्ष का शासन कम्पनी से ब्रिटिश पालिमेंट ने ले लिया। उस समय से श्रव तक का समय तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है:—

- (१) सन् १८५८ ई० से १९१९ तक प्रान्तों में व्यवस्थापक परिषदें स्थापित की गर्थी। उनमें क्रमशः जनता के प्रतिनिधि लिये जाने लगे, पर उनका निर्वाचन अधिकांश में अप्रत्यत्त होता था। शासक इन परिषदों के प्रति उत्तरदायी न थे। सन् १८७० श्रीर विशेषतया सन् १८८४ ई० से यहाँ स्थानीय स्वराज्य-संस्थान्नों की वृद्धि होने लगी।
- (२) सन् १९१९ ई० से १९३५ ई० तक प्रान्तों में श्रंशतः उत्तर-दायी शासन रहा।
- (३) सन् १९३५ ई० में नया शासन विधान बना, जिससे प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया तथा समस्त भारतवर्ष के शासन के जिए संघ की योजना हुई।

कांग्रेस और शासन-सुधार आन्दोलन—एन् १८६५ ई० में यहाँ कांग्रेस स्थापित होने की बात पहले कही जा चुकी है। आरम्भ में उसकी नीति भारत-सरकार या ब्रिटिश सरकार की सेवा में, शासन-सुधारों के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन भेजने की रही। बहुत-कुछ इसके आन्दोलन के फल-स्वरूप सन् १८९२ ई० के कौंसिल-कानून तथा उसके बाद बननेवाले कायदों से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों में कुछ परिवर्तन हुआ। उनके सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, पर कुल सदस्यों में अधिकांश प्राय: सरकारी ही रहे। उन्नत प्रान्तों में ग्रैर-सरकारी सदस्यों को, अधिकांश में सार्वजनिक संस्थाओं की सिफ़ारिश यर नामज़द किया जाने लगा। परिषदों को बजट के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने और बाद-विवाद करने का अधिकार मिला। परन्तु वे उस पर आपना मत नहीं दे सकती थीं; बजट निश्चय करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धकारणी सभा की ही था।

सन १९०५ ई० में वायसराय लार्ड कर्ज़न के समय में बंगाल के दो भाग कर दिये जाने पर देश भर में असंतोष की लहर फैल गयी। सरकार ने बहुत दमन किया, पर जनता का चोभ बना रहा. श्रीर समय-समय पर हिंसात्मक घटनात्रों में भी प्रकट हुन्ना। राष्ट्रीय नेतात्रों तथा कांग्रेस ने हिंसा का नियंत्रण किया। क्रमशः कांग्रेस में कल सज्जन विशेष उत्साह या जोशवाले हो गये। इन्हें गरम दल का कहा जाने लगा। कांग्रेस के नेतृत्व में जनता का शासन-सधार सम्बन्धी आन्दोलन बढ़ता रहा। सन् १९०९ में मार्ले-मिन्टों सुधार किये गये। इनके श्रनुसार व्यवस्थापक परिषदों से सरकारी सदस्यों की श्रिधिकता हटा दी गयी; श्रीर कुल सदस्यों की संख्या बढायी गयी। निर्वाचन का सिद्धान्त मान्य किया गया. परन्त केवल परिमित निर्वाचक-संघ श्रौर श्रप्रत्यच निर्वाचन का ही लक्ष्य रखा गया। म्युनिसपैलिटियों श्रीर जिला-बोडों के श्रितिरिक्त मुसलमानों, ज़मीदारों श्रीर खानवालों श्रादि को निर्वाचन-श्रधिकार दिया गया। परन्तु यह निश्चय किया गया कि परिषदों द्वारा बनाये हुए जिस कानून को सरकार नापसन्द करे, उसे वह श्रस्वीकार कर दे। इन सुघारों से राष्ट्रीयता-घातक जाति-गत प्रतिनिधित्व की भी स्थापना हुई।

मार्जे-िमंटो सुधारों से कुछ श्रादिमयों को क्षियिक संतीष हुश्रा, पर शीव्र ही उनमें से भी बहुत-सों का भ्रम दूर होगया। योरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) श्रारम्भ हो जाने पर मित्र-राष्ट्रों के राजनीतिशों के मह से छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता श्रीर स्वभाग्य-निर्णय श्रादि की

बातें सुन कर, तथा श्रायलैंड को स्वराज्य पाते देखकर भारतवासी भी श्रपने जन्म सिद्ध श्रिषकार, स्वराज्य प्राप्ति के लिए उत्सुक हो गये। सन् १९१६ ई० में शासन-सुधार की एक योजना तैयार की गयी; कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग दोनों से स्वीकृत होजाने पर इसका नाम 'काँग्रेस-लीग योजना' प्रसिद्ध हुआ। ता० २० श्रगस्त १९१७ को भारत-मंत्री ने पार्लिमेंट में घोषणा की कि 'ब्रिटिश सरकार की नीति भारतीयों को शासन के प्रत्येक भाग में श्रिष्ठिकाधिक स्थान देने तथा क्रमशः स्वराज्य-संस्थाओं की बृद्धि करने की है, जिससे भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का श्रंग रहते हुए घीरे-घोरे उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्राप्त कर सके। ब्रिटिश सरकार तथा भारत-सरकार प्रत्येक उन्नति के कम का निश्चय करेंगी।' इस घोषणा का तथा इस श्राघार पर प्रकाशित १९१८ ई० की मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड, या संचेप में मांट-फोर्ड सुधार-योजना का स्वराज्याभिलाषो भारतीयों के लिए श्रसंतोषपद रइना स्वाभाविक था।

सत्याग्रह और श्रसहयोग — इसी श्रवसर पर सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों के घोर विरोध की परवा न कर, एक दमनकारी कानून बना डाला, जो पीछे 'रौलेट ऐक्ट' कहलाया। देश भर में इसके विरुद्ध घोर श्रान्दोलन हुआ। महात्मा गांधी ने जनता को सत्याग्रह श्रौर श्रसहयोग का मार्ग दिखाया। ५ श्रप्रेल १९१९ को रिववार के दिन घर-घर लोगों ने ब्रत रखा, बाज़ार का काम बन्द रहा। इड़तालें हुई। नंगे पांव श्रौर नंगे सिर श्रसंख्य जनता का शहर-शहर में ही नहीं गांव-गांव तक में जलूस निकला, श्रौर बड़ी-बड़ी सभाएँ होकर उनमें रौलेट ऐक्ट के सम्बन्ध में भाषण हुए। इन बातों से जनता को आत्म-बल का ज्ञान हुआ, राजनैतिक आन्दोलन ने व्यापक और प्रचंड रूप धारण किया। अधिकारियों ने भरसक दमन किया। उन्होंने नेताओं को गिर-फ़ार किया। कई जगह निरस्त्र जनता को दबाने के लिए पुलिस के सोटे, और बन्दूकों भी काफ़ी न समभी जाकर मशीनगनों तक का व्यवहार किया गया। पंजाब में तो 'मार्शल ला' (फौज़ी कानून) के ऐसे रोमांचकारी कांड हुए, जो स्वयं कितने-ही ब्रिटिश नेताओं के मत से सर्वथा अ-ब्रिटिश और ब्रिटिश शासन के इतिहास में कलंक के टीके हैं।

यद्यपि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में भी व्यक्तिगत या सामाजिक सत्याग्रह के अनेक उदाहरण मिलते हैं, तथापि राजनैतिक सत्याग्रह का विशेष विकास इसी काल में हुआ है। जनता के दुखों पर ध्यान न देनेवाले राजा या सरकार से असहयोग करने की बात भी कुछ नयी नहीं है। परन्तु सरकारी स्कूलों, अदालतों, व्यवस्थापक सभाओं, और नौकरियों को छोड़कर तथा अन्त में सरकारी कर न देकर सरकार से असहयोग करने के कार्यक्रम को निर्धारित करने का अय महातमा गांधी को ही है। एक बड़े देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की भावनाओं तथा स्वार्थवाली जनता में, इस प्रकार के असहयोग का कार्यक्रम पूरा होना बहुत कठिन है। तथापि इसकी अमोघ शक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता। और, यह आन्दोलन जितने भी अंश में यहाँ सफल हो सका है, इसने जनता की शक्ति बढ़ाने का अभूत-पूर्व कार्य किया है।

मांट-फोर्ड-सुधार, साइमन कमीशन श्रीर दमन— सन् १९१९ ई० के मांट-फोर्ड सुधार, श्रगते वर्ष से कार्य में परिणत किये गये। इनका उद्देश्य प्रान्तों में श्रंशतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इनके श्रनुसार प्रान्तों की शासन-पद्धति कैसी रही, यह छत्तीसर्वे परिच्छेद में बताया जायगा। प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की श्रीर मतदाताश्रों की संख्या बढ़ायी गयी थी, पर उससे जनता को संतोष नहीं हो सका। कई बार प्रान्तों में मंत्रियों का वेतन घटाने श्रादि के श्रसंतोष-सूचक प्रस्ताव पास हुए। भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, श्रीर उसमें एक की जगह दो सभाएँ कर दी गर्थी—भारतीय व्यवस्थापक सभा श्रीर राज्य परिषद। इनके सम्बन्ध में विशेष श्रागे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा। स्मरण रहे कि इन सुधारों से केन्द्र में श्रशतः भी उत्तरदायी शासन श्रारम्भ नहीं किया गया था।

सन् १९१९ के क़ानून में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष में एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो जाँच कर के इस बात की रिपोर्ट करे कि उस समय जो शासन-पद्धति प्रचित्त हो, उसे कहाँ तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है। यह कमीशन १९२७ ईं॰ में नियुक्त हुआ, और अपने सभापित के नाम से 'साइमन कमीशन' कहलाया। इसके सात सदस्यों में सब आँगरेज थे, भारतवासी एक मी नहीं। अधिकांश आँगरेज़ सदस्य भी अनुदार विचारवाले थे। अतः यहाँ के विविध राजनैतिक दलों ने इसका विहस्कार कर दिया। राष्ट्रीय विचारवाले सजनों ने इसके सामने गवाही नहीं दी। कमीशन की रिपोर्ट सन् १९२९ ई० में प्रकाशित हुई; उसकी भारतवर्ष में सर्वत्र निन्दा हुई।

इस बीच में सन् १९१८ ई० में कांग्रेस ने सर्व-दल सम्मेलन का श्रायोजन करके श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की योजना तैयार की। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस योजना में सचित देश की भावाज़ सनी-अनसनी की। इसलिए यथेष्ट प्रतीक्षा कर चुकने पर लाहौर में कांग्रेस ने ३१ दिसम्बर १९२९ को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सन् १९३० ई० में नमक-कानून तोड़कर सत्याग्रह का श्रीगरोश किया गया। क्रमशः आन्दोलन बढता ही गया। सरकार ने इसे दमन करने के लिए नये-नये ब्रार्डिनेंस ( श्रस्थायी कानून ) जारी किये । सत्याग्रह सम्बन्धी समाचार छापने से रोककर उसने राष्ट्रीय समाचार-पत्रों को मूर्छित कर दिया। विदेशी वस्त्रों श्रीर शराब की दुकानों पर घरना देनेवाले सहस्रो श्रादमियों को न केवल जेल की यातनाएं दी गयीं. वरन् बहुत-सों पर श्रीर भी तरइ-तरइ की सिख्तयां की गयीं। लाठी-वर्षा तो उन दिनों एक मामूली बात थी। पुरुषों ने ही नहीं. स्त्रियों श्रीर बालकों ने भी पुलिस की लाठियाँ खूब सही। बहत-से श्रादिमयों की ज़मीन-जायदाद कुर्क की गयी। कितनी-ही जगह गोलियां चलीं. श्रीर श्रनेक माई के लाल मातृ-भूमि के उत्थान में काम श्राये।\*

नागरिकों के मूल श्रिधिकार—मार्च सन् १९३१ ई॰ में कांग्रेस श्रीर सरकार में च्याक संघि होने पर, कांग्रेस का श्रिविशन

<sup>\*</sup>सन् १९३२-३३ में भी ऐसी ही घटनात्रां की पुनरावृत्ति हुई।

करांची में हुआ। रावी-तट (लाहौर) पर की हुई पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा तो यहाँ दोहरायी ही गयी; इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस ने जो स्वराज्य निर्धारित किया है, उसका आशय क्या है। कांग्रेस ने राजनैतिक के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता को भी आवश्यक बताते हुए, स्वराज्य-सरकार में निम्नलिखित बातों के होने की सूचना दी:—

—नागरिकों के मूल श्रधिकार, जैसे (क) सभा-समितियाँ करने की स्वतन्त्रता, (ख) भाषण और समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता, (ग) जहाँ तक सार्वजनिक शान्ति और सदाचार के विरुद्ध न हो. घर्म को मानने श्रीर उसके श्रनुसार काम करने की स्वतन्त्रता, (व) श्रलप-संख्यक समुदायों की संस्कृति, भाषा और विवि की रचा. (च) स्त्री-पुरुष का भेद न करते हुए सब नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्व की समानता. (छ) धर्म या जाति के कारण किसी व्यक्ति के लिए कोई सरकारी नौकरी, पद, श्रधिकार या सम्मान पाने श्रथवा कोई रोज़गार या पेशा करने में प्रतिबन्ध न होना, (ज) सार्वजनिक सद्कों, कुत्रों तथा जनता के लिए बनाये हुए श्रन्य स्थानों के उपयोग का सब नागरिकों को समान श्रधिकार, (म) निर्धारित नियमों और रकावटों के अनुसार, इथियार रखने और बाँधने का अधिकार, (ट) क्रानून में सूचित श्रवस्था के सिवाय, किसी की स्वतन्त्रता का हरगा न किया जाना, किसी के घर जायदाद में प्रवेश न करना, श्रीर न उसका छीना या ज़ब्त किया जाना, (ठ) धार्मिक विषयों में राज्य की तटस्थता, (ड) इर एक बालिग़ श्रादमी को मताधिकार, (ढ) श्रनिवार्य

#### प्रारम्भिक शिचा।

२—श्रमजीवियों की व्यवस्था, (क) कल कारख़ानों में काम करने-वालों के निर्वाह के लिए यथेष्ट वेतन, (ख) काम करने के परिमित्त घरटे, (ग) काम करने का स्वास्थ्यप्रद प्रबन्ध, (घ) बुदापे, बीमारी या बेकारी के श्रार्थिक परिणामों से रचा, (च) दासता या उससे मिलती-जुलती दशा से श्रमजीवियों की मुक्ति, (छ) श्री-श्रमजीवियों की रचा, विशेषतया प्रसृति के समय छुट्टी का यथेष्ट प्रबन्ध, (ज) स्कूर्जों में पदने लायक उम्र के बच्चों के, खानों में भरती होने का निषेत्र, (म) श्रपने हितों की रचा करने के लिए श्रमजीवियों का संघ बनाने का श्रधकार, धीर मान्हों को पंचायतों द्वारा निपटाने की समुचित व्यवस्था।

३—राजकीय कर श्रीर व्यय, (क) जिन खेतों से लाभ न होता हो, उनके किसानों से दिये जानेवाले लगान श्रीर किराये में काफी छूट, श्रीर श्रावश्यक समय तक लगान की माफी, (ख) कृषि से होनेवाली निर्धारित परियाम से जपर की श्राय पर क्रमशः वर्द्धमान कर, (ग) विरासत की आयदाद पर क्रमशः वर्द्धमान कर, (घ) सैनिक व्यय में वर्तमान परिमाण के कम-से कम श्राधे की कमी, (च) मुलकी विभागों के वेतन श्रीर व्यय में बहुत कमी; विशेष दशा में नियुक्त विशेषज्ञों श्रथवा ऐसे ही व्यक्तियों को छोड़कर किसी सरकारी नौकर को प्रायः पाँच सौ क्षये से श्रधिक मासिक वेतन न दिया जाना, (घ) देशी नमक पर कर न होना।

४— आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था, (क) विदेशी कपड़े और स्त को देश में न आने देकर स्वदेशी वस्त को प्रोश्साहन, (ख) शराब तथा भन्य मादक वस्तुओं की रुकावट, (ग) मुद्रा श्रीर ब्यापार-नीति का इस प्रकार नियन्त्रण कि स्वदेशी उद्योग-धन्धों को सहायता मिले श्रीर जनता का हित हो, (घ) मुख्य उद्योगों श्रीर खनिज साधनों पर राज्य का नियन्त्रण, (च) प्रत्यच श्रीर परोच सुद्खोरी पर नियन्त्रण।

सन् १९३० से १९३२ तक लदन में श्रॅगरेज़ों श्रौर भारतीयों की तीन बार 'गोल-मेज़-सभा' हुई। इनमें से केवल दूसरी में कांग्रेस ने, महात्मा गांधी के द्वारा, भाग लिया। गोल-मेज़-सभाशों तथा विविध कमेटियों के परिणाम-स्वरूप शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 'श्वेत पत्र' में प्रकाशित किये गये। श्रौर यह श्वेत पत्र पार्लिमेंट की दोनों सभाशों की संयुक्त कमेटी के सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया। श्राखिर, सन् १९३५ ई० में पार्लिमेंट ने नवीन भारतीय शासन विधान की रचना की।

इस विधान के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व, यह बता देना आवश्यक है कि देशी राज्यों में विगत वर्षों में राजनैतिक जागृति कैसी हुईं।

देशी राज्यों की जागृति—इस परिच्छेद में श्रभी तक जिस राजनैतिक विकास का परिचय दिया गया है, वह श्रिषकतर ब्रिटिश भारत सम्बन्धी है। परन्तु भारतवर्ष का ख़ाता बड़ा भाग देशी राज्यों का है। ब्रिटिश भारत श्रीर देशी राज्यों का चोली-दामन का साथ. है। इनका परस्पर में सामाजिक, श्रार्थिक, ऐतिहासिक श्रीर राजनैतिक श्रादि सभी प्रकार का धनिष्ट सम्बन्ध है। देशी राज्यों में होनेवाले, श्रिषकारियों के श्रन्याय श्रीर श्रत्याचार कुछ श्रंश में ब्रिटिश भारत से भी अधिक थे। उनके निवासी अपने पड़ोसियों के शासन-सुधार और स्वाधीनता आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना न रहे। सत्याग्रह और विदेशी विहष्कार आदि में उन्होंने भी यथा-शक्ति भाग लिया। क्रमशः उनकी जनता में अधिकाधिक जाग्रित होती गयी। कई रियासतों में विविध आन्दोलन हुए, पर अव्यवस्थित और असंगठित होने के कारण उनका विशेष फल न निकला। अन्ततः सन् १९२७ ई० में 'अखिल भारतवर्षीय देशी राज्य-प्रजा परिषद' की स्थपना हुई, जिसका उद्देश्य देशी नरेशों को सुधार करने के लिए प्रेरित करना तथा समय-समय पर संसार के सामने प्रजा की मांग उपस्थित करना है।

परिषद् की श्रोर से सन् १९२७ की मदरास-कांग्रेस में प्रतिनिधि-मंडल गया, श्रीर उसके प्रयत्न से कांग्रेस ने देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार की । देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से श्रार्थिक सम्बन्ध कैसा हो, इसका विचार करने के लिए सरकार की श्रोर से दिसम्बर १९२७ ई० में 'इंडियन स्टेटस कमेटी' नियुक्त हुई, इसे उसके सभापति के नाम पर 'बटलर कमेटी' कहते हैं । उसकी रिपोर्ट जनता की हिन्द से असंतोषप्रद रही । इस पर प्रजा-परिषद ने श्रपना प्रतिनिधि-मंडल इंगलैंड मेजकर उसका विरोध किया ।

गोलमेल-सभा में, भारतवर्ष के लिए संघ-शासन की योजना की गयी। कुछ नरेशों तथा ब्रिटिश श्रिषकारियों ने प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष के भावी संघीय (केन्द्रीय) व्यवस्थापक मंडल में नरेशों के प्रतिनिधि रहें, जनता के नहीं; इसका प्रजा परिषद ने घोर विरोध किया। सन् १९३१ ईं०

में परिषद ने सर्वसाधारण के सामने देशी राज्यों की कम-से-कम मांग उपस्थित की। उसकी मुख्य बातें ये थीं:—

- १—देशी राज्यों के लोगों की संघ-राज्य की नागरिकता और उनके मूल अधिकार शासन-विधान में दर्ज हो।
- ्र—देशी राज्यों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, शासन-विधान में संघीय न्यायालय की व्यवस्था हो।
- ३— संघीय व्यवस्थापक मंडल की सभात्रों में देशी राज्यों के निवासियों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, श्रीर इसके लिए उन्हें भी ब्रिटिश भारत में प्रचलित निर्वाचन-पद्धति श्रीर मताधिकार मिले।

कांग्रेस का कार्य-चेत्र आरम्भ में ब्रिटिश भारत ही था। यद्यपि देशी राज्यों के निवासियों के, उत्तरदायित्व-पूर्ण् शासन स्थापित कराने के शान्तिमय प्रयत्न से कांग्रेस पूर्णं सहानुभूति रखती रही परन्तु उसने उनके मामलों में विशेष हस्तचेप न करने की ही नीति रखी। यह बात बहुत-से कार्य-कर्ताओं को खटकती रही। क्रमशः देशी राज्यों की प्रजा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हढ़तापूर्वक आगे बढ़ती गयी, पर कितने-ही देशी नरेश उनकी जागृति को दबाने के लिए प्रजा पर अत्याचार करने लगे। इस पर कांग्रेस की मावना व्यक्त करनेवाले महात्मा गांधी ने सन् १९३८ के अन्त में देशी नरेशों को चेतावनी देते हुए, 'हरिजन' में साफ्त कह दिया कि या तो वे अपना अस्तित्व बिलकुल मिटा देने के लिए तैयार हो जायँ अथवा अपनी प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी शासन के अधिकार दें, और स्वयं उसके संरक्षक होकर रहें, और अपने परिश्रम के लिए पुरस्कार लें।

महात्माजी ने देशी नरेशों को कांग्रेस से मित्रता करने की सलाह देते हुए लिखा है कि निश्चय ही उनके लिए यह हितकर है कि वे उस सस्था के साथ मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें, जो, भविष्य में बहुत शीघ्र ही, भारतवर्ष में सार्वभीम सत्ता का स्थान लेनेवाली है। महात्माजी ने नरेशों से कहा है कि क्या वे दीवार पर लिखे स्पष्ट श्रक्षरों को पढ़ेंगे! श्राज भारतीय जनता भी, नहीं-नहीं, संसार भारतीय नरेशों से पूछ रहा है कि क्या वे युग-संकेत को समर्भेंगे श्रीर श्रपना कर्तव्य पालन करेंगे।

यह स्पष्ट है कि हमारा राजनैतिक विकास, देश के केवल एक भाग ब्रिटिश भारत तक ही परिमित नहीं है, वह देशी राज्यों में भी है। और, वास्तव में यह हो भी नहीं सकता कि देश के एक हिस्से में सूर्य का प्रकाश हो और दूसरा हिस्सा अन्वकार में पड़ा रहे। अस्तु, अब नये शासन-विधान का विचार करें, जो इस समय प्रचलित है।

वर्तमान शासन विधान—इस विभान की प्रथम विशेषता यह है कि इसके अनुसार भारतवर्ष में केन्द्रीय सरकार का स्वरूप 'संघ सरकार' रखा गया है, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों शामिल हों। सिद्धान्त से भाषा, धर्म, जाति, व्यवहार आदि की हष्टि से भारतवर्ष एक और अखंड है। इसके नक्शे में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के लाल और पीले दिखाये जानेवाले भेद कृतिम हैं। इसलिए भारतवर्ष का शासन संघ-शासन होना उचित ही है, पर विधान का वर्तमान रूप अत्यन्त असंतोषप्रद है; संघ के एक भाग

(ब्रिटिश भारत) में शासन उत्तरदायी होना श्रीर दूसरे भाग (देशी राज्यों) में उसका स्वेच्छाचार-मूलक बना रहना श्रव्याव-हारिक है।

इस विधान की दूसरी विशेषता यह है कि केन्द्र में भी उत्तरदायी शासन स्थापित करने का निश्चय किया गया है। परन्तु उसमें कई महत्व-पूर्ण विषयों में गवर्नर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व माना गया है तथा कुछ विषय ऐसे निर्धारित किये गये हैं, जिन का शासन गवर्नर-जनरल अपने परामर्शदाताओं की सलाह से, अपनी समफ के अनुसार करेगा। इस प्रकार वह जनता के प्रतिनिधियों के प्रति बहुत ही कम उत्तरदायी होगा।

इस विधान की तीसरी विशेषता है, 'प्रान्तीय स्वराज्य'। इस 'विधान के अनुसार अब प्रान्तीय शासन का क्या स्वरूप है, गवर्नरों 'के क्या विशेषाधिकार हैं, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के अधिकारों 'पर कितने प्रतिबन्ध हैं, यह आगे प्रसंगानुसार छुत्तीसवें और सैंतीसवें 'परिच्छेद में बताया जायगा।

इस विधान के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह विधान ऐसा नहीं है; जो पूर्ण हो, या स्वयं विकसित होनेवाला हो। यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक महत्व-पूर्ण परिवर्तन इंगलैंड में ही होगा, या तो वह पार्लिमेंट के क्रान्त से होगा अथवा सम्राट्की आजाओं से होगा। भारतवर्ष में, भारतवासियों द्वारा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता।

विधान का प्रयोग-नवीन शासन विधान के अनुसार प्रान्तीय

व्यावस्थापक मंडलों का प्रथम चुनाव होने पर छ: प्रान्तों (बम्बई मदरास, संयुक्तप्रान्त, विहार, उड़ीसा श्रीर मध्यप्रान्त ) में कांग्रेस-दल का बहुमत था। इसलिए इन प्रान्तों के गवर्नरों ने कांग्रेस-दल के नेताओं को अपने प्रान्त में मंत्री-मंडल बनाने के लिए बुलाया। परन्त कांग्रेष ने मंत्री-पद ग्रहण करना उस समय तक श्रस्वीकार किया जब तक कि गवर्नर यह आश्वासन न देदें कि वे रोज़मरों के शासन कार्य में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे। ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार न थी। श्रतः विधान को श्रमल में लाने के लिए जब श्रन्यः प्रान्तों में बहुमतवाले दलों के, मंत्री-मंडल बने, जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था, उनमें श्रलग-संख्यक दलों द्वारा 'श्रस्थायी मंत्री-मंडल' बनाये गये; इन्हें जनता ने 'गुडिया मंत्री-मंडल' नाम दिया। श्रविश्वास के प्रस्ताव के भय से, ये मंत्री-मंडल व्यवस्थापक सभाग्रों का ऋधिवेशन न कर सके। देश में महान वैधानिक संकट उपस्थित हो गया। भारत-मंत्री श्रादि के वक्तव्य निकले, कांग्रेस की श्रोर से महात्मा गांघी ने जनका उत्तर दिया । श्रन्ततः गवर्नर-जनरल ने यह श्राश्वासन दिया कि श्राम तौर से शासन-कार्य मत्री-मंडल करेंगे श्रीर गवर्नर उनकी सलाह मानेंगे. उसमें इस्तचेप न करेंगे। इस पर कांग्रेस ने उक्त छ: प्रान्तों में मंत्री-मंडल बनाये। पश्चात पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, श्रीर श्रासाम में भी कांग्रेसी मंत्री-मंडल हो जाने से, गवर्नरों के ग्यारह प्रान्तों में से आद में कांग्रेस-शासन हो गया।

काँग्रेस द्वारा पद-ग्रह्ण किये जाने से काँग्रेसी प्रान्तों में नया राज-नैतिक वातावरण हो गया। जनता अपनी शक्ति और अधिकारों को समभने लगी। मंत्रियों ने भी जनता की श्रमुविधाएँ दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। राजबन्दी छोड़े गये, प्रेसों की ज़मानतें वापस की गयीं। पुस्तकालय खोले गये। पंचायतों की वृद्धि की गयी। मद्य-पान-निषेध का कार्य श्रारम्भ किया गया। मज़दूरों की स्थिति सुधारने की कोशिश की गयी। बिहार श्रीर संयुक्तप्रान्त में किसानों के हित का कान्त्र तथा मदरास में ऋण्य-निवारण-क़ान्त्र बनाया गया। काँग्रेस का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचा। सन् १९३८ ई० में इसके सदस्यों की संख्या तीन लाख थी। किसी एक संस्था के इतने सदस्य होना एक श्रमुपम बात है। यदि सब सदस्य श्रपने कर्तव्यों का सम्यक् पालन करें तो देश का राजनैतिक उत्थान होने में शंका या विलम्ब न हो।

विधान-निर्मातृ सभा—पहले कहा जा चुका है कि जनता को, विशेषतया कांग्रेसी विचार-धारावाले व्यक्तियों को यह विधान अत्यन्त असंतोषप्रद प्रतीत हुआ था। कांग्रेस इस विधान के द्वारा नागरिक अधिकारों की वृद्धि, अथवा जनता के कष्ट-निवारण का जो कार्य कर सकती थी, उससे संतुष्ट न थी। उसका लक्ष्य जनता को संगठित कर स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ाना था। उसके पद-प्रहण करने का एक मुख्य कार्य 'विधान-निर्मातृ-सभा' का आयोजन करना था।

जब क्रान्ति या अन्य किसी कारण से देश का पुराना शासन-यंत्र बेकाम हो जाता है, तो जो व्यक्ति अस्थायी रूप से शासन-सूत्र अहण करते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि शीघ्र जनता के प्रतिनिधियों की समा बुलायें, जो नये शासन-विधान का मसौदा तैयार करे। पश्चात् इस विधान के अनुसार नयी सरकार का संगठन हो जाने पर यह सभा सब शासन-सूत्र उसे सोंप देती है, और स्वयं भंग हो जाती है। यह सभा 'विधान-निर्मातृ-सभा' कहलाती है। इसकी रचना व्यापक मता- धिकार पर होती है। यह जनता की सीधी प्रतिनिधि होती है और इसका काम केवल शासन-व्यवस्था का नया स्वरूप निश्चित करना, और उस पर जनता की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। यह सभा समस्त श्रधिकारियों से ऊपर होती है। कोई व्यवस्थापक सभा या प्रबन्धकारियों इसके कार्य में इस्तत्तेप नहीं कर सकती। इस सभा का चुनाव यथा-सम्भव इस प्रकार किया जाता है कि इसमें सब विचारों के श्रादमी श्रा जाते हैं, और इसके निश्चय जनता की सम्मिलित इच्छा को सूचित करनेवाले होते हैं। किसी पार्टी या दल को इसके निर्णय में श्राशंका करने का कारण नहीं होता।

विशेष वक्त व्य — कांग्रेस ने अपने अन्यान्य कार्यों में ऐसी सभा के निर्माण के पक्ष में लोकमत तैयार करने का भरसक प्रयत्न किया। वह थोड़े ही समय (ढाई वर्ष) पदारूढ़ रही थी कि सन् १९३९ ईं क्में योरप में महायुद्ध छिड़ गया। इज्जलैंड ने उसमें भाग लिया तो भारतवर्ष की प्रान्तीय सरकारों का मत लिये बिना ही, उसने भारतवर्ष को युद्ध-संलग्न राज्य घोषित कर दिया तथा यहाँ युद्ध-सम्बन्धी तैयारी का आयोजन करने लगा। इससे प्रान्तीय सरकारों को अपने अधिकारों तथा प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता का अनुभव हुआ। कांग्रेसी सरकारों ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य पूछा और इसका संतोषप्रद उत्तर न पाकर त्याग-पत्र दे दिया। जिन-जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल थे, उनमें अब नवीन शासन-विधान स्थिगित

है। गवर्नरों का एक-छत्र श्रिषकार है। यह बात भारतवासियों के लिए तो श्रमस्य है ही, उस इंगलैंड के लिए भी बहुत बदनामी की है, जो योरप में स्वतन्त्रता श्रीर प्रजातन्त्र-स्थापना के लिए युद्ध करने का दावा करता है।

वर्तमान स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। परन्तु, हम आशा-वादी हैं। यह स्थिति बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती। महात्मा गाँधी आदि महानुभावों के नैतृत्व में काँग्रेस अथवा भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार को परेशान करना, उसके संकट से लाभ उठाना नहीं चाहती, परन्तु वह अपने जन्म-सिद्ध अधिकार का परित्याग कर अपमानजनक जीवन भी व्यतीत करना नहीं चाहती। भारतवर्ष स्वाधीनता की आरे आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी यह यात्रा पूरी होकर रहेगी, जो शक्तियाँ इसमें सहयोग प्रदान कर सकें, के घन्य हैं।

## तेतीसवाँ परिच्छेद ब्रिटिश सरकार श्रीर भारतवर्ष

ित्रु छते परिच्छेदों में भारतवर्ष के घार्मिक सामाजिक, आर्थिक

आदि विषयों पर विचार किया गया। अब इम यह विचार करेंगे कि भारतवर्ष का शासन किस प्रकार होता है। पहले यह जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष स्वतंत्र देश नहीं है। इसका शासन ब्रिटिश सरकार की अधीनता में होता है। इसकिए पहले ब्रिटिश सरकार के बारे में ही आवश्यक बातें बतलायी जाती हैं, इसके साथ ही यह भी बतलाया जायगा कि उसका भारतवर्ष से क्या सम्बन्ध है।

ब्रिटिश सरकार के मुख्य तीन श्रंग है (१) इंगलैंड का बादशाह जो मारतवर्ष का सम्राट् कहलाता है (२) पार्लिमेंट, श्रौर (३) मंत्री-मंडल।

बादशाह — इज्जर्तेंड का बादशाह अपने वंश के ही कारण, सिंहा-सन का उत्तराधिकारी होता है। पुरुष भी गद्दी पर बैठ सकता है और स्त्री भी। परन्तु शाही ख़ानदान में बहिन से भाई का अधिकार अधिक माना जाता है। बादशाह के बड़े लड़के को 'प्रिस-आफ-वेल्ज़' (युवराज) कहते हैं। शाही परिवार के ख़र्च के लिए प्रति वर्ष पार्लिमेंट द्वारा निर्धारित रक्तम दी जाती है। बादशाह सर्वथा स्वतंत्र नहीं होता; यद्यपि उसे कुछ विशेष अधिकार हैं। आम तौर से वह अपने अधिकारों को मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता। सब कामों के उत्तरदाता मंत्री होते हैं, वे पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

पार्लिमेंट — ब्रिटिश पार्लिमेंट की दो सभाएँ हैं। (१) सरदार-सभा या 'हाउस-आफ़-लार्ड् स' श्रीर प्रतिनिधि-सभा या 'हाउस-श्राफ़-कामन्त'। 'लार्ड् स' का अर्थ है मूमि-पित या स्वामी, श्रीर 'कामन्तत' का श्रर्थ है सर्वसाधारण। सरदार-सभा में लगभग सात सौ सदस्य हैं। इनमें से छः सौ से श्रविक वंशागत हैं। प्रतिनिधि-सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। उनकी संख्या ६१५ है। स्त्रियों को निर्वाचन-श्रविकार पुरुषों के समान है। इस सभा का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य को चार सौ पौंड वार्षिक वेतन पाता है। सदस्यों का चुनाव प्रायः प्रति पाँचवें वर्ष होता है। पार्लिमेंट ब्रिटिश साम्राज्य के सम्बन्ध में श्रावश्यक कानून बनाती है, श्रीर उसे कुछ शासन श्रीर प्रवन्ध-सम्बन्धी श्रविकार भी हैं। उसने ये श्रविकार प्रिवी कौंसिल श्रीर मन्त्री-मंडल श्रादि को दे दिये हैं।

बादशाह को शासन-कार्य में परामर्श देने के लिए एक विवी कींसिल (गुप्त सभा) रहती है। इसके सदस्यों को बादशाह स्वयं नियत करता है। इसकी जुड़ीशल (न्याय-सम्बन्धी) कमेटी को भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की ऊँची श्रदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनने का अधिकार है। इस सभा के कुल सदस्यों की संख्या ३०० से ऊपर हो जाती है। छः सदस्यों की उपस्थिति में भी काम किया जा सकता है। सम्राट्की परिषद कहने से इसी सभा का आश्या लिया जाता है। इस सभा की सलाह से सम्राट्की जो आशाएँ निकलती हैं, उन्हें स्परिषद सम्राट्की आशाएँ (आर्डर्स-इन-कोंसिल) कहा जाता है।

मंत्री-मंडल-श्राजकल इंगलैंड में तीन राजनैतिक दल या पार्टियां मुख्य है, (१) उदार या 'लिबरल' (२) श्रनुदार या 'क्कड़ोंटिव' (३) मज़दूर या 'लेबर' दल। शासन सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस दल के श्रादमियों में नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि-सभा में सबसे श्रधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली हो। ये पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं, श्रौर मंत्री या मिनिस्टर कहलाते हैं। इनके समृह को मंत्री-दल या 'मिनिस्टरी' कहते हैं।

कुछ मुख्य-मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग सभा होती है, इसे मंत्री-मंडल या 'केबिनेट' कहते हैं। यह सब शासन-कार्य का उत्तरदायी होता है। इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लगभग बीस मंत्री रहते हैं। जब एक मंत्री-मंडल त्याग-पत्र देता है तो बादशाह दूसरा मंत्री-मंडल बनाने के लिए दूसरे ऐसे दल के नेता को बुलाता है, जिसका पार्लिमेंट के अधिक-से-अधिक सदस्य समर्थन करते हों। यह नेता प्रधान मंत्री बनाया जाता है। प्रधान मंत्री, मंत्री-मंडल के अधिवेशनों में सभापति होता है, और सरकार की नीति उहराता है। मंत्री-मंडल

का एक सदस्य भारत-मंत्री होता है।

पार्लिमेंट श्रौर भारतवर्ष-- ब्रिटिश पार्लिमेंट भारतवर्ष के शासन के सम्बन्ध में जो कार्य करती है, उनमें से मुख्य ये हैं:—

- (१) वह भारतवर्ष की शासन-पद्धति निश्चित करती है। वह प्रचलित शासन-पद्धति अथवा शासन के किसी विभाग सम्बन्धी जाँच के लिए कमीश्चन नियुक्त करती तथा आवश्यक परिवर्तन करने के लिए नया विधान या क़ानून बनाती या सम्राट्की आज्ञा निकल-वाती है।
- (२) ब्रिटिश भारत के आय-व्यय का अनुमान-पत्र (बजट) तथा इस देश की उन्नति का विवरण प्रति वर्ष पार्लिमेंट के सामने उपस्थित किया जाता है। उस अवसर पर पार्लिमेंट के सदस्य भारतीय शासन-पद्धति की आलोचना कर सकते हैं।
- (३) पार्लिमेंट की दोनों सभाश्रों के कुछ सदस्यों की एक कमेटी भारतवर्ष सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करती है तथा पार्लिमेंट को श्रावश्यक परामर्श देती है।
- (४) भारत-मंत्री का वेतन श्रीर उसके कार्यालय का व्यय ब्रिटिश कोष से दिया जाता है। बजट की इस मद पर विचार करने के समय पार्लिमेंट में भारतीय विषयों की चर्चा होती है।
- (५) पार्लिमेंट के सदस्य कभी-कभी भारतवर्ष-सम्बन्धी प्रश्न पूछते श्रीर प्रस्ताव करते हैं।

साधारणतया पार्लिमेंट के श्रधिकांश सदस्य भारतवर्ष-सम्बन्धी विषयों में बहुत श्रानुराग नहीं रखते । उन्हें श्रपने देश तथा साम्राज्य- सम्बन्धी विविध समस्याओं से बहुत कम अवकाश मिलता है।

भारत-मंत्री श्रोर उसका कार्य — भारत-मंत्री को सम्राट्, श्रपने प्रधान मंत्री के परामर्श से नियत करता है। वह पार्लिमेंट को समय-समय पर भारतवर्ष-सम्बन्धी सूचना देता है तथा उसके सामने प्रति वर्ष, मई महीने की पहली तारीख़ के बाद, जिस दिन पार्लिमेंट का श्रधिवेशन श्रारम्भ हो, उससे २८ दिन के भीतर, भारतवर्ष की श्राय-व्यय का हिसाब पेश करता है। उसी समय वह इस बात की सविस्तर रिपोर्ट देता है कि गत श्रालोचनीय वर्ष की नैतिक, सामा-जिक तथा राजनैतिक उन्नति कैसी हुई। उस समय पार्लिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी विषयों की श्रालोचना कर सकते हैं। इसे भारतीय बजट की बहस कहते हैं।

सम्राट्, भारत-मंत्री के द्वारा, भारत-सरकार के बनाये कुछ क्रानूनों को रद्द कर सकता है। भारतवर्ष के जंगी लाट, बंगाल, बम्बई श्रौर मदरास के गवर्नर, इनकी कौंसिलों के सदस्य, हाईकोटों के जज तथा श्रन्य उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भारत-मंत्री सम्राट् को सम्मित देता है। वह भारत-सरकार के उच्च श्रक्तसरों को श्राचा दे सकता है श्रौर उन्हें श्रपने श्रविकार का दुरुपयोग करने से रोक सकता है।

भारत-मंत्री को भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण श्रीर नियंत्रण का श्रिधकार है। उसके दो सहायक मंत्री होते हैं; एक स्थायी श्रीर दूसरा ब्रिटिश पार्लिमेंट की उस सभा का सदस्य, जिसमें भारत-मंत्री न हो। भारत-मंत्री के दफ़्र को 'इंडिया-श्राफ़िस' कहते हैं। यह लंदन (इक्ज़लैंड की राजधानी) में है। भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल श्रौर गवर्नरों के नाम जारी किये जानेवाले श्रादेश-पत्रों (इन्स्ट्रमेंट्स-स्राफ़-इन्स्ट्रक्शन्स) का मसविदा पार्लिमेंट के सामने उपस्थित करता है श्रौर पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ, सम्राट् से उन श्रादेश-पत्रों को जारी करने का निवेदन करती हैं।

इंडिया कौंसिल - भारत-मंत्री को भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी कार्य में सहायता या परामर्श देनेवाली सभा 'इंडिया-कौंसिल' कह-लाती है। इसका श्रिविशान भारत-मंत्री की श्राज्ञा से एक मास में एक बार होता है। इसका सभापति भारत मंत्री या उसका सहकारी मंत्री, या भारत-मंत्री द्वारा नामज़द, कौंसिल का सदस्य होता है। कौंसिल के सदस्यों को भारत-मंत्री नियुक्त करता है। विशेष अवसरों पर वह इस कौंसिल के बहुमत के बिनाभी काम कर सकता है। कौं िसल के सदस्य ८ से १२ तक होते हैं। इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं, जो भारतवर्ष में भारत-सरकार की नौकरी कम-से-कम दस वर्ष कर चुके हैं, और जिन्हें वह नौकरी छोड़े पाँच वर्ष से श्राधिक समय न हुत्रा हो । प्रत्येक सदस्य प्रायः पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। श्रव इसमें प्रायः तीन हिन्दुस्तानी हैं। प्रत्येक सदस्य का वार्षिक वेतन १२०० पौंड है. भारतीय सदस्यों को ६०० पौंड वार्षिक भत्ता श्रीर मिलता है। सदस्य भारत-मंत्री की श्राज्ञानसार लन्दन में भारतवर्ष-सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पार्लिमेंट में बैठने का श्रधिकार नहीं है; इन्हें इनके काम से हटाने का श्रधिकार पार्लिमेंट को ही है। भारत-मंत्री श्लीर उसकी कौंसिल के नाम से

लन्दन के 'वैंक-श्राफ़-इङ्गर्लेंड' में भारत का खाता है। उसका हिसाव जाँचने के लिए एक लेखा-परीक्षक रहता है।

हाई किमिश्नर इङ्गलैंड में एक श्रिषकारी 'हाई किमिश्नर' भी रहता है, यह पाँच वर्ष के लिए भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल द्वारा और भारत-मंत्री की श्रनुमित से, नियुक्त किया जाता है। इसका काम है, ठेके देना, इंडिया श्राफ़िस के 'स्टोर'-विभाग और इसके सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और भारतीय ट्रेड (व्यापार) किमश्नर के कार्य का निरीक्षण। इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पौंड है। यह वेतन भारतवर्ष के खजाने से दिया जाता है।

[सन् १९३५ ई० का विधान और भारत-मन्त्री—नये विधान के अनुसार, संघ निर्माण की योजना की गयी है। इसके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा। संघ बन जाने पर इंडिया कोंसिल तोड़ दी जायगी। हाँ, भारत-मन्त्री के कुछ परामर्शदाता रहा करेंगे। उनकी संख्या तीन से कम और छः से अधिक न होगी। उनकी नियुक्ति वह स्वयं करेगा। गवर्नर-जनरल, या गवर्नर अपना मज़ीं या स्यक्तिगत निर्णय से जो कार्य करेंगे, उनमें वे भारत-मन्त्री के नियन्त्रण में रहेंगे। गवर्नरों पर भारत-मन्त्री का नियंत्रण गवर्नर-जनरल द्वारा होगा।]



# चौतीसवाँ परिच्छेद

#### भारत-सरकार

क्षित-सरकार या 'गवमेंट-आफ़-इंडिया' का अर्थ है 'गवर्नर-जनरल-इन-कौंसिल' अर्थात् कौंसिलयुक्त गवर्नर-जनरल । स्मरण रहे कि यहाँ कौंसिल से मतलब गर्वनर-जनरल की प्रबन्धकारिणी सभा से है, व्यवस्थापक सभा से नहीं । इसका कारण यह है कि गर्वनर-जनरल के साथ कौंसिल शब्द का इस अर्थ में प्रयोग, व्यवस्थापक सभा के जन्म से बहुत वर्ष पहले से हो रहा है ।

गवर्नर-जनरत्त या वायसराय—गवर्नर-जनरत्त भारत-सरकार का सबसे महत्व-पूर्ण ग्रंग है, श्राँर उसे उसके श्रन्य पदाधिकारियों की श्रपेक्षा विशेष श्रधिकार प्राप्त हैं। वह भारतवर्ष के शासन-प्रवन्ध या व्यवस्था-कार्य में भारत-मंत्री श्रौर पार्लिमेंट की श्राज्ञाश्रों का पालन करता या करवाता है, श्रौर ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है। इसलिए वह गवर्नर-जनरत्न कहलाता है। वह सम्राट् के प्रतिनिधि के रूप से रहता है। इस हैस्यित से वह देशी राज्यों में जाता है, सभा या दरवार करता है श्रौर घोषणा-पत्र श्रादि निकालता है। इसलिए वह वायसराय कहलाता है। वायसराय का अर्थ 'बादशाह का प्रतिनिधि' है। साधारण व्यवहार में 'गवर्नर-जनरल' और 'वायसराय' शब्दों में कोई मेद नहीं माना जाता। अपने प्रधान मंत्री की सिफ़ारिश से सम्राट् किसी योग्य अनुभवी एवं साधारणत: 'लार्ड' उपाधिवाले व्यक्ति को गवर्नर-जनरल नियत करता है। उसके कार्य करने की अवधि प्राय: पाँच साल की होती है। उसका वार्षिक वेतन २, ५०, ८०० रूपये है। इसके अतरिक्त उसे बहुत-सा भत्ता आदि मिलता है, जिससे वह अपने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पूर्वक कर सके, अर्थात् उसकी शान-शौक़त भली-भांति बनी रहे।

गवर्नर-जनरल के अधिकार—अपनी प्रबन्धकारिणी सभा की अनुपिश्यित में गवर्नर-जनरल किसी प्रान्तीय सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता है। आवश्यकता होने पर वह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छ: महीने के वास्ते अस्थायी क़ानून (आर्डिनेंस) बना सकता है। यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फ़ौजदारी के मामले में अपराधी ठहराया हो, बिना किसी शर्त के, या कुछ शर्त लगा कर, क्षमा कर सकता है। उसे (१) भारत-सरकार (२) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों (४) प्रान्तीय ब्यवस्थापक परिषदों और (५) नरेन्द्र-मंडल के सम्बन्ध में विविध अधिकार हैं। उनका वर्णन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा। उसकी भवन्थकारिणी सभा (कौंसिल)—गवर्नर-जनरल को कौंसिल के सदस्यों की संख्या प्रायः छः होती है; यह आवश्यकता-नुसार घट-बढ़ सकती हैं। हाँ, कम-से-कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिएँ, जिन्होंने भारतवर्ष में दस वर्ष भारत-सरकार की नौकरी की हो। क़ानूनी योग्यता के लिए एक सदस्य हाईकोर्ट का ऐसा वकील, अथवा इंगलैंड या आयलैंड का ऐसा बैरिस्टर होना चाहिए, जिसने दस वर्ष वकालत (प्रैक्टिस) की हो। इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस समा में हिन्दुस्तानियों की अमुक संख्या रहे; बहुधा तीन सदस्य भारतीय होते हैं। प्रत्येक सदस्य सम्राट् की अनुमित से प्रायः पाँच साल के लिए नियुक्त होता है।

उपर्यु क छः सदस्यों में से प्रत्येक को भारत-सरकार के एक-एक विभाग का कार्य सुपूर्व रहता है। इन विभागों का नाम तथा कार्य-चेत्र आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदलता रहता है। पिछले दिनों ये विभाग (१) अर्थ या फाइनेंस, (२) स्वदेश या 'होम' (३) क्रानून, (४) संवाद-वाइन, (कम्यूनिकेशंस,), (५) शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि तथा (६) रेल और वाणिज्य विभाग थे। इनके अतिरिक्त भारत-सरकार के दो विभाग और होते हैं—विदेश विभाग और सेना विभाग। विदेश विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन होता है और सेना विभाग पर जंगी लाट अर्थात् कमांडरनचीफ़ का प्रभुत्व रहता है। अगर जंगी लाट गवर्नर-जनरल की प्रवन्धकारिणी सभा का सदस्य हो, तो सभा में उसका पर और स्थान गवर्नर-जनरल से दूसरे दर्जे पर होता है।

सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी — प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों को सहायता देने के लिए उपयुक्त प्रत्येक विभाग में एक सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, कई असिस्टेंट सेक्रेटरी तथा कुछ क्रकें आदि रहते हैं। सेक्रेटरी प्रायः भारतीय सिविल स्विस के होते हैं; परन्तु गवनंर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्रेटरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित अथवा नामज़द, सरकारी या ग्रेर-सरकारी स्टर्स्यों में से नियुक्त कर सकता है। ऐसे सेक्रेटिरियों को 'क्रेंसिल-सेक्रेटरी' कहते हैं। इनका पद उस समय तक बना रहता है, जब तक गवनंर-जनरल चाहता है और ये उसकी प्रवन्धकारिणी सभा के सदस्यों को सहायता देने का ऐसा काम करते हैं जो इनके सुपूर्व किया जाय। इनका वेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है। अगर कोई सेक्रेटरी छः महीने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह अपने पद्से पृथक् हो जाता है। सेक्रेटरी अपने विभाग के दफ़र को संभालता है और सभा की बैठक में उपस्थित रहता है।

चित्र सेक्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय (सेक्रेटेरियट) भारत-वर्ष की राजधानी देहली में है। परन्तु भारत-सरकार का सदर मुकाम (हेडकार्टर) सदीं में देहली श्रीर गर्मियों में शिमला रहता है, इसलिए सेक्रेटरियों को श्रावश्यकतानुसार देहली या शिमले में रहना होता है

भारत-सरकार के श्रधीन डायेरक्टर-जनरल श्रीर इन्सपेक्टर-जनरल श्रीर इन्सपेक्टर-जनरल श्रीर इत्सपेक्टर-जनरल श्रीर क्षिक्टर-जनरल श्रीर क्षिक्टर-जनरल श्रीर क्षिक्टर-जनरल श्रीर प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों के कार्य की निगरानी

रखें श्रौर उन्हें यथोचित परामर्श दें।

प्रबन्धकारिणी सभा के अधिवेशन—इस समा का अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताइ होता है। उसमें उन विषयों पर विचार होता है जिन पर गवर्नर-जनरल विचार करवाना चाहे, अथवा जिन्हें बह अस्वीकार करे और जिन पर कोई सदस्य सभा का निर्णय चाहे। अधिवेशन में सभापित स्वयं गवर्नर-जनरल होता है। उसकी अनुपियति में उप-सभापित उसकेकार्य का सम्पादन करता है। उप-सभापित के पद के लिए गवर्नर-जनरल इस सभा के सदस्यों में से किसी को नियुक्त करता है। सभा के अधिवेशन में गवर्नर-जनरल (या ऐसा अन्य व्यक्ति जो सभापात का कार्य करे) और सभा का एक सदस्य (कमांडरनचीफ को छोड़कर) कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के सब कार्यों का सम्पादन कर सकते हैं।

काम करने का ढंग — जब किसी विभाग-सम्बन्धी कोई विचारणीय प्रश्न उठता है तो उस विभाग का सेक्रेटरी उसका मसविदा तैयार करके गवर्नर-जनरल या उस सदस्य के सामने पेश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हो। साधारणतया सदस्य हस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फैसला समफा जाता है, परन्तु यदि प्रश्न विवाद-प्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की बात आती हो तो सेक्रेटरी से तैयार किया हुआ मसविदा सभा में पेश होता है और वहाँ से जो हुकम हो, उसे सेक्रेटरी प्रकाशित करता है। सभा के साधारण अधिवेशनों में मत-भेदवाले प्रश्नों के विषय में बहुमत से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हों, तो जिस तरफ

गवर्नर-जनरल (समापित) मत प्रकट करे. उसी के पत्त में फैसला होता है। मगर गवर्नर-जनरल को इस बात का श्रिषकार रहता है कि यदि उसकी समभ में सभा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मित के श्रनुसार कार्य कर सकता है, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में, विरुद्ध पद्ध के दो सदस्यों की इच्छा होने पर, उसे श्रपने कार्य की, कारण-सहित सूचना देनी होती है तथा सभा के सदस्यों ने उस विषय में जो कार्रवाई लिखी हो, उसकी कापी भारत-मंत्री के पास्ट भेजनी होती है।

गवर्नर-जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपस्थित—
भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल को, और कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल की
क्षिणारिश पर कमांडरनचीफ को, उनके कार्य-काल में एक बार चार
मास तक की छुट्टी सार्वजनिक दित के लिए या स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत कारण से दे सकता है। और, कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल,
कमांडरनचीफ़ को छोड़कर, कौंसिल के अन्य सदस्यों को उनके
कार्य-काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी स्वास्थ्य या व्यक्तिगत
कारण से दे सकता है। इस छुट्टी के समय में उक्त पदाधिकारियों को
निर्धारित भत्ता मिलता है। गवर्नर-जनरल और कमांडरनचीफ़ को
तो उक्त भन्ते के अतिरिक्त, सफर ख़र्च सम्बन्धी इतना भत्ता और भी
मिलता है, जितना भारत-मंत्री उचित समके। गवर्नर-जनरल और
कमांडरनचीफ के स्थानापन व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट् की अनुमित से
होती है।

यदि गवर्नर-जनरल का पद रिक्त होते समय उसका उत्तराधिकारी भारतवर्ष में न हो तो मदरास, बम्बई या बंगाल के गवर्नरों में से जिसकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा पहले हुई हो, वह गवर्नर-जनरल का कार्य करता है। जब तक उपर्युक्त गवर्नर द्वारा गवर्नर-जनरल का कार्य-भार ग्रहण न किया जाय, कौंसिल का उप-सभापित, श्रीर उसकी श्रमुपस्थिति में कौंसिल का सीनियर (श्रिष्ठक समय से काम करने-वाला) मेम्बर (कमांडरनचीफ को छोड़कर) गवर्नर-जनरल का कार्य करता है।

अगर कमांडरनचीफ़ को छोड़कर प्रवन्धकारिणी कोंसिल के किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली हो जाय, और उसका कोई उत्तराधिकारी विद्यमान न हो तो सकौंसिल गवर्नर-जनरल अस्थायी निर्युक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है।

भारत-सरकार का कार्य-शासन-सम्बन्धी विषयों के दो आग हैं—(१) श्रिविल भारतवर्षीय या क्रेन्द्रीय विषय, श्रौर (२) प्रान्तीय विषय। इसी वर्गीकरण के श्राधार पर भारत-सरकार (केन्द्रीय सरकार) श्रौर प्रान्तीय सरकारों के कार्यों तथा उनकी श्राय के श्रोतों का विभाजन किया गया है। केन्द्रीय विषयों का उत्तरदायिक्ष भारत-सरकार पर है। यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि यह प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल करता है; परन्तु इस विषय में श्रन्तिम श्रिधकार भारत-मंत्री को है।

संत्तेप में, भारतवर्ष में मुख्य-मुख्य केन्द्रोय विषय ये हैं:-

(१) देश-रक्षा, भारतीय सेना तथा हवाई जहाज़ (२) विदेशी तथा विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी राज्यों के सम्बन्ध. (४) राजनैतिक खर्च, (५) बड़े बन्दरगाह (६) डाक, तार, टेलीफोन श्रीर बेतार - के - तार (७) श्रायात - निर्यात - कर. नमक श्रौर श्राखिल भारतवर्षीय श्रायके श्रन्य साधन, (८) सिक्का नोट ब्रादि (९) भारतवर्ष का सरकारी ऋण, (१०) पोस्ट ब्राफिक सेविंग वैंक, (११) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, (१२) दीवानी श्रीर फीजदारी क़ानून तथा उनके कार्य-विधान (१३) व्यापार, बैंक श्रीर बीमा-कम्पनियों का नियन्त्रण. (१४) तिजारती कम्पनियाँ श्रीर समितियाँ, (१५) श्राक्षीम श्रादि पदार्थों की पैदावार, खपत श्रीर निर्यात का नियन्त्रण, (१६) कापी-राइट (किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार, (१७) ब्रिटिश भारत में आना अथवा यहाँ से विदेश जाना (१८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, (१९) हथियार श्रीर युद्ध-सामग्री का नियन्त्रण, (२०) मनुष्य गणना श्रीर श्रीकड़े या 'स्टेटिसटिक्स', ( २१ ) श्राखिल भारतवर्षीय नौकरिया, ( २२ ) प्रान्ती की सीमा श्रौर ( २३ ) मजद्रों सम्बन्धी नियन्त्रण ।

भारत-सरकार के अधिकार—भारत-सरकार को निर्धारित नियमों के अनुसार, ब्रिटिश भारत के शासन और सेना-प्रवन्ध के निरी- क्षण तथा नियन्त्रण का अधिकार है। वह ब्रिटिश भारत की किसी सम्पत्ति को बेच सकती है। वह प्रान्तों की सीमा नियत या परिवर्तन कर सकती है और प्रान्तीय सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की शान्ति और सुशासन के लिए नियम बना सकती है।

वह हाईकोटों का अधिकार चेत्र बदल सकती है, श्रौर दो साल तक के लिए जज नियत कर सकती है। वह एशिया के तथा अन्य राज्यों से सिन्ध या सममौता कर सकती है। उसे अपने अधीन भू-भाग किसी राज्य को देने और उसके अधीन भू-भाग लेने का अधिकार है। भारतीय व्यवस्थापक मंडल; प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों श्रौर देशी राज्यों के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका विवेचन श्रागे प्रसंगानुसार किया जायगा। सारांश यह कि सम्राट्की प्रतिनिधि होने के कारण उसे उसकी ऐसी शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं, जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हों।

भारत-सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर गवर्नर-जनरल या उसकी प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्य इंगलैंड की सरकार से किसी बात में सहमत न हों तो या तो उन्हें अपने मत को दबाना पड़ता है, अथवा त्याग-पत्र देना होता है।

सन् १९३५ ई० की विधान श्रीर भारत-सरकार— सन् १९३१ ई० के विधान के श्रनुसार, यहाँ संघ स्थापित होने पर भारत-सरकार का नाम, 'भारतवर्ष की संघ-सरकार' होगा। संघ-स्थापना की घोषणा सन्नाट द्वारा की जायगी श्रीर उस समय की जायगी, जब निर्धारित शर्तनामे के श्रनुसार हतने देशी राज्य संघ-शासन को स्वीकार कर जों, जितने राज्य-परिषद (कौंसिज-श्राफ़-स्टेट) के कम-से-कम ४२ सदस्य चुनने के श्रधिकारी हों श्रीर जिनकी जन-संख्या कुल देशी राज्यों की जन-संख्या की कम से कम श्राधी हो। संघ-निर्माण होने के बाद सम्राट् का प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के शासन-सम्बन्धी विषयों में गवर्नर-जनरख, श्रौर देशी राज्यों के शासन-प्रबन्ध में वायसराय, होगा । होनों पदों पर नियुक्तियाँ सम्राट् द्वारा हुआ करेंगी, श्रौर सम्राट् को होनों पदों के खिए एक ही व्यक्ति नियुक्त करने का भी श्रीधकार होगा ।

इस समय जो शासन-कार्य कौंसिज-युक्त गवर्नर-जनरत्व के नाम से होता है, वह फिर गवर्नर-जनरत्व के ही नाम से होगा। उसका एक मन्त्री-मंडज (कौंसिज-ब्राफ़-मिनिस्टर्स) होगा। यह मडंज उसे उसके विशेषा-धिकारों को छोड़कर ब्रन्य विषयों में सहायता या परामर्श देगा। इसमें ब्रिधिक-से-ब्रिधिक दस मन्त्री होंगे।

देश-रक्षा अर्थात् सेना, धर्म (ईसाई मत), पर-राष्ट्र तथा जंगली जातियों के विषय के प्रबन्ध में गवर्नर-जनरल अपनी मर्ज़ी के अनुसार कार्य करेगा। इनमें मन्त्रियों का परामर्श नहीं लिया जायगा। इसके सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल को सहायता देने के लिए अधिक-से-अधिक तीन सलाहकार (कौंसिजर) रहेंगे।

कुछ विषयों के लिए गवर्नर-जनरल विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। इनके सम्बन्ध में वह (मिन्त्रयों की सलाह के विरुद्ध भी) श्रपने स्यक्तिगत निर्णय के श्रनुसार कार्य करेगा। इनमें से मुख्य ये हैं—
(१) भारतवर्ष या इसके किसी भाग के शान्ति भंग का निवारण।
(२) संघ सरकार की श्रिथिक स्थिरता। (३) श्रन्यसंख्यकों के उचित हितों की रत्ता (४) सरकारी कर्मचारियों के श्रधिकारों श्रोर हितों की रत्ता। (१) देशी-नरेशों के श्रधिकारों की रत्ता।

### पेंतीसवाँ परिच्छेद भारतीय व्यवस्थापक मंडल

दो भाग हैं:—(१) राज्य-परिषद् या 'कौंसिल-श्राफ स्टेट' और (२) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 'लेजिस्लेटित एसेम्बली'। ये दोनों सभाएँ इङ्गलैंड की सरदार-सभा और प्रतिनिधि सभा के ढङ्ग पर बनायी गयी हैं, यद्यपि यहाँ राज्य-परिषद् में निर्वाचित सदस्य भी रहते हैं, इतना ही नहीं, उनका श्राधिक्य भी होता है।

सिवाय कुछ ख़ास हालतों के, किसी क़ानून का मसविदा पास हुआ नहीं समका जाता, जब तक दोनों समाएँ उसे मूल रूप में, अथवा कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न कर लें। दोनों समाएँ कुछ सदस्यों का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना कार्य कर सकती हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता; अपर समा का कोई ग़ैर-सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर समा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी समा का सदस्य हो जाय तो पहली सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों सभाओं में निर्वाचन हो जाय तो वह किसी समा में सिमालित होने से पूर्व, लिखकर यह सूचित

करेगा कि वह कौनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है; ऐसा होने पर दूसरी सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जायगी।

गवर्नर-जनरल की प्रवन्धकारिणी सभा का हर एक सदस्य उपर्युक्त दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया जाता है; उसे दूसरी सभा में बैठने और बोलने का श्रिधकार रहता है, लेकिन वह दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता। इन सभाओं का संगठन जानने से पूर्व मुख्य-मुख्य निर्वाचन-नियम जान लेना श्रावश्यक है।

निर्वाचक-संप्र — निर्वाचन के सुभीते के लिए प्रत्येक प्रान्त, ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या चेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक चेत्र के निर्वाचक-समृह को निर्वाचक-संघ कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचक-संघ अपनी आरे से प्रायः एक-एक (कहीं-कहीं एक से अधिक) प्रतिनिधि चुनता है।

भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं—साधारण श्रीर विशेष ।
भारतीय व्यवस्थापक सभा श्रीर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रो (तथा कुछ,
स्थानों में म्युनिसपैलिटियों श्रीर ज़िला-बोडों) के लिए साधारण निर्वाचक-संब, जातिगत निर्वाचक-संघों में विभाजित किये गये हैं। जैसे मुसल-मानों का निर्वाचक-संघ, ग्रीर-मुसलमानों का निर्वाचक-संघ, इत्यादि ।
आजाति-गत निर्वाचक-संघ प्राय: नगरों श्रीर ग्रामों में विभक्त किये जाते हैं, जैसे मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक-संघ, मुसलमानों का

<sup>ैि</sup>कसी जाति-गत निर्वाचक-संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उस जाति के हों, जिस जाति का निर्वाचक-संघ है। यह प्रथा साम्प्रदायिक वैमनस्य बदानेवाली तथा राष्ट्र-निर्माण के लिए घातक है।

नगर-निर्वाचक-संघ, इत्यादि।

विशेष निर्वाचक-संघों में ज्मीदार, विश्व-विद्यालय, व्यापारी, खान, नील श्रीर खेती तथा उद्योग श्रीर वाखिज्यवाले निर्वाचक होते हैं।

कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?---निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते:---

र-जो ब्रिटिश प्रजा न हों। [देशी राज्यों के नरेश श्रौर उनकी प्रजा के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

र-जो अदालत से पागल उइराये गये हो।

३ - जो इक्सेस वर्ष से कम आयु के हों।

४ — जिन्हें सरकारी श्राफ्सर के विरुद्ध किये हुये किसी श्रापराध में छ: मास से श्राधिक दंड दिया गया हो।

५ — जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय धमकी या रिश्वत आदि दूषित कार्य करने के अपराधी उहराये गये हों।

राज्य-परिषद्ग-राज्य-परिषद् में ६० सदस्य होते हैं, ३३ निर्वाचित, और सभापित को मिलाकर २७ गवर्नर-जनरल द्वारा नाम- ज़द। नामज़द सदस्यों में २० तक (अधिक नहीं) अधिकारियों में से हो सकते हैं। बरार प्रान्त का एक सदस्य निर्वाचित होता है, परन्तु यह प्रान्त कान्तन ब्रिटिश भारत में न होने से उसका निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा नामज़द कर दिया जाता है। अतः वास्तव में निर्वाचित सदस्य २४, और (समापित को छोड़कर) नामज़द सदस्य २४ होते हैं। इनका विशेष व्योरा अगले पृष्ठ में दिया जाता है।

| Weekende de destruit au deur generale de religiée amought de seu partie en la contraction de la contra | निर्वाचित |            |            |       |                  |                  |          | नामज़द     |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|------------------|------------------|----------|------------|------------------|--|
| सरकार<br>या<br>प्रान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जनरल      | गैर-मुसलिम | मुसलिम     | मिक्ख | योरपियन ज्यापारी | कुल              | सरकारी   | गैर सरकारी | कुल              |  |
| भारत-सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         |            |            |       |                  |                  | १२       | ***        | १२               |  |
| मदरास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 8          | <b>ξ</b>   |       | •••              | y                | ٤:       | १          | 2                |  |
| बम्बई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b> </b>  | ३          | <b>ર</b>   | •••   | ţ                | દ                | ş        | 2          | २                |  |
| बंगाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ą          | २          | ••    | ₹                | હ                | ę        | 8          | 7                |  |
| संयुक्त प्रान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ₹          | २          |       |                  | પ્               | <b>१</b> | १          | 2                |  |
| 'पंजाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 8          | 12*        | १     | •••              | 32*              | <b>१</b> | २          | ą                |  |
| बिहार- <b>उड़ी</b> षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ₹ *        | á          | •••   | ••-              | ₹ <del>9</del> * | १        |            | \$               |  |
| बर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १         | •••        | ***        | • • • | ?                | २                |          | •••        |                  |  |
| मध्यप्रान्त-बरार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २         | •••        | • • •      | • • • | •••              | २                | •••      | •••        | • •              |  |
| श्रासाम<br>देहली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •••       | 9+         | <b>q</b> † | •••   | •••              | १                | ٠        | •••        | <del></del><br>१ |  |

<sup>\*</sup> एक निर्वाचन में पञाब के मुसलिम निर्वाचकों को दो, बिहार-उड़ीसा के ग़ौर-मुसलिम निर्वाचकों को दो; दूसरे निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को एक श्रौर बिहार उड़ीसा के ग़ौर-मुसलिम निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का श्रधिकार होता है।

ं एक निर्वाचन में ग़ैर-मुसलिम श्रौर एक निर्वाचन में मुसलिम निर्वाचकों को बारी-बारी से एक सदस्य चुनने का श्रधिकार है। राज्य-परिषद् का समापित साधारणतः उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिषद् के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानार्थ 'माननीय' (आनरेबल) शब्द लगाया जाता है। परिषद् का निर्वाचन प्रायः प्रति पाँचने वर्ष होता है। गवर्नर-जनरल इस समय को आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकता है।

√नियोचक की योग्यता——जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की (पहले बतलायी हुई) अयोग्यताएँ न हों तथा जिनमें निम्नलिखित योग्यताएँ हो, वे ही निर्वाचक हो सकते हैं:—

१—जो निर्वाचन चेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और २—(क) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की ज़मीन हो, या (ख) जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों, या (ग) जो किसी व्यवस्थापक सभा या परिषद् के सदस्य हों, या रहे हों, या (घ) जो किसी म्युनिसपैलटी या ज़िला-बोडों के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों. या (च) जिन्हें किसी विश्व-विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त हो, या (छ) जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों, या (ज) जिन्हें सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामहोपाध्याय की लगांधि मिली हो।

भिन्न-भिन्न प्रान्तों में निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए आय-कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग-अलग है। कुछ प्रान्तों में मुसलमान निर्वाचकों के लिए आर्थिक योग्यता का परिमाण कुछ कम है। तथापि बड़े-बड़े ज़मींदारों और पूँजीवालों को ही निर्वाचन-अधिकार दिया गया है।

सदस्य कौन हो सकता है ?— राज्य-परिषद् के लिए वे व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेदवार हो सकते हैं, या निर्वाचित या नामज़द किये जा सकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक संघ की सूची में दर्ज हो, बशर्ते कि—

- १—वे ऐसे वकील न हों, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने के ऋषिकार से बंचित कर दिये गये हों।
- २—वे ऐसे दिवालिये न हों, जो बरी न किये गये हों, अर्थात् जिनका पूरा सुगतान न हुआ हो।
  - ३--- उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो।
- ४-वे ऐसे व्यक्ति न हो, जिनको क्षीजदारी श्रदालत द्वारा एक वर्ष से श्रधिक दंड, या देश-निकाला दिया जा चुका हो।
  - ५-वे सरकारी नौकर न हों।

निर्वाचित और नामज़द सदस्यों को राजभिक्त की श्रापथ लेने के बाद, राज्य-परिषद् के कार्य में भाग लेने का अधिकार होता है।

भारतीय व्यवस्थापक सभा — इस सभा के सदस्यों की कुल संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घट-बढ़ सकती है और निर्वाचित तथा नामज़द सदस्यों का परस्पर में अनुगत भी घट-बढ़ सकता है। परन्तु कम-से-कम है सदस्य निर्वाचित होने चाहिएँ, और नामज़द सदस्यों में कम-से-कम एक-तिहाई ग्रैर-सरकारी होने चाहिएँ। इनका विशेष व्योरा अगले पृष्ठ में दिया जाता है।

## भारतीय व्यवस्थापक मंडल भारतीय व्यवस्थापक सभा का संगठन

|                        | निर्वाचित    |                    |          |         |          |               |      |          |             |              |          |
|------------------------|--------------|--------------------|----------|---------|----------|---------------|------|----------|-------------|--------------|----------|
| सरकार<br>या<br>प्रान्त | ग्रैर-मुखलिम | मुसलिम             | सिक्ख    | योरपियन | जमीदार   | न्यापारी मंडल | जोड़ | सरकारी   | ग़ैर-सरकारी | <u>जो</u> ड़ | कुल जोड़ |
| भारत-सरकार             | •••          |                    |          | • • •   |          |               |      | १२       | •••         | १२           | १२       |
| मदरास                  | १०           | 3                  | ***      | \$      | १        | ?             | १६   | २        | 2           | ¥            | २०       |
| बम्बई                  | 6            | ¥                  | •••      | ર       | <b>१</b> | ્ર            | १६   | २        | ¥           | ઘ            | १२       |
| <del>वं</del> गाल      | હ            | Ę                  | •••      | 3       | *        | ₹.            | १७   | २        | R           | પૂ           | २२       |
| संयुक्तप्रान्त         | 5            | Ę                  | ••       | *       | ?        |               | १६   | ₹        | ?           | n            | 25       |
| 'पंजाब                 | ą            | Ę                  | <b>ર</b> | *       | १        |               | १२   | <b>१</b> | 8           | 7            | १४       |
| विद्वार-उड़ीसा         | 5            | 3                  | •••      |         | *        | •••           | १२   | ?        | १           | ₹            | 28       |
| मध्यप्रान्त            | 3            | *                  | •••      | •••     | ?        |               | પ્   | ₹.       | •••         | ?            | હ        |
| त्रासम                 | २            | ?                  | •••      | ?       | •••      | •••           | ¥    | ?        |             | ?            | ¥        |
| बर्मा                  | ३ ग्रै       | र-योर              | पियन     | *       |          |               | Y    | *        | •••         | ?            | ų        |
| बरार                   |              |                    |          | •••     |          | ,             |      |          | 7           | २            | ર        |
| श्रजमेर                |              | •••                | •••      |         |          |               |      |          | ?           | *            | ?        |
| देहली                  |              | १ जनरल या साधारण १ |          |         |          |               |      | l        | ·           |              | 1        |

भारतीय व्यवस्थापक सभा की श्रायु तीन वर्ष है, परन्तु गवर्नर-जनरल को श्रिधकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सके।

जिस तरह ब्रिटिश पार्लिमेंट के मेम्बरों को एम० पी० (M. P.) कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य को एम० एल० ए० (M. L,A.) का पद रहता है। यह "मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली" का संसेप है। इस सभा के सदस्यों को राज्य-परिषद के सदस्यों की भौति माननीय (आनरेबल) की पदवी नहीं दी जाती।

निर्वाचक की योग्यता— जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की श्रयोग्यताएँ न हों, श्रीर निम्नलिखित योग्यताएँ हों, वे भारतीय व्यवस्थापक सभा के साधारण निर्वाचक-संघ में निर्वाचक हो सकते हैं:—

- रैं जो निर्वाचक-संघ के चेत्र के सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और रें (क) जो निर्वारित या उससे अधिक मृल्य की ज़मीन के मालिक हों, या
  - (ख) जिनके चेत्र में निर्धारित या उससे श्रिधिक मूल्य की ज़मीन हो, या
  - (ग) जो ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते हों, जिसका वार्षिक किराया निर्धारित रक्तम या उससे अधिक हो, या
  - (घ) जो ऐसे शहरों में जहाँ म्युनिसपैलिटियों द्वारा हैसियत-कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक

पर म्युनि सिपैलटी को हैसियत-कर देते हों, या

(च) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों, अर्थात् जिनकी, कृषि की आय के अतिरिक्त, अन्य वर्षिक आय २०००) रुपया या इससे अधिक हो

निर्वाचक होने के लिए साम्यत्तिक योग्यता, भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक्-पृथक् है, श्रीर राज्य-परिषद के निर्वाचकों की अपेदा कम है; तथापि निर्वाचकों की संख्या असन्तोषप्रद है।

जी व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक सभा ( एवं राज्य-परिषद ) के लिए किसी निर्वाचक-संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे ५००) ज़मानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि उसके निर्वाचक-संघ के तमाम मतों में से, उसके पद्म में आठवें हिस्से से कम आवें, तो ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।

सदस्य श्रोर सभापति — भारतीय व्यवस्थापक सभा की सदस्यता के नियम वैसे ही हैं, जैसे राज्य-परिषद की सदस्यता के हैं, श्रीर ये इम पहले बता श्राये हैं। इस सभा के सभापति श्रीर उप-सापति सभा के ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें वह चुन ले श्रीर गवनंर-जनरल पसन्द कर ले। ये उस समय तक ही पदाधिकारी रहते हैं, जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं।

व्यवस्थापक मंडल का कार्य-क्षेत्र—भारतीय व्यवस्थापक मगडल के तीन कार्य हैं :—(१) क्रानून बनाना, (२) शासन-कार्य की जांच करने के लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव करना, और (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना। यह मंडल ऐसी संस्था नहीं है, जो स्वतन्त्रता-पूर्वक क़ानून बना सके। उसके अधिकारों की सीमा परिमित है। वह निम्निलिखित विषयों के सम्बन्ध में क़ानून बना या बदल सकता है:—(क) ब्रिटिश मारत के सब आदिमियों, अदालतों, स्थानों और ऐसे विषयों के लिए जो प्रान्तीय नहीं हैं। (ख) मारत के देशी राज्यों या वैदेशिक राज्यों में रहनेवाली भारतीय प्रजाके लिए जो ब्रिटिश मारत में या बाहर (किसी देश में) हों। जब तक पार्लिमेंट के ऐक्ट से स्पष्टतया ऐसा अधिकार प्राप्त न हो, भारतीय व्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ानून नहीं बना सकता, जो पार्लिमेंट के भारतवर्ष की राज्य-पद्धति-सम्बन्धी किसी ऐक्ट या अधिकार अथवा सम्राट् के आदेश पर प्रभाव डाले, या उसे संशोधित करें।

कार्य-पद्धित — व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाश्रों के श्रिष्टिन साधारणतः दिन के ग्यारह बजे से पाँच बजे तक होते हैं। श्रारम्भ के पहले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभाश्रों के श्रम्य कार्यों के दो भाग होते हैं, सरकारी श्रीर ग्रैर-सरकारी। ग्रैर-सरकारी काम के लिए गवनर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं, इनमें ग्रैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर ही विचार होता है। श्रम्य दिनों में सरकारी काम होता है। सेक टरी विचारणीय विषयों की सूची तैयार करता है, उसी के श्रमुसार कार्य होता है। समापति की श्राज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया जाता।

राज्य-परिषद में १५, श्रीर व्यवस्थापक सभा में २४ सदस्यों की

उपस्थित के बिना कार्यारम्म नहीं हो सकता। सदस्यों के बैठने का कम समापित निश्चय करता है। समाभों को भाषा ग्राँगरेज़ी रखी गयी है। समापित ग्रांगरेज़ी न जाननेवाले सदस्यों को देशी भाषा में बोल ने की क्रनुमित दे सकता है। प्रत्येक सदस्य समापित को सम्बोधन करके बोलता है, श्रीर उसी के द्वारा प्रश्न कर सकता है। जहाँ तक कोई सदस्य सभाशों के नियमों की श्रवहेलना न करे उसे भाषण करने की स्वतंत्रता है, श्रीर भाषण या मत देने के कारण किसी सदस्य पर मुक्कद्मा नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक विषय का निर्णय सभापित को छोड़कर, सभा के सदस्यों के बहुमत से होता है; दोनों श्रोर समान मत होने से सभापित के मत से निपटारा होता है। सना में श्रान्त रखना सभापित का कर्तव्य है। श्रीर इसके लिए श्रावश्यकता होने पर वह किसी सदस्य का एक दिन या श्रीषक समय के लिए समा में श्रान्त बन्दकर सकता है, श्रयवा श्रीविश्यन भी स्थिति कर सकता है।

प्रश्न—व्यवस्थापक मण्डल की समाओं का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पृद्ध सकता है। प्रश्न उन्हीं विषयों के हो सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा प्रक प्रश्न पृद्धा जा सकता है, जिससे पूर्व प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े। समापति को अधिकार है कि इन्द्र दशाओं में वह किसी प्रश्न, उसके अंश, या प्रक प्रश्न के पृद्धे जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी विभाग के सदस्य से वही प्रश्न

पूछे जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका सम्बन्ध हो हे ऐसे प्रश्न पूछे जाने की सूचना कम-से-कम दस दिन पहले देनी होती है।

प्रस्ताव व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश के रूप में होते हैं, वे भारत-सरकार पर वाध्य नहीं होते । इस संस्था में निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो। सकते:—

्ब्रिटिश सरकार, गवर्नर-जनरल या कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल का विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सम्बन्ध, देशी राज्यों का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हो।

निम्नलिखित विषयों के लिए गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति विना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकताः—धार्मिक विषय या रीतियाँ, जल, स्थल या वायु सेना, विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सरकार का सम्बन्ध, प्रान्तीय विषय का नियंत्रण, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों का कोई क़ानून रह या संशोधन करना, गवर्नर-जनरल के बनाये हुए किसी ऐक्ट या श्रार्डिनैंस को रह या संशोधन करना।

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य-परिषद में प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिए सभा के साधारण कार्य को स्थागित करने के, श्रीर (२) भारत-सरकार से किसी कार्य के करने की सिफ़ारिश के । पहले प्रकार का प्रस्ताव सभा के श्राधिवेशन में प्रश्नोत्तर बाद ही सेक्रेटरी को सूचना देकर किया जा सकता है। सभापति इस प्रस्ताव को पढ़कर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को, प्रस्ताव करने की श्रनुमति देने में श्रापित्त हो तो सभापति कहता है कि श्रनुमति देने के पक्षवाले सदस्य खड़े हो जायाँ। यदि राज्य-परिषद में १५, या व्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े हो जायाँ, तो सभापति यह सूचित कर देता है कि श्रनुमित है और ४ बजे या इससे पहले प्रस्ताव पर विचार होगा।

दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्राय: १५ दिन, और कुछ दशाओं में इससे अधिक समय पहले सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय समापित करता है। अधिवेशन से दो दिन पहले एक कागज़ पर १, २, ३ आदि संख्याएँ लिखकर उसे कार्यां ज्या में रख दिया जाता है। जिन सदस्यों के प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकने का निर्णय होता है, वे उन संख्याओं के सामने अपना नाम लिख देते हैं। तीसरे दिन काग़ज़ के उतने दुकड़े लेकर उनपर क्रमश: १, २, ३. आदि संख्याएँ लिखी जाती हैं और, उन्हें एक वक्स में डाल दिया जाता है। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में जितने प्रस्ताव उपस्थित हो सकने की सम्भावना हो, उतने काग़ज़ों को एक आदमी वक्स में से बिना विचारे, एक-एक करके निकालता है। जिस क्रम से काग़ज़ निकालते हैं, उसी क्रम से नाम एक सूची में लिख दिये जाते हैं\*। अधिवेशन में इस सूची के क्रम के अनुसार ही प्रस्ताव

<sup>\*</sup>नामों का क्रम निश्चय करने के इस ढंग को 'बैलट' पद्धति कहते हैं 🗓

उपस्थित किये जाते हैं। समापित की श्राज्ञा बिना किसी श्रन्य प्रस्ताक पर विचार नहीं होता।

सभापित की अनुमित से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य सदस्य से उपस्थित करा सकता है, और वह चाहे तो उसे वापस भी ले सकता है। प्रस्तावक अनुपश्थित होने पर उसका प्रस्ताव रह समभा जाता है। प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर इसके लिए भी साधारणतः दो दिन पहले सूचना देनी पड़ती है।

कृ नित्न किस प्रकार बनते हैं ?— जब किसी सभा का कोई सदस्य किसी क़ानून के मस्विदे (बिल) को पेश करना चाइता है तो वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है। यदि उसकी पेश करने के लिए नियम के अनुसार पहले हो गवर्नर-जनरल की अनुमित लेने की आवश्यकता हो तो वह मांगी जाती है। अनुमित मिल जाने पर निश्चित किये हुये दिन मस्विदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मर्सविदे के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता हो तो मस्विदा साधार्यातया उसी सभा की (जिसका सदस्य मस्विदा पेश करता हो,) या दोनों सभाओं की स्लिक्ट कमेटी अमें विचारार्थ मेना

<sup>\*</sup>इसमें सरकार का क़ानून-सदस्य, मसविदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का सदस्य, मसविदे को पेश करनेवाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं। हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखनेवाले क़ानून के मसविदों पर विचार करने के लिए पृथक् पृथक् स्थायी समितियाँ हैं। इन समितियों में अधिकांश उस जाति के ही सुधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त इनमें उस-उस: जाति के क़ानून-विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये जाते हैं।

जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन श्रादि करके श्रपनी रिपोर्ट देती है। पश्चात बिल के वाक्यांशों पर एक-एक कर के विचार किया जाता है और वे आवश्यक सुधार सहित पासः किये जाते हैं। फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशोधन सहित; पास करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास हो जाने पर, मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहाँ बिनाः संशोधन के पास हो जाय, तो उसे गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए मेज दिया जाता है, श्रीर स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून बन जाता है। अवर्गर मसविदा दूसरी सभा में सशोधनों सहित पास हो तो उसे इस निवेदन सहित लौटाया जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों: पर सहमत हो जाय। संशोधनों पर फिर वही कार्रवाई (सूचना देने, विचार करने, स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार मेजने आदि: की ) की जाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लौटाया बाय कि दसरी सभा ऐसे संशोधन पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली सभा मानने को तैयार नहीं हैं. तो वह सभा चाहे तो (१) मसविदे को रोक दे या (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर-जनरल के पास छ: मास तक मेज दे। दसरी परिस्थिति। में, मसविदा श्रीरा संशोधन दोनों सभाग्रों के ऐसे संयुक्त श्रधिवेशन में पेश होते हैं, जो गवर्नर-जनरल श्रपनी इच्छानुसार करे । इसका श्रध्यक्ष राज्य-परिषद का सभापति होता है। मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर विचार या वादानुवाद होता है-जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होता है,

वे स्वीकृत समके जाते हैं। इस प्रकार मसविदा, स्वीकृत संशोधन सिहत पास होता है, श्रीर यह मसविदा दोनों सभाश्रों से पास हुश्रा समका जाता है।

राज्य-परिषद्धं से हानि — राज्य-परिषद् ने समय-समय पर भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत (क़ानूनों के) मसिवदे अस्वीकार कर दिये तथा ऐसे मसिवदे पास कर दिये, जिनसे भारतीय व्यवस्थापक सभा का घोर विरोध था। भारतीय व्यवस्था-पक सभा राज्य-परिषद् की अपेक्षा, कहीं अधिक निर्वाचकों की प्रतिनिधि-सभा है। इसिलए राज्य-परिषद् का उक्त कार्य सर्वसाथार के हितों का घातक है। यद्यपि राज्य परिषद् में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकांश स्दस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो लोकमत की परवाह नहीं करते। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, कारण कि उनके चुननेवाले प्रायः ऐसे ही आदमी को चुनते हैं, जो सरकार की और मुकनेवाले हों। अधिकारी इस परिषद् की आड़ में अपनी मनमानी कार्यवाई कर सकते हैं। इस प्रकार इससे होनेवाली हानि स्पष्ट है।

गवर्नर जनरल के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार—
गवर्नर जनरल को यह अधिकार है कि वह राज्य-परिषद् के सदस्यों में
से किसी को सभापित नियुक्त कर दे, अथवा ख़ास हालतों में, किसी
दूसरे सज्जन को सभापित का कार्य करने के लिए नियत करे। वह
राज्य-परिषद् तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सम्मुख भाषण कर
सकता है, और इस काम के लिए उक्त सभाओं का अधिवेशन करा

खकता है। कई विषयों के मसविदे उसकी अनुमित बिना, किसी सभा में पेश नहीं हो सकते। जिन प्रस्तावों के उपस्थित किये जाने के लिए उसकी अनुमित की आवश्यकता नहीं है, उनमें से भी किसी प्रस्ताव या उसके अंश का उपस्थित किया जाना, वह इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उसके उपस्थित किये जाने से सार्व-जनिक हित की हानि होगी। दोनों समाओं में पास होने पर भी ससविदा उसकी स्वीकृति बिना कृतन् नहीं बनता। उसे यह अधिकार है कि वह दोनों समाओं से पास हुए मसविदे को स्वीकृति के लिए रख छोड़े। अन्तिम दशा में, मसविदे पर सम्राट् की स्वीकृति के लिए रख छोड़े। अन्तिम दशा में, मसविदे पर सम्राट् की स्वीकृति मिलने से ही, वह कृतन्त बन सकता है।

जब कोई सभा किसी कानून के मसिवदे के उपस्थित किये जाने की अनुमित न दे, या उसे गवर्नर-जनरल की इच्छानुसार पास न करें तो यदि गवर्नर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरचा या हित की हिन्ट से इस मसिवदें का पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा तसदीक कर देने पर वह मसिवदा कानून बन जाता है, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करें। ऐसा हर एक कानून गवर्नर-जनरल का बनाया हुआ स्चित किया जाता है। वह पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के सामने पेश किया जाता है, और जब तक सम्राट् की स्वीकृति न मिले, वह व्यवहार में नहीं लाया जाता। जब गवर्नर-जनरल यह समक्ते कि उक्त कानून को व्यवहार में लाने की अत्यन्त आवश्यकता है तो उसके ऐसा आदेश करने पर वह अमल में आ जाता है। केवल यह शर्त है कि सम्राट् ऐसे कानून ३४°

को नामंज्र कर सकता है। गवर्नर-जनरल को यह भी श्रधिकार हैं कि सूचना देकर श्रीर यह तसदीक करके कि यह मसविदा देश की रक्षा, शान्ति या हित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसविदे के सम्बन्ध में होनेवाली कार्रवाई को रोक दे, जो किसी सभा में पेश हो चुका हो या होनेवाला हो।

जैसा पिछते परिच्छेद में कहा गया है, आवश्यकता समभते पर अपनी मर्ज़ी से गवर्नर-जनरल छः माह के लिए आर्डिनेंस अर्थात् अस्थायी कृतन्त बना सकता है। गत वर्षों में कितने हो आर्डिनेंस बने हैं।

भारतीय श्राय-व्यय का विचार—भारत-सरकार के श्रतु-मानित श्राय-व्यय का विवरण (बजट) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है। गवर्नर जनरल की सिफ़ारिश बिना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। विशेषतया निम्नलिखित व्यय की महों के लिए कौंसिल युक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत (बोट) के लिए नहीं रखे जाते, न कोई सभा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक गवर्नर-जनरल इसके लिए श्राज्ञा न दे:—

(१) ऋग्य का सूद। (२) ऐसा खर्च जिसकी रक्तम क़ानून से निर्धारित हो। (३) उन लोगों के वेतन और भन्ने या पेन्शन जो सम्राट् द्वारा, या सम्राट् की स्वीकृति से, नियुक्त किये गये हों। चीफ किमशनरों या जुडिशल किमशनरों के वेतन। (४) वह रक्तम जो सम्राट् को देशी राज्यों-सम्बन्धी कार्य के खर्च के उपलक्ष में दी जाने-

वाली । है (५) किसी प्रान्त के प्रथक् किये हुए (एक्सक्लूडेड) चेत्रों के शासन-सम्बन्धो खर्च। (६) ऐसी रक्षम जो गवर्नर-जनरल उन कार्यों में खर्च करे, जिन्हें उसे अपने विवेक से करना आवश्यक हो। (७) वह खर्च जिसे कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने (क) धार्मिक। (ख) राजनैतिक या। (ग) रक्षा अर्थात् सेना-सम्बन्धी टहराया हो।

इन महों को छोड़कर अन्य विषयों के खर्च के लिए कौं खिल-युक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के बास्ते, माँग के रूप में, रखे जाते हैं। इस सभा को अधिकार है कि वह किसी माँग को स्वीकार करे, या न करे, अथवा घटा-कर स्वीकार करे। परन्तु कौंसिल-युक्त गवर्नर जनरल सभा के निश्चय को रह कर सकता है। विशेष दशाओं में गवर्नर-जनरल ऐसे ख़र्च के लिए स्वीकृति दे सकता है, जो उसकी सम्मित में देश की रक्षा या शान्ति के लिए आवश्यक हो।

गवर्नर-जनरल के विविध श्रिषकारों के होते हुए, वास्तव में भारतीय व्यवस्थापक मंडल के श्रिषकारों का कुछ महत्व नहीं है।

[सन् १९३५ ई० का विधान श्रीर भारतीय व्यवस्थापक मंडल — सन् १६३१ ई० के विधान के श्रनुसार संघ का निर्माण हो जाने पर भारतवर्ष के केन्द्रीय कानून बनानेवाजी संस्था का नाम संघीय व्यवस्थापक मंडल ('फ़ीडरल लेजिस्लेचर') होगा। उसमें दो सभाएँ होगी—राज्य-परिषद ('कोंसिल-श्राफ्त स्टेट') श्रीर संघीय व्यवस्थापक समा ('फीडरल ऐसेम्बली')। राज्य परिषद में २६० सदस्य

होंगे:—१५६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के । यह एक स्थायी संस्था होगी; इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाया करेंगे । ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से १४० जनता द्वारा निर्वाचित श्रोर छ: नामज़द होंगे ।

संबीय व्यवस्थापक सभा में ३७१ सदस्य होंगे, २४० ब्रिटिश भारत के, घौर १२१ देशी राज्यों के। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रस्यच होगो। वह प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाश्रों (ऐसेम्बिजियों) के सदस्यों द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष होगा।

दोनों सभाग्रों में देशी राज्यों की श्रोर से बिये जानेवा सं सदस्य निर्वाचित न होकर नरेशों द्वारा निर्धारित हिसाब से नियुक्त हुआ करेंगे। निर्धारित नियमों तथा सीमा को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्थापक मंडब समस्त बिटिश भारत, या उसके किसी भाग के बिए, या संघ में सिमिबित देशी राज्यों के बिए, कानून बना सकेगा। गवर्नर जनरब चाहे तो वह मंडब में स्वीकृत प्रस्ताव तथा क़ानून को श्रद्धीकार कर सकेगा, श्रथवा उसे सम्राट की स्वीकृत के बिए रख सकेगा।

श्रमुमानित श्राय-व्यय का नक्षशा दोनों सभाशों के सामने उपस्थित किया जाया करेगा, परन्तु जैसा श्राज-कत है, मंडल को व्यय की कितनी-ही महीं पर मत देने का श्रधिकार न होगा। व्यय के जिन महीं पर मंडल का मत देने का श्रधिकार होगा, यदि हनमें से किसी के सम्बन्ध में दोनों सभाशों में मत-भेद हो तो दोनों सभाशों की संयुक्त बैठक में बहुमत से जो निर्याय होगा, वह माना जायगा। गवर्नर-जनरख को श्रधिकार होगा कि यदि सभाशों ने व्यय की कोई माँग स्वीकार नहीं की, या घटाकर स्वीकार की, तो वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यकता समझने पर, अपने विशेषाधिकार से उस माँग की पूर्ति कर सके।

गवर्नर-जनरज (१) संवीय व्यवस्थापक मंडल के अवकाश के समय आर्डिनेंस (अस्थायी कानून) बना सकेगा (२) अपने उत्तरदायित्व के बिचार से आवश्यक समक्तने पर कुछ दशाओं में मंडल के कार्य-काल में आर्डिनेंस बना सकेगा और (२) विशेष दशाओं में वह स्थायी रूप से भी, मंडल की इच्छा के विरुद्ध, कानून बना सकेगा।



## ञ्जत्तीसवाँ परिच्छेद प्रान्तीय सरकार

- BOOK -

वर्तमान शासन-विधान से पहले--सन् १९३५ ई० के शासन-विधान के श्रमल में श्राने से पूर्व, भारतवर्ष में सन् १९१९ ई॰ के 'मांट-फ़ोर्ड' सुधारों के अनुसार शासन होता था। उस समय ब्रिटिश भारत के सब प्रान्तों की संख्या १५ थी, श्रीर उन के दो भेद थे: - बड़े प्रान्त और छोटे प्रान्त । बंगाल, बम्बई, मदरास, संयुक्तप्रान्त, पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त-बरार, बर्मा श्रीर श्रासाम बड़े प्रान्त कहलाते थे। इन्हीं नी प्रान्तों में अंशतः उत्तरदायी शासन पद्धति श्रारम्भ की गयी थी । शेष छ: प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते थे । इन में देहली, पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, ब्रिटिश बिलोचिस्तान, श्रंदमान-निकोवार, श्रौर कुर्ग सम्मिलित थे। बड़े प्रान्तों में गवर्नर, प्रवन्धकारिणी समाएँ श्रीर व्यवस्थापक परिषदें थीं। छोटे प्रान्तों का शासन चीफ़-कमिश्नर करते थे, जो गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त और भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। इन प्रान्तों के लिए कानून भारतीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये जाते थे, ( केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद् थी )।

बड़े प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विषय दो आगों में विभक्त थे-(१) रक्षित या 'रिज़र्वंड' श्रीर (२) इस्तान्तरित चा 'टांस्फ़र्ड'। रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार गवर्नर श्रीर उसकी प्रबन्धकारिया। सभा को था। ये भारत-सरकार श्रीर भारत-मंत्री द्वारा ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति, श्रीर श्रप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश मतदातात्रों के प्रति, उत्तरदायी थे। इस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर अपने महित्रयों के परामर्श से करता था। मंत्री प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के प्रति अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मत-दाताओं के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार प्रान्तीय सरकार के दो भाग थे: एक भाग में गवर्नर श्रीर उनकी प्रवन्धकारिणी सभा के सदस्य होते थे, दूसरे भाग में गवर्नर श्रीर उसके मंत्री। साधारणतया प्रान्तीय सरकार इकट्ठो ही किसी विषय का विचार करती थी; तथापि यह गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था कि वह किसी विषय का अपनी सरकार के केवल उस भाग से ही विचार कर ले, जो उसका प्रत्यच रूप से उत्तरदायों हो। जिस पद्धति में शासन-कार्य ऐसे हो भागों में विभक्त दोता है उसे देथ शासन-पद्धति या 'डायकीं' कहते हैं ]।

वर्तमान शासन-विधान; पान्तों का वर्गीकरण-श्रव हम यह विचार करते हैं कि वर्तमान शासन-विधान के श्रनुसार प्रान्तों का शासन किस तरह होता है। इस समय प्रान्तों के दो मेद हैं, — (क) गवर्नरों के प्रान्त श्रीर (ख) चीफ़-किमश्नरों के प्रान्त। गवर्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं:—(१) मदरास, (२) बम्बई, (३) बंगाल, (४) संयुक्तप्रान्त, (५) पंजाब, (६) बिहार, (७) मध्यप्रान्त भौर बरार, (८) श्रासाम, (९) पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, (१०) उड़ीसह भौर (११) सिन्ध ।

चीक कमिशनरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं:—(१) अजमेर-मेरवाड़ा,
(२) देहली, (३) ब्रिटिश बिलोचिस्तान (४) कुर्ग (५) अरएदमान-निकोबार और (६) पंथ पिपलौदा । इन प्रान्तों के सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा। पहले गवर्नरों के प्रान्तों के विषय में ही विचार किया जाता है।

पहले की स्थिति से तुलना करने पर पाठकों को यह जात हो बायगा कि गवनेंरों के प्रान्तों में अब बर्मा नहीं है, ऋौर तीन प्रान्त इस सूची में नये बढ़ाये गये हैं:—(१) पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, (२) उड़ीसा, और (३) सिन्ध। इनमें से पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त की गणना पहले चीफ़-कमिश्नरों के प्रान्तों में होती थी; उड़ीसा बिहार के साथ था, तथा सिन्ध बम्बई के साथ मिला हुआ था।

नये प्रान्तों का निर्माण कोई प्रान्त (चाहे वह गवर्नर का प्रान्त हो या चीफ़-किमश्नर का) निर्माण करने या उसका चेक घटाने या बढ़ाने अथवा किसी प्रान्त की सीमा बदलने का अधिकार सम्राट् को है। वह यह कार्य 'आर्डर-इन-कौंसिल' अर्थात् स-परिषद-सम्राट् की आज्ञां से करता है। इस विषय में यह आवश्यक है कि ऐसी आजा का मसविदा पार्लिमेंट में उपस्थित किये जाने से पूर्व

\*यइ भूमि पहले होल्कर राज्य के अन्तर्गत थी।

| इसके सम्बन्ध में पिञ्जले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। भारतवर्ष-सम्बन्धीः

अब आजाएँ भार त-मंत्री की सलाह से जारी की जातो है।

भारत-मंत्री भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार भीर व्यवस्थापक मंडला का तथा जिस जिस प्रान्त पर उक्त कार्य का प्रभाव पड़े वहाँ की सरकार तथा वहाँ के व्यवस्थापक मण्डल का मत मालूम करने का वह सब्द कार्य करे, जिसके लिए सम्राट्का आदेश हो।

गर्वनरः उनकी नियुक्ति, वेतन श्रीर पद —गवर्नरों के प्रांतीं के शासन-कार्य में गवर्नरों का पद मुख्य है। उन्हों पर प्रान्तीय शासन, शान्ति, सुब्यवस्था तथा विविध प्रकार की उन्नित का दायित्व है। उनकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है। उन्हें उसके कुछ निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं श्रीर वे उसी की भोर से काम करते हैं। उनके नाम एक शादेश-पत्र जारी किया जाता है। इसका मसविदा पहले भारत-मंत्री द्वारा पार्लिमेंट के सामने उपस्थित किया जाता है, फिर पार्लिमेंट सम्राट् से उस भादेश-पत्र को जारी करने का शावेदन करती है। गवर्नर इस शादेश-पत्र के श्रनुसार कार्य करता है, परन्तु उसके किसी कार्य के श्रीचित्य का प्रश्न इस श्राधार पर नहीं उठाया जा सकता कि वह कार्य शादेश-पत्र की स्वनाश्रों के श्रनुसार नहीं है। श्रादेश-पत्रों के सम्बन्ध में विशेष श्रागे लिखा जायगा।

प्रान्तों का शासन गवर्नरों के नाम से होता है। गवर्नर इस कार्य को स्वयं करने के अर्थितरिक्त, अपने विविध अधीन कर्मचारियों द्वारा भी कराता है। प्रत्येक प्रान्त का शासन-चेत्र उन सब विषयों तक होता है जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को क्रानून बनाने का अधिकार होता है। (यह विषय-सूची आगे दी जायगी)। सब प्रान्तों के गवर्नरों का वार्षिक वेतन विधान द्वारा निर्धारित है। \* वेतन के अतिरिक्त उन्हें भत्ता आदि भी इतना काफ़ी दिया जाता है जिससे वे आने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पूर्वक कर सकें, अर्थात् उनकी शान-शोकृत भली भौति बनी रहे।

बँगाल, बम्बई श्रीर मदरास के गवर्नर, श्रम्य गवर्नरों से ऊँचे दर्जे के माने जाते हैं। ये तीन गवर्नर इङ्गलैंड के राजनीतिशों में से भारत मंत्रों को खिफ़ारिश से नियत किये जाते हैं। श्रम्य प्रान्तों के गवर्नर, गवर्नर-जनरल के परामर्श से नियत हो जाते हैं; श्रमेक बार सिविल-सरिवस के कर्मचारियों में से ही स्थायी या स्थानापन्न गवर्नर बनाये जाते रहे हैं। श्रम प्रान्तीय स्वराज्य के साथ ऐसी बात श्रमंगत श्रीर श्रमहा है। मंत्रियों की श्रधीनता में काम करनेवाला राज्य-कर्मचारी एक दम उनके ऊत्तर श्रा जाय, इसका श्रमीचित्य स्पष्ट ही है।

आदेश-पत्र — आदेश-पत्र (इन्स्ट्र्मेन्ट-आफ़ इन्स्ट्रकशन्य) का उल्लेख उपर हुआ है। यह सम्राट् की ओर से जारी किया जाता है। इसमें यह लिखा रहता है कि गवर्नर को आपने शासन कार्य के

| *मदरास <b>ःः१,</b> २०,०००) | मध्यप्रान्त-बरार | मध्यप्रान्त-बरार         |    |  |  |  |
|----------------------------|------------------|--------------------------|----|--|--|--|
| बम्बई ••• "                | त्रासाम          | •••                      | 55 |  |  |  |
| बंगाल ""                   | पश्चिमोत्तर-सीम  | पश्चिमोत्तर-सोमा-प्रान्त |    |  |  |  |
| संयुक्तप्रान्त… "          | <b>उड़ी</b> सा   | •••                      | "  |  |  |  |
| पंजाब 😬 १,००,०००)          | सिन्ध            | •••                      | 97 |  |  |  |
| विहार ,,                   |                  |                          |    |  |  |  |

खम्मादन में किन-किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। गवर्नर अपने प्रान्त में सम्राट्के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता है, अतः आदेश-पत्र के द्वारा सम्राट् उसे अपने नियन्त्रण में रख सकता है। सब प्रान्तों के गवर्नरों के आदेश-पत्रों की मुख्य-मुख्य साधारण बार्ते प्रायः समान ही हैं। उनमें से कुछ निम्नोलिखित हैं--

(क) गवर्नर अपने प्रान्त के हाईकोर्ट के चीक जिस्टिस या अन्य जज के सामने राजमिक के अतिरिक्त, इस बात की श्रान्य ले कि वह अपने कार्य टीक तरह से संचालन करेगा, और निष्मक्षता तथा न्याय-पूर्वक शासन करेगा।

्र (ख) गवर्नर प्रत्येक मंत्री को इस आशय की शाय खिजावे कि वह अपने पद का कार्य अच्छी तरह करेगा और सरकारी रहस्यों को नाम रक्खेगा।

्य ) गवर्नर प्रत्येक वर्ग श्रीर धर्म के श्रनुयायियों, विशेषतया श्रहर संख्यक जातियों, के हितों का ध्यान रखे श्रीर सबका सहयोग श्राप्त करने का प्रयत्न करे।

गवर्नर के अधिकार; पान्तीय विषयों का प्रवन्ध—
यद्यि नवीन शासन-विधान का उद्देश्य प्रान्तीय स्वराज्य की स्थानना
चोषित किया गया है, गवर्नर अनेक अधिकारों से सुस्रिजत है। यहाँ
केवल शासन सम्बन्धी अधिकारों का ही विचार किया जाता है।
कानून निर्माण सम्बन्धी तथा आर्थिक अधिकार अगले परिच्छेर में
बताये जायँगे। कुछ प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर अपने

विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। उन्हें ख्रोड़कर, शेष विषयों में वह अपने मंत्री मंडल की सहायता या परामर्श से काम करता है। किसी विषय में गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का किया हुआ फैसला ही अन्तिम माना जाता है।

विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गवर्नर अपने विवेक के अनुसार कार्रवाई कर सकता है, अर्थात् इनमें उसे अपने मंत्री-मंडल से परा-मर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है:—(क) मंत्रियों की नियुक्ति तथा वर्खास्तगी, (ख) मंत्री-मंडल का समापित होना ख्रौर (ग) प्रांतीय सरकार के कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियम बनाना । विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है । अर्थात् इन विषयों में गवर्नर मंत्री-मंडल से परामर्श लेगा, परन्तु उससे सहमत न होने की दशा में वह अपने निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है:—(क) जिन विषयों में गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है, (ख) पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था और (ग) आतङ्कताद का दमन।

जो कार्य गवर्नर श्रपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कर सकता है, उनके सम्बन्ध में वह गवर्नर-जनरत्त के नियंत्रण में रहता है, और गवर्नर-जनरत्त द्वारा समय-समय पर दी हुई स्चनाओं के अनु-सार व्यवहार करता है। ये स्चनाएँ गवर्नर के नाम जारी किये हुए अधादेश-पत्र के अनुसार ही होती हैं, (इसके सम्बन्ध में पहले कह आये हैं)। परन्तु गवर्नर के, उपर्युक्त व्यवस्था के विगरीत किये हुए कार्य के भी श्रीचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे गवर्नर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता है।

गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व—गवर्नर निम्नलिखित विषयों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होताहै। [यह उत्तर-दायित्व ब्रिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता अर्थात् उसके प्रतिनिधियों के प्रति नहीं। जब कभी उसे अपने उत्तरदायित्व पर आधात पहुँचता हुआ प्रतीत होता है तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार (मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी) कार्य कर सकता है।

- (१) प्रान्त या उसके किसी भाग के शान्ति-भंग का निवारण।
- ,( २ ) ग्रल्प-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा।

[यहाँ 'श्रन्य-संख्यकों' में मुसलमान, ईसाई, दलित जातियां (हरिजन), सिक्ख, श्रीर एंग्लो-इण्डियन श्रादि माने जाते हैं]

- (३) वर्तमान तथा भूत-पूर्व सरकारी कर्मचारियों—सिविलियनों, (आई॰ सी॰ एस॰) आदि—और उनके आश्रितों के उन अधिकारों और उचित हितों की रक्षा का ध्यान रखना, जो सन् १९३५ ई॰ के विधान के अनुसार उन्हें पास हैं।
- (४) प्रान्तीय कानूनों के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था करना कि व्यापारिक और जातिगत विषयों के मेद-भाव का, या पक्षपात-मूलक, कानून न बने।

(१) अंशतः पृथक् ('एक्सक्लूडेड') घोषित किये हुए च्रेत्रों के शासन और शान्ति का प्रबन्ध।

> [भारत-मंत्री द्वारा पार्लिमेंट में मसविदा उपस्थित किये जाने पर सम्राट् की श्राज्ञा से किसी प्रान्त का कोई चेत्र पृथक् या श्रांशतः पृथक् घोषित किया जाता है | ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में ऐसे चेत्र बहुत हैं। इन चेत्रों में पुलिस श्रादि के श्रधिकारियों का ही प्रभुख होता है | नागरिकों के श्रधिकार श्रायत्व होते हैं।

- (६) देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के अधिकारों और मान-मर्थादा की रक्षा करना।
- (७) गवर्नर-जनरल की अपने विवेक से क़ानून के अनुसार निकाली, हुई आजाओं और हिदायतों के पालन किये जाने की व्यवस्था करना । उपर्युक्त उत्तरदायित्व तो सब गवर्नरों के हैं। कुछ गवर्नरों के इनके अतिरिक्त, अन्य उत्तरदायित्व भी हैं। उदाहरखरूप, मध्यप्रान्त और बरार के गवर्नर पर इस विषय का भी उत्तरदायित्व है कि उस प्रान्त से होनेवाली आय का उचित अंग्र बरार में अथवा बरार के लिए ख़र्च हो। सिन्ध के गवर्नर पर सक्खर बाँध के उचित प्रवन्ध का भी विशेष उत्तरदायित्व है।

पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था—गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार मुल्की या फीजी पुलिस के सम्बन्ध में नियम बनाता है, उन्हें स्वीकार करता है उनमें संशोधन करता है एवं आजाएँ जारी करता है। अर्थात् इस विषय में उसे मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि गवर्नर शान्ति-भंग-निवारण तथा सरकारी कर्मचारियों

के हितों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। उपर्यक्त व्यवस्था के श्रनुसार पुलिस विभाग का नियन्त्रण बहुत-कुछ इसके हाथ में रहता है।

स्रातङ्क्ष्याद् का द्मन—यदि कि धी प्रान्त के गवर्नर को यह प्रतीत हो कि प्रान्त की शान्ति ऐसे हिंसात्मक कार्यों से ख़तरे में डाली जा रही है, जो गवर्नर की सम्मित में क्वानून द्वारा स्थापित सरकार को उलटनेवाले हैं तो वह यह आदेश कर सकता है कि वह अमुक कार्य अपने हाथ में लेता है। फिर उसे उस कार्य को अपने विवेक से करने का अधिकार हो जायगा, और जब तक वह दूसरा आदेश जारी न करे वह उक्त अधिकार का प्रयोग करता रहेगा। ऐसा आदेश जारी करते समय गवर्नर एक अफ़सर को यह अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में भाषणा दे और उसकी अन्य कार्रवाई में भाग ले। इस प्रकार का अधिकार-प्राप्त अफ़सर व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में, दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में तथा उनकी उस कमेटी में, जिसमें वह गवर्नर द्वारा मेम्बर नामज़द किया गया हो, भाषणा दे सकता है, तथा उसकी कारवाई में भाग ले सकता है। हां, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता।

गवर्नर अपने विवेक के अनुसार इस बात के लिए नियम बनाता है कि अन्याधों का पता मिलने के साधन या कागज़ात प्रान्त के किसी पुलिस अफ़सर द्वारा पुलिस के किसी अन्य अफ़सर को, पुलिस इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर की आजा के बिना न बताये जायँ, तथा प्रान्त में सम्राट् की नौकरी करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को गवर्नर की आजा बिना न बताये जायँ। इसका अर्थ यह है

कि भातक्कवाद को दमन करने के लिए खुफिया पुलिस पर मन्त्रियों का श्रीविकार नहीं; गवर्नर के श्रांतिरिक्त पुलिस-इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर को ही (जो कहने को मन्त्रियों के श्राधीन हैं) गुप्त कागृज़ात-सम्बन्धी सब श्रीविकार है।

कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण—प्रान्तीय सरकार का सब शासन-कार्य गवर्नर के नाम से स्चित किया जाता है। जो कार्य गवर्नर को अपने विवेक से करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके सुविधा-पूर्वक सम्पादन के लिए तथा मंत्रियों को विविध कार्य सौंपने के लिए वह आवश्यक नियम बनाता है। इन नियमों में इस बात की व्यवस्था रहती है कि मंत्री तथा सेक्रेटरी गवनर को प्रान्तीय सरकार के कार्य सम्बन्धी ऐसी समस्त सचना दें, जो नियमों में उल्लिखित हो, या जिसका दिया जाना गवर्नर आवश्यक समके। विशेषतया मंत्री गवर्नर को, और सेक्रेटरी सम्बन्धित मंत्री एवं गवर्वर को, उस विषय की स्चना दें जो, गवर्नर के विचाराधीन हो और जिसमें उसके विशेष उत्तरदायित्व का सम्बन्ध हो या आनेवाला हो। इस प्रसंग में गवर्नर अपने मंत्रियों का परामर्श लेने के बाद अपने विवेक से कार्य करता है।

गवर्नर के अधिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य — पूर्वोक्त विवेचन से यह स्वध्ट है कि गवर्नर के शासन-सम्बन्धी निशेष अधिकार प्राय: अमर्यादित हैं (क्रानून निर्माण तथा आय व्यय-सम्बन्धी अधिकारों का विचार आगे किया जायगा)। गवर्नर के ब्रिटिश सरकार के अधीन और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हुए यह कहना दुस्साइस

है कि नवीन विधान से प्रान्तों में स्वराज्य की स्थापना की गयी है। केन्द्र का तो कुछ ज़िक ही नहीं है। यह ठीक है कि पूर्व विधान के अनुसार (गवर्नरों के) प्रान्तों में केवल 'इस्तान्तरित' कहे जाने-वाले विषयों में ही मंत्रियों का अधिकार था, सुरक्षित विषयों में नहीं था, और अब सभी विषयों में मन्त्रियों का अधिकार है। पर यह अधिकार अत्यल्प है।

श्रव इम मिन्त्रयों के विषय में विचार करते हैं। सन् १९३५ ई० के विधान का उद्देश्य प्रान्तों में स्वराज्य या उत्तरदायो शासन स्थापित करना है। इसका व्यावहारिक श्रर्थ यह है कि गवर्नर सब शासन-कार्य मिन्त्रयों के परामर्श के श्रनुसार करे श्रीर मन्त्री प्रान्त की जनता के प्रतिनिधियों श्रर्थात् प्रान्तीय व्यवस्थापक-मंडल के प्रति उत्तरदायी हों। चाहे प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी कोई कार्य गवर्नर के नाम से ही हो, उत्तरदायी शासन-पद्धति में गवर्नर प्रायः उसे श्रपने जिम्मेवारी पर नहीं करता।

मंत्री-मंडल का निर्माण — प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद, गवर्नर उस दल के नेता को मन्त्री-मंडल बनाने का निमन्त्रण देता है, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत हो। जब वह नेता मन्त्री मंडल बनाना स्वीकार कर लेता है तो उससे मन्त्रियों के नाम देने के लिए कहा जाता है। मन्त्री-मंडल बनानेवाला व्यक्ति प्रधान-मन्त्री (प्राहम-मिनिस्टर या प्रीमियर) कहलाता है। मन्त्रियों के काम का बँटवारा किस प्रकार हो, उसका निर्णय गवर्नर प्रायः प्रधान-मंत्री के परामर्श से करता है,

वैसे विधान के अनुसार वह अपने विवेक से भी कर सकता है। जिस् मंत्री को जो मुख्य कार्य सौंपा जाता है, उसे उसके अनुसार ही सम्बोधित किया जाता है, यथा अर्थे मंत्री, शिचानमंत्री, न्याय-मंत्री आदि।

मंत्री उन व्यक्तियों में से ही हो सकते हैं, जो प्रान्त के व्यवस्थापक मंडल के सदस्य हों। अगर कोई मंत्री लगातार छः महीने तक व्यवस्थापक मंडल का सदस्य न हो तो उसे अपने पद से पृथक होना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रधान-मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री-मंडल में लेना चाहता है जो व्यवस्थापक मंडल का सदस्य निर्वाचित न हुआ हो। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मंत्री तो बना लिया जाता है परन्तु प्रधान मंत्री अपने दल के किसी प्रमुख सदस्य से त्याग-पत्र दिलवाकर उसकी जगह उस मंत्री को निर्वाचित कराने का प्रयत्न करता है। यदि यह कार्य छः महीने के अन्दर न हो तो मंत्री को त्याग-पत्र दे देना होता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यवस्थापक सभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता। ऐसी दशा में मंत्री-मंडल निर्माण करने के लिए गवर्नर उस दल के नेता को निर्मात्रत करता है जो दूसरे दलों के सहयोग से (बहुमत प्राप्त कर) मंत्री-मंडल बना सके। इस प्रकार बनाये हुए मंत्री-मंडल को सम्मिलित मंत्री-मंडल या गंगा-जमुनी मंत्री-मंडल ('कोश्रालशन मिनिस्टरी') कहते हैं। ऐसे मंत्री-मंडल के सदस्यों के उद्देश्यों में भिन्नता होने के कारण, उसकी प्रायः कोई स्थिर नीति नहीं रहती।

मन्त्रियों की नियुक्ति-शासन-विधान के श्रनुसार किसी प्रान्त

के मन्त्रियों की संख्या निर्घारित नहीं हैं। उन की नियुक्ति का श्रिषकार गवर्नर को है, श्रीर वह यह कार्य अपने विवेक से कर सकता है। श्रार्थात् इसमें उसे किसी का परामर्श लेने की श्रावर्यकता नहीं है। श्रादेश-पत्र के श्रानुसार गवर्नर को व्यवस्थापक सभा के उस दल के नेता से परामर्श करके मंत्री-मंडल बनाना चाहिए, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत हो। परन्तु गवर्नर श्रादेश-पत्र को मंग कर सकता है, श्रीर सम्राट् को छोड़कर कोई अन्य श्रिषकारी उसे इसके लिए दोषी नहीं उहरा सकता। मन्त्री अपने पद पर उसी समय तक बने रहते हैं जब तक कि गवर्नर चाहता है।

साधारण प्रथा यही है कि गवर्नर उस दल के नेता के परामर्श के अनुसार ही मंत्री-मंडल बनाये, जिसका व्यवस्थापक सभा में, बहुमत हो। जब इस प्रथा की अवहेलना की जाती है, और अल्प-संख्यक दल के नेता को मंत्री-मंडल बनाने का अवसर दिया जाता है तो वह मंत्री-मंडल स्थायी नहीं हो पाता, जब तक कि उसे सहयोग देनेवाले दलों की शक्ति पर्याप्त न हों। अर्थात् व्यवस्थापक सभा के इन सब दलों के सदस्य मिलकर बहुमत-दल के सदस्यों से काफ़ी अधिक न हों।

मिन्त्रियों का वेतन — मन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल समय-समय पर निर्धारित करता है और जब तक वह निर्धारित न करे, गवर्नर उसका निश्चय करता है। परन्तु किसी मंत्री का वेतन उसके कार्य-काल में बदला नर्ी जाता। सन् १९३७ से १९३९ तक आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल रहा। इन प्रान्तों में मन्त्रियों का वेतन पाँच-पाँच सौ रुपये मासिक था। अन्य प्रान्तों में वेतन आधिक था। कांग्रेसी मन्त्री-मंडल बनने के पूर्व इन प्रान्तों में भो मन्त्रियों का वेतन बहुत अधिक था।

मंत्री-मंडल का सभापितत्व—मन्त्री-मंडल अपने-अपने कार्य के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इस दृष्टि से उसका सभापित वास्तव में प्रधान-मन्त्री होना चाहिए जिससें प्रत्येक मन्त्री उसको मुख्या माने। परन्तु भारतीय शासन-विधान के अनुसार गवर्नर को अपने विवेक से मन्त्री-मंडल का सभापित होने का अधिकार है। इससे मन्त्री-मंडल में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का उदय होने में बाधा उपस्थित होतो है।

मन्त्री-मंडल से किसी मन्त्री का पृथकरण—यदि प्रधान-मन्त्री किसी मन्त्री को मन्त्री-मंडल से पृथक् करना चाहता है तो वह उसे त्याग-पत्र देने की प्रेरणा करता है। यदि इसमें छकल हो जाय श्रयीत् वह मंत्री इस्तीक्षा दे दे तो मामला निषट जाता है। परन्तु यदि वह मंत्री समभाने-खुभाने से श्रयने पद का परित्याग करे तो प्रधान-मंत्री श्रयना तथा मंत्री-मंडल का त्याग-पत्र देकर पुनः ऐसा मंत्री-मंडल बनाता है पृथक जिसमें उपयुक्त एक मंत्री न रहे। इस प्रकार यह मंत्री पृथक् कर दिया जाता है।

मन्त्रियों के अधिकार—नया विधान प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध में गवर्नरों के अधिकारों से भरा हुआ है। उन्हीं के साथ मन्त्रियों के अधिकारों का भी कुछ उल्लेखहैं। यदि वास्तव में यहाँ प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की जाती, तो यह बात न होती—उस

दशा में तो प्रान्तीय शासन के सूत्र-संचालक और कर्चा-घर्चा सब कुछ मन्त्री ही होते, श्रीर गवर्नर उनकी बात पर मोहर लगानेवाला होता। परन्तु वर्तमान दशा में गवर्नर अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में मन्त्रियों का परामर्श मानने को बाध्य नहीं हैं। श्रीर गवर्नर को कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण का जो श्रिषकार है उसके श्रनुसार सरकारी (सिविलियन) सेक टेरियों को सीचे गवर्नर के पास पहुंचने का, श्रीर मंदियों के कार्य में बाधक होने का, श्रवसर मिलता है।

कई बड़े-बड़े सरकारी विभागों के प्रधान श्रिषकारी श्रिखल भारतीय सर्विस के होते हैं। उनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा होने के कारण, मंत्रियों का उन पर यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता।

पार्लिमेन्टरी सेक्रेटरी—कई प्रान्तों में मन्त्रियों के सहायक भी हैं; इन्हें पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी कहते हैं। ये मन्त्रियों को, उनके विशेषतया व्यवस्था-सम्बन्धी कार्यों में श्रावश्यकतानुसार सहायता देते हैं। इनके वेतन श्रीर मत्ते के लिए प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की स्वीकृति ली जाती है। क्योंकि इन पदों पर व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती है, इसलिए विधान के श्रनुसार यह श्रावश्यक होता है कि व्यवस्थापक सभा यह क़ानून पास करे कि सरकारी कोष से वेतन पाने के कारण कोई पार्लिमेंटरी सेक्रेटरी व्यवस्थापक सभा की सदस्यता से बंचित नहीं किया जायगा। विधान में इनकी नियुक्ति तथा श्रधिकारों का उल्लेख नहीं हैं। इनका पद उप मंत्रियों की तरह का समभा जाना चाहिए। एडवोकेट जनरल - गवर्नरों के प्रान्तों में से प्रश्येक में एकएक एडवोकेट-जनरल रहता है। इस पद के लिए उस प्रान्त का
गवर्नर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें हाईकोर्ट का जज होने
की योग्यता हो। उसका कर्तव्य प्रान्तीय सरकार को कानूनी विषयों
परामर्श देना, श्रीर हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से वकालत
करने श्रादि के ऐसे श्रन्य क़ानूनी कार्य करना होता है जो गवर्नर
समय-समय पर उसके लिए निर्धारित करे। वह उस समय तक श्रपने
पद पर श्रास्त्व रहता है जब तकिक गवर्नर चाहे श्रीर उसे उतना
वेतनादि मिलता है जितना गवर्नर निश्चय करे। गवर्नर यह कार्य
श्रपने व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता है, श्रर्थात् इसमें वह मित्रयों का
निर्णय मानने को वाध्य नहीं है।

इङ्गलैंड में इस प्रकार का अधिकारी ('अटानीं-जनरल') मंत्रो-मंडल का ही आंग समभा जाता है; उसकी नियुक्ति प्रधान-मनी द्वारा होती है और मन्त्री-मण्डल के बदलने पर उसे भी त्याग-पत्र देना पड़ता है । भारतवर्ष में विधान से एडवोकेट-जनरल का पद ऐसा नहीं किया गया।

शासन-विधान की निस्सारता—नये शासन-विधान में कहने को तो प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गयो है, परन्तु इस दावे की कमज़ोरी पद-पद पर प्रकट है। गवर्नर श्रीर उसके मन्त्रियों के सम्बन्ध का ही विचार कीजिए। गवर्नर श्रपने मन्त्रियों को श्रपनी इच्छानुसार श्राज्ञा दे सकता है। यदि मन्त्री उसकी श्राज्ञा का पालन न करें तो गवर्नर व्यवस्थापक मण्डल को भंग करके श्रथवा बिना

संग किये उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए वाध्य कर सकता है, श्रीर उनके स्थान पर अपने विवेक के अनुसार नयी नियुक्तियाँ कर सकता है; ये नये मन्त्री उसकी इच्छानुसार ही सब कार्य करेंगे। यदि कदाचित ऐसा हो कि गवनर को अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए उपयुक्त मन्त्रों न मिलें तो वह शासन-विधान मंग होने की घोषणा निकालकर समस्त शासन-कार्य अपने हाथ में ले सकता है। इससे मान्त्रयों के प्रभाव-हीन होने में कुछ सन्देह नहीं है। यह समस्य है कि मन्त्री-मएडल के वैधानिक अधिकार बहुत कम हैं। और, फलस्वरूप शासन-विधान का प्रान्तीय स्वराज्य का दावा निस्सार है।\*

चीफ किमश्नरों के प्रान्तों का शासन —चीक किमश्नरों के छः प्रान्तों के नाम पहले बताये जा चुके हैं। इन प्रान्तों का शासन चीक किमश्नरों द्वारा गवर्नर-जनरल करता है। चीक किमश्नरों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार करता है। कुछ चीक किमश्नर राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते है। ब्रिटिश विलोचिस्तान का चीक किमश्नर विलोचिस्तान की रियासतों का, और अजमेर-मेरवाड़े का चीक किमश्नर राजपूताने

<sup>\*</sup>पहले बताया जा चुका है कि सन् १९३९ ई० से कांग्रसी मंत्रा-मंडलवाले प्रान्तों में शासन-विधान स्थागित है। इन सात प्रान्तों में सब श्रियकार सूत्र गवनैरों के हाथ में हैं। पुस्तक छपते समय इन प्रान्तों के विविध विभागों के लगभग सब भूत-पूर्व मंत्री (तथा श्रन्थ बहुत से कांग्रसवादी) युद्ध-विरोधी नारे लगाने श्रादि के कारण जेल में हैं।

की रियासतों का, एजंट होता है। कुर्ग का चीफ़ कमिश्नर मैसूर राज्य के लिए भारत-सरकार के रेजीडेन्ट का कार्य करता है। पंथ-पिपलीदा का चीफ-कमिश्नर मध्य-भारत का रेजीडेन्ट है।

चीफ़ कमिश्नरों के अन्य सब प्रांतों के लिए तो क़ानून आरतीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा ही बनाये जाते हैं, केवल कुर्ग मे व्यवस्थापक परिषद है; वह भी छोटी-सी तथा शक्ति-हीन है।

प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना करनेवाले विधान से भी चीफ किमरनरों के प्रांतों की स्थिति पूर्ववत् बना रहना अत्यन्त चिंतनीय है। चीफ किमरनर की अधीनता में किमरनर कार्य करते है और चीफ किमरनर गवर्नर-जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है; परन्तु जहां तक जनता का स्मवन्ध है इन प्रांतों के उक्त दोनों अधिकारी निरंकुश और स्वेच्छाचारी कहे जा सकते हैं।

इन प्रांतों के शासन-सुधार का एक उपाय यह है कि प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या तथा शक्ति के अनुसार एक व्यवस्थापक सभा का आयोजन होना चाहिए। साथ ही एक छोटा-सा मंत्री-मगडल भी होने की आवश्यकता है जो चीफ़ कमिश्नर को प्रत्येक शासन-कार्य में सफल सहयोग प्रदान करे और व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तर-दायी हो। यह व्यवस्था मितव्यायतापूर्वक की जानी चाहिए। सुधार का दूसरा मार्ग यह है कि इन प्रान्तों में से जिसका, जिस 'गवर्नर के प्रान्त' से, अधिक मेल बैठ सके, उसे उसके साथ संलग्न कर दिया जाय; जिससे उसके निवासियों को अपने राजनैतिक अधिकारों

का यथेष्ट उपयोग श्रौर विकास करने का श्रवसर मिले। उदा-हरणार्थ श्रजमेर-मेरवाड़ा संयुक्तपान्त के साथ मिलाया जा सकता है।

प्रान्तों के भाग; किमश्निरियाँ — मदरास प्रान्त को छोड़ कर प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार-पांच किमश्निरियाँ हैं। किमश्नरी के अफ़सर को किमश्नर कहते हैं। यह शासन-सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल ज़िलों के काम की जांच-पड़ताल करता है। इनका विशेष सम्बन्ध मालगुज़ारी से रहता है। मदरास में किमश्निरियां नहीं, हैं। वहीं किमश्नरों के बिना भी सब काम सुचार रूप से हो रहा है। अन्य प्रान्तों में भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

ज़िले का शासन—प्रत्येक किमश्नरी में तीन या श्रिषक ज़िले होते हैं, प्रत्येक का शासन एक ज़िला-मिजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। ज़िलाधीश ज़िले का 'कलेक्टर' भी होता है। कलेक्टर का श्रिश्य है, वस्त करनेवाला। ज़िला-मिजिस्ट्रेट का एक मुख्य कार्य मालगुज़ारी वस्त करनेवाला। ज़िला-मिजिस्ट्रेट का एक मुख्य कार्य मालगुज़ारी वस्तूल करना होने के कारण, उसे साधारण बोलचाल में 'कलेक्टर कहते हैं। (पंजाब, श्रवध श्रीर मध्यप्रान्त में वह डिप्टी-किमिश्नर कहलाता है।) ज़िले की सब प्रकार की मुख-शान्ति का वही उत्तर-दाता है।) ज़िले की सब प्रकार की मुख-शान्ति का वही उत्तर-दाता है। पुलिस मुपरिन्टडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, मुंसिफ़, एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल सर्जन, जेल मुपरिन्टन्डेन्ट तथा स्कूल इन्सपेक्टर श्रादि। श्रफ़सर श्रपने पृथक-पृथक विभागों के उच्च कर्म वार्यों के श्राधीन होते हैं परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज श्रीर मुन्सिफ़ श्रादि को छोड़ कर सब पर मिजस्ट्रेट ही प्रधान होता है। ज़िले का हाकिम वही

कहा जाता है। इसके कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी श्रौर सहायक मजिस्ट्रेट रहते हैं।

प्रायः प्रत्येक ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविज़न कहते हैं। हर एक सब-डिविज़न एक डिप्टो कतेक्टर अथवा ऐक्त्र्द्रा-ऐसिस्टेन्ट-कमिश्नर के अधीन रहता है। अपनी-अपनी अमलदारी में सब-डिविजनों के अफ़्सरों के अधिकार थोड़े-बहुत मेद से कतेक्टर-मजिस्ट्रेटों के समान हो होते हैं।

बंगाल तथा बिहार को छाड़कर, श्रान्यत्र प्रत्येक ज़िले के श्रान्तंगत ५-६ तहसील (या ताल्लुके) हैं। ज़िले के ये भाग सब-डिप्टो-कलेक्टरों, या तहसीलदारों के श्रायोन हैं; इन के सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, पेराकार, कानूनगो, रेवेन्यू इन्सपेक्टर श्रादि होते हैं। प्राय: एक तहसील में कई सर्कल या हल्के होते हैं। तहसीलदार के श्रायीन गाँवों में नम्बरदार (पटेल), चौकोदार श्रीर पटवारो रहते हैं।

बंगाल, बिहार तथा संयुक्त शानत के जिन-जिन भागों में मालगुज़ारी का स्थायी वन्दोबस्त है उनमें सब-डिविजनल अफ्षर के नोचे थानेदार तथा एक एक ग्राम-समूह के लिए दफ़ादार, अगेर प्रत्येक ग्राम में चौकीदार रहते हैं।

ब्रिटिश भारत में शासन की इकाई ज़िला है। मुख्य शासक ज़िला॰ मिजस्ट्रेट प्रायः आई० सी० एस० ऋर्थीत् इडियन विवित्त सर्वितवाले होते हैं। इन पर प्रान्त के मन्त्री-मंडल का ययेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता। इससे भी प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता स्वष्ट है।

## इत्तीसवाँ परिच्छेद

## प्रान्तीय व्यवस्थापक मगडल

[संघ की स्थापना होने तक, जहाँ इस परिच्छेद में संघ, श्रौर 'संघीय व्यवस्थापक मगडल शब्दों का प्रयोग हुश्रा है वहीं उनसे क्रमशः केन्द्रीय सरकार श्रौर भारतीय व्यवस्थापक मंडल का श्राशय जिया जाना चाहिए । संघान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धो नियम संघ स्थापित होने तक लागू न होंगे।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल की सभाएँ और उनकी प्रविध—पहले बताया जा चुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रान्त गवनर के प्रान्त कहलाते हैं। इनके व्यवस्थापक मण्डलों में सम्राट् के प्रतिनिधि-स्वरूप एक-एक गवर्नर होता है। उसके अतिरिक्त छः प्रान्तों अर्थात् (१) मदरास (१) बम्बई (३) बंगाल (४) संयुक्तप्रान्त (५) बिहार और (६) आसाम में दो समाएँ और शोष पाँच प्रान्तों अर्थात् पंजाब, मध्यप्रान्त और बरार, पश्चिमोत्तर-

सीमा-प्रान्त, उड़ीसा और सिन्ध में एक-एक सभा है । जिन छुट्ट प्रान्तों के व्यवस्थापक मएडलों में दो-दो सभाएं हैं उनकी उन सभाओं के नाम क्रमश व्यवस्थापक परिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल) और व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) हैं। और, जहाँ एक ही सभा है, वहाँ वह व्यवस्थापक सभा कहलाती है। किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) यदि वह पहले भंग न की जाय तो अपने बैठक के निर्धारित दिन से अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक रहती है, इस समय के बाद भङ्ग हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद एक स्थायी संस्था होती है। जों कभी भंग नहीं होती। इसके यथा-सम्भव एक-तिहाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार तीन-तीन साल में बदलते रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक तीन साल के बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का नया जुनाव होगा; कौन-कौन से सदस्य पहले तीन साल बाद, और कौन-कौनसे पहले छु: साल बाद इससे प्रथक होंगे, इसका निर्ण्य गवर्नर अपने विवेक से करेगा।

सदस्य न होते हुए भी प्रत्येक मन्त्री तथा एडवोकेट-जनरल अपने प्रान्त की व्यवस्थापक सभा तथा व्यवस्थापक-परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। हाँ, वे अपना मत उसी सभा में दे सकेंगे, जिसके वे सदस्य होंगे।

इन सभात्रों के सम्बन्ध में श्रन्य बातें जानने से पहले यह ज्ञान प्राप्त कर लेना श्रावश्यक है कि इनके सदस्यों को जुनने में कौन-कौन व्यक्ति भाग नहीं ले सकते श्रीर कैसी योग्यता के व्यक्ति सदस्य हो। सकते हैं। कोन-कोन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते?— निर्वाचक-सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया जाता, जो इक्तीस वर्ष का न हो, और ब्रिटिश प्रजा न हो।

जो न्यक्ति पागल हो, श्रीर न्यायालय से पागल ठहराया गया हो, वह निर्वाचक नहीं हो सकता।

सिक्ख, मुसलमान, एंग्लो-इंडियन, योरिययन या भारतीय ईसाई निर्वाचक-संघों से क्रमशः इन्हीं जातियों के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक-संघ में मत नहीं दे सकते।

साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक-संघ में मत नहीं दे सकता । हाँ, किसी निर्वाचक संघ में मत देनेवाला व्यक्ति स्त्रियों के चुनाव के लिए विशेष रूप से बनाये हुए निर्वाचक-संघ में मत दे सकता है।

निर्वाचन सम्बन्धी श्रापराध का दोषी तथा देश-विहिष्कार या क्रैद की सज़ा भुगतनेवाला व्यक्ति मत नहीं दे सकता।

स्त्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति की योग्यता के कारण निर्वाचक-सूचों में दर्ज हो, उसका नाम उक्त सूची में तब तक दर्ज रहता है, जब तक कि वह फिर विवाह न कर ले या उसमें कोई उपर्युक्त अर्थोग्यता न हो जाय। किसी आदमी की योग्यता के आधार पर एक ही स्त्री मताधिकारिणी हो सकती है।

सदस्यों की योग्यता आदि—वही व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्था-पक मण्डल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होता है, जिसका नाम निर्वाचक-संघ की सूची में दर्ज होता है श्रीर (क) जो ब्रिटिश प्रजा या संघानतिरत देशी राज्य का नरेश या प्रजा हो, (ख) जो व्यव-स्थापक सभा की मेम्बरी के लिए पच्चीस वर्ष श्रीर व्यवस्थापक परिषद की मेम्बरी के लिए तीस वर्ष से कम श्रायु का न हो, तथा (ग) जिसमें निर्धारित थोग्यता हो।

सरकारी नौकर, पागल दिवालिया श्रौर कुछ श्रपराधों के श्रपराधी विवक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद के सदस्य चुने जाने या होने के श्रयोग्य ढहराये जाते हैं।

[ संघ या किसी प्रांत का मन्त्री होने से कोई व्यक्ति सदस्य बनने के प्रयोग्य नहीं होता ! ]

यदि कोई ऐसा व्यक्ति, सदस्य के रूप में, किसी सभा में बैठे श्रीर मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न हो, या जो सदस्य होने के लिए श्रयोग्य ठहराया गया हो, तो जितने दिन वह बैठेगा श्रीर मत देगा, उस पर प्रति दिन पाँच सौ रुपये के हिसाब से दराइ होगा।

सदस्यों के रियायती श्रिधिकार, वेतनादि जहाँ तक कोई सदस्य इन सभाओं के नियमों की श्रवहेलना न करे, उसे इनमें भाषण करने की स्वतन्त्रता है। किसी सदस्य पर सभाओं या इनकी कमेटियों में भाषण या मत देने के कारण, या सभा के श्रादेशानुसार उसकी रिपोर्ट श्रादि प्रकाशित करने के कारण, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

•यवस्थापक मंडल के सदस्यों को दिया जानेवाला वेतन श्रौरः भत्ता समय-समय पर निर्घारित होता है। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों को यह श्रिषकार है कि यदि कोई सदस्य या दर्शक श्रादि सभा के नियमों के विरुद्ध या श्रिशिष्ट व्यवहार करें तो उसे सभा-भवन से निकाल दें। वे यह क़ानून भी बना सकती हैं कि यदि कोई व्यक्ति सभा की किसी कमेटी के सभापित की श्राज्ञा की श्रवहेलना करके कमेटी के सामने गवाही देने, या कोई दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करें तो उसे न्यायालय द्वारा द्युड दिया जाय।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का संगठन—श्रगले पृष्ठ में दिये हुए नक्ष्में से यह जात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाश्रों में किस-किस निर्वाचक-संघ से कितने-कितने सदस्य होते हैं श्रर्थात् भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और विशेष हितों के प्रतिनिधियों जिए कितनी-कितनी जगहें निश्चित हैं।

साम्प्रदायिक जगहों को शहरी श्रीर देहाती निर्वाचन-चेत्रों में विभक्त किया गया है। उदाहरणार्थ संयुक्तप्रान्त में १४० साधारण जगहों में से १७ शहरी श्रीर १२३ देहाती; मुसलमानों की ६४ जगहों में से १३ जगह शहरी श्रीर ५१ देहाती हैं। स्त्रियों की ४ साधारण जगहों में से १ शहरी श्रीर ३ देहाती; तथा मुसलमान स्त्रियों की ३ जगहों में से १ शहरी श्रीर १ जगह देहाती निर्वाचन-चेत्रों के लिए सुरक्षित हैं। योरपियन, एंग्लो-इंडियन, श्रीर भारतीय ईसाइयों की जगहों को शहरी श्रीर देहाती निर्वाचन-चेत्रों में विभक्त नहीं किया गया है, कारण ये लोग श्रधिकतर नगरों या कस्बों में दी रहते हैं।

|                   | 000    |           | योग                             | 200        | 100        | 2 2           | 5 K             | 200        | 6        | 6                | Son Son   | 9            | o w           | w          |
|-------------------|--------|-----------|---------------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|------------|----------|------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|                   | w<br>~ |           | भारतीय ईखाई                     | ۵          | ^          |               | :               | •          |          |                  |           |              |               | :          |
|                   | 2      |           | <b>∓</b> ¤डोड़-कि•्रे           |            | •          |               | ,               | :          |          |                  |           |              |               | :          |
|                   | 20     | स्त्रियाँ | र्वेद्यसाच                      | ~          |            | - A           | / B             | <i>^</i> • | · •v     | ,                |           |              |               | ~          |
|                   | 80     |           | <b>छ</b> म्म)                   | <u> </u> : |            | :             | :               | . ~        | • :      | •                |           |              |               | :          |
|                   | 2      |           | Blaka                           | w          |            | B             | · >             | • ~        | · wx     | , W.             | ~         | . :          | a.            | ~          |
| गठन               | ~~     | 1         | मबंद्र                          | w          | 9          | IJ            | ſm              | , WA       | · m·     | R                | >=        | :            | R             | ~          |
| मं.               | °~     |           | विश्व विद्यालय                  | 1 ~        | ۰ م        | - A           |                 | ^ ~        | · 0~     | • ~              |           |              | :             | :          |
| 100 H             | 00     |           | नुमीदार                         | w          | B          | , <u>a</u>    | <i>w</i>        |            | >        | m                | . :       | n            | n             | er.        |
| सभाष्टों का संगठन | n      | The       | पिष्टि प्रापाष्ट्र<br>रूप्रोक्ट | w          | 9          | ٥<br><b>م</b> | · m             | · ~        | · >>     | a                | e√<br>e√  | :            | 0~            | e e        |
| विक               | 9      |           | मारतीय ईसाई                     | Ŋ          | us.        | (A)           | B               | · 0        | •        | :                | ~         | :            | ~             | :          |
| ठयवस्थापक         | w      |           | व्यव्यवस                        | m          | m          | ~             | n               | • •        | R        | ~                | a         | ;            | :             | ~          |
| 10                | 54     | \ <u></u> | म्फडोंड्-फिग्र्                 | R          | موی        | m             |                 | ~          | ~        | ~                | :         | :            | :             | :          |
| प्रान्तीय         | >      |           | सर्वयवान                        | វិ         | 8          | 9<br>~<br>~   | w               | ŭ          | 8        | »<br>~           | )4<br>114 | m            | <b>&gt;</b> - | US.<br>No. |
| E                 | m      |           | <b>छ</b> म्भी                   | -:         | :          |               |                 | m          | <u>.</u> | :                | w         | :            | :             | :          |
|                   | ~      | र्जीह     | हर्फ पृष्ट इंद्वर्ग<br>फिनीक    | 0~         | o~         |               |                 |            | 9        | ~                | ~         | :            | ಶ             | :          |
|                   | ~      |           | Blake                           | \$ X &     | ×          | ัฐ            | >>              | )o         | W        | II >             | 9         | 0^           | > >           | ភ          |
|                   |        |           | प्रान्त                         | <b>b</b> 1 | ब्र म बर्ड |               | संयुक्त प्रान्त | पंजाब      | बिहार    | मध्यप्रांत-ब्रार | आक्षाम    | प० सीमारान्त | उड़ीसा        | सिंघ       |

निर्वाचक कौन हो सकता है ?— मताबिकार का मुख्य आधार अभी तक सम्पत्ति है। शिक्षा-सम्बन्धी तथा सैनिक योग्यता के आधार पर भी मताबिकार दिया गया है। जिन व्यक्तियों में निर्वाचक की पहले बतायी हुई अयोग्यता न हो, और जिनमें निम्न- लिखित योग्यताएँ हों, \* वे ही प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के किसी निर्वाचक-संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:—

- १-जो निर्वाचक-संघ की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और
- २-(क) जो २४) या अधिक वार्षिक किराये के मकान में रहते हों। या
  - (ख) जो म्युनिसिपैलटी को १५०) या अधिक की वार्षिक आय पर हैसियत-कर देते हों । या
  - (ग) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों। या
  - (घ) जो ५) या ऋषिक वार्षिक मालगुज़ारी या १०) या ऋषिक लगान देनेवाली ज़मीन के मालिक हों। या
  - (च) जो अपर-प्राइमरी क्रास पास हों। या
  - (छ) जो भारतीय सेना के पेंशन पानेवाते या नौकरी छोड़ चुकने-वाले त्राफ़सर या सिपाही हों।

किंसी स्त्री का नाम निर्वाचक-सूची में निम्नलिखित दशा में ही दर्ज किया जाता है:—(क) श्रगर वह भारतीय सेना के पेंशन पाने- वाले या नौकरी छोड़ चुकनेवाले श्रफ्सर या सिपाही की पेंशन पाने-

<sup>\*</sup>भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इन योग्यता-सम्बन्धी नियमों में भेद है। स्थानामाब् स इमने यहाँ संयुक्तप्रान्त के ही मुख्य-मुख्य नियमों का उल्लेख किया है।

वाली विधवा या माता हो, या (ख) श्रगर उसे लिखना-पढ़ना श्राता हो या (ग) श्रगर उसके पति में निर्धारित श्राधिक योग्यता हो। [यह योग्यता पूर्व-सूचित साधारण योग्यता से कुछ श्रधिक है।]

ये योग्यताएँ साधारण्तया जाति गत निर्वाचक संघों के विषय की हैं। कई प्रान्तों में (क) व्यापार उद्योग श्रीर खिण्ज (ख) जमी दार, (ग) विश्व-विद्यालय श्रीर (घ) मज़दूरों के विशेष हितों के लिए विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी है। इनके निर्वाचक संघों के निर्वाचकों के लिए श्रन्य योग्यताएँ निर्धारित हैं।

भारतीय नेताओं की माँग थी कि प्रत्येक बालिग पुरुष स्त्री को मताधिकार मिले, परन्तु यह नहीं हुआ। हाँ, जब कि नवीन शासन-विधान से पूर्व बिटिश भारत के ७१ लाख, अर्थात् तीन प्रतिशत व्यक्तियों को मताधिकार था, अब साढ़े तीन करोड़ पुरुष-स्त्रियों को अर्थात् लगभग १४ प्रतिशत जनता को मताधिकार है।

नवीन विधान के श्रनुसार यहाँ १४ प्रकार के निर्वाचक संघ हैं। निर्वाचक संघों की श्रनेकता राष्ट्रीयता का श्रंग भंग करती है, जनता को वास्तविक स्वराज्य के लिए संयुक्त निर्वाचन चाहिए। इस विषय में, पहले (उन्नीसवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद — अगले पृष्ठ में दिये हुए नकशे से यह ज्ञात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक प्रारंपदों में किस-किस निर्वाचक-संघ के कितने-कितने सदस्य हैं।

|                   |            |                         | प्रान्तीय | ड्यवस्था        | वक परिष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रान्तीय ब्यवस्थापक परिषदों का संगठन |                                    |
|-------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| प्रान्त           | साधारया    | साधारया मुसलमान योरपियन | योरिययन   | मारतीय<br>ई 8ाई | व्यव्हथा-<br>पक् सभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गवनेर द्वारा नामज़द                   | योग                                |
| मद्राप्त          | <b>र्ज</b> | 9                       | ~         | as .            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द से कम नहीं<br>१० से अधिक नहीं       | ५४ से कम नहीं<br>४६ से अधिक नहीं   |
| ুল<br>জ<br>ব<br>ব | 2          | ಕ                       | ~         | :               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३ से कम नहीं<br>४ से ऋधिक नहीं        | २९ से कम नहीं<br>३० से श्रंधक नहीं |
| is in             | •          | 9                       | m         | •               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६ से कम नहीं<br>द से अधिक नहीं        | ६३ से कम नहीं<br>६५ से अधिक नहीं   |
| संयुक्तप्रोत      | > mr       | <b>9</b><br>%           | ~         | :               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६ से कम नहीं<br>द से अधिक नहीं        | ५८ से कम नहीं<br>६० से श्रधिक नहीं |
| बिहार             | <b>◆</b>   | >-                      | ~         | ;               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३ से कम नहीं<br>४ से अधिक नहीं        | २९ से कम नहीं<br>३० से अधिक नहीं   |
| श्रासाम           | •          | w                       |           | :               | And a supple sup | ३ से कम नहीं<br>४ से आधिक नहीं        | २१ से कम नहीं<br>२२ से अधिक नहीं   |

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्चों के सदस्यों द्वारा चुने जानेवाले सदस्य 'एकाकी इस्तान्तरित मत' (सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट ) प्रणाली से, श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व के श्रनुसार, चुने जाते हैं। इसके सम्बन्ध में पहले (उन्नीसवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है।

निर्वाचकों की योग्यता—प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों को जुननेवाले निर्वाचक वे ही व्यक्ति हो सकते हैं, जो निर्वाचक संघ के चेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों। उनकी अन्य योग्यता का परिमाण भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक-पृथक है। स्थानाभाव से हम यहाँ संयुक्तप्रान्त के निर्वाचकों की ही मुख्य-मुख्य योग्यताओं का उल्लेख करते हैं। इस प्रान्त में निम्नलिखित योग्यतावाले व्यक्तियों को निर्वाचकों की सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार है:—

साधारण योग्यता—(अ) गतवर्ष में ४०००) या अधिक पर श्राय-कर देना; या (आ) दोवान-बहादुर, खाँबहादुर, रायबहादुर, रायबहादुर, रायबहादुर, रावबहादुर या इनसे ऊँची उपाधि प्राप्त होना, या (इ) २५० ६० मासिक पेन्शन पाना, या (ई) निम्नलिखित पदों पर रह चुकना, या होना—ब्रिटिश भारत के किसी व्यवस्थापक मंडल का गैर-सरकारी सदस्य; किसी विश्व-विद्यालय का चान्सलर; फ़ेलो, कोर्ट या सिनेट का सदस्य; संघ-न्यायालय, हाईकोर्ट या चीफ्रकोर्ट का न्यायाधीश; किसी म्युनिसिपैलटी या ज़िला-बोर्ड का गैर-सरकारी सभापति; या (उ) १०००) रु० या अधिक सालाना मालगुज़ारी देना या इतनी मालगुज़ारी माफ्री की ज़मीन का मालिक होना; या (ऊ) १५००) या अधिक सालाना लगान देना।

स्त्रियों सम्बन्धी योग्यता—ऐसी प्रत्येक स्त्री को मताधिकार है जिसके पित में निम्नलिखित योग्यताएँ पायी जावें—(क) गत वर्ष में १०,०००) या श्रिषक पर श्राय-कर देना, या (ख) ५,०००) रु० या श्रिषक पालाना मालगुज़ारी देना, या (ग) दीवान-बहादुर, खांबहादुर, रायबहादुर, रावबहादुर या इनसे ऊँची उपिष प्राप्त होना या (घ) २५०) रु० या श्रीषक मासिक पेंशन पाना।

दिलित जातियों सम्बन्धी योग्यता—(श) २,०००) या अधिक पर आय कर देना, या (ष) २००) या अधिक सालाना मालगुज़ारी देना, या (स) ५००) या अधिक सालाना लगान देना, या (ह) जावर्नर-जनरल से कोई पद प्राप्त करना।

इसमें सन्देह नहीं कि निर्वाचकों की योग्यता का आधार उच आर्थिक स्थिति अथवा उच पदोंवाली सरकारी नौकरी है, और इन परिषदों के निर्वाचित सदस्य सर्वसाधारण के हितों के प्रतिनिधि न होकर उक्त थोड़े से निर्वाचकों का ही मत प्रकट करनेवाले होते हैं।

दूसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्तव्य— पहले सब गवर्नरों के प्रान्तों में एक-एक ही व्यवस्थापक सभा थी; श्रव सन् १९३५ ई० के विधान के श्रनुसार एक-दो नहीं, श्राधे दर्जन प्रान्तों में दूसरी सभा [सैकंड चेम्बर] का श्रायोजन किया गया है। केन्द्र में दूसरी सभा [श्रर्थात् राज्य-परिषद] होने से क्या हानि है, यह पहले बताया जा चुका है। प्रान्तों में दूसरी सभा की व्यवस्था उससे भी श्रधिक हानिकर है। व्यवस्थापक मंडल के अधिकार—प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्था-पक मंडल को तीन प्रकार के कार्य करने का अधिकार है—

- (१) शासन-कार्य की जाँच के लिए आवश्यक प्रश्न पूछ्ना और प्रस्ताव करना।
  - (२) क्रानून बनाना।
  - (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना।

इनके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा, और यह भी बताया जायगा कि वर्तभान विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के अधिकार कहाँ तक सीमित हैं, उनमें क्या-क्या प्रतिबन्ध या रकावटें हैं। पहले व्यवस्थापक मंडलों के अधिवेशनों तथा कार्य-पद्धित आदि के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य नियम जान लेना उपयोगी होगा।

व्यवस्थापक मएडल का अधिवेशन—प्रत्येक प्रान्तीय व्य-वस्थापक मएडल की सभा या सभाओं का, प्रतिवर्ष कम-से-कम एक अधिवेशन होने का, और किसी अधिवेशन की अन्तिम बैठक के दिन से एक वर्ष के भीतर दूसरा अधिवेशन होने का, नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए, गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर कर सकता है जिसे वह उचित समके। वह सभाओं का कार्य-काल बढा सकता है और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा ( एसेम्बली ) को भंग कर सकता है।

सभापति श्रोर उप-सभापति—संगठित होने के पश्चात्, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा यथा-सम्भव शीव्र अपने सदस्यों में से एक सभापित और एक उप-सभापित चुनती है। इन्हें क्रमशः 'स्वीकर' श्रीर 'डिप्टी-स्वीकर' कहा जाता है। जब ये व्यवस्थापक सभा के सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है। ये गवर्नर को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, और व्यवस्थापक सभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास किये हुए प्रस्ताव द्वारा अपने पद से इटाये जा सकते हैं। हाँ, ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित करने को सूचना चौदह दिन पहले दी जानी चाहिए।

जब स्वीकर का पद रिक्त हो तो डिप्टो-स्वीकर, श्रौर, उसका भी पद रिक्त होने की दशा में, गवर्नर द्वारा नियुक्त किया हुश्रा सदस्य इस पद का कार्य-सम्पादन करता है। स्वोकर श्रौर डिप्टो-स्वीकर को आन्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है; श्रौर जब तक मंडल द्वारा निर्धारित न हो, उन्हें गवर्नर द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है।

व्यवस्थापक सभा की तरह व्यवस्थापक परिषद् भी श्रपना सभा-पित श्रीर उप-सभापित चुनती है; ये 'प्रेसीडेंट' श्रीर 'डिप्टो प्रेसीडेंट' कहलाते हैं।

सभाश्रों में मत-प्रदान इन समाश्रों में से प्रत्येक की बैठक एवं दोनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के श्रनुसार होता है। मंत्री उस समा में मत दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य हों। समापित या उनके स्थान पर कार्य करनेवाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का श्रिषकार नहीं होता; हाँ, जब किसी प्रश्न के पच्च श्रीर विपच्च में समान मत हों, तो उपर्युक्त

पदाधिकारी को अपना निर्णायक मत देना होता है।

ये सभाएँ अपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा में भी, अपना कार्य कर सकती हैं। इनकी कार्रवाई उस दशा में भी नियम्ति मानी जाती हैं जब कि पीछे यह जात हो जाय कि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठा है और उसने इनमें भाग लिया है, जो ऐसा करने का अधिकारी नहीं था। अगर किसी समय प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की मीटिंग में कुल सदस्यों के छठे भाग से कम, या परिषद् की मीटिंग में दस मेम्बरों से कम उपस्थित हों तो सभापति या उसके स्थान पर कार्य करनेवाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह सभा की कार्रवाई को उस समय तक स्थगित कर दे जब तक कि उनकी स्तर लिखी कमी दूर न हो जाय।

सदस्यों सम्बन्धी नियम प्रत्येक सभा का हर एक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व गवर्नर के सामने राजभक्ति की रापय लेता है। कोई सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता। अगर किसी सभा का सदस्य सभा की अनुमित बिना, साठ दिन तक सभा की सब बैठकों में अनुपिस्थित रहे तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। इन साठ दिनों में वे दिन नहीं गिने जाते, जो दो अधिवेशनों के बीच में हों, या जिनमें लगातार चार से अधिक दिन तक कार्य स्थागत रहा हो।

श्रंगरेज़ी भाषा का प्रयोग — प्रान्तीय व्यवस्थापक मगडल की सब कार्रवाई श्रंगरेज़ी भाषा में होने का नियम है, परन्तु प्रत्येक सभा की कार्य-पद्धति श्रीर संयुक्त बैठक सम्बन्धी नियमों में, इस बात की व्यवस्था रहती है कि श्रंगरेज़ी भाषा न जाननेवाले या उसे अपर्याप्त रूप से जाननेवाले व्यक्ति श्रन्य भाषा का प्रयोग कर सर्के।

विधान के इस नियम की ब्याख्या के सम्बन्ध में ब्यवस्थापक सभाशों में काफ़ी मत-भेद रहा है। संयुक्तप्रान्त के स्वीकर ने श्रंगरेज़ी बाननेवाले सदस्यों को भी हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा में बोखने की श्रजुमित दी। इससे श्रोताश्रों को निस्सन्देह बहुत सुविधा हो गयी।

व्यवस्थापक मएडल की कार्य-पद्धित— व्यवस्थापक मंडलों की कार्य-प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं। हम यहाँ उनमें से कुछ ख़ास-ख़ास का ही उल्लेख कर सकते हैं। सभा-भवनों में चारों श्रोर बरामदों (गैलिरियों) में कुछ दर्शक भी उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक दर्शक को पहले एक 'पास' लेना होता है। 'पास' श्रपनी पहचान के किसी सदस्य द्वारा लिया जा सकता है। वह जिस व्यक्ति के लिए होता है, वही उसका उपयोग कर सकता है। वह दूसरे व्यक्ति के काम नहीं श्रा सकता। सभा-भवन में सदस्यों के बैठने के स्थान एक ख़ास दक्त से निश्चित किये जाते हैं, जिसमें सरकारी पक्ष तथा विपक्ष के, एवं भिन्न-भिन्न दलों के मत गिनने में यथा-सम्भव सुविधा हो। भवन में श्रध्यक्ष, सदस्यों, मन्त्रियों, एडवोनेट-जनग्ल श्रोर सेकेटरियों के श्रातिरिक्त कुछ समाचार पन्नों के संवाददाताश्रों के भी बैठने की व्यवस्था रहती है।

साधारणतया दैनिक कार्य-क्रम में पहली बात प्रश्नोत्तरों की होती है। यह कार्य थोड़ी ही देर का होता है। इसके बाद क़ान्नों के मस-विदों या प्रस्तावों पर विचार होता है। गवर्नर को अधिकार है कि ग्रैर-सरकारी कार्य के लिए समय और क्रम निश्चय करे। स्मापित को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे जाने की अनुमित, इस आधार पर देने से इनकार कर दे कि इसका प्रान्तीय सरकार से विशेष सम्बन्ध नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मण्डल की किसी सभा में विचार नहीं हो सकता; उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर को है। सार्वजनिक महत्व के किसी ख़ास विषय की बहस करने के लिए परिषद् के अधिवेशन को स्थिगत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। समापित को अधिकार है कि वह किसी सदस्य के भाषण में पुनविक या अप्रांसिंगक विषय का उल्लेख करे, और उसको बोलने से रोके।

सदस्य जब स्पीकर अथवा मंत्री-मंडल के किसी कार्य का विरोध करना चाहते हैं तो वे सामृहिक रूप में सभा भवन से बाहर चले आते हैं। इसे 'वाक आउट' कहते हैं।

कार्य-पद्धित के नियमों का निर्माण—शासन विधान के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा अपनी कार्य-पद्धित के नियम बना सकती है। परन्तु कुछ विषयों के नियम गवर्नर उस सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकता है।

जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो, उसमें गवनर दोनों सभाश्रों के संयुक्त श्रिविशन तथा पारस्परिक विचार-विनिमय के नियम उनके सभापतियों का परामर्श लेकर बनाता है। संयुक्त श्रिविशन में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद का श्राध्यक्ष सभापित होता है उसकी श्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद का श्राध्यक्ष सभापित होता है उसकी

पद्धति के नियमों के अनुसार निश्चित हो।

संयुक्तप्रान्त में वह न्यवस्था की गयी है कि संयुक्त श्रिष्विशन में विश्वयनस्थापक परिषद का सभापति (प्रेसीडेन्ट) उपस्थित न होने की दिशा में न्यवस्थापक सभा का सभापति श्र्यांत् स्पीकर, श्रीर स्पीकर की श्रिष्ठा में डिप्टो-प्रेसीडेंट एवं डिप्टी प्रेसीडेन्ट की श्रिष्ठा में डिप्टो-प्रेसीडेंट एवं डिप्टी प्रेसीडेन्ट की श्रिष्ठात न हो तो संयुक्त श्रिष्ठवेशन द्वारा निर्वाचित सदस्य सभापति बने । दोनों सभागों के ४८ सदस्य होने पर 'कारम' पूरा होगा । संयुक्त श्रिष्ठवेशन में उस प्रस्ताव के श्रितिरिक्त, जिसके विचारार्थ श्रिवेशन किया गया है, श्रम्य किसी विषय पर विचार न होगा ।

प्रश्न श्रोर प्रस्ताव—शासन कार्य की जांच के लिए नियं क्या स्थापक मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने श्रीर प्रस्ताव करने का विश्वा ही श्रिषकार है, जैसा हम भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में बता श्राये हैं। प्रश्न पूछ कर सरकार का ध्यान जनता की शिका- यतों की श्रोर श्राकर्षित किया जाता है, श्रीर महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला जाता है।

मंडल में किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपस्थित किये जाने से रोकने का अधिकार उस प्रान्त के गवर्नर को होता है।

प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं:—(१) साधारण नीति के प्रस्ताव पास करके सरकार को निर्धारित कार्य करने का आदेश जिंकया जाता है। (२) सार्वजनिक महत्व के विषय की बहस के लिए

कार्रवाई स्थगित करने का अर्थात् 'काम-रोको' प्रस्ताव किया जाता-है। इसका श्राशय यह होता है कि सरकार पर विश्वास नहीं है। यह प्रस्ताव उसी दिन चार बजे श्रान्य कार्यवाही बन्द करके ले लिया जाता है। कैंभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव के बाद-विवाद के बीच में ही सभा की बैठक का समय समाप्त हो जाता है श्रीर प्रस्ताव पर मत लिये जाने का अवसर नहीं आता। इस प्रकार निर्णय न होने की दशा में प्रस्ताव को 'चर्चा में ही गया' ( 'टाक्ड ब्राउट' ) कहते हैं (३) सरकारी नीति से असन्तोष प्रकट करने के लिए मंत्री-मंडल के प्रति श्रविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव किया जाता है। सभापति किसी सदस्य को इस प्रकार प्रस्ताव करने की अनुमति उस समय देता है जब सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर अनुमति देने के पक्ष में होना स्चित करदे । सदस्यों की यह संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक-पृथक् निर्धारत है। इस प्रस्ताव पर 'स्पीकर' द्वारा निश्चित किये हुए दिन विचार होता है। दूसरे और तीसरे प्रकार के प्रस्तावों में से किसी के पास हो जाने पर, उत्तरदायी शासन-पद्धति में, मंत्री-मंडल को त्याग-पत्र देना होता है। स्पीकर के प्रति भी श्रविश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकताहै।

पान्तीय व्यवस्थापक मगडल के कानूनों का क्षेत्र— नवीन विधान के अनुसार व्यवस्था सम्बन्धी विषय तीन सूचियों में विभक्त किये गये हैं:—(क) संघीय सूची, (ख) सम्मिलित सूची और (ग) प्रान्तीय सूची । जिन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्था पक मंडल क़ानून बना सकता है, वे संदोप में निम्नलिखित हैं:—

१-सार्वजनिक शान्ति िसेना छोड़कर ], श्रदालतों का संगढन अभौर फ़ीस [संध-न्यायालय छोड़कर] (२) पुलिस, (३) जेल, (४) प्रान्त का सरकारी ऋण, (५) कुछ प्रान्तीय सरकारी नौकरिया, नौकरी-कमीशन. (६) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना, (७) प्रान्तीय च्यवस्थापक मंडल का चुनाव, (८) प्रान्तीय मन्त्रियों तथा व्यवस्थापक सभाश्रों श्रोर परिषदों के सभापति, उपसभापति और सदस्यों का वेतन श्रीर भत्ता, (९) स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ, (१०) सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रीर स्प्राई; श्रस्पताल, जन्म श्रीर मृत्यु का खेखा, (११) शिक्षा, (१२) सड़कें पुल, घाट और आवागमन के अन्य साधन विड़ी रेलों को छोड़कर ], (१३) जल-प्रबन्ध, आवपाशी, नहर, बाँध तालाब श्रौर जल से उत्पन्न होनेवाली शक्ति, (१४) कृषि. कृषि-शिक्षा श्रौर श्रनुसन्घान, पशु-चिकित्सा तथा कांजी-हाउस, (१५) भूमि, मालगुज़ारी श्रौर किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध, (१६) जंगल, (१७) खान, तेल के कुओं का नियन्त्रण और उन्नति (१८) गैस और गैस के कारख़ाने, (१९) प्रान्त के अन्दर का न्यापार, चाणिज्य, मेले-तमाशे, साहुकारी श्रीर साहुकार। (२०) उद्योग-धन्धी की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण (२१) खाद्य पदार्थी न्त्रादि में मिलावट; तोल और नाप, (२२) शराब और अन्य मादक वस्तुश्रो सम्बन्धी ऋय-विक्रय, श्रार ब्यापार श्रिफीम की उत्पत्ति छोड़ कर ], (२३) दान श्रीर दान देनेवाली संस्थाएँ (२४) नाटक, थियेटर श्रीर छिनेमा, (२५) जुश्रा श्रीर छट्टा, (२६) प्रान्तीय विषयों-सम्बन्धी कर।

इन विषयों के श्रांतिरिक्त कुछ श्रन्य विषयों के सम्बन्ध में भी प्रान्तीय ब्यवस्थापक मंडल क़ानून बना सकता है; परन्तु केवल उसी दशा में जब कि संघीय ब्यवस्थापक मंडल न बनाये। इन्हें सम्मिलित विषय कहते हैं। प्रांतीय तथा केन्द्रीय ब्यवस्थापक मंडल के बनाये, किसी विषय के क़ानून में परस्पर विरोध हो तो केन्द्रीय ब्यवस्थापक मंडल का बनाया क़ानून ठीक समभा जायगा।

· कानून कैसे बनते हैं — किसी कानून का मसविदा ब्यवस्थापक समा में, श्रौर जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हैं किसी भी सभा में, उसके सदस्य द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। मसविदा किसी ऐसे विषय के ही सम्बन्ध में हो सकता है, जो प्रान्तीय व्यवस्थापकः मंडल के श्राधकार के श्रान्दर हो। सरकारी मसविदा सरकार के उस सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है जो मसविदे के विषय का श्रवि-कार रखता हो। जब कोई गुर-सरकारी सदस्य कोई मसविदा उपस्थित करना चाहता है, तो उसे अपने इस विचार की सूचना पहले देनी होती है। जब कोई मसविदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो वह प्राय: एक विशेष कमेटी में मेजा जाता है। इस कमेटी का चेयरमैन वह सरकारी सदस्य होता है, जो इस विषय का अधिकार रखता हो। उसकी रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक सदस्य हो। पश्चात् मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर पृथक्-पृथक् विचार किया जाता है । सर्व-सम्मति या बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर मसिवदा उस सभा में पास हुआ कहा जाता है। यदि उस प्रांत में दूसरी ब्यवस्थापक सभा हो तो उपर्युक्त सभा में पास हुआ

मसिवदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। अब यदि वह इस सभा में भी उसी रूप में पास हो जाता है या ऐसे संशोधनों सिहत पास हो जाता है, जिन्हें पहली सभा स्वीकार कर ले, तो वह मसिवदा दोनों सभाश्रों अर्थात् व्यवस्थापक मएडल में पास हुआ कहा जाता है।

यदि कोई मसिवदा जो व्यवस्थापक सभा में पास हो गया है, श्रीर व्यवस्थापक परिषद् में भेज दिया गया है, परिषद में श्राने के बारह महीने समाप्त होने से पूर्व गवर्नर की स्वीकृति के लिए न मेजा जाय तो गवर्नर उस पर विचार करने श्रीर मत लेने के लिए दोनों सभाश्रों की संयुक्त बैठक करा सकता है। यदि गवर्नर को यह प्रतीत हो कि मसिवदा श्रर्थ-सम्बन्धी है, श्रयवा ऐसे विषय-सम्बन्धी है, जिसका प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा, जिनके विषय में उसे श्रपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना है, तो वह बारह महीने से पूर्व भी समाश्रों की संयुक्त बैठक करा सकता है। यदि दोनों समाश्रों की संयुक्त बैठक में मसिवदा (यदि कोई संशोधन दोनों समाश्रों द्वारा स्वीकृत हो तो उसके सहित) दोनों समाश्रों के उपस्थित, श्रीर मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत से पास हो जाय तो वह दोनों समाश्रों में (पृथक्-पृथक्) पास हुशा समक्ता जाता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा द्वारा, या जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परि-षद भी है, दोनों सभाश्रों द्वारा पास किया हुन्ना मसविदा गवर्नर के सामने रखा जाता है। गवर्नर को यह श्रिषकार है कि वह अपने विवेक से उसको सम्राट् की श्रोर से स्वीकार करे, या अपनी स्वी-कृति को रोक ले, या उसे गवर्नर-जनरल के विचारार्थ रख छोड़े। गवर्नर को वह भी अधिकार है कि यह मसिवदे को इस संदेश-सिहत लौटा दे कि सभा या सभाएँ मसिवदे या उसके किन्हीं अंशों पर पुन: विचार करें; विशेषतया उसके द्वारा सूचित संशोधन को उपस्थित करने का विचार करें। इस पर सभा या सभाओं को उस मसिवदे के सम्बन्ध में पुन: विचार करना पड़ता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा पास किया हुआ मसविदा जब उसे गवर्नर स्वीकार कर ले, श्रीर सम्राट् श्रस्वीकार न करें, श्रथवा यदि गवर्नर उसे गवर्नर-जनरल या सम्राट् की स्वीकृति के लिए रख छोड़े तो क्रमशः इनकी स्वीकृति मिलने पर, क़ानून बन जाता है।

च्यवस्थापक सभा भंग होने और श्रिधवेशन स्थिगत होने में जो अन्तर है वह समक्त लेना चाहिए। व्यवस्थापक सभा भंग होने पर उसका नया चुनाव होता है। श्रिधवेशन गवर्नर भंग करता है और वही भंग होने पर उसे फिर खुला सकता है। श्रिधवेशन स्थिगत करने का कार्य स्पीकर (सभापति) करता है और श्रिधवेशन स्थिगत होने पर स्पीकर उसे फिर खुला सकता है।

प्रान्तोय व्यवस्थापक मएडल के अधिकारों की सीमा — गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना प्रान्तीय व्यवस्थापक मएडल की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता—

(क) जो पालिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धी किसी क़ानून को -रइ (रिपील) या संशोधित करता हो, या जो उससे श्रसंगत हो।

- (ख) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो जो गवर्नर-जनरल को, नवीन विधान के श्रनुसार, श्रपने विवेक से करना हो।
- (ग) जो योरिपयन ब्रिटिश प्रजा-सम्बन्धी फीज़दारी कार्य-पद्धित पर प्रभाव डालता हो ।

गवर्नर की पूर्व स्वीकृति विना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उप-स्थित नहीं किया जा सकता:—(१) जो गवर्नर के किसी क्रानून या श्राहिनेन्स को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, श्रथवा (२) जो पुलिस-सम्बन्धी किसी क्रानून के प्रस्ताव को रद्द या संशोधित करता हो, या उस पर श्रसर डालता हो।

प्रांतीय व्यवस्थापक मडंल को ऐसा क्वानुन बनाने का श्रिषकार नहीं है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के लिए पार्लिमेंट के क्वानुन बनाने के श्रिषकार पर पड़े या जिसका सम्बन्ध सम्राट्या उसके परिवार से, सम्राट् के भारत के प्रभुत्व से, सपरिषद सम्राट्की श्राज्ञाश्रों से, या भारत-मन्त्री के नवीन विधान के श्रनुसार बनाये हुए नियमों से, या गवर्नर या गवर्नर-जनरल के बनाये हुए नियमों से हो; या जिससे सम्राट् के किसी न्यायालय में श्रपील करने की श्रनुमित देने के विशेषाधिकार में कमी पड़े।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मराइल में संघीय न्यायालय, या हाईकोर्ट के किसी जज के अपने कर्तव्य को पालन करने के समय के व्यवहार पर वादानुवाद नहीं हो सकता । अगर गवर्नर अपने विवेक से यह

तसदीक कर दे कि किसी क़ानून के मसिवदे, उसके श्रंश या संशोधन से, उसके शान्ति-रक्षा-सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व पर श्रसर पड़ता है तो वह इस विषय का श्रादेश करके उस मसिवदे श्रादि के सम्बन्ध में होनेवाली करिवाई को रोक सकता है।

गवर्नर के श्रिधिकार, भाषण श्रीर सन्देश—गवर्नर श्रिपने विवेक से व्यवस्थापक सभा में, श्रीर यदि उसके प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाश्रों के संयुक्त श्रिपने में, भाषण कर सकता है। वह दोनों में से प्रत्येक सभा में, किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रिपना सन्देश भेज सकता है, चाहे वह मण्डल के सामने उस समय विचाराधीन हो या न हो । जिस सभा में कोई सन्देश भेजा जायगा, वह यथा-सम्भव शीधता-पूर्वक सन्देश में स्चित विषय का विचार करेगी।

गवर्नर के आदिनेन्स—गवर्नर को आर्डिनेन्स अर्थात् अस्थायी कातून बनाने का अधिकार है। यह अधिकार (१) व्यवस्थापक मंडल के अवकाश के समय होता है और (२) उसके कार्य-काल में भी। जब किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मण्डल का कार्य-काल न हो, यदि गवर्नर को निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अपनी सम्मति के अनुसार आवश्यक आर्डिनेन्स बना सकता है। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल के कार्य-काल में भी गवर्नर जब वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक समक्ते, निर्धारित काल के लिए वैसा ही क़ानून बना सकता है जैसा कि मण्डल। निदान, उसको कुछ विषयों में मण्डल के समान अधिकार भाप्त हैं त्रौर वह मएडल की इच्छा के विरुद्ध भी उनका अस्थायी रूप से प्रयोग कर सकता है।

गवर्नर के कानून—यही नहीं; कुछ दशाश्रों में वह स्थायी रूप से भी कानून बना सकता है। इस प्रसंग में विधान में यह नियम है कि यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि उसके उत्तरदायित्व को पालन करने के लिए उसके विवेक से काम करने या उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के सम्बन्ध में कानून से व्यवस्था होनी चाहिए तो वह सन्देश मेजकर सभा या सभाश्रों को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करायेगा, श्रीर वह या तो 'गवर्नर का कानून' बना देगा या श्रपने सन्देश के साथ प्रस्ताव का मसविदा लगा देगा। दूसरी दशा में वह एक मास के बाद 'गवर्नर का कानून' बना देगा, जो या तो उसी रूप में होगा जैसा कि उसने सभा या सभाश्रों में मसविदा भेजा था, या उसमें उसके विवेक के श्रनुसर श्रावश्यक संशोधन होंगे। हाँ, ऐसा करने से पूर्व यदि किसी सभा की श्रोर से उस प्रस्ताव या संशोधन-सम्बन्धी कोई निवेदन-पत्र दिया जाय तो वह उस पर विचार करेगा।

गवर्नरों को ऋार्डिनेन्स जारी करने या क्यानून बनाने का श्रिधकार नवीन शासन-विधान से ही मिला है; फिर भी कुछ ब्रिटिश ऋधिकारियों का यह दावा है कि यह विधान प्रान्तों में स्वराज्य स्थापित करने वाला है।

पृथक् या अंशतः पृथक् क्षेत्रों की व्यवस्था—इन चेत्रों के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका है। प्रान्तीय (या केन्द्रीय) व्यवस्थापक मराडल का कोई क्रानून या उसका कोई भाग इन पर उस समय तक लागू नहीं होता जब तक कि गवर्नर सार्वजनिक स्चना द्वारा ऐसी हिदायत न करे। गवर्नर इन चेत्रों के लिए नियम बना सकता है, श्रीर, उसके नियम उन संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक मराडल के या श्रन्य भारतीय क्रानूनों को रह या संशोधित कर सकते हैं जो इन चेत्रों-सम्बन्धी हों। ये नियम गवर्नर-जनरल के सामने उपस्थित किये जाते हैं, श्रीर उसकी स्वीकृति होने तक, इन पर कोई श्रमल नहीं होता।

श्राय-व्यय सम्बन्धी कार्य-पद्धृति—गवर्नर प्रति वर्षे प्रान्तीय व्यवस्थापक मएडल की सभा या दोनों सभाश्रों के सामने उस वर्ष के श्रानुमानिक श्राय-व्यय का नक्षा उपस्थित कराता है। उसमें दो प्रकार की महों की रक्षमें पृथक् पृथक् दिखायी जाती हैं, (१) जो पूर्व निश्चित है, जिन पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता, श्रोर (२) जिन पर मत लिया जाता है। कर-निर्धारण तथा व्यय के लिए माँग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक परिषद का मत नहीं लिया जाता।

व्यय की निम्नलिखित मद्दों पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा को मत देने का अधिकार नद्दीं है:—

- (क) गवर्नर का वेतन श्रीर भत्ता तथा उसके कार्यालय-सम्बन्धी निर्धारित व्यय।
  - ( ल ) प्रान्तीय ऋगु-सम्बन्धी व्यय, सूद आदि ।
  - (ग) मंत्रियों और ऐडवोकेट जनरल का वेतन श्रौर भत्ता।

- ( व ) हाईकोर्ट के जजों का वेतन श्रीर भत्ता।
- (च) पृथक् चेत्रों के शासन-सम्बन्धी व्यय।
- ( छ ) श्रदालती निर्णयों के श्रनुसार होने वाला व्यय।
- (ज) श्रन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के क्वानून के श्रनुसार किया जाना श्रावश्यक हो। इसके श्रन्तर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन श्रीर मत्ते भी सम्मिलित हैं, जो भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे इण्डियन सिविल सर्विस या इण्डियन पुलिस सर्विस श्रादि के कर्मचारी।

कोई प्रस्तावित व्यय उक्त महों में से किसी में श्राता है या नहीं, इसका निर्णय गवनर श्रापने विवेक से करता है। (क) को छोड़ कर श्रान्य महों पर व्यवस्थापक मंडल में वादानुवाद हो सकता है। उप-र्युक्त (क) से (ज) तक की महों को छोड़कर श्रान्य विषयों के ख़र्च के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत के लिए माँग के रूप में रखे जाते हैं। इस सभा को श्राधिकार है कि यह किसी माँग को स्वीकार करे, श्रास्वीकार करे, या उसे कुछ घटाकर स्वीकार करे।

गवर्नर की सिफ़ारिश के बिना किसी काम के लिए रुपये की माँग का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। यदि सभा व्यय-सम्बन्धी कोई माँग स्वीकार न करे या घटाकर स्वीकार करे, और इससे गवर्नर की सम्मित में उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने में बाधा उपस्थित हो तो वह श्रपने विशेषाधिकार से, रह की हुई या घटायी हुई माँग की, पूर्ति कर सकता है।

सारांश यह है कि गवर्नर की इच्छा बिना, मंत्री-मंडल या व्य-वस्थापक सभा किसी कार्य के लिए खर्च स्वीकार नहीं कर सकती। बजट-अधिवेशन—व्यवस्थापक मंडल की एक मुख्य बैठक फरवरी के अन्त और मार्च के आरम्भ में होती है। इसमें आगामी वर्ष के प्रान्तीय आय-व्यय का अनुमान-पत्र उपस्थित किया जाता है; वैसे वास्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के पास १५ दिन पहले मेज दिया जाता है। सदस्य भिन्न-भिन्न ख़र्चों का विचार करते हैं और यदि उन्हें किसी ख़र्च में कुछ कटौती की सूचना देनी हो तो वे सभा में बजट उपस्थित किये जाने से तीन दिन पहले उस सूचना को सेकटरी के पास भेज देते हैं। यदि किसी ख़ास मद में ख़र्च की कमी न करते हुए केवल उस विभाग की कार्य-प्रणाली की आलोचना या शिकायत करनी हो, तो उस मद में कटौती-करके एक रुपये की स्वी-कृति सूचित की जाती है। इससे उस कटौती-सम्बन्धी चर्चा के प्रसंग में, सदस्य उस विभाग के विषय में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं।

बजट काफ़ी बड़ा होता है, वह सभा में पढ़ा नहीं जाता। उसे उपस्थित करते समय अर्थ-मत्री उसके सम्बन्ध में अपना भाषण करता है। पश्चात् (अगले दिन) उस बजट पर चर्चा होती है, इसमें सदस्य कुल बजट पर अपने साधारण विचार प्रकट करते हैं। इसके बाद एक इपते तक भिन्न-भिन्न महों की, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत, कटौ-तियों की चर्चा होती है। पहले किसी विभाग की नीति की आलोचना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुई कटौतियों पर विचार होता है। पश्चात् अन्य कटौतियों का विचार होकर एक-एक मह के ख़र्च की मांग की जाती है। बजट को बहस के लिए निश्चित किये हुए सप्ताह के अन्तिम दिन, पांच बजे कटौतियों की समाप्ति ('गिलोटिन') हो

जाती है; इसके बाद किसी कटौती पर बहस नहीं होती। सदस्य के आग्रह करने पर कटौती की रक्तम पर मत लिये जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय तो उस मद्द की रक्तम को, उसमें आवश्यक कमी करके, मंज़ूर किया जाता है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ी देर में ही नियटा लिया जाता है।

विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवाले नियम; गवर्नर की घोषणा—यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थित में प्रांतीय शासन का कार्य इस विधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो वह घोषणा निकाल कर सूचित कर सकता है कि (क) अमुक कार्य वह स्वयं अपने विवेक से करेगा, या (ख) प्रांतीय संस्था या अधिकारियों के सब या कुछ अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा। इस घोषणा में इसे व्यवहृत करने के उपयोगी आवश्यक नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। हाँ, गवर्नर हाईकोर्ट के अधिकार नहीं ले सकता और न इस न्यायालय-सम्बन्धी विधान की किसी धारा को स्थिगत कर सकता है।

गवर्नर किसी भी समय अपनी उपर्युक्त घोषणा में परिवर्तन कर सकता है तथा उसे मन्स्ख़ भी कर सकता है।

ऐसी घोषणा की सूचना तत्काल भारत-मंत्री को दी जायगी, और उसके द्वारा पार्लिमेंट की दोनों सनाभ्रों के सामने रखी जायगी।

गवर्नर इस प्रकार की घोषणा तब तक नहीं निकालेगा, जब तक

कि गवर्नर-जनरल इसमें सहमत न हो जाय। ऋौर इस विषय में गवर्नर ऋौर गवर्नर-जनरल दोनों ऋपने विवेक से कार्य करेंगे।

श्रारम्भ में ऐसी घोषणा छु: माइ के लिए जारी होगी। परन्तु अगर इस घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव पार्लिमेंट की दोनों सभाश्रों से स्वीकार हो जाय (या होता रहे), तो यह घोषणा, मंसूख न किये जाने की दशा में, श्रपनी श्रविध के पश्चात् बारह मास तक बारी रहेगी। परन्तु ऐसी कोई घोषणा तीन साल से श्रिधक व्यवहृत न होगी।

श्रगर गवर्नर घोषणा द्वारा, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के क्वानून, बनाने का श्रिषकार प्रहण कर ले, तो उसका बनाया हुश्रा क्वानून, श्रोषणा का प्रभाव समाप्त होने के दो साल बाद तक जारी रहेगा, सिवाय उस दशा के, जब कि उसे कोई श्रिषकार-प्राप्त व्यवस्थापक संस्था नियमानुसार दो साल से पूर्व संशोधित कर दे।

विशेष वक्तव्य — यद्यपि प्रजातन्त्राश्मक देशों की शासन-पद्धति के अनुसार ही यहाँ मंत्री-मंडल की व्यवस्था की गयी है, तथापि इस आधार पर जो शासन-भवन निर्माण किया गया है, वह प्रजातन्त्रात्मक न होकर बहुत कुछ स्वेच्छाचार-मूलक है। गवर्नर के विशेष उत्तर-दायित्वों और विशेषाधिकारों का श्रायोजन करके, उन्हें प्रान्तीय श्राय के श्रधिकांश भाग को स्वयं ख़र्च करने का श्रधिकार देकर, मंत्रियों को कितने ही महत्व-पूर्ण श्रधिकारों से वंचित करके, एवं छः प्रान्तों में दो-दो व्यवस्थापक सभाओं की स्थापना करके, प्रान्तीय स्वराज्य का मानों उपहास किया गया है।

यहाँ गवर्नर प्रायः सर्वे-सर्वा बना दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि अनेक स्वतंत्र राज्यों में भी किसी-न-किसी के हाथ में ऐसे अधिकार रहते हैं, जिनसे विशेष परिस्थित में देश को राजनैतिक संकट से बचाया जा सके। परन्तु स्मरण् रहे कि वहाँ विशेषाधिकारों का प्रयोग बहुत ही कम और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। भारतवर्ष में, गतवर्षों में इसके विपरीत यह अनुभव में आया है कि अधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारण् परिस्थिति में भी करते हैं। पुनः स्वतंत्र देशों में जिन व्यक्तियों के हाथ में विशेषाधिकार रहते हैं, वे जनता के विश्वास—पात्र होते हैं। उनका, और उन देशों के जन-साधारण् का, हित परस्पर-विरोधी न होकर एक ही होता है। इसलिए यहाँ प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कार्य-चेत्र में गवर्नर को व्यापक और स्वेच्छाचार-मूलक विशेषाधिकारों से सम्पन्न करना, उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-प्रणाली के मूल पर कुठाराधात करना है। नवीन शासन-विधान की यह बात अत्यन्त चिन्तनीय है।



# अड़तीसवाँ परिच्छेद

### स्थानीय स्वराज्य

जिर्निता को श्राने-श्राने स्थानों श्रार्थात् शहरों श्रीर देहातों का प्रबन्ध या सुधार करने के श्राधिकार होने को स्थानीय स्वराज्य कहते : हैं। इन श्राधिकारों का उपयोग करने के लिए बनायी हुई संस्थाएँ स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ कहलाती हैं।

प्राचीन व्यवस्था — प्राचीन समय में यहाँ विरकाल तक स्थानीय कार्य गाँवों में ग्राम्य संस्थाओं श्रीर नगरों में व्यागर-संघों श्रादि द्वारा होता रहा। भारतवर्ष की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रहीं हैं। प्रत्येक गाँव या नगर स्वावलम्बी होता था; पंचायत उसकी रक्षार्थ पुलिस रखती थी, छोटे मोटे भगड़ों का निपटारा करती थी, भूमि-कर वस्ल करके राज-कोष में भेजती थी, तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सड़क

आदि सार्वजनिक उपयोगिता के कामों की व्यवस्था करती थी। राज-वंश बदलें, क्रान्तियाँ हुईं, बारी-बारी से हिन्दू (क्षत्रिय राजपूत), पठान, मुगल, मराठों श्रीर सिक्खों का प्रमुख हुआ। परन्तु सब विन्न बाधाश्रों का सामना करते हुए भी ग्राम-संस्थाश्रों ने अपना श्रस्तित्व श्रीर श्रापनी स्वतन्त्रता बनाये रखी।

श्राधुनिक स्थिति — श्रंगरेजी शासन के प्रारम्भिक समय में आम संस्थाओं की आय और श्रधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा ले लिये जाने पर आम-संगठन का कमशः हास हो गया। यद्यपि श्रव मी पंचायती मन्दिर और धर्मशाला आदि बनते हैं, ये प्राचीन व्यवस्था के स्मृति-चिन्ह-मात्र हैं। श्रव पुनः नवीन रूप से पंचायतें स्थापित की जा रही हैं। इसका विवेचन श्रागे किया जायगा।

श्रॅगरेज़ श्रिषकारियों ने पहले नगरों या शहरों की श्रोर ध्यान दिया श्रोर छन् १८४२ ई० से कुछ स्थानों में क्रमशः म्युनिसपैलिटियाँ स्थापित कों। इसके दो उद्देश्य थे। नगरों का सुधार होना, श्रोर जनसाधारण को सार्वजनिक कार्य करने की न्यावहारिक शिक्षा मिलना। इन संस्थाश्रों की कुछ वास्तविक उन्नति सन् १८७० ई० से (लाई मेयो के समय से) हुई। सन् १८८४ ई० में लार्ड रिपन ने इनके श्रिष्ट कार बढ़ाये, तब से इनका प्रचार बढ़ा है। तथापि पैंतीस वर्ष तक उन्नति की गति बहुत ही मन्द रही। सन् १९१८ ई० में सरकारी मन्तव्य प्रकाशित हुआ, उसमें म्युनिसपैजिटियों में निर्वाचित सदस्यों श्रोर निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने तथा ग्रैर-सरकारी समापतियों के इं।ने, उनके श्रिषकार बढ़ाने, श्रीर ग्राम-पंचायतें स्थापित करने, पर

को इस्तान्तरित विषय कर दिया, श्रर्थात् इसे उत्तरदायी मन्त्रियों को स्थानितरित विषय कर दिया, श्रर्थात् इसे उत्तरदायी मन्त्रियों को सौंप दिया। इससे इन संस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इन पर सरकारी नियंत्रिया कम हो गया तथा इनके श्रिष्टिकार बढ़ गये। सन् १९३५ ई० के शासन-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शिक्त की श्रीर भी वृद्धि हुई।

स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ — भारतवर्ष की वर्तमान स्वराज्य-संस्थाओं के निम्नलिखित भेद हैं:—

- (१) पंचायतें
- (२) बोर्ड
- (३) म्युनिसपैलटियाँ, कारपोरेशन, नोटीफ़ाइड एरिया
- (४) इम्प्रूवमैंट द्रस्ट और पोर्ट-द्रस्ट।

पंचायतें — इनमें चार-पाँच या अधिक नामज़द सदस्य तथा एक सरपंच होता है। इन्हें छोटे-मोटे दीवानी तथा फ़ौजदारी मामलों का फैसला करने का अधिकार होता है। इनमें पेश होनेवाले मुकदमों में किसी पक्ष का कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता, अन्य ख़र्च भी कम पड़ता है। पंचायतों को गाँव में सफ़ाई के, और आवारा फिरकर नुकसान पहुँचानेवाले मवेशियों को रोक रखने के, सम्बन्ध में कुछ अधिकार होता है। पंचायतें साधारण अपराध करनेवालों पर कुछ अर्माना कर सकती हैं और मुकदमा लड़नेवालों (वादी प्रतिवादी) से फीस ले सकती है। इन्हें ज़िला-बोर्ड या सरकार से कुछ रक्षम मिलती है। इसके अतिरिक्त यह निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने

चित्र के आदिमियों पर कुछ कर लगा सकती तथा अपरािवयों पर छुर्माना कर सकती हैं (इन्हें क़ैंद करने का अधिकार नहीं होता)। यदि इनका कोई कर या छुर्माना वसूल न हो तो ज़िला-मिलिस्ट्रेट उसे वसूल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय कलेक्टर की अनुमित से ही शिचा, स्वास्थ्य, सफ़ाई या कच्ची सड़कों आदि के कार्य में खर्च करनी होती है। सरपंच, पंचायत का सभापित होने के अतिरिक्त, ग्रामकोष और उसका हिसाब तथा अन्य आवश्यक कागृज़ और रिजस्टर रखता है, सम्मन की तामील करवाता है और समय-समय पर कलेक्टर को पंचायत-सम्बन्धी रिपोर्ट देता रहता है।

पंचायतों की बहुत उन्नित तथा वृद्धि करने की आवश्यकता है। वर्तमान अवस्था में उनके अधिकार बहुत कम हैं, और उनकी आय भी बहुत थोड़ी है। इसिलए गाँवों के सुधार या उन्नित में वे विशेष भाग नहीं ले पार्ती। मुकदमे-मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में भी उनके द्वारा बहुत थोड़ा कार्य हो रहा है। यदि उनके अधिकार यथेष्ट हों तो उनके द्वारा बहुत सा न्याय-कार्य बहुत जल्दी तथा अल्प ज्यय में हो सकता है।

बोर्ड—देहातों में प्रारम्भिक शिचा श्रीर स्वास्थ्य श्रादि का कार्य करनेवाली मुख्य संस्थाएँ बोर्ड कहलाती हैं। इनके तीन मेद हैं— लोकल बोर्ड, ताल्लुका-बोर्ड या सब-डिविजनल बोर्ड, श्रीर ज़िला-बोर्ड । अ लोकल बोर्ड एक गाँव में या कुछ गाँवों के समूह में होता

<sup>\*ि</sup>कसी प्रान्त में तीनों ही प्रकार के बोर्ड़ हैं, और किसी में दो या एक ही तरह के । ज़िला-बोर्ड को मध्यप्रान्त में ज़िला-कोंसिल कहते हैं।

है। ताल्लुका या सब-डिविजनल बोर्ड एक ताल्लुके या सब-डिविजन में दोता है। यह लोकल बोर्ड के काम की देख-माल करता है।

जिला-बोर्ड एक ज़िले में होता है और ज़िले भर के लोकल बोर्डों (या ताल्लुका बोर्डों) का निरीक्षण करता है। भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बोर्डों की न्यवस्था एक सी नहीं है। मदरास और मध्यप्रान्त में इनकी स्थापना अधिक हुई है। मदरास में प्रत्येक गाँव का—अथवा, कई गाँवों को मिलाकर उन सब का—एक यूनियन बना दिया गया है। ब्रिटिश भारत में लगभग २०० ज़िला-बोर्ड और ५८० अधीन-ज़िला बोर्ड हैं। इनके अतिरिक्त लगभग ४५० यूनियन कमेटियों हैं। पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त को छोड़ कर ज़िला और लोकल बोर्डों में प्राय: चुने हुए सदस्यों की संख्या ही अधिक है। किस ज़िला-बोर्ड में कितने सदस्य हों, उसका सभापति चुना हुआ रहे, या नियुक्त किया जाय, यह प्रत्येक प्रान्त के ज़िला-बोर्ड-क़ानून से निश्चित किया हुआ है। संयुक्तप्रान्त में सभापति चुना हुआ एवं ग्रैर-सरकारी होता है। बोर्डों के चुनाव के लिए नये नियम बन रहे हैं।

चोडों का कार्य श्रीर व्यय — बोडों का कर्तव्य अपने प्राप्त-चेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य श्रीर सफ़ाई आदि के श्रितिरिक्त कृषि श्रीर पशुश्रों की उन्नति करना है। इनके खर्च के कुछ श्रन्य कार्य ये हैं:—

सड़कें बनवाना श्रीर उसकी मरम्मत करवाना;

सड़कों पर पेड़ लगवाना तथा उन पेड़ों की रचा करना;

पशुत्रों का इलाज करना ऋौर नस्ल सुधारना; मेले ऋौर नुमायशें करना ऋादि।

बोडीं की आय के साधन—बोडों की अधिकतर आय अववाब अर्थात् उस महसल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है। इसे सरकारी वार्षिक लगान या मालगुज़ारी के साथ ही प्राय: एक आना की रुपये के हिसाब से वस्त करके इन बोडों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ रक्म कुछ शतों से प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाब, घाट, सड़क पर के महस्त, पशु-चिकित्सा और स्कूलों की क्रीस, मवेशी-खाने की आमदनो, मेले या नुमायशों पर कर तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर है। (आसाम प्रान्त को छोड़कर) अधीन-जिला-बोडों का कोई स्वतंत्र आय-श्रोत नहीं, उन्हें समय-समय पर ज़िला-बोडों से ही कुछ मिल जाता है। वे उस रुपये को ज़िला-बोर्ड की इन्छा या सम्मति के विरुद्ध खुर्च नहीं कर सकते।

प्रांत तथा परिस्थिति-मेद से बोर्डों की आय तथा व्यय भिन्न-भिन्न होता है। एक ही बोर्ड के आय-व्यय में भी प्रति वर्ष कुछ अन्तर होता रहता है। तथापि एक ज़िला-बोर्ड के आय-व्यय से इस विषय का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। इसलिए आगे इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड की सन् १९३९-४० के आय-व्यय का बजट दिया जाता है:—

## इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड की श्राय

| मइ                 |           | रूपये    |
|--------------------|-----------|----------|
| प्रांतीय सरकार रे  | ते सहायता |          |
| शिक्षा             | २,६९,३६८  | )        |
| चिकित्सा           | १२,५५०    |          |
| स्वास्थ्य          | ११,३२८    | ३,४९,६४६ |
| श्चन्य             | ५६,४००    | j        |
| श्चबवाब            |           | २,५१,५७४ |
| हैसियत या जाय      | ₹0,000    |          |
| मवेशीख़ाना         |           | १७,६००   |
| यातायात            |           | ३६,०००   |
| शिक्षा-शुल्क       |           | १०,६००   |
| चिकित्सा           |           | १,१५०    |
| स्वास्थ्य          |           | 8,400    |
| पशु-चिकित्सा       |           | १३०      |
| बाज़ार             |           | १,३००    |
| किराया             |           | ₹,०००    |
| पेड़ लगाना         |           | 900      |
| श्चन्य             |           | 4,000    |
| कुर्व              |           | १४,२००   |
| पिछली बाक्री (वर्ष | १६,९६९    |          |
| योग                | ७,३८,२६९  |          |

| इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड का ब्यय    |                  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|--|--|--|
| मह                              | रुपये            |  |  |  |
| साधारण प्रवन्ध                  | <b>१</b> ,३९,२८० |  |  |  |
| मवेशीख़ाना                      | १२,०१५           |  |  |  |
| शिक्षा                          | ४,१७,⊏९७         |  |  |  |
| चिकित्सा                        | ४१,०९६           |  |  |  |
| स्वास्थ्य                       | १६,१०३           |  |  |  |
| चेचक का टीका                    | ११,२६५           |  |  |  |
| पशु-चिकित्सा                    | १२,६४०           |  |  |  |
| मेले और नुमायश                  | ५००              |  |  |  |
| पेड़ लगाना                      | 2,860            |  |  |  |
| निर्माण कार्य                   | ४६,७६०           |  |  |  |
| श्चन्य                          | ७,४००            |  |  |  |
| कर्ज                            | १४,२००           |  |  |  |
| बाक़ी देना (वर्ष के श्रन्त में) | १७,४४३           |  |  |  |
| योग                             | ७,३८,२६९         |  |  |  |

आगे दिये हुए म्युनिसपैलटी के आय-व्यय के अंकों से इन अंकों की तुलना की जिए । जिला-बोई का चेत्रफल और जन - संख्या म्युनिसपैलटी के चेत्रफल और जन-संख्या से कई गुना है। तथापि उसकी श्राय-व्यय म्युनिसपैलटी की आय-व्यय के आपे से भी कम है। जनता की शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा श्रादि के जैसे काम म्युनिसपैलटी को करने होते हैं, वैसे ही काम ज़िला-बोर्डों को अपने चेत्र में करने होते हैं। परन्तु वर्तमान दशा में उनकी आय इतनी कम होने से के अपना कर्तब्य कैसे पालन कर सकते हैं! यही कारण है कि प्राय: गाँव-वालों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था बहुत ही कम हो रही है। भारतवर्ष की नब्बे फीसदी आबादी गाँवों में रहती है, इसलिए गाँवों की जनता के हितार्थ जिला-बोर्डों की कितनी उन्नति होनी चाहिए, यह स्पट है।

म्युनिसपैलटियाँ और कारपोरेशन — म्युनिसपलटियाँ नगरों में काम करती हैं। ब्रिटिश भारत में इनकी कुल संख्या लगभग सात सौ है। प्रत्येक म्युनिसपैलटी की सीमा निश्चित की हुई है। जो लोग उसके अन्दर रहते और उसे टैक्स देते हैं वे 'रेट-पेयर या कर-दाता कहलाते हैं। जो कर-दाता निर्धारित वार्षिक कर देते हैं, श्रथवा जिनके पास जागीर हैं, वे वोटर या मतदाता कहाते हैं। इन्हें अपनी अपनी म्युनिसपैलटी के लिए मेम्बर (म्युनिसिपल कमिश्नर) चुनने का अधिकार होता है।

कलकत्ता, बम्बई श्रोर मदरास शहर की म्युनिसपैलिटियाँ म्युनिसि-पल कारपोरेशन या केवल 'कारपोरेशन' कहलाती हैं। इनके मेम्बरों (किमश्नरों) को कौंसिलर कहते हैं। श्रान्य म्युनिसपैलिटियों से इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, श्रोर श्राय-व्यय तथा कार्य-चेत्र श्राधक होता है।

इनका कार्य त्रौर व्यय—म्युनिसपैलिटियों श्रौर कारपोरेशनों के मुख्य कार्य कहीं-कही कुछ मेद होते हुए, साधारणतया ये हैं:—

(१) सर्वसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना, सड़कें

बनवाना, उनकी मरम्मत कराना; पेड़ लगवाना; डाक बंगला या सराय आदि सार्वजनिक मकान बनवाना; कहीं आग लग जाय तो उसे बुभाना; अकाल, जल की बाढ़ या अन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना।

- (२) स्वास्थ्य-रक्षा अस्पताल या श्रीषधालय खोलना; चेचक श्रीर प्लेग के टीके लगाने तथा मेला पानी बहाने का प्रवन्ध कराना; छूत की विमारियों को रोकने के उचित उपाय काम में लाना; पीने के लिए स्वच्छ जल (नल श्रादि) की व्यवस्था करना, लाने के पदार्थों में हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलायी गई है. इसका निरीक्षण करना।
- (३) शिक्षा विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना; मेले और नुमायशें कराना।
- (४) बिजली की रोशनी, ट्रामबे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना।

उपर्युक्त कार्यों में काफ़ी ख़र्च होता है। इस लिए इन संस्थाओं को आय की आवश्यकता होती है।

श्रामदनी के साधन—इन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य-मुख्य साधन ये हैं:— (१) चुङ्की (अधिकतर उत्तर भारत, वम्बई और मध्य-प्रान्त में) इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आनेवाले माल तथा जानवरों पर लगती है। संयुक्तप्रान्त में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्युनिसपैलिटियों का नाम ही चुङ्की पड़ गया है। (२) मकान और ज़मीन पर कर (विशेषतथा आसाम विहार, उड़ीसा, वम्बई, मध्यप्रान्त और बङ्काल में)। (३) व्यापार- पेशों पर कर (विशेषतया मदरास, संयुक्तप्रान्त, बम्बई. मध्यप्रान्त श्रीर बङ्गाल में)। (४) सड़कों श्रीर निंदयों के पुलों पर कर (विशेषतया मदरास, बम्बई श्रीर श्रासाम में)। (५) स्वारियों, गाड़ी, बग्बी, सायिकल, मोटर श्रीर नाव-ग्रुल्क। (६) पानी, रोशनी, नालियों की सफ़ाई हाट-बाज़ार कसाईखाने, पाख़ाने श्रादि का ग्रुल्क। (७) हैसियत, जायदाद श्रीर जानवरों पर कर (८) यात्रियों पर कर । यह कर निर्धारित दूरी से श्रीवक के फासले से श्रानेवालों पर लगता है श्रीर प्राय: रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वसूल कर लिया जाता है। (९) म्युनिसपल स्कूलों की फ़ीस। (१०) कांजी होस की फ़ीस। (११) सरकारी सहायता या ऋषा।

कभी-कभी शिक्षा, अस्पतालों श्रीर पशु-चिकित्सा के लिए म्युनि-सपैलिटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किसी म्युनिसिपैलटी को मैले पानी के बहाव के लिए नालियाँ बनानी होती हैं अथवा जल-प्रबन्ध के लिए शहर में नल श्रादि लगाने होते हैं तो वह ऋण लेती है। यदि उचित समभा जाय, तो इस खर्च का भार प्रान्ताय सरकार कुछ शर्तों से श्रपने ऊपर ले लेती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि म्युनिसपैलिटियों की श्रावश्यकताश्रों के विचार से उनकी श्राय बहुत कम है।

आगे इलाहाबाद म्युनिसपैलटी का सन् १९३९-४० बजट दिया जाता है। इससे यह ज्ञात हो जायगा कि विशेषतया संयुक्तप्रान्त में म्युनिसपैलटियों की आय प्रायः किन-किन साधनों से होती है तथा वे किन-किन कामों में रुपया ख़र्च करती हैं।

| इलाहाबाद म्युनिसपैलटो की ग्राय     |                 |                             |  |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|
| मद                                 |                 | रुपये                       |  |  |
| म्युनिसिपल कर:                     |                 |                             |  |  |
| चुङ्गी                             | ¥,62,000        | )                           |  |  |
| मकान और जायदाद                     | १,६६,५००        |                             |  |  |
| घरेलू जानवर श्रौर सवारी            | पू३,५००         | <sup>}</sup><br>} ११,६५,₹०० |  |  |
| पानी                               | ३,८२,३००        |                             |  |  |
| यात्री-कर                          | 69,000          |                             |  |  |
| श्चन्य                             | ११,९००          |                             |  |  |
| ख़ास क़ानून के अनुसार:—            |                 |                             |  |  |
| मवेशीख़ाना                         | १,५००<br>२२,०२४ | े <b>२३</b> ,५२५            |  |  |
| इका, ताँगा आदि                     | २२,०२४          | (1,717                      |  |  |
| म्युनिसिपत जायदाद श्रादि:          |                 |                             |  |  |
| ज़मीन, मकान आदि का किराया          | १,०३,०००        |                             |  |  |
| ज़मीन या उपज की बिक्री             | १,६००           |                             |  |  |
| स्कूल, बाजार श्रादि की फीस         | २५,७१०          | २,९६,५००                    |  |  |
| पानी की बिक्री                     | १,३२,०००        |                             |  |  |
| श्रन्य फ़ीस श्रौर जुर्माना         | ₹₹,०००          |                             |  |  |
| सूद श्रादि                         | १,१९०           | j                           |  |  |
| प्रान्तीय सरकार से सद्दायता        | •••             | ५०,१९३                      |  |  |
| <b>अ</b> न्य                       | • • •           | ४५,५४०                      |  |  |
| कर्ज़                              | ,               | २,⊏६,६५४                    |  |  |
| पिछला बाकी (वर्ष के श्रारम्भ में ) | •••             | ७०,१५८                      |  |  |
| योग                                |                 | <b>१९,३७,७७</b> ०           |  |  |

### इलाहाबाद म्युनिसपैलटी का ब्यय

| 4 400 400 104               | 3. 41.        | •                |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| मद्                         |               | रुपयं            |
| साधारण प्रबन्ध              | •••           | <b>१,९८,६९४</b>  |
| जनता की रक्षा:-             |               |                  |
| श्राग                       | ११,९०९        | 9 - 2 01111      |
| रोशनी                       | ९२,०४६        | <b>१,०३,९५५</b>  |
| स्वास्थ्य तथा श्रन्य सुविधा | ाएँ <b>:—</b> |                  |
| पानी                        | ३,७१,८९७      | )                |
| नाली श्रौर मोरी             | २,२१,३६९      | l o es Biais     |
| सफ़ाई                       | २,७०,२५६      | १,१३,२७७         |
| त्रस्पताल श्रोर टीका        |               | <u>'</u>         |
| पार्क आदि                   | •••           | १, <b>८९०</b>    |
| मवेशीख़ाना, कधाईख़ाना,      | , सराय आदि    | 9,680            |
| मवेशी श्रस्पताल             | ***           | १५,२२६           |
| जन्म-मरण रजिस्टर            |               | ३,९२८            |
| निर्माण कार्यः-             |               |                  |
| सड़क                        | 98,800        | 1                |
| इमारत                       | १०,१९४        | !<br>१,३९,५४६    |
| श्चन्य                      | ३४,९५२        | 1,13,401         |
| शिक्षा:—                    | (0),141       | ,                |
| स्कूल श्रौर कालिज           | १,५९,०००      | )                |
| लायब्रोरी, म्यूज़ियम        | ३२,२२८        | <b>१,९१,२२</b> न |
| श्रन्य                      | •••           | १,०२,६६०         |
| कर्ज श्रोर सूद              | ***           | १,७४,५८७         |
| बाक़ी देना (वर्ष के अपन्त   | तमें)         | ७०,०६९           |
| योग                         |               | १९,३७,७७०        |

नोटीफ़ाइड एरिया—ये श्रधिकतर पंजाब श्रीर छंयुक्तप्रान्त में हैं। इन्हें म्युनिसपैलिटियों के थोड़े-थोड़े से श्रधिकार होते हैं। ये उसी च्रेत्र में होते हैं, जहाँ बाज़ार या क़स्वा श्रवश्य हो श्रीर जिसकी जन-संख्या दस हज़ार से श्रधिक न हो। म्युनिसपैलिटियों की श्रपेक्षा इनकी श्राय (एवं व्यय) कम है। इनके श्रधिकांश सदस्य नामज़द होते हैं।

इम्पूवमेंट ट्रस्ट —बड़े-बड़े शहरों की उन्नित या सुधार के लिए कभी-कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सड़कों को चौड़ी करना, घनी बस्तियों को हवादार बनाना, गरीबों और मज़दूरों के लिए सकानों की सुञ्यवस्था करना, श्रादि । इन कामों के वास्ते 'इम्पूवमेंट-ट्रस्ट' बनाये जाते हैं । इनके सदस्य प्रान्तीय सरकार, म्युनिसपैलिटियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं । ये अपने श्रिषकार की भूमि आदि का किराया तथा आवश्यकतानुसार ऋष्य या सहायता लेते हैं ।

पोर्ट ट्रस्ट —वन्दरगाहों के स्थानीय प्रवन्ध करनेवाली संस्थाएँ 'पोर्ट-ट्रस्ट' कहलाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनाती हैं श्रोर व्यापार के सुभीते के श्रनुसर नाव श्रोर जहाज़ की सुव्यवस्था करती हैं। समुद्र-तट, नगर के निकटवर्ती समुद्र-भाग, या नदी पर इनका पूरा श्रधिकार रहता है। इनकी पुलिस श्रलग रहती है। इनके सभा-सद कमिश्नर या ट्रस्टों कहलाते हैं। कलकत्ते के श्रतिरिक्त सब पोर्ट-ट्रस्टों में निर्वाचित सदस्यों की श्रपेद्या नामज़द ही श्रधिक रहते हैं। श्रधिकांश सदस्य योरपियन होते हैं। म्युनिसपैलटियों को श्रपेद्या

नोर्ट-ट्रस्टों में सरकारी इस्तच्चेप श्रधिक है। ये ही ऐसी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ हैं, जिनके सभासदों को कुछ भत्ता मिलता है। माल-लदाई श्रौर उतराई, गोदाम के किराये तथा जहाज़ों के कर से जो श्रामदनी होती है, वह इनकी श्राय है। इन्हें श्रावश्यक कार्यों के लिए कुर्ज लेने का श्रधिकार है।

विशेष वक्तव्य इमारी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं में अनेक आदमी कोई ख़ास कार्य-क्रम लेकर नहीं पहुँचते, व्यक्तिगत कीर्ति या यश के लिए जाते हैं। वे दलवन्दी करते हैं, जिससे सार्वजनिक हित की उपेचा होती है। पुनः हमारी पंचायतों और ज़िला-बोर्डों की ही नहीं, म्युनिसपैलिटियों तक की स्थिति अच्छी नहीं हैं। इनकी आय बहुत कम है, और इन्हें अपने कार्य के लिए आवश्यक धन के वास्ते परमुखापेक्षी रहना पड़ता है। इसलिए इनके द्वारा किये जानेवाले कार्यों का असन्तोषप्रद रहना स्वामाविक ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि इन संस्थाओं की स्थापना का कार्य आरम्म हुए सौ वर्ष होने को आये, तथापि अब तक इन्हें स्थानीय पुलिस आदि सम्बन्धी कुछ नवीन अधिकार नहीं दिये गये।

इन विषयों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त को सक्जन इन संस्थाओं के सदस्य बनें, उन्हें अपने उत्तरदायित्व का स्थान रखते हुए नागरिक कार्यों में उदार हिन्ट-की ए खना चाहिए। उन्हें सम्प्रदाय या जाति-बिरादरी आदि का पच्चपात न कर अपने स्वेत्र के समस्त नागरिकों की उन्नति में दत्त-चित्त होना चाहिए।

# उन्तालीसवाँ परिच्छेद सरकारी नौकरियाँ

[इस परिच्छेद में कुछ संघान्तरित राज्यों सम्बन्धी बातों का भी उल्लेख किया गया है, उन पर श्रमल उस समय होगा जब संघ की स्थापना हो जायगी। वर्तमान श्रवस्था में संघ सरकार श्रीर संघीय व्यवस्थापक मंडल से क्रमशः केन्द्रीय सरकार श्रीर केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का श्राशय लिया जाना चाहिए।]

किसी देश का शासन अच्छा होने के लिए वहाँ कायदे-कानून तो अच्छे होने ही चाहिएँ, पर यही काफ़ी नहीं है। शासन-कार्य जनता के लिए यथेष्ट हितकर तभी होगा, जब सरकारी कर्मचारी योग्य और अनुभवी हों तथा उनमें लोक-सेवा और देश-प्रेम की भावना हो। जो व्यक्ति केवल वेतन के लोभ से काम करते हैं, उनके योग्य होने पर भी बहुधा सर्वसाधारण के प्रति उनका व्यवहार अहितकर और अक्विकर होता है।

सरकारी नौकरियों के मुख्य दो मेद हैं :— सैनिक और मुल्की । पहले भारतवर्ष के सैनिक नौकरियों के विषय में लिखा जाता है। सैनिक नोकरियाँ—भारतवर्ष को सैनिक व्यवस्था करनेवाला सर्वोच्च अधिकारी भारत-मंत्री है। वह ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति, अन्यान्य वातों में भारतवर्ष के रक्षा-कार्य के लिए प्रत्यक्ष का से उत्तर-दायी होता है। भारतवर्ष में उसके परामर्श और आदेशानुसार कार्य करनेवाला मुख्य अधिकारी गवर्नर-जनरल है। विधान के अनुसार सेना का निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण उसके ही हाथ रहता है। भारत-सर्वार के विभागों में से एक विभाग सेना विधाग है, यह पहले बताया जा चुका है। इस पर जंगो लाट (कर्मांडरन चीक्ष) का प्रमुत्व रहता है, वह सैनिक परिषद (मिलिटरो कौंसिज) का समापति होता है। इस समय जंगीलाट, गवर्नर-जनरल को प्रवन्धकारिणी सभा का सदस्य है, संघ की स्थापना के बाद वह इस सभा का सदस्य नहीं हुआ करेगा। सैनिक नौकरियों की व्यवस्था में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् भारतीय व्यवस्थापक मंडल का कुछ अधिकार नहीं है।

मुल्की नौकिरियाँ—श्रव असैनिक या मुल्की पदों की बात लीजिए। भारतवर्ष में कुछ सर्वोच्च मुल्की पदों के लिए नियुक्तियाँ सम्राट द्वारा होती है। इनमें गवर्नर-जनरल, तथा बंगाल, बम्बई श्रोर मदरास के गवर्नर श्रादि शामिल हैं। इनका उल्लेख पहले प्रसंगानुसार किया जा चुका है। इन पदों से नीचे इम्मीरियल सर्वित के सदस्यों का दर्जा है। इन्हें इंडियन सिविल सर्वित (श्राई० सो० एस०) कहते हैं। ये कर्मचारी प्रायः प्रान्तों का हो काम करते हैं; परन्तु चूँकि इनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा समस्त भारतवर्ष के लिए होती है, ये

आल-इंडिया ( श्राखिल भारतवर्षीय ) सर्विसवाले कहलाते हैं। इनमें से ही ज़िला-मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ज़िला-जज, सेशन्स जज, कमिश्नर, श्रीर रेवन्यू - वोर्ड के सदस्यों श्रादि की नियुक्ति होती है; यहाँ तक कि ये बंगाल, वम्बई श्रीर मदरास को छोड़कर श्रान्य प्रान्तों के गवर्नर तक हो सकते हैं।

इन कर्मचारियों के बाद दूसरा नम्बर उन कर्मचारियों का है, जो प्राविश्यल (प्रान्तीय) विविल-सर्विस के (पी० सी० एस०) कहलाते हैं। इस श्रेणी के कर्मचारी, प्रान्तीय सरकारों द्वारा मिन्न-मिन्न विभागों में, अपनी योग्यतानुसार नियत किये जाते हैं। भर्ती के लिए कभी तो परीचा होती है, और कभी नीचे की सर्विस के आदमी उसमें बदल दिये जाते हैं। प्रान्तीय सिविल-सर्विस में प्रान्त का नाम होता है, जैसे मदरास सिवल-सर्विस। इस सर्विस में डिप्टी-कलेक्टर, एक्सट्रा-एसिस्टेंट-कमिश्नर, मुन्सिफ, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, कालिजों के प्रोफेसर, सब-जज, ऐसिस्टेंट सर्जन आदि कर्मचारी होते हैं। प्रान्तीय सर्विस के बाद सबार्डिनेट-सर्विस या अधीन कर्मचारियों का नम्बर है। इनमें छोटे-से-छोटे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। इन की नियुक्ति मिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारें अथवा उनके विविध विभागों के उच्चाधिकारी करते हैं।

इंडियन सिविल-सर्विस की प्रभुता—भारतवर्ष में सर्व-साधारण के लिए इंडियन सिविल सर्वित का ही राज्य है। गावों की जनता कलेक्टर को ही सरकार समभती है, जो इस सर्वित का होता है। भारतीय शासन-पद्धति में इस सर्विस का वही स्थान है, जो मनुष्य के शरीर में रीढ़ की इडड़ी का होता है। इसिलए सरकारी क़ानूनों में इस सर्विधवालों की माँगों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके लिए उच्च पद श्रिधिक से-श्रिधिक संख्या में सुरक्षित रखे जाते हैं, श्रीर इन्हें इर प्रकार से प्रसन्न श्रीर संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया जाता है। यह कार्य निर्धन भारतीय जनता के लिए बहुत मँहगा पड़ता है। विशेष चिन्तनीय बात तो यह है कि भारतवर्ष को (प्रान्तीय) स्वराज्य देने का दावा करते हुए भी ब्रिटिश श्रिधिकारियों ने इस सर्विध को श्रिधिकांश विदेशों बनाये रखने, तथा इसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों श्रथवा मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त रखने, की व्यवस्था की। इस विषय की कुछ बातों का विचार पिछले परिच्छेदों में हो चुका है।

कुछ ज्ञातव्य बातें — इस सर्वित में भर्ती होने की परीक्षा पहले हंगलैंड में होती थी, अब भारतवर्ष में भी होती है। यह परीक्षा प्रतियोगिता से होती है। अर्थात् किसी वर्ष जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अधिक से अधिक नम्बर पानेवाले व्यक्ति चुन लिये जाते हैं। पहले इंगलैंड की परीक्षा पास किये हुए व्यक्तियों में से चुनाव होता है। उसके बाद भारतवर्ष की परीक्षा पास उम्मेदवारों का नम्बर आता है। इसका परिगाम यह होता है कि हंगलैंड में परीक्षा पास करनेवालों की, चुनाव में आने की अधिक सम्भावना होती है और, भारतीय परीक्षा का महत्व कम रह जाता है। पुनः भारतवर्ष में होनेवाली परीचा के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को दो वर्ष विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलैंड जाना होता है, ( इसका ख़र्च सरकार देती है )। इसके पश्चात् ये व्यक्ति भारतवर्ष के किसी प्रान्त में नौकरी के लिए भेजे जा सकते हैं।

सन् १९१९ ई० के सुधारों के अनुसार निश्चय हुआ था कि जिन सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती इंगलैंड में होती है, और जिन में योरपियन और भारतीय दोनों लिए जाते हैं, उनमें सैकड़े पीछे ३६ भारतवासी ही भर्ती किये जायँ, और इनमें डेढ़ फी सदी वार्षिक वृद्धि तब तक होती रहे, जब तक एक समयिक कमीशन नियत होकर फिर से सब मामले की जाँच करे। सन् १९२३ ई० में नियुक्त ली-कमीशन' ने उच पदों पर काम करनेवाले योरपियनों के लिए खूब पेंशन तथा भन्ते आदि दिये जाने की सिफारिश की। यद्यपि भारतीय व्यवस्थापक समा ने इसकी सिफारिशों पर अमल करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, तथापि ब्रिटिश सरकार ने भारत-सरकार से सहमत होकर उसकी प्रधान सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इससे यहाँ शासन-व्यय, जो पहले ही अधिक था, और भी बढ़ गया।

नवीन शासन-विधान श्रीर सरकारी नौकरियाँ— नवीन विधान में बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरी करनेवालों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा गया है। उनकी नियुक्त, वेतन, पेंशन श्रीर भर्च श्रादि के नियमों में इस बात की न्यवस्था की गयी है कि उनकी सुविधा तथा मर्यादा की यथेष्ट रच्चा हो तथा वे यथा-सम्भव श्रपने पद पर बने रहें। उनके वेतन श्रादि सम्बन्धी सरकारी न्यय पर न्यवस्थापक मंडल का मत नहीं लिया जाता। रेलवे, श्रायात-निर्यात डाक-तार श्रादि विभागों में एंग्लो-इंडियनों की नियुक्ति का लिहाज़ रखे जाने का स्पष्ट श्रादेश है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि प्रतिशत जितने पदों पर वे श्रव तक रहे हैं, उसका भी भविष्य में विचार रखा जाय। साधारणतः केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियाँ करने तथा उनकी नौकरी की शतें तय करने का कार्य गवर्नर-जनरल करेगा श्रीर किसी प्रान्त सम्बन्धी यह कार्य उस प्रान्त का गवर्नर करेगा। परन्तु इंडियन-सिविल-सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, श्रीर इंडयन पुलिस सर्विस तथा श्रावपाशी विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति भारत-मंत्री ही करेगा।

पिक्तिक सर्विस कमीशन—नवीन शासन विधान के अनुसार एक पिक्तिक सर्विस कमीशन संघ या केन्द्र के लिए श्रीर एक-एक सर्विस-कमीशन प्रत्येक प्रान्त के लिए रहेगा। परन्तु यदि दो या अधिक प्रान्त समभौता करलें तो वे एक ही कमीशन रख सकते हैं। संघीय (केन्द्रीय) कमीशन के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा श्रीर प्रान्तीय कमीशन के सभापित और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा होगी। प्रत्येक कमीशन के कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय भारतवर्ष में कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय भारतवर्ष में कम-से-कम दस वर्ष नौकरी कर चुके हों। संघीय श्रीर प्रान्तीय कमीशनों के सदस्यों की संख्या तथा उनकी नौकरी की शर्तें क्रमशः गवर्नर-जनरल श्रीर गवर्नर तय करेंगे। इन कमीशनों का कार्थ क्रमशः संघ श्रीर प्रान्तीय नौकरियों के लिए नियुक्तियाँ करने के वास्ते परीक्षा लेना तथा इन नौकरियों के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल श्रीर गवर्नरों को विविध विषयों पर श्रावश्यक परामर्श देना होगा। इन कमीशनों का इत्त्रें इनके

सदस्यों का बेतन, पेंशन, भत्ता आदि क्रमशः केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार देंगी, और इस पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को मत देने का ऋषिकार न होगा।

विशेष वक्तव्य पहले बताया जा चुका है कि गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल के अन्यान्य उत्तरदायित्वों में एक यह भी है कि वे वर्तमान तथा भृतपूर्व उच सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करें। यह बात विशेष चिन्तनीय इसिलए है कि यहाँ सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में देश, जाति, या वर्ण विशेष का पक्षपात किया जाता है। योरिपयनों या ऐंग्लो-इंडियनों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, तथा इन्हें भारतीयों की अपेक्षा अच्छा समक्ता जाता है। इससे यह स्वामाविक है कि यहाँ की विविध जातियां भी अपने-अपने आदिमयों के लिए कुछ पद सुरक्षित कराने की माँग करें और यहाँ साम्प्रदायिक वातावरण और भी अधिक विषमय हो। इस नीति का सर्वथा परित्याग होना चाहिए।

पुनः सरकारी पदों पर विदेशियों का बोलबाला न रहना चाहिए। वे चतुर या अनुभवी हो सकते हैं। पर उनका और इस देश का स्वार्थ भिन्न होने के कारण उनकी योग्यता जनता के लिए हानिकर ही होती है। इसलिए यहाँ कुछ थोड़े-से अपवादों को छोड़ कर शेष सब पद भारतीयों को मिलने चाहिएँ। साथ ही सब नौकरों पर, उनका पद कितना ही उच्च क्यों न हो, प्रजा-प्रतिनिधियों का यथेष्ट नियंत्रण होना चाहिए, जिससे जनता का स्वराज्य हो, न कि नौकरशाही का। और, उनके वेतन, भन्ने आदि में जनता की निधनता को न सुला

दिया जाय। सरकारी नौकरियों का वेतनादि अधिक होने का एक परिणाम यह भी होता है कि देश के अब्छे-अब्छे मस्तिष्क इसी ओर भुकते हैं, वे व्यापार, उद्योग आदि अन्य स्वतंत्र कार्यों की उपेक्षा करते हैं। अतः जैसा कि कांग्रेस का मत है, देश-काल का विचार करके साधारणतया यहाँ पदाधिकारियों का वेतन पाँच सौ स्पर्य से अधिक न होना चाहिए। सन् १९३७ से १९३९ ई० तक, जब कि प्रान्तों में नवीन शासन-विधान के अनुसार शासन-कार्य हो रहा था, जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल थे, उनमें कांग्रेसवादियों ने ५००) मासिक से अधिक वेतन नहीं लिया; यहां तक कि प्रधान-मंत्री का भी वेतन ५००) र० ही रहा। आवश्यकता है कि समस्त उच्च सरकारी पदों के सम्बन्ध में ऐसे नियम का हढ़ता से पालन किया जाय।

इस प्रसंग में छोटे कर्मचारियों का विषय भी विचारणीय है।
ऊँच वेतन पानेवालों की संख्या तो अपेक्षाकृत कम ही है। अधिकांश नौकरियां तो थोड़े-थोड़े वेतनवाली ही हैं। भारतवर्ष में जहाँ
ऊँचे अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन मिलता है, वहाँ छोटे
अहलकारों को बहुत ही कम दिया जाता है। यहां तक कि बहुत-से
सरकारी नौकर अपनी आय से अपने परिवार का पालन-पोषण भी
नहीं कर सकते। उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे सहायक कार्यों की खोज करनी पड़ती है। उदाहरणवत् पाठशालाओं
और स्कूलों के कितने-ही अध्यापक 'प्राह्वेट टय शन' करते हैं, अर्थात्
अवकाश के समय बालकों को उनके घर पर पढ़ाते हैं। जिन लोगों
को ऐसा सहायक कार्य नहीं मिलता, उनमें बहुत-से अनुचित मार्य

अहरण करते हैं। अनेक स्थानों में रिश्वत, या डाली-भेंट श्रादि का बाज़ार गर्भ रहता है। रेल श्रीर पुलिस के कर्मचारी तो इस विषय में काफ़ी बदनाम है। यद्यपि पुलिस पर प्राय: सरकार की कृपा-हिष्ट रही है इसमें अन्य विभागों की अपेक्षा अच्छा वेतन दिया जाता है. तथापि अनेक आदमी अधिक वेतनवाले काम की वजाय पुलिस की नौकरी इसलिए पसन्द करते हैं कि इसमें उन्हें 'ऊपर की श्रामदनी' की बहुत आशा रहती है। कहावत प्रचलित है 'छ: के चार कर दे, पर नाम दरोगा घर दे।' ऐसे सरकारी नौकरों से उनका कर्तव्य ठीक तरह पालन नहीं होता। वे बहुत पक्षपात से काम करते हैं। वे जनता के धामने निन्दनीय उदाहरण उपस्थित करते श्रीर उसकी मनोवृत्ति बिगाड़ते हैं। इन बातों में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि छोटे पदों पर काम करनेवालों का वेतन बढ़ाया जाय। उन्हें इतना वेतन अवश्य दिया जाय कि वे अपना तथा अपने परिवार का साधारण सरख-पोषण कर सके। उनके वेतन में श्रधिक रुपया ख़र्च करना कुछ कठिन भी न होगा, जब कि ऊँची नौकरीवालों का वेतन घटाकर अर्थादित कर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है।

## चालीसवाँ परिच्छेद

#### न्यायालय

[ इस परिच्छेद की संघ श्रीर संघान्तरित देशी राज्यों-सम्बन्धी बातें, यहाँ संक की स्थापना होने पर श्रमल में श्रायेंगी। ]

संघ-न्यायालय — नवीन विधान के अनुसार भारतवर्ष का सर्वोच्च-न्यायालय संघ-न्यायालय है। यह देहली में है। इसके प्रधान जज को भारतवर्ष का चीफ़-जिस्टिस कहते हैं। उसके अतिरिक्त, इसमें आवश्यकतानुसार छः जज रहते हैं। जजों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। प्रत्येक जज पैसठ वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। हाँ, वह गवर्नर-जनरल को त्याग-पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। सम्राट, दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निर्वंजता के आधार पर, उसे अपने पद से हटा सकता है, जब कि पिवी कौंसिल की जुडीशल कमेटी की भी ऐसी सम्मित हो। जज अथवा चीफ़ जिस्टिस के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निर्घारित योग्यता होना आवश्यक है। जजों का वेतन, भत्ता और मार्ग-व्यय,

खुटी का वेतन और पेंशन आदि सपरिषद सम्राट् निर्धारित करता है। किसी जज के नियुक्त हो जाने पर उसके वेतन या छुटी अथवा पेंशन आदि के अधिकार में कमी नहीं की जा सकती।

इसका अधिकार-क्षेत्र — संघ-न्यायालय के दो भाग हैं— आरिजनल और अपील भाग। संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का क्रान्नी अधिकार-सम्बन्धी मत-मेद होने पर उसका फ़ैसला केवल संघ-न्यायालय में होता है। और यह न्यायालय उसका विचार अपने 'आरिजनल' भाग में करता है। देशी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले विशेषतया उसी मत-मेद का विचार होगा, जिसका सम्बन्ध (क) भारतीय शासन-विधान की व्याख्या से या इस विधान के अन्तर्गत दी हुई सम्राट् की किसी आज्ञा से हो, या (ख) इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में समिमिलत होने के शर्तनामें के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्था-संबन्धी अधिकार कहाँ तक है, या (ग) इस बात से हो कि संघीय व्यवस्थापक मंडल का कोई क्रान्न किसी देशी राज्य में कहाँ तक लागू हो सकता है।

संघ-न्यायालय में ब्रिटिश भारत के किसी हाईकोर्ट के ऐसे फ़ैसले या श्रांतिम श्राज्ञा की अपील हो सकती है, जिसके विषय में हाईकोर्ट तसदीक कर दे कि उसमें शासन-विधान की व्याख्या से या विधान के अन्तर्गत सपरिषद सम्राट् की किसी श्राज्ञा से संम्बधित कोई महत्व-पूर्ण कान्त्नी प्रश्न श्राता है। क़ान्नी प्रश्न का ठीक निर्णय न होने के श्राधार पर, संघान्तरित देशी राज्यों के हाईकोर्टों के उन विषयों के फ़ैसलों की अपील संघ-न्यायालय में हो सकेगी, जो इस न्यायालय के श्रारिजनल भाग में लिये जा सकते हैं, (यह विषय पहले बताये जा चुके हैं)। संघीय व्यवस्थापक मडल क़ानून बनाकर सघ न्यायालय को निर्धारित प्रकार के, साधारणतया पन्द्रह हज़ार रुपये या श्रीधक के, दीवानी दावों की अपील सुनने का श्रीधकार दे सकता है। वह इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि ब्रिटिश भारत के हाईकोटों के सब या कुछ दीवानी मामलों की श्रापील सीधी प्रिवी-कोंसिल में न हो।

यहि गवर्नर-जनरल किसी सार्वजनिक महत्व के क़ानून के प्रश्न पर संव-न्यायालय की सम्मित लेना चाहे तो यह न्यायालय उसके सम्बन्ध में श्रावश्यक बातें जानलेने पर श्रपनी रिपोर्ट देगा। यह न्यायालय गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से समय-समय पर श्रपनी कार्य-पद्धति के नियम बना सकता है, जिनमें यह बातें भी सम्मिलित होंगी:—इस न्यायालय में कैसे वकील श्रादि पैरवी कर सकते हैं, कितने समय में यहाँ श्रपील दाख़िल की जानी चाहिए, मुक़हमें की कार्रवाई में क्या-क्या ख़र्च हो, क्या फ़ीस लगे, किस प्रकार व्यर्थ श्रपीलों का तुरन्त निपटारा कर दिया जाय, श्रीर किसी विषय के विचारार्थ कम-से-कम कितने जज बैठे, जो तीन से कम न हो। इस न्यायालय का सब काम श्रॅगरेजो में होगा श्रीर इसकी फ़ीस श्रादि की श्रामदनी केन्द्रीय श्राय में सम्मिलित की जाया करेगी।

संघ-न्यायालय के फ़ैसले की अपील प्रिवी-कौंसिल में हो सकती है। जिन मामलों का संघ-न्यायालय अपने आरिजनल भाग में फ़ैसला कर सकता है, उनकी अपील संघ-न्यायालय की अनुमति के बिना हो सकती है। अन्य विषयों के फ़ैसले की अपील संघ-न्यायालय या सपरिषद सम्राट्की अनुमति मिलने पर ही होती है। संघ-न्यायालय द्वारा (तथा पिवी-कौंसिल के फ़ैसलों से) स्चित किया दुआ क़ानून प्रंसगानुसार ब्रिटिश-भारत के सब न्यायालयों में मान्य होता है।

हाईकोट — निम्नलिखित न्यायालय हाईकोर्ट माने गये हैं:— कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, पटना तथा नागपुर के हाईकोर्ट; अवघ का चीफ कोर्ट, पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त और सिंघ के चीफ़-कमिश्नर्स कोर्ट। इनके अतिरिक्त सपरिषद सम्राट् ब्रिटिश भारत में किसी न्यायालय को हाईकोर्ट के अधिकार दे सकता है तथा कोई नया हाईकोर्ट बना सकता है।

साधरणतया प्रत्येक प्रान्त के लिए एक पृथक हाईकोर्ट है। परन्तु कलकत्ते का हाईकोर्ट बँगाल और श्रासाम के वास्ते, लाहौर का हाई-कोर्ट पंजाब और देहली के वास्ते, और पटना का हाईकोर्ट बिहार और उड़ीसा के वास्ते है। हलाहाबाद का हाईकोर्ट संयुक्त प्रान्त के केवल श्रागरा भाग के लिए है, श्रवध के लिए नहीं है।

जां की संख्या—प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीफ़-जस्टिस और कुछ जज होते हैं। उनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार सम्राट को है। इस समय विभिन्न हाईकोर्टी के जजों की अधिकतम संख्या चीफ़ जस्टिस सिहत, निम्न लिखित निर्धारित की हुई है:— कलकत्ता हाईकोर्ट २०, मदरास १६, लाहौर १६, बम्बई १४, हलाहाबाद १३, पटना १२, नागपुर ८, अवध का चीफ़कोर्ट ६, सिंघ श्रौर पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त के जूडीशल-कमिश्नर्ध-कोर्ट क्रमशः ६ श्रौर ३।

जर्जों की नियुक्ति—जज के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, जो :—

- े(१) कम-से-कम दस साल बैरिस्टर रह चुका हो,
- (१) इंडियन छिविल-सर्विष का कम-से-कम दस साल तक सदस्य रहा हो, श्रीर कम-से-कम तीन साल ज़िला-जज का काम कर चुका हो,
- ﴿ ३) ब्रिटिश भारत में कम-से-कम पाँच वर्ष ऐसे पद पर रहा हो, जो सब-जज या जज खक्रीका के पद से नीचान हो,
- (४) कम-से-कम दस वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का वकील, सोडर या एडवोकेट रहा हो।

इससे स्पष्ट है कि जजों के पद, इंडियन सिविल-सर्वित के सदस्यों को भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है, आवश्यकता होने पर अस्थायी रूप से गवर्नर-जनरल भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

नये विधान से पूर्व भी इन जर्जों की नियुक्ति सम्राट् द्वारा ही होतो थी। परन्तु उस समय चीफ्र जस्टिस श्रपनी सिफ्रारिश प्रान्तीय सरकार को भेजता था। यह सिफ्रारिश भारत-सरकार द्वारा भारत-मंत्री के पास भेजी जानी थी श्रौर श्रस्थायी नियुक्ति प्रान्तीय-सरकार द्वारा की जाती थी। श्रव प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना हो जाने से इस विषय का पूर्णं श्रधिकार प्रान्तीय सरकारों श्रर्थात् मंत्रो-मंडलों को दिया जाना चाहिए था। परन्तु यह दिया नहीं गया।

पहले नियमों के श्रनुसार इंडियन सिविब-सिविंस के सदस्य जर्जों की दो-तिहाई से श्रिषक जगहों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। श्रावश्यकता थी कि न्यायालयों के लिए उनकी नियुक्ति बिलकुल बन्द कर दो जाती; परन्तु श्रव तो उनकी संख्या का कोई प्रतिबन्ध न रहने से, उनके लिए मार्ग श्रीर भी प्रशस्त हो गया है।

जजों का वेतनादि: — प्रत्येक जज साठ वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। जजों का वेतन, भत्ता, माग-व्यय, छुट्टी का वेतन और परान आदि समय-समय पर सपरिषद सम्राट् निश्चय करता है जजों की नियुक्ती हो जाने पर, उसके वेतन या छुट्टी अथवा पेंशन आदि के अधिकार में कमी नहीं की जाती । इस समय कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ़-जिस्टिस का वार्षिक वेतन ७२,०००) निर्धारित है; मदरास, बम्बई, हलाहाबाद, पटना और लाहीर के हाईकोर्ट के चीफ़-जिस्टिस का द०,०००) है। उपर्युक्त सब हाईकोर्टों के जजों में से प्रत्येक का वार्षिक वेतन ४८,०००) है। नागपुर हाईकोर्ट के चीफ़-जिस्टिस का वार्षिक वेतन ५८,०००) है। नागपुर हाईकोर्ट के चीफ़ जिस्टिस का वार्षिक वेतन ५०,०००) और उसके जजों में से प्रत्येक का ४०,०००) है।

जो हाईकोर्ट जिस प्रान्त में है, उसका व्यय, उस प्रान्त का गवनर अपने व्यक्तिगत निर्णय से स्वीकार करता है। उस पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता। जो हाईकोर्ट एक से अधिक प्रान्तों के लिए काम करते हैं, उनका व्यय उन प्रान्तों में बँट जाता है।

हाईकोर्ट का अधिकार-क्षेत्र—हाईकोर्टों का चेत्र और अधिकार क़ान्त से निश्चित हैं और सम्राट् की आज्ञा से ही उनमें परिवर्तन हो सकता है। प्रत्येक हाईकोर्ट में दो भाग होते हैं। 'ओरिजनल' और अपील भाग। साधारणतया 'आरिजनल' भाग का कार्य-चेत्र हाईकोर्टवाले नगर की सीमा से बाहर नहीं होता। इस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामले जाते हैं, जो 'स्माल-काज़-कोर्ट' अर्थात् अदालत ख़कीफ़ा में नहीं जा सकते; तथा ऐसे सब फीजदारी मुक़दमें जाते हैं, जिनका अन्य स्थानों में सेशन जज की अदालतों में फेसला हों। इसी भाग में फीजदारी मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार मुक़-स्थिल अदालतों में नहीं हो सकता। हाईकोर्ट, वादी-प्रतिवादी की प्रार्थना पर, अथवा न्याय के विचार से, मुक़दमों को सब-जजों की अदालतों से उठाकर अपने इस (आरिजिनल) भाग में ले सकते हैं।

अपील भाग में 'आरिजिनल' भाग के तथा मुफस्सिल अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनी जाती है।

हाईकोर्ट अपनी निर्यामत सीमा की सब दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं। प्रान्तिक सरकारों की स्वीकृति से वे उनकी कार्य-प्रणाली के नियम बना सकते हैं; 'अटनीं', अमीन और मोहर्गिर आदि की फ़ीस की दर ठहरा सकते हैं। वे मुक़दमें को या उसकी अपील को, एक अदालत से दूसरी, उसके समान या उससे बड़ी, अदालत में बदल सकते एवं अदालतों

की 'रिटर्न' अर्थात् लेखा माँग सकते हैं। प्रायः माल (लगान)-सम्बन्धी मुक़दमों का, हाईकोर्ट के 'आरिजिनल' भाग में फ़ैसला होने का रिवाज़ नहीं है। हाईकोर्टों का सब काम आँगरेज़ी भाषा में होता है।

रेवन्यू कोर्ट—मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फ़ैसला करने के लिए कहीं कहीं रेवन्यू-कोर्ट, और कहीं-कहीं सेटलमेंट (बन्दोबस्त) किमश्नर हैं। इनके अधीन किमश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार आदि रहते हैं, जिन्हें लगान, मालगुज़ारी और आबपाशी आदि के मामलों का फ़ैसला करने का निर्धारित अधिकार है।

दीवानी अद्गलतें — हाईकोटों के नीचे दीवानी और फीजदारी की अदालतें हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इनके संगठन तथा
नियमों में कुछ-कुछ भेद है। प्रायः हर एक ज़िले एक ज़िला-जज
होता है। उसकी अदालत ज़िले में सबसे वड़ी दीवानी अदालत है। उसमें नीचे की अदालतों के फ़ैसलों की अपील हो सकती
है। ज़िला-जज के नीचे सबार्डिनेट-जज या सब-जज होते हैं। (इन्हें
संयुक्त प्रान्त में सिविल जज कहते हैं)। कलकत्ता, बम्बई, मदरास
तथा कुछ अन्य स्थानों में 'स्माल काज़ कोर्ट' या अदालत ख़क्कीका
है, जो छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम ख़र्च में श्रंतिम निर्णय
सुना देती हैं।

फ़ीजदारी अदाल तें-- फ़ीजदारी के मामलों का विचार करने के लिए प्रत्येक ज़िले में, या कुछ ज़िलों के एक समूह में, एक 'सेशनकोर्ट' रहता है। इसका प्रधान भी ज़िला-जज ही होता है; जो फ़ीज-दारी के अधिकार रखने के कारण, सेशन जज का कार्य सम्पादन

करता है। उसे अन्य सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता मिल सकती है। फ़ौजदारी के मामले में सेशन कोटों के अधिकार हाईकोटों सरीखं ही हैं। हाँ, मृत्यु-सम्बन्धी हुनम हाईकोर्ट से स्वीकृत होना चाहिए। इनमें फ़ैसला जूरी या असेसरों की सहायता से होता है। असेसर जज को अपनी सम्मित पर चलने के लिए वाध्य नहीं कर सकते।

सेशन जज के नीचे मजिस्ट्रेट रहते हैं। बम्बई, कलकत्ता और मद-रास में 'प्रेमीडेन्सी मजिस्ट्रेट', छावनियों में छावनी-मजिस्ट्रेट एवं नगरों और कस्बों में 'श्रानरेरी' अर्थात् अवैतानिक मजिस्ट्रेट और पहले, दूसरे तथा तीसरे दर्जें के मजिस्ट्रेट रहते हैं। प्रेमीडेन्सी मजि-स्ट्रेट तथा अव्वल दर्जें के मजिस्ट्रेट को दो साल तक की केंद्र और एक हज़ार रुपये तक जुर्माना करने तक का अधिकार होता है। दूसरे दर्जें के मजिस्ट्रेट छः मास तक की केंद्र और दो सो रुपया जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दर्जें के मजिस्ट्रेट एक मास तक की केंद्र और पचास रुपये तक जुर्माना कर सकता है।

श्रानरेरी मिजस्ट्रेटों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ये पहले प्रायः श्रिधकारियों के कृपा-पात्र होने से ही अपने पद पर नियुक्त कर दिये जाते थे, इनमें उसके लिए यथेष्ट योग्यता न होती थी। श्रातः इनके द्वारा न्याय-कार्य अच्छी तरह नहीं होता था। कांग्रेसी शासन में इनकी नियुक्ति में शिक्षा, योग्यता श्रादि का विचार किया गया। देश में अनेक श्रवकाश-प्राप्त श्रादमी ऐसे मिल सकते हैं, जो इस कार्य को करने के लिए यथेष्ट योग्य हो और साथ ही श्रवैतनिक रूप से इसे करने के लिए तैयार भी हों। उनकी नियुक्ति से, इस विभाग की कार्य-क्षमता बढ़ायी जा सकती तथा इसके खर्च में भी बहुत कि कायत हो सकती है।

अपील-पद्धिति—यहाँ दूसरे ब्रोर तोसरे दर्जे के मिजिस्ट्रेट के किसले के विरुद्ध, ज़िला-मेजिस्ट्रेट के समने अपील हो सकती है; ब्रोर ब्राव्ल दर्जे के मिजिस्ट्रेट के फ़ैसले की अपील सेशन कोर्ट में चल सकती है। जिन मनुष्यों को मुकदमें की प्रारम्भिक दशा में सेशन कोर्ट ने दोषों ठहराया हो, उनकी अपील उस प्रान्त के चीक कोर्ट या हाईकोर्ट में हो सकती है। जब मृत्यु का हुक्म दे दिया जाता है तो प्रान्त के शासक या वायस्त्राय के पास दया के लिए दफ्किंस्त दी जा सकती है। दीवानी के मुकदमों में भी अपील के लिए कम स्थान नहीं है। मुंसिफ़ के फ़ैसलों की अपील ज़िला-जज के यहाँ हो सकती है, जो यदि चाहे तो उसे सब-जज के पास भेज सकता है। सब-जज या ज़िला-जज के फ़ैसलें की अपील कुछ, दशाओं में जुडीशल-कमिश्नर्स-कोर्ट में, या हाईकोर्ट में हो सकती है। हाईकोर्टों के कुछ, फ़ैसलों की अपील संघ-न्यायालय में हो सकती है; ख़ास-ख़ास हालतों में अपील हंगलेंड की प्रिवी-कौंसिल तक भी पहुँचती है।

पंचायतें—गांवों में पंचायतों को कुछ छोटे-छोटे दीवानी और की जदारी मामलों का कै सला करने का अधिकार है। गत वर्षों में, सब प्रान्तों में, विशेषतया कांग्रेसी प्रान्तों में, इनका विस्तार और वृद्धि हुई है। आशा है, इससे जनता की, मुक्दमेवाज़ी द्वारा होने वाली, हानि कम हो जायगी। नागरिकों को चाहिए कि इनके कार्य

में यथेष्ट सहयोग प्रदान करें। पंचायतों से विशेष लाभ यह है कि पंच स्थानीय व्यक्ति होने से मामले-मुक्दमे के सम्बन्ध में अच्छी जान-कारी रखते हैं, और इसलिए न्याय अच्छा कर सकते हैं; क्योंकि पंचायतों में वकील पैरवी नहीं करते और अदालती स्टाम्प आदि की ज़रूरत नहीं होती, इनके द्वारा मुक्दमों का फ्रेसला कराने में लोगों का खर्च भी कम पड़ता है। निदान, पंचायतों का काम अभी बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है।



## इकतालीसवाँ परिच्छेद सरकारी आय-व्यय

[ इस परिच्छेद में ब्रिटिश भारत के ही आय-व्यय पर विचार किया गया है। देशी राज्यों के हिसाब के सम्बन्ध में कुछ वातों का उल्लेख अगले परिच्छेद में किया जायगा।]

त्रिटिश भारत का हिसाब—हिटिश भारत में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें प्रति वर्ष कुल मिलाकर लगभग तीन सौ रुपये वस्त करती श्रीर इसके करीब ही ख़र्च करती हैं। साधारणतया यह समभा जाता है कि सरकारी श्राय तथा व्यय लगभग दो-दो सौ करोड़ रुपये है, सरकारी हिसाब में श्राय की तथा व्यय की रक्तमों का जोड़ यही दिखाया जाता है। बात यह है कि रेल, डाक, तार, नहर श्रादि से जो कुल श्राय होती है, उसमें से इन कार्यों के प्रबन्ध श्रीर संचालन श्रादि में ख़र्च होनेवाला रुपया निकालकर विशुद्ध श्राय ही हिसाब में दिखायी जाती है। इसी प्रकार इन महों के व्यय में, इनके विविध कर्मचारियों के वेतन श्रादि का ख़र्च न दिखाकर केवल इन कार्यों में लगी हुई पूँजी का सूद ही दिखाया जाता है। इसके श्रातिरिक,

इन कार्यों में जो मृलधन लगता है, वह भी ख़र्च की रक्तमों में सम्मिलित नहीं किया जाता, श्रलग दिखाया जाता है।

सरकारी हिसाब के लिए किसी वर्ष की १ अप्रैल से लेकर, अगले वर्ष की ३१ मार्च तक एक साल समभा जाता है। इस प्रकार १ अप्रैल सन् १९४१ से ३१ मार्च सन् १९४२ तक के साल को सन् १९४१ – ४२ई० कहते हैं। वर्ष आरम्भ होने से पूर्व बजट-एस्टिमेट या आय व्यय का अनुमान तैयार किया जाता है। इसे व्यवस्थापक समाओं में उपस्थित करते समय गत वर्ष के आय-व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर लिया जाता है। उस समय लगभग ११ महीने का असली हिसाब और साल के शेष समय का अनुमानित हिसाब रहता है। इसे संशोधित अनुमान कहते हैं। कुछ समय पीछे वर्ष भर के आय-व्यक के ठीक अंक मिल जाने पर वास्तविक हिसाब प्रकाशित होता है।

राज्य साधारणतया पहले यह विचार करता है कि उसे देश में क्या-क्या काम करने हैं, उनमें कितना ख़र्च होगा। इस खर्च के लिए वह आय-प्राप्ति के मार्ग निकालता है, और विविध कर आदि निश्चय करता है। इसलिए यहाँ सरकारी व्यय का विचार पहले किया जाता है और सरकारी आय का पीछे। यह स्मरण रखना चाहिए कि चीफ किमश्नरों के प्रान्तों का व्यय और आय केन्द्रीय सरकार के हिसाव में शामिल की जाती है।

केन्द्रीय सरकार का व्यय—आगे यह बतलाया जाता है कि भारत सरकार की ख़र्च की मुख्य-मुख्य महें क्या है और उनमें कितना खर्च होता है।

#### (सन् १९४०-४१ ई० के व्यय का अनुमान)

| मह                          | लाख रुपये     |
|-----------------------------|---------------|
| १—-कर∙प्राप्ति का व्यय      | 8,06          |
| २रेल (सूद श्रादि)           | <b>₹</b> ₹,५१ |
| ३ श्राबपाशी                 | ११            |
| ४—डाक तार                   | ৬০            |
| ५—-मूद                      | १२,११         |
| ६— सिविल शासन               | ११,८१         |
| ७—मुद्रा, टक्साल            | ६२            |
| <सिविल निर्माण कार्य        | <b>₹,₹</b> ₹  |
| ९—सैनिक व्यय                | प्र,४१        |
| १०—विविध ब्यय               | 8,09          |
| ११—प्रांतों को दी हुई रक्नम | ३,०५          |
| योग                         | ₹,₹⊏,७१       |

श्रव इन महों का कुछ परिचय दिया जाता है।

कर-प्राप्ति का व्यय—इस व्यय में आयात-निर्यातकर, उत्पा-दन-कर (चीनी आदि का), आय-कर, अफ़ीम और नमक आदि विभागों के कर्मचारियों के वेतन के आदि के अतिरिक्त अफ़ीम और नमक तैयार करने का ख़र्च भी सम्मिलित है। यह ख़र्च यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होने का एक कारण यह है कि यहाँ उच्च कर्मचारी, जो अधिकतर श्रॅगरेज़ है, बहुत वेतनादि पाते हैं। रेल, आवपासी, डाक और तार—इस व्यय में इन महों में लगाई हुई पूंजी का सुद गिना जाता है। ये कार्य मुख्यतया आय के लिए किये जाते हैं।

सूद —यह ख़र्च ऐसा है, जिसके बदले में हमें न तो इस समय ही कुछ मिलता है और न भविष्य में ही कुछ मिलेगा। सूद उस रक्षम पर दिया जाता है जो भारत-सरकार ने ऋगा लेकर युद्ध श्रादि में ख़र्च की है। इस ऋगा की मद का बहुत-सा रुग्या लुकाया जा लुका है। जितना ऋगा शेष है, उसका सूद दिया जाता है। [उत्पादक कार्यों के ऋगा का सूद इस मद से श्रालग उन कार्यों के हिसाब में दिखाया जाता है।]

सिविल शासन—इस महमें भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल और इनके दक्तरों का तथा बन्दरगाहों. और चीक कमिश्नरों के प्रान्तों का सब ख़र्च सम्मिलत होता है। भारतवर्ष में शासन-व्यय बहुत श्रिधक है, कारण, जैसा कि पहले कहा गया है, यहाँ के उच्च श्रिधकारियों का वेतनादि बहुत श्रिधक है। और, वह क़ानून से निर्धारित होने से व्यवस्थापक मंडल उसमें कुछ कमी नहीं कर सकता। इस मह में वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में यथेष्ट परिवर्तन हो।

मुद्रा, टकसाल और विनिषय—इस मह में इन विषयों के केन्द्रीय कार्यालयों का तथा टकसाल चलाने का ख़र्च शामिल है। विनिषय की क़ान्नी दर एक शिलिंग छः पैंस फ़ी रुपया है। जब कभी ब्यवहार में, यह दर गिर जाती हैं, उदाहरण के लिए फ़ी रुपया

की रुपया एक शिलिंग चार पैंस हो जाती है, तो इससे जो च्ति होतीहै, वह विनिमय-सम्बन्धी ख़र्च में डाली जाती है। (यदि विनिमय की दर बढ़ जाय तो उससे होनेवाला लाभ, विनिमय की आय-में शामिज किया जाता है)।

सिविला निर्माण कार्य—इस मद में भारत-सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली इमारतें तथा दफ़्र, एवं समुद्रों में रोशनी-घर आदि बनाने और उनकी मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित है।

सेना—इस मद में स्थल-सेना, जल-सेना तथा हवाई-सेना का ख़र्च सम्मिलित है। सन् १८५६ ई० में वार्षिक सैनिक व्यय साढ़ें बारह करोड़ रुपये था। सन् १८५७ के बाद यह व्यय बढ़ कर साढ़ें चौदह करोड़ रुपये हो गया और १८८५ में सत्रह करोड़ हुन्ना। योरपीय महायुद्ध से पूर्व सन् १९१३-१४ में यह लगभग ३० करोड़ रुपये था। महायुद्ध में यह न्नीर बढ़ा। सन् १९२१-२२ ई० में यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा। इस वर्ष कि फ़ायत-कमेटी बैठी। पश्चात् व्यय कुछ घटा। अब यह लगभग पचास करोड़ रुपये वार्षिक है। अ

भारतवासियों की आर्थिक स्थिति देखते हुए यह व्यय अत्यन्त अधिक है। इस व्यय के बहुत अधिक होने के कारण यहाँ अनेक लोकोपयोगी कार्यों के लिए धन की चिन्तनीय कमी रहती है। इसमें शीघ्र काफ़ी कमी होनी चाहिए। अधिक से अधिक यह आधा रह जाना चाहिए।

<sup>\*</sup>इस समय महायुद्ध जारी हैं, और इंगलैंड ने भारतवर्ष की युद्ध-संलग्न वीषित कर रखा है। सरकार यहाँ युद्ध-सम्बन्धी श्रायोजन कर रही है। इसलिए सैनिक व्यय और भी श्रिधिक हो रहा हैं। सन् १९४१-४२ में प्रश्व करोड़ रु० केवल सेना में ख़र्च होने का श्रमुमान है, जब कि इस वर्ष की कुल श्राय केवल १०४ करोड़ रु० होगी।

विविध व्यय — इसमें स्टेश्नरी, प्रिंटिंग ( छ्याई ) श्रीर पेंशन श्रीदि का व्यय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाला व्यय भी इसी में जोड़ दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार की आय—आगे यह बताया जाता है कि आरत-सरकार की आय की महें कौन-कौन सी हैं और इनमें कितना-कितना खुर्च होता है।

| ( सन् १९४०-४१ की आय             | का अनुमान)  |
|---------------------------------|-------------|
| मद्द                            | रुपये       |
| १श्रायात-निर्यात-कर             | ३७,⊏६       |
| २—उत्पादन-कर ( चीनी श्रादि पर ) | . ११,४४     |
| ३ग्राय-कर                       | १४,२०       |
| ४कारपोरेशन कर                   | 4,30        |
| ५—नमक                           | ८,२०        |
| ६—श्रक्रीम                      | <b>४</b> ७. |
| ७ श्रन्य कर                     | १,०१        |
| द—रे <del>ल</del>               | ३७,⊏२       |
| ९—डाक-तार                       | १,०७        |
| १०—सूद                          | ६१          |
| ११—मुद्रा, टकसाल श्रोर विनिमय   | १,२४        |
| १२—सिविल निर्माण-कार्य          | ३३          |
| १३—सैना                         | ય,⊏९        |
| १४—विविघ स्राय                  | ६,२९        |
| योग                             | १३१,७३      |

श्रव इन महों का कुछ परिचय लीजिए।

त्रायात-निर्यात-कर — यह कर भारतवर्ष में बाहर से आने तथा यहाँ से विदेश जानेवाले माल पर लगता है। श्रायात-कर उन व्यापारिक समभौतों का विचार रखते हुए लगाये जाते हैं, जो भारतवर्ष के श्रन्य देशों से हुए हैं। इंगलैएड के माल पर प्रायः १० फ्री सदी कर की रियायत है। श्रर्थात् उस पर, उस तरह के, श्रन्य देश के माल की श्रपेक्षा इतना कर कम लगता है। इसके बदले में इंगलैंड भारतवर्ष के माल पर इतना ही कम कर लगाता है। लोहा, कागज़, कपड़ा श्रादि के श्रायात पर 'संरच्या' कर लगाया जाता है; इसका उद्देश्य यह होता है कि भारतवर्ष में इन चीज़ों के बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। संरक्ष्य के विषय में पहले लिखा जा चुका है।

उत्पादन-कर—यह कर भारतवर्ष में बननेवाली चीनी और दियासलाई पर लगता है। विदेशों से आनेवाली इन वस्तुओं पर भारी संरक्ष्य-कर लगने के कारण वहाँ से इन वस्तुओं का आयात कम होता है और फल स्वरूप सरकार को उस मह से आय भी कम होती है। उसकी पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार यह कर लगाती है।

आय-कर और कारपोरेशन-कर—यह कर विशेषतया मुनाफ़ी या वेतन पर लगता है। किसी भी वर्ष आय-कर उससे पिछले वर्ष की आमदनी पर लगाया जाता है। अतः कुल आय-कर और उसकी वस्लयाबी के आधार पर देश की पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। यह कर दो हजार रुपये से कम आमदनी।

पर नहीं लगाया जाता; इतनी श्राय एक परिवार के लिए श्रावश्यक मानी जाती। व्यक्तियों, रजिस्टरी न की हुई फ़र्मों (कोढियों) श्रीर संयुक्त परिवारों की श्राय पर इस कर का स्वरूप वर्द्धमान है, श्रायंत् जितनी श्राय श्राधिक होती है, उतनी ही कर की दर बढ़ती जाती है। गत योरपीय महायुद्ध के समय से पचीस हज़ार या इससे श्राधिक की श्राय पर सूपर-टैक्स (श्रातिरिक्त कर) लगता है। श्राय-कर की तरह इसकी दर भी वर्षधमान है।

प्रत्येक कम्पनी और रजिस्ट्री की हुई फर्म से आय-कर तथा स्पर-टैक्स एक निर्धारित दर से लिया जाता है। इसे कारपोरेशन-कर कहते हैं।

नमक-कर—यह एक उत्पादन-कर है श्रीर उस नमक पर १।)
प्रति मन के हिसाब से लगता है, जो यहाँ बनाया जाता है। यह कर
बहुत श्रिष्ठिक है, श्रीर श्रखरनेवाला हैं। नमक भोजन का श्रावश्यक
पदार्थ होने से इस पर लगनेवाला कर जीवन-रक्षक वस्तु पर कर है,
श्रीर इसका भार ग्ररीब-से-ग्ररीब श्रादमी पर पड़ता है। इस प्रकार इस
कर का श्रनुचित होना स्वयं-सिद्ध है। इसीलिए इस कर का यहाँ घोर
विरोध किया जाता है।

अफ़ीम-कर—अब से तीस वर्ष पूर्व अफ़ीम की, चीन आदि देशों में खूब निर्यात होती थी। और, भारत-सरकार को इस मादक पदार्थ के कर से बहुत आमदनी होती थी। अब भारतवर्ष से, औषि के रूप के सिवाय इसकी कहीं निर्यात नहीं होती। इसलिए इसकी आय भी बहुत कम—पहले की अपेचा तो नाम-मात्र की ही—होती है। अन्य कर — केन्द्रीय सरकार को यह आय प्रायः देशी राज्यों से मिलनेवाले नज़राने से होती है, जो प्रायः उन संघियों के अनुसार मिलता है, जिनसे पूर्व काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों का ब्रिटिश भारत के स्थानों से परिवर्तन हुआ था, या जिनसे देशी नरेश अपने राज्य में फ़ौज रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त हुए थे।

रेल — भारतवर्ष में रेलों में लगभग नौ सौ करोड़ रूपये लगे हुए हैं, श्रिधकांश पूंजी श्रीर प्रवन्ध विदेशी हैं। जनता के हितों की श्रोर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यदि माल ले जाने की दरों में श्रावश्यक परिवर्तन किया जाय श्रीर जनता की सुविधाश्रों का यथेष्ट ध्यान रखा जाय तो इनसे बहुत लाभ हो।

इस मद्द की आय के हिसाब के वास्ते सरकारी रेलों की कुल आय में से उनके चलाने का ख़र्च तथा कम्पनियों को दिया हुआ सुनाफ़ा घटा दिया जाता है और शेष में कम्पनियों की रेलों से होने वाली आय जोड़ दी जाती है। सन् १९२५ ई० से रेलों का हिसाब अन्य सरकारी हिसाब से पृथक् कर दिया गया है। इस समय यह व्यवस्था है कि रेलों में लगी हुई पूँजी का एक प्रति-शत सरकारी आय में समिलत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष निर्धारित से अधिक मुनाफ़ा होता है, उस वर्ष के अधिक मुनाफ़े का पंचमांश भी सरकार को मिलता है। अगर सैनिक महत्ववाली रेलों से नुक़सान हो, तो उतनी रक़म सरकार को दी जानेवाली रक़म सुकाने के बाद

रेलवे ६ इतं फंड के लिए तीन करोड़ से श्रधिक रुपया रह जाय तो जितना रुपया श्रधिक हो, उसका तृतीयाँश सरकार को दिया जाता है।

डांक श्रीर तार—इस मह का श्राय में वह रक्तम दिखायी जाती है, जो कुल श्राय में से संचालन-व्यय निकालकर शेष रहती है। भारतवर्ष में सरकार ने, जनता की सामर्थ्य श्रीर सुविधा का विचार न करते हुए, पोस्टकाडों श्रीर लिफ्ताफ़ों का मूल्य तथा पेकेट या पार्सल की दर बढ़ा रखी है। इससे लोगों के पारस्परिक व्यवहार-बृद्धि एवं साहित्य-प्रचार में बहुत बाधा उपस्थित होती है।

सूद — इस आय में भारत-सरकार द्वारा प्रान्तों को दिये हुए श्रीण और पेशगी का सूद, रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी का सूद तथा प्रोविडेंट फंड की सिक्यूरिटियों (ऋण्य-पत्रों) के सूद की आय सिम्मलित है।

सिविला निर्माण-कार्य—इस मद्द में सरकारी मकानों का किराया, उनकी विक्री का रूपया तथा इस प्रकार श्रन्य श्राय सम्मिलित है।

मुद्रा, टकसाल ख्रोर विनिमय—इस मद्द में सरकार के 'पेपर करेन्सी रिज़र्व' नामक कोष में जो सिक्यूरिटियाँ रखी जाती हैं, उनकी रक्रम का सूद तथा भारतवर्ष के लिए पैसा, इकन्नी खादि सिक्के खालने का लाभ सम्मिलित है। रुपया टालने का लाभ 'गोल्ड स्टैंडर्ड

रिज़र्व' श्रर्थात् 'मुद्रा-दलाई-लाभ-कोष' में डाजा जाता है। विनिमय की श्राय के सम्बन्ध में, इस मद्द में होनेवाले व्यय के प्रसंग में लिखा जा चुका है।

सेना—इस मह की आय में सैनिक स्टोर, कपड़े, दृध, मक्खन तथा पशुओं की बिका से और सैनिक निर्माण-कार्य से होनेवाली आय सम्मिलित है।

विविध आय—इस मह में सरकारी गुज़ट, रिपोटों तथा पुस्तकों आदि की बिकी से होनेवाली तथा सरकारी प्रेस्त की अन्य आय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी में जोड़ दी गयी है।

प्रान्तीय आय-व्यय—श्रव प्रान्तीय श्राय-व्यय के सम्बन्ध में लिखा जाता है। प्रान्तीय सरकारों से यहाँ श्राशय गवर्नरों वाले प्रान्तों की सरकारों से ही है। जैसा पहले कहा गया है, चीफ़-किमश्नरों के प्रान्तों का श्राय-व्यय केन्द्रीय हिसाव में सिम्मलित होता है।

पहले प्रान्तीय ब्यय के विषय को लीजिए। सब प्रान्तों का मिलाकर कुल ब्यय लगभग द्र करोड़ रुपये होता है। प्रत्येक प्रान्त में होनेवाले ब्यय की रक्षम भिन्न भिन्न है—और प्रति वर्ष योड़ी-बहुत बदलती रहती है। स्थानाभाव से यहाँ केवल उदाहरण-स्वरूप संयुक्तप्रान्त की सरकार के ब्यय की महें, और उनकी रक्षम के श्रंक दिये जाते हैं।

# संयुक्तप्रान्त के व्यय का अनुमान

(सन् १९४०-४१ ई०)

| मद्द                  | लाख रुपये  |
|-----------------------|------------|
| १-कर-प्राप्ति का व्यय | १,६३       |
| २—श्राबपाशी           | १,१७       |
| <b>३—</b> -सूद        | ६९         |
| ४—शासन                | १,४३       |
| प्-न्याय              | <b>৩ १</b> |
| ६—जेल                 | ३३         |
| ७—पुलिस               | १,७९       |
| <b>८</b> —शिचा        | २,१९       |
| ९—स्वास्थ्य चिकित्सा  | ६१         |
| १०— कृषि              | <b>৬৩</b>  |
| ११—सहकारिता           | 9          |
| १२—उद्योग-धंधे        | २१         |
| १५ श्रन्य शासन-व्यय   | \$         |
| १४सिविल निर्माण कार्य | ६१         |
| १५श्रकाल-निवारण       | 8          |
| १६पेंशन               | १,११       |
| १७-स्टेश्नरी बिंटिग   | १४         |
| १८—विविध व्यय         | १०         |
| योग                   | १३,५८      |

श्रव व्यय की सुख्य-मुख्य महों पर विचार करते है।

कर-पाप्ति का व्यय—इसमें मालगुज़ारी, आवकारी, स्टाम्प, जंगल, रजिस्टरी आदि के कर वस्तुल करनेवाले कर्मचारियों का वेतन आदि सम्मिलित है।

आवपाशी—यह प्रधानतया आय की मह है। इसके सम्बन्ध में आगे कहा जायगा।

शासन—इसमें गवर्नर, मंत्रियों, किमश्नरों, कलेक्टरों श्रोर उनके सहायकों तथा तहसीलदार श्रीर उनके श्रधीन कर्मचारियों के वेतन, भन्ने तथा श्राफ़िस-व्यय के श्रितिरिक्त, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल श्रादि का ख़र्च सम्मिलित है। केन्द्रीय शासन-व्यय की तरह प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी उच्च कर्मचारियों का वेतन बहुत श्रिषक है। यह जनता- की परिस्थित के श्रमुसार निर्धारित होना चाहिए। कांग्रेसी सज्जनों ने पांच सौ रूपये मासिक लेकर मंत्री-पदों पर काम कर दिखाया है, श्रन्य सज्जनों को भी उनके श्रादर्श का श्रमुकरण करना चाहिए। श्रावश्यकतानुसार नियम बन जाने से उच्च श्रिषकारियों सम्बन्धी ख़र्च में बहुत किफ़ायत हो सकती है।

न्याय—इस मद् में हाईकोर्ट से लेकर नीचे तक की सब अदालतों का ख़र्च सम्मिलित है। हाईकोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते आदि को छोड़ कर न्याय-सम्बन्धी ख़र्च प्रान्तीय सरकारों के अधीन है और वे इसमें बहुत बचत कर सकती है। गत वर्षों में कांग्रेसी सरकारों ने योग्य व्यक्तियों को आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके इस विभाग का ख़र्च बढ़ाये बिना ही, इसकी कार्य-क्षमता बढ़ायी तथा पंचायतों की बृद्धि करके, खर्च कम करने का प्रयत्न किया था।

जेला — इस मद्द में सब प्रकार की जेलों के प्रवन्ध का व्यय, जरायमपेशा जातियों के सुवारार्थ किया हुआ व्यय, क्रैदियों के लिए खाद्य-पदार्थ आदि का व्यय तथा उनके छूटने पर उनके निर्वाहार्थ दिया हुआ व्यय शामिल है। वर्तमान दशा में, जेलों में नागरिकों का जीवन विगड़ने की प्रवृत्ति रहती है। यदि उचित व्यवस्था हो जाय तो क्रैदियों का जीवन सुधरने लग जाय। राजनैतिक क्रैदियों से व्यर्थ में व्यय-भार बढ़ता है। जनता की राजनैतिक मांग को पूर्ण करते रहने से यह ख़र्च सहज ही काफो घट सकता है।

पुलिस—इस मह में निम्नलिखित ब्यय समिलित है:—(क) इन्ह्पेक्टर-जनरल आदि बड़े अफ्सरों और उनके सहायकों, तथा पुलिस के सिपाहियों आदि का वेतन और आफ़िस-ख़र्च, (ख) ख़ुफ़िया विभाग या सी० आई० डो० का ख़र्च, (ग) गाँव की पुलिस का ख़र्च, तथा (घ) रेलवे पुलिस का ख़र्च। आवश्यकता है कि उच पदाधिका-रियों का वेतन कम कर के, इस मह का ख़र्च घटाया जाय। गाँव की पुलिस के ख़र्च के सम्बन्ध में ख़र्च बहुत अधिक घटने की सम्भावना नहीं है। उसका अधिकांश भाग चौकीदारों का वेतन होता है, जो कम ही है।

स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा—इस मह में यह ख़र्च शामिल है:—विविध कर्मचारियों का वेतन, मत्ता, कार्यालय का व्यय श्रीर सामान श्रादि, ज़िला बोडों श्रादि को सहायता, छूत की बोमारियों के निवारण का ख़र्च, अस्पताल और शफ़ाख़ानों का ख़र्च, दाइयों और सेवा-सितियों को दी जानेवाली रक्तम, और आयुर्वेदिक कालिज आदि, मेडिकल स्कूल और कालिज, पागलख़ाने, रास्रयनिक परीक्षक का ख़र्च।

देश में मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ी हुई है, बुख़ार, चेचक, है जा आदि अनेक बीमारियों ने घर कर रखा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विभाग में वैज्ञानिक उपायों का अवलम्बन कर के लोगों के प्राण बचाये जाय और उन्हें अधिक स्वस्थ बनाया जाय।

शिक्षा—इस मद्द में इन विषयों का ख़र्च होता है:—विश्व-विद्यालय और कालिज, हाई और मिडिल स्कूल, प्रारम्भिक शिक्षा, विशेष पेशों के स्कूल, कर्मचारियों का वेतन, आफ़िस-ख़र्च, छात्रवृत्ति । विगत वर्षों में, शिक्षा में व्यय कम हुआ है, और जो व्यय हुआ है, उसका भी जनता को यथेष्ट लाम नहीं पहूँचा है। देश में निरक्षरता और वेकारी भयंकर रूप से है। अब इन दोषों को दूर करने तथा इस मद्द के व्यय को अधिक उपयोगी बनाने का विचार हो रहा है।

कृषि — इस मद्द में नीचे लिखा खर्च शामिल है: — निरीक्षण-कर्मचारी, पशु-पालन, कृषि-प्रयोग, कृषि-कालिज और अन्वेषण-शाला, कृषि-फार्म, नुमायश और मेले, वनस्पति-शाला, कृषि-स्कूल, पशु-चिकित्सा, सहकारिता विभाग के कर्मचारी, और उनका आफिस-ज्यय आदि। प्रान्तीय सरकारों की आय का एक मुख्य साधन किसानों से प्राप्त मालगुज़ारी है, उनकी भलाई के लिए जितना ख़र्च किया जा सके श्रन्छा है, हां, वह मितव्ययिता-पूर्वक होना चाहिए।

उद्योग धन्धे—इस मह में खर्च इन विषयों में होता है:— निरीक्षण, उद्योग धन्धों की सहायता, श्रन्वेषण-संस्था, उद्योग और शिल्प-संस्थाएँ श्रादि। इस विभाग में भी विगत वर्षों में बहुत कम खर्च हुश्रा है। स्वदेशी उद्योगधन्धों की उन्नति श्रीर पेशों-सम्बन्धी शिज्ञा के कार्य में प्रगति होनी चाहिए।

सिविल निर्माण-कार्य—इस मह में निम्नलिखित ख़र्च होता है:—हमारतों, सड़कों श्रीर पुलों को बनवाने तथा उनकी मरम्मत कराने का ख़र्च, इस विभाग के श्रफ़सरों का वेतन श्रीर श्राफ़िस-ख़र्च श्रीज़ार श्रादि ख़रीदने का ख़र्च; म्युनिसपैलिटियों, ज़िला-बोडों श्रादि को हमारतों के लिए दी जानेवाली रकम। श्रव तक इस मह में सर्व-साधारण की श्रावश्यकताश्रों का विचार बहुत कम किया गया। नगरों या शहरों की सरकारी हमारतों या सड़कों श्रादि पर ही विशेष ध्यान दिया गया। श्रावश्यकता है, देहातों को जानेवाले रास्तों की सुधि लेने की। श्राशा है, प्रान्तीय सरकारें इस श्रोर कमशः श्रपना कर्तव्य पालन करेंगी।

श्रव प्रान्तीय श्राय के विषय को लीजिए। सब प्रान्तों की विषिक श्राय मिला कर लगभग ८० करोड़ रुपये होती है। स्थानाभाव से भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सम्बन्ध में व्यौरेवार न लिखकर यहाँ केवल संयुक्तप्रान्त की सरकार श्राय की महें श्रौर उनकी रक्तम के श्रंक दिये जाते हैं:—

## संयुक्तपान्त की आय का अनुमान

( सन् १९४०-४१ ई० )

| मद                              | रूपये      |
|---------------------------------|------------|
| ्रमालगुज़ारी                    | ६,०९       |
| <b>२</b> —श्राबकारी             | १,३६       |
| ३—स्टाम्प                       | १,३४       |
| ४—जंगल                          | પૂર        |
| <b>५—र</b> जिस्टरी              | 9          |
| ६—मोटर श्रादि पर-कर             | १२         |
| ७त्राय कर                       | 45         |
| ८— अन्य कर (मनोरंजन कर आदि)     | पू६        |
| ९श्राबपाशी                      | १,६९       |
| १०—सूद                          | 48         |
| ११—सिविल निर्माण-कार्य          | १०         |
| १२—न्याय                        | ??         |
| १३—जेल                          | Ę          |
| १४—पुलिस                        | 2          |
| ং ্— যিত্বা                     | 4.8        |
| १६स्वास्थ्य चिकित्सा            | 6          |
| १७ – कृषि श्रौर सहकारिता        | <b>₹</b> ¥ |
| १८—उद्योग धन्धे                 | Ę          |
| १९ — शासन-सम्बन्धी श्रन्य त्राय | २          |
| <b>২০—</b> বিবি <b>ষ খ্যা</b> য | 71         |
| २१ — केन्द्रीय सरकार की सहायता  | २५         |
| भोग                             | १३,५८      |
|                                 |            |

श्रव इन में से मुख्य-मुख्य महों का विचार किया जाता है :--

मालगुज़ारी—इस मह में मालगुज़ारी, सरकारी जागीर की विक्री, ज़मीन का महस्रल तथा अववाब के अतिरिक्त निम्नलिखित आय भी सम्मिलित होती है:—मालगुज़ारी-सम्बन्धी जुर्माना, ख़ास पटवारी रखने से होनेवाली आय, खेतों की हह ठीक करने के लिए अमीनों की फ़ीस, उन जंगलों या ज़मीनों से होनेवाली खिण्ज पदार्थों की आय, जो जंगल विभाग के प्रबन्ध में नहीं।

प्रान्तीय सरकार की आय का मुख्य साधन मालगुज़ारी ही है। इसकी (एवं लगान की) अधिकता के कारण अधिकाँश कृषकों की बुरी दशा है। पिछले दिनों कुछ प्रान्तों में लगान और मालगुज़ारी के सम्बन्ध में सुधार किया गया है।

त्रावकारी—माँग, चरस, शराब, अफ़ीम आदि मादक पदार्थों पर लगाया जानेवाला कर 'आबकारी-कर' कहलाता है। यहाँ मादक पदार्थों को बनाने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इनकी बिक्री से जो आय होती है उसमें से उत्पादन-व्यय निकलने पर जो शेष रहे, वह सरकारी मुनाफ़ा है, और आय में सम्मिलित होता है। इस महः में लाइसेंस फ़ीस, डिस्टलरी (शराब की मही) की फीस, शराब और अन्य मादक पदार्थों की विक्री का महसूल, (आबकारी विभाग का) अफ़ीम की बिक्री का लाभ, मादक पदार्थों के सेवन-सम्बन्धी जुर्मीना आदि सम्मिलित हैं।

विगत वर्षों में इस मद्द की श्राय में उत्तरोत्तर बृद्धि होती रही

थी। कांग्रेसी सरकारों ने अपने समय में मादक-वस्तु-निषेध के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट रखी, और बहुत-से ज़िलों में मद्यपान-निषेध का प्रयोग सफलता-पूर्वक किया। ऐसी नीति से आय कम होती है परन्तु यह अच्छा ही है।

स्टाम्प स्टाम्प दो प्रकार का होता है, श्रदालती श्रीर गैर-श्रदालती । श्रदालती स्टाम्प की श्राय में कोर्ट-फीस या श्रदालतों में पेश हो नेवाले मुक़हमें के काग्रजों श्रीर दर्झास्तों पर लगाये जानेवाले टिकटों की श्रामदनी शामिल है। गैर-श्रदालती स्टाम्प में व्यापार श्रीर उद्योग-सम्बन्धी कागज़ों (हुएडी, पुज़ें, चेक, रुपयों की रसीद श्रादि ) पर लगनेवाले टिकटों की श्रामदनी गिनी जाती है।

श्रदालती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप के न्याय पर कर है। ग्रैर-श्रदालती स्टाम्प भी (परोक्ष रूप में ) न्याय-कर ही है; रूपया लेने की रसीद श्रादि पर स्टाम्प इसीलिए तो लगाया जाता है कि पीछे श्रावश्यकता होने पर न्याय के लिए प्रमाण रहे।

जंगला—इस मद्द में निम्नलिखित आय होती है—जंगल की लकड़ी या अन्य पैदावार से होनेवाली आय, जंगल का लावारसी या ज़ब्त किया हुआ माल, जँगल की पैदावार पर महसूल, इस विभाग-सम्बन्धी सुमीना आदि।

र जिस्टरी—इस मह की आय निम्नलिखित विषयों से होती है— दस्तावेज़ों की रजिस्टरी कराने की फ़ीस, रजिस्टरी करायों हुई दस्तावेज़ों की नक़ल की फ़ीस या जुर्माना आदि। कांगज़ों की रजिस्टरी होने से लोगों को वेईमानी करने का अवसर कम आता है। आय-कर — श्राय-कर से होनेवाली श्राय केन्द्रीय सरकार की होती है. वह उसका निर्धारित भाग प्रान्तों में विभक्त करती है।

आवपाशी—यहाँ नहरों और बड़े तालाबों का कार्य बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के साथ आय का बढ़ना अनुचित नहीं, परन्तु इसकी व्यवस्था और दरों में जनता की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

स्द — यह आय ज़िला और अन्य लोकल फंड कमेटियों म्युनिसपैलटियों, ज़िला-बोडों, ज़मीदारों, किसानों तथा सहकारी समितियों आदि को दिये हुए ऋणा के सूद से होती है।

न्याय — इस मद्द में यह आय होती है — कोर्ट फ़ीस, मिलिस्टेटों का किया हुआ जुर्माना और ज़ब्ती आदि, वकालत की परीक्षा की फीस, अनिधकृत माल की विक्री।

जिला—इस मद्द की आय विशेषतया उस सामान की बिकी से होती है, जो जेलों के कारख़ानों में क्रैदियों द्वारा तैयार कराया जाता है।

पुलिस—इस मह में निम्नलिखित आय होती है—सार्वजनिक विभागों या प्राइवेट संस्थाओं आदि को जो पुलिस दी जाय, उसके उपलक्ष्य में होनेवाली आय, हथियार रखने के क़ानून से होने-वाली आय, मोटर आदि की रिजस्टरी कराने की फ़ीस, जुर्माना और ज़ब्ती।

शिक्षा—इस मद्द में इस आय का समावेश होता है—सरकारी आर्ट (साहित्य) तथा श्रीद्योगिक शिक्षा-संस्थाश्रों की फ़ीस, सुधारक

स्कूलों के कारखानों की आय, परीक्षा-फीस, शिद्धा के लिए सार्वजनिक सहायता या दान आदि ।

स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा—इस मह में निम्नलिखित श्राय होती है—दवाइयों श्रीर टीका लगाने की चीक़ों की बिकी, मेडिकल स्कूलों श्रीर कालिजों की फीस, श्रस्पतालों की श्राय, पागलखानों से होनेवाली विशेषतया वह श्राय जो ऐसे पागलों को रखने से होती है, जिनकी श्रार्थिक स्थिति श्रच्छी हो, म्युनिसपैलिटियों श्रीर छावनियों की इस विषय की सहायता, रास्यिनिक विश्लेषण की फीस श्रादि।

विविध आय—इसमें सरकारी गृज़ट, रिपो,टों पुस्तकों आदि की बिको तथा प्रेस की छुपाई आदि से होनेवाली आय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी मह में जोड़ दी गयी है।

विशेष वक्तव्य — ऊपर हमने भारत-सरकार श्रीर प्रान्तीय सरकारों के श्राय-व्यय की महों का परिचय दिया है। प्रान्तीय सरकारों में हमने केवल संयुक्तप्रान्त का ही उदाहरण लिया है। यद्यपि श्राय-व्यय के श्रंक भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक्-पृथक् हैं, श्राय-व्यय की महें सब प्रान्तों में एक-सी ही है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय महों का परिचय देते हुए हमने स्थान-स्थान पर प्रंसगानुसार यह संकेत किया है कि श्राय की किस-किस मह में कमी होनी चाहिए, श्रीर किसमें बृद्धि। इसी प्रकार व्यय की महों के सम्बन्ध में भी उत्तेख किया गया है। मुख्य बात यह है कि श्राय-व्यय की प्रत्येक मह पर भारतीय जनता के

प्रतिनिधियों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तभी यथेष्ट सुधार हो सकेगा। वर्तमान अवस्था में सरकारी आय व्यय की भिन्न-भिन्न महों के सम्बन्ध में कहाँ तक भारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को अधिकार है, और, कहाँ तक शासक उक्त संस्थाओं के निर्णय के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं. यह पिछले (पैंतीसवें और धैंतीसवें) परिच्छेदों में बताया जा चुका है।

प्रान्तों में उत्तरदायी शासन-पद्धति श्रारम्भ हो जाने पर प्रान्तीय सरकारों को अपनी आय-व्यय पर गम्भीर विचार करने के लिए वाध्य होना पड़ा है। उनको आय बहुत परिमित है। पुनः एक ओर तो लगान कम करने. और शराब बन्द करने के कार्य-क्रम से उनकी श्राय श्रीर भी कम होनेवाली है, दूसरी श्रोर उन्हें शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्षा, प्राम-सधार श्रादि श्रनेक जन-हितकारी कार्यों के लिए खर्च बढाना है। इसलिए उनकी श्राय-बृद्धि के उपायों को सोचना श्रावश्यक हो गया है। एक उपाय यह है कि कृषि से होनेवाली आय पर भी कर लगे। बिहार में यह कर लगाया गया है, इसका उल्लेख उन्तीसवें परिच्छेद ('श्रार्थिक स्थिति') में किया जा चुका है। मध्यप्रान्त की सरकार ने पेट्रोल पर कर लगाया था। भारत-सरकार का विचार था कि प्रान्तीय सरकार को ऐसा कर लगाने का श्रिधकार नहीं है. परसंघ न्यायालय के निर्णय से यह सिद्ध हो गया कि प्रान्तीय सरकारें इस कर के द्वारा श्रापनी श्राय बढा सकती हैं। मदरास में प्रान्तीय सरकार ने वस्तुत्रों की बिक्री पर कर लगाया है, यह कर दुकानदारों से उनकी विकी की कुल रक्तम पर बहुत अल्प परिमाण में लिया

जाता है। इसी प्रकार ऊँची ऊँची तनख्वाह पानेवालों पर 'वेतन-कर' लग सकता है। श्रीर जब कोई व्यक्ति श्रन्छी जायदाद या पूँजी छोड़-कर मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियों पर मृत्यु-कर या विरासत-कर लगाया जा सकता है। समय-समय पर श्राय-वृद्धि के श्रीर भी ऐसे उपायों पर विचार होते रहना चाहिए, जिनसे जनता को कष्टन हो। परन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जनता द्वारा वसूल किया हुआ द्रब्य बहुत सोच-विचारकर, मितव्ययिता-पूर्वक जनता के हितार्थ उपयोगी कार्यों में व्यय किया जाय। इस समय अनेक ऊँचे पदों पर विदेशियों का प्रभुत्व हैं, श्रीर उन्हें इतना श्रिधिक रुपया वेतन, भत्ता, श्रीर पेंशन श्रादि के रूप में दिया जाता है, जो देश की श्चार्थिक स्थिति तथा सर्वसाधारण जनता की निर्धनता का विचार करते हर कदापि उचित नहीं है। इसमें तुरन्त सुधार किये जाने की श्रावश्य-कता है । इस विषय में विस्तार-पूर्वक हमारी 'भारतीय राजस्व' पुस्तक में लिखा गया है। साधारण ज्ञान के लिए ऊपर लिखी बातें पर्याप्त हैं।



### वयालीसवाँ परिच्छेद

#### देशी राज्य

किया गया है, वह केवल ब्रिटिश-भारत की है। यह बताया जः चुका है कि राजनैतिक टांघ्ट से भारतवर्ष का एक मुख्य भाग और भी है— वह है देशी राज्यों का। इस परिच्छेद में इस भाग की ही शासन-पद्धति

लक्षण पहले खंड में बताये गये हैं। उस हिष्ट से भारतवर्ष के देशी राज्यों को 'राज्य' कहना उचित नहीं है: रियासतें ही कहना चाहिए।

पर साधारण व्यवहार में इतना सुक्षम विचार न कर दोनों शब्दों का

के सम्बन्ध में लिखा जायगा। 'राज्य' (स्टेट) की परिभाषा श्रीर

समान उपयोग होता है।

देशी राज्यों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है, जिनका आनतिरक शासन यहाँ के ही राजा या सरदार, विविध संसिदों के अनुसार सम्राट्की अधीनता में रहते हुए, करते हैं। छोटे-बड़े इन सब राज्यों की संख्या ५६० है। इनमें से हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर

कश्मीर श्रीर गवालियर श्रादि कुछ तो अपने विस्तार और जन-संख्या में योरप के एक-एक राष्ट्र के समान तथा एक-एक करोड़ रुपये से श्रधिक वार्षिक श्रायवाले हैं, श्रीर बहुत-से राज्य साधारण गाँव सरीखे हैं। वास्तव में राज्यों की संख्या दो सौ से भी कम है, शेष सनदी जागीरें (इस्टेट्स) हैं, जिनके श्रधिपति सरदार या 'चीफ़' कहलाते हैं। केवल ३० ही राज्य ऐसे हैं, जिनकी श्रावादी, च्रेत्रफल श्रीर साधन ब्रिटिश भारत के श्रीसत ज़िले के समान हैं।

देशी राज्यों का शासन-प्रबन्ध—श्रविकतर देशी राज्यों में कोई शासन-विधान नहीं है। उनका शासन शासक की व्यक्तिगत इच्छा, रूचि या योग्यता श्रादि के श्रनुसार बदलता रहता है। जिन राज्यों का शासन-प्रबन्ध कुछ निश्चित है, उनमें भी परस्र स्मानता नहीं है। प्रायः सब का श्रवना-श्रवना निराला हंग है। कहीं-कहीं तो महाराजा (प्रधान शासक) के बाद मुख्याधिकारी दीवान होता है, श्रीर सब बड़े-बड़े श्रविकारी उसके श्रवीन रहते हैं। कहीं-कहीं दीवान प्रधान मंत्री होता है, श्रीर विविध विभागों का प्रवन्ध करनेवाले मंत्री उसके सहायक होते हैं। किसी-किसी राज्य में प्रबन्धकारिणी कौंसिल है, इसके सदस्य भिन्न-भिन्न विभागों का संचालन करते हैं; परन्तु सब पर महाराजा का नियन्त्रण रहता है।

कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ हैं। पर ऐसे राज्यों की संख्या केवल तीस के लगभग है। इनकी अधिकतर समाओं में सरकारी सदस्यों की संख्या काफी होती है तथा गैर-सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर, नामज़द होते श्रथवा म्युनिसपैलटियों श्रादि द्वारा चुने जाते हैं। वास्तव में देशी राज्यों में निर्वाचन-प्रथा का बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। जनता को व्यवस्था-कार्य के लिए श्रपने प्रतिनिधि चुनने का श्रधिकार नहीं-सा है। फिर देशी राज्यों की श्रधिकतर व्यवस्थापक सभाश्रों को क़ानून बनाने या बजट की महों पर मत देने का यथेष्ट श्रधिकार न होने से, वे एक प्रकार से परामर्श देनेवाली संस्थाएँ हैं, उनका शासकों पर कुछ नियन्त्रया नहीं है।

न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की भांति उसकी भी, भिन्न-भिन्न राज्यों में, पृथक् पृथक् रीति है। अधिकांश राज्यों में निराले-निराले क़ानून प्रचलित हैं। कुछ में तो न्याय-सम्बन्धो क़ानून का अभाव ही कहा जा सकता है; शासक की इच्छा ही कानून है। केवल चालीस राज्यों में हाईकोर्ट ब्रिटिश भारत के ढंग पर संगठित है। कुछ, राज्यों में यह विशेषता है कि उनमें न्याय-कार्थ शासन-विभाग से पृथक् है।

कुछ योड़े से उन्नत राज्यों को छोड़कर, श्रन्य राज्यों में म्युनिसपैलिटियों श्रादि स्थानीय संस्थाश्रों की भी बहुत कमी है। कितने ही राज्यों में तो राजधानी में भी म्युनिसपैलटी नहीं है; श्रथवा, यदि है भी तो उसमें नागरिकों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं, राज-कर्मचारियों का ही प्रभुत्व रहता है।

देशी राज्यों का आय व्यय—श्रधिकतर देशी नरेश स्वेच्छा-नुसार मांति-भांति के कर लगाते हैं, और जब चाहें उन्हें बढ़ा देते हैं; उन पर किसी व्यवस्थापक सभा का कुछ नियंत्रण नहीं रहता। खर्च के विषय में भी वे बहुधा स्वच्छन्द हैं। प्रजा के, करों के बोक्त से, दबे रहने पर भी वे लाखों रुपये के महल आदि बनवाते हैं। यदि राज्य की रिपोर्ट छुपती है तो वे इस ख़र्च को निर्माण-कार्य के अन्तर्गत दिखा देते हैं। जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की चिन्ता न कर, शिकार, मनोरंजन और विदेश-यात्रा में तथा कुत्ते मोटर आदि ख़रीदने में, और भारत-सरकार के अफ़सरों आदि का स्वागत-सत्कार करने में असंख्य धन ख़र्च कर डालते हैं। निदान, वे आय का अधिकांश भाग अपनी इच्छानुसार ख़र्च करते हैं। उनका स्वयं अपने लिए वा राज-परिवार के वास्ते लिया जानेवाला द्रव्य निर्घारित नहीं होता, और यदि निर्घारित होता भी है, तो प्राय: उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है।

भारत-सरकार का नियन्त्रण—सब देशी राज्य भारतसरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं। भारत-सरकार का विदेश-विभाग उनकी
निगरानी किया करता है। यह विभाग स्वयं वायसराय के अधीन
है। उसकी सहायता के लिए एक पोलिटिकल सेकेटरी तथा उसके
कुछ सहायक रहते हैं। देशी राज्यों में से हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा,
कश्मीर, गवालियर और सिक्कम, ये छः ऐसे हैं, जिनका भारतसरकार से सीधा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक की राजधानी में भारतसरकार का एक-एक रेजीडेंट रहता है। देशी राज्यों और भारतसरकार में जो पत्र-व्यवहार आदि होता है, वह रेजीडेंट द्वारा ही
होता है। रेजीडेंट देशी नरेश को प्रत्येक आवश्यक विषय पर परामर्श

#### देता रहता है।

कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समूह की एक एक 'एजंसी' है। प्रत्येक एजंसी में एक 'गवर्नर-जनरल का एजंट' या 'ए, जी. जी.' रहता है। यह भारत-सरकार के अधीन होता है, और इसके अधीन कई-कई पोलिटिकल एजंट या (छोटे रेजीडेंट) होते हैं। प्रत्येक पोलिटिकल एजंट एक या अधिक देशी राज्यों का कार्य करता है। वह इनके नरेशों को शासन आदि विषयों में आवश्यक परामर्श देता है। इन नरेशों और भारत-सरकार में जो पत्र-ज्यवहार आदि होता है, वह कमशः पोलिटिकल एजंट और 'ए. जी. जी.' के द्वारा होता है।

कुछ राज्य प्रान्तीय सरकारों के अधीन हैं। उनमें भी पोलिटिकल एजंट (या छोटे रेजीडेंट रहते हैं) किन्तु जहाँ-तहाँ फैले हुए छोटे-छोटे राज्यों या जागीरों (इस्टेट्स) में एजंट का कार्य प्राय: उस कलक्टर या कमिश्नर को ही सौंगा हुआ रहता है, जिसके छेत्र में वह राज्य होता है।

नरेशों का सम्मान — भारत- एरकार द्वारा देशी नरेश दो प्रकार से सम्मानित होते हैं — (१) उगिषयों तथा अवैतिनिक छैनिक पदों से, और (२) तोषों की सलामी से। कुछ उपिषयों पैतृक और स्थायी होती हैं तथा कुछ अस्थायी और व्यक्तिगत रहती हैं। देशी नरेशों में से ११८ को सलामी का सम्मान प्राप्त है। इनमें से जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता या बाहर से आता है, अथवा नरेश की हैसियत से ब्रिटिश-भारत में आता है, या यहाँ से

लौटता है, तो उसके सम्मान के लिए निर्धारित संख्या में तोपें छोड़ी जाती हैं। यह संख्या ९ से २१ तक होती है। इस सम्मान के तीन भेद हैं:—(१) स्थायी, (२) व्यक्तिगत और (३) स्थानीय अर्थात् केवल राज्य के भीतर मिलनेवाली सलामी।

देशी राज्यों के अधिकार—देशी राज्यों के निवासी अपने-श्रपने नरेश की प्रजा हैं। साधारणतया इन पर, श्रथवा इनके शासकों पर, ब्रिटिश-भारत का क़ानून नहीं लग सकता। हा, देशी राज्यों में रहनेवाली ब्रिटिश प्रजा तथा रेजीडेंसी, छावनी, रेल या नहर की भूमि में, अथवा राजकोट या बड़वान (गुजरात) जैसे स्थानों में, जहाँ व्यापार आदि के कारण बहुत-से आँगरेज रहते हों, ब्रिटिश भारत के ही क़ानून का व्यवहार होता है। ब्रिटिश भारत का कोई श्रपराधी यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय तो वह उस नरेश की श्राज्ञा से पकड़ा जाकर. ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता है। देशी राज्यों की प्रजा अपने राज्य की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है। साधारणतः देशी नरेश श्रपनी प्रजा से कर लेते तथा उसके दीवानी श्रीर फ़ीजदारी मामलों का फ़ैसला करते हैं। कुछ नरेश अपने यहाँ श्रानेवाले माल पर चुङ्गी लेते हैं। कई नरेश अभी तक अपने रुपये आदि सिक्के ढालते हैं। परन्तु, इन्हें अपने यहाँ श्रॅगरेजी रुपये को वही स्थान देना पड़ता है, जो उसे ब्रिटिश भारत में मिला है।

भारत-सरकार की नीति—देशी राज्यों के प्रति भारत-सरकार की नीति यह है कि जब तक वे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजमिक

बनायी रखें, श्रीर पहले की संघि की शतों का यथोचित पालन करते रहें, तब तक सरकार उनकी रक्षा करेगी, श्रीर उनका श्रस्तित्व बनाये रखेगी। यद्यपि साधारण दशा में देशी नरेश श्राने राज्यों का स्वयं प्रबन्ध करते हैं. कुछ नरेश वायसराय को 'मेरे दोस्त' लिखते हैं, श्रीर इक्त तैंड को अपना 'मित्र राज्य' कहते हैं, परन्तु कार्य-व्यवहार में नरेश भारत-सरकार के परामर्श की श्रवहेलना नहीं कर सकते। सर-कार जिल नरेश को अयोग्य या असमर्थ समसे. उसे गही से उतार कर, उसकी जगह उसके किसी सम्बन्धी को बैठा देती है, या उसके राज्य में किसी ऋँगरेज को 'एडिमिनिस्ट्रेटर' (शासक) बना देती है। यदि किसी नरेश के सन्तान न हो तो वह उसे उत्तराधिकारी या वारिस गोद लेने की इजाजत दे देती है। वारिस की नाबालगी ( अल्यावस्था ) की हालत में देशी राज्य के शासन का प्रबन्ध सरकार करती. या रिजेंसी द्वारा करवाती है । इन राज्यों को इस बात की श्रनुमति नहीं रहती कि सरकार की श्राज्ञा बिना वे परस्पर एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशी राष्ट्र से, किसी प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सकें, श्रथवा किसी विदेशी को श्रपने यहाँ नौकर रख सकें। इन राज्यों की रक्षा का भार सरकार ने अपने ऊपर ले रखा है। इन्हें एरकार की एहायता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती है। इसके श्रतिरिक्त, ये थोड़ी-धी फौज अपनी श्रांतरिक शान्ति श्रथवा दिखावे के लिए रख सकते हैं: परन्तु किसी पर चढाई करके. श्रयवा किसी को चढ़ाई से श्रपने को बचाने के लिए वे कोई फौज नहीं रख सकते।

बरार के सम्बन्ध में निज़ाम-हैदराबाद से पत्र-व्यवहार करते समय भूत-पूर्व वायसराय लार्ड रीडिंग ने जिस सिद्धान्त का प्रति-पादन किया था, उसका आश्य यह है कि देशी नरेश अपने राज्यों के भीतरी प्रवन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हैं। भारतवर्ष में शान्ति और सुव्यवस्था रखना साम्राज्य-सरकार का, किसी संधि-पत्र से नहीं, स्वयं-सिद्ध अधिकार है। ब्रिटिश सरकार को जब जैसा जँचे, वह किसी देशी राज्य के भीतरी प्रवन्ध में हस्तन्नेप कर सकती है।

जाँच-कमीशन — ऐसे क्रगड़ों के विषय में जो दो या अधिक राज्यों में, किसी राज्य और किसी प्रान्तिक सरकार में, या किसी राज्य और भारत-सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई राज्य भारत-सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असन्तुष्ट हो, वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो क्रगड़ेवाले मामले की जांच करके अपनी सम्मति उसके सामने उपस्थित करें । अगर वायसराय हसे मंजूर न कर सके तो वह उस मामले को फैसले के लिए भारत-मंत्री के पास मेज देगा । जांच कमीशन की व्यवस्था सन् १९२० ई० से हुई है । पर अभी तक इसके प्रयोग को अवसर नहीं आया। जब कभी भारत-सरकार को किसी नरेश के विरुद्ध बहुत शिकायत हुई, तो नरेश ने अन्ततः 'स्वेच्छा-पूर्वक' राज्य त्याग करना ही उचित समक्षा । इससे प्रतीत होता है कि राजा अपने दोषों पर प्रकाश नहीं पड़ने देना चाहते तथा वे कमीशन के परिणाम का पहले से अनुमान कर, उससे आशंकित रहते हैं।

नरेन्द्र मंडल--सन् १९२१ ई॰ से बड़े-बड़े राज्यों की एक नरेन्द्र-मंडल (चेम्बर-आफ़-प्रिंसेज़) नामक छंस्था बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से न हो. जिनका प्रभाव साधारणतः सब राज्यों पर पड़ता हो, श्रथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत श्रौर देशी राज्यों से हो. उन पर इस संस्था की सम्मिति माँगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है: उसकी अनुपिश्यित में कोई राजा ही सभापित का कार्य करता है। मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में है। इसका ऋधिवेशन प्राय: साल में एक बार होता है. उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद होता है। मंडल के नियम वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर बनाता है। नरेन्द्र मंडल प्रति वर्ष एक छोटी-सी स्थायी समिति बनाता है, जिससे वायसराय या केन्द्रीय सरकार का राजनैतिक विभाग देशी राज्यों सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करता है। नरेन्द्र-मंडल के कुल १२ - सदस्य हैं, १०८ सदस्य तो उन ११८ नरेशों में से हैं, जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, श्रीर १२ सदस्य श्रन्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार श्रभी मंडल में केवल २३५ नरेशों के प्रतिनिधि है। शेष ३२५ जांगीरों के सरदार आदि की श्रोर से उसमें प्रतिनिधि भेजने श्रादि की योजना पर विचार हो रहा है। मंडल के श्रधिवेशन में कुछ दर्शक उपस्थित हो सकते हैं। अपने अब तक के जीवन में मंडल प्रजा-हित की दृष्टि से कोई स्वतन्त्र या सन्तोषप्रद कार्य नहीं कर सका है।

बटलर कमेटी श्रीर उसके बाद — देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से उनका आर्थिक सम्बन्ध कैसा हो, इस विषय का विचार करने के लिए दिसम्बर १९१७ ई॰ में 'इंडियन स्टेट्स कमेटी' नियुक्त हुई थी, जिसे उसके सभापति के नाम पर बटलर कमेटी कहते हैं। उसने देशी राज्यों में भारत सरकार के इस्त च्रेप-श्रधिकार को श्रीर भी हढ़ किथे जाने की सलाह दी। हाँ, उसने नरेशों का सम्राट् के साथ सीधा सम्बन्ध होने की बात स्वीकार की श्रीर देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत की, आयात-कर आदि उन महों को आय में से कुछ रूपया देने के सम्बन्ध में विचार किये जाने की सिफारिश की, जिनकी कुछ आय देशी राज्यों की प्रजा से वस्त्त होकर ब्रिटिश-भारत के ख़ज़ाने में आती है। इससे नरेशों को सन्तोष न हुआ। पश्चात् उन्होंने गोलमेज़ परिषदों के में अपने दृष्टि-कोषा को प्रकट करने का प्रयत्न किया। इसके परिणाम स्वरूप, संघ-शासन-विधान में उनके हित का बहुत कुछ ध्यान रखा गया है।

देशी राज्यों का सुधार—कुछ उन्नत या सुधार-प्रिय राज्यों को छोड़कर देशी राज्यों की प्रजा को सार्वजनिक कार्य करने की उतनी स्वाधीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश भारत की जनता को है। बहुधा उनमें सार्वजनिक मत दर्शानेवाले समाचारपत्रों का अभाव ही है। अनेक स्थानों में 'राजा करे सो न्याय,' और नरेश की इच्छा ही क़ानून है। कर लगाने की निश्चित नीति नहीं, प्रजा से कितने-ही

<sup>\*</sup> बत्तीसवाँ परिच्छेद देखिए।

प्रकार से धन-संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार ख़र्च किया जाता है; प्रजा की सुनाई नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की ओर भी यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता। देशी राज्यों के इन दोषों का दायित्व स्वयं उनके नरेशों पर तो है ही — यदि नरेश चाहें तो बहुत-कुछ सुधार कर सकते हैं — हां, कुछ अंश में ब्रिटिश सरकार की नीति भी दूषित है। नरेशों की यह धारणा है कि जब तक वे उसके प्रतिनिधियों को प्रसन्न करते रहेंगे, सरकार उनके शासन-सम्बन्धी दोषों पर विशेष ध्यान न देगो। इसलिए वे प्रजा के प्रति अपने कर्त्तव्य का समुचित पालन नहीं करते।

बत्तीसवें परिच्छेद में, देशी राज्यों की जाग्रति के प्रसंग में, श्रांखल भारतवर्षीय प्रजा-परिषद के सम्बन्ध में लिखा जा चुका है। पिछले दिनों इस परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया था कि बीस लाख से कम श्राबादी श्रीर पचास लाख से कम वार्षिक श्रायवाले राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ मिला देना चाहिए या उन्हें श्रापस में मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया जाना चाहिए। राज्य नामघारी प्रत्येक संस्था का यह श्रानवार्य कर्तव्य है कि नागरिकों के सुख-समृद्धि श्रीर उन्नति में दत्तचित हो। जो राज्य श्राय या च्रेत्रफल श्रादि की हिण्ट से इतने छोटे या श्रासमर्थ हैं कि उपर्युक्त कर्तव्य-पालन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, श्राजीवका श्रीर न्याय श्रादि की भी व्यवस्था नहीं कर सकते, उन्हें श्रपने पृथक् श्रास्तित्व का श्राधिकार नहीं है। उन्हें चाहिए कि श्रपने निकटवर्ची राज्य या प्रान्त में सम्मिलित हो जायें। श्रस्तु, यदि प्रजा-परिषद् का प्रस्ताव कार्यक्रप में परिणत हो जायें।

तो केवल इक्कोस राजा रह जाते हैं। परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए यह आवश्यक है कि यह इक्कीस राज्य भी अपनी पृथक्ता का राग अलापने वाले न हो वरन् भारत की स्वतंत्र केन्द्रीय सरकार के अधीन रहें और उत्तरदायी शासनवाले हों।

[संघ शासन श्रोर देशी राज्य—सन् १६३४ ई० के शासनविधान में, भारतवर्ष के केन्द्रीय शासन का स्वरूप संघ-शासन निर्धारित
किया गया है, जिससे ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक संघ बन
कर दोनों का एक साथ शासन हो। किसी देशी राज्य का, संघ में
सम्मिजित होना उस समय समस्ता जायगा, जब सम्राट् उस राज्य के
नरेश का प्रवेश-पत्रक या शर्तनामा (इन्स्ट्रू मेंट-श्राफ-एक्सेशन) स्वीकार
कर लेगा। संघ को किसी देशी राज्य-सम्बन्धी किन-किन कार्मों को
करने का श्रिषकार रहेगा, इसका निश्चय उस राज्य के प्रवेश-पत्रक
हारा होगा। संघ के सम्बन्ध में श्रन्य श्रावश्यक बाते 'भारत-सरकार'
और 'भारतीय ध्यवस्थापक-संडल' शीर्षक परिच्छेदों में जिस्सी जा
चुकी हैं।]



# तेतालीसवाँ परिच्छेद भारतवर्ष ग्रीर राष्ट्र-संघ

TO SECOND

प्रकृष्टिचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्धगारतवर्ष का अन्य देशों से राजनैतिक सम्बन्ध चिरकाल से रहा है।
महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ उस समय में दूरदूर के राजा और राजनोतिज आया करते थे और वे भारतवर्ष को बहुत
आदर-सम्मान की हिण्ट से देखते थे। अब से सवा दो हजार वर्ष
पहले भारतवर्ष कैसा स्वराज्य-भोगी था और इसका अन्य देशों से
कैसा राजनैतिक सम्बन्ध था, इसकी साक्षी तो विदेशी इतिहास और
अन्य प्रन्थ भी दे रहे हैं। सम्राट् चन्द्रगुष्त के समय यहाँ यूनान आदि
देशों के राजदूत रहते थे। उन्होंने यहाँ के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक
लिखा है। पीछे समय-समय पर यहाँ केन्द्रीय शक्ति निर्वल और
असंगठित रही; तथापि मुगलों का शासन जम जाने पर फिर यहाँ का
सिका योरपवाले मानने लग गये। भिन्न-भिन्न देशों के शासक सम्राट

श्रकवर श्रीर जहाँगीर के दरवार में अपने दूत मेजते. थे, श्रीर इन्हें प्रथन रखने के इच्छुक रहते थे। श्रीरंगजेन के बाद यहाँ फिर फूट श्रीर पारस्परिक कलह रहने लगा। फल-स्नरूप श्रन्ततः, जैसा पहले कहा गया है, श्रॅगरेजों का प्रमुख बढ़ता गया। सन् १८५७ ई० में भारतवािंखों ने उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयत्न किया, पर ये उसमें श्रुषक रहे। श्राख़िर, १८५८ ई० से यहाँ क़ानूनी तौर से भी श्रॅगरेजों का शासन श्रारम्भ हो गया। इस प्रकार श्रपनी स्वतंन्त्रता खोने पर, भारतवर्ष का, श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, पहला स्थान जाता रहा। कुछ काल पश्चात् भारतवािंस फिर जाग्रत होने लगे; विशेषतया सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना करके, उन्होंने शासन-पद्धति में सुधार कराने का श्रान्दोलन श्रारम्भ किया। इसका बर्णन पहले किया जा चुका है।

योरपीय महायुद्ध श्रीर साम्राज्य-परिषद में भारत — संसार में समय-समय पर राज्यों के युद्ध रहे हैं। बहुचा कुछ राज्य इकट्ठे एक पक्ष में हो जाते हैं श्रीर इसी प्रकार दूसरी श्रोर से लड़नेवाले राज्यों का भी एक गुट बन जाता है। इससे युद्ध का आकार-प्रकार बढ़ जाता है। युद्ध महायुद्ध में परिषात हो जाता है। फिर, श्राज कल विज्ञान की बहुत उन्नति हो जाने से युद्ध में बढ़िया से बढ़िया हिंसक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका दुष्परिषाम भी बड़ा भीषण होता है। पिछला योरपीय महायुद्ध सन् १९१४ ई० से १९१८ तक रहा। इसके बाद भी चिरकाल तक सर्वत्र त्राहि-लाहि मची रही। इस युद्ध के सम्बन्ध में यह घोषित किया गया था कि यह छोटे राष्ट्रों की

स्वतंत्रता तथा स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त के लिए लड़ा जा रहा है। भारतवर्ष ने इगर्लैंड की श्रोर से इस युद्ध में भाग लिया। उस समय से ब्रिटिश-साम्राज्य-परिषद् में भारतवर्ष को भी भाग लेने का श्रवसर मिलने लगा। परन्तु जब कि परिषद में साम्राज्य के स्वाधीन भागों के मन्त्री श्रपने-श्रपने राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं, भारतवर्ष की श्रोर से इसका सदस्य बननेवाला भारत-मंत्री एवं उसके सलाह-कार भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। श्रतः वास्तव में इन्हें इस देश का प्रतिनिधि कहना ठीक नहीं है।

पिछले योरपीय महायुद्ध की समाप्ति पर वारसाईं की संघि हुई। संघि पत्र पर जिन राज्यों की श्रोर से हस्ताक्षर हुए, उनमें भारतवर्ष भी था। इसलिए पीछे जब सन् १९२० ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई तो यह भी उसका सदस्य बनाया गया।

राष्ट्र-संघ, उसका संगठन और कार्य — युद्ध के बाद वैराय श्रौर शान्ति का वातावरण होता है। पिछला योरपीय महायुद्ध बहुत विकराल था। इसके बाद विश्व-शान्ति की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। इसी उद्देश्य से सन् १९२० ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई, जिसे श्रॅगरेज़ी में 'लीग-श्राफ नेशन्स' कहते हैं। इस संघ के सदस्य विविध राज्य हैं। इन राज्यों नेसंगठन-पत्र पर हस्ताक्षर करके

<sup>\*</sup>इस परिषद में साम्राज्य के भिन्न-भिन्न मागों के विवाद-ग्रस्त विषयों का विचार होता है तथा उन मागों की त्रार्थिक राजनैतिक ग्रादि उन्नति के उपाय सोचे जाते हैं। इसका अधिवेशन दूसरे-तीसरे वर्ष प्रायः लन्दन में होता है। इसके स्वीकृत निर्णय परामर्श-रूप में होते हैं।

यह प्रतिज्ञा की कि बाहरी हमलों से एक-दूसरे की रक्षा करेंगे, श्रौर परस्पर, श्रथवा श्रन्य किसी भी राज्य से युद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि अपने भगड़ों को पंचायत के सम्मुख फैछले या जांच के लिए न रखें, श्रौर तीन मास से लेकर नौ मास तक का समय न गुज़ारदें। जो राज्य श्रानी प्रतिज्ञा को तोड़िगा वह श्रन्य सब राज्यों का विरोधी समभा जायगा, श्रौर उन सब का कर्तव्य होगा कि प्रतिज्ञा भंग करनेवाले राज्य से आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध न रखें। राष्ट्र-संघ का कार्यालय जेनेश (स्विटज़रलैंड) में रखा गया। पिछले दिनों ५७ राज्य हसके सदस्य थे; यह संख्या समय-समय पर घटनी बढ़ती रहती है।

राष्ट्र-संघ के कार्य तीन प्रकार के हैं:—व्यवस्था, शासन (प्रवन्ध ) और न्याय। इस कार्यों को क्रमशः सभा (एसेम्बली), कोंसिल और अन्तर्राष्ट्रीय अदालत करती है। संघ की सभा के सदस्य वे सब राज्य होते हैं, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य हों। प्रत्येक सदस्य-राज्य को तीन प्रतिनिधि मेजने का अधिकार होता है, परन्तु उसका मत एक ही होता है। सभा के अधिवेशन जेनेवा में होते हैं, प्रति वर्ष प्रायः एक ही अधिवेशन होता है। कोंसिल के कुछ सदस्य स्थायी और कुछ अस्थामी होते हैं। इज़्लेंड, फ्रांस, इटली आदि स्थायी सदस्य है, इनका कभी जुनाव नहीं होता। इसलिए इनका प्रभाव बहुत अधिक है। कोंसिल के अधिवेशन प्रति वर्ष कम-से-कम चार होते हैं। वह वर्ष भर अपना कार्य कमीशनों और समितियों द्वारा करती रहती है।

संघ की छः कमेटियाँ है, वे निम्नलिखित विषयों पर विचार करती है:—

१ - क्रानूनी प्रश्न।

२-विशिष्ट (टेक्निकल) कार्यों की संस्था स्रों का विषय।

३-- निरस्त्रीकरण् ।

४--- बजट और अन्तर्व्यवस्था सम्बन्धी बातें।

५ — सामाजिक प्रश्न।

६--राजनैतिक प्रश्न।

संघ के मंत्री-मंडल-कार्यालय के विविध आंग हैं, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:—

१-राजनैतिक विभाग।

र-श्रार्थिक विभाग।

३ - रफ्तनी या यातायात विभाग।

४-- श्रल्प-संख्यक विभाग ।

५ -- निरस्त्रीकरण विभाग।

६ - स्वास्थ्य-विभाग।

७—सामाजिक प्रश्न और अक्षीम की रफ्तनी का विभाग।

द—बौद्धिक सद्दकारिता और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय (ब्यूरो) विमाग।

९--कानून विभाग।

१० - सूचना या जानकारी विभाग।

११--- श्रन्तर्राष्ट्रीय-श्रम कार्यालय।

संघ के सब विभाग परस्पर एक-दूसरे के सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ छूत के रोगों के फैलने का प्रश्न जहाज़ी बन्दरगाहों के नियमों की श्रेणी में है, अत: रफ्तनी के विभाग से स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध रहना आवश्यक है। इसी तरह 'नरकोटिक' नामक विष का दुरुपयोग न किया जाय, इसकी व्यवस्था के लिये रफ्तनी-विभाग का सम्बन्ध मेडिकल विभाग से रहता है। इसलिए अफीम-विभाग स्वास्थ्य और रफ्तनी-विभाग से समय-समय पर परामर्श किया करता है।

राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष - राष्ट्र-संघ के सदस्य वे राज्य होते हैं, जिनका पद राष्ट्र की तरह माना जाता है। भारतवर्ष राष्ट्र-संघ का सदस्य है। इससे यह समभा जाता है कि इस देश का भी मान स्वतंत्र राष्ट्रों की तरह किया जाता है। राष्ट्र संघ का सदस्य होने से, भारतवर्ष का, संसार के अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध भी बढ़ता है। परन्तु इस देश की ओर से संघ की सभा में भाग लेनेवाले व्यक्ति वास्तव में यहाँ के प्रतिनिधि नहीं होते; भारत-सरकार द्वारा नामज़द होने से वे वर्तमान अवस्था में ब्रिटिश-सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतवर्ष को संघ की कौंखिल में अस्थायी सदस्य का पद भी नहीं मिला है। इस प्रकार संघ में भारतवर्ष का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं है। संघ के कर्म-चारियों में भारतवास्थि की संख्या भी बहुत कम है। अतः यहाँ के नेताओं का मत है कि जब तक भारतवर्ष की संघ में अपना वास्तविक मत प्रकट करने और अपने समुचित पदाधिकारी रखने का अधिकार न हो, उसे इस संस्था से अलग रहना और इस विषय के व्यय-भार

से बचना ही उचित है। व्यय की बात यह है कि संघ का वार्षिक व्यय लगभग साढ़े तेरह लाख पाँड होता है। यह व्यय ९२३ हिस्सों में विभक्त है, संघ के भिन्न-भिन्न सदस्य-राज्यों को इसके लिए भिन्न-भिन्न परिमाण में चन्दा देना होता है। भारतवर्ष पहले ९२३ हिस्सों में से ५१ हिस्सों की रकम देता था। इसका यहाँ बहुत विरोध हुन्ना। अब यह ४९ हिस्से अर्थात् लगभग ग्यारह लाख रुपये देता है।

राष्ट्र-संघ से भारतवर्ष को विशेष लाभ नहीं हुआ, तथापि कळ दिशाओं में लाभ हुत्रा है। भारतवर्ष संघ के अन्तर्राष्ट्रीय अम-कार्यालय का सदस्य है।यह उन श्राठ राज्यों में सम्मिलित है, जिनके श्रीद्योगिक हितों की श्रोर संघ ध्यान देता है। यह श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्बन्धी सम्मेलनों में भाग लेता है और उनके कई निर्णयों को मान्य कर चुका है। उदाहर गुवत श्रम के घंटे कम करना। इससे भारतीय जनता-विशेषतया श्रमजीवियों-को बहुत लाभ पहुँचा है। बम्बई में संघ का एक दक्तर है, जो यहाँ संघ के निर्णयों का प्रचार करता है, श्रीर उसके के कार्यों के सम्बन्ध में उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों का उत्तर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय अभ-कार्यालय की एक शाखा देहली में भी है। संघ का एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सह-कारिता विभाग है यह भी भारतवर्ष के लिए बहुत हितकर है। उसका सामाजिक कार्य तो विशेष रूप से उपयोगी है। संघ की ओर से नियुक्त मेलेरिया कमीशन ने भारतवष त्राकर भी जांच की थी। इसी प्रकार संघ ने एक कमेटी ख्रियों श्रीर बच्चों के अनैतिक व्यापार की जांच के लिए नियत की । उसने इस प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला है। सिंगापुर में संघ का एक दक्तर है, वह प्रति दिन वहाँ से होकर एशियाई बन्दरगाहों पर आनेवाले जहाजों के यात्रियों की बीमारियों के विषय में, बेतार के तार द्वारा समाचार मेजता है। संघ ने निश्चय किया था कि किसी देश से अफीम की निर्यात केवल उतनी ही हो, जितनी औषिवयों के लिए आवश्यक हो। पहले भारत-सरकार द्वारा बहुत-सी अफीम चीन जाती थी, परन्तु अफीम सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करनेवालों में भारतवर्ष के भी होने से, अब यह अनैतिक व्यापार बन्द हो गया है इससे भारतवर्ष और चीन दोनों को ही लाम हुआ है।

राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पृति — जपर संघ के भारतवर्ष-सम्बन्धी काम का उल्लेख लिया गया है ऐसा ही कार्य संघ ने कई अन्य देशों के लिए करके उन्हें लाभ पहुँचाया है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की, अनेक दिशाओं में, आवश्यकता है, और राष्ट्र-संघ जैसी संस्थाएं इसमें बहुत सहायक हो सकती हैं। हाँ, संघ के कार्य में उन्नति और वृद्धि की अभी बहुत गुंजायश है।

एक बात में रुंघ से लोगों को बड़ी निराशा रही है। संघ का निर्माण विशेषतया इस उद्देश्य से हुआ था कि यह युद्धों से होनेवाली, मानव जाति की भयंकर हानि को रोके, किसी देश की स्वतंत्रता अपहरण होती हो, तो उसकी रखा करें और राष्ट्रों की सैनिक शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये। सघ इस विषय में नितान्त अस्पक्त रहा है। इसारे देखते-देखते कितने ही राष्ट्र अपनी प्यारी स्वाधीनता से वंचित हो गये; संघ के होने से उनकी स्थिति में कुछ अन्तर न श्राया । इसलिए लोकमत इस संस्था के प्रति उपेक्षा करने लगा है। बात यह है कि यह संघ सारे संसार का नहीं है, इसके स्त्र-संचालक केवल कुछ ही राष्ट्र हैं। वे कहीं सम्यता-प्रचार के नाम से, कहीं शासन-कार्य की शिक्षा के नाम पर, असंगठित या अवनत भूखंडों को अपने अधीन किये हुए हैं। अतः संघ के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। अन्यान्य बातों में संघ कहता है कि विविध राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु उसके सदस्य-राष्ट्र ही नहीं, वे राष्ट्र भी, जिनका इसमें विशेष बोलबाला है, आत्म-रक्षा या व्यापार वृद्धि की आड़ में अपनी-अपनी सेना और सैनिक सामग्री आदि को भरसक बढ़ा रहे हैं। संसार में हर घड़ी महायुद्ध की आशुंक्ष रहती है, और प्रत्येक महायुद्ध आने से पहले महायुद्ध से अधिक घातक तथा प्रलयकारी होती है। जब संघ के सदस्य-राज्यों में हृदय की उदारता तथा त्याग के भावों का यथेष्ट उदय होगा, तभी वह अपने महान उद्देश्य में सफल होगा। १%

<sup>\*</sup>पुस्तक ख्रपते समय महायुद्ध अपना विनाश-कार्यं कर रहा है। राष्ट्र-संघ युद्धों का अन्त करने के लिए स्थापित हुआ था। पर इस समय तो महायुद्ध ने ही राष्ट्र संघ को निजीव कर रखा है। आशा है महायुद्ध का अन्त होने पर कोई नई व्यवस्था होगी, राष्ट-संघ का पुनर्जन्म होगा। क्या उस समय इसके स्त्रधार इसके अब तक के अनुभवों के लाभ उठावेंगे?